समाजवादी आन्दोलन में समाजवादी पार्टी

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल्० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध - प्रबन्ध

निर्देशक
डॉ० पंकज कुमार
राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

शोधकर्ता
सतिराम सिंह यादव
राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद (उ०प्र०)
2002

From the desk of
Dr. Pankaj Kumar
Department of Political Science
Allahabad University
Allahabad

C/o Mr Krishna Chandra
6, Bank Road, Allahabad-211 002
Ph (0532) [redacted]
2641507, 2644073

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि **श्री सतिराम सिंह यादव पुत्र श्री के0 एस0 यादव** शोध छात्र (राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद) ने मेरे निर्देशन में अपना शोध-प्रबन्ध पूरा किया है। इनके शोध-प्रबन्ध का विषय **"समाजवादी आन्दोलन मे समाजवादी पार्टी की भूमिका"** है। इन्होने विश्वविद्यालय के शोध नियमो की अर्हता को पूरा करते हुए इलाहाबाद मे रहकर अपना शोध-प्रबन्ध पूरा किया है।

मैं डी0 फिल्0 उपाधि हेतु इनके शोध-प्रबन्ध को जमा किये जाने की संस्तुति करता हूँ।

(डा0 पंकज कुमार)
राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

दिनांक : 26-12-2002

विषय सूची

प्रस्तावना

शोधार्थी एक किसान परिवार मे पला बढ़ा है, इसलिए वहॉ की सस्कृति, सोच एव रहन-सहन जेहन मे विद्यमान है। शोधार्थी स्कूली शिक्षा भी इसी वातावरण मे रहते हुए ग्रहण की है। किसानों की समस्याएं एवं गरीबी को अपने व्यवहारिक जीवन मे देखा है एव महसूस किया है। इसलिए पूरा बचपन ही इसी ग्रामीण परिवेश मे बीता है तथा परिवारिक पृष्ठभूमि भी निम्न-मध्यम श्रेणी की है। उसने अपने परिवार से ही समस्याओ से लड़ने, उसका समाधान करने तथा आगे बढ़ने की सीख ली है। शोधार्थी का बचपन शुरु से ही समाजवादी सोच के इर्द गिर्द रहा है। चाहे जाने या अनजाने मे, क्योंकि उसकी परिवारिक पृष्ठभूमि भी इसी के इर्द-गिर्द रही है। उसके सोचने, कार्य करने एवं मतदान प्रक्रिया मे भाग लेने के स्तर पर कांग्रेस पार्टी भी समाजवाद की बात करती थी और समाजवादी विचारधारा को सीधे-सीधे आगे बढ़ाने वाले दल भी थे जो जुड़ते-टूटते रहते थे। ऐसा लगता था जैसे भारतीय राजनीति के केन्द्र मे समाजवादी विचारधारा है और बहुतेरे राजनीतिक दल जनता को इसी लुभावने नारे के द्वारा आकर्षित करने का प्रयास करते थे। जागरुक छात्र होने के नाते प्रारम्भ से ही यह जिज्ञासा मन मे घर कर गयी कि वास्तव मे समाजवाद का दर्शन और विचारा क्या है? सौभाग्य से शोधार्थी का जनपद भी समाजवादी आन्दोलन के विचारधारा का प्रणेता रहा है और इस आन्दोलन के प्रति शायद बचपन से ही आकर्षण ने घर बनाना शुरु कर दिया।

जब उसने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तो छात्र राजनीति मे सक्रिय रहने के कारण सक्रिय वामपंथी, समाजवादी विचारधारा के संगठनो से जुडा। राजनीति विज्ञान मे शोध छात्र के रुप में पजीकृत होने से पहले ही उसने अपने शोध-प्रबन्ध को इसी विषय वस्तु पर केन्द्रित करने का निश्चय कर लिया था। सौभाग्य से शोध निर्देशक के रुप मे आदरणीय डॉ0 पंकज कुमार का उसे प्रोत्साहन मिला और उन्होंने इस विषय पर हर प्रकार से सहयोग का आश्वासन दिया। यही से उसके शोध की औपचारिक शुरुआत शुरु हुई।

इस शोध प्रबन्ध में यह दिखाने की कोशिश की गयी है कि 1977-1990 के बीच भारत मे समाजवादी आन्दोलन मृत प्राय हो गया था और समाजवादी विचारधारा के नाम पर अवसर वादियों तथा पिछलग्गुओं की जमात पैदा हो गयी क्योंकि जनता पार्टी के विघटन के बाद चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में भारतीय लोकदल समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश की

किन्तु उनकी मृत्यु के बाद पुन· उसमे फूट पड़ गयी। पुन· लोकदल (अ) तथा लोकदल (ब) बना किन्तु अन्तर्कलह के कारण यह प्रभावशाली नही बन पाये और विखर गये। पुनः 11 अक्टूबर 1988 अर्थात जय प्रकाश नारायण के जन्म दिन के अवसर पर जनता दल का निर्माण हुआ। 1989 में केन्द्र मे तथा कई प्रान्तो में इसकी सरकार भी बनी लेकिन इसके मूल मे काग्रेसी मानसिकता, अवसरवादिता, पदलोलुपता तथा पिछलग्गुओ की जमात कही न कही विद्यमान थी। कुछ ही समय बात इसका परिणाम सामने आ गया। इन सारी घटनाओ मे सच्चे समाजवादी भी थे लेकिन परिस्थितियों वश उन्हे दमघोटू महौल मे समझौता करना पड़ता था। समाजवाद की जो मूल भावना थी उससे उन लोगों ने कभी समझौता नही किया। इसी का परिणाम है कि श्री मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी प्रेणता डॉ0 राम मनोहर लोहिया के पद चिन्हो पर चलते हुए इस देश में सच्चे समाजवाद की स्थापना करने के लिए स्वतन्त्र रुप से 4 नवम्बर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन करके साबित कर दिया कि जो समाजवाद की मूल अवधारणा है उसे समाप्त नही होने दिया जायेगा चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितिया क्यो न हों? व्यवहार मे भी ये बाते साबित हो चकुी हैं।

यह शोध प्रबन्ध विवरणात्मक विश्लेषण, साक्षात्कार तथा तथ्य विश्लेषण पर आधारित है।इतिहास से सम्बन्धित होने के कारण अन्त. विषय उपागम पद्धति का सहारा शोध प्रबंध मे लिया गया है।

इस कार्य को पूर्ण करने के लिए शोधार्थी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय लाइब्रेरी, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय लाइब्रेरी एवं डॉ0 राम मनोहर लोहिया न्यास, लखनऊ से सहयोग प्राप्त किया है।

आभार

शोध-प्रबन्ध जैसा कठिन, असाध्य और सम्मानित कार्य बिना गुरु के असभव है। मैंने अपने जीवन मे शुरु मे यह नही सोचा था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय मे शोध कार्य पूरा कर सकूँगा। यह असाध्य कार्य था, लेकिन अपने शोध निर्देशक आदरणीय डा0 पकज कुमार (राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद) के असीम प्रेम, सहयोग एव प्रेरणा की भावना ने मेरे अंदर आत्मविश्वास पैदा किया जिससे हमने इस कार्य को पूरा किया।शोध निर्देशक की अनुपस्थिति में उनकी धर्म पत्नी आदरणीया डॉ0 अनुराधा कुमार (राजनीति विभाग, इ0 वि0 वि0) ने शोध कार्य हेतु हर प्रकार से सहयोग किया ।

अत: मैं दोनो प्रबुद्ध जनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और इस महती कार्य के लिए जीवन पर्यन्त ऋणी रहूँगा।

आदरीणय डा0 अलोक पन्त (विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, इ0 वि0 वि0) ने हमेशा मेरे प्रति सहयोगात्मक रुख रखा है। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

राजनीति विज्ञान विभाग, इ0 वि0 वि0 के आदरणीय अध्यायपको मे, डॉ0 मो0 काजमी, डॉ0 मोहम्मद शाहिद, डॉ0 कृष्णा गुप्ता, डॉ0 असलम डॉ0 वी0 के0 राय, डॉ0 डी0 डी0 कौशिक श्री कार्तिकेय मिश्र तथा श्री अश्विनी दूबे ने मेरे इस शोध कार्य मे हमेशा सहयोग एव प्रोत्साहित करने का कार्य किया। इसलिए हृदय से इन गुरुजनों का आभार व्यक्त करता हूँ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डॉ0 हर्ष कुमार (प्राचीन इतिहास विभाग), (मनोविज्ञन विभाग, के प्रो0 ए0 के0 दलाल, डा0 योगा नन्द सिन्हा एव प्रो0 सत्य नारायण, डा0 उमाकान्त यादव (संस्कृत विभाग, इ0 वि0 वि0) तथा सुनील उमराव (पत्रकारिता एवं जनसांचार विभाग, इ0 वि0 वि0,) का भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते है जिन लोगो ने हर स्तर पर सहयोग किया।

अपने शुभचिन्तकों एवं मित्रों में श्री शालिग्राम यादव, श्री शिवभान यादव,मेरे श्री संग्राम सिंह यादव गुरु भाईयों मे श्री विनोद पाल, श्री सघसेन सिंह, श्री बिजेन्द्र सिंह,श्री प्रमोद मल्ल, सीताराम यादव जी, वीरेन्द्र यादव जी, कौशल किशोर जी, एवं अनिल यादव जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री वासुदेव यादव, (निदेशक, शिक्षा उ0 प्र0 सरकार) का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होने हर संभव शोध कार्य हेतु सहयोग प्रदान किया।

प्रिय साथी, धर्मेन्द्र यादव जी का मै विशेष रुप से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ क्योकि उन्होंने शोध मे प्रवेश के समय से ही जल्द से जल्द शोध कार्य पूरा करने के लिए उत्साहित करते रहे तथा हर संभव सहयोग प्रदान किये।

समाजवादी पार्टी उ0 प्र0 के सचिव अदारणीय एस0 आर0 एस0 यादव जी, सांसद श्री अखिलेश यादव जी, सामाजवादी बुलेटिन के संपादक त्रिलोकी नाथ मेहता जी तथा समाजवादी पार्टी उ0 प्र0 कार्यालय एवं डॉ0 राम मनोहर लोहिया न्यास, लखनऊ के सभी कर्मचारियो का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जो शोध-प्रबन्ध हेतु आवश्यक शोध सामग्री उपलब्ध करायी।

अपने पूज्य पिता आदरणीय के0 एस0 यादव जी, मॉ आदरणीया बासमती देवी, अग्रज श्री परशुराम यादव एवं भाभी श्रीमती गामा यादव का हृदय से नमन एव बदन करता हूँ जिनका हमेशा मुझे स्नेह, प्यार एवं आशीर्वाद मिला। उसी का परिणाम है कि आज इस कठिन कार्य को संभव बना सका।

कंप्यूटर ले-आउट, श्री **गोपेश चन्द्र सोनकर** का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि उनके सहयोग के बिना यह कार्य संपादित करना संभव नही था।

और अंत में एक बार पुन: अपने गुरुजनों मित्रो, शुभचिन्तकों एव पारिवारिक सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

(सतिराम सिंह यादव)

शोध छात्र

राजनीति विज्ञान विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

इलाहाबाद

दिनांक:- 25-12-2002

के पर
का उदय

अध्याय—१

विचारधारा के आधार पर समाजवाद का उदय

अध्याय–1

विचारधारा के आधार पर समाजवाद का उदय

I - समाजवाद का आशय

समाजवाद की वर्तमान विचारधारा 19वी शताब्दी मे विकसित हुई। सन् 1807 ई0 मे रॉबर्ट ओवेन के अनुयायियो के लिए अग्रेजी भाषा मे समाजवादी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। 19वी शताब्दी मे औद्योगिक क्रान्ति तथा पूजीवाद ने समाज मे इतनी उग्र आर्थिक विषमता पैदा कर दी तथा श्रमिक वर्ग मे इतनी अधिक दयनीय दरिद्रता तथा शोचनीय स्थिति पैदा कर दी कि उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप समाजवाद की विचारधारा उत्पन्न हुई। लेकिन इसके कुछ मौलिक विचार जैसे-आर्थिक विषमता का उन्मूलन,पूजीवादी वर्ग की आलोचना, पूजीपति वर्ग द्वारा शोषण का विरोध अतिप्राचीन है। इनका सभी कालो तथा सभी देशो मे विरोध किया गया है। समाजवाद की विचारधारा भी अपने आप मे एक प्रतिक्रियात्मक विचारधारा है। औद्योगिक क्रान्ति के समय मे प्रबल होने वाली व्यक्तिवाद की विचारधारा ने इसके प्रादुर्भाव एव विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दिया। बीसवी शताब्दी मे विश्व के राजनीतिक और सामाजिक चिन्तन को जिस विचारधारा ने सबसे अधिक प्रभावित किया है, वह समाजवादी विचारधारा है ।[1] वर्तमान मे तो समाजवाद एक प्रभावशाली आन्दोलन तथा एक क्रान्तिकारी सिद्धात के रूप मे गतिमान है।[2] लेकिन समाजवाद क्या है? यह स्पष्ट करना एक कठिन कार्य है।[3] इसका कारण यह है कि विभिन्न विद्वानो ने अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार समाजवाद की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है।[4]अरस्तू से लेकर महात्मा गॉंधी तक विचारकों ने समाजवाद के विषय मे भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किये हैं।[5] कुछ विद्वान समाजवाद को

---

1 प0 जवाहरलाल नेहरू-विश्व इतिहास की झलक, खण्ड 2, पृष्ठ 760

2 सी0 ए0 आर0 क्रासलैण्ड द फ्यूचर आफ सोशलिज्म, द मीनिंग आफ सोशलिज्म, पृष्ठ 97 117

3 - समाजवाद की जटिलता का उल्लेख शाडवेल निम्नाकित शब्दो मे करता है- 'मनुष्य के मस्तिष्क को यदि सबसे अधिक किसी प्रश्न ने सक्रमित किया है, तो वह है अनेक रूपी जटिल तथा अस्पष्ट समाजवाद। समाजवाद एक बहुमुखी दैत्य है, जब हम इसके एक सिर को काटने का प्रयत्न करते है, तभी इसका दूसरा सिर निकल आता है"।

4 - वही, पृष्ठ 97-114

5 - फ्रासिस डब्ल्यू कोकर-रीसेन्ट पोलिटिकल थाट, पृष्ठ 36

व्यक्तिवाद के विरूद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप मे स्वीकार करते है, कुछ इसे एक राजनीतिक दर्शन मानते है, और कुछ के विचार मे यह एक महान श्रमिक आन्दोलन है, जिसका लक्ष्य श्रमिको को उनका हक दिलाना है।[6] वास्तविकता यह है कि समाजवादी विचारधारा मे आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सिद्धातो मे ऐसा समन्वय हो गया है कि उन्हें पृथक करना कठिन है। आधुनिक युग मे समाजवाद मात्र एक विचारधारा मात्र नही है, वरन यह मानव जीवन का एक आदर्श, एक सिद्धात, एक नीति, एक आस्था और एक जीवन प्रणाली बन गया है।[7]

समाजवाद की परिभाषा-

सी0 ई0 एम0 जोड का विचार है कि समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है, जिसकी आकृति बिगड चुकी है क्योकि प्रत्येक इसे अपनी इच्छानुसार पहनना चाहता है।[8] इसकी पुष्टि मे रैम्जेम्योर ने भी कहा है कि समाजवाद एक गिरगिट के समान है, जो वातावरण के अनुकूल अपने रग को बदल लेता है।[9] इस विचारो से स्पष्ट होता है कि समाजवाद की सर्वमान्य परिभाषा देना एक कठिन कार्य है। जॉन ग्रीफिथ के सर्वेक्षण के अनुसार समाजवाद की 260 से अधिक परिभाषाए है। इलाई ने अपनी पुस्तक मे समाजवाद की 400 परिभाषाएं दी है और पेरिस के प्रमुख पत्र ''ल फिगारो'' के 1891 ई0 के संकलन मे 600 परिभाषाए सकलित की जा चुकी है।[10] आकड़ो से स्पष्ट होता है कि जितने विचारको ने समाजवाद पर विचार किया है, उतनी ही समाजवाद की परिभाषाए है। इसलिए समाजवाद की परिभाषा का प्रश्न अब विवादास्पद विषय बन गया है। इस विषय पर टिप्पणी करते हुए रम्पो पोर्ट नामक विद्वान ने कहा है कि ''यदि कोई मुझसे पूछे कि मै स्वय समाजवादी हूँ अथवा नहीं, तब मै उसे

---

6 - सी ई0 एम जोड-माडर्न पोलिटिकल थ्योरी- पृष्ठ 3

7 - आर0 ए0 प्रसाद- सोशलिस्ट थाट उन माडर्न इण्डिया, पृष्ठ 5

8 - सी ई एम जोड- माडर्न पोलिटिकल थ्योरी, पृष्ठ 40

9 - रैम्जेम्योर- लिबरलिज्म एण्ड एन्डस्ट्री, टूवर्डस ए बेटर सोशल अर्डर, अध्याय-1

10 - डब्ल्यू, डी0 पी0 बिलिस- हैण्ड बुक आफ सोशलिज्म (1907), जॉन मार्टिन- एन अटैम्प टू डीफाइन सोशलिज्म-अमेरिकन इकोनामिक एसोसिएशन बुलेटिन, (1911), पृष्ठ 347-359, जान ग्रीफिथ- व्हाट इज सोशलिज्म- (1924), समाजवाद की व्याख्या के आधार पर इसके विभिन्न सम्प्रदायो की गणना की गयी है, जिनमे प्रमुख सम्प्रदाय है- कल्पनावादी समाजवाद, राज्य समाजवाद, इसाई समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, फेबियनवाद, सशोधनवाद, श्रेणी समाजवाद,श्रमिक सघवाद,बोल्शेविकवाद आदि। इनके प्रमुख वक्ताओ मे क्रमश राबर्ट ओवन, सेंट साइमन, स्मोलर बिस्मार्क, किग्ले गाडरिस, मार्क्स, ऐगेल्स, बर्नार्ड शॉ, सिडनी वेब, बर्नस्टाइन, कोल, हाब्सन, लेनिन और ट्राट्स्की आदि आते है।

ठीक-ठीक उत्तर न देकर स्पष्ट रूप से यह कह दूगा कि मै नही जानता कि मै समाजवादी हूँ अथवा नहीं। यह तो उस व्यक्ति की बुद्धि पर आधारित है कि वह समाजवाद का क्या अर्थ लगाता है।[11]

इन मतभेदो के बावजूद भी समाजवाद की कतिपय महत्वपूर्ण परिभाषाओ का उल्लेख करना हमारे लिए आवश्यक है, जिनका विवरण निम्नलिखित है --

हूबर्ड ब्लाड[12] "समाजवाद का अर्थ उत्पादन तथा विनिमय के साधनो के समान स्वामित्व से तथा इस प्रकार की व्यवस्था करने से है कि सबको समान लाभ हो।"

एमाइल[13] "समाजवाद श्रमिको का ऐसा सगठन है, जिसका उद्देश्य पूजीवादी सत्ता मे परिवर्तन करने के लिए राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना है"।"

हम्फे[14] "समाजवाद एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत जीवन के साधनो पर सम्पूर्ण समाज का स्थायित्व होता है और पूरा समाज सामान्य हित को बढाने के उद्देश्य से उनका विकास और प्रयोग करता है।"

शैफले[15] समाजवाद का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत तथा खुली प्रतियोगिता [illegible] को सामूहिक पूजी मे परिवर्तन करना है।"

ह्यूमन[16] "समाजवाद श्रमिक वर्ग का एक आन्दोलन है, जिसका उद्देश्य उत्पादन तथा वितरण के बुनियादी साधनो के सामूहिक स्वामित्व और लोकतांत्रिक प्रबन्ध के द्वारा शोषण का अन्त करना है।"

रैम्जे मैक्डानल्ड[17] - "सामान्य शब्दो मे समाजवाद की सर्वोच्च परिभाषा यही है कि इसका उद्देश्य समाज के भौतिक तथा आर्थिक साधनो पर जनता का नियत्रण है।"जी0 डी0 एच 0 कोल "[18]समाजवाद के अर्थ मे चार बाते निहित है- समस्त व्यक्तियो का भ्रातृत्व, जिसमे वर्ग भेद का नाम न हो, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने साथियो से न अधिक धनी हो और न ही अधिक निर्धन, ताकि

एच डब्ल्यू लैडलर हिस्ट्री आफ सोशलिज्म, पृष्ठ 28
डब्ल्यू डी0 पी0 विलियम हैण्ड बुक आफ सोशलिज्म पृष्ठ 28
[illegible] एमाइल उद्धृत फ्रांसिस, डब्ल्यू कोकर रीसेन्ट पोलिटिकल थाट एण्ड जान ग्रीफिथ-व्हाट इज सोशलिज्म
हम्फे-उद्धृत जान ग्रीफिथ व्हाट इज सोशलिज्म- अध्याय 1 पृष्ठ 31
अल्बर्ट शैफले उद्धृत हेनरी डब्ल्यू लैडलर हिस्ट्री आफ सोशलिस्ट थाट पृष्ठ 673
लेन्सीलाट हूबन उद्धृत हैण्ड बुक आफ सोशलिज्म, पृष्ठ 30
रैम्जे मैक्डानल्ड सोशलिज्म एण्ड सोसाइटी, पृष्ठ 13
जी0 डी0 एच0 कोल सोशल थ्योरी, पृष्ठ 7

वे समानता के आधार पर एक दूसरे से मिल सके, समस्त उत्पादन के साधनो पर सामूहिक स्वामित्व तथा समस्त नागरिको को अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार एक दूसरे की सेवा करना है ।''

इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार-''समाजवाद वह सिद्धात है, जिसका उद्देश्य केन्द्रीय जनतान्त्रिक शासन द्वारा एक अच्छी वितरण व्यवस्था और उसके अधीन सम्पत्ति के उत्पादन की अच्छी व्यवस्था करना है ।''

अलैक्जेण्डर ग्रे अनुसार-''समाजवाद अधिक से अधिक सम्पत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व के उन्मूलन की माग करता है और चाहता है कि इस प्रकार के हस्तान्तरित सम्पत्ति पर अधिकार और उसका उपयोग पूरे समाज द्वारा किया जाय ।''

रॉबर्ट के अनुसार-''समाजवादी कार्यक्रम मे वास्तव मे एक ही माग है कि भूमि तथा उत्पादन के अन्य साधन जनता की सामान्य की कम्पनी बना ली जाय ।इनके उपयोग एव प्रबन्धन की व्यवस्था जनता द्वारा जनता के हित के लिए किया जाये ।''

बर्ट्रेण्ड रसल के अनुसार- ''यदि हम अर्थ, सम्पत्ति और भूमि के सामूहिक स्वामित्व से समाजवाद का अर्थ ले तो हम उसके साराश के निकट पहुँच जाते है ।''

प्रो0 पीगू के अनुसार- ''उत्पादन के साधनो पर व्यक्तिगत अधिकार को ही पूजीवाद और सार्वजनिक अधिकार को समाजवाद कहते है ।''

रोश्चर के अनुसार-''समाजवादी उन सब प्रवृत्तियो के पक्ष मे है, जिनमे मनुष्य के व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सार्वजिनक सुख की बात निहित हो ।''

प्रो0 ईली के अनुसार- ''एक समाजवादी वह है जो कि समाज को एक राजकीय सगठन के रुप मे देखता है और जिसका उद्देश्य आर्थिक वस्तुओ का अधिक पूर्ण वितरण तथा मानवता को ऊँचा उठाना है ।''

एम.दूगन बोरो विस्की के अनुसार-''समाजवाद की नैतिकता का मौलिक आधार है कि मनुष्य की क्षमता के आदर्श को स्वीकार करना चाहिए ।''

पं0 जवाहर नेहरु के अनुसार- ''समाजवाद के कई रुप है, लेकिन एक बात मे सभी सहमत है कि इसका उद्देश्य यह है कि उत्पादन के साधनो अर्थात खानो,जमीन, कारखानो आदि पर और रेलो जैसे

साधनो पर और बैको जैसी सस्थाओ पर सभी राज्य का प्रभुत्व हो।"[19]

आचार्य नरेन्द्रदेव के अनुसार-"समाजवाद का उद्देश्य एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है, जिसमे न कोई शोषक हो, न शोषित, बल्कि समाज सहकारिता के आधार पर निर्मित व्यक्तियो का एक सामूहिक सगठन हो ।"[20]

जय प्रकाश नारायण के अनुसार- "समाजवादी समाज एक ऐसा वर्गरहित समाज होता है, जिसमे सभी समान होते है। यह एक ऐसा समाज होता है, जिसमे व्यक्तिगत सम्पत्ति के लिए मानवश्रम का शोषण नही होता, जिसमे समस्त सम्पत्ति वास्तविक रुप मे राष्ट्रीय होती है,जिसमे किसी को बिना कुछ किये नही मिलता और जिसमे आप की अधिक असमानताए नही होती, तथा जिसमे मानव का सचालन व उसकी उन्नति योजनाबद्ध ढग से होती है तथा जिसमे सब व्यक्तिगत सबके लिए जीवित रहते है ।"[21]

इन परिभाषाओ की समीक्षा करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि समाजवाद न केवल एक राजनीतिक दर्शन है वरन् यह एक महान आन्दोलन भी है। यह व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक तीव्र प्रतिक्रिया है। समाजवादी समाज एक ऐसा वर्ग विहीन समाज होता है, जिसमे व्यक्तिगत सम्पत्ति वास्तविक रुप मे राष्ट्रीय सम्पत्ति होती है,जिसमे प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम करने पर ही पारिश्रमिक मिलता है और जिसमे आय की अधिक विषमता नहीं होती है । जिसमें मानव जीवन का सचालन व उसकी प्रगति योजनाबद्ध तरीके से होती है तथा जिसमे सभी व्यक्ति सबके लिए जीवित रहते है।

समाजवाद के तत्व-

समाजवादी के सिद्धात के प्रमख तत्व निम्नवत है --

1 समाजवादी समाज वह है जहाँ उत्पादन और वितरण के साधनो पर समाज का स्वामित्व हो, जहाँ राज्य समाज के प्रतिनिधि के रुप मे इन साधनो पर नियत्रण रखे तथा राज्य केवल व्यवस्था के रुप मे स्थित रहे, लेकिन मार्क्सवाद पर आधारित समाजवाद राज्य उन्मूलन के पक्ष मे है।

---

19 - प0 जवाहरलाल नेहरु विश्व इतिहास की झलक, खण्ड 2, पृष्ठ 761
20 - आचार्य नरेन्द्र देव राष्ट्रीयता और समाजवाद, पृष्ठ 409
21 - जय प्रकाश नारायण दि फाउन्डेशन ऑफ सोशलिज्म, (1936), बिमला प्रसाद, पृष्ठ 12-13

2 समाजवाद आर्थिक उत्पादन के साधनो पर सामाजिक नियत्रण की स्थापना करना चाहता है जिससे इनका उपयोग एक या कुछ व्यक्तियो के हित मे नही वरन् सम्पूर्ण समाज के हित मे है।

3 समाजवादी समाज मे आर्थिक प्रगति का अर्थ केवल प्रचुर भौतिक साधन की उपलब्धि नही है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इनका उपयोग मनुष्य के सुख, विकास, सम्मान और समृद्धि हेतु किया जाय ।[22]

4 समाजवादी समाज मे राजनीतिक स्वतन्त्रता और आर्थिक स्वतन्त्रता को एक दूसरे का पूरक समझा जाता है। वास्तविकता यह है कि वर्तमान विश्व मे समाजवाद से रहित कोई भी वास्तविक लोकतन्त्र नही है ।[23]

5 समाजवादी समाज मे व्यक्ति और समाज के मध्य एक विशेष प्रकार के सम्बन्ध होते है।व्यक्ति समाज के आवश्यक यन्त्र के रुप मे आर्थिक उपलब्धियो का सामूहिक रुप से उपयोग करता है ।[24]

6 समाजवाद का उद्देश्य मनुष्य की भैतिक समस्याओं से मुक्त कराकर उसे वास्तविक स्वतन्त्रता का उपयोग करने और अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का अवसर देना है।[25]

7 समाजवाद का लक्ष्य शोषण विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है ।[26]

8 समाजवाद जाति-पाति, ऊँच-नीच, वर्ग- भेद आदि मे आस्था नही रखता है ।[27]

2- समाजवादी संकल्पना का अभ्युदय

समाजवादी विचारधारा का विकास क्रम अत्यधिक विस्तृत है ।[28] आधुनिक काल मे "समाजवाद" शब्द का सर्व प्रथम लिखित प्रयोग इटालियन भाषा मे सन् 1803 ई0 मे किया गया,

---

22 - आचार्य नरेन्द्र देव डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इन इण्डिया, पृष्ठ 64

23 - वही, पृष्ठ 64

24 - वही, पृष्ठ 62

25 - सी0 ई0 एम0 जोड़- माडर्न पोलिटिकल थ्योरी, पृष्ठ 49

26 - वही, पृष्ठ 51

27 - आचार्य नरेन्द्र देव-डेमोक्रटिक सोशलिज्म इन इण्डिया, पृष्ठ 62, पृष्ठ 63, राममनोहर लोहिया- विल टू पावर, पृष्ठ 120

28 - फ्रासिस डब्ल्यू कोकर- रीसेन्ट पोलिटिकल थाट, पृष्ठ 36

तत्पश्चात् सन् 1827 मे राबर्ट ओवेन ने सहकारिता के सिद्धातो के सन्दर्भ मे इस शब्द का प्रयोग किया ।[29] 19वी शताब्दी के चौथे दशक मे आक्सफोर्ड डिक्शनरी मे "समाजवादी" और "सामजवाद" शब्दो को सकलित किया गया। इसी समय अलैक्जेण्डर जैक्स ने अपनी पुस्तक मे "समाजवाद", साम्यवाद, समूहवाद आदि शब्दो का प्रयोग किया ।[30] इसके बाद विश्व के कुछ देशो मे "समाजवाद" निरन्तर लोकप्रिय होता गया।

पाश्चात्य राजदर्शन में समाजवादी चिन्तन

पाश्चात्य राजदर्शन मे समाजवाद के उद्गम की कल्पना प्लेटो के यूनानी राजदर्शन मे की गयी थी ।[31] कई राजनीतिक विशारदो ने प्लेटो के "रिपब्लिक" मे समाजवाद के कुछ तत्वो का समावेश पाया है ।[32] लेकिन प्लेटो ने जिस साम्यवादी धारण का प्रतिपादन किया था, वह सम्पत्ति के सामूहिक वितरण पर आधारित न होकर शासको तथा सैनिको तक ही सीमित थी । अत प्लेटो का साम्यवाद वर्तमान समाजवाद से भिन्न प्रतीत होता है ।[33] लैडलर, प्लेटो के सिद्धान्त को "अभिजात साम्यवाद" की सज्ञा देता है ।[34] स्टोइक दर्शन मे प्लेटो के समान ही एक आध्यात्मिक समाजवाद की कल्पना मिलती है ।स्टोइक के अनुसार विश्व नागरिकता का अधिकार सभी व्यक्तियो को है और ससार का जीवन चक्र समानता व कल्याण की भावना से सचालित होता है ।

कुछ इटेलियन विचारको के ग्रन्थो मे समाजवाद विषयक आशिक भाव उपलब्ध होते है।[35] मध्ययुगीन ईसाई लेखको की कृतियो मे, जिन आर्थिक विचारो का प्रतिपादन किया गया

---

29 - वही, पृष्ठ 36, फुट नोट 2, सन् 1833 मे ' पुअर मैन गार्जियन' नामक पत्र मे भी समाजवाद शब्द प्रयुक्त किया गया था ।

30 - वही पृष्ठ 36, फुट नोट 2 व 3

31 - दि रिपब्लिक आफ प्लेटो (अनुवाद-कार्नफोर्ड), पृष्ठ 106

32 - दि रिपब्लिक आफ प्लेटो (डेवीज), पृष्ठ 125, प्लेटो की रिपब्लिक, पृष्ठ 107-108, जी0 डी0 एच0 कोल-सोशलिस्ट थाट, जिल्द-1, पृष्ट 2, अलैक्जेण्डर ग्रे-दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 3, बार्कर- ग्रीक पोलिटिकल थ्योरी, पृष्ठ 61, डनिग- हिस्ट्री आफ पोलिटिकल थ्योरीज, पृष्ठ 88

33 - मैक्सी- पोलिटिकल फिलासफीज, पृष्ठ 55, बार्कर-ग्रीक पोलिटिकल थ्योरी, पृष्ठ 213, टेलर-प्लेटो, पृष्ठ 226

34 - दि रिपब्लिक आफ प्लेटो (डेवीज), पृष्ठ 28, कोकर-रीसेन्ट पोलिटिकल थाट पृष्ठ 36

35 - हैरी डब्ल्यू लैडलर-हिस्ट्री आफ सोशलिस्ट थाट, पृष्ठ 14

है, उनमे समाजवादी विचारो की झलक मिलती है ।[36] आधुनिक समाजवादी लेखको का मत है कि समाजवादी विचारधारा का विकास 1789 ई0 की फ्रासीसी राज्य क्रान्ति के समय से हुआ था ।[37]

राज्य क्रान्ति से पूर्व फ्रांस की राजनीतिक ,आर्थिक और सामाजिक दशा अत्यधिक शोचनीय थी और जन साधारण मे राजतन्त्र के विरुद्ध घोर असन्तोष व्याप्त था। इस असन्तोष का विस्फोट 5 मई 1789 ई0 को हुआ, इनमे निम्न विचारो की स्थापना की गयी। उनका प्रभाव न केवल फ्रान्स वरन सम्पूर्ण यूरोप मे स्थापित परम्परागत व्यवस्था पर पड़ा। फ्रास के क्रान्तिकारियो द्वारा उद्घोषित "स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व" के नारे से समाजवादी चिन्तको को बड़ी प्रेरणा मिली। इसके साथ ही 1775 ई0 की अमेरिकी क्रान्ति और इग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति ने भी समाजवादी चिन्तन को एक नयी दिशा प्रदान की।

19वीं शताब्दी मे समाजवादी विचारधारा के विकास के कारण-

18वी शताब्दी तक समाजवादी आन्दोलन प्रभावशाली न बन सका, किन्तु 19वी शताब्दी से इस आन्दोलन मे तीव्रता और प्रखरता आने लगी। उसका मूल कारण औद्योगिक क्रान्ति से उत्पन्न होने वाली विशेष परिस्थितियाँ थी। उसने कई कारणो से उस आन्दोलन को प्रोत्साहित किया ।[38]

1 उसने समाज मे स्पष्ट रुप से कारखानो मे, उत्पादन के साधनो पर स्वामित्व रखने वाले पूजीपति वर्ग को उत्पन्न किया । मध्यकाल से चली आने वाली गिल्ड व्यवस्था (Guild system) को उस पूंजीवादी व्यवस्था ने समाप्त कर दिया था । मध्य युगीन श्रमिक वर्ग का उत्पादन के साधनो पर श्रम के अलावा भी आधिपत्य था, किन्तु अब मशीनो द्वारा उत्पादन के होने के कारण श्रमिक उत्पादन के साधनो से वंचित हो गया । वह केवल मशीनो को अपने हाथ से चलाने वाला सामान्य मजदूर बन गया । यह श्रमिक पहले के श्रमिको से भिन्न था । एक साथ कार्य करने के कारण एकता की भावना

---

36 - इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, जिल्द 18, इग्लैण्ड के क्रान्तिकारी प्रोटेस्टेण्ट विचारक जान बाइक्लिफ ने भी समानता और प्राकृतिक अधिकारो के सिद्धात का समर्थन किया इन्हे 'राजतन्त्रवादी साम्यवादी" की उपाधि दी गयी है, लैडलर-ए हिस्ट्री आफ सोशलिस्ट थाट, पृष्ठ 23

37 - जी0 डी0 एच0 कोल-सोशलिस्ट थाट, दि फारनर्स, पृष्ठ 11, डनिग- दि हिस्ट्री आफ पोलिटिकल थ्योरी, पृष्ठ 398, भगवान दास- ऐन्सीएन्ट वर्सेज माडर्न साइन्सटिफिक सोशलिज्म (1934), पृष्ठ 13, अलैक्जेण्डर ग्रे-दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन (1946), पृष्ठ 28

38 - थामस किरकप- हिस्ट्री आफ सोशलिज्म, पृष्ठ 20

का विकास होने लगा । अपनी श्रेणी के कष्टो को दूर करने की,उसके लिए पूजीपतियो के प्रति रोष प्रकट करने की तथा अपनी शिकायते दूर करने के लिए सघ बनाने की प्रवृत्तियो उत्पन्न होने लगी।

2 उससे सबधित दूसरा कारण पूंजीवाद का उत्कर्ष था । औद्योगिक क्रान्ति के विकास एव प्रगति के साथ-साथ मशीनीकरण के विकास की सभावनाए भी बढने लगी तथा दूसरी ओर उद्योगो का विकास होने से श्रमिको की सख्या मे वृद्धि होने लगी । उन सब कारणो ने पूंजीवाद के विकास में काफी योगदान दिया । श्रमिक वर्ग मे उस पूजीवादी व्यवस्था के प्रति विरोध की भावना विकसित होने लगी ।

3 जैसे-जैसे उद्योगो मे अधिक पूजी लगायी जाने लगी वैसे-वैसे उद्योगो का स्वामित्व भी अल्प पूॅजीवादियो के हाथो मे जाने लगा। यह पूँजीपति वर्ग अपने स्वार्थ तथा हितो की दृष्टि से उद्योगो का सचालन तथा स्वार्थो को प्राथमिकता देने लेगे।पूजीपतियो द्वारा मजदूर वर्ग के हितो की उपेक्षा की जाने लगी। उससे उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामो से समाजवादी आन्दोलन को प्रेरणा मिली, उन्हे यह विश्वास होने लगा कि पूँजीपति वर्ग अपने स्वार्थो तथा हितो को कभी नही छोडेंगे उत्पादन के साधन उनसे बल पूर्वक छीनकर समाज के स्वामित्व और प्रभुत्व मे लाये जाने चाहिए।

औद्योगिक क्रान्ति से ये परिस्थितियॉ सर्वप्रथम पश्चिमी यूरोप के देशो-फ्रास और इग्लैण्ड के देशो मे उत्पन्न हुई, अत· समाजवादी विचारो का विकास भी सर्वप्रथम उन्हीं देशो मे हुआ। समाजवादी विचारधारा के विकास मे सबसे अधिक योगदान व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रतिक्रियात्मक शक्ति थी । औद्योगिक क्रान्ति के साथ एक नवीन विचारधारा का विकास होने लगा था। व्यक्तिवाद की विचारधारा औद्योगिक क्रान्ति की देन थी ।इग्लैण्ड मे बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्ति के अधिकारो का उग्र समर्थन किया। जे0 एस0 मिल बेन्थम से भी आगे गये, वे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के इतने उग्र समर्थक थे कि वे उसमे किसी प्रकार के अवरोध को अमान्य ठहराते थे तथा हर्बर्ट स्पेन्सर ने योग्यतम की विजय के सिद्धात का प्रतिपादन किया। व्यक्ति को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हुए राज्य "समाज" के कार्यक्षेत्र को अत्यधिक सीमित और सकुचित कर दिया। इस व्यक्तिवाद की विचारधारा के विपरीत बुद्धिजीवी वर्ग मे एक प्रतिक्रिया हुई, इस प्रतिक्रिया के

फलस्वरुप एक नवीन विचारधारा का विकास होने लगा, जिसने व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्व दिया तथा समाज अथवा राज्य को व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक माना ।

वर्तमान समय मे समाजवाद का केन्द्र बिन्दु रुस को माना जाता है । परन्तु समाजवादी विचारधारा का विकास सर्वप्रथम फ्रास और इग्लैण्ड मे हुआ । इस विचारधारा के वैज्ञानिक स्वर देने का श्रेय जर्मनी के विचारको को है । 19वी शताब्दी के समाजवादी विचारधारा को विकास को दो भागो मे विभाजित किया जा सकता है- कार्ल मार्क्स के पूर्ववर्ती विचारक तथा उसके बाद के विचारक ।कार्ल मार्क्स ने अपने से पूर्व के विचारको को कल्पनावादी विचारक की सज्ञा दी थी, क्योकि उन्होने उसे स्थापित करने के लिए कोई व्यवहारिक योजनाए प्रस्तुत नहीं की थी । सर्वप्रथम समाजवादी विचारधारा का प्रादुर्भाव एव विकास फ्रास मे हुआ, उसके बाद इग्लैण्ड मे, क्योकि उन्हीं देशो की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियाँ ही विषमताओ से परिपूर्ण थीं ।

3-कल्पनावादी समाजवाद-

टामस मूर (1478-1535ई0)-फ्रांस की राज्य क्रान्ति से पूर्व ही 16वी शताब्दी में सर टामस मूर ने इंग्लैण्ड की दुर्दशा से दु खी होकर 1616 ई0 मे प्रकाशित 'यूटोपिया' नामक ग्रन्थ की रचना की । इस ग्रन्थ मे समाजवाद के अनेक तत्वो का उल्लेख मिलता है, विशेष रुप से इस ग्रन्थ का दूसरा भाग टामस मूर के समाजवादी चिन्तन पर प्रकाश डालता है, जिसमे उसने तत्कालीन निरकुश राजतन्त्र और सामन्तशाही की कटु आलोचना की है एवं एक ऐसे काल्पनिक समाज का चित्रण किया है- जिसे हम वर्ग विहीन और विशेषाधिकार हीन समाज की संज्ञा दे सकते है ।[39]टामस मूर को आधुनिक राजदर्शन के इतिहास मे कल्पनावादी समाजवादा का जनक माना जाता है । टामस मूर के बाद फ्रासिस बेकन ने उसके समाजवादी विचारों को वैज्ञानिक रुप प्रदान किया । बेकन ने अपने न्यू एटलाटिंस मे एक ऐसे द्वीप का वर्णन किया, जिसमे वैज्ञानिक साधनो को समानता, स्वतन्त्रता एवं बन्धुत्व युक्त जीवन के निर्माण मे प्रयोग किया गया था । इसी समय जर्मन यात्री एण्ड्रियास ने "क्रिश्चियन नोपोलिस" मे तथा इटली के "मान्क कैम्पानेला" ने अपने "सिटी आफ दि सन" में काल्पनिक साम्यवाद का उल्लेख किया ।17वी शताब्दी मे जॉन लाक और डिमर्स ने भी कल्पनावादी

---

39 - अलैक्जेण्डर ग्रे- दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 61-62

समाजवाद का पक्ष पोषण किया ।18वी शताब्दी के प्रारम्भ मे मेबल (1709-1785ई0) ने अपने समानता और सम्पत्ति सबधी विचारो मे समाजवाद को एक दिशा प्रदान की ।[40]

4-फ्रास के कल्पनावादी समाजवादी विचारक

फ्रास मे सर्वप्रथम समाजवादी विचारधारा का विकास हुआ । इसका कारण फ्रास की आर्थिक, सामाजिक एव राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियाँ थी। फ्रास की अपेक्षा अन्य यूरोपीय देशो मे सामाजिक विषमता उतनी उग्र नही थी जितनी फ्रास मे । फ्रास के सर्वप्रथम समाजवादी विचारक नोयल वावेफ थे । उनके समय की मजदूरो की स्थिति का वर्णन थामसन किरकुप ने बहुत स्पष्ट शब्दो मे किया है। किन्सले, जो उस समय के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थे, उस समय की सामाजिक दशा तथा श्रमिको की आर्थिक एव सामाजिक स्थिति का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया है ।[41]

फ्रासिस नायल वावेफ-(1764-1797 ई0)

फ्रासिस नायल वावेफ फ्रास की क्रान्ति के समय हुए थे । उस क्रान्ति ने सब मनुष्यो के समान होने की घोषणा की थी, किन्तु फ्रास के समाजवादी विचारक यह मानते है कि सभी मनुष्यो को राजनीतिक समता के साथ-साथ आर्थिक समता भी मिलनी चाहिए । उसमे वावेफ को प्राचीन तथा अर्वाचीन समाजवाद का विभाजक और आधुनिक साम्यवाद का निर्माता कहा जाता है। रोवेस्पियर के पतन के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि क्रान्ति का सबसे अधिक लाभ निजी भूमि रखने वालो को हुआ है, साधारण जनता को उसमे कोई लाभ नही हुआ । सन् 1790 ई0 मे उसने लिखा था कि-"जब मै देखता हूँ कि गरीबो के शरीर पर न कपडे है और न पैरो मे जूते, गरीब लोग ही कपडे और जूते बनाते है, पर उन्हे ही वे इस्तेमाल के लिए नही मिलते, और जब मै उन लोगो का विचार करता हूँ, जो स्वय भी कुछ कार्य नहीं करते, पर जिनके पास किसी भी प्रकार की कमी नही है तो मेरा यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि राज्य भी जन साधारण के विरुद्ध कुछ लोगो का षडयन्त्र है ।" वह समाज मे आर्थिक विषमता का अन्त करके समानता स्थापित करना चाहता था । उसका विश्वास था कि निजी सम्पत्ति

---

[40] - अलैक्जेण्डर ग्रे- दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 87-90

[41] - थामसन किरकुप-हिस्ट्री आफ सोशलिज्म, पृष्ठ 23

गृह युद्ध और विषमता को उत्पन्न करती है, अत उसका उन्मूलन होना चाहिए । उसका यह प्रस्ताव था कि मृत व्यक्तियो की सम्पत्ति पर राज्य अधिकार कर ले और इस प्रकार पचास वर्ष मे राज्य ही सब प्रकार की सम्पत्ति का स्वामी बन जायेगा । उसके विचार मे सब व्यक्तियो से समान रुप से काम लेना चाहिए, कार्य का समय कानून द्वारा निश्चित होना चाहिए । उसने उत्पादन पर नियत्रण स्थापित करने तथा व्यक्ति की आवश्यकताओ के अनुसार सम्पत्ति के वितरण पर बल दिया ।

वावेफ से पूर्व समाजवादियो ने केवल एक नवीन समाज की कल्पनाए की थी, किन्तु इसकी यह विशेषता थी कि इसने उसकी उपयुक्त योजना बनाने के साथ-साथ उसे व्यावहारिक रुप देने के लिए भी क्रान्तिकारी पद्धति का विकास किया । इस विषय मे ऐसे तरीको का प्रतिपादन किया, जिनका अनुसरण समाजवादी दल आज तक कर रहे है । इसने अपनी योजना को सफल बनाने के लिए समानता चाहने वाले व्यक्तियो का षडयंन्त्र (Conspiracy of equals) किया । इसने अपने सिद्धांतो के प्रचार के लिए सर्वप्रथम कम्यूनिस्ट पत्र "दि ट्रिव्यून आफ द पीपुल" की स्थापना की। सेना की पुलिस मे अपने समर्थको के गुप्त गुटो का निर्माण किया, तथा बलपूर्वक सत्ता हथियाने की योजना बनायी। वावेफ का विचार था कि पूजीपति वर्ग कभी भी स्वेच्छापूर्वक अपनी शक्ति नही छोडेगे, उसे उनसे जबरदस्ती छीनना पडेगा । उसका विचार था कि एक बार विद्रोह करने से कम्यूनिस्ट लोकतत्र की स्थापना होने तक एक अधिनायक तन्त्र की स्थापना करना आवश्यक है। किन्तु वावेफ की योजना सफल नही हुई । सन् 1796 ई0 मे उसे गिरफ्तार कर लिया गया, और अगले वर्ष उसे मौत की सजा दी गयी। किन्तु उसकी योजना और विचारो का भावी समाज पर गहरा प्रभाव पडा । **नार्मन मैकेन्जी** के शब्दो मे किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा उसने लेनिन का तथा सन् 1917 ई0 की बोल्शेविक क्रान्ति का अधिक मात्रा मे पथ-प्रदर्शन किया ।[42] वह पहला महत्वपूर्ण समाजवादी था जिसने यह घोषणा की थी कि बडी सावधानी पूर्वक तथा योजना के साथ की जानी वाली सैनिक कार्यवाही की भाँति सम्पन्न होने वाली क्रान्ति द्वारा ही श्रमिक वर्ग राजनैतिक सत्ता हस्तगत कर सकता है ।[43]

---

42 - नारमन मैकेन्जी-सोशलिज्म, पृष्ठ 20

43 - एच0 डब्ल्यू0 लैडलर,-इकोनामिक सोशल मूवमेन्ट, पृष्ठ 58

सेंट साइमन (1760-1825) ई0

सेंट साइमन सम्भवत प्रथम व्यक्ति था, जिसने औद्योगिक सभ्यता के महत्व को समझा और उसने नये युग को "सगठन के युग" की सज्ञा दी ।[44]उसका पूरा नाम "Claude-Henry de Rouvroy, saint simon" था। वह 1760 ई0 मे फ्रांस के एक सामन्तवादी परिवार मे उत्पन्न हुआ था। उसका जीवन बड़ा रोमाचकारी था । वह फ्रास की राज्य क्रान्ति का समर्थक था, और निरकुश राजतन्त्र, दूषित आर्थिक तन्त्र और भ्रष्ट समाज मे अमूल चूल परिवर्तन करना चाहता था ।[45] साइमन को इस बात का गहरा विश्वास हो चुका था कि समाज के सगठन और निर्देशन मे बौधिक तत्व की प्रधानता होनी आवश्यक है।उसकी यह मान्यता थी कि समाज का नियन्त्रण कुछ विशिष्ट व्यक्तियो के हाथो मे है, उन्हे समाज मे विशेषाधिकार प्राप्त है और वे जीवन का पूर्ण आनन्द उठाते है, दूसरी ओर कुछ ऐसे भी व्यक्ति है, जो दिन रात कठिन परिश्रम करते है, फिर भी उन्हे दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुए भी उपलब्ध नही हो पाती है ।[46]

साइमन समाज की इस विषमता को मिटाकर एक नवीन समाज की स्थापना करना चाहता था। वह विज्ञान की सहायता से जन साधारण का हित करना चाहता था।[47] वह समाज का नियन्त्रण वैज्ञानिको, उद्योगपतियो तथा टेक्नीशियनो के हाथो मे रखने का पक्षपाती था। लेकिन साइमन सम्पत्ति के समाजीकरण के पक्ष मे नहीं था । उसका मत था कि सम्पत्ति से जन साधारण का हित होना चाहिए और धन के उत्पादन मे प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिश्रम के अनुसार ही पारितोषिक प्राप्त होना चाहिए । साइमन की जन हितकारी भावना से स्पष्ट होता है कि वह लोकतन्त्र की स्थापना मे विश्वास रखता था परन्तु वास्तव मे वह लोकतन्त्रवादी न ही था और नही वह जन साधारण के हाथों मे शासन सत्ता देने के पक्ष मे था ।[48] साइमन की यह धारणा थी कि यदि बड़े-बड़े उद्योगपतियो को समाज का नेतृत्व दे दिया जायेगा तो ट्रस्टी के रुप मे अपने कार्यो को सम्पादित करेगे । वे जनता की क्रय शक्ति को बढाकर निम्न स्तर के लोगो मे पर्याप्त सुधार ला देगे । इसके परिणाम

---

44 - अशोक मेहता- डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, पृष्ठ 18 मैक्सी-पोलिटिकल फिलासफीज, पृष्ठ-543-44

45 - हैरी डब्ल्यू लैडलर-हिस्ट्री आफ सोशलिस्ट थाट- (1927), अध्याय 14, थामस किरकप-हिस्ट्री आफ सोशलिज्म-(1913),अध्याय 5

46 - अलैक्जेण्डर ग्रे-दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 152

47 - अशोक मेहता-स्टडीज इन सोशलिज्म, पृष्ठ 19-20

48 - इनसाइक्लोपीडिया आफ सोशल साइन्सेज-पृष्ठ 507-508

स्वरुप उत्पादन मे वृद्धि होगी तथा समाज की विषमता का धीरे-धीरे अन्त हो जायेगा और श्रमिक तथा उद्योगपतियो के मध्य किसी सघर्ष की सभावना तक न रहेगी ।

सेंट साइमन के मूल सिद्धान्तो मे समाजवाद के तत्व बहुत कम है उसने अपने समय मे कई समाजवादी केन्द्र स्थापित किये उसके अनुकरण कर्ताओ ने सघो के माध्यम से उसके विचारो का प्रचार कार्य प्रारम्भ किया तथा फ्रास मे वह प्रबल समाजवादी विचारक समझा जाने लगा । इस रुप मे परवर्ती विचारको पर उसका गहरा प्रभाव पडा ।मैक्सी ने लिखा है कि-"जर्मनी मे उसने विस्मार्क तथा कार्ल मार्क्स को प्रेरणा प्रदान की, फ्रास मे अगन्तलोन्टे तथा लुई ब्लाक का सैद्धातिक गुरु था, इग्लैण्ड मे राबर्ट ओवेन तथा अन्य समाजवादी विचारको को प्रभावित किया । सेट साइमन ने प्रथम बार विज्ञान का औद्योगिक उन्नति के साथ अर्न्तसम्बन्ध बताते हुए ऐतिहासिक विकास की उस पद्धति की ओर सकेत किया जिसके आधार पर विभिन्न समयो (कालो) के मनुष्य-समाज की प्रगति की व्याख्या की जा सकती है । इस प्रकार इतिहास की आर्थिक व्याख्या मे वह कार्ल मार्क्स और एगेल्स का पूर्ववर्ती है।[49]

चार्ल्स फोरियर-(1772-1837 ई0)

चार्ल्स फोरियर की गणना कल्पनावादी समाजवाद के आधार स्तम्भो मे की जाती है। साइमन के समान वह भी एक फ्रासीसी विचारक था । वह साइमन का अनुयायी था, तथापि साइमन के कुछ विचारो से वह असहमत था । फोरियर बड़े उद्योगो के स्थान पर छोटे उद्योगो की स्थापना को उपयुक्त समझता था ।[50] वह उत्पादन मे अपव्यय तथा प्रतिस्पर्धा का विरोधी था ।वह एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता था, जो तत्कालीन दोषो से रहित हो ।

फोरियर के अनुसार नवीन समाज मे प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतन्त्रता मिलेगी । इस नवीन समाज मे सबसे छोटी इकाई एक व्यावसायिक समूह होगी इस समूह मे सात सदस्य होगे जिनकी रुचिया और हित समान होगे ।पाच या कुछ अधिक समूह मिलकर एक सीरीज बनायेगे और

49 - थामस किरकप- हिस्ट्री आफ सोशलिज्म, पृष्ठ 28

50 - अशोक मेहता डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, पृष्ठ 19, मैक्सी- पोलिटीकल फिलासफी, पृष्ठ 520 21

पच्चीस सीरीजो से मिलकर एक फ्लैक्स का निर्माण होगा जो नवीन समाज की सबसे बड़ी इकाई होगी ।[51]

प्रत्येक फ्लैक्स मे श्रमजीवी, उद्योगपति, डाक्टर, इन्जिनियर आदि विभिन्न पेशो के लोग सम्मिलित होगे । फ्लैक्स के सभी सदस्य आन्तरिक सहायता तथा सहयोग के द्वारा एक आत्मनिर्भर इकाई का निर्माण करेगे। इसके प्रमुख तीन धन्धे- कृषि, पशुपालन तथा भोजन निर्माण होगे । फोरियर के अनुसार नवीन समाज मे लोग निजी सम्पत्ति रख सकेगे और सम्पत्ति का उत्तराधिकार भी वशानुगत रहेगा । फ्लैक्स के सगठन से उत्पादन मे अत्यधिक वृद्धि हो जायेगी । स्त्री और पुरुषो के एक साथ करने से एक उच्चतम श्रम विभाजन सम्भव हो सकेगा ।

लुई ब्लांक-(1713 ई0)

लुई ब्लाक पहला विचारक था जिसने समाजवादी विचारो को राज्य की सहायता से क्रियात्मक रुप देने का विचार रखा था । लुई ब्लाक की पुस्तक ''परिश्रम का सगठन'' सन् 1839 मे प्रकाशित हुई । उसने फ्रास के सर्वहारा वर्ग मे चेतना का सचार किया । वह पहला विचारक था जिसने मजदूर किसानो को अपने कल्याण के लिए राजनीतिक सत्ता हाथ मे लेने का सुझाव रखा । उसका प्रथम सिद्धात था कि हमारे सामाजिक प्रयत्नो का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति तथा उसका विकास होना चाहिए । विकास का अभिप्राय यह है कि मानव के पास अपनी उच्चतम मानसिकता, नैतिक और शारीरिक प्रगति करने के लिए तथा उत्तम व्यक्ति का निर्माण करने के लिए उपयुक्त साधन होने चाहिए ।लुई ब्लाक के विचारो का आदर्श एक औद्योगिक सरकार थी, जो कि राष्ट्र के औद्योगिक यन्त्र का प्रबन्ध करे। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक कारखानो (सोशल वर्कशाप)का विचार रखा । आदर्श समाज बनाने के लिए प्रत्येक सदस्य को कार्य देना आवश्यक है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य को सामाजिक उद्योगो का निर्माण करना चाहिए। प्रारम्भिक अवस्था मे यह व्यक्तिगत अधिकार मे होगे, तथा शनै -शनै समाज के अधिकार मे आ जायेगे । राज्य को उसका सचालन सार्वजनिक तथा सामान्य हित की दृष्टि से करना होगा । इस प्रयत्न से धीरे-धीरे समाजवादी समाज की स्थापना से और समाज अग्रसर होगा । इन सभी कार्यो को प्रजातन्त्र

51 - सेलेक्शन्स फ्राम दि वर्क्स आफ फोरियर- सोशल साइन्स सीरीज, खण्ड 3 व 6

के आधार पर करना होगा ।समाजवादी समाज मे इन उद्योगो मे प्रबन्ध और परिश्रम करने वाले व्यक्तियो को यह अधिकार होना चाहिए कि अपने-अपने व्यवसाय के प्रबन्ध का चुनाव कर सके । तथा अपने व्यवसाय मे होने वाले लाभ को परस्पर सहयोग के आधार पर विभाजित करें एवं उद्योगों के विकास का प्रयत्न करे ।

लुई ब्लाक उत्पादन पर व्यक्तिगत अधिकार को समाज के लिए हितकर नही समझता था । सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण तथा सामाजिक अधिकार मे लाने का सर्वप्रथम विचार ब्लाक ने रखा था। सरकार को और उद्योगो की स्थापना स्वय की करना चाहिए, जिससे व्यक्तिगत उद्योग स्वत· ही समाप्त हो जायेगे ।

ब्लाक ने एक अन्य सिद्धात समाज के सामने रखा । प्रत्येक को अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार समाज की सेवा करनी चाहिए तथा उसे अपनी आवश्यकताओ के अनुसार समाज की सेवा करनी चाहिए तथा उसे अपनी आवश्यकताओ के अनुसार समाज से प्रतिफल मिलना चाहिए । शक्ति और ज्ञान का मानवहित की दृष्टि से पूर्ण सदुपयोग किया जाना आवश्यक है । ब्लाक से पूर्ववर्ती विचारक व्यक्ति से उसकी योग्यतानुसार कार्य लेने मे एक मत थे । परन्तु पारिश्रमिक देने मे भिन्न मत रखते थे । सेंट साइमन के अनुयायी यह मानते थे कि व्यक्ति का वेतन काम के अनुसार होना चाहिए । फोरियर ने उसके बारह हिस्से करके उन्हे पूजीपति, मजदूर और कुशल श्रमिकों मे विभिन्न अनुपात मे बॉटा था । ब्लाक ने उन दोनो मतो को न मानते हुए इस मत को प्रतिपादित किया कि प्रत्येक व्यक्ति को वेतन उसके आवश्यकतानुसार दिया जाना चाहिए ताकि वह अपनी शक्ति और गुणो का विकास कर सके । ब्लाक ने ही समाजवाद के प्रसिद्ध सिद्धात को जन्म दिया कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुसार काम लिया जाना चाहिए, और उसकी आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए । "From each according to his ability, to each according to his needs"

फ्रास की क्रान्ति से (सन् 1789 ई0) सत्ता हस्तान्तरण जनता के हाथ मे नही आयी । राजसत्ता सामन्त शाही के हाथो से निकलकर उच्च मध्यम वर्ग के हाथो मे चली गयी । उसके बाद भी फ्रांस मे क्रान्ति के अनेको प्रयास हुए उन क्रान्तिकारियो ने प्रजातन्त्र और समाजवाद के क्षेत्र मे विशेष

योगदान दिया। ब्लाक के प्रभाव के कारण उसकी समकालीन सरकार ने, जिसका वह भी एक सदस्य था, सम्पत्ति के समाजीकरण के अनेक प्रयास किये, जो पूर्णतया सफल नही हो पाये।

पी0 जे00 प्राउधों (P.S.Proudhon)-(1809-1865 ई0)

यह फ्रास के सभी समाजवादियो मे सबसे उग्र विचारक था। इसने अब तक के सभी विचारको की अपेक्षा अधिक उग्रता तथा प्रबलता के साथ निजी सम्पत्ति का विरोध किया। आर्थिक विपन्नता ने प्राउधो को पूँजीवादी समाज का उग्र विरोधी बना दिया। सन् 1840 ई0 मे उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक (What is Property?) "सम्पत्ति क्या है ?" प्रकाशित की। उसमे निजी सम्पत्ति की व्यवस्था का उग्रतम खण्डन है। छ वर्ष बाद प्राउथो ने निर्धनता की विवेचना करने वाला एक ग्रन्थ "दरिद्रता का दर्शन" प्रकाशित किया, इसमे समाजवादी और साम्यवादी सिद्धातो की कडी आलोचना की और अपनी योजना को विस्तार पूर्वक प्रचारित करने के लिए उसने "न्याय और धर्म की भावना" (1858) मे प्रकाशित की। चर्च तथा प्राचीन आदर्शो की उसने कडी आलोचना की, इसी वजह से उसे कडा दण्ड दिया गया।[52]

प्राउधो का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धात निजी सम्पत्ति का विरोध है। उसके आदर्श समाज मे सम्पत्ति की कोई व्यवस्था नही थी। वह सम्पत्ति को चोरी समझता था। उसका विचार था कि श्रम ही सम्पत्ति को पैदा करने का प्रधान साधन है। यदि श्रम न किया जाय तो भूमि और पूँजी से कोई वस्तु उत्पन्न नही की जा सकती। मनुष्य जब स्वय कोई श्रम किये बिना अपनी भूमि तथा पूँजी पर दूसरे व्यक्तियो का श्रम लगाकर उसका लगान अथवा लाभ प्राप्त करता है तो वह चोरी होती है, क्योकि उस श्रम पर मजदूरो का अधिकार होना चाहिए।[53]

यद्यपि प्राउधो समाजवादी होने की अपेक्षा शासन हीन व्यवस्था (अराजकतावाद) का अधिक समर्थक था, परन्तु फिर भी उसने ऐसे विचारो को प्रतिपादित किया जिन्हे मार्क्स ने अपने सिद्धातो मे सम्मिलित किया, तथा एक ठोस नीव तैयार करने मे सहायक तत्व का कार्य किया।[54] प्राउथो पहला विचारक था जिसने इस ओर सकेत किया कि श्रमिक वर्ग के साधन हीन होने के

---

52 थामस किरकप-हिस्ट्री आफ सोशलिज्म, पृष्ठ 52

53 - वही, पृष्ठ 53

54 - प्रो0 यशपाल- मार्क्सवाद, पृष्ठ 20

कारण उन्हे अपने श्रम का पूर्ण मूल्य नही मिलता तथा साधनो का स्वामी परिश्रमो के बिना ही श्रम के फल पर अपना आधिपत्य जमा लेता है । मार्क्स ने 'अतिरिक्त मूल्य' के जिस सिद्धात की स्थापना की उसका पहला अविकसित सकेत हम यहीं पाते है ।

प्राउधो के विचारो मे जिस आर्थिक विचारधारा का वर्णन है, वह प्रजातन्त्र के आधार पर ही सफल हो सकती है । उसके विचारो मे न्याय, स्वतन्त्रता, एव समानता के तत्वो का समिश्रण है। उसने जिस समाज की कल्पना की है उसके आधार मे भी स्वतन्त्रता, समानता तथा न्याय ही मौजूद है ।[55] सरकार के सगठन के सबध मे, वह किसी भी प्रकार के शासन का विरोधी था, क्योकि शासन मे व्यक्ति को अपने विकास के लिए पूर्ण अवसर नही प्राप्त होते । प्राउधो के समय मे समाज की व्यवस्था के साथ, धर्म-विश्वास का गहरा सम्बन्ध माना जाता था । समाज व्यवस्था मे परिवर्तन लाने के लिए परम्परागत सामाजिक नियमो तथा धर्म-विश्वासो को अमान्य किये बिना सम्भव नही था । प्राउधो ने उस कार्य मे पहल की तथा परम्परागत सामाजिक नियमो की कटु आलोचना की ।

यद्यपि फ्रास के प्रारभिक समाजवादी विचारक सेट साइमन, नोयल वावेल, फोरियर इत्यादि धार्मिक प्रभाव से मुक्त नही थें । उन्होने धार्मिक -विश्वासो और सामाजिक समस्याओ की ओर ध्यान नही दिया था । प्राउधो के विचारो ने समाज मे एक नई चेतना पैदा की सर्व साधारण को उसके विचारो मे आचार हीनता की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी । उसका विचार था कि स्त्री-पुरुष के आचार सम्बन्धी नियमो को केवल धर्मिक भय से न मानकर वैक्तिक विकास का साधन और व्यवस्था के लिए आवश्यक समझना चाहिए । उसके इन विचारो को क्रियात्मक रुप समाज मे प्रदान किया गया ।

फ्रांस विश्व मे पहला देश था जिसमे सर्वप्रथम समाजवादी विचारो का उदय हुआ तथा विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

5-ब्रिटेन के समाजवादी विचारक

समाजवादी विचारधारा का विकास फ्रास के समानान्तर इग्लैण्ड मे भी हुआ । औद्योगिक क्रान्ति सर्वप्रथम ब्रिटेन मे सम्पन्न हुई थी ।अत यहाँ समाजवादी विचारधारा का अभ्युदय एव विकास सर्वथा स्वाभाविक था । इंग्लैण्ड मे समाजवादी विचारको मे दो समान विचारधाराओ का

---

55 - थामस किरकप- हिस्ट्री आफ सोशलिज्म पृष्ठ 54

विकास हुआ, एक शाखा गाडविन के अराजकतावादी विचारो की थी तथा दूसरी विचारधारा रिकार्डो के इस सिद्धात पर आधारित थी कि किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण उस पर लगाये गये श्रम के आधार पर किया जाता है । ब्रिटेन की समाजवादी विचारधारा ने आधुनिक समाजवाद के प्रवर्तक मार्क्स को भी प्रभावित किया ।

यद्यिप फ्रास और इंग्लैण्ड मे एक समान ही सामाजिक तथा आर्थिक विषमताांए मौजूद थी । परन्तु फ्रांस की अपेक्षा इग्लैण्ड की समाजवादी विचारधारा मे नैतिकता का मिश्रण अधिक था । यद्यपि यहॉ फ्रास की अपेक्षा पूजीवाद अधिक विकसति तथा समर्थ था । इग्लैण्ड में कुलीनतत्र फ्रास की अपेक्षा कम पनप रहा था । यद्यपि लॉक तथा एडम स्मिथ के उदारवादी विचारो ने समाजवाद की नीव तैयार कर दी थी । दोनो ही विचारको ने मजदूरी और मूल्य के सिद्धात का प्रतिपादन किया था । सर्वप्रथम इग्लैण्ड मे स्मिथ ने यह विचार रखा था कि राज्यो को वस्तुओ का उत्पादन तथा भूमि सबधी नियम तथा उत्पादन का सग्रह, जो मजदूरो द्वारा उत्पादित किया जाता है, नियत्रण तथा नियमन करना चाहिए ।[56]

समाजवादी विचारधारा के अभ्युदय का कारण सामाजिक एव आर्थिक विषमताए होती है । यह विचार सर्वमान्य विचार है । इस विषमता का सबसे अधिक प्रभाव समाज के सबसे निम्नवर्ग (श्रमिक वर्ग) पर पड़ता है । एक विचारक ने इग्लैण्ड के श्रमिको को आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध मे लिखा है कि---

1 किसानो और मजदूरो का निर्वाह उन्हे मिलने वाली मजदूरी से सम्भव है ।

2 उनके निवास स्थानो की दशा अत्यन्त सोचनीय है ।

3 पूँजीपति एव जमींदार वर्ग लगातार मजदूरी घटाने का प्रयत्न करते रहते है । इसलिए पुरुषो के स्थान पर स्त्रियो तथा बच्चो को कार्य पर लगाया जाता है, जिनसे कार्य उनकी क्षमता भर लिये जाता है तथा मजदूरी आधी या उससे भी कम दी जाती है । इस कारण से मजदूरो मे बेरोजगारी बढ़ जाती है ।

---

56 - इनसाइक्लोपीडिया आफ सोशल साइन्सेज,- वैल्यूम 7, पृष्ठ 193

4 शिक्षा प्राप्त करने का उन्हे अवसर नही है ।[57]

ब्रिटेन की समाजवादी विचारधारा अपने सही रुप मे राबर्ट ओवन से प्रारम्भ होती है । परन्तु उससे पूर्व भी कुछ विचारको का प्रादुर्भाव हो चुका था ।

जैसे- गाडविन, रिकार्डो इत्यादि ।

विलियम गाडविन -(1756-1836 ई0)

विलियम गाडविन ब्रिटेन मे अराजकतावाद का प्रबल समर्थक और वैक्तिक सम्पत्ति का उग्र विरोध करने वाला प्रथम महत्वपूर्ण विचारक था । फ्रास की क्रान्ति के समय सन् 1793 ई0 मे उसकी प्रसिद्ध पुस्तक व राजनीतिक न्याय के विषय मे अन्वेषण (इन्क्वायरी कन्सर्निग पोलिटिकल जस्टिस) ने इसे कीर्ति के चरम शिखर पर पहुचा दिया । उसके विचार इतने क्रान्तिकारी थे कि इग्लैण्ड की सरकार को उसकी पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा ।

उसका प्रथम मौलिक सिद्धात है कि शासन अथवा राज्य एक आवश्यक बुराई है और उसका उन्मलून होना चाहिए । उसकी वह पुष्टि निम्नलिखित परम्परा के आधार पर करता है।उसके विचारानुसार मानव के मन मे कोई नैसर्गिक धारणाए अथवा विचार नही है । वह केवल क्रान्तियों से प्राप्त होने वाले अनुभवो (ससेशन्स) को ग्रहण करता है और उसमे तर्क करने की शक्ति है, उससे वह अपने अनुभवो को विचारो मे बदल लेता है । किसी वस्तु का नैतिक अथवा अनैतिक होना हमारे विचार पर निर्भर है । विचार परिस्थितियो पर निर्भर है। यदि सामाजिक सस्थाए और परिस्थितिया न्याय पर आधारित हो तो मनुष्य के विचार अच्छे होगे तथा विकास भी समुचित तरीके से होगा । किन्तु सरकार शक्ति तथा हिंसा का माध्यम है, वह समाज मे आर्थिक विषमताओ को स्थाई बनाती है। सामाजिक कल्याण की दृष्टि से उनका उन्मूलन होना चाहिए । गाडविन निजी सम्पत्ति के उन्मूलन का उग्र समर्थक था । सामाजिक असमानता का मुख्य आधार वैक्तिक सम्पत्ति ही है । समाज मे वस्तुओ का उत्पादन तथा वितरण समानता के आधार पर होना चाहिए । गाडविन ने ब्लाक द्वारा प्रतिपादित सिद्धात की नीव इग्लैण्ड मे रखी कि "प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाना चाहिए।" चौथा सिद्धात नई व्यवस्था को लाने मे शक्ति के स्थान पर बुद्धि के

---

[57] - थामस किरकप, ऐन इन्क्वायरी इन्टू सोशलिज्म पृष्ठ 48

साधन पर बल देना था । फ्रास क्रान्ति ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हिंसा के माध्यम से व्यक्ति को नही बदला जा सकता है ।

रिकार्डो --यद्यपि कि यह पूंजीवाद का समर्थक था, परन्तु उसके दो सिद्धान्तो ने समाजवाद के विकास पर गहरा प्रभाव डाला । पहला सिद्धात मूल्य विषयक है । रिकार्डो का यह मत था कि एक वस्तु का विनिमय मूल्य (एक्सचेंज वैल्यू) उस पर लगाये गये श्रम पर आधारित है। किसी वस्तु के उत्पादन करने मे जितना समय लगता है, उसी से उस वस्तु का मूल्य निश्चित होता है । मार्क्स ने इस सिद्धात को पूजीवादी व्यवस्था के लिए प्रयुक्त किया । दूसरा है मजदूरी सिद्धात--(थियरी आफ वेजेज), उसके अनुसार मजदूरी मजदूर द्वारा पैदा की हुई वस्तु से निश्चित नही होती वरन उसकी स्थिति के तत्वो के अनुसार होनी चाहिए ।

राबर्ट ओवेन -(1771-1858 ई0)

राबर्ट ओवेन, सेट साइमन और फोरियर का समकालीन था । उसका जन्म 1771 ई0 मे इग्लैण्ड के एक सम्पन्न परिवार मे हुआ था । उसे अग्रेजी कल्पनावादी समाजवाद का जनक माना जाता है। ओवन प्रारम्भ से ही श्रमिको की दयनीय दशा के प्रति सहानिभूती रखता था । इसलिए उसने अपनी पूजी श्रमिको के हितार्थ नियोजित की । ओवन का विश्वास था कि मानव की प्रगति उसकी परिस्थतियो पर आधारित होती है । यदि मनुष्य को अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध करा दी जाये, तो वह स्वयं उन्नति के शिखर पर पहुँच जायेगा । ओवन ने गरीबी को मनुष्य के विकास मे बाधक बताया । गरीबी का मूल कारण आलस्य है, इससे मनुष्य की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है और समाज गरीबी के प्रकोप का शिकार हो जाता है ।[58] ओवन का मत था कि औद्योगिक क्रान्ति द्वारा गरीबी को दूर किया जात सकता है ।[59]

समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग सन् 1807 ई0 मे राबर्ट ओवन ने ही किया था ।ओवन समाज की उस अवस्था के अन्तर्विरोध से परेशान था कि समाज मे उत्पादन के साधन उन्नति कर रहे है और पूजी मे वृद्धि हो रही है, परन्तु समाज मे मजदूरो की दशा अवनति की ओर है। ब्रिटेन

---

58 - विलियम एबन्सटीन- जी0 डी0 एच0 कोल आन ओवन इन पोलिटिकल थाट इन पर्सपेक्टिव, पृष्ठ 454, राबर्ट ओवेन- ए न्यू व्यू आफ सोसाइटी थर्ड ऐज ईवरी मैन, पृष्ठ 45

59 - वही पृष्ठ 37

मे समाजवादी विचारधारा को क्रियात्मक रुप देने वाला वह प्रथम विचारक था[60] राबर्ट ओवन एक राजनीतिक विचारक की अपेक्षा सुधारवादी अधिक था ।इगलैण्ड के औद्योगिक सस्थानो मे सुधार की योजनाए राबर्ट ने ही प्रस्तुत की थी । वह अपना उद्देश्य सामाजिक अवस्था मे परिवर्तन समझता था । उस समय इग्लैण्ड के औद्योगिक मजदूर वर्ग की दशा काफी शोचनीय थी, तथा उसने श्रमिको की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा बनाने वाले कानूनो मे विशेष सहयोग दिया । सन् 1813 तक राबर्ट एक सुधारक के रुप तक ही सीमित रहा, तथा उसी समय उसने 'समाज का नया दृष्टिकोण'(A New view of society (1813) नामक पुस्तक का सम्पादन किया । परन्तु 1817 ई0 से उसके विचारो मे कुछ उग्रता आने लगी । सबसे पहले ससद मे पेश गरीब सहायक कानून (पुअर ला) पर उसने लिखा कि-" मजदूरो की निम्न अवस्था का कारण, मशीनो द्वारा उनके परिश्रम का मूल्य घटा देना है ।[61]

ओवेन हडताल तथा क्रान्ति का पोषक होकर भी हिंसा और वर्ग सघर्ष मे कोई आस्था नहीं रखता था । वह सवैधानिक उपायो का समर्थक था । वह समाजवाद को सहयोग पर आधारित करना चाहता था । वह धृणा का विरोधी तथा प्रेम का उपासक था । वह श्रमिको को उनके परिश्रम का समुचित पारितोषिक देने के पक्ष मे था, परन्तु वह श्रमिको द्वारा हिंसात्मक कार्यवाही करने तथा राजनीति मे हस्तक्षेप का प्रबल विरोधी था । वह राज्य की अपेक्षा समाज मे परिवर्तन लाने का इच्छुक था [62] इस प्रकार ओवेन का समाजवाद कार्ल मार्क्स के समाजवाद से भिन्न था ।फिर भी मार्क्सवाद के अनेक तत्व ओवेन के समाजवाद मे छिपे थे । स्वयं मार्क्स ने भी उसे परोपकारी सुधारक की संज्ञा दी है ।

इन समाजवादियो के अतिरिक्त लुई ब्लाक (1813-1882 ई0) विलियम थामस और थामस हाग्सकिन (1787-1869 ई0) आदि समाजवादी विचारको ने भी अपने समाजवादी चिन्तन का प्रतिपादन किया । लुई ब्लाक को आधुनिक "लोकतात्रिक समाजवाद" का अग्रवर्ती,[63] और श्रमिक समाजवाद का प्रतिनिधि[64] माना जाता है ।विलियम थामस की गणना वैज्ञानिक समाजवाद के

---

60 थामस किरकप हिस्ट्री आफ सोशलिज्म, पृष्ठ 60
61 - वही ,पृष्ठ 64
62 - एम0 बीयर- ए हिस्ट्री आफ ब्रिटिश सोशलिज्म खण्ड 1, पृष्ठ 60
63 - जी0 डी0 एच0 कोल- ए हिस्ट्री आफ पोलिटिकल थाट, जिल्द 3, पृष्ठ 169
64 - अलैक्जैण्डर ग्रे दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 219

सस्थापको मे की जाती है [65] और उसे ब्रिटिश समाजवादी चिन्तन का प्रवर्तक माना जाता है ।[66] थामस हाग्सकिन की गणना मार्क्स के पूर्ववर्ती समाजवादी विचारको मे की जाती है ।[67] तथा उसके विचारो मे व्यक्तिवाद और अराजकतावाद दोनो का समिश्रण मिलता है ।[68]

सन् 1830 ई0 मे ओवेन ने तत्कालीन स्थिति का पूर्ण विश्लेषण करते हुए अपनी साम्यवादी योजना प्रस्तुत की । उसके सम्बन्ध मे उसने कहा कि वर्तमान परिस्थितियो का सामना करने का एकमात्र उपाय साम्यवाद की स्थापना है । उस योजना के प्रारुप का वर्णन करते हुए, ओवन ने यह विचार रखा कि इस योजना को पहले छोटे-छोटे समुदायो मे विभक्त करके सफल बनाया जायेगा । इसके लिए 1000 से 1500 एकड़ तक की भूमि हो तथा जनसख्या 500 से 2000 तक की होनी चाहिए । यह समुदाय सभी साधनो से परिपूर्ण होगा ।यहॉ कृषि तथा उद्योगो से होने वाली आय का सयुक्त रुप से उपयोग करेगे तथा कोई भी व्यक्ति बेकार नही रहेगा । एक समुदाय का भूमि तथ उद्योगो पर एव उत्पादन पर सयुक्त रुप से अधिकार होगा ।[69] यह योजना न्यू लेनार्क की योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई ।फ्रास के समाजवादी फूरियर ने सम्भवत उसी के आधार पर अपनी फ्लैक्स (Phalanxes)की योजना बनायी थी परन्तु ससद ने ओवेन की योजना को स्वीकार नही किया तथा सन् 1817 ई0 मे श्रमिको ने उसका विरोध किया । उसका मुख्य कारण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के ऊपर कुछ प्रतिबन्धो का सकेत उसने अपनी योजना मे किया था । श्रमिक वर्ग स्वतन्त्रता के ऊपर प्रतिबन्ध के घोर विरोधी थे । तथा दूसरा कारण धर्म को भी ओवेन ने प्रगति के मार्ग मे अवरोधक बताया था । इससे धार्मिक व्यक्ति भी ओवेन की योजना का विरोध करने लगे ।

सन् 1819 ई0 मे उसने मजदूरो के सम्मुख भाषण (अड्रेस टू द वर्कमेन) मे इस बात पर बल दिया कि श्रमिक वर्ग, शासक वर्ग के प्रति हिंसा की भावना का त्याग करे, तथा सहयोग का रास्ता अपनाये । सन् 1821 ई0 मे उसने सामाजिक पद्धति (सोशल सिस्टम) नामक पुस्तक लिखी, इसमे उसने पूर्ण साम्यवादी स्थिति स्वीकार करते हुए व्यक्तिगत सम्पत्ति का उग्र विरोध किया तथा

---

65 - मेन्जर- दि राइट टू दि होल प्रोड्यूस आफ-लेबर, उद्धृत-अलैक्जेन्डर दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 264

66 - डा0 केयल कमल - समाजवादी चिन्दन, पृष्ठ 55

67 - वही, पृष्ठ 59

68 - वही, पृष्ठ 63

69 - एच0 डब्ल्यू लैडलर सोशल इकोनामिक मूवमेन्ट, पृष्ठ 93

समाज मे समानता लाने के लिए वितरण की समुचित व्यवस्था आवश्यक है, । इस पर बल दिया । ओवेन ने पूजीवाद की सबसे बड़ी बुराई, वितरण मे असमानता की ओर सकेत किया ।

ओवेन की इस योजना को, ओवन के निर्देशन मे ही सर्वप्रथम अमेरिका मे क्रियात्मक रुप देने का प्रयास किया गया । परन्तु सन् 1827 ई0 मे उसकी यह योजना असफल सिद्ध हुई ।

मैक्सी के अनुसार- ''काल्पनिक समाजवाद का विकास ओवेन के साथ ही साथ समाप्त हो गयी''।

राबर्ट के विचारो से हम विकास का स्पष्ट क्रम देख सकते है । उसकी पुस्तक गरीबो का सरक्षण (पुअरमेन गार्जियन) (1835) मे उन विचारो का स्पष्ट उल्लेख करती है ।जिन्हे अतिरिक्त मूल्य (सरप्लस वैल्यू) के वैज्ञानिक सिद्धान्तो की स्पष्ट भूमिका कहा जा सकता है । ओवन के अनुसार सम्पूर्ण पैदावार मजदूर और किसानो के श्रम से ही होती है ।सहयोग द्वारा उत्पादन की पद्धति के प्रारम्भिक विचारो का श्रेय भी राबर्ट को ही है । जिसका आज विश्व के सभी देशो मे सर्वमान्य प्रचार है । ''सोशलिज्म' शब्द का भी सर्वप्रथम प्रयोग राबर्ट द्वारा ही स्थापित सम्पूर्ण समाजवादी राष्ट्रो की सम्पूर्ण श्रेणियो के सहयोग की सस्था (एसोसिएशन आफ आल क्लासेज आफ आल नेशन्स) के वाद-विवादो मे भी हुआ था ।[70]

राबर्ट की आरम्भिक सफलता का कारण उसके द्वारा चलाये गये सहायक आन्दोलन की जड़ मे भी धार्मिकता तथा मनुष्यता की भावना ही प्रधान थी इस आन्दोलन मे धनिक वर्ग एव सम्पन्न श्रेणियो के आत्माभिमान के भावना की पूर्ण होने की काफी सभावनाए थी इसलिए राबर्ट को इन वर्गो का काफी समर्थन मिला परन्तु जैसे ही उसने पूजीवादी व्यवस्था को सुरक्षित रखने वाले कारणो पर कठोर प्रहार किया, उसके विचारो का समाज मे विरोध होने लगा एव उसके सगठन के तत्व बिखरने लगे तथा उसका साम्यवादी आन्दोलन स्वय ही बिखर गया । राबर्ट का आन्दोलन समाप्त हो जाने पर भी श्रमिक वर्ग के अन्दर अपने अधिकारो के प्रति चेतना बढती गयी तथा क्रिश्चियन सोशलिस्ट मूवमेन्ट के रुप मे सन् 1848-52 ई0 मे एक सुधारवादी आन्दोलन हुआ इस आन्दोलन का आधार तथा उद्देश्य समाज मे नैतिकता तथा अध्यात्मिकता के क्षेत्र मे समानता स्थापित करना था । इस आन्दोलन

70 - थामस किरकप- हिस्ट्री आफ सोशलिज्म- पृष्ठ 67

ने मजदूरो मे 'सहयोग के सिद्धात' का समर्थन किया । इस आन्दोलन के नीव मे भी राबर्ट के सहयोग सिद्धान्त के विचार निहित थे ।

यद्यपि राबर्ट को अपने विचारो को क्रियात्मक रुप प्रदान करने मे सफलता नही मिली, लेकिन उसके विचारो का समाजवाद के इतिहास मे महत्वपूर्ण स्थान है राबर्ट के साथ ही आधुनिक समाजवाद की विचारधारा का इग्लैड मे उदय हुआ एव उसने प्रथम बार क्रियात्मक रुप देने का प्रयास किया परन्तु असफल रहा । लेकिन भविष्य के समाजवादी विचारको के लिए उसने एक निर्देशक तत्वो की श्रृखला जोड दी कि इन विचारो को भी क्रियात्मकरुप प्रदान किया जा सकता है ।जॉन ग्रे, जो एक समाज सुधारक थे, उन्होने उत्पादन को मजदूरी के सिद्धात के आधार पर विश्लेषित किया । जॉन फ्रासिस ने, जो कि ओवेन की शिक्षा का समर्थक था, उसने पूजीवाद की आलोचना की तथा सवाद (Synthesis) के कारणो की व्याख्या एव समाजवाद के विकास की श्रृखला मे सहयोग प्रदान किया ।[71]

6-जर्मनी के समाजवादी विचारक

19वी शताब्दी के आरम्भ मे समाजवादी विचारो का जो विकास इग्लैण्ड और फ्रास मे तीव्र गति से हुआ वह कोई स्थाई परिणाम के बिना ही 19वी शताब्दी के मध्य मे कुछ समय के लिए दब सा गया । इसके बाद इस विचारधारा का विकास जर्मनी मे बहुत तीव्र गति से हुआ क्योकि वहॉ के समाज संगठन का ढाचा परम्परावादी तथा सामन्तवादी व कुलीनतंत्री आधार पर सगठित तथा । इस विचारधारा के विकास मे पूर्व के विचारको ने काफी सहयोग दिया ।

1 जर्मनी के आदर्शवादी दर्शन मे जिसके प्रवर्तक कान्ट तथा फिक्टे थे,तथा हिगल जो उस समय के सबसे बडे आदर्शवादी समझे जाते थे, उसने राष्ट्रीय समाजवाद के तत्वो को जन्म दिया । उनके विचारो मे गिल्ड समाजवाद के तत्व भी मौजूद थे । फिक्टे ने एक नवीन आर्थिक योजना प्रस्तुत की कि राज्य को विदेशी व्यापार करना चाहिए तथा समाज सगठन व्यवसाय के आधार पर होना चाहिए ।

---

71 - इनसाइक्लोपीडिया आफ सोशल साइन्सेज, वैल्यूम 7 पृष्ठ 195

2 दूसरा कारण, मार्क्स का उद्भव वास्तव मे जोकि आधुनिक समाजवाद के जनक समझे जाते है, मार्क्स की विचारधारा की सबसे अधिक लुडविख फेवरबाख (Ludwing Feuerbach) ने अधिक प्रभावित किया।

3 आदर्शवादी विचारधारा, उस समय की व्यवस्था की प्रतिक्रिया मात्र थी, जो उस समय समाज मे मौजूद थी। यह विचारधारा पूजीवादी विचाधारा के विरुद्ध थी इसने भी जर्मन समाजवाद के विकास मे सहयोग प्रदान किया। मुख्य रुप से फ्रेन्ज वान वोडर तथा एडम मूलर ने पूजीवादी व्यवस्था के दुस्परिणाम के कारणो की ओर सकेत किया।

4 उस समय के आर्थिक अनुसधानो ने समाजवाद की विचारधारा मे महत्वपूर्ण योगदान दिया। वैज्ञानिक कारण भी, जो अपने प्राथमिक रुप मे थे परन्तु उन्हे मान्यता नही मिली थी। आर्थिक, नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणो का भी समाजवाद के विकास मे काफी योगदान रहा [72]

जर्मनी के समाजवादी इतिहास मे, कार्ल मार्क्स तथा लैस्सली एवं राडवर्ट्स के नाम विशेष रुप से उल्लेखनीय है।

कार्ल मार्क्स (मार्क्सवाद)

कार्ल मार्क्स से पूर्व का समाजवाद काल्पनिक समाजवाद कहा जाता है,क्योकि वह इतिहास के किसी दर्शन पर आधारित नही था।वेपर के अनुसार "उन्होने सुन्दर गुलाब के फूलो की कल्पना तो की परन्तु गुलाब के फूलो के लिए कोई भूमि तैयार नही की।[73]

समाजवादी विचारधारा को वैज्ञानिक स्वरुप प्रदान करने मे कार्ल मार्क्स और एग्जेल्स का काफी योगदान रहा है। मानव समाज की नवीन व्याख्या उसके द्वारा ही की गयी। लेकिन मार्क्स ने किसी नवीन विचार का प्रतिपादन नही किया बल्कि पूर्व सिद्धातो की वैज्ञानिक व्याख्या ही प्रस्तुत की ।[74]

जिन सिद्धातों की मार्क्स ने व्याख्या प्रस्तुत की उसका प्रतिपादान पूर्व मे हो चुका था। जैसे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत; टगर्ट,गाडविन,थामसन इत्यादि विचारक पहले ही कर चुके थे।

---

72 - इनसाइक्लोपीडिया आफ सोशल साइन्सेज, वैल्यूम 7, पृष्ठ 196

73 - सी0 एल0 वेपर- राजदर्शन का स्वाध्ययन, पृष्ठ 207

74 - इनसाइक्लोपीडिया आफ सोशल साइन्सेज, वैल्यूम 7, पृष्ठ 197

पूजीवाद की व्याख्या फोरियर तथा ब्लाक ने तथा वर्ग सहर्ष की व्याख्या ब्लाक, वान स्टेन, (Van Stain), थैरी (Theiry) तथा गुजाट के द्वारा की जा चुकी थी । तथा पूजीवाद की प्रतिक्रिया के रुप मे नये सर्वहारा वर्ग का उदय होगा, राडवर्ट्स द्वारा की गयी थी ।[75]

जर्मन विचारक कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक था ।[76] उसे श्रमिको का मसीहा और उसके ग्रन्थ "दास कैपिटल" को आधुनिक बाइबिल कहा जाता है । मार्क्स ने एगेल्स के साथ मिलकर समाजवाद के वैज्ञानिक सिद्धात का प्रतिपादन करके उसे आधुनिक रुप प्रदान किया ।[77]

मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद इसलिए कहा गया है कि उसने एक ऐसा आन्दोलन चलाया जिसका एक निश्चित सिद्धात था । उस समय चल रहे निराधार समाजवादी आन्दोलन को एक आधार प्रदान किया । सेट साइमन, फोरियर और ओवर ने भले ही ऐसे सत्यो को प्रकट किया था जो बाद मे मार्क्स द्वारा उपेक्षित हुए परन्तु उनके सिद्धात केवल बौधिक आधार रखते थे ।मार्क्स ने समाजवादी आन्दोलन के लिए वही कार्य किया,जो मैकियावली ने राज्य सिद्धात के लिए किया था । मार्क्स से पूर्व श्रमजीवी आन्दोलन एक विरोध तथा भावना तक सीमित था । मार्क्स के बाद उसे एक वैज्ञानिक आधार मिल गया श्रमजीवी आन्दोलन का लक्ष्य तथा उद्देश्य निश्चित हो गया, उसमे एक निश्चित सगठन उत्पन्न हो गया तथा पूजीवाद पर आक्रमण करने के लिए एक सैनिक शक्ति उसमे उत्पन्न हो गयी । समाजवाद को वैज्ञानिक रुप देना मार्क्स के सिद्धातो मे से था । उसने केवल समाजवाद को केवल वैज्ञानिक आधार ही प्रदान नही किया, वरन उसे विशाल शक्ति भी प्रदान की ।[78] वास्तव मे मार्क्स ने समाजवाद को कोलाहल से उठाकर एक सशक्त आन्दोलन का रुप दे दिया, ऐसे आन्दोलन का जो समाजवाद के सिद्धात पर आधारित है मार्क्स ने श्रमिको को, जो असगठित और बिखरे हुए थे, एक अन्तर्राष्ट्रीय सगठन के रुप मे बदल दिया ।[79] मार्क्सवादी समाजवाद मे पूर्व की समाजवादी विचारधाराओ के अनेक तत्व मौजूद होने के कारण भी उसकी वैज्ञानिक व्याख्या मार्क्स

---

75 - वही, पृष्ठ 197

76 - सी0 सी0 मैक्सी पोलिटिकल फिलासफीज, पृष्ठ 698

77 हैरी डब्ल्यू लैडलर हिस्ट्री आफ सोशलिस्ट थाट (1927), अध्याय 19, थामस किरकप-हिस्ट्री आफ साशलिज्म (1913), पृष्ठ 5,6, फ्रासिस डब्ल्यू कोकर-रीसेन्ट पोलिटिकल थाट, पृष्ठ 46

78 सी0 सी0 मैक्सी पोलिटिकल फिलासफीज, पृष्ठ 698 99

79 - लास्की-कम्यूनिज्म, पृष्ठ 32

द्वारा ही की गयी । सन् 1847 ई0 मे घोषणा की थी कि समाजवाद बुर्जुवा वर्ग का आन्दोलन है, लेकिन साम्यवाद मजदूर वर्ग का आन्दोलन है। समाजवाद को प्रारम्भ से ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था , जबकि साम्यवाद एक विरोधी विचारधारा थी, श्रमिक वर्ग उसका समर्थन क्रान्ति के आधार पर करता था । सर्वहारा वर्ग के समक्ष दो रास्ते थे या तो उस विचारधारा को तथा उसके साधनो का चुनाव करे अथवा उसका परित्याग ।

मार्क्स से पूर्व जो समाजवादी विचारधाराए थी, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से उन पर धार्मिक अथवा भौतिक प्रभाव अवश्य था । जब समाजवाद वैज्ञानिक रुप मे सामने आया तब जनता धर्म-विश्वासो से विमुख होने लगी थी, जिसने मार्क्सवादी विचारधारा के विकास मे महत्व पूर्ण योगदान दिया ।

मार्क्स से पूर्व के विचारको ने समाज के भविष्य के लिए आर्थिक सस्थओ का विचार स्पष्ट रुप से नही रखा था । मार्क्स ने इस कमी को काफी सीमा तक दूर किया ।

पूर्व की समाजवादी विचारधारा काल्पनिक तत्वो से परिपूर्ण थी एव इतिहास को विकास का परिणाम मानती थी। एगेल्स ने घोषणा की थी कि मार्क्स ने डार्विन के ''विकासवाद'' के आधार पर ही, जिस प्रकार प्रकृति का विकास होता है उसी प्रकार मानवीय इतिहास का भी विकास होता है, उस सिद्धान्त का निर्माण किया । यह विचार दो विभिन्न विचारधाराओ के समिश्रण से बना था, प्रथम विकासवादी विचारधारा तथा क्रान्तिकारी विचारधारा से । इन्ही आधारो पर उसने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की ।

इस प्रतिवादी विचारधारा का उदय अग्रेजी दर्शन के अन्दर हो चुका था। 17वी व 18वी शताब्दी मे लॉक के दर्शन मे व भौतिकवादी विचार दर्शन फ्रास की क्रान्ति (1789 ई0) मे मिल जाता है ।[80] मार्क्स ने इस सत्य को स्वीकार किया है कि वह दर्शन आदर्शवादी विचारको, कांट, फिक्टे तथा हिगल के दर्शन से प्रभावित था। स्पेगलर का विचार है कि पेरुसियन की विचारधारा ने मार्क्स को काफी प्रभावित किया । लेविस 'चेतना के विचार' ने मार्क्सवाद को एक नई शक्ति प्रदान की। जैसे-वाकूनिन और सोम्बार्ट ने भी मार्क्स को प्रभावित किया । सन् 1848 ई0 मे साम्यवादी

---

80 - इनसाइक्लोपीडिया आफ सोशल साइन्सेज, वैल्यूम 7, पृष्ठ 198

घोषणा पत्र का प्रकाशन हुआ । यह पुस्तक मार्क्स तथा एगेल्स की सयुक्त कृति है । इस पुस्तक मे मार्क्स के सभी सिद्धातो का समावेश है । यह एक प्रकार से उसकी विचारधारा का सग्रह है तथा साम्यवाद का आधार मानी जाती है । सन् 1860 ई0 मे मार्क्स की पुस्तक "दास कैपिटल" प्रकाशित हुई ।यह पुस्तक आर्थिक व्यवस्था के सिद्धातो तथा नीतियो का विश्लेषित सग्रह है । इस पुस्तक मे पूजीवादी व्यवस्था का बड़ा गंभीर विश्लेषण किया गया है । इसके बाद के दो भागो को एगिल्स ने पूर्ण किया ।[81]

कार्ल मार्क्स ने अपनी विचारधारा को स्वय वैज्ञानिक समाजवाद की सज्ञा दी थी। यह विचार पूर्ववर्ती समाजवादी विचारको से स्वय मार्क्स को पृथक करती है। उसने अपने मत को स्वय वैज्ञानिक इसलिए कहा है कि उसने एक वैज्ञानिक के समान समाज के स्वरुप एव विकास के नियमो की खोज करने का प्रयास किया है ।

कार्ल मार्क्स अपने समाजवादी विचारो मे हिगल, फ्रासीसी व ब्रिटिश समाजवादियो के विचारो से काफी प्रभावित था ।[82] इसलिए उसके विचारो को एकदम मौलिक नही कहा जा सकता तथापि उसके द्वारा समाजवाद को एक दर्शन मिला और एक नयी दिशा मिली ।[83]

मार्क्सवादी चिन्तन बडा विस्तृत और क्रमबद्ध है । कार्ल मार्क्स के क्रान्तिकारी कदम वर्ग-सघर्ष के सिद्धात पर है वर्ग सघर्ष अतिरिक्त मूल्य के सिद्धात पर,अतिरिक्त मूल्य का सिद्धात इतिहास पर तथा द्वन्दात्मक भौतिकवाद आध्यात्मिक विद्या पर आधारित है ।[84]

इस प्रकार मार्क्सवादी चिन्तन के चार प्रमुख तत्व है।

1 द्वन्दात्मक भौतिकवाद ।

2 इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या ।

3 वर्ग सघर्ष का सिद्धात ।

4 अतिरिक्त मूल्य का सिद्धात ।

इन तत्वो की सक्षिप्त व्याख्या निम्नवत् है ।

---

81 हेनरी, वी0 माया-इन्ट्रोडक्शन टु मार्क्स सिस्ट थियोरी, पृष्ठ 22

\- सेबाइन- राजनीतिक दर्शन का इतिहास, पृष्ठ 703

83 - अलैक्जेण्डर ग्रे- दि सोशलिस्ट ट्रेडिशन, पृष्ठ 295

84 - लास्की कम्यूनिज्म, पृष्ठ 103, मैक्सी-पोलिटिकल फिलासफीज, पृष्ठ 672

द्वन्दात्मक भौतिकवाद

द्वन्दात्मक भौतिकवाद मार्क्सवादी चिन्तन की आधार शिला है । कार्ल मार्क्स ने हीगल के द्वन्दवादी सिद्धात को ग्रहण किया था । हीगल का मत था कि मानव का सामाजिक विकास अबाध गति से होता रहता है, और इस विकास के साथ ही साथ मनुष्य मे निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। इस विकास प्रक्रिया को ही हीगल द्वन्दवाद की सज्ञा देता है ।हीगल का विश्वास है कि वाह्य विश्व आन्तरिक विचारो का ही प्रतिरुप होता है । हीगल की द्वन्दात्मक प्रणाली भाव प्रणाली कही जाती है । मार्क्स ने हीगल के द्वन्दवाद को स्वीकार तो किया, परन्तु उसको उसने अपनी इच्छानुसार संशोधित कर लिया । मार्क्स ने स्वय ही दास कैपिटल मे लिखा है-

"मैने हीगल के द्वन्दवाद को सिर के बल खडा पाया,इसलिए मैने उसे सीधाकर पैरो के बल खडा कर दिया ।[85]

मार्क्स ने हीगल को कल्पनावादी बताकर उसके द्वन्दवाद के भाव पक्ष को त्याग कर भौतिक पक्ष को स्वीकार कर लिया । उसने यह स्पष्ट किया कि "वाह्य विश्व का प्रभाव ही आन्तरिक विचारो का निर्माण करता है । मार्क्स ने बताया कि विचार तथा विचार-वस्तु का अटूट सम्बन्ध होता है, और उन दोनो को पृथक नही किया जा सकता । विचार या चेतना शक्ति का प्रादुर्भाव मस्तिष्क मे होता है, जो भौतिक तत्वो की सर्वोच्च कृति है । भैतिक तत्व मस्तिष्क के द्वारा उत्पन्न नही होते है और आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन सम्भव नही है ।इसलिए मनुष्य के लिए उसका कोई अस्तित्व नही है । मार्क्स पृथ्वी, वृक्ष,पर्वत तथा शरीर आदि को सत्य मानता था और आत्मा को असत्य तथा अनिश्चित कहता था । उसकी मान्यता थी कि आत्मा पर आधारित दर्शन कभी भी स्पष्ट और सत्य नही हो सकता, अपितु भौतिक वस्तुओ पर आधारित दर्शन ही सत्य और स्पष्ट होता है ।[86] इस प्रकार मार्क्स का द्वन्दात्मक सिद्धात भौतिकवाद पर आधारित है ।उसके अनुसार भौतिक वस्तु सदैव परिवर्तन शील होती है । और उसमे स्थिरता का अभाव होता है । इस परिवर्तन की प्रक्रिया मे कुछ तत्व नष्ट होते रहते है और कुछ का विकास होता रहता है । विकास प्राकृतिक पदार्थो मे एक अभयतारिक विरोध रहता है, जो कि भौतिक जगत के विकास का मूलाधार है ।

---

85 - कार्ल मार्क्स-पूजी, खण्ड 1, पृष्ठ 28

86 - वी0 अफ्नास्येव मार्क्सवादीदर्शन, पृष्ठ 18

मार्क्स का मत है कि भौतिक जगत का विकास क्रमबद्ध न होकर भी अबाध गति से निरन्तर होता रहता है। इस विकास प्रक्रिया मे वाद, प्रतिवाद तथा सवाद का क्रम निरन्तर जारी रहता है। इनमे से प्रत्येक अपने पूर्वगामी का विरोधी होता है। मार्क्स सम्पत्ति का उदाहरण देकर स्पष्ट करता है कि सम्पत्ति के जन्म के साथ ही सर्वहारा वर्ग की उत्पत्ति होती है। पूजीवादी वर्ग और सर्वहारा वर्ग मे सघर्ष चलता है। अन्त मे क्रान्ति द्वारा सामूहिक स्वामित्व की स्थापना हो जाती है।इस प्रक्रिया मे पूजीवादी वर्ग वाद, सर्वहारा वर्ग प्रतिवाद और सामूहिक स्वामित्व सम्वाद होता है।[87] इस प्रकार मार्क्स अपने द्वन्दवाद द्वारा वर्ग सघर्ष को अनिवार्य बना देता है। सेबाइन ने लिखा हे कि- "मार्क्स की अधिक रुचि इस बात मे थी कि वह द्वन्दात्मक प्रणाली को ठोस परिस्थितियो मे लागू करे, विशेषकर इस उद्देश्य से कि उसके आधार पर क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्ग के लिए किसी कार्यक्रम की खोज की जा सके।सन् 1848 मे एगेल्स और उसके साम्यवादी घोषणा पत्र, जो समस्त युगो की एक बडी क्रान्तिकारी पुस्तक बन गयी है, मे वर्ग सघर्ष को अब तक के समस्त समाजो का मूलमत्र माना है।[88]

इस प्रकार मार्क्स के अनुसार द्वन्दवादी भौतिकवाद का वाद, प्रतिवाद तथा सम्वाद विचार न होकर आर्थिक वर्ग है। मार्क्स के द्वन्दवाद का अन्तिम लक्ष्य वर्गविहीन तथा शोषण विहीन समाज की स्थापना करना है।यह अन्तिम लक्ष्य सवाद है। जिसमे से प्रतिवाद का जन्म नही होगा। वर्गविहीन समाज की स्थापना के साथ ही वर्ग सघर्ष की द्वन्दवादी प्रक्रिया भी रुक जायेगी।

ऐतिहासिक भौतिकवाद-

मार्क्सवादी चिन्तन का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद है। मार्क्स ने अपने द्वन्दवादी भौतिकवाद के औचित्य को सिद्ध करने के लिए इतिहास की नवीन रुप मे व्याख्या की है। वेपर ने उसके सिद्धात को "इतिहास की आर्थिक व्याख्या" का नाम दिया है।[89] मार्क्स की मान्यता है कि भौतिक पदार्थ, जो इतिहास के विकास मे निर्णायक तत्व है, वास्तव मे उत्पादन शक्ति है। अत मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद आर्थिक नियतिवाद है, अर्थात् मनुष्य जो भी कुछ करता

---

[87] - मार्क्स व एगेल्स- सकलित रचनाए, भाग 3, पृष्ठ 53

[88] - सेबाइन राजनीतिक दर्शन का इतिहास, पृष्ठ 713

[89] - कोल- हिस्ट्री आफ सोशलिस्ट थाट, पृष्ठ 18

है, उसका निर्माण आर्थिक या भौतिक कार्यो द्वारा होता है, क्योकि मनुष्य पूरी तरह से आर्थिक शक्तियो का दास है ।[90] मार्क्स के द्वन्दवादी भौतिकवाद के अनुसार इतिहास का प्रत्येक युग वर्ग सघर्ष का इतिहास है ।[91] मार्क्स ने इतिहास के युगो का विभाजन इस प्रकार किया है ।-

1 आदि मानव युग

2 दास युग

3 ामन्तवादी युग

4 ूजीवादी युग

5 मामाजवादी युग

6 ाम्यवादी युग

वर्ग संघष

ाार्क्स की वर्ग सघर्ष की धारणा समकालीन इग्लैण्ड की परिस्थितियो पर आधारित है ।उस समय इ ाण्ड के उत्पादन मे भारी वृद्धि हो रही थी, पूजीपति वर्ग दिन प्रतिदिन धनी हो रहा था तथा श्रमिक व । की निर्धनता निरन्तर बढती जा रही थी । मार्क्स ने पूजीपति के शोषण तथा श्रमिक वर्ग के कष्टो को ेखकर एक कल्पना के आधार पर वर्ग सघर्ष की धारणा बनायी और कल्पना के आधार पर पूजीवादी व्यवस्था के विनास तथा समाजवाद की स्थापना का स्वप्न देखा ।[92]

वर्ग सघर्ष के सिद्धात की विस्तृत व्याख्या साम्यवादी पार्टी के घोषणा पत्र मे की गयी है । स घोषणा पत्र मे मार्क्स ने लिखा है कि सम्पूर्ण समाज का इतिहास वर्ग सघर्षो का इतिहास है ।[93] म र्क्स के पूर्ववर्ती टामस मूर, सेट साइमन, फोरियर, राबर्ट ओवन आदि सभी समाजवादी विचारको ने भी यह स्वीकार किया है कि समाज मे दो वर्ग पूजिपति व श्रमिक है ।तथा पूजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करके वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करता है फलस्वरुप दोनो वर्गो मे सघर्ष चलता रहता है । लेकिन ये विचारक इस सघर्ष का कारण बताने मे असफल रहे । इस कार्य को कार्ल मार्क्स ने कर दिखाया उसने स्पष्ट किया कि इन दोनो वर्गो के मध्य सघर्ष का मूल कारण भौतिक

---

90 - फेथ चेजिग फेस ऑफ कम्यूनिज्म, पृष्ठ 26

91 र्स व एगल्सि सकलित रचनाए, भाग 3 पृष्ठ 354

92 -) डी0 एच0 कोल हिस्ट्री आफ सोशलिस्ट थाट, पृष्ठ 20

93 - र्क्स व एगेल्स-कम्यूनिस्ट घोषणा पत्र, पृष्ठ 80

उत्पादन है ।मार्क्स ने कहा कि पूजीपति वर्ग उत्पादन के लाभ से श्रमिको को वचित करके उनका शोषण करता है और श्रमिक अपनी श्रम शक्ति को पूँजीपति के हाथो बेचने के लिए विवश है ।[94] अत. दोनो वर्गो मे सघर्ष अनिवार्य है, और यह निरंतर सघर्ष पूजीवादी समाज की प्रकृति है । इस स्थिति मे सर्वहारा वर्ग को पूजीवादी व्यवस्था का अन्त करके एक वर्ग विहीन समाज का निर्माण करना पड़ेगा और एक सशस्त्र क्रान्ति के द्वारा ही सम्भव हो सकेगा ।

मार्क्स की धारणा है कि पूजीवाद ने स्वय ही अपनी कब्र खोद रखी है, उसी कब्र मे वह एक दिन जीवित दफन हो जायेगा और वर्ग सघर्ष उसकी मृत्यु का प्रतीक बनेगा ।[95] अशोक मेहता ,[96] नरेन्द्रदेव[97] और आचार्य कृपलानी[98] ने मार्क्स के सघर्ष की मूलभूत मान्यताओ पर प्रकाश डाला है । मार्क्स का विचार है कि प्रत्येक युग मे अर्थोपार्जन के कोई न कोई प्रमुख साधन होते है और जिस वर्ग का उन साधनो पर आधिपत्य होता है वही वर्ग समाज मे शक्तिशाली वर्ग होता है और उसी के हाथो मे राजनैतिक शक्ति होती है । तथा दूसरे साधनहीन वर्ग उसके अधीन होते है । प्राचीन काल मे स्वामी और दास, मध्यकाल मे सामन्त और कृषक तथा आधुनिक युग मे पूजीपति औ सर्वहारा दो विरोधी वर्ग रहे निरत है । मार्क्स वर्ग सघर्ष को समाज परिवर्तन का साधन मानता है ।[99]

मार्क्स का मत है कि वर्गो के स्वरुप मे काल के अनुसार चाहे परिवर्तन होता रहे लेकिन समाज मे सदैव दो वर्ग मौजूद रहे हैं ।एक वर्ग साधनो का स्वामी तथा दूसरा साधनहीन सर्वहारा ।[100] एक शोषक वर्ग होता है तथा दूसरा शोषित वर्ग, दोनो सदैव एक दूसरे के विरोध मे खडे होकर कभी प्रत्यक्ष तथा कभी परोक्ष रुप से सघर्ष करते रहते हैं ।

कार्ल मार्क्स ने वर्ग सघर्ष के परिणाम स्वरुप सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व तथा वर्गहीन समाज की कल्पना की थी ।लेकिन मार्क्स की इस कल्पना से उसके द्वन्दात्मक सिद्धात का साम्य

---

94 - मार्क्स व एगेल्स-सकलित रचनाए, भाग 4, पृष्ठ 91
95 - हेराल्ड जे0 लास्की-कम्यूनिस्ट मेनीफेस्टो, सोशलिस्ट लैण्डमार्क, पृष्ठ 111
96 - अशोक मेहता-स्टडीज इन सोशलिज्म, पृष्ठ 120
97 - नरेन्द्र देव - राष्ट्रीयता और समाजवाद
98 - जे0 बी0 कृपलानी-वर्ग सघर्ष, पृष्ठ 2-3
99 - एव0 डब्ल्यू लैडलर-सोशल इकोनामिक मूवमेट, पृष्ठ 162-163
100 - कार्ल मार्क्स-कम्यूनिस्ट घोषणा पत्र पृष्ठ 33-34

किस प्रकार किया जाय । मार्क्स ने द्वन्दात्मक तत्व की कल्पना की, दूसरी ओर वर्गहीन समाज का आदर्श प्रस्तुत किया । इन दोनो सिद्धांत मे विरोधाभाष है ।[101]

अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत [102]

मार्क्स के मूल्य का सिद्धात रिकार्डो के मूल्य के सिद्धांत से प्रभावित है । मार्क्स ने पूजीवाद के विकास और सामाजिक परिणामो की व्याख्या की है, इसमे उसकी मुख्य बात उसका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धात है जिसे उसने श्रम सिद्धात के आधार पर स्थिर किया है । अपनी पुस्तक "दास कैपिटल" मे मार्क्स ने लिखा है कि किसी तैयार माल का विनिमय मूल्य या बाजार मे प्राप्त होने वाला मूल्य वह श्रम है जो उस वस्तु के तैयार करने मे और विक्री योग्य बनाने मे लगाया जाता है अर्थात् पूंजीपति ऐसी वस्तु तैयार करवाता है जिसकी कीमत बेचने पर उस व्यय से अधिक होती है जो उसने कारखाने को चलाने, रखने और श्रमिको को उनका पारिश्रमिक देने मे किया होता है अर्थात् ,"उत्पादित वस्तु के विनिमय- अर्थ और श्रमिक को दिये जाने वाले श्रम के मूल्य का यह अन्तर ही अतिरिक्त अर्थ कहा जाता है ।" अतिरिक्त अर्थ का जन्म श्रमिक के परिश्रम के बाद होता है । लेकिन इसे पूँजिपति जो उसे काम पर लगाता है, स्वय हड़प लेता है, वस्तुत: अतिरिक्त मूल्य वह श्रम है जिसका पूँजिपति कोई मूल्य नही देता है ।[103] वास्तव मे यह अतिरिक्त मूल्य श्रमिकों को मिलना चाहिए किन्तु पूँजीपति श्रमिकों की निर्धनता का लाभ उठाकर इस अतिरिक्त मूल्य को लेकर दिन प्रतिदिन पूँजीपति होता जाता है । और श्रमिको को पेटभर भोजन नही मिलता है, उसी कारण पूँजिपति वर्ग और श्रमिक के मध्य घृणा की भावना बढती जाती है और वर्ग सघर्ष निरतर जारी रहता है ।[104] इस सिद्धात के अनुसार मार्क्स पूँजिपतियो द्वारा श्रमिको के शोषण के औचित्य को सिद्ध करता है ।[105]

---

101 - सी0 ई0 एम0 जोड- मार्डन पोलिटिकल थ्योरी, पृष्ठ 44

102 - इस सिद्धात का प्रतिपादन सर्वप्रथम 17वी शताब्दी मे अग्रेज विचारक विलियम पेरी ने किया था, बाद मे एड्म स्मिथ, और डेविड रकार्डो ने इसमे सशोधन किये, अलैक्जेण्डर ग्रे-दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 309

103 - सी0 ई0 एम0 जोड़- आधुनिक राजनीतिक सिद्धात प्रवेशिका (अम्बादत्त पन्त), पृष्ठ 37

104 - कोकर- आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृष्ठ 50, वेपर -राजदर्शन का इतिहास, पृष्ठ 214

105 - कार्ल मार्क्स -पूजी, खण्ड, 1 पृष्ठ 238

इस प्रकार स्पष्ट है कि मार्क्स से पूर्व कल्पनावादी विचारको ने जिस समाजवादी चिन्तन का प्रारम्भ किया था वह अपनी शिथिलता के कारण असफल हो गया, परन्तु मार्क्स ने अपने भाषणो लेखो और वैज्ञानिक सिद्धातो द्वारा समाजवादी चिन्तन को एक नया जीवन प्रदान कर दिया ।उसने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र के प्रकाशन, सम्मेलनो तथा सभाओ के आयोजनो द्वारा श्रमिको मे एक नये उत्साह और एक असीम उत्तेजना का संचार कर दिया । इसके बाद समाजवादी दर्शन निरन्तर विकासमान होता गया ।

ब्लादिमीर इलियच लेनिन (1870-1924 ई0)

मार्क्स के बाद समाजवादी चिन्तन के विकास मे लेनिन का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । लेनिन की महत्ता इस बात मे निहित है कि उसने रुस के सन्दर्भ मे मार्क्स के विचारो की व्याख्या की तथा उन्हे रुस की परिस्थितियो के अनुरुप बनाया ।[106] स्टालिन ने लिखा है कि "लेनिन ने मार्क्सवाद को आधुनिक रुप प्रदान किया । उसने मार्क्स के पूजीवादी समाज के विकास को अवलोकित करके और उन प्रवृत्तियो को ध्यान मे रखते हुए, जिनका मार्क्स ने केवल प्रारम्भ ही देखा था । उसकी नीति और सिद्धांत का पुर्नस्थापना किया ।[107] 19वी शताब्दी के उत्तरार्द्ध मे रुस मे सिद्धातो के बीच यह विवाद का विषय था कि रुस मे पूँजीवादी व्यवस्था है या नही वहाँ के कई विचारको के अनुसार पूजीवादी व्यवस्था रुस के हितो के अनुरुप नही थी ।लेनिन ने अपनी पुस्तक "दि डेवलपमेन्ट आफ कैपिटलिज्म" मे रुस की इस व्यवसथा का विश्लेषण किया और पूँजीवादी व्यवस्था की परिभाषा करते हुए लिखा है कि "यह वह व्यवस्था है जिसमे न केवल उत्पादित वस्तुओ का क्रय -विक्रय किया जाता है,वरन मानव श्रम भी क्रय-विक्रय की वस्तु बन जाती है"।उस रुस मे भी मानवश्रम का क्रय-विक्रय किया। जा रहा था, इसी दृष्टि से उस समय रुस भी एक पूजीवादी देश था ।[108]

किसी भी देश की वास्तविक परिस्थितियो के सन्दर्भ मे लेनिन ने मार्क्स के विचारो के परीक्षण का पहला प्रयास किया और रुस मे एक अस्थिर पूँजीवादी शासन होते हुए भी उसने वहाँ

---

106 - स्टालिन-फाउन्डेशन आफ लेनिनिज्म, पृष्ठ 3

107 - नील हार्डिग-लेनिन के राजनीतिक विचार, पृष्ठ 98

108 - नील हर्डिग- लेनिन के राजनीतिक विचार, पृष्ठ 81

पर समाजवादी क्रान्ति को सफल बनाया।[109] इतना ही नही लेनिन ने एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के पिछड़े हुए देशो के लिए भी मार्क्सवाद की स्थापना का पथ -प्रशस्त कर दिया और उन्हे सर्वहारा क्रान्ति करने की एक सशक्त प्रेरणा प्रदान की।[110]

20वी शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो मे एडवर्ड बर्नस्टाइन जैसे सशोधनवादियो ने इस प्रश्न को उठाया कि मार्क्स की भविष्यवाणियाँ सत्य सिद्ध नही हुई, अत· मार्क्स के विचारो मे सशोधन की आवश्यकता है। सशोधनवादियो के मतानुसार मार्क्स ने ये भविष्यवाणी की थी कि पूजीवाद का निकट अन्त था लेकिन वास्तव मे पूंजीवाद के अन्त होने के कोई लक्षण नही थे। लेनिन ने सशोधनवादियो के इस विचार को स्वीकार नही किया।लेनिन के अनुसार पूजीवाद का अन्त अवश्य होगा। और मार्क्स की भविष्यवाणी सिद्ध होगी। लेनिन के अनुसार पूँजीवाद के विकास की वर्तमान अवस्था साम्राज्यवाद की अवस्था है। यह पूँजीवाद की सबसे विकसित अवस्था है। इसके बाद पूँजीवाद का विनाश होगा।[111] इस प्रकार लेनिन ने मार्क्स के सिद्धातो मे पूरी आस्था प्रकट की,तथापि उसने मार्क्सवादी चिन्तन मे उसने सशोधन अवश्य किये।[112] लेनिन ने सशोधन वादियो द्वारा दबाये गये मार्क्स के सिद्धांतो का पुनरुद्धार किया।[113] इस अर्थ मे लेनिनवाद मार्क्स के मार्क्सवाद का विस्तार है ।[114] इस प्रसग मे स्टालिन का महत्वपूर्ण वाक्य उद्धृत किया जा सकता है कि "लेनिनवाद साम्राज्यवाद और श्रमिक क्रान्ति के युग का मार्क्सवाद है।[115]

मार्क्सवाद के विकास मे लेनिन का विशिष्ट अनुदार दल सम्बन्धी सिद्धात है[116] अपनी पुस्तक "राज्य व क्रान्ति" में लेनिन ने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के रुप मे विशद रुप से विचार किया है।मार्क्स के विचारो मे इतने विस्तार से विचार नही मिलते हैं। कार्ल मार्क्स ने श्रमिकों मे वर्ग चेतना के निर्माण पर अधिक जोर दिया तो लेनिन ने दलीय सगठन को, उसका विचार था कि

109 - हिस्ट्री आफ कम्युनिस्ट पार्टी आफ द सोवियत यूनियन, पृष्ठ 209 कोकर-रीसेन्ट पोलिटिकल थाट, पृष्ठ 195

110 - वही पृष्ठ, 216

111 - लेनिन-इम्पीरियलिज्म, द हाइयेस्ट स्टेज आफ कैपिटलिज्म, पृष्ठ 241

112 - सेबाइन- ए हिस्ट्री आफ पोलिटिकल थ्योरी, पृष्ठ 748

113 - लेनिन- सकलित रचनाए, भाग 3, पृष्ठ 135

114 - अलैक्जेण्डर ग्रे- दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 460

115 - स्टालिन- फाउण्डेशन आफ लेनिनिज्म, पृष्ठ 14

116 - डेविड मैकलेनन-मार्कसिज्म आफटर मार्क्स, पृष्ठ 87-90, नील हार्डिग-लेनिन के राजनीतिक विचार, पृष्ठ 138-158

कोई भी क्रान्ति एक सुदृढ और सगठित दल सेना के बिना सभव नही । लेनिन पार्टी की सदस्यता सीमित रखने के पक्ष मे था उसके अनुसार श्रमिक वर्ग के सभी सदस्यो मे इसकी क्षमता नही होती है कि वह वर्ग चेतना का पूर्ण विकास कर सके, अत दल के नेतृत्व का यह कर्त्तव्य है कि वह वर्ग चेतना के विकास मे सहायक हो । उसका यह विश्वास था कि श्रमिक वर्ग मे दल के नेतृत्व द्वारा वर्ग चेतना का विकास किया जा सकता है। मार्क्स ने साम्यवादी आन्दोलन को श्रमिक वर्ग के लिए छोड़ दिया था । लेकिन लेनिन ने ऐसे दल के निर्माण पर जोर दिया जिसका सैनिक अनुशासन हो, एव जो सर्वहारा वर्ग का केवल क्रान्ति के दिनो मे ही वे नेतृत्व न करे बल्कि इसके उपरान्त भी श्रमिक सरकार बनाकर क्रान्ति के शत्रुओ का सफाया कर दे । इस प्रकार लेनिन ने दल सम्बन्धी सिद्धांत को लेकर मार्क्सवाद मे सुधार किया ।[117]

लेनिन के अनुसार क्रान्ति का अर्थ[118] केवल शक्ति का एक वर्ग से दूसरे वर्ग को स्थानान्तरण नही है, बल्कि शक्ति का एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का रास्त है क्योकि इसमे श्रमिक अपना शासन स्वय चलाते है । लियो ट्रॉट्स्की के अनुसार एक हाथ से दूसरे हाथ मे शक्ति के जाने का मतलब यह नही है कि एक नयी शक्ति बन जाती है, बल्कि इस शक्ति के प्रयोग करने का अधिकार उस व्यकित को दे दिया जाता है जो श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है न कि श्रमिक को दिया जाता है ।सन् 1917 ई0 मे रुसी क्रान्ति का ट्रॉट्स्की एव लेनिन ने नेतृत्व किया और साम्यवादी दर्शन को व्यावहारिक दृष्टि से पूर्ण बनाने का प्रयास किया । लेनिन ने मार्क्स के सपनो के अनुसार समाज स्थापित करने के लिए क्रान्ति को अत्यन्त आवश्यक बताया । लेनिन ने उन परिस्थितियो का पुन स्पष्टीकरण दिया जिनके आधार पर किसी भी देश मे क्रान्ति हो सकती थी, उसके अनुसार समाजवादी क्रान्ति के लिए आवश्यक है-

1 देश मे दृढ़ विचार वाले क्रान्ति की भावना से सम्पन्न लोग हो, जो अपने ध्येय के प्रति सचेत रहे ।

2 इन क्रान्तिकारियो को अधिकांश मजदूर वर्ग की पूर्ण सहायता एवं समर्थन प्राप्त होना चाहिए।

---

117 - डेविड मैकलेनन मार्क सिज्म , आफ्टर मार्क्स पृष्ठ 86-97

118 - नील हार्डिग- लेनिन के राजनीतिक विचार, पृष्ठ 21-95

3 क्रान्ति का विगुल उस समय बजाया जाना चाहिए जब पूजीवादी व्यवस्था कमजोर हो तथा परस्पर सघर्ष मे व्यस्त रहे ।

इस प्रकार लेनिन ने मार्क्स के प्रारम्भिक कृतियो मे पाये जाने वाले उग्र क्रान्तिकारी विचारो का पुनरुद्धार किया । यह कथन कि,"साम्राज्यवाद पूँजीवाद की अन्तिम अवस्था है " लेनिन की ऐतिहासिक उक्ति हो गयी । सम्भवत यह मार्क्सवाद को उसकी महती देन है ।

वास्तव मे लेनिन का स्थान एक विचारक और कर्मठ व्यक्ति के रुप मे इतिहास मे सुरक्षित है । आधुनिक साम्यवादी सिद्धात और व्यवहार दोनो ही उसका ऋणी है । उसने मार्क्सवाद को धरातल पर उतारा, इसको जीवन और स्फूर्ति प्रदान की । उसकी शक्ति एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने मे निहित थी और इसे प्राप्त करने के लिए वह कठोर उग्र एव कठिबद्ध था ।[119] उसके सहयोगी ट्राटस्की ने उसे बहुत बडा अन्तर्राष्ट्रीयवादी माना है । उसके अनुसार लेनिन का अन्तर्राष्ट्रवाद ऐतिहासिक घटनाओ का व्यवहारिक मूल्याकन है तथा यह अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्यो हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहारिक क्रियान्वित भी है । रुस और उसका भाग्य इस ऐतिहासिक सघर्ष मे केवल एक तत्व है और इसकी उपलब्धि पर ही समस्त मानवता का भाग्य निर्भर करता है ।[120]

लेनिन ने निम्नलिखित सुधार मार्क्स के सिद्धातो मे किये-

1 मार्क्स के अनुसार पूँजीवाद की चरम अवस्था के बाद ही साम्यवादी क्रान्ति सम्भव है लेकिन लेनिन ने उसे क्रान्ति के लिए आवश्यक नही समझता था ।उसका प्रत्यक्ष प्रमाण रुस है, जो औद्योगिक दृष्टि से अविकसित देश था, मे साम्यवादी क्रान्ति सम्पन्न हुई।

2 मार्क्स की आर्थिक नियतिवाद (इकोनामिक डिटरमिनिज) के अनुसार पूँजीवाद आन्तरिक विरोधो के माध्यम से पतन की ओर अग्रसर होगा यह पतन स्वाभाविक है, इसके लिए प्रयास किया जाय या न किया जाय । मार्क्स के ठीक विपरीत लेनिन का विचार है कि क्रान्ति आर्थिक घटनाओ के माध्यम से स्वत· नही आयेगी। उसके लिए प्रयास करना आवश्यक है।

3 मार्क्स की घोषणा के अनुसार साम्यवादी क्रान्ति के बाद उत्पादन के साधनो-भूमि तथा उद्योग पर राज्य का स्वामित्व होगा, लेकिन लेनिन ने क्रान्ति के बाद भूमि पर राज्य का स्वामित्व स्थापित

119 - अलैक्जेण्डर ग्रे- दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 458

120 - ट्राटस्की, लेनिन- दि पोलिटिकल थाट इन पर्सपेक्टिव बाइ बर्नस्टीन, पृष्ठ 563

नही किया ।इससे क्रान्ति की भावनाओ के प्रति अविश्वास होना स्वाभाविक था । लेकिन देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कुछ बातो मे पूँजीवादी व्यवस्था से समझौता करने के लिए नवीन आर्थिक नीति (न्यू इकोनामिक पालिसी) को अपनाया ।

4 मार्क्स क्रान्ति के बाद सक्रमण काल तक सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता को आवश्यक मानता था ।उसके बाद शासन का ढाचा लोकतत्र के स्वरुप को लिए हुए होगा । लेकिन लेनिन उसे अधिनायकता के विरुद्ध शक्ति पर आधारित मानता है ।

) क्रान्ति की सफलता तथा नेतृत्व सर्वहारा वर्ग करेगा । परन्तु लेनिन ने विचार व्यक्त किया कि श्रमिक वर्ग की प्रवृत्ति श्रमिक सधवाद के माध्यम से अपने अधिकारो तथा आर्थिक कठिनाइयो को दूर करने की होती है ।ऐसी अवस्था मे सर्वहारा वर्ग मे विरोध की भावना कुछ कमजोर पड जाती है। लेनिन ने क्रान्ति की सफलता के लिए पेशेवर क्रान्तिकारी सगठन का निर्माण किया ।

ओसेफ वी0 स्टालिन (1879-1953 ई0)

स्टालिन ने लेनिनवाद मे कुछ सशोधन करके मार्क्सवादी चिन्तन के विकास मे एक नई कडी जोड दी। उसने "एक देशीय समाजवाद" का सिद्धात प्रतिपादित किया और कहा कि समाजवाद की स्थापना एक ही देश मे सम्भव है ।इस सिद्धात के बल पर स्टालिन रुस का एक निरकुश तानाशाह बन गया और उसने रुस को एक सर्वाधिकार पूर्ण राज्य के रुप मे परिभाषित कर दिया । स्टालिन का दूसरा सिद्धात क्रान्ति सम्बन्धी था, वह देशीय समाजवाद का पोषक होकर भी विश्व क्रान्ति की धाराण मे गहरी आस्था रखता था ।[121] वह मार्क्स के अनुसार ही क्रान्ति द्वारा समाजवाद लाना चाहता था, परन्तु वह लेनिनवाद के विरुद्ध पूँजीवादी देशो से घिरे देशो मे शान्ति पूर्ण ढग से समाजवाद लाने के पक्ष मे था।

माओ-त्से-तुंग (माओ जेदोग) (1893-1976 ई0)

रुस की साम्यवादी क्रान्ति की सफलता रो प्रेरित होकर माओत्सेतुग ने 1 अक्टूबर 1949 ई0 को चीन मे साम्यवादी चीनी गणराज्य की स्थापना की। माओ ने चीन की परिस्थितियो के अनुसार मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतो मे सशोधन किया ।मार्क्स के समान माओ भी क्रान्ति पर

---

[121] - वेपर-पोलिटिकल थाट- पृष्ठ 231

विशेष बल देता था।वह किसानो द्वारा सशस्त्र क्रान्ति कराकर साम्यवाद की स्थापना करने का इच्छुक था और चीन मे उसने कृषक क्रान्ति को ही सफल बनाया था।[122] माओ का मत था कि क्रान्ति का नेतृत्व श्रमिको के हाथो मे न होकर कृषक वर्ग के हाथ मे होना चाहिए।[123] इस प्रकार माओ ने मार्क्सवाद के विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दिया।

7-समाजवाद के अन्य रुप-

20वी शताब्दी मे समाजवादी विचारधारा अपने कई रुपो मे विकसित हुई।यद्यपि उन समाजवादी विचारधाराओ को हम दो भागो मे विभक्त कर सकते है।

1. **मार्क्सवादी समाजवाद -**

मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा सबसे अधिक रुस मे विकसित हुआ। रुस मे लेनिन तथा स्टालिन ने, मार्क्सवादी विचारधारा मे कुछ सशोधन करके उसे रुस की परिस्थितियो के अनुसार कार्य रुप मे परिणित किया।चीन मे इसका विकास माओत्सेतुग के नेतृत्व मे हुआ लैटिन अमेरिकन देशो मे इसका विकास लियो ट्राट्स्की के नेतृत्व मे हुआ। पाश्चात्य देशो मे नव मार्क्सवाद का भी विकास हुआ है।इसके नेताओ मे जॉज ल्यूकाच, एटोनियो ग्राम्सी फ्रांज फैनन आदि विचारक हैं।

2 **प्रजातान्त्रिक समाजवाद**

दूसरी विचारधारा प्रजातान्त्रिक समाजवाद के रुप मे विकसित हुई।यद्यपि ये विचारधारा भी मार्क्स से परोक्ष रुप मे प्रभावित थी, साथ ही साथ इसने कई दृष्टियो से लोकतान्त्रिक मान्यताओ को स्वीकार किया। विकासवादी समाजवाद के समर्थको ने लोकतन्त्र को न केवल एक साधन के रुप मे माना वरन एक साध्य के रुप मे भी माना।[124] 20वी शताब्दी के प्रजातान्त्रिक समाजवाद को हम जिन रुपो मे पाते है उनका विवरण निम्नवत् है-

---

122 - सेलेक्टेड वर्क्स आफ माओत्सेतुग, खण्ड 1, पृष्ठ 25

123 - चेयरमैन माओत्सेतुग की विचारोक्तिया, पृष्ठ 88

124 - वर्न्स-आइडियाज इन कनफ्लिक्ट, पृष्ठ 164-168

फेबियनवाद[125] -

इग्लैण्ड मे जार्ज बर्नार्ड शॉ, सिडनी वेब, सिडनी ओलिवर और ग्राहम वैलास आदि विचारको ने 1884 ई0 मे रोमन सैनिक "फेबियस" के नाम पर फेबियन सोसाइटी की स्थापना की और 1887 ई0 मे यह घोषणा की कि व्यक्तिगत सम्पत्ति और वर्ग सघर्ष का अन्त करके ही जन साधारण को अधिकाधिक लाभ पहुचाया जा सकता है।

सितम्बर 1884 ई0 मे फेबियन सोसाइटी घोषणा पत्र मे कहा गया कि भूमि का राष्ट्रीयकरण करके इस पर व्यक्तिगत अधिकार समाप्त कर दिया जाना चाहिए।[126] सन् 1887 ई0 के घोषणा पत्र मे कहा गया है कि फेबियन समाज, समाजवादियो का समाज है। अत इसका उद्देश्य समाज का नव निर्माण करना है।यह नया सगठन भूमि तथा उद्योग धन्धो को व्यक्तिगत तथा वर्ग स्वामित्व से पृथक कर समाज को उसका स्वामी बनाकर किया जायेगा, जिससे वह सामान्य लाभ के लिए कार्य करे।[127]

फेबियनवादी समाजवाद को युग की सम्पूर्ण सस्कृति से परिपूर्ण मानते है। वे समाजवाद की स्थापना सवैधानिक साधनो द्वारा करके पूजीवाद का अन्त करना चाहते है।उनका सर्वहारा वर्ग की तानाशाही मे विश्वास नही है, वे लोकतन्त्र और समाजवाद को एक दूसरे का पूरक बताकर समाज मे व्याप्त शोषण व वर्ग सघर्ष का अन्त करना चाहते है।[128]

समष्टिवाद अथवा राज्य समाजवाद-

विकासवादी समाजवाद का दूसरा रुप समष्टिवाद अथवा राज्य समाजवाद है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार, "समष्टिवाद अथवा राज्य समाजवाद वह नीति अथवा सिद्धात है, जो लोकतान्त्रिक राज्य द्वारा सम्पत्ति के अन्त की अपेक्षा अधिक अच्छे वितरण और

---

125 - फेबियनवाद एक विशुद्ध अग्रेजी विचारधारा है, जार्ज बर्नार्ड शॉ और सिडनी वेब इस विचारधारा के प्रवर्तक थे और ग्राहम वैलास, एच0 जी0 वेल्स, श्रीमती एनी बेसेन्ट, कार्ल जे0 लास्की, विलियम क्लार्क और जे0 आर0 मेकडानल्ड आदि विद्वानो ने इसका विकास किया। एडवर्ड आर0 पीस की " हिस्ट्री आफ फेबियन सोसाइटी जार्ज बर्नार्ड शॉ की 'दि फेबियन सोसाइटी तथ जी0 डी0 एच0 कोल की "फेबियन सोशलिज्म नामक पुस्तको मे फेबियन बाद के सम्बन्ध मे पर्याप्त सामग्री मिलती है।

126 - बर्नार्ड शॉ का घोषणा पत्र (सितम्बर 1884 ई0)

127 - कोकर आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृष्ठ 110

128 - बार्कर- पोलिटिकल थाट इन इग्लैण्ड, पृष्ठ 16, बर्न्स- आइडियाज इन कनफ्लिक्ट, पृष्ठ 67-68 कोकर-रीसेन्ट पोलिटिकल थाट, पृष्ठ 98 107

उत्पादन मे विश्वास करता है ।समाजशास्त्र के विश्वकोष के अनुसार " समष्टिवाद व्यक्तिवाद के विरोधी सिद्धातो का सामान्य नाम है "।[129] इस विचारधारा के समर्थक राज्य के सहयोग से समाजवाद लाना चाहते है। राज्य समाजवादी मार्क्स के समान राज्य को एक आवश्यक बुराई तथा उद्योगो को राज्य के नियन्त्रण मे रखना चाहते है ।समष्टिवाद का अभिप्राय समाज से सबंधित है।

समष्टिवादी व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देते है ।वे उत्पादन के साधनो का राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष मे है । वे पूजीवाद को समूल नष्ट करना नही चाहते, अपितु पूजीपतियो की सम्पत्ति छीनकर उन्हे उचित मुआवजा भी देना चाहते है ।उनका मार्क्स के वर्ग सघर्ष के सिद्धात मे विश्वास नही है, वे समाज के समस्त वर्गो का हित करने के पक्ष मे है । राज्य समाजवादी लोकतान्त्रिक तथा वैधानिक उपायो से समाजवाद की स्थापना करना चाहते है ।जोड ने इस विचारधारा का समर्थन किया है ।[130]

समष्टिवाद के मूलभूत आधार जर्मन समाजवाद तथा अग्रेजी समाजवाद (फेबियनवाद) है । समष्टिवाद को लोकतान्त्रिक समाजवाद भी कहते हैं । क्योकि यह वाद लोकतान्त्रिक तरीके से भूमि तथा उद्योग पर व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त करके उन्हे राज्य के अधिकार मे लाना चाहता है । यह वह नीति अथवा सिद्धात है जो केन्द्रीय प्रजातान्त्रिक सत्ता द्वारा आजकल की अपेक्षा श्रेष्ठतम वितरण तथा उसके अधीन श्रेष्ठतम उत्पादन की व्यवस्था करना चाहता है ।[131]

इस विचारधारा के सिद्धात और स्वरुप मार्क्सवाद आदि अन्य वादो के समान स्पष्ट और सुनिश्चित नही है ।इस विचारधारा के मानने वालो को उदार (लिबरल), उदार लोकतन्त्रीय (लिबर लडेमोक्रैट), सामान्य जनता के हित पर बल देने वाले तथा प्रगतिवादी कहते है ।[132] उनका कोई सगठित आन्दोलन नही है । इनके सिद्धातो अथवा मत का कोई निश्चित सस्थापक नही है और इनके सुनिशचित सिद्धात नही है ।वे सामाजिक न्याय, उदारवाद, आर्थिक उदारवाद, आर्थिक लोकतन्त्र, तथा औद्योगिक लोकतन्त्र के सिद्धातो पर बल देते है ।

---

129 - ब-र्स आइडियाज इ-न कनफ्लिक्ट, पृष्ठ 161 164

130 - सी0 ई0 एम0 जोड़-इन्ट्रोडक्शन टु माडर्नपोलिटिकल थ्योरी, पृष्ठ 42

131 - सी0 ई0 एम0 जोड-माडर्न पोलिटिकल थ्योरी, पृष्ठ 54

132 - कोकर रीसेन्ट पोलिटकल थाट, पृष्ठ 595

पुनर्विचारवाद अथवा संशोधनवाद-[133]

विकासवादी समाजवाद का एकरुप पुनर्विचारवाद है, जिसे सशोधनवाद भी कहा जाता है ।[134] जर्मन विचारक एडवर्ड बर्नस्टाइन आरम्भ मे मार्क्स का अनुयायी था, किन्तु इग्लैण्ड तथा जर्मनी की परिस्थितियो से प्रभावित होकर उसने कुछ दृष्टियो से मार्क्स के विचारो मे सशोधन की आवश्यकता पर बल दिया । 20वी शताब्दी के वर्षो मे उसके विचारो के फलस्वरुप एक समाजवादी आन्दोलन हुआ जिसे सशोधनवाद का नाम दिया गया । बर्नस्टाइन ने मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धात और इतिहास की भौतिकवाद की आलोचना की और मार्क्स के पूजीवादी व्यवस्था के सिद्धात तथा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही आदि सिद्धातो मे सशोधन किया ।[135]

वह उद्योगो को समाज के नियन्त्रण मे रखकर लोकतन्त्रतात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था ।[136] इस विचारधारा के समर्थको मे जीन जोरस, एडवर्ड अनासीले, विस्लोलाटी, कार्ल ब्रेटिंग तथा तुगन बेरोनस्की आदि प्रमुख थे ।[137] कोकर ने लिखा है कि सशोधनवाद फेबियनवाद और मार्क्सवाद दोनो के मध्य की विचारधारा है वे क्रान्ति को प्रारम्भिक साधन मानकर अन्तिम साधन मानते है ।[138]

श्रम संघवाद[139]

आधुनिक युग मे श्रमिक सघवाद से अभिप्राय इन क्रान्तिकारियो के सिद्धात एव साधनो से है, जो पूँजीवाद को नष्ट करने तथा समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए औद्योगिक सघो

---

133 - जिन विचारको ने मार्क्सवाद मे सशोधन किया उनमे जर्मनी के बर्नस्टाइन के अतिरिक्त फ्रास के जीन जारी, इटली के कियोलाटी, बेल्जियम के एडवर्ड अनसीले और रुस के केरोनस्की के नाम विशेष रुप से उल्लेखनीय है ।लैडलर- एहिस्ट्री आफ सोशलिस्ट थाट, पृष्ठ 294

134 - बर्नस्टाइन की मूल पुस्तक का अग्रेजी अनुवाद सन् 1909 मे ईवोल्यूशनरी सोशलिज्म के नाम से इडिथ सी0 हार्वे द्वारा प्रकाशित हुआ । सशोधनवादियो की अन्य रचनाए सन् 1906 और 1910 मे क्रमश मिल्र्डेड मिण्टर्न और रेडमाउण्ट द्वारा 'स्टडीज इन सोशलिज्म, ' माडर्न सोशलिज्म, इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेन्ट शीर्षकों से अनुदित हुई ।

135 - दि प्रिकसर एडवर्ड बर्नस्टाइन इन रिविनिज्म, लियोबोल्ड लेहेज्ड द्वारा सम्पादित (1962), पृष्ठ 41, अलैक्जेण्डर ग्रे- दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 404 406

136 - एडवर्ड बर्नस्टाइन-विकासवादी समाजवाद (अग्रेजी अनुवाद) हूचेज्स, पृष्ठ 8-9

137 - लैडलर ए हिस्ट्री आफ सोशलिस्ट थाट, पृष्ठ 296

138 - कोकर रीसेन्ट पोलिटिकल थाट, पृष्ठ 71

139 - श्रम सघवाद का अग्रेजी रुपान्तर सिडीकेलिज्म है, जो फ्रेंच शब्द सिडीकेट से निकला है । इसका अर्थ श्रम सघ है लेकिन अग्रेजी मे सिडीकेट शब्द का अर्थ स्पष्ट नही है ।अलैक्जेण्डर ग्रे दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन । पृष्ठ 408

की आर्थिक शक्ति का प्रयोग करना चाहते है ।सघवादी वर्ग सघर्ष और श्रमिक वर्ग की सत्ता को ही समाजवाद की स्थापना का मौलिक तत्व मानते है ।सघवादी राज्य विरोधी है और मार्क्स के समान वे भी राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते है ।

श्रम सघवाद का प्रादुर्भाव फ्रास मे हुआ। फ्रास सरकार की श्रमिक विरोधी नीति से क्षुब्ध होकर वहाँ का श्रमिक वर्ग असतोष से भर उठा और वह राज्य को घृणा की दृष्टि से देखने लगा। सघवादियो ने संसदीय शासन और प्रतिनिधि शासन की कटु आलोचना की और उन्होने श्रमिको को आत्मनिर्भर बनाने की योजना बनायी ।सघवादी क्रान्तिकारी कार्यक्रम रखते है और वे हडताल,तोड फोड, बहिष्कार आदि साधनो द्वारा क्रान्ति लाकर समाजवाद की स्थापना करना चाहते है ।[140] श्रम सघवाद के प्रमुख नेताओ मे सोरल (1847-1922) तथा पिलेव्यिर के नाम विशेष रुप से उल्लेखनीय है

श्रम सघवाद श्रमिक सघो का स्वामित्व उत्पादन के साधनो पर स्थापित करना चाहता है ।[141] सघवादी प्रत्यक्ष कार्यवाही एक राज्यविहीन, शोषण विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते है ।[142] लैडलर ने लिखा है कि-''20वी शताब्दी के प्रारम्भ मे श्रम सघ वादियो ने समाजवादी विचारधारा पर व्यापक प्रभाव डाला ।उन्होने तत्कालीन ससदीय शासन के दोषो को उजागर किया और राजनीतिज्ञो को श्रमिको के कष्टो की ओर आकर्षित किया ।[143]

श्रेणी समाजवाद

श्रेणी समाजवाद,श्रेणी समाजवाद का अग्रेजी सस्करण है । इसे ब्रिटिश फेबियनवाद और फ्रासीसी सघवाद का बुद्धिजीवी शिशु कह सकते है ।[144] श्रेणी समाजवाद के प्रमुख प्रवर्तक ऐ0 जे0 पेण्टी, ए0 आर0 आरेन्ज, एस0 जी0 हाब्सन तथा जी0 डी0 एच0 कोल है । श्रेणी समाजवाद समष्टिवाद और श्रम सधवाद दोनो की त्रुटियो को दूर कर मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है ।[145]

---

140 - सेबाइन- ए हिस्ट्री आफ पोलिटिकल थ्योरी ,पृष्ठ 582 , हैरी डब्ल्यू लैडलर- सोशल एण्ड इकोनामिक मूवमेण्ट्स, पृष्ठ 632

141 - लुडविग वान मिजेज- सोशलिज्म, पृष्ठ 270 ,महादेव प्रशास शर्मा-आधुनिक राजनीति के विभिन्न वाद, पृष्ठ 230

142 - अलैक्जेण्डर ग्रे - दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 417

143 - हैरी डब्ल्यू लैडलर- सोशल एण्ड इकोनामिक मूवमेण्ट्स, पृष्ठ 634

144 - रोक्को कन्टेम्प्रेरी पोलिटिकल थाट आन ओल्ड इगलैण्ड, पृष्ठ 150

145 - हैरी डब्ल्यू लैडलर-सोशल एण्ड इकोनामिक मूवमेन्ट्स, पृष्ठ 619

श्रेणी समाजवाद का प्रवर्तक इग्लैण्ड निवासी आर्थर जोसेफ पेन्टी था । लेकिन कोल ने श्रेणी समाजवाद को लोकप्रिय बनाया । कोल का मत था कि उद्योग धन्धो के सचालन पर श्रमिको का नियन्त्रण होना चाहिए, लेकिन वह उद्योगो के राष्ट्रीयकरण के पक्ष मे नही था और उत्पादन कार्य मे राज्य के हस्तक्षेप का विरोधी था ।[146] श्रेणी समाजवादी हाब्सन का कहना था कि श्रमिक सघो को समाज की आर्थिक व्यवस्था पर नियन्त्रण करके उद्योगो को अपने हाथ मे ले लेना चाहिए ।[147]

सन् 1915 मे श्रेणी समाजवाद को व्यवहारिक रुप देने के लिए आक्सफोर्ड के दो विद्वानो विलियम मेलोर और मोरिस रेकिट ने एक- "नेशलन गिल्डस लीग" की स्थापना की । उसका उद्देश्य मजदूरी पद्धति को समाप्त करके उद्योगो मे श्रेणियो द्वारा स्वशासन की स्थापना करना था ।[148] लेकिन इस लीग को विशेष सफलता न मिल सकी और श्रेणी समाजवादी आन्दोलन अल्प काल में ही समाप्त हो गया । लैडलर, ने लिखा है कि "पूँजीवादी व्यवस्था और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक जटिल समाज मे मध्यकालीन श्रेणी व्यवस्था को लागू करना असम्भव सा है ।मध्ययुग मे ही गुटबाजियो के कारण श्रेणी व्यवस्था का पतन हो गया, तो वर्तमान युग मे गडे मुर्दे उखाडने से कोई लाभ नही हो सकता है ।[149] इस प्रकार श्रेणी समाजवादी विचारधारा अपनी अव्यवहारिकता के कारण अल्प समय तक ही जीवित रह सकी तथपि इसने इग्लैण्ड और अमेरिका की राजनीति को अवश्य प्रभावित किया ।

गिल्ड समाजवादी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के तरीको मे एक मत नही है, । कुछ लोग कहते है कि उस अन्तिम व्यवस्था मे वैध उपायो से ही शेष स्वत्व श्रमिको के हाथ मे आ जायेगे,दूसरे लोगो का विचार है कि अनुकूल स्थिति मे क्रान्तिमय उपायो से काम लेना होगा और उनके लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए ।[150] कुछ गिल्ड समाजवादी सीधे उपायो का पक्ष लेते है लेकिन कोल का विचार है कि-शीघ्रता से क्रान्ति लाना हमारा उद्देश्य नही है। हमारा उद्देश्य है-

---

- अलैक्जेण्डर ग्रे दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 451
- [illegible] पृष्ठ 272
- अलैक्जेण्डर ग्रे- दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 257
- हैरी डब्ल्यू लैडलर-सोशल एण्ड इकोनामिकल मूवमेन्ट्स, पृष्ठ 658
- डा0 सम्पूर्णानन्द- समाजवाद, पृष्ठ 295

विकासवाद के मार्ग द्वारा उन सब शक्तियो को दृढ करना जिससे आने वाली क्रान्ति गृह युद्ध न होकर समाज मे क्रियाशील प्रवृत्तियो का एक अन्तिम परिणाम न प्राप्त तथ्य सा मालूम हो ।150 [151]

लोकतान्त्रिक समाजवाद

समाजवाद के जिस रुप को 20वी शताब्दी मे सर्वाधिक मान्यता मिली, उसे लोकतान्त्रिक समाजवाद कहा जाता है । समाजवाद का यह रुप उदारवादी विचारधारा से प्रभावित है । यह व्यक्तिवाद और पूजीवाद के स्थान पर ससदीय प्रणाली द्वारा एक नयी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना चाहता है ।लोकतान्त्रिक समाजवाद स्वस्थ प्रतियोगिता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय आर्थिक समानता तथा विश्व-बन्धुत्व का पोषक है ।इसमे नियोजित अर्थ व्यवस्था पर विशेष बल दिया जाता है ।[152] लोकतान्त्रिक समाजवाद भी इंग्लैण्ड की देन है और इसके प्रवर्तको मे आर0 क्रासमैन, फ्रासिस विलियम,आर0 एच0 टानी, इवान डार्विन, क्लीमेण्ट एटली क्रासमैन आदि विशेष रुप से उल्लेखनीय है ।[153]विश्व के अनेक देशे मे लोकतान्त्रिक समाजवाद के आधार पर राजनीतिक दलो का निर्माण किया गया है ।

लोकतान्त्रिक समाजवाद के चिन्तन का स्वरुप विविध पक्षीय है। यह अधिनायकवाद और फासीवाद का विरोध करता है और लोकतान्त्रिक उपायो द्वारा समाज मे आर्थिक सामाजिक परिवर्तन का हामी है ।[154] लोकतान्त्रिक समाजवादी सीमित व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने के समर्थक है ।और आधारभूत उद्योगो का राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष मे है ।

लोकतान्त्रिक समाजवाद आज एक अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन बन गया है और भारत मे भी यही समाजवाद विकासमान है ।भारतीय समाजवादी जय प्रकाशनारायण अपने समाजवादी दल का लक्ष्य ही लोकतान्त्रिक समाजवाद लाना बताते है ।[155]

डा0 राममनोहर लोहिया कहते है कि लोकतान्त्रिक समाजवाद तानाशाही साम्यवादी का विरोधी है ।[156] आचार्य नरेन्द्र देव समाजवाद और लोकतन्त्र को एक दूसरे का पूरक मानते है ।[157]

---

151 - जी0 डी0 एच0 कोल-गिल्ड सोशलिज्म, पृष्ठ, 183,187

152 - इवान डार्विन-पालिटिक्स आफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म,पृष्ठ 135

153 - एबन्सटीन-मास्टर्स आफ पोलिटिकल थाट पृष्ठ 581-582

154 - प0 जवाहरलाल नेहरु-कुछ पुरानी चिट्ठिया, पृष्ठ 199

155 - जय प्रकाश नारायण-डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, पृष्ठ 4

इस प्रकार समाजवाद एक अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन बन गया । आज हमे समाजवाद के अनेक रुप दिखाई पडते है ।समाजवाद के इन विभिन्न रुपो मे कुछ दृष्टियो से समानताए दिखाई पडती है जैसे ये सभी शोषण विहिन समाज की स्थापना करना चाहते है, श्रम की महत्ता को महत्व देते है तथा श्रम के उचित उपयोग पर बल देते है तथा समाज मे समानता, स्वतन्त्रता,भ्रातृत्व जैसे मूल्यो का विकास करना चाहते है, ताकि सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार समाज की सम्पूर्ण उपलब्धियो का उपभोग कर सके, और एक आदर्श समाज की स्थापना हो सके ।

156 - डा0 राम मनोहर लोहिया- मार्क्स, गाँधी एण्ड सोशलिज्म ,पृष्ठ 895

157 - नरेन्द्र देव- राष्ट्रीयता और समाजवाद पृष्ठ 142

में का

उदय,

अध्याय—२

भारत में समाजवाद का उदय, प्रभाव व विकास

अध्याय-2
भारत में समाजवाद का उदय, प्रभाव व विकास

1- भारतीय समाजवादी चिन्तन का विकास

भारत मे समाजवाद की संकल्पना अति प्राचीन है । वैदिक ग्रन्थो मे कहा गया है कि सभी प्राणियो की सहज समानता, स्वतन्त्रता तथा बन्धुत्व सामाजिक सगठन का मूलाधार होती है ।[1] बौध ग्रन्थ भी मानव एकता और भ्रातृत्व पर बल देते है ।[2] महाभारत मे भी इस प्रकार के विचार मिलते है कि प्रारम्भिक काल मे व्यक्तियो के मध्य भेदभाव की भावना का अभाव था, तथा उसे धर्म के अनुरुप माना गया है । अत हम कह सकते है कि प्राचीन भारतीय ग्रन्थो मे भी समाजवादी विचारो के मूल तत्व विद्यमान थे फिर भी आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के दर्शन के रुप मे समाजवाद भारत मे पाश्चात्य प्रभाव के फलस्वरुप ही विकसित और लोकप्रिय हुआ ।[3]

आधुनिक भारतीय समाजवाद की झलक सर्वप्रथम श्री अरविन्द द्वारा 1893 ई0 मे प्रकाशित लेखो मे मिलते है ।[4] इन लेखो मे उन्होने अखिल भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस की मध्यम वर्गीय मनोवृत्ति की आलोचना करते हुए देश के सर्वहारा वर्ग की दशा सुधारने की अपील की थी।

लाला लाजपत राय को ऐसा प्रथम भारतीय माना जा सकता है, जिन्होने समाजवाद तथा बोल्शेविकवाद के सम्बन्ध मे कुछ लिखा ।[5] तथापि यह निर्विवाद है कि उन्होने पाश्चात्य बोल्शेविकवाद के प्रति सहानुभूति का रुख नहीं अपनाया था ।[6] लाला लाजपत राय ने सन् 1920

---

1 - छान्दोग्य उपनिषद् 5/11/5 वैदिक ग्रन्थ

2 - बौध ग्रन्थ- धम्मपद

3 - महाभारत, शक्तिपर्व-59/14

4 - अरविन्द घोष-पत्रिका इन्दु प्रकाश' तथा लेख ' पुरानो के बदले नये दीपक 1893 ई0

5 - लाला लाजपत राय-दि फ्यूचर आफ इण्डियन पालिटिक्स, पृष्ठ 104

6 - मानवेन्द्र नाथ राय मेमायर्स-इनका मत है कि लाला लाजपत राय एक बुर्जवा राजनीतिज्ञ थे और उन्हे समाजवाद से कोई सहानुभूति नही थी।

मे भारतीय ट्रेड यूनियन काग्रेस के प्रथम अधिवेशन का सभापतित्व भी किया था ।[7] भारतीय पुनर्जागरण के समय स्वामी विवेकानन्द ने "समाजवाद" के अर्थ को स्पष्ट किया ।[8] तथा बाद मे डा0 सम्पूर्णानन्द ने वेदान्ती समाजवाद की वकालत की ।[9] सन् 1921-23 मे मानवेन्द्र नाथ राय ने "इण्डिया इन ट्राजीशन" और "इण्डियन प्रोब्लम" नामक पुस्तके लिखीं। इन रचनाओ मे उन्होने कांग्रेस पर भारतीय पूजीपतियो के प्रभुत्व की कटुआलोचना की । इस समय देशबन्धु चितरजन दास ने काग्रेस के गया अधिवेशन मे अपनी अध्यक्षीय भाषण मे सन् 1917 की साम्यवादी क्रान्ति को विश्व की एक महान घटना बताया, तथपि उन्होने साम्यवादियो के प्रति कोई सहानुभूति नही व्यक्त की, फिर भी उन्होने भारत मे श्रम सघ या ट्रेड यूनियन आन्दोलन को गतिशील बनाने मे महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

सन् 1926 मे पहली बार प0 मोती लाल नेहरु और प0 जवाहर लाल नेहरु सोवियत सघ की यात्रा पर गयें प0 जे0 एल0 नेहरु ने रुस की नई आर्थिक नीति और 1921 ई0 तक उसकी शानदार उपलब्धियो का उल्लेख अपनी पुस्तक 'सोवियत रशिया' मे किया और बाद मे उसने "अपनी आत्म कथा"[10] और "विश्व इतिहास की झलक"[11] नामक रचनाओ मे भी मार्क्स की वैज्ञानिक तथा आर्थिक प्रणाली की काफी प्रसशा की । मई **1925** मे भारत मे ***साम्यवादी दल*** की स्थापना हुई। इसी समय से भारत मे समाजवादी विचारधारा लोक प्रिय होने लगी।

सन् 1929 ई0 मे मे प0 जवाहरलाल नेहरु ने लाहौर काग्रेस अधिवेशन मे पहली बार समाजवाद सबधी अपने कार्यक्रम की रुपरेखा प्रस्तुत की ।[12] सन् 1931 मे कराची काग्रेस अधिवेशन मे मूल अधिकार सबधी जो मूल सकल्प पारित हुआ, उसमे भी समाजवादी विचारधारा के बीज निहित थे।[13] सन् 1934 मे प0 नेहरु के नेतृत्व मे राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना और सन् 1937 मे फैजपुर कृषि कार्यक्रम का निर्धारण समाजवाद की दिशा मे महत्वपूर्ण

- श्री नारायण मल्हार जाशी को अखिल भारतीय ट्रड यूनियन काग्रस का सस्थापक माना जाता है । उन्होने 1909 मे गोखले की सर्वेट्स आफ इण्डियन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और 1917 मे बम्बई मे सोशल सर्विस लीग की नीव डाली

8 - दि कम्पलीट वर्क्स आफ स्वामी विवेकानन्द-जिल्द 5 पृष्ठ 144, (अल्मोड़ा अद्वैत आश्रम)

9 - सम्पूर्णा नन्द- इण्डियन सोशलिज्म

10 - प0 जवाहर लाल नेहरु मेरी कहानी, पृष्ठ 48

11 - प0 जवाहर लाल नेहरु - विश्वइतिहास की झलक, खण्ड 2, पृष्ठ 753

12 - काग्रेस प्रेसीडेन्शल एड्रेसेज (स) खण्ड 2,

13 - अखिलेन्द्र प्रसाद राय- सोशलिस्ट थाट इन माडर्न इण्डिया, पृष्ठ 72

अग्रगामी कदम थे ।[14] मई 1934 मे काग्रेस समाजवादी दल की स्थापना भारत मे समाजवाद के सगठनात्मक विकास की एक महत्वपूर्ण घटना थी ।[15] इस दल की स्थापना से बिहार समाजवादी दल (1931 ई0), बम्बई समाजवादी गुट (1934 ई0) आदि अनेक प्रान्तीय सगठनो और गुटो को एक अखिल भारतीय आधार तथा मच प्राप्त हो गया । देश के प्रमुख समाजवादी नेताओ का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन 17 मई 1934 को पटना मे आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता मे हुआ । इस दल की स्थापना मे जय प्रकाश नारायण का महत्वपूर्ण योगदान था और यूसूफ मेहर अली, अच्युत पटवर्धन तथा अशोक मेहता ने इस कार्य मे अत्याधिक सहायता भी थी ।[16] इस समय से भारतीय समाजवाद तेजी के साथ फलने-फूलने लगा ।

वस्तुत भारतीय समाजवाद आर्थिक एव सामाजिक पुनर्निर्माण की एक योजना के रुप मे ही नही अपितु साम्राज्यवादी शोषण से मुक्ति एव राष्ट्रीय आन्दोलन की एक विचारधारा के रुप मे विकसित हुआ है ।[17] भारतीय समाजवाद के प्रणेताओ मे प0 जवाहरलाल नेहरु, आचार्य नरेन्द्र देव, जय प्रकाश नारायण, डा0 राम मनोहर लोहिया, डा0 सम्पूर्णनन्द और अशोक मेहता आदि प्रमुख नेता थे ।

2- भारतीय समाजवाद की पृष्ठभूमि

भारतीय समाजवाद की पृष्ठभूमि ब्रिटिश शासन की शोषण नीति मे निहित थी ।सन् 1757 ई0 मे अग्रेजो ने प्लासी के युद्ध मे विजयी होकर भारत मे ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की और सन् 1857 ई0 के प्रथम स्वाधीनता सग्राम तक सम्पूर्ण भारत ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया । ब्रिटिश सरकार की शोषण नीति व पक्षपात पूर्ण नीति के विरोध मे भारतीयो ने सन् 1857 ई0 मे एक सशक्त विद्रोह किया, यद्यपि इस विद्रोह मे भारतीयो को सफलता नही मिली, फिर भी पाश्चात्य विचारो के देश मे आगमन, औद्योगीकरण, सचार व परिवहन के साधनो के विकास के फलस्वरुप भारत मे नवजागरण प्रारम्भ हो गया ।

14- पटटाभि सीता रमैया -काग्रेस का इतिहास, खण्ड 2, पृष्ठ 36, रजनी पाम दत्त - आज का भारत, पृष्ठ 523

15- डा0 वी0 पी0 वर्मा- आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, पृष्ठ 418

16- अशोक मेहता-डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एण्ड स्टडीज इन एशियन सोशलिज्म,

17- डा0 वी0 पी0 वर्मा- आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, पृष्ठ 419

महात्मा गॉधी ने लिखा है कि "समाजवाद ही नही साम्यवाद भी हर्षोपनिषद के पहले मंत्र मे स्पष्ट है । इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है कि जगत मे जो कुछ है, वह सब ईश्वर द्वारा बनाया हुआ है, इसलिए उसके नाम से त्याग करके तू भोग करता जा, किसी धन के प्रति लालसा न रख"[18]

भारतीय विचारक कौटिल्य का राज्य निश्चित रुप से लोक कल्याणकारी था। उनके विचारो मे हमे समाजवाद का अभास होता है यद्यपि कौटिल्य के राज्य मे सामाजिक सगठन वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित है, परन्तु राज्य एव राजा के क्रर्त्तव्य पालन के श्रेष्ठता पर बल दिया गया है ।राज्य को समस्त जनो की शिक्षा व्यवस्था का दायित्व सौपा गया है । वह चाहता था कि राज्य की ओर से समस्त परोपकारी कार्य सम्पादित हो । राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह वृद्धो, अपगो, असहाय स्त्रियो, अनाथो,रोगियो और दुखियो की सहायता करे।

अत यह स्पष्ट है कि कौटिल्य के राज्य की अवधाराणा 'कल्याणकारी राज्य' पर आधारित है क्योकि राज्य व्यक्ति के सभी पहलुओ से सबद्ध कार्यों का सपादन करता है। वह प्रजा की रक्षा और पालन नही करता, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य है 'योगक्षेम' की स्थापना 'योग' का अर्थ यदि किसी वस्तु की सफलतापूर्वक उपलब्धि है, तो 'क्षेम' का अर्थ शान्ति पूर्वक उस वस्तु का उपयोग करना है ।'योगक्षेम' का दूसरा अर्थ है, जो नही है, उसे प्राप्त करना और जो है, उसकी सुरक्षा करना ।

इस प्रकार 'योगक्षेम' मे लोक कल्याणकारी राज्य के भाव निहित है, जिनके द्वारा राज्य प्रजा के सुख, कल्याण और आनन्द के लिए प्रयासरत है । कौटिल्य का कथन है कि-

प्रजा सुखे सुख राज्ञ प्रजाना च हिते हितम् ।

तात्म प्रिय हित राज्ञ प्रजाना तु प्रिय हितम् ।।

(अर्थ शास्त्र,पहला अधिकरण, अठारहवॉ अध्याय)

अर्थात प्रजा के सुख मे राजा का सुख और प्रजा के हित मे राजा का हित है । अपने आप को अच्छे लगने वाले कार्यो को करने मे राजा का हित नही, बल्कि उसका हित तो प्रजाजनो को अच्छे लगने वाले कार्यो का सपादन करने मे है ।

---

18 - महात्मा गॉधी- हरिजन, 20 जनवरी सन् 1937 के अक से

निष्कर्षत यह कहा जा सकता है कि कौटिल्य के राज्य का उद्देश्य पुलिस-राज्य के समान न तो केवल शाति और व्यवस्था बनाये रखना है और न केवल करो की वसूली करना है। वस्तुत उसका राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य है जो प्रजा के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे अपने दायित्वो को निभाने के लिए सदा क्रियाशील रहता है । ***के0 मोटवानी ने*** अपनी पुस्तक मनु धर्मशास्त्र मे लिखा है कि "मनु के निर्देशन मे राज्य द्वारा बनाये जाने वाले अनेक कानून वर्तमान-कालीन राजशास्त्र के विद्यार्थी को समाजवादी प्रतीत होगे"।

आधुनिक युग मे महात्मा गाधी और बिनोवा भावे ने इसी सर्वमगल या सर्वोदय के प्रवर्तन का प्रयास किया है । इस प्रकार से भारत मे वैदिक काल से आधुनिक काल तक सर्वोदय का वास्तविक समाजवाद की प्रतिष्ठा के लिए सदैव ही प्रयास होता रहा है । प्राचीन समाजवाद की धारणा अध्यात्म और सत्य पर प्रतिष्ठित है । इस मौलिक समाजवाद मे वास्तविक अध्यात्मिक चेतना प्राप्त करने के लिए निर्गुण और सगुण की पूजा, निष्काम कर्म, ज्ञान आदि साधन माने गये हैं, जिनके सम्यक अनुष्ठान मे समत्व बुद्धि प्राप्त होती है। इस समाजवाद का लक्ष्य था अनाशक्ति और अपरिग्रह ।परन्तु जब से भारतीय समाजवाद पर कार्ल मार्क्स का प्रभाव पडा, इसका उद्देश्य जन शक्ति या विधि द्वारा सम्पत्ति की सस्था को समाप्त करने का हो गया है। डा0 लोहिया ने उचित ही लिखा है कि "समाजवादी आन्दोलन की शुरुआत भारत मे और विश्व मे एक अर्थ मे बहुत पहले ही हो जाती है, वह है अनाशक्ति का, मिल्कियत और ऐसी चीजो के प्रति लगाव समाप्त करने का, मोह घटाने का । किन्तु जब से समाजवाद के ऊपर कार्ल मार्क्स की छाप पडी तब से एक दूसरा अर्थ सामने आ गया । वह है सम्पत्ति की सस्था को समाप्त करने का, सम्पत्ति रहे ही नही, चाहे कानून से, चाहे जनशक्ति से ।"[19]

3- उन्नीसवीं शताब्दी मे समाजवाद

19वी शताब्दी के धार्मिक एव सामाजिक सुधार आन्दोलन का भारत की राजनीति मे विशेष स्थान है ।इसके बहुमुखी स्वरुप एव व्यापकता की दृष्टि से इस आन्दोलन को सघर्ष पूर्ण आधुनिक इतिहास मे एक महत्वपूर्ण घटना माना जा सकता है । इस आन्दोलन ने भारत की तत्कालीन जडता को समाप्त किया और देश के जन जीवन को झकझोर दिया । इसने

---

19 - डा0 लोहिया -समाजवादी आन्दोलन का इतिहास, पृष्ठ 1

जहाँ एक ओर धार्मिक तथा सामाजिक सुधारो का आह्वान किया वही दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियो के मन मे आत्म सम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की। धार्मिक उपदेशो के साथ-साथ आन्दोलन के नेताओ ने स्वतन्त्रता और समानता का भी उपेदश दिया।"भारत मे समसामयिक, ऐतिहासिक एव राजनीतिक परिप्रेक्ष्य मे इस स्वतत्रता का अर्थ मात्र बौद्धिक चिन्तन की स्वतन्त्रता से ही नहीं, बल्कि असमानता, शोषण और अत्याचार से मुक्ति भी था"। [20]

भारत पर अग्रेंजो की विजय ने भारतीय समाज की कमजोरियो एव गिरी हुई हालत को स्पष्ट कर दिया।अत कुछ विचारशील और बुद्धिमान भारतीयो ने देश की दुर्दशा, पिछडेपन, और विदेशियो के समक्ष अपनी पराजय के कारणो की खोज बीन शुरु की तथा देश के उद्धार के लिए प्रयत्न करने लगे। वैसे अधिकाश भारतीय अभी भी परम्परागत विचारो, रीति-रिवाजो एव सस्थाओ मे विश्वास जमाये बैठे थे, लेकिन उनमे से कुछ ने सम्पर्क मे आते ही पश्चिम के नये विचारो एव ज्ञान के महत्व को पहचाना। पश्चिम के वैज्ञानिक ज्ञान, बुद्धिवाद (Rationlism) के सिद्धात और मानववाद (Humanitarianism) का इन प्रबुद्ध भारतीयो पर गहरा प्रभाव पडा। वे इस नये ज्ञान एव सिद्धान्तो की सहायात से अपने समाज की भलाई मे लग गये। इसमे समाज के विभिन्न वर्गो को अपना निजी हित भी नजर आया।"नये सामाजिक वर्ग जैसे पूँजिपति वर्ग, श्रमजीवी वर्ग और आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग पाश्चात्य विचारो एव ज्ञान को इसलिए अपनाना चाहते थे ताकि उनसे देश का आधुनिकीकरण हो और इन विभिन्न सामाजिक वर्गो की स्वार्थ सिद्धि हो सके। धीरे-धीरे बाकी भारतीयो पर इस पाश्चात्य विचारो का प्रभाव पडा क्योकि भारतीय उत्तरोत्तर यह महसूस करते गये कि पश्चिमी विचार केवल पश्चिमी समाज के लिए ही नहीं बल्कि भारत सहित सम्पूर्ण मानव जाति के लिए भी उपयोगी थे।[21]"

भारत मे समाजवाद का विकास राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि पर हुआ।जिन प्रारम्भिक चिन्तको ने राष्ट्रवादी पृष्ठभूमि तैयार करने मे प्रमुख भूमिका अदा की उनमे राजाराममोहन राय,

---

20 - रामलखन शुक्ला "आधुनिक भारत का इतिहास (स) हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय - 1998, पृष्ठ 342

21 - वही, पृष्ठ 343

[22] दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द और रामकृष्ण परमंहस के नाम उल्लेखनीय है।इस दिशा मे ब्रह्म समाज,[23] आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन तथा थियोसोफिकल सोसाइटी जैसी सुधारवादी सस्थओ का भी योगदान बडा प्रसंशनीय और महत्वपूर्ण है ।[24] आधुनिक काल मे भारतीय समाजवाद की पृष्ठभूमि तैयार करने मे भारतीय काग्रेस का भी बड़ा योगदान रहा है ।

I-दयानन्द सरस्वती (1824-1883 ई0)

10 अप्रैल सन् 1975 ई0 मे बम्बई मे आर्य समाज की स्थापना की । यद्यपि दयानन्द एक महान समाज सुधारक थे, लेकिन उनके विचारो मे समाजवादी धारणा और दर्शन के प्रमुख बिन्दु मिलते हैं । जहा एक ओर उन्होने मानव समानता पर बल दिया वही दूसरी ओर भारतीय समाज के दलित तथा गिरे हुए वर्गो के उद्धार करने का हर सभव प्रयास भी किया।उनका उद्देश्य मानव मात्र की मुक्ति करना था । मानव को किसी भी बन्धन मे रहना उनको प्रिय नही था ।दयानन्द की शिक्षाओ मे मानवतावादी सार्वभौमवाद के अश देखने को मिलते हैं । उन्होने लिखा है "समाज का प्राथमिक उद्देश्य मनुष्य जाति की शारीरिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक दशा को सुधारकर समस्त विश्व का कल्याण करना है ।मै उस धर्म को स्वीकार करता हूँ जो सार्वभौम सिद्धान्तो पर आधारित है, और जिसमे वह सब समाविष्ट है, जिसको मनुष्य जाति सत्य समझकर सदैव से मानती आयी है और जिसका वह आगे के युगो मे भी पालन करती रहेगी । इसी को मै धर्म कहता हूँ सनातन नित्य धर्म जिसका विरोधी कोई भी न हो सके । मै उसी को मानने योग्य मानता हूँ जो सब मनुष्यो के द्वारा और सब युगो मे विश्वास करने योग्य हो।[25] दयानन्द मानते थे कि सामाजिक तथा राजनीतिक कर्म और भौतिक समृद्धि का अपना मूल्य और महत्व है । इनके समाज सुधार तथा पुन स्थापना, दलिताद्धार तथा मानव असमानता को दूर करने के प्रयास तथा कार्यक्रम की योजना भारत मे राष्ट्रीय राजनीतिक प्रगति की

---

22 - राजाराम मोहन राय इग्लैण्ड मे एक बार कल्पनावादी समाजवादी राबर्ट ओवेन से भेट की ।इस भेट वार्ता से स्पष्ट होता है कि वे समाजवादी विचारो से परिचित थे ।यू0 एम0 देसाई- भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ 114

23 - बी0 आर0 पुरोहित हिन्दू रिवाइवलिज्म एण्ड इण्डियन नशेनलिज्म, पृष्ठ 116,ब्रजेन्द्रनाथ गील- राममोहनराय दि यूनिवर्सल मैन, भाग-2, पृष्ठ 101-109

24 - विपिन चन्द्र पाल- बिगनिग आफ फ्रीडम मूवमेंट इन इण्डिया, पृष्ठ 50

25 - दयानन्द सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश' सार्वदेशिक प्रकाशन लिमिटेड दरियागज नई दिल्ली अध्याय 6 पृष्ठ 125

पूर्वगामी सिद्ध हुई। उनके इस सन्देश का भी महान राष्ट्रीय मूल्य है कि किसी को (अछूतो तथा विश्वभर के लोगो को भी) वेदो का ज्ञान प्राप्त करने तथा वेदाध्ययन का समान अधिकार है।

II- **स्वामी विवेकानन्द (1863-1902 ई0)**

स्वामी विवेकानन्द-हबर्ट स्पेन्सर और जॉन स्टुअर्ट मिल से प्रभावित थे। वे शैली के सर्वात्मवाद और वर्डस्वर्थ की दार्शनिकता के प्रेमी एव हीगेल के वस्तु-निष्ठात्मक आदर्शवाद पर अनुरक्त थे, फ्रासीसी राज्य क्रान्ति का प्रभाव, उस समय साहित्य के माध्यम से जोरो से फैल रहा था, विवेकानन्द भी उसके स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धान्त त्रय मे बडे उत्साह से विश्वास करते थे।[26] स्वामी विवेकानन्द अद्वैत वेदान्ती थे। वे जीव को तत्वत ब्रह्मा ही मानते थे। एक सच्चे अद्वैत वादी की भॉति उनका विश्वास था कि अन्तोगत्वा सब जीव ब्रह्मा ही हैं अत प्रत्येक मनुष्य के अन्दर ईश्वर विद्यमान है। मनुष्यो की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। स्वामी विवेकानन्द के हृदय मे गरीबो और दलितो के लिए अत्यधिक सहानुभूति थी। इस लिए वे गॉधी के काफी करीब और उनके विचारो से काफी प्रभावित थे। वे सबसे बडे समाजवादी थे क्योकि उन्होने अमीरी तथा गरीबी दोनो को दर किनार कर पद-दलितो को सीने से लगाने का सन्देश देते थे और अपने कार्यो से अपने मिशन मे यह करके दिखाया। उनका विचार था- गरीब,पीडित अभावग्रस्त, पद दलित, सब आओ। हम सभी लोग रामकृष्ण की शरण मे एक है। हम पूजा के इस आडम्बर को जैसे-देव मूर्ति के सामने सखबजाना, घण्टा बजाना, और आरती करना छोड दे, हम शास्त्रो के पठन-पाठन और व्यक्तिगत मोक्ष के लिए सब तरह की साधनाओ को छोड दे तथा गॉव-गॉव जाकर गरीबो और पीडितो की सेवा करने का बीडा उठा ले।[27]

विवेकानन्द जी ने शिक्षितो को कहा कि "जब तक करोडो लोग भूख और अज्ञान मे गोते खा रहे है, तब तक मै हर आदमी को एक विश्वासघातक मानता हूॅ, जिसने उनकी गाढी कमाई के पैसे से शिक्षा पायी है और अब उन्ही पर कोई ध्यान नही देता।[28] विवेकानन्द ने अमीरो को उनके कपट, शोषण और अनाचार के लिए फटकारा। उन्होने बडे दुख भरे शब्दो मे कहा कि "भारत वर्ष मे हम लोग गरीबो को, साधारण लोगो को,पतितों को क्या समझते है? उनके लिए न कोई

---

26 - रामधारी सिह दिनकर- 'सस्कृति के चार अध्याय' लोक भारती प्रकाशक, एम0 जी0 मार्ग इलाहाबाद (1999)" पृष्ठ 500

27 - ताराचन्द- 'भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास' (दूसराखण्ड), नई दिल्ली, पृष्ठ 368

28 - स्वामी विवेकानन्द पत्रावली, प्रथम भाग, पृष्ठ 83 (अद्वैत आश्रम अल्मोड़ा)

उपाय है,न बचने की राह और न उन्नति के लिए कोई मार्ग ही ।भारत के दरिद्रो का,पतितो का कोई साथी नही, उन्हे कोई सहायता देने वाला नही, वे कितनी ही कोशिश क्यो न करे,उनकी उन्नति का कोई उपाय नही, वे दिन पर दिन डूबते जा रहे है । राक्षस जैसा नृशस समाज पर जो लगातार चोटें कर रहा है, उसका अनुभव तो वे खूब कर रहे है, पर वे यह नहीं जानते कि ये चोटे कहाँ से आ रही हैं ।[29] इसके साथ ही विवेकानन्द को यह विश्वास था कि जब पद दलित वर्ग, जनता का साधारण वर्ग उठ खडा होगा तो उसकी प्रगति को रोकने का साहस कोई नही करेगा। गरीबो की सर्वसाधारण शक्ति को जगाते हुए विवेकानन्द ने कहा-"ऊँचे पद वालो या धनिको का भरोसा मत करना, उनमे जीवन शक्ति नहीं है, वे तो जीते हुए भी मुर्दे के समान है । भरोसा तुम लोगो पर है, गरीब, पद-मर्यादा रहित किन्तु विश्वास भी तुम्ही लोगो पर है"[30]

यूरोप मे विकसित हो रहे पूँजीवाद की गलत प्रवृत्ति से विवेकानन्द अत्यधिक निराश हुए। वे नये क्रान्तिकारी विचारो की ओर आकर्षित हुए जो भी प्रारम्भिक चरण या अवस्था मे थे। वे रुस के क्रान्तिकारी और अराजक्तावादी विचारक प्रिन्स क्रोपाटिकिन से मिले। समाजवादी विचारो ने उनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होने स्वय को समाजवादी कहना प्रारम्भ कर दिया । वे गरीबो व पद दलितो के प्रति अत्यधिक सवदेनशील थे ।समाज मे उन्होने उनके लिए समुचित स्थान दिये जाने की जबरदस्त वकालत की और जन साधारण के उत्थान को अपने कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अग बनाया ।उन्होने कहा कि राष्ट्र का गौरव महलो से सुरक्षित नही रह सकता ।झोपडियो की दशा भी सुधारनी होगी तथा गरीबो को उनके दीन हीन स्तर से ऊँचा उठाना होगा ।देश भक्त बनने की दशा मे सबसे पहला कदम यही है कि हम भूख और अभाव से पीडित करोडो व्यक्तियो के प्रति वास्तविक सवदेना का अनुभव करे और उनके उत्थान की दिशा मे कुछ करके दिखाएँ । यदि गरीबो और शूद्रो को दीन हीन ही रख गया तो देश और समाज का कोई कल्याण नही हो सकता"[31] विवेकान्द के समाजवादी हृदय इन शब्दो मे चित्कार किया-"मै उस भगवान या धर्म पर विश्वास नहीं करता जो न विधवाओ के ऑसू पोछ सकता है

29- वही, पृष्ठ 368

30 - स्वामी विवेकानन्द प्रत्रावली, प्रथम भाग, पृष्ठ 369 (अद्वैव आश्रम अल्मोड़ा)

31 - द कम्पलीट वर्क्स आफ स्वामी विवेकानन्द (अद्वैत आश्रम अल्मोड़ा), जिल्द 6, पृष्ठ 389

और न अनाथो के मुँह मे एक टुकडा रोटी ही पहुँचा सकता है"।[32] पूंजीवादी और शोषणवादी अमीरो के बारे मे उन्होने कहा कि "वे लोग जिन्होने गरीबो को कुचलकर धन पैदा किया है और राजसी ठाट-बाट से अकडकर चलते है, वे उन 20 करोड देश वासियो के लिए जो इस समय भूखे और असभ्य बने हुए है, यदि कुछ न करे, तो वे लोग घृणा के पात्र है ।[33]

"विवेकानन्द भारत के पहले विचारक थे जिन्होने भारतीय इतिहास की समाजशास्त्रीय दृष्टि से यथार्थवादी व्याख्या की । उन्होने राजनीतिक उथल-पुथल के प्रलयकारी विप्लवो के मूल मे सामाजिक सघर्षो का निरतर सूत्र ढूँढ निकाला ।उन्होने भारत की जो व्याख्या की वह स्वरुप मे अशत मार्क्सवादी भी है, किन्तु वह उनके अपने ढग की मार्क्सवादी है । ऐसा कोई प्रमाण नही है कि उन्होने 'दि कैपिटल' (पूँजी) अथवा दि कम्यूनिस्ट मैनिफस्टो पढी थी ।[34] विवेकानन्द के अनुसार प्राचीन भारत मे राजशक्ति तथा ब्रह्मशक्ति के बीच सघर्ष चला करता था। बौध धर्म क्षत्रियो का विद्रोह था । उसके कारण पुरोहितो की शक्ति का ह्रास और राजशक्ति का उत्कर्ष हुआ । आगे चलकर कुमारिल, शकर और रामानुज ने पुरोहित शक्ति के उत्कर्ष का प्रयत्न किया । उदरम्भि ब्राह्मण पुरोहितो ने मध्ययुगीन राजपूती सामतवाद से मेल करके अपनी शक्ति को कायम रखने की चेष्टा की, किन्तु मुस्लिम शक्ति की प्रगति के कारण पुरोहित वर्ग के उत्कर्ष की सम्पूर्ण आशाए ध्वस्त हो गयी, और न ही पुरोहित लोग विदेशी ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत ही अपनी शक्ति के पुनरुत्थान का स्वप्न देख सकते थे ।"[35] भारतीय इतिहास की यह समाजशास्त्रीय व्याख्या अशत मार्क्सवादी है और अशत विल्फ्रेडो पैरेटो के सिद्धात से मिलती जुलती है ।यह मार्क्सवादी इस अर्थ मे है कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय निरतर जनता के शोषण मे लगे रहे दलित वर्ग के शोषण की धारणा मार्क्सवादी है। किन्तु विवेकानन्द का सिद्धात पैरोटो की धारणा से इस अर्थ मे मिलता-जुलता है कि उन्होने शोषक वर्गो के बीच सघर्ष की धारण का प्रतिपादन किया।जिसे पैरेटो भाषा मे 'विशिष्ट वर्ग का चक्रावर्तन' कहते हैं।[36]" इसी प्रकार

---

32 - वही पृष्ठ 389

33 - वही, पृष्ठ 390

34 - वी0 पी0 वर्मा -'आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन (लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा 1995-96), पृष्ठ 148

35 - विवेकानन्द- ' माडर्न इण्डिया", (द कम्पलीट वर्क्स आफ विवेकानन्द), जिल्द, 4 पृष्ठ 394-95

36 - वी0 पी0 वर्मा- 'आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन' पृष्ठ 148-49

विवेकानन्द के अनुसार भारतीय इतिहास मे दो सामाजिक प्रवृत्तियॉ रही है ।पहली ब्राह्मणो और क्षत्रियो के बीच निरतर सघर्ष की प्रवृत्ति है ।कभी-कभी ऐसे भी अवसर आये जब दोनो वर्गो ने परस्पर सहयोग किया। दूसरे पुरोहितो ने अपनी धार्मिक क्रियाओ के द्वारा और क्षत्रियो तथा बाद मे राजपूतो ने तलवार के बल पर जनता का निरन्तर शोषण किया । श्रमिक वर्ग के प्रति विवेकानन्द की गहरी सहानुभूति थी। उनके जीवनकाल में भारत मे श्रमिक वर्ग का आन्दोलन अथवा सगठन मौजूद नही था,क्योकि उस समय इस वर्ग की स्वय रचना हो रही थी ।लेकिन एक महान क्रान्तिकारी की भाति विवेकानन्द ने श्रमिक वर्ग के प्रति अडिग आस्था प्रकट की और अपनी मातृभूमि के महान भविष्य के लिए, न केवल स्वतन्त्रता की वरन् समाजवाद की भविष्यवाणी की ।वास्तव मे उन्होने भारत मे समाजवाद का नारा रुस मे समाजवादी क्रान्ति के दो दशक पूर्व ही दे दिया । इन्होने एक भविष्य दृष्टाकी भॉति देख लिया था कि किसी न किसी रुप मे समाजवाद निकट आ ही रहा है, और वह दिन दूर नही जब शूद्र के रुप मे ही शूद्र शासक वर्ग बन जायेगे ।

स्वामी विवेकानन्द उस अर्थ मे समाजवादी नही थे जिस अर्थ मे हम आधुनिक किसी राजनीतिक दार्शनिक को समाजवादी कहते है ।उनकी दृष्टि मे समाजवाद कोई एकदम निर्दोष या आदर्श व्यवस्था नही थी ।उन्होने लिखा था-''मै समाजवादी हूॅ इसलिए नही कि मै इसे पूर्ण रुप से निर्दोष व्यवस्था समझता हूॅ, परन्तु इसलिए कि रोटी न मिलने से आधी रोटी ही अच्छी है । अन्य व्यवस्थाओ को आजमाया जा चुका है ।और वे विफल अथवा दोष युक्त सिद्ध हुई हैं । अब इसकी (समाजवाद की) भी परीक्षा होने दो, यदि और किसी कारण से नही तो केवल नवीनता के लिए ही सही ।[37] विवेकानन्द को दो अर्थो मे समाजवादी कहा जा सकता है । प्रथम, इसलिए कि उनमे यह समझने की ऐतिहासिक दृष्टि थी कि भारतीय इतिहास मे दो उच्च जातियो-ब्राह्मणो तथा क्षत्रियो का आधिपत्य रहा है। क्षत्रियो ने गरीब जनता का अर्थिक तथा राजनीतिक शोषण किया और ब्राह्मणो ने उसे नवीन तथा जटिल धार्मिक क्रिया कलाप और अनुष्ठानो के बन्धन मे जकड कर रखा । उन्होने खुले तौर पर जातिगत उत्पीडन की भर्त्सना की

---

37 - द कम्पलीट वर्क्स आफ स्वामी विवेकानन्द', जिल्द 6, पृष्ठ 389

और आत्मा तथा ब्राह्मा मे आस्था रखने के नाते मनुष्य तथा मनुष्य के बीच सामाजिक बन्धनो को अस्वीकार कर दिया "[38]

विवेकानन्द की रचनाओ मे सामाजिक समानता का जो समर्थन देखने को मिलता है वह प्रबल पुरातनवाद तथा ब्राह्मणो की स्मृतियो मे व्याप्त सामाजिक ऊँच-नीच के सिद्धात का सबल प्रतिवाद है । उनका सामाजिक समानता का सिद्धात तत्वत समाजवादी है ।

दूसरे, विवेकानन्द समाजवादी इसलिए थे कि उन्होने देश के सब निवासियो के लिए 'समान अवसर के सिद्धात' का समर्थन किया ।[39] उन्होने लिखा-"यदि प्रकृति मे असमानता है,तो भी सबके लिए समान अवसर होने चाहिए अथवा यदि कुछ को अधिक और कुछ को कम अवसर दिया जाय तो दुर्बलो का सबलो से अधिक अवसर दिया जाना चाहिए दूसरे शब्दो मे- ब्राह्मण को उतनी शिक्षा की आवश्यकता नही है जितनी की चण्डाल को । यदि ब्राह्मण को एक अध्याापक की आवश्यकता है तो चण्डाल को दस की है । क्योकि जिनको प्रकृति ने जन्म से [illegible] बुद्धि नही दी है उसे अधिक सहायात [illegible] । पद-दलित,दरिद्र और अज्ञानी इन्ही को अपना देवता समझो"[40] समान अवसर का सिद्धात निश्चय ही समाजवादी दिशा का द्योतक है।

स्वामी विवेकानन्द तथा आधुनिक समाजवादी दार्शनिको मे आधारभूत अन्तर है ।प्रथम, विवेकानन्द का, मार्क्स के समान, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या मे विश्वास नहीं था और न ही उन्होने मार्क्स तथा उनके अनुयायियो की भाति वर्ग सघर्ष के सिद्धात को मानव इतिहास को समझने की कुजी माना था ।विवेकानन्द आध्यात्मिक पुरुष थे, वेदान्ती थे और वेदान्त पर आधारित किसी भी सामाजिक दर्शन मे वर्ग सघर्ष के सिद्धात के लिए कोई स्थान नही हो सकता। द्वितीय, विवेकानन्द का अन्य समाजवादी दार्शनिको के समान वर्गविहीन समाज के सिद्धात मे विश्वास नही था । यद्यपि उन्होने तत्कालीन भारतीय जाति प्रथा का विरोध किया था लेकिन [illegible]तियो के उन्मूलन की बात नही की बल्कि यह माना कि हर समाज मे किसी न किसी प्रकार के [illegible]र्ग अवश्य ही होने चाहिए ।तृतीय, विवेकानन्द ने केवल मात्र आर्थिक समानता को ही सर्वाधिक

---

[38] - वी0 पी0 वर्मा - आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन' , पृष्ठ 149

[39] - वही, पृष्ठ 149

[40] - " द कम्पलीट वर्क्स आफ स्वामी विवेकानन्द' , जिल्द 6, पृष्ठ 321

महत्व नहीं दिया वरन उनका आदर्श तो एक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक भ्रातृत्व था जिसमें आर्थिक समाजवाद के अतिरिक्त नैतिक तथा बौद्धिक आत्मीयता भी होगी ।

III- महात्मा गाँधी-(1869-1948 ई0)

सन् 1920 से 1947 ई0 तक भारतीय राजनीति का युग गाँधी युग कहलाता है [41] महात्मा गाँधी ने सन् 1920 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन एवं कांग्रेस की नीतियों को एक नयी दिशा प्रदान की ।[42]

सन् 1934 में जब पटना में कांग्रेसी समाजवादियों का सम्मेलन हुआ, उस समय उनके समक्ष समाजवादी कार्यक्रम रखा गया । इस कार्यक्रम के प्रति गाँधी जी ने अपनी प्रतिक्रियाएं पं0 जवाहर लाल नेहरु को पत्रों के माध्यम से स्पष्ट की जिससे पता चलता है कि उनके अन्दर समाजवाद के प्रश्न पर संघर्ष चल रहा था ।[43] लेकिन गांधी जी आत्मा से एक समाजवादी थे ।[44] गाँधी जी की जीवनी में तेंदुलकर ने लिखा है कि गांधी ने तो समाजवाद का सिद्धांत उस समय स्वीकार कर लिया था जब वे दक्षिण अफ्रीका में थे ।[45]लेकिन वे समाजवाद के वर्ग संघर्ष और हिंसात्मक क्रान्ति के सिद्धांत को नहीं मानते थे ।पं0 जवाहर लाल नेहरु ने गाँधी जी की समाजवादी भावना के विषय में लिखा है-" कभी-कभी वह अपने को समाजवादी भी कहते हैं, लेकिन वह समाजवाद का प्रयोग एक ऐसे अनोखे अर्थ में करते हैं, जो खुद उनका लगाया हुआ है और जिसका उस आर्थिक ढाँचे से कोई सरोकार नहीं है, जो सामान्यतया समाजवाद के नाम से पुकारा जाता है ।वे समाजवाद को और उससे भी अधिक विशेषत : मार्क्सवाद को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह हिंसा से संबंधित है ।[46] उल्लेखनीय है कि पं0 नेहरु वैज्ञानिक समाजवाद के पक्षधर थे और गाँधी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त, औद्योगीकरण का विरोध, राजनीति का आध्यात्मिकरण और खादी आन्दोलन को उन्होंने पूरा समर्थन नहीं दिया था ।तथापि वे गाँधी

41 - पट्टाभिसीता रमैया- कांग्रेस का इतिहास, खण्ड 1 पृष्ठ 161

42 - पं0 जवाहरलाल नेहरु - मेरी कहानी, पृष्ठ 75, पी0 डी0 कौशिक- दि कांग्रेस आइडियोलाजी एण्ड प्रोग्राम, पृष्ठ 35

43 - पं0 जवाहर लाल नेहरु- कुछ पुरानी चिट्ठियाँ, पृष्ठ 155,- हरिजन, 20 सितम्बर, 1940 ई0 गाँधी जी, नेहरु के इस मत से सहमत नहीं थे कि औद्योगीकरण से समाजवाद की स्थापना संभव हो सकती हैं

44 - डा0 वी0 पी0 वर्मा - पोलिटिकल फिलास्फी आफ गाँधी एण्ड सर्वोदय, पृष्ठ 120,पं0 जवाहर लाल नेहरु- आत्म कथा, पृष्ठ 518

45 - डी0 जी0 तेन्दुलकर - महात्मा, खण्ड 7, पृष्ठ 476

46 - पं0 जवाहरलाल नेहरु - मेरी कहानी (अध्याय -विकट समस्याएं,) पृष्ठ 717

जी के महान व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बहुत से काग्रेसी भी 'समाजवाद' शब्द का प्रयोग करने लगे ।[47] देश के प्रमुख समाजवादी नेता जैसे नरेन्द्र देव, जय प्रकाश,सम्पूर्णानन्द, अशोक मेहता, राममनोहर लोहिया आदि गॉधी जी के समाजवादी चिन्तन से प्रभावित थे ।काग्रेस के अन्दर भी समाजवादी और गॉधीवादी गुटो मे अनेक बार वैचारिक मतभेद हुए, जिनकी मध्यस्थता गॉधी जी ने की और उनके मतभेदो का निराकरण भी किया ।[48] राय अखिलेन्द्र प्रसाद भी स्वीकार करते है कि गॉधी जी का समाजवादियो से घनिष्ठ सम्बन्ध था ।[49] और उन्ही के प्रयत्नो का यह परिणाम था कि सन् 1948 तक समाजवादी नेता इच्छा रखते हुए भी काग्रेस से अपना सम्बन्ध विच्छेद न कर सके ।

वस्तुत गॉधी जी का समाजवाद मार्क्सवादी विचारधारा से हटकर एक अहिसक समाजवाद था । राममनोहर लोहिया ने भी लिखा है कि "आर्थिक प्रश्नो पर गॉधी जी के विचारो का उपयोग समाजवाद के लिए किया जा सकता है ।[50]

गाँधी जी के समाजवादी चिन्तन पर विभिन्न विद्वानो ने भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किये है । तेदुलकर का मत है कि "गॉधी जी ने 1920 मे लका मे दिये गये अपने भाषण मे कहा था कि आप कोष दरिद्र नारायण के लिए खोल दो[51] इस कथन से उनके समाजवादी दर्शन का आशय स्पष्ट होता है । उन्होने समयानुकूल अपने विचारो को प्रकट किया । इस सन्दर्भ मे किशोरी लाल मशरुवाला ने लिखा है कि वास्तव मे गॉधी जी का समाजवाद हिंसा रहित साम्यवाद के अधिक निकट है ।[52] गॉधी जी के समाजवादी चिन्तन का मूल आधार सत्य और अहिसा का सिद्धात है । इस सन्दर्भ मे नरेन्द्रदेव ने लिखा है "उनकी अहिसा का सिद्धात भी केवल व्यक्तिगत आचरण का उपदेश मात्र था, किन्तु सामाजिक समस्याओ को हल करने के लिए अहिसा को एक उपकरण बनाना और राजनीति के क्षेत्र मे अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए उसका सफल प्रयोग करना महात्मा गॉधी का ही काम था और चूँकि वह ससार मे अहिसा को प्रतिष्ठित करना चाहते थे । इसलिए

- डा0 शोभा शकर आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन, पृष्ठ 75 76
- पी0 डी0 कौशिक दि काग्रेस आइडियोलाजी एण्ड प्रोग्राम पृष्ठ 132
- दि सेमीनार आन सोशलिज्म इन इण्डिया, खण्ड 1 (स), पृष्ठ 339 राय अखिलेन्द्र प्रसाद- सोशलिस्ट थाट इन मार्डन इण्डिया पृष्ठ 58
- डा0 राममनोहर लोहिया- मार्क्स-गाँधी एण्ड सोशलिज्म पृष्ठ -135
- डी0 जी0 तेन्दुलकर- महात्मा, खण्ड 2, पृष्ठ 385
- डा0 शोभाशकर- आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन, पृष्ठ 79-80

उनके अहिसा की व्याख्या भी अद्भुत, बेजोड और निराली थी ।[53] गॉधी जी के सत्य और अहिसा पर विचार व्यक्त करते हुए हरिभाऊ उपाध्याय ने भी लिखा है कि-गॉधीवाद के दो ध्रुव सत्य है, जिन्हे गॉधी जी क्रमश सत्य और अहिंसा कहा करते है । यही गाँधीवाद के पथ-प्रदर्शक सिद्धात है।"[54] इस प्रकार सत्य है कि गॉधी जी का चिन्तन सत्य और अहिंसा पर आधारित है ।सत्य को वे ईश्वर समझते थे और अहिसा को एक व्यापक वस्तु बताते थे ।[55] उन्होने सत्य की खोज मे ही राजनीतिक क्षेत्र मे प्रवेश किया,[56] और स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सत्याग्रह नामक एक अनोखे हथियार का प्रयोग किया ।[57] मार्क्सवाद-लेनिनवाद से हटकर गॉधी जी ने साधनो की पवित्रता पर बल दिया और समाजवाद की स्थापना के लिए रक्त रजित क्रान्ति के सिद्धात को मान्यता नही दी ।[58]

गॉधी जी ने जिस स्वराज की कल्पना की, उसका आशय शोषण हीन समाज से है । उनके स्वराज का अर्थ था निर्धनो के लिए भोजन और वस्त्र तथा सभी को अपना सर्वागिण विकास करने का अवसर।[59]

गॉधी जी ने स्वय अपनी पुस्तिका "हिन्द स्वराज" मे उद्योगपतियो तथा पूजीपतियो द्वारा श्रमिको के अमानवीय शोषण को स्वीकार किया है और उन्होने स्वालम्बी बनने हेतु लोगो को चरखा चलाने की शिक्षा दी है । वे शारीरकि श्रम के प्रबल समर्थक थे, क्योकि इसके बल पर ही व्यक्ति स्वालम्बी बन सकता है ।[60]

गॉधी जी के समाजवादी चिन्तन का आधार श्रम पर आधारित उनका सर्वोदय समाज है ।[61] सर्वोदय की प्रेरणा उन्होने रस्किन की पुस्तक "आन टू दि लास्ट" [62] से ग्रहण की थी। सर्वोदय का शाब्दिक अर्थ सबका उदय अर्थात समाज के प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति और

53 - नरेन्द्र देव- राष्ट्रीयता और समाजवाद, पृष्ठ 473
54 - हरिभाऊ उपाध्याय गाँधीवादी समाजवाद पृष्ठ 25
55 - गाँधी जी- आत्मकथा ,पृष्ठ 356
56 - पट्टाभि सीता रमैया-काग्रेस का इतिहास, खण्ड 2 पृष्ठ 463
57 - प0 जवाहरलाल नेहरु हिन्दुस्तान की कहानी, पृष्ठ 233
58 - महात्मा गाँधी सेलेक्टेड वर्क्स, खण्ड 42, पृष्ठ 355
59 - पट्टाभि सीता रमैया- काग्रेस का इतिहास, जिल्द 1 पृष्ठ 246
60 - बी0 बी0 रमन मूर्ति- (स) गाँधी, पृष्ठ 716
61 - डा0 वी0 पी0 वर्मा पोलिटिकल फिलास्फी आफ महात्मागाँधी एण्ड सर्वोदय पृष्ठ 279-80
62 - गॉधी जी ने रस्किन की पुस्तक "आन टू दि लास्ट" का अनुवाद हिन्दी भाषा मे 1904 मे किया था

विकास है। सर्वोदय सिद्धात के आधार पर गॉधी जी का विचार था कि समाज मे कोई वर्ग भेद नही होना चाहिए। उनका कहना था कि मनुष्य को, प्रेम, दया, सहयोग आदि नैतिक गुण प्रकृति से प्राप्त होते है। अत स्वार्थ और ईर्ष्या के आधार पर समाज का विभाजन करना अनुचित है। समाजवाद और सर्वोदय मे केवल यही अन्तर है कि समाजवाद भौतिक हितो पर बल देता है, जबकि सर्वोदय मे अध्यात्मिक हितो का पोषण किया जाता है तथा दोनो के उद्देश्य समान है, दोनो ही समाज मे शोषण का उन्मूलन कर मानव जाति को उन्नति के पथ पर अग्रसर करना चाहते है। लेकिन सर्वोदय मार्क्सवाद के समान क्रान्ति द्वारा समाजवाद नही स्थापित करना चाहता, वरन् सर्वोदय नैतिकता के आधार पर मनुष्य के हृदय परिर्वतन का पक्षपाती है। इस प्रकार अन्य समाजवादी विचारको की अपेक्षा गॉधी जी का सर्वोदय सिद्धान्त विशुद्ध नैतिकता पर आधारित है। गॉधी जी सर्वोदय के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लिखे हैं कि सर्वोदय का लक्ष्य मनुष्य और मनुष्य के मध्य खाई को समाप्त करना है।[63]

सर्वोदयी समाज की स्थापना के लिए गॉधी जी ने ग्रामोद्धार, ग्रामीण पुनर्निर्माण, कुटीर उद्योगो को प्रोत्साहन, आर्थिक विकेन्द्रीकरण आदि का समर्थन किया और आर्थिक समानता की आवश्यकता पर बल दिया।[64] वे सत्य, प्रेम और अहिंसा पर आधारित एक शोषणविहीन सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के पक्ष मे थे। मार्क्स के समान वे भी व्यक्तिगत सम्पत्ति का विरोध करते थे और अपरिग्रह का समर्थन करते थे। उनका कहना था कि अनावश्यक वस्तुओ का सग्रह करना चोरी है। लेकिन जहॉ मार्क्सवादी व्यक्तिगत सम्पत्ति का उन्मूलन क्रान्ति द्वारा करना चाहते है वहॉ गॉधी जी अहिंसक उपायो द्वारा पूॅजीपतियो का हृदय परिवर्तन करके और उन्हे उत्पादन के साधनो का ट्रस्टी।[65] बनाकर व्यक्तिगत सम्पत्ति की बुराई को समाप्त करने के पक्ष मे थे। इस प्रकार गॉधी जी का समाजवादी चिन्तन आदर्शवादी है, जबकि मार्क्सवाद यथार्थ पर आधारित है। इसी सन्दर्भ मे गॉधी जी "रोटी के लिए श्रम का

---

63 - हरिभाऊ उपाध्याय- गॉंधीवादी, समाजवाद पृष्ठ 27

64 - महात्मा गॉंधी विलेज रिक -स्ट्रक्शन, पृष्ठ 4

65 - गॉंधी जी के अनुसार ट्रस्टी का अर्थ मालिक नही, वरन समाज की ओर से उस वस्तु का रक्षक है, मालिक तो सम्पूर्ण समाज है।

सिद्धान्त प्रतिपादित किया और स्वय को भी एक 'श्रमिक' बताये।[66] गॉधी जी अन्य समाजवादी चिन्तको के समान आर्थिक असमानता को वर्गीय क्रान्ति द्वारा समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, वरन वे नैतिकता द्वारा स्वेच्छापूर्वक मनुष्य का हृदय परिवर्तन कर आर्थिक समानता लाने के पोषक थे।[67] गाँधी जी का लक्ष्य सबके लिए सामाजिक-न्याय व आर्थिक अवसर की समानता को प्राप्त करना है। इस दृष्टि से गाधी जी को एक समाजवादी और गाँधीवाद को समाजवाद का एक विशिष्ट रुप समझा जा सकता है। किन्तु उनका समाजवाद दूसरे व्यक्तियो के समाजवाद से सर्वथा भिन्न था, वह मार्क्स अथवा किसी अन्य पश्चिमी विचारक से नही लिया गया था। उसका मूल था अहिसा मे अदम्य विश्वास। उन्होने लिखा है कि समाजवाद का जन्म उस समय नहीं हुआ था जबकि पूँजीपतियो द्वारा पूजी के दुरुपयोग का पता चला।जैसा कि मै कह चुका हूँ, समाजवाद यहॉ तक कि साम्यवाद भी, 'इशोपनिषद' के प्रथम श्लोक मे झलकता है। सत्य तो यह है कि जब कुछ सुधारको को हृदय परिवर्तनो के साधनो मे विश्वास आता रहा तो उस चीज का जन्म हुआ जिसे वैज्ञानिक समाजवाद कहते है। मै उसी समस्या को सुलझाने मे लगा हुआ हूँ जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है।[68]

गॉधी जी समाजवाद को सुन्दर शब्द मानते हैं। समाजवाद मे सभी सदस्य समान है- न कोई नीचा, न कोई ऊँचा। व्यक्ति के शरीर मे सिर इसलिए ऊँचा नही है कि वह शरीर के ऊपर है, न पैर के तलवे इस कारण निचे है कि ये जमीन को छूते है। जैस-शरीर के अंग समान है वैसे ही समाज के सदस्य भी। यह समाजवाद है।[69] गॉधी जी बोल्शेविकवाद के सम्बन्ध मे कहते है कि यह निजी सम्पत्ति के उन्मूलन मे विश्वास करता है, एक प्रकार से यह सिद्धात अपरिग्रह के नैतिक आदर्श का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किया गया प्रयोग है।लेकिन अपने वर्तमान रुप मे बोल्शेविकवाद अधिक दिनो तक नही चल सकता क्योकि वह हिंसा पर आधारित

---

66 - महात्मा गाँधी कैपिटल-एण्ड लेबर, पृष्ठ 46

67 - अनेक विद्वानो ने गाँधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धात को अव्यवहारिक बताया प0 नेहरु तक ने इस सिद्धात का समर्थन नही किया और विनोबभावे और जय प्रकाश नारायण तक इस सिद्धात को कार्य रुप न दे सके।नारायण सिह- मार्क्स और गाँधी का साम्यदर्शन, पृष्ठ 488

68 - यग इण्डिया 20 1 1920

69 - हरिजन-13 7 1947

है, हिसा पर आधारित कोई विचार अधिक दिन तक नही टिक सकता।[70] गॉधी जी ने वर्ग सघर्ष के मार्क्सवादी विचार को स्वीकार नही किया। वे पूॅजी तथा श्रम मे कोई नैसर्गिक विरोध नही मानते। वे श्रम तथा पूॅजी को समान स्तर पर रखने की आवश्यकता पर बल दते है। पूॅजीपतियो को केवल श्रमिको की भौतिक आवश्यकता का ही ध्यान नही रखना है, अपितु उसका नैतिक कल्याण भी करना है। वे न्यासी के रुप मे श्रमिको के हित का पालन करे। लडाई पूॅजी से नही अपितु पूॅजीवाद से है। गॉधी जी के अनुसार सम्पत्ति के निजी स्वामित्व के नष्ट करने के स्थान पर उसके उपभोग पर नियत्रण लगाने की आवश्यकता है ताकि अमीर एव गरीब के बीच की खाई को मिटाया जा सके।[71]

गॉधी जी की मान्यता है कि यदि जनता अहिसा को जीवन का आधारभूत सिद्धात बना ले तो वर्ग सघर्ष असभव हो जायेगा। इसके द्वारा पूॅजीपति को नष्ट करने के स्थान पर पूजीवाद को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है। पूॅजीपति न्यासी के रुप मे पूजी का उत्पादन सग्रह एव सबर्धन करने के लिए आमान्त्रित हैं।श्रमिको को पूॅजीपति के हृदय परिवर्तन की प्रतीक्षा नही करती है। यदि पूॅजी शक्ति है तो श्रम भी दोनो ही शक्तियॉ रचनात्मक अथावा विध्वसात्मक कार्य मे प्रयुक्त हो सकती है। श्रमिको मे अपनी शक्ति का बोध जागृत होते ही वे पूॅजी की साझेदारी की बात सोचेगे न कि पूॅजीपतियो के दास बने रहने की। प्रत्येक मनुष्य को जीवन की आवश्यकताओ की पूर्ति करने का समान अधिकार प्राप्त है। श्रमिको को अपने शरीर से श्रम करने के कर्त्तव्य का निर्वाह करना है, और उन व्यक्तियो से असहयोग करना है जो श्रम का शोषण करते है। मूलभूत समानता मे विश्वास रखते हुए पूॅजीपति एव श्रमिक को एक ही धरातल पर देखना है। पूॅजीपति को नष्ट करने के स्थान पर उसा हृदय परिवर्तन करना है।[72]

आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने की उनकी तकनीकि तथा समाजवादियो एव साम्यवादियो की तकनीकि मे अन्तर है। गॉधी जी, इस सम्बन्ध मे कहते है कि "समाजवादी तथा साम्यवादी यह कहते है कि वे आर्थिक समानता लाने के लिए आज कुछ नही कर सकते। वे इसके पक्ष मे प्रचार करते रहेगे और अन्त मे उनके अनुसार घृणा उत्पन्न होगी

---

70 - यग इण्डिया 15 11 1928
71 - वही, इण्डिया-21 11 1929
72 - वही, 26 3 1931

और बढ़ेगी । वे कहते है कि जब उनको राज्य पर नियत्रण प्राप्त हो जायेगा वे समता लागू करेगे । मेरी योजना के अनुसार, राज्य व्यक्ति की आकाक्षा की पूर्ति के लिए रहेगा न कि उनको अपने निर्देशो के अनुसार कार्य करने अथवा बाध्य करने के लिए । मै अहिसा द्वारा आर्थिक समानता की स्थापना कॅरुगा, जनता को अपने विचारो के अनुरुप परिवर्तित कॅरुगा, धृणा के स्थान पर प्रेम की शक्ति का उपयोग कॅरुगा । मेरे विचारो के अनुरुप समाज को बनाने तक मैं प्रतीक्षा नही कॅरुगा अपितु मै स्वय से ही इसका प्रारम्भ कर दूॅगा । यदि मै पचास मोटर कारो अथवा दस बीघा जमीन का भी मालिक हूॅ तो यह सत्य है कि मै अपने विचारो की आर्थिक समानता नही ला सकता इसके लिए मुझे स्वय को निर्धन से निर्धनतम स्तर तक अपने आपको घटाना होगा। मैं गत पचास वर्षो से यही करने का प्रयास कर रहा हूॅ और इस कारण से मै अपने आपको अग्रणी साम्यवादी कहने का दावा करता हूॅ हालॉकि मै धनिको द्वारा प्रस्तुत कार एवं अन्य सुविधाओं का उपयोग करता हूॅ उनका मेरे पर प्रभाव नही है और जनहित की मांग पर मैं उन्हे एक क्षण मे त्याग सकता हूॅ ।[73] वास्तव मे गॉधीवादी विचारधारा एक समग्र जीवन दर्शन प्रस्तुत करती है ।उसमे जीवन के सभी पक्षो, आध्यात्मिक,सामाजिक, राजनैतिक आदि का विवेचन हुआ है । यह व्यक्ति के व्यक्तित्व की गरिमा,विकास और महत्व पर बल देती है । उसका उद्देश्य राज्यशक्ति को क्षीण और व्यक्ति को सबल बनाना है। इसमे शोषण को शन्ति पूर्ण उपाय से समाप्त करने का जो प्रयास (न्यास पद्धति) किया गया है वह एक आदर्शवादी धारणा है और सिद्धांत रुप मे समाजवादी वर्ग-संघर्ष का एक विकल्प है । वस्तुत मार्क्स न पूॅजीपति और मजदूर के बीच सघर्ष को काफी बढा-चढाकर अकित किया है । गॉधी जी उसे शाश्वत मूल्य व्यवस्था के अन्तर्गत लेकर सहयोग और नैतिकता का आयाम प्रदान करते है, वे आर्थिक और लौकिक समस्याओ को आध्यात्मिक तथा पारलौकिक दृष्टियो से देखते है । इस आदर्श को व्यवहार में प्राप्त न मानकर भी नैतिकता की दृष्टि से अनुगमन योग्य मानते है ।[74]

इस प्रकार स्पष्ट है कि गॉधीजी की समाजवादी कल्पना का मूलआधार नैतिक है । उनका समाजवाद मानवीय समाजवाद है जो कि वैज्ञानिक समाजवाद (मार्क्सवाद-लेनिनवाद) से

73 _ एन0 के0 बोस- 'सेलेक्शन्स फ्राम गॉधी', बम्बई, पृष्ठ 37-38

74 _ डा0 एस0 एल0 वर्मा- ''समकालीन राजनीतिक चिन्तन' मीनाक्षी प्रकाशन (मेरठ) 1989, पृष्ठ 237-238

भिन्न है ।[75] उनके समाजवाद मे वर्ग-सघर्ष हिंसात्मक क्रान्ति और औद्योगीकरण का गौण स्थान है।[76] वे समाजवाद की स्थापना के लिए सत्य, प्रेम, अहिसा, सत्याग्रह ग्रामोद्धार,ग्रामीण पुनर्निर्माण, ट्रस्टीशिप आदि बातो को विशेष महत्व देते है ।

भारतीय समाजवादी चिन्तन के विकास मे महात्मागॉधी का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। देश के प्रमुख समाजवादी नेताओ और चिन्तको पर गॉधीवाद की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है।[77] उन्होने जिस समाजवादी विचारधारा को विकसित किया वह सर्वथा भारतीय परिस्थितियो पर आधारित है । यद्यपि इनकी रामराज्य की अवधाराण काल्पनिक प्रतीत होती है । तथापि भारत की शोषित और पीडित जनता के उद्धार के लिए और देश मे सच्चे समाजवाद की स्थापना के लिए उनके द्वारा निर्मित सत्य, अहिसा और सत्याग्रह का मार्ग प्रकाश स्तम्भ के समकक्ष है । उनका यह कथन भारत के समाजवादियो के लिए बडा ही प्रेरणावर्द्धक है कि "यदि समाजवाद का अर्थ दूसरो को मित्र बनाना है यहॉ तक कि अपने शत्रुओ को भी, सच्चे समाजवादियो को समाजवाद मुझसे सीखाना चाहिए तभी हम मजदूरो और किसानो का सच्चा राज्य स्थापित कर सकते है ।[78]

iv- <u>पं0 जवाहर लाल नेहरु</u> [79] (1989-1964 ई0)

प0 जवाहर लाल नेहरु को काग्रेसी नेताओ मे प्रमुख समाजवादी के रुप मे स्वीकार किया जाता है। अपने विद्यार्थी जीवन मे इग्लैण्ड मे रहकर वे फेबियनवादी समाजवाद के सपर्क मे आये, तथापि वे मूलत राष्ट्रवादी ही रहे ।[80]

नेहरु के सस्कारो पर ही कुलीनता का प्रभाव था और यह प्रभाव उनकी विचारधारा मे भी जीवन पर्यन्त तक बना रहा । नेहरु जी ने स्वय इस तथ्य को स्वीकार करते हुए लिखा है-" मै

---

75 - डा0 शोभा शकर- आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन पृष्ठ 93

76 - लुई फिशर (अनु0 लेख राम) गाँधी और स्टालिन पृष्ठ 93

77 - राममनोहर लोहिया मार्क्स , गाँधी एण्ड सोशलिज्म पृष्ठ 118

78 - डी0 जी0 तेन्दुलकर- महात्मा, खण्ड 8, पृष्ठ 41

79 - प0 जवाहर लाल नेहरु ने अपने विचार अनेक पुस्तको मे व्यक्त किये है जिनमे, ऐन आटोबायोग्राफी", "गिलिम्पसेज आफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और डिस्कवरी आफ इण्डिया विशेषरुप से उल्लेखनीय है

80 - प0 जवाहर लाल नेहरु -मेरी काहानी ,पृष्ठ 62

आदर्श बुर्जुवा हूँ तथा वह सभी पूर्वाग्रह जो बुर्जवा वातावरण मे बड़े होने मे सीख रुप मे मिलते हैं, मुझमे है।[81]

नेहरु जी को सन् 1926 मे यूरोप प्रवास का अवसर मिला और वह प्रवास उनका कुछ अधिक समय तक रहा। उन्हे वहाँ बहुत से समाजवादी और साम्यवादियो से संपर्क स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। सन् 1927 ई0 मे नेहरु जी रुस की यात्रा की और वहाँ पर साम्यवादियो की उलब्धियो को प्रत्यक्षत देखा।[82] इसी समय नेहरु जी की समाजवाद के प्रति रुचि बढने लगी।[83] ब्रुसेल्स मे 10 फरवरी 1927 ई0 को साम्राज्यवाद विरोधी अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में नेहरु जी द्वारा दिये गये भाषण के कुछ अश उनके समाजवादी विचारों पर प्रकाश डालते हैं।[84] नेहरु जी के लेखो और भाषणो से ज्ञात होता है कि 1917 की रुस की मार्क्सवादी राज्य क्रान्ति के पश्चात नेहरु जी मार्क्सवादी विचारो से अधिक प्रभावित थे लेकिन धीरे-धीरे प्रजातांन्त्रिक समाजवाद की ओर झुकते चले गये। उन्होने कार्ल मार्क्स को उन्नीसवी शताब्दी का एक प्रभावशाली विचारक बताया,[85] और मार्क्सवाद के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या से काफी प्रभावित हुए।[86]

इसके साथ ही साथ इस समय उन पर प्राचीन भारतीय वेदान्त दर्शन का भी प्रभाव दिखलाई पड़ता है। उन्होने अपनी पुस्तक "भारत की खोज" मे न केवल विज्ञान की महानता पर बल दिया वरन आध्यात्मिकता को भी मानव जीवन के लिए आवश्यक माना है। समाजवाद के सन्दर्भ मे उन्होंने साम्यवाद की आलोचना की तथा गॉधी जी की ही भॉति साधनो की पवित्रता पर बल दिया।यद्यपि उन्होने कई दृष्टियो से साम्यवाद की आलोचना की तथा अत तक वे कुछ

---

81 - प0 जवहार लाल नेहरु -ऐन आटोबायोग्राफ, पृष्ठ 526

82 - सेवियत रुस की उपलब्धियो का विवरण नेहरु जी ने अपनी पुस्तक "सोवियत एशिया" मे दिया है। यह पुस्तक उन्होने 1928 ई0 मे लिखी थी।सोवियत एशिया -पृष्ठ-50-74

83 - प0 जवाहर लाल नेहरु ने अपनी पुस्तक "विश्व इतिहास की झलक" मे रुसी क्रान्ति की काफी प्रशसा की है और यह भी स्पष्ट किया है कि समाजवाद के आगमन, कार्ल मार्क्स व मजदूर सगठनो के प्रति आपकी गहरी रुचि थी। विश्व इतिहास की झलक- खण्ड 3 पृष्ठ 761-62, मेरी कहानी- पृष्ठ 105

84 - नेहरु जी के इन भाषणो का सकलन "नेहरु- व्यक्तित्व और विचार" नाम पुस्तक मे किया गया है। यह पुस्तक 1965 मे प्रकाशित हुई थी

85 - प0 जवाहर लाल नेहरु "विश्व इतिहास की झलक', खण्ड 2, पृष्ठ 753, नेहरु- व्यक्तित्व और विचार (स) पृष्ठ 366

86 - राय अखिलेन्द्र प्रशाद - सोशलिस्ट थाट इन माडर्न इण्डिया, पृष्ठ 72

दृष्टियो से मार्क्स के विचारो से प्रभावित रहे।जैसे- अन्त तक इन्होने शोषण का विरोध किया तथा साम्राज्य वादियो की आलोचना की । कार्नफ्लिट ने अपनी पुस्तक मे स्पष्ट किया है कि यह नही कहा जा सकता है कि नेहरु जी ने गॉधी जी के सभी विचारो को मान लिया था ।कई दृष्टियो से उनके मतो मे भिन्नता दिखाई पड़ती है ।[87] नेहरु जी के समाजवादी चिन्तन का क्रमबद्ध विकास सन् 1929 के लाहौर अधिवेशन से प्रारम्भ होता है, जिसमे कांग्रेस ने "पूर्ण स्वाधीनता" का प्रस्ताव पारित किया है लाहौर अधिवेशन मे नेहरु जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण मे कहा कि मैं स्पष्ट रुप से यह स्वीकार करता हूॅ कि मै समाजवादी और लोकतन्त्र वादी हूॅ और राजा महाराजाओ मे मेरी कोई आस्था नही है, और नही मेरी उस प्रणाली मे निष्ठा है जिसमे जिसके परिणाम स्वरुप उद्योगो मे आजकल के राजा (पूॅजीपति) पैदा होते है ।[88] इस भाषण से स्पष्ट होता है कि नेहरु जी की समाजवाद मे निष्ठा थी, पर देश की परिस्थितियो को देखकर उन्होने अपने भाषण मे कहा कि हमारे समक्ष तीन बडी समस्याए हैं अल्पसख्यक,देशी नियासते और मजदूर तथा किसान ।इन समस्याओ पर नेहरु जी ने समाजवादी तरीके से विचार किया और इन्हें हल करने का भी प्रयत्न किया ।[89]

झासी प्रान्तीय राजनीतिक अधिवेशन (27 अक्टूबर 1927 ई0) मे नेहरु जी ने अपने समाजवादी चिन्तन का स्पष्टीकरण करते हुए यह कहा कि "हम लोगो के सभी बुराईयो का एक ही निदान है और यह है समाजवाद । इसलिए हमारा ध्येय समाजवाद होना चाहिए ।समाजवाद की स्थापना एक दिन मे नही हो सकती, किन्तु धीरे-धीरे नीति का निर्धारण करके अमीर-गरीब की दूरी कम की जा सकती है और अर्थिक शोषण तथा आर्थिक विषमता को समाप्त किया जा सकता है ।इस समय देश मे औद्योगीकरण का विकास हो रहा था, इसलिए नेहरु जी ने श्रमिको की समस्या की ओर विशेष ध्यान दिया और उन्हे अनेक सुविधाए देने की बात कही।[90]

---

87 - डोरोथी नार्मन - नेहरु, खण्ड 1, पृष्ठ 377

88 - काग्रेस प्रेसीडेन्सल एड्रेसेज (स) खण्ड 2, पृष्ठ 395-897, दिसम्बर 1929

89 - नेहरु जी ने अपने समाजवादी विचारो को कार्यरुप देने का प्रयत्न किया । उन्होने देशी रियाशतो के उन्मूलन, उद्योगो के विकास व कृषि सुधार कार्यक्रम पर विशेष बल दिया । नेहरु -व्यक्तित्व और विचार (स), पृष्ठ 402

90 - नेहरु-व्यक्तित्व और विचार, (स) पृष्ठ 392

नेहरु जी ने अपने समाजवादी चिन्तन का निरन्तर विकास किया । सन् 1934 मे जब काग्रेस मे एक समाजवादी दल बना तो नेहरु जी ने उसकी सदस्यता स्वीकार न करते हुए उस दल के समाजवादियो का समर्थन प्राप्त किया। मई 1934 मे नरेन्द्र देव की अध्यक्षता मे समाजवादी दल का पहला अधिवेशन पटना मे हुआ जिससे नरेन्द्र देव के अलावा, जय प्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन सम्पूर्णनन्द, अशोक मेहता आदि प्रमुख समाजवादियो ने भाग लिया ।[91] विभिन्न विद्वानो का मत है कि अब तक नेहरु जी मार्क्सवाद से प्रभावित थे और अपने लेखो तथा भाषणो मे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, पूँजीवाद, वर्ग-सघर्ष, औद्योगिककरण आर्थिक असमानता आदि प्रश्नो पर मार्क्सवादी तरीके से विचार रखते थे ।[92] राय अखिलेन्द्र प्रसाद ने इस सम्बन्ध नेहरु जी द्वारा लिखित "भारत किधर" नामक लघु पुस्तिका का उल्लेख किया, जिसमे नेहरु जी ने [93] उस समय के अपने समाजवादी विचारो को व्यक्त किया है । नेहरु जी पर गॉधी के व्यक्तित्व के प्रभाव को इगति करते हुए एम एन राय [94] और सुभाष चन्द्र बोस ने उनका विरोध किया है । सुभाष चन्द्र बोस ने लिखा है- नेहरु अपने को समाजवादी क्रान्तिकारी कहते है, पर वे व्यवहार मे महात्मा गॉधी के वफादार अनुयायी हैं ।सम्भवत यह कहना कठिन होगा कि उनकी बुद्धि वामपथियो के साथ है, पर हृदय महात्मा गॉधी के साथ [95]

सन् 1936 के बाद नेहरु जी के समाजवादी चिन्तन मे एक नया मोड आया । लखनऊ काग्रेस के 49वे अधिवेशन मे अपने अध्यक्षीय भाषण मे उन्होने कहा "समाजवाद एक आर्थिक सिद्धात है ।वह समाज मे उत्पादन, वितरण तथा अन्य क्रियाओ को सगठित करने का एक तरीका है, इसके समर्थको के अनुसार समाज की मौजूदा बुराइयो से मुक्ति दिलाने का उपाय है।[96] नेहरु जी का विश्वास था कि भारत की आर्थिक असमानता को समाजवाद की स्थापना करके ही दूर किया जा सकता है। वे कहते है कि "मै उस मूल आर्थिक सिद्धात मे विश्वास रखता

---

91 - एम एन दास -दि पोलिटिकल फिलास्फी आफ प0 जवाहरलाल नेहरु, पृष्ठ 129

92 - पट्टाभि सीता रमैया काग्रेस का इतिहास, खण्ड 1, पृष्ठ 455

93 - नेहरु जी के जीवनी लेखक सर्वपल्ली गोपाल ने लिखा है कि नेहरुजी के प्रारम्भिक समाजवादी विचार अस्पष्ट थे । 1929 ई0 के बाद वे मार्क्सवाद- लेनिनवाद के निकट आ गये और उन्होने गाँधी जी के खादी कार्यक्रम तथा ट्रस्टीशिप सिद्धात की आलोचना की थी ।सर्वपल्ली गोपाल-'जवाहर लाल नेहरु खण्ड 1, पृष्ठ 52-55,1933

94 - रायअखिलेन्द्र प्रसाद-सोशलिस्ट थाट इन माडर्न इण्डिया, पृष्ठ 72 नेहरु भारत किधर' (-नेहरु आन सोशलिज्म मे सकलित), पृश्इ 712-715

95 - सुभाष चन्द्र बोस- दि इडियन स्ट्रगल, पृष्ठ 39

96 - डोरोथी नार्मन-(स), नेहरु दि फर्स्ट सिक्सटी ईयर्स, पृष्ठ 450

हूँ जो रुस के सामाजिक ढ़ाँचे का आधार है । मै यह भी सोचता हूँ कि रुस ने सास्कृतिक और औद्योगिक यहाँ तक कि आध्यात्मिक दृष्टि से उल्लेखनीय प्रगति की है ।[97] वे मार्क्सवादी लेनिनवादी व्यवस्था को पूर्ण रुप से स्वीकार करने के पक्षधर नही थे । उन्होने विजयलक्ष्मी पण्डित को एक पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि मै रुस मे जो कुछ हुआ उसे ज्यो का त्यो न तो स्वीकार करता हूँ और न ही समर्थन देता हूँ । मै रुस का अन्धानुकरण नही करना चाहता, इसलिए मै साम्यवाद के स्थान पर समाजवाद शब्द का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त समझता हूँ।[98] इससे स्पष्ट है कि नेहरु जी भारत के लिए साम्यवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना उपयुक्त मानते है । उनका विश्वास था कि भारत मे गरीबी और बेकारी की जटिल समस्या को हल किये बिना समाजवाद की स्थापना असम्भव है । वे भारत की समस्या का एक मात्र समाधान समाजवाद को ही मानते है, इसलिए उसने अपने समाजवाद का आधार भारत की आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि को बनाया । उनका विचार था कि मै समाजवाद के अतिरिक्त कोई अन्य दूसरा मार्ग नही देखता, जो गरीबी, अपमान और दासता से भारत के लोगो को मुक्ति दिला सके। लेकिन नेहरु जी ने अपने समाजवादी विचारो को काग्रेस पर जबरन थोपने[99] का प्रयास नही किया फिर भी उन्होने यह प्रयत्न अवश्य किया कि काग्रेस अपने कार्यक्रमो का सचालन समाजवादी ढॉचे के अनुरुप ही करे।

नेहरु ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के आलोचक है, वे कहते है कि ब्रिटिश पूजीवाद का अन्त किये बिना समाजवाद की स्थापना सम्भव नही है । वे फासीवाद को विचित्र खिचडी बताकर उसका कडा विरोध करते है ।[100] अपनी पुस्तक "विश्व इतिहास की झलक" मे उन्होने साम्राज्यवाद और फासीवाद दोनो की कडी आलोचना की है ।

नेहरु जी के समाजवादी चिन्तन की यह विशेषता रही है कि उन्होने समाजवाद और राष्ट्रीयता मे समन्वय स्थापित किया । समाजवाद के मुद्दे पर उनका गॉधी के अतिरिक्त, नरेन्द्र

---

97 - लियोनाद मिटोनिक (स) इण्डियाज ग्रेटसन्, पृष्ठ 7

98 - डोरोथी नार्मन (स), नेहरु फर्स्ट सिक्सटी ईयर्स, पृष्ठ 410

99 - नेहरु- व्यक्तित्व और विचार, पृष्ठ 403

100 - प0 जवाहरलाल नेहरु- विश्व इतिहास की झलक खण्ड 2, पृष्ठ 1136-37

देव, जय प्रकाश नारायण, सुभाष चन्द्र बोस, डा0 राजेन्द्र प्रसाद, बल्लभ भाई पटेल, एम0 एन0 राय आदि नेताओ से उनका वैचारिक मतभेद हुआ ।[101]

नेहरु जी ने अपने निबन्ध "लखनऊ से त्रिपुरी तक" मे सन् 1936 ई0 से 1939 ई0 तक की देश की राजनीतिक घटनाओ पर प्रकाश डाला है [102] इसमे हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन (1938) का विवरण शामिल है, जिसमे सुभाष चन्द्र बोस गाधी जी की इच्छा के विरुद्ध काग्रेस के अध्यक्ष चुने गये । इसी समय से नेहरु और काग्रेसी समाजवादियो के बीच टकराहट आरम्भ हो गयी और एक बार उन्होने यहॉ तक कह दिया कि "स्वाधीनता से पहले कोई समाजवाद नही हो सकता । वास्तव मे नेहरु जी ने गाधीवादियो और समाजवादियो दोनो को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया "। उन्होंने लिखा है कि-मैंने इसकी पूरी कोशिश की कि पुराने नेताओ और नये समाजवादी गुट मे कोई समझौता करा सकूँ, क्योकि मेरा ऐसा विचार है कि साम्राज्यवाद से लड़ने मे दोनो की जरुरत है ।[103] इस प्रकार नेहरु जी ने काग्रेस के अन्दर की दोनो विचारधाराओं को एक साथ लेकर चलने का प्रयत्न किया, फिर भी उनमे मेल कराने मे सफल नही हो सके ।

स्वाधीनता के बाद भी नेहरु जी के समाजवादी चिन्तन मे प्रजातात्रिक समाजवाद की झलक दिखाई देती है । प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होने अपने भाषण मे कहा कि जिन आर्थिक व सामाजिक समस्याओ को दूर करने का आवश्वास दिया उनके मूल मे उनकी समाजवादी भावना निहित है । इन समस्याओ मे आर्थिक विषमता का उन्मूलन, गरीबी का निकास, किसानों और मजदूरो को सुविधाए जन साधारण के लिए भोजन, आवास व वस्त्र आदि की उपलब्धता आदि मुख्य है ।[104]

सन् 1950 मे नेहरु जी ने अपने समाजवादी विचारो को व्यवहारिक रुप देने के लिए पचवर्षीय योजनाओ का कार्यक्रम प्रारम्भ किया ।योजना आयोग [105] द्वारा प्रथम योजना (1951-56) बनायी गयी जिसमे मुख्यत· अधूरे काम पूरा करने का प्रयत्न किया गया । साथ ही युद्ध के

---

101 - प0 जवाहरलाल नेहरु- कुछ पुरानी चिट्ठियाँ पृष्ठ 150-152, वाई0 जी0 कृष्णमूर्ति -जवाहरलाल नेहरु, पृष्ठ 27-28

102 - नेहरु जी का यह निबन्ध "दि युनिटी आफ इण्डिया " नामक पुस्तक मे सकलित है ।

103 - वही, पृष्ठ 95-98

104 - डोरीथी नार्मन- नेहरु दि फर्स्ट सिक्सटी ईयर्स, खण्ड 2, पृष्ठ 338

105 - योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ई0 को की गयी जिसके पहले अध्यक्ष प0 जवाहर लाल नेहरु थे ।

बाद की स्थिति से जटिल सकट का सामना करने का भी प्रयत्न किया गया। आजादी देश विभाजन के साथ मिली, और इसलिए सारे देश मे भारी अफरा-तफरी मच गयी इतिहास का सबसे बड़ा जनसख्या हस्तान्तरण हुआ और बड़े पैमाने पर शरणार्थियो के आने से समस्या और गभीर हो गयी ।इन्हीं समस्याओ के मद्देनजर नेहरु अपनी नीतियों से समझौता करते गये । काग्रेस दल के समाजवादी भी इन्ही सब कारणो से नाराज हुए, उन्हे लगा कि समाजवाद के आदर्शों को जानबुझकर के नाकारा जा रहा है । दूसरे यह भी कि मन्त्रिमडल मे बल्लभ भाई पटेल के होने के कारण नेहरु अपने चरम लक्ष्य को कार्य रुप मे प्रदान करने मे अपने को असमर्थ पा रहे थे। पटेल जी के निधन के उपरान्त समाजवादी दल ने अपने 14 सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर काग्रेस से सहयोग करने का निश्चय किया, परन्तु नेहरु ने इस सबन्ध मे अपनी असमर्थता प्रकट की । यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पटेल की मृत्यु के बाद नेहरु जी स्वय चार वर्ष तक काग्रेस के अध्यक्ष रहे । परन्तु काग्रेस के किसी भी प्रस्ताव मे उन समाजवादी आदर्शों का कोई सकेत मात्र नही था जिसके संबंध मे नेहरु जी सन 1927 से चर्चा करते आ रहे थे ।दूसरी योजना (1956-61) मे प्रसिद्ध नेहरु-महालनोबिस विकास रणनीति लागू की गयी जो तीसरी योजना (1961-66) मे भी जारी रही । प्रो0 पी0 सी0 महालनोबिस ने द्वितीय योजना तैयार करने मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । इस रणनीति का एक मूलतत्व भारी तथा मूल वस्तुओ के उद्योगो का विकास था, जो मुख्यत सार्वजनिक क्षेत्रों मे होना था ।[106] भारी उद्योगो के विकास के साथ-साथ श्रम-गहन छोटे और गृह उद्योगो का विकास भी तय पाया गया ताकि उपभोक्ता वस्तुओ का उत्पादन किया जा सके ।यह समझा गया कि सामुदायिक विकास योजनाओ के तहत कृषि मे सामुदायिक कार्यक्रम के जरिये श्रम का अधिकाधिक उपयोग करेगे और पूँजी का उत्पादन करेगे। इनमे कृषि सहकारिताओ की अपनी भूमिका होगी ।[107] लेकिन बेकारी की समस्या के समाधान हेतु कोई समुचित उपाय नही ढूढ़ा गया ।

नेहरु-महालनोबिस रणनीति का एक और महत्वपूर्ण अग विकास और समानता पर जोर था । इसलिए उद्योग और खेती मे सकेन्द्रण और वितरण के प्रश्न पर काफी

---

106 - बिपिन चन्द्र पाल (स)- "आजादी के बाद भारत" (1947-2000), पृष्ठ 455

107 - विपिन चन्द्र पाल (स0) "आजादी के बाद भारत "(1947-2000), पृष्ठ 455-56

ध्यान दिया गया, हालाकि इसमे अपेक्षित सफलता नही मिली। रणनीति मे विकास तथा समानता को एक दूसरे का विरोधी नही समझा गया। यह माना गया कि उच्चतर विकास से समानता के उच्चतर स्तरो तक पहुँचा जा सकता है।

दूसरी पचवर्षीय योजना मे भी वही नीति अपनायी गयी जो पहली योजना मे थी। इसमे कृषि के स्थान पर उद्योगो को प्राथमिकता प्रदान की गयी, परन्तु सामाजीकरण और राष्ट्रीय करण की नीति के सम्बन्ध मे कोई स्पष्ट नीति नही थी,बल्कि जिस विचार को उन्होने पहली योजना मे रखा था,उसी को फिर दोहराया गया।

सन् 1955 ई0 मे अवाड़ी मे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमे यू0 एन ढेब़र की अध्यक्षता मे नेहरु सहित काग्रेस ने, समाजवादी समाज की रचना का लक्ष्य स्वीकार किया। परन्तु इसके विपक्ष मे कुछ समाजवादी और साम्यवादियो ने काग्रेस पर यह आरोप लगाया कि यह मात्र मत प्राप्त करने का तरीका है। इस सिद्धात मे इस लक्ष्य को स्वीकार किया गया कि उत्पादन, सामाजिक स्वामित्व अथवा नियन्त्रण मे होगा तथा उत्पादन मे तीव्रता से वृद्धि और राष्ट्रीय आय का समता के आधार पर वितरण किया जायेगा। लेकिन समाजवाद और समाजवादी आधार पर समाज की रचना मे काफी अन्तर है इस सम्बन्ध मे नेहरु जी का प्रश्न नकारात्मक है, अप्रैल 1955 मे नेहरु जी ने कहा था कि जनता को समाजवाद के सिद्धान्तो और समाजवादी आधार पर समाज की स्थापना मे कुछ विशेषता ही मिलेगी, न कि अन्तर। दोनो वस्तुए एक ही है इसमे किसी भी प्रकार का सूक्ष्म अन्तर नही है, लेकिन दोनो की व्याख्या करना कोई आसान कार्य नही है। किसी भी सिद्धात की व्याख्या करना एक कठिन कार्य होता है और उस व्याख्या की चरम स्थिति एक ऐसे स्थान पर पहुँच जाती है जहाँ वह सिद्धात ही शुष्क और धूमिल पड़ने लगता है। लेकिन इसका यह अभिप्राय नही होता कि हम समाजवादी समाज के सिद्धान्तो का विश्लेषण ही नही करेगे। यह सत्य है कि इस सिद्धात को वास्तविक क्रियात्मक रुप प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता तो अवश्य ही एक अच्छे मार्ग का निर्माण हो सकता था।

सन् 1954 मे अपनी चीन यात्रा के दौरान नेहरु ने वहाँ की आर्थिक प्रगति को देखा तथा उसी प्रकार की तीव्र प्रगति की कल्पना भारत के सन्दर्भ मे भी करने लगे। लेकिन नेहरु को चीन की शासन व्यवस्थ और भारतीय शासन व्यवस्था मे स्पष्टत· भिन्नता दिखाई पडी। फिर भी वे

इस बात पर सोचने को मजबूर हो गये कि ससदीय (प्रजातान्त्रिक) प्रणाली से अधिक आर्थिक उन्नति की जा सकती है या साम्यवाद व्यवस्था के अन्तर्गत । नेहरु अपने समाजवादी समाज की स्थापना जनतान्त्रिक आधारो पर करना चाहते थे । इस समय तक नेहरु जी के विचारो मे काफी भिन्नता आ गयी थी । अब नेहरु किसी आर्थिक सिद्धात की घोषणा न करके मध्यम वर्ग का अनुकरण करने लगे थे।सन् 1958 ई0 मे उन्होने कहा था कि मै किसी प्रकार के राज्य समाजवाद को पसन्द नही करता हूँ, जिसमे राज्य ही सर्वे-सर्वा हो तथा व्यवहार मे प्रत्येक क्रिया पर शासन करे । राज्य राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली होता ही है । मेरा समाजवाद के सम्बन्ध मे विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होने चाहिए ।[108]

सन् 1964 ई0 मे काग्रेस के भुवनेश्वर अधिवेशन मे नेहरु जी ने जो वक्तव्य दिया,[109] उससे स्पष्ट होता है कि उनके समाजवादी चिन्तन मे एक नया मोड आ गया है । अब वे लोकतान्त्रिक समाजवाद के हामी बन गये जो कि व्यक्ति की गरिमा और सामाजिक न्याय पर आधारित है ।[110] इस अधिवेशन मे जो प्रस्ताव पारित हुआ उसके अनुसार लोकतत्र और उसकी विचार धारा समाजवाद का साधन है। समाजवाद के इस नये रुप को विद्वानो ने नेहरु का समाजवाद कहकर पुकारा है । जिसमे व्यक्ति का सम्मान,लोकतान्त्रिक व्यवस्था और मानवतावादी दृष्टि की प्रधानता है ।[111]

नेहरु जी का समाजवादी चिन्तन विकासमान रहा है ।[112] प्रारम्भ मे वे एक कल्पनावादी समाजवादी के रुप मे, हमारे सामने आते है, पुन मार्क्सवाद-लेनिनवाद से प्रभावित होकर वे वैज्ञानिक समाजवाद का समर्थन करने लगते है। द्वितीय विश्वयुद्ध शुरु होने के बाद वे गॉधीवाद से प्रभावित होकर अपने समाजवादी चिन्तन मे आध्यात्मिकता को प्रथम स्थान देने लगते है और स्वाधीनता के बाद वे लोकतान्त्रिक समाजवाद समर्थक हो जाते है । नेहरु जी के समाजवादी

---

108 _ माइकेल ब्रेचर -' ए पोलिटिकल बायोग्राफी आफ जवाहर लाल नेहरु, पृष्ठ 204

109 _ भुवनेश्वर अधिवेशन मे नेहरु जी ने स्पष्ट रुप से कहा था कि भारत एक समाजवादी राज्य होगा ।अभय राव, बी0 जी0 राव- सिक्स थाउजेन्ड डेज, पृष्ठ 20

110 _ डा0 शोभा शकर- आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन, पृष्ठ 122

111 _ सोशलिज्म इन इण्डिया (स), पृष्ठ 18

112 _ पी0 डी0 कौशिक ने स्वाधीनता के पूर्व की काग्रेस की समाजवादी विचारधारा के विकास को तीन चरणो 1920-1929, 1929-1934 और 1934-1937 मे बाँटा है । स्वाधीनता के बाद इसके दो चरणो अवाड़ी अधिवेशन से पूर्व और अवाड़ी अधिवेशन के बाद और जोड़े जा सकते है । दि काग्रेस आइडियोलोजी एण्ड प्रोग्राम, पृष्ठ 127 डा0 शोभाशकर- आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन पृष्ठ 123

विचारो की समीक्षा करते हुए अनेक विद्वानो ने यह मत व्यक्त किये है कि स्वाधीनता से पूर्व नेहरु जी के समाजवादी विचार जितने प्रखर थे उतने प्रधान मत्री बनने के बाद नही रहे।[113] नम्बूदरीपाद जैसे कुछ साम्यवादी नेताओ ने नेहरु के समाजवादी विचारो की आलोचना की है।[114] माइकेल ब्रेचर ने उनके समाजवादी चिन्तन को उलझन भरा बताया है ।[115] लेकिन इस आलोचनाओ मे सत्यता कम है, वास्तव मे नेहरु जी ने अपने समाजवादी चिन्तन को अपने लेखन द्वारा स्पष्ट करने की चेष्टा की है ।वे मुख्यत एक लोकतान्त्रिक समाजवादी हैं और वे लोकतान्त्रिक मूल्यो के आधार पर नये भारत का निर्माण करना चाहते है ।[116]

V- आचार्य नरेन्द्र देव :(सन् 1889-1956 ई0)

आचार्य नरेन्द्र देव समाजवाद के प्रारम्भिक चिन्तको में से थे । बीसवी शताब्दी के प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् जब समाजवादी विचारो का हमारे देश मे विकास होने लगा तब नरेन्द्र देव ने इसे न केवल स्वीकार किया वरन् आगे बढाने मे भी अग्रणी रहे । प्रारम्भ मे वे कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे और उन्होने कांग्रेस मे रहकर समाजवादी विचारो को आगे बढाने की सफल कोशिश की लेकिन बाद मे उन्होने यह अनुभव किया कि भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस की नीतिया उनकी समाजवादी धारणओ से भिन्न थी । अत भारत के स्वतन्त्रता के पश्चात् वे काग्रेस से अलग हो गये तथा काग्रेस से पृथक होकर समाजवादी आन्दोलन को आगे बढाने मे प्रयत्नशील हो गये । काग्रेस के साथ रहकर और काग्रेस से पृथक होकर उन्होने अनेको गतिविधियो का संचालन किया ।

नरेन्द्र देव पर अपने विद्यार्थी जीवन से ही देश की राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियो का प्रभाव पडने लगा था ।[117] 1906 मे जब उन्होने मेयो सेन्ट्रल कालेज मे प्रवेश लिया तो वहाँ का हिन्दू बोर्डिग हाउस उग्रवादी विचारो का केन्द्र बना हुआ था । वहॉ की उग्रवादी विचारधाराओ ने

---

113 - अभय राव, बी0 जी0 राव- सिक्स थाउजेन्ड डेज, पृष्ठ 5

114 - रफीक जकारिया-ए स्टडी आफ नेहरु, पृष्ठ 272

115 - माइकेल ब्रेचर (स)-नेहरु पोलिटिकल बायोग्राफी, पृष्ठ 597

116 - जवाहर लाल नेहरु-यूनिटी आफ इण्डिया, पृष्ठ 110 वही- इन्डीपेन्डेन्स एण्ड आफ्टर, पृष्ठ 231 नेहरु के भाषण-(1949-1953) वही,- (1953-1957) इन भाषणो मे नेहरु जी के लोकतान्त्रिक समाजवादी विचारो की झलक मिलती है ।

117 - राय अखिलेन्द्र प्रसाद -सोशलिस्ट थाट इन माडर्न इण्डिया, पृष्ठ 89

उन्हे प्रभावित किया ।[118] आचार्य नरेन्द्र देव ने अपना राजनीतिक जीवन तिलक एव अरविन्द के अतिवादी राष्ट्रवाद के अनुयायी के रुप मे शुरु किया । गॉधी जी द्वारा असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ करने पर वे उसमे सम्मिलित हुए । सन् 1934 ई0 मे उन्होने अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी के उद्‌घाटन का सभापतित्व किया। आचार्य नरेन्द्र देव की गणना भारत के प्रमुख समाजवादी बुद्धिजीवियो तथा प्रचारको मे की जाती है ।[119] उनकी भारतीय किसान आन्दोलन मे भी काफी गहरी रुचि थी । वे अखिल भारतीय किसान सभा के सस्थापको मे से थे । दो बार उनको इस सभा का अध्यक्ष बनाया गया । वे कई वर्ष तक अखिल भारतीय काग्रेस समिति की कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहे ।वे इस पक्ष मे नही थे कि समाजवादी काग्रेस से पृथक हो,किन्तु दल के निर्णय के आगे उन्हे झुकना पडा ।[120]

नरेन्द्र देव जी गॉधी जी से प्रभावित थे, गॉधी जी के साथ उनका घनिष्ठ सबन्ध था और गॉधी जी पर उनका व्यक्तिगत स्नेह भी था।नरेन्द्र देव जी नैतिक समाजवादी थे इस कारण वे नैतिक मूल्यो को प्राथमिकता देते थे । वे समाजवाद को एक सास्कृतिक आन्दोलन भी मानते थे, इसलिए उन्होने समाजवाद के मानववादी आधार पर बल दिया ।उन्होने हिन्दू तथा बौध चिन्तन का गंभीर अध्ययन किया था, जिसके फलस्वरुप मूल्यों की पवित्रता मे उनकी आस्था अधिक गहरी हो गयी थी ।[121] उन्होने सत्य की व्यवहारवादी कसौटी को स्वीकार करने से स्पष्टत इन्कार कर दिया । उनकी दृष्टि मे सत्य प्राथमिक तथा बुनियादी चीज थी किन्तु इसके बावजूद वे गॉंधी जी के अहिंसा के सिद्धात को समग्र रुप मे मानने के लिए तैयार नही थे ।[122]

नरेन्द्र देव जी विचारधारा की दृष्टि से मार्क्सवादी थे । यद्यपि उन्होने द्वन्दात्मक भौतिकवाद के दर्शन की विशद व्याख्या नही की फिर भी उन्होने उसके सामान्य सिद्धातो का विवेचन किया। उनका कहना था कि वास्तविकता जटिल है, किन्तु द्वन्दात्मक पद्धित वास्तविकता

118 - जी0 एस0 भार्गव- लीडर्स आफ दि लेफ्ट, पृष्ठ-25-26

119 - विश्वनाथ प्रसाद वर्मा- 'आधुनिक भारतीय राजनीति चिन्तन", पृष्ठ 530

120 - नरेन्द्र देव ने कहा कि अगस्त 1947 तक काग्रेस एक राष्ट्रीय मोर्चा थी, अब वह अपने इस रुप को खो बैठी है और एक पार्टी बन गयी हैं । उन्होने काग्रेस की सत्तावादी तथा केन्द्रीकरण की प्रवृत्तियो की आलोचना की। आचार्य नरेन्द्र देव-"राष्ट्रीयता और समाजवाद' पृष्ठ 317-19

121 - "विश्वनाथ प्रसाद वर्मा' -"आधुनिक भारतीय राजनीति चिन्तन" पृष्ठ 531

122 - विश्वनाथ प्रसाद वर्मा-"आधुनिक भारतीय-राजनीति चिन्तन, पृष्ठ 531

को उसके समग्र तथा जटिल रुप मे समझने का प्रयत्न करती है।[123] वे द्वन्दवाद के सिद्धात तथा पद्धित को स्वीकार करते थे, किन्तु उसमे सन्देह है कि वे मार्क्सवादी के रुप मे भौतिकवाद के समग्र दर्शन को अंगीकार करने के लिए उद्धत थे। फिर भी वे मार्क्सवाद को भौतिकवादी एकत्ववाद वे रुप मे मानते थे और गति की सार्वभौमिकता को स्वीकार करते थे,जिसका अर्थ है कि विश्व एक प्रक्रिया है। नरेन्द्रदेव जी वैज्ञानिक समाजवादी होने का दावा करते थे।उनका कहना था,"हमारे सामने जो काम है उसे हम तभी पूरा कर सकते है जब हम समजावाद के सिद्धांत और उद्देश्यो को हृदयगम कर ले तथा परिस्थितियो को सही ज्ञान के लिए मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वन्दात्मक पद्धति को समझे और उसे अपने कार्यकलाप का आधार बनाने का प्रयत्न करे। हमे वैज्ञानिक समाजवाद का आश्रय लेना चाहिए,और यूटोपियाई समाजवाद अथवा सामाजिक सुधारवाद से बचने का प्रयास करना चहिए। विद्यमान सामाजिक व्यवस्था का क्रान्तिकारी रुपातर ही परिस्थितियो की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। उससे कम किसी चीज से काम नही चल सकता।[124]

नरेन्द्र देव जी बुखारिन की प्रसिद्ध पुस्तक "हिस्टोरिकल मैटीरियलिज्म" (ऐतिहासिक भौतिकवाद) से काफी प्रभावित थे। उन्होने बुखारिन की वर्गो की कसौटी तथा विभाजन के सिद्धात को स्वीकार किया। उसकी भॉति वे भी मानते थे कि समाज मे पूँजीपतियो तथा सर्वहारा के अतिरिक्त अन्य वर्ग भी होते है, जैसे-मध्यमवर्ग, सक्रमणवर्ग तथा मिश्रित वर्ग।[125] लोकतान्त्रिक समाजवाद के समर्थक होने के नाते नरेन्द्र देव राज्य के नौकरशाही हस्तक्षेप के विरुध थे। इसलिए उनका प्रस्ताव था कि मजदूरो का एक वर्ग के रुप मे उद्योग के प्रबन्ध मे साझा होना चाहिए। यद्यपि उनका गाधी जी से घनिष्ठ सम्बन्ध था,फिर भी उन्होने वर्ग-सघर्ष के सिद्धांत का परित्याग नही किया[126] नरेन्द्र देव जी ने भारत की सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओ को

---

123 - नरेन्द्र देव -सोशलिज्म एण्ड नेशनल रिवोल्यूशन, पृष्ठ 148

124 - वही, पृष्ठ 24-25

125 - वही, पृष्ठ 417-19

126 - नरेन्द्र देव ने यहाँ तक कह दिया कि गॉधीवादी हिंसा वर्ग विहीन समाज मे अन्तत पर्यवसित होने की क्षमता रखती है। अहिसा ब्रत के अपने इस अनुसधान से गॉधीवाद को यह तथ्य मिला है कि वर्ग भेदो और सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओ को मिटाये बिना समाज मे से हिंसा का उन्मूलन सभव नही है। अत वर्ग विहीन समाज इसका ध्येय है और समत्व युक्त समाज की एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था इसे करनी है जिससे जनतन्त्र का भाव नष्ट न हो जाये और मनुष्य की

वर्ग सघर्ष की दृष्टि से समझने का प्रयत्न किया । वे इस पक्ष मे थे कि निम्न मध्यम वर्गो तथा सामान्य जनता के बीच मैत्री सम्बन्ध कायम किये जाय । उनका कहना था कि साधारण जन समुदाय अनुसघनीय अधिकारो तथा लोक प्रभुत्व के सामान्य सिद्धान्तो से आकृष्ट नही हो सकता । उसमे वर्ग चेतना तभी उत्पन्न हो सकती है जबकि उससे आर्थिक हितो की भाषा मे बात किया जाय।[127]

समाजवादी क्रान्ति के सम्बन्ध मे नरेन्द्र देव जी लेनिन के विचार से सहमत थे । लेनिन के अनुसार यह अनिवार्य नही है कि समाजवादी क्रान्ति पहले उस देश मे हो जो औद्योगिक दृष्टि से सबसे अधिक विकसित है वह तो उस देश मे होगी जहॉ साम्राज्यवादी श्रृखला सबसे दुर्बल है।[128] नरेन्द्र देव जी श्रमिक वर्ग को साम्राज्यवाद-विरोधी सघर्ष का हिरावल (अग्रगामी टुकड़ो) तथा किसानो और बुद्धिजीवियो को उसका सहायक मानते थे ।[129] उन्हे कोरे सुधारवाद और सविधानवाद से सहानुभूति नही थी ।[130] उनका कहना था कि "जन समुदाय को क्रियाशील बनाने तथा देश को लोकतन्त्र के लिए तैयार करने का एक मात्र उपाय यह है कि किसी लोक हितकारी आर्थिक विचारधारा को अगीकार करके राष्ट्रीय सग्राम का समाजीकरण किया जाय।[131]

नरेन्द्र देव जी ने समाजवादी आन्दोलन तथा राष्ट्रीय आन्दोलन के बीच सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे चाहते थे कि समाजवादियो को राष्ट्रीय मुक्ति सग्राम मे सम्मिलित होकर अपनी भूमिका निभानी चाहिए । यदि वे अपने को राष्ट्रीय आन्दोलन से पृथक रखते है तो उनका यह कार्य आत्म हत्या करने के समान होगा । उन्होने समाजवादियो को यह मानने की सलाह दी कि एक औपनिवेशिक देश के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता समाजवाद के मार्ग मे एक अपरिहार्य अवस्था है ।[132]

सर्वश्रेष्ठता स्थापित हो ।" (नरेन्द्रदेव- राष्ट्रीयता और समाजवाद, पृष्ठ 740, विश्वनाथ प्रसाद वर्मा -आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, पृष्ठ 532 से उद्धृत)

127 - नरेन्द्र देव- ' सोशलिज्म एण्ड नेशनल रिवोल्यूशन, पृष्ठ 8

128 - वही, पृष्ठ 22-23

129 - वही, पृष्ठ 23

130 - वही, पृष्ठ 28

131 - वही, पृष्ठ 29-30

132 - नरेन्द्र देव- "सोशलिज्म एण्ड नेशनल रिवोल्यूशन' पृष्ठ 4

नरेन्द्र देव जी ने काग्रेस के अगस्त 1948 के प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि यह प्रस्ताव स्वतन्त्रता के सामाजिक पहलू की व्याख्या करता है ।[133] वह खेतो तथा कारखानो की सम्पूर्ण शक्ति को श्रमिक वर्ग मे निहित करना चाहता है । उनकी दृष्टि मे अगस्त प्रस्ताव का उद्देश्य जन साधारण की सर्वोच्चता स्थापित करना था ।

नरेन्द्र देव जी जन समुदाय की एकता के समर्थक थे। वे चाहते थे कि जन समुदाय की क्रान्तिकारी भावना को तीव्र किया जाय और उन्होने स्वय जनता को क्रान्तिकारी कार्यवाही के लिए उत्तेजित करने का कार्य किया ।[134]उनका विचार था कि सामाजिक तथा आर्थिक मुक्ति के जिस कार्य को पश्चिमी यूरोप मे अठारहवी शताब्दी मे पूँजीपतियो ने किया था, उसे भारत मे शोषित जनता के सगठन के द्वारा सम्पादित करना होगा ।[135] उनकी दृष्टि मे भारतीय स्वतन्त्रता सग्राम के आधार को व्यापक बनाने के लिए जनता मे रचनात्मक कार्य करना आवश्यक था ।[136] भारत मे ब्रिटिश साम्राज्यवाद देशी राजाओ, पूँजीपतियो तथा सामन्तो की सहायता से अपनी जडो को मजबूत करने का प्रयत्न कर रहा था । इस प्रकार शोषण की व्यवस्था के स्तम्भो को दृढ बनाया जा रहा था ।पूँजीपतियो ने भी जमीदारो के साथ समझौता कर लिया था । प्रति क्रान्तिकारी शक्तियो के इन गठबन्धनो ने शोषित जनता के कार्य को भी कठिन बना दिया था। उसे देश की राजनीतिक तथा आर्थिक दोनो प्रकार की मुक्ति के लिए सघर्ष करना था। ऐसी स्थिति मे औद्योगिक मजदूरो, किसानो तथा निम्न मध्यम वर्ग का सयुक्त मोर्चा आवश्यक हो गया था ।इसी प्रकार आर्थिक तथा राजनीतिक सघर्ष सफलता की अधिक आशा के साथ चलाया जा सकता था ।इसीलिए नरेन्द्र देव जी ने देश के स्वाधीनता सग्राम के आधार को मजबूत बनाने पर बल दिया । उन्हे आशा थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त ससार मे अनेको जन क्रान्तियाँ होगी।[137]

नरेन्द्र देव जी भारतीय कृषको के बहुत हिमायती थे । वे उनका पुनिर्निमाण करना चाहते थे । इसलिए उन्होने किसानो के आर्थिक अधिकारो की प्राप्ति के लिए किसान सभाओ को

133 - वही, पृष्ठ 167

134 - वही,पृष्ठ 149

135 - वही, पृष्ठ 68-69

136 - वही, पृष्ठ 87

137 - विश्वनाथ प्रसाद वर्मा आधुनिक भारतीय राजनीतिक चि त-I, पृष्ठ 533

सगठित किया । उनका आग्रह था कि सभी प्रकार के किसानो की शक्तियो को एक जुट किया जाय ।भारत मे किसानो तथा खेतिहर मजदूरो की समस्याए बड़ी विकराल थी ।जो जन समुदाय खेती-बाड़ी मे लगा हुआ था उनका अत्यधिक गरीबी से किसी न किसी प्रकार से उद्धार करना आवश्यक था । इसके लिए देहाती जीवन के पुनर्निर्माण की एक क्रान्तिकारी योजना की आवश्यकता थी ।नरेन्द्र देव, स्टालिन की इस बात से पूर्णत सहमत थे कि किसानो के विशाल समुदाय को समाजवादी विचारधारा से अनुप्रमाणित करना आवश्यक है ।[138] बहुसख्यक किसानो को देश के समाजवादी पुनर्निर्माण की योजना से सम्बद्ध करने के लिए सहकारी समितियो को सगठित करना और उन्हे सुदृढ बनाना अति आवश्यक था ।नरेन्द्र देव जी ने कृषि को सहकारी आधार पर सगठित करने का समर्थन किया। उनका आग्रह था कि ऋण निरस्त कर दिये जाए और किसानो के लाभ के लिए सस्ते ब्याज पर ऋण की व्यवस्था की जाय ।[139]

भूमि व्यवस्था का क्रान्तिकारी रुपान्तर करने के लिए आवश्यक था कि वास्तविक कृषको तथा राज्य के बीच जो बहुत से बिचौलिये थे उनका उन्मूलन कर दिया जाय । किन्तु नरेन्द्र देव जी राष्ट्रीय समस्याओ को किसानों के वर्गगत दृष्टिकोण से देखने के लिए तैयार नही थे । उन्होन 'किसानवाद' की निन्दा की उसे एक प्रकार का ऐसा ग्रामवाद बताया जो किसानो की विचारधारा को आवश्यकता से अधिक महत्व देता था ।इस बात का भय था कि किसानवाद से कहीं देहात तथा नगरो के बीच हानिकारक सघर्ष न उत्पन्न हो जाय।नरेन्द्र देव जी इस पक्ष मे थे कि गॉवो मे सहकारी व्यवस्था[140] कायम करके लोकतान्त्रिक ग्राम सरकार की स्थापना की जाय। जनता के पिछडेपन को दूर करने तथा उसे नवीन आदर्शो और आकाक्षाओ से अनुप्रमाणित करने के लिए नरेन्द्रदेव जी ने इस बात का समर्थन किया कि भारत के गॉवो मे किसी न किसी रुप मे नवीन जीवन आन्दोलन प्रारम्भ किया जाय ।[141] भारत के समाजवादी चिन्तको मे आचार्य नरेन्द्र देव का विशेष स्थान रहा है । उनकी गणना भारतके प्रमुख समाजवादी बुद्धिजीवियो तथा प्रचारको मे की जाती है । गॉधी जी के घनिष्ठ समर्थक होते हुए भी विचारो से वे मार्क्सवादी थे ।

138 - नरेन्द्र देव- "सोशलिज्म एण्ड नेशनल रिवोल्यूशन," पृष्ठ 87

139 - वही, पृष्ठ 161

140 - वही, पृष्ठ 54

141 - वही, पृष्ठ 183

वे मार्क्स के द्वन्दात्मक भौतिकवाद मे द्वन्दवाद का समर्थन करते थे ।किन्तु भौतिकवाद मे उरनकी आस्था नही थी। वे वैज्ञानिक समाजवाद के समर्थक थे । नरेन्द्र देव एक ओर लोकतान्त्रिक समाजवाद के समर्थक थे तो दूसरी ओर वे वर्ग सघर्ष के सिद्धान्त के भी ।वर्ग सघर्ष के सिद्धान्त के माध्यम से उन्होने भारत की आर्थिक व सामाजिक समस्याओ का अध्ययन किया ।सामान्य जनता मे वर्ग चेतना का सचार करने के लिए उनकी दृष्टि मे निम्न मध्यम वर्ग तथा साधारण वर्ग मे मधुर सबधो की स्थापना आवश्यक थी । वे कृषको,बुद्धिजीवियो के सहयोग से श्रमिक वर्ग को समाजवाद विरोधी सघर्ष का अग्रगामी मानते थे ।वे भारतीय स्वतन्त्रता सग्राम को आर्थिक आधार प्रदान कर उसका सामाजीकरण चाहते थे । वे किसानो को समाजवादी विचारधारा से अनुप्रमाणित करना चाहते थे । उनका कृषक को पुनर्निर्माण का कार्यक्रम सहकारी समितियो के सगठन पर आधारित था। वे कृषी भी सहकारिता के आधार पर उन्नत करना चाहते थे तथा कृषको और ग्राम विकास के लिए सस्ते ऋण की व्यवस्था के पक्षपाती थे । वे गावो मे लोकतान्त्रिक सरकार के पक्ष मे थे ।

vi- <u>डा0 राम मनोहर लोहिया (1910-1967 ई0)</u>

भारतीय समाजवाद के प्रणेताओ मे डा0 राममनोहर लोहिया को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है । वे एक लडाकू व्यक्तित्व वाले प्रखर समाजवादी नेता माने जाते है ।लोहिया ने जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय मे "नमक और सत्याग्रह" नामक शोध प्रबन्ध पर पी0 एच0 डी0 की उपाधि ग्रहण की । जर्मनी मे ही उन्हे समाजवाद की प्रेरणा प्राप्त हुई ।[142] उनके प्रारम्भिक समाजवादी चिन्तन पर हीगल और मार्क्स का गहरा प्रभाव दिखाई पडता है । वे गॉधी जी के यक्तित्व से भी काफी प्रभावित थे । उन्होने सर्वप्रथम भारतीय परिस्थितियो के अनुकूल एक ऐसा समाजवाद लाने का प्रयास किया जो एशिया के सभी अविकसित देशो मे स्थापित किया जा सके । उन्होने स्वयं लिखा है-यहॉ सबसे बडा प्रश्न यह उठता है कि [143] भारत का समाजवादी आन्दोलन अपने पैरो पर भी खडा हो सकता है या उसे सदैव दक्षिण या वामपथी बैसाखियो की जरुरत पड़ती

---

142 - राय अखिलेन्द्र प्रसाद "सोशलिस्ट थाट इन मार्डन इण्डिया, पृष्ठ 124 राय अखिलेन्द्र प्रसाद ने लिखा है कि लोहिया जर्मनी के लोकतान्त्रिक समाजवादी शूमचर तथा ब्रिटिश समाजवादी वेल्स फोर्ड के प्रत्यक्ष सम्पर्क मे आये थे और उनके विचारो से काफी प्रभावित थे ।

143 - डा0 शोभाशकर -"आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन", पृष्ठ 155

रहेगी।वास्तव मे लोहिया न केवल भारत के लिए वरन् एशिया के सभी [144] पिछडे देशो के लिए एक नये समाजवाद को प्राप्त करने का प्रयत्न किया, यही तथ्य उनके समाजवादी चिन्तन का आधारभूत तत्व है।

लोहिया ने सर्वप्रथम अपने समाजवादी विचारो का प्रतिपादन एक सम्पादक के रुप मे किया।[145] उन्होने लिखा कि "समाजवादियो को साम्यवादियो या उदारवादियो के साथ मित्रता के सबध रखने चाहिए । केवल इसी तरह विश्वभर मे और भारत मे एक सहज और सृजनात्मक समाजवाद की रचना होगी।[146] द्वितीय विश्वयुद्ध मे लोहिया ने अपना एक चार सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसमे उन्होने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रबल विरोध किया।[147] सन् 1940 से 1947 तक राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन मे लोहिया ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और वे कई बार जेल भी गये [148] उन्होने देश के विभाजन का प्रबल विरोध किया।[149]

स्वाधीनता के बाद मार्च 1948 मे स्वतन्त्र समाजवादी दल की स्थापना मे लोहिया ने महत्वपूर्ण योगदान दिया । उन्होने समाजवादी दल से सदैव यह अपेक्षा की कि वह एक लड़ाकू मच के रुप मे कार्य करे । उन्होने स्वाधीन भारत मे जनता की समस्याओ के निराकरण के लिए कई जन आन्दोलन चलाये और जेल यात्रा भी की ।उनहोने पूर्वी उत्तर प्रदेश, चम्पारन, मैसूर विन्धय प्रदेश आदि जन आन्दोलनो का समर्थन किया।[150] उनकी अध्यक्षता मे 25 फरवरी 1950 ई0 को रीवा (मध्य प्रदेश) किसान पचायत के प्रथम सम्मेलन मे सर्वप्रथम "गरीबी हटाओ कार्यक्रम" बनाया गया । सन् 1953 मे जब समाजवादी दल और किसान मजदूर प्रजा पार्टी को

---

144 - राम मनोहर लोहिया-' समाजवादी एकता" पृष्ठ 12

145 - सन् 1935 मे "काग्रेस सोशलिस्ट" नामक पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से प्रारम्भ हुआ, जिसके सम्पादक लोहिया बनाये गये थे।

146 - सन् 1936 मे लोहिया को प0 जवाहर लाल नेहरु ने काग्रेस के परराष्ट्र विभाग का कार्य सौपा। इस पद पर रहकर उन्होने एशिया व भारत की राजनीति का गहन अध्ययन किया। उन्होने साम्यवादियो और समाजवादियो के वैचारिक मतभेद का अनुभव किया और निष्कर्ष निकाला कि समाजवादी आन्दोलन की सफलता के लिए सभी समाजवादियो मे एकता का होना आवश्यक है ।राम मनोहर लोहिया,- समाजवादी एकता पृष्ठ 17, काग्रेस समाजवादी दल के अन्दर साम्यवादियो की निन्दनीय भूमिका का वर्णन एम0 आर0 मसानी ने भी किया है ।
एम0 आर0 मसानी, "दि कम्युनिष्ट पार्टी आफ इण्डिया, पृष्ठ 69

147 - इन्दुमति केलकर-लोहिया, सिद्धात और कर्म, पृष्ठ 74

148 - ओकार सरद ने लोहिया की आत्मकथा मे उनके राजनीतिक जीवन का विस्तृत विवरण दिया है।

149 - ओंकार शरद (स)-लोहियाके विचार, पृष्ठ 243-244

150 - लोहिया ने दाम बॉधो, जाति तोड़ो, हिमालय बचाओ, अग्रेजी हटाओ जैस जन आन्दोलन चलाये।

मिलाकर प्रजा समाजवादी दल की स्थापना हुई, तब लोहिया बड़े असतुष्ट हुए[151] क्योकि वे समझौतावादी नीति के विरुद्ध थे। इसी के परिणाम स्वरुप 28 दिसम्बर 1955 ई0 को हैदराबाद मे उन्होने समाजवादी दल की पुनर्स्थपना की। [152] सन् 1963 से 1967 तक लोहिया ने लोक सभा मे अन्दर रहकर काग्रेस सरकार की कटु आलोचना की और समाजवादी एकता को ध्यान में रखकर सयुक्त समाजवादी दल को अपना पूरा समर्थन दिया।[153]

लोहिया के समाजवादी चिन्तन पर गॉधी जी का गहरा प्रभाव दिखाई पडता है। गॉधी जी भी लोहिया से विशेष लगाव रखते थे [154] सन् 1941 मे जब लोहिया जेल मे थे, गॉधी जी ने कहा था-"जब तक राममनोहर लोहिया जेल मे है, तब तक मै खामोश नही बैठ सकता, उनसे ज्यादा बहादुर और सरल आदमी मुझे मालूम नही "[155] लोहिया गॉधी जी को राष्ट्रपिता और भारतीय सस्कृति का प्रतीक मानते थे। उन्होने गॉधी जी के अहिसा सिद्धात को अपने क्रान्ति दर्शन और अहिंसात्मक सत्याग्रह के सिद्धात को अपने सिविल नाफरमानी के सिद्धात मे स्वीकार किया है। उनके अनुसार "सिविल नाफरमानी या अन्याय से शान्ति पूर्वक लडना अपने आप मे कर्त्तव्य है "[156] लेकिन लोहिया "गॉधीवाद और समाजवाद" मे गॉधीवाद के अन्तर्विरोधो का उल्लेख किया है। उनका मत था कि गॉधी जी ने जीवन के भौतिक और अर्थिक आधार की ओर ध्यान नही दिया।[157] लोहिया गॉधीवादी हृदय परिवर्तन मे भी आस्था नही रखते थे और अन्याय का विरोध करने के लिए घेराव के सिद्धात का समर्थन किया और श्रम क्रान्ति का आवह्न किया।[158]

इतना होने पर भी लोहिया गॉधी जी के प्रभाव मे सदैव रहे। उनके अनुसार गॉधी जी ने हमे वह मार्ग दिखाया, जिसके जरिए साधारण लोग भी सुकरात या प्रहलाद जैसे बन सकते हैं,

---

151 - लोहिया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को "लकवा मार" कहते थे और उसमे लड़ाकूपन कमी बताये लोहिया -समाजवादी एकता पृष्ठ 18

152 - इस समाजवादी दल मे मधुलिमये, राजनारायण, मनीराम बागडी लाडली मोहन निगम, रविराय, बालेश्वर दयाल, बद्री विशाल आदि समाजवादी नेता शामिल थे।

153 - सन् 1956 मे समाजवादी दल और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मिलन के फलस्वरुप सयुक्त समाजवादी दल का निर्माण हुआ

154 - ओकार शरद ने राम मनोहर लोहिया और गाँधीजी के सम्बन्धो का विस्तृत विवरण दिया है। ओकार शरद- लोहिया', पृष्ठ 106-113

155 - लोहिया- सिविल नाफरमानी सिद्धात और अमल पृष्ठ 7

156 - लोहिया "मार्क्स गाँधी एण्ड सोशलिज्म" पृष्ठ 133

157 - लोहिया -क्रान्तिकरण पृष्ठ 39

158 - इन्दुमति केलकर- जन का लोहिया अक पृष्ठ 128

वह कष्ट उठाने का हथियार सिविल नाफरमानी था ।[159] गॉधी जी के निधन पर स्वय लोहिया ने अपने को अनाथ घोषित किया[160] और गॉधी जी के समाजवाद को अपने चिन्तन के अनुकूल ढालकर उसे यथार्थ रुप मे प्रस्तुत किया। विद्वानो ने लोहिया को गॉधीवाद का विकसित उत्तराधिकारी बताया ।[161] इन्दुमति केलकर के अनुसार गॉधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारियो ने तो गॉधीवाद का एक करुणा का बाजू पकडा और क्रोध का दूसरा बाजू छोड़ दिया ।इससे उनके द्वारा भी गॉधीवाद की रक्षा न हो सकी । लेकिन इनके दगा देने के बाद भी गॉधीवाद जिन्दा रहा और लोहिया ने उसे बचाया । लोहिया ने गॉधीजी के मूल सिद्धान्तो को जीवित रखा, आगे बढाया और नये सिद्धान्तो के जन्म दिया ।[162]

भारत के अन्य समाजवादियो के समान लोहिया भी मार्क्सवाद से प्रभावित हुए । उन्होने भी कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समजावाद का महान व्याख्याकार माना है [163] और अपने अनेक लेखो मे अपने मार्क्सवादी सिद्धातो के सम्बन्ध मे अपने विचार व्यक्त किये। उन्होने मार्क्सवाद की पूजी सचय सबन्धी सिद्धात और पूॅजीवादी एकाधिकारवाद तथा श्रम के समाजीकरण को स्वीकार किया, तथा वर्ग-सघर्ष और विश्वक्रान्ति को ये मान्यता नही देते है ।[164] लोहिया मार्क्सवाद के आर्थिक विश्लेषण को भी ज्यो का त्यो स्वीकार नही किये और लेनिन के इस विचार से सहमत थे कि साम्राज्यवाद पूॅजीवाद की अन्तिम मजिल है ।[165] उनके अनुसार''साम्राज्यवाद केवल पूॅजीवाद के प्रथम चरण मे दिखाई ही नही देता, बल्कि वह उसके साथ विकसित भी होता जाता है । [166] मार्क्स के द्वन्दात्मक भौतिकवाद का विश्लेषण करते हुए लोहिया ने मार्क्स और हीगल की तुलना की है और कहा है कि मार्क्स की व्याख्या यूरोपीय परिवेश की उपज है और यही उसकी सीमा है ।[167]

---

159 - ओकारशरद - 'लोहिया के विचार' , पृष्ठ 231
160 - डा0 शोभाकर शकर- आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन , पृष्ठ 160
161 - यह बात सन् 1957 मे जापान मे समाजवादी नेता याशिकी होशिवो ने कही थी ।
162 - इन्दुमति केलकर- जन' का कालोहिया अक, पृष्ठ 25
163 - लोहिया-''व्हील आफ हिस्ट्री, पृष्ठ 23
164 - लोहिया- 'मार्क्स, गाँधी एण्ड सोशलिज्म, पृष्ठ 9,
165 - डा0 शोभाशकर-''आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन, पृष्ठ 162
166 - लोहिया-मार्क्स, गाँधी एण्ड सोशलिज्म, पृष्ठ 13
167 - लोहिया-''व्हील आफ हिस्ट्री, पृष्ठ 23, लोहिया- आस्पेक्ट्स आफ सोशलिस्ट पालिसी, पृष्ठ 76

मार्क्सवाद के वर्ग सघर्ष सिद्धात और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को भी लोहिया पूर्णतया स्वीकार नही करते । उनका कहना था कि मानव सभ्यता के इतिहास मे जाति सघर्षो की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।[168] इस प्रकार लोहिया मार्क्सवाद के बारे मे विचार करके भारतीय परिस्थितियो के अनुकूल ढ़ालने के पक्षधर रहे हैं ।

नरेन्द्र देव के समान ही लोहिया का समजावादी चिन्तन राष्ट्रीयता को साथ लेकर चलता है तथापि उसका आधार व्यापक है । उनके अनेक लेखो मे राष्ट्रीयता और समाजवाद का समन्वय दिखाई देता है ।[169] इसलिए उन्होने तिब्बत पर चीन के आक्रमण और भारत पर चीन के आक्रमण की कडी निन्दा की । वास्तव मे लोहिया की राष्ट्रीयता उनकी समाजवादी विचारधारा की पोषक है।[170]

वस्तुत लोहिया ने भारतीय परिस्थितियो के अनुकूल एक नया समाजवादी चिन्तन विकसित करने का प्रयास किया ।[171]

उनके समाजवादी चिन्तन के प्रमुख आधार है जो कि मौलिक हैं । लोहिया ने क्रान्तिकरण,[172] सात क्रान्तियाँ[173] चौखम्भायोजना,[174] निजी और सार्वजनिकक्षेत्र,[175] जाति प्रथा

---

168 - लोहिया-मार्क्स, गाँधी एण्ड सोशलिज्म, पृष्ठ 366-67 लोहिया व्हील आफ हिस्ट्री, पृष्ठ 13

169 - लोहिया ने अपने राष्ट्रीयता सबधी विचारो का प्रतिपादन भारत-चीन और उत्तरी सीमाए नामक पुस्तक मे किया है । उसके कई खण्ड है, हिमालय कश्मीर, डर्वसीअम, नेपाल, तिब्बत नीति, दस्तावेज आदि। इस पुस्तक के लेखो को ओकार शरद ने लोहिया के विचार नामक पुस्तक मे सकलित किया ।

170 - डा0 शोभाशकर आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन, पृष्ठ 165

171 - लोहिया का समाजवादी चिन्तन उनके अनेक ग्रन्थो, लेखो, भाषणो आदि मे बिखरा पड़ा है, जिसका विस्तृत विवेचन यहाँ अपेक्षित नही है, फिर भी सन्दर्भित ग्रन्थो का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है ।

172 - लोहिया-क्रान्तिकरण (लघु पुस्तिका)

173 - लोहिया-सात क्रान्तियाँ (लघु पुस्तिका), इस पुस्तक मे लोहिया ने जातियो की बराबरी,हरिजन आदिवासियो के लिए समान अवसर, रग भेद की समाप्ति, नर-नारी समानता, हथियारो का विरोध, मूल्य की बराबरी, जीवन की आजादी के लिए क्रान्ति का आवाह्न किया है ।

174 - चौखम्भा योजना, लोहया के समाजवादी चिन्तन के अन्तर्गत इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योकि इसमे गाँधी जी के विकेन्द्रीकरण के सिद्धात को स्वीकार किया गया है । लोहिया आसपेक्ट्स आफ सोशल पालिसी, पृष्ठ 17, लोहिया क्रान्ति के लिए सगठन, पृष्ठ 12

175 - लोहिया- "निजी और सार्वजनिक क्षेत्र," इस पुस्तक मे लोहिया ने निजी सम्पत्ति का विरोध और सार्वजनिक सम्पत्ति का समर्थन किया है ।वे उद्योगो के राष्ट्रीयकरण के स्थान पर उसके समाजीकरण के पक्ष मे थे । लोहिया-समाजवाद की अर्थ नीति, पृष्ठ 13-15

उन्मूलन,[176] नारी समस्या,[177] सामप्रदायिकता [178] आदि अनेक सामाजिक प्रश्नो पर अपने विचार व्यक्त किये है ।

अपने आर्थिक चिन्तन मे लोहिया [179] ने दाम बॉधो, आय-व्यय की सीमा, [180] खर्च पर नियत्रण [181] आदि पर विचार प्रस्तुत किये है । लोहिया ने एशिया और अफ्रीका पर भी दृष्टि डाली है और रगभेद नीति का विरोध किया है ।[182] गॉधी के समान उन्होने कुटीर उद्योगो का समर्थन किया और अन्न बॉटो आन्दोलन चलाया। भूमि वितरण की समस्या पर भी उनके विचार काफी प्रखर है । साराशत लोहिया के समाजवादी चिन्तन मे राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक और सास्कृतिक पक्ष एक दूसरे से जुडे हुए है ।[183]

वास्तव मे लोहिया भारतीय समाजवाद के इतिहास मे एक बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न समाजवादी विचारक थे। उन्होने विश्व बन्धुत्व के आदर्श को अपने समाजवादी चिन्तन का आधार बनाया[184] और विद्रोही क्रान्तिकारी, सन्यासी और, अजेयजन प्रहरी के रुप मे विख्यात हुए । वे जन्मजात समाजवादी थे और जीवन पर्यन्त समाजवादी ही रहे ।

vii- डा0 सम्पूर्णानन्द

सम्पूर्णानन्द की गणना काग्रेस समाजवादी दल के सस्थापको मे की जाती हे।वे भाातरीय सस्कृति के आदर्श से अनुप्रेरित होने के कारण मार्क्सवाद और लेनिनवाद को स्वीकार नही किये। उनके ऊपर गॉधीवाद का गहरा प्रभाव था, और वे गॉधीवाद और साम्यवाद में समन्वय स्थापित करने के इच्छुक थे । उनका मत था कि गॉधीवाद और साम्यवाद के समन्वय

---

176 - लोहिया जाति प्रथा' की इस पुस्तक मे लोहिया ने यह विचार व्यक्त किया है कि भारत मे समाजवाद लाने के लिए जाति प्रथा का उन्मूलन करना आवश्यक है ।

177 - लोहिया ने नारियो को भी पिछड़ी जातियो मे शामिल किया और उन्हे सम्मान के लिए उन्हे क्रान्ति करने के लिए प्रेरित किया। लोहिया-क्रान्तिकरण, पृष्ठ 39

178 - लोहिया ने साम्प्रदायिकता का प्रबल विरोध किया है । लोहिया धर्म पर एक दृष्टि लोहिया-हिन्दू और मुसलमान

179 - लोहिया-काचन मुक्ति

180 - लोहिया-खर्च पर सीमा

181 - लोहिया विश्व समाजवाद के पोशक और समतावादी दर्शन के प्रणेता थे । उन्होने ने विश्वसरकार का स्वप्न देखा और सयुक्त राष्ट्र सघ की व्यवस्था मे परिवर्तन की माग की ।

182 - लोहिया-विल टू पावर, पृष्ठ 80, डा0 वी0 पी0 वर्मा -आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, पृष्ठ 430 डा0 शोभा शकर आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन, पृष्ठ 184

183 - लोहिया (स)- जीवन और दर्शन, पृष्ठ 44

184 - ' जन" लोहिया अक पृष्ठ 161

का प्रयत्न विश्व के लिए एक महान सन्देश हो सकता है ।[185] सम्पूर्णानन्द गॉधीवाद के आधार पर अपने समाजवादी चिन्तन का विकास किया ।[186] उन्होने भौतिकवाद को अस्वीकार करके मोक्ष, ब्रह्मधर्म व चेतना जैसे शब्दो का प्रयोग अपने चिन्तन मे किया, लेकिन ये शब्द समाजवाद की शब्दावली मे नही आते है । उनके समाजवादी विचारो के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि वे भारतीय समाजवाद की एक ऐसी रुपरेखा बनाना चाहते थे, जिसमे प्राचीन भारतीय आदर्शो और मूल्यो का भी स्थान हो ।वे भारतीय साम्यवादियो की यह कहकर आलोचना किये कि उनका चिन्तन स्वतन्त्र रुप से विकसित नही हुआ है ।और वे बदले हुए सत्ता समीकरण मे उन्हे अनेक बार कठिनाइयो का सामना करना पडा है ।[187]

वास्तव मे सम्पूर्णनन्द मार्क्सवादी न होकर पूर्णतया गॉधीवादी है और उनका चिन्तन विशुद्ध भारतीय आदर्शो से परिपूर्ण है ।[188]

सम्पूर्णानन्द अपने समाजवादी चिन्तन मे समाजवाद के स्थान पर सर्वोदय शब्द का प्रयोग करना उचित समझते थे । उनके अनुसार समाजवाद केवल मात्र शोषण का अन्त करने का एक राजनीतिक या आर्थिक चिन्तन नही है, वरन वह तो मानव के सम्पूर्ण जीवन की दृष्टि है। वे समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देते थे ।[189] उनके अनुसार" मनुष्य को सच्चा मानव बनाने के लिए उसमे उदारता, सहानुभूति, सहनशीलता, परोपकार तथा दया आदि गुणो का विकास करना होगा ।[190]

सम्पूर्णानन्द भारतीय साम्यवादियो की कार्य पद्धति के आलोचक थे । वे साम्राज्यवाद का विरोध करते थे और साम्यवादी साम्राज्यवाद को 'सनकीपन' की संज्ञा देते थे । गॉधी जी के समान उन्होने अपने चिन्तन को नैतिकता पर आधारति किया, उन्होने समाजवाद की स्थापना के लिए रक्त पूर्ण क्रान्ति के स्थान पर अहिंसात्मक उपायो के प्रयोग का समर्थन किया। लोकतन्त्र मे

---

185 - सम्पूर्णानन्द गाँधीवाद-समाजवाद, पृष्ठ 158

186 - सम्पूर्णानन्द का समाजवादी चिन्तन उनकी पुस्तक इण्डियन सोशलिज्म' मे निहित है ।

187 - सम्पूर्णानन्द- इण्डियन सोशलिज्म" पृष्ठ 50

188 - सम्पूर्णानन्द का चिन्तन रामायण, महाभारत मनुस्मृति कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा शुक्राचार्य के नीतिसार से प्रभावित है ।राय अखिलेन्द्र प्रसाद- "सोशलिस्ट थाट इन माडर्न इण्डिया' ,पृष्ठ 99, सम्पूर्णानन्द मेमायर्स एण्ड रिफ्लेक्शन्स, पृष्ठ 50

189 - डा0 शोभा शकर आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन, पृष्ठ 206

190 - सम्पूर्णानन्द- इण्डियन सोशलिज्म, पृष्ठ 7

उनका दृढ विश्वास था ।उनके अनुसार लोकतन्त्र और समाजवाद के अतिरिक्त कोई विकल्प ही नही है । उन्होने लोहिया के विचार से सहमति रखते हुए कहा कि "समाजवाद न आने पर फासीवाद आयेगा या साम्यवाद [191] उनका यह भी मानना था कि "विश्व मे कोई शान्ति नही होगी जब तक कि विचार और कर्म मे सच्चे समाजवाद को स्वीकार नही कर लिया जाता [192] विद्वानो ने सम्पूर्णानन्द के समाजवादी चिन्तन को 'वेदान्ती समाजवाद' की सज्ञा दी है ।[193]

viii -अशोक मेहता

अशोक मेहता सन् 1932 मे नासिक जेल मे जय प्रकाश व अन्य समाजवादी नेताओ के सपर्क मे आये। उन्होने जय प्रकाश जी से मार्क्सवाद का पहला पाठ सीखा ।[194] जेल से बाहर आकर मेहता एक समाजवादी बन गये । उन्होने सामाजिक लोकतन्त्र और लोकतान्त्रिक समाजवाद को भारतीय समाजवाद का आधार बनाया ।[195] सन् 1946 तक मेहता ने अनेक मजदूर आन्दोलनो मे सक्रिय भाग लिया ।[196] सन् 1950 मे मेहता ने समाजवादी दल के आठवे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की ।इस अवसर पर उन्होने अपने समाजवादी विचारो को व्यक्त करते हुए कहा "समाजवाद मे सामाजिक, आर्थिक के साथ नैतिक दृष्टि भी होना चाहिए ।[197] भारतीय समाजवादी एकता स्थापित करने के लिए मेहता ने प्रजा समजावादी दल को सगठित किया और कई वर्षो तक इसके अध्यक्ष भी रहे । मेहता 1952 और 1957 मे लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और 1966 मे राज्य सभा के सदस्य चुने गये । काग्रेस मे शामिल होकर उन्होने अनेक महत्वपूर्ण पदो को सुशोभित किया ।[198]

---

191 - डा0 शोभा शकर-आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन, पृष्ठ 208

192 - सम्पूर्णानन्द इण्डियन -सोशलिज्म, पृष्ठ 35

193 - राय अखिलेन्द्र प्रसाद- "सोशलिस्ट थाट इन माडर्न इण्डिया, पृष्ठ 102 सम्पूर्णानन्द-समाजवाद (पुस्तिका), पृष्ठ 39

194 - राय अखिलेन्द्र प्रसाद, सोशलिस्ट थाट इन माडर्न इण्डिया, पृष्ठ 135

195 - हरिकिशोर सिह के अनुसार मेहता के विचार पाश्चात्य लोकतान्त्रिक समाजवाद से प्रभावित है । ए हिस्ट्री आफ प्रजासोशलिस्ट पार्टी, पृष्ठ 20

196 - जी0 एस0 भागर्व- 'लीडर्स आफ दि लेफ्ट" पृष्ठ 66

197 - समाजवादी दल का आठवाँ वार्षिक अधिवेशन (मद्रास,1950), पृष्ठ 29 32

198 राय अखिलेन्द्र प्रसाद,सोशलिस्ट थाट इन माडर्न इण्डिया, पृष्ठ 138 139

1968 मे चेकोस्लोवाकिया के प्रश्न पर मन्त्री पद से त्याग पत्र दे दिया ।[199] कुछ समय तक मेहता सगठन काग्रेस के साथ रहे, बाद मे जनता पार्टी मे शामिल हो गये ।

मेहता लोकतान्त्रिक समाजवाद के समर्थक थे। वे पूँजीवाद को एक बुराई के रुप में स्वीकार करते थे ।उनका आर्थिक चिन्तन काफी समृद्ध था ।[200] वे योजना बद्ध आर्थिक कार्यक्रम द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते थे । वे गॉधी जी के इस तर्क से असहमति रखते थे कि केवल देश मे कुटीर उद्योग का विकास करना ही उचित होगा ।[201] वे आर्थिक क्रान्ति के प्रवर्तक थे और उसे वे जीवन की पुर्नव्यवस्था की सज्ञा देते थे ।[202] भारतीय समाजवाद के इतिहास मे मेहता एक पत्रकार, अर्थशास्त्री और लोकतान्त्रिक समाजवादी के रुप मे महत्वपूर्ण स्थान रखते है ।[203]

भारतीय समाजवाद के चिन्तको मे युसूफ मेहर अली, एम0 आर0 मसानी, अच्युत पटवर्धन, कमला देवी चटोपाध्याय, श्री प्रकाश, एस0 एम0 जोशी और एन0 जी0 गोरे की गणना की जाती है ।[204]

.X- जय प्रकाशनारायण (1902-1979 ई0)

जय प्रकाश नारायण पर उन नवीन तत्वो एव विचारधाराओ का प्रभाव पडा, जिन्होने उनकी विचार धारा के निर्माण और विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।प्रत्येक विचारक अपने काल की परिस्थितियों की उपज होता है । जे0 पी0 भी उसके अपवाद नहो हो सकते हैं । जे0 पी0 के विचारधारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह एक समानान्तर रेखा मे न होकर वह विभिन्न मोडो से होकर गुजरी है। ये विभिन्न मोड विभिन्न विचारधाराओ की ओर संकेत करते हैं । जे0 पी0 का सम्पूर्ण दर्शन मूलरुप से तीन सिद्धातो, स्वतन्त्रता, समता और बन्धुत्व पर टिका हुआ है । इन्ही सिद्धातो के आधार पर जे0 पी0 के सम्पूर्ण चिन्तन का निर्माण हुआ है ।वे एक ऐसी

---

199 - सन् 1963 मे भारत सरकार ने चेकोस्लोवाकिया पर सोवियत सघ के आक्रमण का खण्डन नही किया जिससे क्षुब्ध होकर मेहता ने मन्त्री पद से त्याग पत्र दे दिया ।

200 - अशोक मेहता के आर्थिक विचार डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, स्टडी इन एशियन सोशलिज्म, इकोनामिक प्लानिग इन इण्डिया'' आदि पुस्तको मे सग्रहित है ।

201 - एम0 वी0 सिन्हा, दि लेफ्ट विंग इन इण्डिया पृष्ठ 379

202 - एम0 एन0 सरीन, स्टडीज आफ इण्डियन लीडर्स, पृष्ठ 13

203 - एस0 एम0 जोशी ''सयुक्त समाजवादी दल के अध्यक्ष और एन0 जी0 गोरे काग्रेस समाजवादी दल के अध्यक्ष रहे । अच्युत पटवर्धन समाजवाद का मार्ग छोड़कर आध्यात्मिक क्षेत्र मे प्रविष्ट हो गये एम0 आर0 मसानी ने स्वतन्त्र दल की स्थापना की कमला देवी चटोपाध्याय समाज सेविका बन गयी ।

204 - मार्क्स, एजिल्स, कम्युनिष्ट पार्टी का घोषणा पत्र पृष्ठ 65

सामाजिक व्यवस्था की खोज मे हैं जो इन तीन मूल्यो पर आधारित हो।इसी खोज मे वे कभी मार्क्सवाद की ओर मुडे, कभी गॉधीवाद की ओर और अन्त मे इसी खोज मे उन्होने मार्क्सवाद, गॉधीवाद एव लोकतन्त्र के सिद्धात का समन्वय कर एक ऐसी विचारधारा के निर्माण का प्रयास किया जो व्यवस्था को सबल आधार प्रदान करने की क्षमता रखती है।

मार्क्सवाद मे जे0 पी0 की पूर्ण आस्था थी। जे0 पी0 ने समाजवाद के सम्बन्ध मे कहा था कि "समाजवाद का केवल एक रुप है, एक सिद्धात है, और वह मार्क्सवाद है [205] वे स्वीकार करते थे कि विभिन्न समाजवादी विचारधाराओ के मध्य प्रक्रिया और व्यूह रचना के प्रश्न को लेकर मतभेद है। परन्तु जे0 पी0 मानते थे कि अभी तक केवल साम्यवादियो ने ही अपने महान और विलक्षण सफलता के द्वारा, व्यूह रचना करके अपने सिद्धातो की सार्थकता प्रमाणित की है।

निश्चय ही रुस मे समजावाद का मार्क्सवादी प्रतिपादन है। समजावाद सामाजिक पुनर्निर्माण की पद्धति होता है। आदर्शवादियो का कोई भी वर्ग सत्ता पर आधिपत्य किये बिना समाजवाद की स्थापना नही कर सकता।[206] समाजवाद के इसी ध्येय को लेकर उन्होने "समाजवाद ही क्यो" (सन् 1936 ई0), "सघर्ष की ओर "(1948 ई0),"नेशन विल्डिग इन इण्डिया" इत्यादि पुस्तको की रचना की।

जे0 पी0 के ऊपर गॉधी जी के व्यक्तित्व का काफी प्रभाव पडा। स्वतन्त्रता का आकाशदीप जे0 पी0 को उन्नीस वर्ष की अवस्था मे ही तभी मिल गया जब उन्होने सन् 1922 मे गॉधी जी के आग्रह पर पटना कालेज का परित्याग कर असहयोग आन्दोलन मे भाग लिया था। जे0 पी0 को अगर स्वतन्त्रता का ध्येय गाँधी जी से मिला तो समता का ध्येय मार्क्स से। उनके चिन्तन के विकास मे दोनो दार्शनिको का महत्वपूर्ण योगदान है। स्वतन्त्रता के ध्येय की पूर्ति के लिए तो जे0 पी0 काग्रेस मे गये, लेकिन वह समता के ध्येय के लिए तत्पर रहे, ताकि दोनो ध्येयो के लिए साथ-साथ कार्य किया जा सके।इसी आधार पर सन् 1934 में अन्य समाजवादी साथियो सहित काग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की, उस समय उनकी विचारधारा पूर्ण रुपेण मार्क्सवाद पर आधारित थी। सन् 1936 ई0 मे काग्रेस समाजवादी दल द्वारा प्रकाशित अपनी

---

205 - डॉ0 लक्ष्मी नारायण लाल 'जय प्रकाश नारायण पृष्ठ 24

206 - डा0 लक्षिम नारायण पृष्ठ 64-65

पुस्तक "समाजवाद ही क्यो " मे जे0 पी0 ने लिखा है कि "और पहले से कही अधिक स्पष्ट तौर पर यह कहना सभव है कि समाजवाद का एक ही रुप व एक ही सिद्धांत है- मार्क्सवाद[207]

जे0 पी0 और लोहिया के विचारो मे काफी साम्यता है । दोनो विचारक चुनाव प्रक्रिया को जातिगत विषमता को समाप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। जे0 पी0 भी जाति प्रथा की अनुदार प्रवृत्ति के लिए ब्राह्मण वर्ग को ही जिम्मेदार ठहराते है । क्योकि ब्राह्मण वर्ग ही समाज मे सबसे अधिक शिक्षित वर्ग था ।[208] वर्तमान समय मे जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है, समाज की प्रत्येक क्रिया किसी न किसी रुप मे जातिवाद के प्रभाव से सम्पन्न होती है । भारत की चुनाव प्रक्रिया भी इससे विमुक्त नही है। इस समस्या की ओर जे0 पी0 ने सकेत करते हुए उन दलो की भर्त्सना की जो इनका सहारा लेते है ।[209] जे0 पी0 ने अपने को केवल समाजवादी रुप तक ही सीमित नही रखा बल्कि एक सामाजिक पर्यवेक्षक के रुप मे सामाजिक समस्याओ के सुधार के लिए सामाजिक बुराईयो को समाप्त करना अनिवार्य समझा ।[210] जय प्रकाश नारायण ने अछूत समस्या को एक विनाशकारी समस्या के रुप मे चित्रित किया है । इन्होने काफी समय पहले ही कहा था कि " भारत मे अछूत समस्या बहुत बडी समस्या है। इसका निराकरण करना हमारा परम कर्त्तव्य है । निम्न कार्यो से छुटकारा दिलाया जाय तथा उनके व्यवसायो मे भी सुधार किया जाये, तभी समाज का कल्याण हो सकता है ।[211] जे0 पी0 भी नेहरु एव लोहिया के समान ही अस्पृश्यता को विकास के मार्ग मे बाधक समझते है तथा अस्पृश्यता की समस्या का यदि समाधान नही किया जाता तो भविष्य मे राष्ट्र और समाज के लिए खतरा बन सकती है । जे0 पी0 ने लिखा है कि आज हिन्दुस्तान मे प्राथमिक सुधार की आवश्यकता है । यह हिन्दू समाज एव राष्ट्र के स्वतन्त्रता के लिए बहुत बडा खतरा है ।[212] जे0 पी0 की विचारधारा मे नये परिवर्तन समय के अनुसार हुए । उन नवीन विचारधाराओ के ग्रहण करने से साध्य मे कोई परिवर्तन नही हुआ लेकिन साधनो मे परिवर्तन आना स्वाभाविक था ।

---

207 - जय प्रकाश नारायण "समाजवादी ही क्यो' पृष्ठ 64

208 - जय प्रकाश नारायण , नेशन बिल्डिग इन इण्डिया," पृष्ठ 17

209 - मीनू मसानी "जे0 पी0 मिशन पार्टी एकम्पिलश्ड पृष्ठ 56

210 - वही, पृष्ठ 56

211 - जय प्रकाश नारायण "मेरी विचार यात्रा" भाग-2 पृष्ठ 85, (सर्व सेवा सध प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी)

212 - जय प्रकाश नारायण "नेशन बिल्डिग इन इण्डिया" पृष्ठ 190

जे0 पी0 ने हृदय परिवर्तन पर आधारित सर्वोदय आन्दोलन की विफलता को स्वीकार किया तथा पुन वह मार्क्सवादी साधनो मे आस्था रखते हुए क्रान्ति को समस्त समस्याओ के समाधान का मूल मानने लगे। जे0 पी0 ने सर्वोदयी विचारधारा को ग्रहण करने के पूर्व लिखा था कि हमे सामाजिक क्रान्ति करनी है, गरीबी, सामन्तशाही, पूॅजीवाद और जातिभेद को मिटाये बिना हम उन्नति नही कर सकते। यदि हिन्दुस्तान मे समाजवाद कायम करना है तो ऊॅच-नीच, जाति-पॉति का भेद मिटाना होगा।[213]

राष्ट्र की उन्नति किसी एक वर्ग विशेष का कार्य नही है।उसमे सभी वर्ग विशेष का सहयोग होना अति आवश्यक है।सभी वर्गों का सहयोग तभी ही हो सकता है जब समाज मे समता हो।यदि राष्ट्र की उन्नति करनी है तो सामाजिक क्रान्ति और आर्थिक क्रान्ति के द्वारा न्याय होना आवश्यक है।क्योकि आर्थिक क्रान्ति की सफलता सामाजिक क्रान्ति पर निर्भर होती है। सामाजिक ऊॅच-नीच के भेद-भाव को समाप्त किये बिना सामाजिक न्याय नही रह सकता।[214] जे0 पी0 चुनाव प्रक्रिया को एवं मताधिकार को अस्पृश्यता की समस्या के समाधान के लिए साधन के रुप मे देखते है। उनका मत है कि "चुनाव इन वर्तमान वस्तु योजनाओ के चुनौती के रुप मे आया है"।[215]

जे0 पी0 ने वर्ग सघर्ष की अनिवार्यता को स्वीकार्य करते हुए युवा वर्ग का आवाह्न किया कि वह हरिजनो एव भूमिहीनो को वर्ग के आधार पर सगठित करने का बीडा उठाये। इस विचार से यह ध्वनि निकलती है कि उनकी विचारधारा एक नये दौर से गुजरी है। गरीबी एक सामाजिक अभिशाप है, उसको समाज से जब तक समाप्त नही किया जाता तब तक सामाजिक सुधार और क्रान्ति सफल नही होगी। किसी भी व्यक्ति या सामाजिक जीवन के किसी भी पहलू को सामाजिक क्रान्ति की लहर से पृथक नही रखा जा सकता। इन समस्याओ के समाधान के लिए उन्होने शिक्षा प्रणाली मे पूर्ण परिवर्तन करने का सुझाव दिया। हिन्दू समाज वर्ग और जाति

---

213 - रामवृक्ष बेनी पुरी "जय प्रकाश की विचारधारा" पृष्ठ 423

214 - जय प्रकाश नारायण नेशन बिल्डिग इन इण्डिया' पृष्ठ 423

215 - रामवृक्ष बेनी पुरी "जय प्रकाश की विचारधारा पृष्ठ 295

भिन्नता से परिपूर्ण है । वास्तविक शिक्षा वही होगी जो इन असमनताओ को मिटा दे और मानव समाज मे सहयोग की भावना का विकास करे ।[216]

जय प्रकाश नारायण ने वर्गो के प्रादुर्भाव मे सामाजिक विषमता को आर्थिक तत्व से सम्बद्ध किया है । आर्थिक तत्व वर्ग अभ्युदय के लिए केवल पूर्ण रुपेण केवल उत्तरदायी नही हो सकता । समाज की दूसरी असमनताए भी उद्भव के लिए उतनी ही उत्तरदायी है जितनी आर्थिक विषमता वर्ग अभ्युदय के सम्बन्ध मे डॉ0 लोहिया एव जे0 पी0 मे काफी साम्यता है । जे0 पी0 के अनुसार "हमारी सामाजिक मूल विषमताओ का कारण यह है कि हम सामाजिक रुप से कभी अलग नही हुए है, हमारे मानस मे अब भी सामन्तवाद की मान्यताए मौजूद है ।ये सामजिक जीवन को बहुत कुछ प्रभावित करती है । हमारे यहॉ अभी भी वर्ग व्यवस्था मौजूद है जो पहले कर्म के आधार पर थी और अब जन्म के आधार पर ग्रहण कर ली गयी है । इस जन्म के आधार के कारण समाज मे वर्गो का निर्माण एव बिखराव उत्पन्न हो गया है । समाज विभिन्न वर्गो मे विभाजित हो गया है । जो व्यक्ति निम्न वर्ग के है वही आर्थिक दृष्टि से पिछडे हुए है । आर्थिक वर्गो और सामाजिक वर्गो मे ऐसा सम्बन्ध स्थापित हो गया है जो कि एक दीर्घ प्रक्रिया का परिणाम है ।जो आर्थिक दृष्टि से पिछडे हुए थे वही सामाजिक दृष्टि से भी पिछडे हुए बन गये । इन वर्गो मे विषमता बढती गयी ।[217]

जे0 पी0 ने वर्ग उन्मूलन के सम्बन्ध मे सघर्षपूर्ण और शान्ति पूर्ण दोनो साधनो को ग्रहण किया, जो उनकी परिवर्तित विचारधारा की सूचक है । जे0 पी0 जब मार्क्सवादी थे तब मार्क्सवाद के ही आधार पर भारत मे भारत की सस्कृति एव समाज के अनुकूल समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे । लेकिन 80 के दशक मे जैसे नयी परिस्थितियॉ और समस्याए देश के समक्ष आती गयी उनके अनुसार वे अपने विचार और कार्यक्रम मे परिवर्तन करते गये ।वे अहिंसा को एक मात्र कामचालऊ अस्त्र मानते थे, हिंसा ही अन्तिम रुप से अस्त्र होगा[218]

80 के दशक से जे0 पी0 की विचारधारा पर पुन· मार्क्सवादी विचार दृष्टिगोचर होने लगा था । उन्होने असमानता दूर करने के लिए वर्ग-सघर्ष को पुन मान्यता प्रदान की और हृदय

216 - जे0 पी0 ' समाजवाद क्यो और कैसे," पृष्ठ 325

217 - जे0 पी0 ' सघर्ष की ओर, पृष्ठ 20

218 - 8 अगस्त 1977, "सामाजिक क्रान्ति" धर्मयुग के अक से

परिवर्तन पर आधारित सर्वोदय आन्दोलन की विफलता को स्वीकार करते हुए वर्ग सघर्ष को अनिवार्य बतलाया और युवा वर्ग का आवाह्न किया कि वह हरिजनो एव भूमिहिनो को वर्ग के आधार पर सगठित करने का बीडा उठा ले ।[219] इस तर्क से यही अर्थ निकलता है कि वर्ग संघर्ष एव वर्ग सगठन की उस पूर्ण भूमिका पर जिसे वह काफी समय पूर्व त्याग चुके थे, उस पर पुन: वापस लौट आये ।

हमारे समाज मे वर्ण व्यवस्था के कारण उत्पन्न वर्गो ओर अर्थिक समानता के कारण यह सभव है कि भारत मे वर्ग उन्मूलन के प्रयास किये जाये यदि इस ओर ध्यान नही दिया गया और शान्ति पूर्ण ढग से समाज परिवर्तन की प्रक्रिया को नही अपनाया गया तो अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है और वर्ग-सघर्ष हो सकता है । जे0 पी0 वर्ग उन्मूलन और समाज मे समानता लाने के लिए प्रारम्भ से ही प्रयत्नशील रहे है । जे0 पी0 के शब्दों मे-मै और मेरे साथियो के मस्तिष्क मे एक स्वच्छ विचार है कि सामाजिक,आर्थिक,राजनीतिक और सास्कृतिक आन्दोलनो को चलाने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की जाय ।[220]

जे0 पी0 की औद्योगीकरण की नीति मध्यममार्गी है । औद्योगीकरण के सबध मे उनके विचार नेहरु के नजदीक है । उनके अनुसार "समाजवादी भारत मे बडे और छोटे पैमाने पर चलने वाले दो प्रकार के उद्योग धन्धे होगे । सभी बडे पैमाने पर चलने वाले उद्योग धन्धो का स्वामित्व सघ सरकार अथवा प्रान्तीय सरकारो का होगा ।[221]

जे0 पी0 भारी उद्योग के साथ लघु उद्योगो को नेहरु के समान आवश्यक मानते थे । यह उद्योग सहायक उद्योग होगे । लघु उद्योगो के सबध मे इनका कहना था कि " छोटे पैमाने पर चलने वाले उद्योग-धन्धो का स्वामित्व समितियो के हाथ मे होगा । इन समितियो के सचालन सबधी नियम बनाने के अतिरिक्त राज्य उनके कार्य मे कोई हस्तक्षेप नही करेगा । राज्य द्वारा सचालित तथा उत्पादक समितियो द्वारा संचालित उद्योग-धन्धो के अतिरिक्त शहर की नगर पालिकाओ

---

219 - जे0 पी0 का भाषण- 'पाँच जन्य', 4 सितम्बर 1977

220 - अवध बिहारी लाल- "सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार-लोकनायक जय प्रकाश' पृष्ठ 115

221 - जे0 पी0 का भाषण- 14 सित0 1977 पटना

द्वारा सचालित उद्योग धन्धे भी होगे । नगर महापालिका बड़े उद्योग-धन्धो को तो नही लेकिन मध्यम और लघु उद्योगो का संचालन तो कर ही सकती है ।[222]

जे0 पी0 के लघु उद्योगो के संबध मे विचार नेहरू के विचारो से भिन्न है । जहॉ पर नेहरू जी लघु उद्योगो का स्वामित्व निजी हाथो मे प्रदान करने के पक्षधर थे वहॉ पर जे0 पी0 वैक्तिक स्वामित्व के स्थान पर सहकारी तत्व को अधिक महत्व देते थे । जे0 पी0 राज्य एकाधिकार को भी अनुचित मानते थे, लेकिन उद्योगो की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए उनका प्रबन्ध राज्य के अधीन ही करना उचित समझते है । जे0 पी0 ने जिस सहकारी तत्व को अनिवार्य बताया है उससे उनका अभिप्राय वैक्तिक एकाधिकार पर पाबन्दी लगाना था, जिससे विकेन्द्रण के आधार पर उत्पादन का लाभ सम्पूर्ण समाज को हो सके । लघु उद्योगो की ओर सकेत करते हुए तथा उनके आधुनिकीरण की ओर जे0 पी0 का विचार है कि "छोटे और सहायक उद्योग वास्तव मे बहुत महत्वपूर्ण साबित होगे । किसान एव मध्यम वर्ग का आर्थिक जीवन वास्तव मे सुखी हो जायेगा तथा एक प्रगति का मार्ग निश्चित होगा, ग्रामीण और छोटे-छोटे कुटीर उद्योग धन्धो को पुनजीवित करने की भी आवश्यकता होगी। इस विकास के लिए स्थानीय परिस्थितियो का अध्ययन का बहुत जरूरी है । लेकिन स्थूल सिद्धात तो निश्चित किये ही जा सकते है ।[223]" जे0 पी0 ने इन उद्योगो के सम्बन्ध मे सकेत किया कि जहॉ तक सम्भव हो सभी उद्योग धन्धे औद्योगिक सहयोग के अन्तर्गत चलाये जाये । उद्योगो से उत्पादन और तकनीकि मे उन्नति करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए । गॉव वालो को विशेषतया उत्साहित करने के लिए उन्ही उद्योगो को चलाना चाहिए जिनकी तकनीकि विस्तृत उतपादन की मशीनी तकनीकि से दूर न हो । ग्राम मे सहयोग मूलक धन्धो को कायम करना सम्भव है ।[224]

जे0 पी0 भारतीय परिस्थितियो के अनुसार उद्योगो की स्थापना करना चाहते थे नेहरू जी रूस की भौतिकवादी सम्पन्नता एवं आर्थिक विकास से बहुत प्रभावित थे । वे आधुनिक तकनीकि के आधार पर भारत का तीव्र गति से औद्योगीकरण करना चाहते थे । इसके लिए वे देशी एव विदेशी, दोनो साधनो को अनिवार्य समझते थे ।लेकिन जे0 पी0 भारतीय परिस्थितियो

---

222 - मीनू मसानी- "जे0 पी0 मिशन पार्टी एकम्पिलश्ड" पृष्ठ 49

223 - जय प्रकाश नारायण-"समाजवाद क्यो और कैसे,' पृष्ठ 27

224 - जय प्रकाश नारायण-"सामजवाद क्यो और कैसे,", पृष्ठ 132

के अनुरूप एव आवश्यकता के अनुसार उद्योगो को प्राथमिकता देते है । जे0 पी0 भारी उद्योगो को सीमित एव लघु उद्योगो को अधिक प्राथमिकता देना चाहते थे, क्योकि परिस्थितियां इसी के अनुकूल थी । वे नेहरू जी के समान छोटे पैमाने की उत्पादन इकाइयो मे आधुनिक तकनीकि एव विज्ञान का प्रयोग करना चाहते थे । जे0 पी0 ने अपनी पुस्तक "समाजवाद से सर्वोदय की ओर" मे प्रो0 हक्सले का कथन व्यक्त करते हुए कहा कि मेरा व्यक्तिगत विचार और समस्त विकेन्द्रीकरण के समर्थको का विचार है कि जब तक शुद्ध विज्ञान के निष्कर्षो का प्रयोग बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण करने वाली उद्योग व्यवस्था को महगे मूल्य पर अधिक विस्तृत और अधिकाधिक विशिष्ट बनाने मे होता रहेगा तब तक सत्ता का थोडे से हाथो मे विकेन्द्रीकरण के अलावा और कुछ नही हो सकता । आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के इस विकेन्द्रीकरण के परिणाम स्वरूप जनता निरन्तर अपनी नागरिक स्वतन्त्रता, अपनी व्यक्तिगत स्वायत्ता और स्वशासन के अवसरो से वचित रहेगी ।[225]

जे0 पी0 राष्ट्रीयकरण को सम्पत्ति के समान वितरण के लिए अति आवश्यक मानते थे । जे0 पी0 के अनुसार" मै इस निष्कर्ष पर आता हूँ कि सम्पत्तिक असमानताओ का मूल कारण इस वास्तविकता मे है कि प्रकृति की देन, जो मानव जाति के लिए जो सम्पत्ति की दाता है, साथ ही उत्पादन के कल-पूर्जो को अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगो ने वैक्तिक अधिकार मे कर रखा है, आर्थिक शोषण का यही कारण है । यानि मजदूर जितना उत्पादन करते है, उसमे से उतने ही छोडकर जितना एक निर्धारित जीवन माप के अनुसार गुजर के लिए आवश्यक समझा जाता है, सबका सब उसमे दबा लिया जाता है ।[226] जे0 पी0 के अनुसार इस समस्या का समाजवादी हल यह है कि उत्पादन के साधनो पर से वैक्तिक स्वामित्व का उन्मूलन कर दिया जाये और इन साधनो पर समूचे समाज का स्वामित्व स्थापित किया जाये ।[227] उत्पादन के साधनो पर व्यक्तिगत आधिपत्य के ह्रास और सामाजिक आधिपत्य की स्थापना होने से आर्थिक शोषण का लोप हो जायेगा ।दूसरे शब्दो मे कहा जाये तो वर्तमान समाज के मूलभूत विकार का नाश हो जायेगा ।

---

225 - जय प्रकाश नारायण-' समाजवाद क्यो और कैसे, पृष्ठ 132

226 - जय प्रकाश नारायण-"समाजवाद क्यो और कैसे, पृष्ठ, 133

227 - जय प्रकाश नारायण समाजवाद से सर्वोदय की ओर' पृष्ठ 55-56

समाजवाद के मौलिक सिद्धांत की ओर इंगति करते हुए जे0 पी0 ने कहा कि समाजवाद का मौलिक सिद्धान्त यही है कि "उत्पादन के साधानों का सामाजीकरण हो । समाजवादी निर्माण के किसी भी प्रयत्न के समय उत्पादन के साधनों पर से व्यक्तिगत आधिपत्य का अन्त करना ही होगा । आर्थिक शोषण जब समाप्त होगा तो आर्थिक असमानता ही नहीं रह जायेगी।[228]

जे0 पी0 मूल रूप से उत्पादन के साधनों का समाजीकरण करना चाहते थे । उनका मत है कि समाज में व्याप्त असमान्ता को कैसे दूर किया जाये ? इसंके संबन्ध में उन्होंने कुछ सुझाव रखे । उनके मतानुसार समाज में व्याप्त असमानता को दूर करने के दो ही उपाय हैं कि उत्पादन के साधनों पर सबका अधिकार हो और उसमें सबकों उपभोग की गारण्टी हो और जो कुछ पैदा होगा उसका बँटवारा पहले काम के रुप में और बाद में परिणाम के रूप में होगा । किन्तु पुनः धीरे-धीरे सबसे योग्यता के अनुसार काम लेने और अवश्यकतानुसार देने की व्यवस्थ की जायेगी । पैदावार का बँटवारा करते समय कुछ अंश राज्य और रक्षा के लिए तथा आर्थिक विकास के लिए रख दिया जायेगा । उन्होंने कहा कि "समाजवाद का मौलिक सिद्धांत क्या है ? उत्पादन के सभी साधनों पर समाजभर का अधिकार हो ।समाजवाद की मूलभित्ती यही है ।[229] समाजवादी ढंग पर समाज का पुनर्निर्माण तब तक सम्भव नहीं है, जब तक उत्पादन के साधनों पर से व्यक्तिगत अधिकार समाप्त नहीं कर दिया जयेगा ।"[230] यदि कोई राज्य समाजवाद का संगठन करना चाहता है तो सम्भव है कि वह तुरन्त स्थापित करने में समर्थ न हो सकेगा । लेकिन यदि उसे सफल होना है तो उत्पादन के उन सभी बड़े साधनों पर सामाजिक अधिकार कायम करना होगा । जो देश के आर्थिक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव रखते है । विकसित समाज में उत्पादन के साधनों के साथ ही विनिमय और वितरण के साधन भी उन्नतिशील होते रहते हैं ।उन पर भी सामाजिक अधिकार होना चाहिए । उद्योगों का राष्ट्रीयकरण मात्र ही समाजवाद नहीं है । जे0 पी0 के अनुसार " समाजवाद केवल पूँजीवाद नहीं है, न राज्यवाद है । उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और कृषि

---

228 - जय प्रकाश नारायण-"संघर्ष की ओर,"पृष्ठ 75-76

229 - जय प्रकाश नारायण-" संघर्ष की और," पृष्ठ 78

230 - जय प्रकाश नारायण-"समाजवाद क्यों और कैसे" पृष्ठ 1-8

का सामूहिकरण समाजवादी अर्थ रचना के महत्वपूर्ण पहलू है, परन्तु वे अपने आप मे समाजवाद नही है ।[231]

भारतीय कृषि व्यवस्था के सबध मे जे0 पी0 कृषि के स्वामित्व पर सामाजिक अधिकार को अधिक उचित मानते थे ।इस सबध मे उनका कहना था कि "यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाये तो इस संबध मे हम पायेगे कि समाजवादी आधार पर हिन्दुस्तानी जिन्दगी को ढालने के किसी प्रयत्न की सफलता के लिए खेती मे समाजवाद अर्थात सहकारी और सामूहिक किसानी की नितान्त आवश्यकता है ।"[232] प्राय सहकारी कृषि के सबध मे आक्षेप किया जाता है तथा समाजवादी राज्य मे जो कृषि व्यवस्था अपनायी जाती है उस पर व्यक्तिगत स्वामित्व के समर्थक उसकी आलोचना करते है कि इसमे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन किया जाता है । जे0 पी0 का इस सबध मे विचार था कि "मुख्य प्रश्न समाजवाद की स्थापना की सभवना के सबध मे नही है, किन्तु यह है कि समाजवाद के द्वारा हिन्दुस्तानी काश्तकारी हिन्दुस्तानी किसान और हिन्दुस्तानी राष्ट्र का कितना हित होगा और इस प्रश्न का हमारे पास प्रबल उत्तर है। हमारे हृदय मे तनिक भी सदेह नही है कि केवल समाजवाद ही भारतीय किसानो की बरबादी और दिवालियापन से बचा सकता है । अकेला यही राष्ट्र को शक्ति सपन बना सकता है ।[233]

जे0 पी0 ने जहॉ कृषि समस्याओ की ओर सकेत किया वहॉ उन्होने सुझाव भी रखे उनका विचार है कि-"इसका तो एक मात्र हल यही है कि भूमि के जोतो के शोषण मे किसी भी प्रकार से सहायक होने वाले निश्चित स्वार्थो का सफाया कर दिया जाये ।अराजियो का राष्ट्रीयकरण करके सहयोगी और सामूहिक किसानी की स्थापना की जाये । कर्ज देने और मण्डियो की व्यवस्था सरकार और सहयोग समितियो के हाथो मे रहे तथा सहयोग समितियो द्वारा सहायता प्राप्त उद्योग धन्धो की स्थापना की जाये ।[234]

जे0 पी0 असमानता का एक मुख्य कारण भूमि का असमान वितरण मानते थे । उनका विचार था कि भूमि के पुनर्वितरण के बिना अपने लक्ष्य को हम प्राप्त नही कर सकते ।

---

231 - वही,' पृष्ठ 17

232 - वही,' पृष्ठ 18-19

233 - डा0 लख्मी नारायण लाल-"जय प्रकाश नारायण' पृष्ठ 18

231 - जय प्रकाश नारायण - सघर्ष की ओर,"पृष्ठ 98

उन्ही के शब्दो मे "सार्वजनिक स्वामित्व हमारा लक्ष्य है अतएव यह बात की हम किसानो को फिर से जमीन बॉटने की सोचे, एक अजीब सी मालूम होती है । इसलिए सार्वजनिक स्वामित्व और जमीन की काश्त की तरक्की नही हो सकती । इसलिए हमे जमीन पर किसानो के स्वामित्व की बात को पहले लेना पडेगा ।[235] उन्होने आगे कहा कि "इस समय किसानो को मिली हुई आराजी मे घोर विषमता है ।जहॉ तक कुछ अराजियॉ सैकडो एकड की है वहॉ दूसरी एक एकड भी नही है। इसलिए एक बडे फर्क को मिटाने के लिए हम जमीन का फिर से बॅटवारा करने की तजबीज पेश करते है ।[236]

जे0 पी0 नेहरु के समान ही जर्मीदारी प्रथा को कृषि के विकास मे बाधक समझते थे । इनका विचार था कि जमीदारी प्रथा की मौजूदगी मे हम कृषि व्यवस्था का विकास नही कर सकते । हमारी कृषि व्यवस्था वास्तव मे असमानता के आधार पर आधारित है । समाजवाद कृषि की स्थापना के सिलसिले मे सहयोग तथा सामूहिक कृषि की दो प्रणालियॉ है । जमीदारी प्रथा की समाप्ति के बाद ज्यादा बडी जोतो को तोडने और बिल्कुल छोटी जोतो को इतनी बडी बनाने के उद्देश्य से कि उन पर खेती करना आर्थिक दृष्टि से अलाभकर हो, भूमि का फिर से बॅटवारा करना जरुरी होगा । गॉव की जमीन पर मालिक कानून की दृष्टि से अलग-अलग न होकर समूचा गॉव ही होगा । और अलग व्यक्तियो के साथ खेत का बन्दोबस्त करना राज्य के द्वारा बनाये गये नियमो के अनुसार ग्राम पचायतो का कार्य होगा । इस प्रकार बन्दोबस्त की गयी जमीन पर किसानो का एक प्रकार मालिकाना हक होगा । उन जमीनो को छोडकर जिनसे बडी या छोटी होने के कारण घोर विषमता को दूर करने की दृष्टि से बॅटवारा करना जरुरी हो जायेगा।[237]

सन् 1952 ई के आम चुनाव के उपरान्त जे0 पी0 की विचारधारा मे एक नया मोड आया । सन् 1951 ई0 से विनोबा के नेतत्व मे चलते हुए भूदान ग्रामदान आन्दोलन ने जे0 पी0 के नये चिन्तन को एक ठोस आधार प्रदान किया । इसके प्रति उनका आकर्षण बढ गया कि उन्होने सन् 1954 ई0 मे बोध गया के सर्वोदय सम्मेलन के अवसर पर भूदान ग्राम-दान आन्दोलन के लिए अपना जीवन दान करने की घोषणा कर दी तथा प्रजा समाजवादी दल से त्याग पत्र दे दिया । उन्हे

---

235 - वही, पृष्ठ 94

236 - वही, पृष्ठ 95

237 - जय प्रकाश नारायण" सघर्ष की ओर ", पृष्ठ 13

अपने लक्ष्य की प्राप्ति इसी विचारधारा मे दिखाई देने लगी । उन्होने कहा कि किसी एक पक्ष द्वारा भू-वितरण का आन्दोलन चलाने की अपेक्षा, विनोबा जी का पक्षातीत आन्दोलन चलाने का रास्ता मुझे ज्यादा सही लगा । धीरे-धीरे मुझे यहॉ तक प्रतीत होने लगा कि विनोबा जी ने केवल हमारे सामने भू-समस्या का हल रखा, बल्कि भूदान आन्दोलन अहिंसक तरीके से सामाजिक क्रान्ति तथा समाज के नव निर्माण का पहला कदम है ।[238]

जे0 पी0, नेहरु जी के समान ही भूमि के पुनर्वितरण मे तथा जमीदारी प्रथा के उन्मूलन मे विश्वास रखते है । उन्होने न केवल सैद्धान्तिक क्षेत्र मे ही बल्कि व्यवहार मे भी भूमि पुनर्वितरण के लिए कार्य किया । उन्होने भूदान आन्दोलन के अन्तर्गत जमीदार वर्ग से जमीन लेकर भूमिहीन किसानो मे वितरण किया ।

जे0 पी0 का आगमन भारतीय राजनीति मे एक मार्क्सवादी के रुप मे हुआ । परन्तु उद्देश्य की अपूर्णता और मार्क्सवादी असफलता ने जे0 पी0 को सर्वोदय की ओर आकर्षित किया । सन् 1954 ई0 मे उन्होने मार्क्सवाद से सबध विच्छेद कर लिया और भूदान आन्दोलन में अपनी आस्था व्यक्त की और उसे शान्ति पूर्ण क्रान्ति का नाम दिया, परन्तु उसमे भी जे0 पी0 को अपना उद्देश्य पूर्ण होने मे शका हुई । जे0 पी0 ने सन् 1974 ई0 मे सम्पूर्ण क्रान्ति की घोषणा की ।

सत्तर के दशक मे जे0 पी0 की विचारधारा मे एक नया मोड आने लगा था । वे प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए क्रान्ति की अनिवार्यता को महसूस करने लगे थे ।5 जून 1974 को पटना के गॉधी मैदान की विशाल सभा मे उन्होने पहली बार सम्पूर्ण क्रान्ति शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि " यह आन्दोलन छात्र सघर्ष समिति की मात्र 10-12 मागो की पूर्ति के लिए ही नही, यह सम्पूर्ण क्रान्ति की शुरुआत है । इसके उद्देश्य बहुत दूरगामी है, भारतीय लोकतन्त्र को वास्तविक तथा सुदृढ बनाना, जनता का सच्चा राज कायम करना, समाज से अन्याय शोषण आदि का अन्त करना, एक नैतिक, सास्कृतिक तथा शैक्षणिक क्रान्ति करना, नया भारत बनाना ।"[239] जे0 पी0 ने नेहरु एव लोहिया के समान ही समस्या के विरुद्ध आन्दोलन को मान्यता प्रदान की तथा नेहरु के समान एक ऐसे सगठन का विचार रखा जिसमे व्यक्ति

---

238 - वही, पृष्ठ 13

239 - जय प्रकाश नारायण-"समाजवाद क्यो और कैसे," पृष्ठ 24

स्वेच्छापूर्वक अपना योगदान दे । व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक सगठन बनाये जिसमे शिक्षण संस्थाएँ तथा राजनैतिक दल एव प्रत्येक नागरकि इसमे सयुक्त रुप से हिस्सा ले । प्रत्येक नवयुवक का यह राष्ट्रीय कर्त्तव्य है कि वह इस सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शान्तिपूर्ण साधनो और यदि आवश्यक हो तो हिंसात्मक साधनो से भी पूर्ण करे ।[240]

सम्पूर्ण क्रान्ति से जे0 पी0 का अभिप्राय था कि समाज मे आमूल परिवर्तन हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सास्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक एव आध्यात्मिक परिवर्तन।''[241] इस प्रकार की क्रान्तियॉ यहॉ मिलकर सम्पूर्ण क्रान्ति होगी । सात की इस सख्या को घटाया और बढाया जा सकता है । उदाहरणार्थ-सास्कृतिक क्रान्ति मे शैक्षिणिक क्रान्ति सन्निहित हो सकती है और यदि कल्चर का एन्थ्रोपोलिजिकल अर्थ लिया जाये तो उसमे लगभग सब कुछ आ जाता है किन्तु जो प्राथमिक समाज के सन्दर्भ मे लिया जाता है उसी प्रकार यदि सामाजिक क्रान्ति को भी मार्क्सवाद की भूमिका मे 'सामाजिक क्रान्ति' जैसा अर्थ लिया जाये तो आर्थिक राजनैतिक क्रान्तियॉ उसमे अवश्य आ जाती है, अन्य बहुत कुछ भी इसमे समा सकता है। यदि इसकी सख्या को बढाना है तो उदाहरण स्वरुप आर्थिक क्रान्ति मे से ही औद्योगिक क्रान्ति, कृषि से सबधित क्रान्ति व यान्त्रिक क्रान्ति इत्यादि भेद किये जा सकते हैं ।

आर्थिक क्रान्ति समाज की आर्थिक रचना तथा आर्थिक संस्थाओ मे क्रान्तिकारी परिवर्तन और उनका नया क्रान्ति-कृत रुप अर्थात क्रान्ति शब्द से परिवर्तन और नव निर्माण दोनो ही अभिप्रेरित है । आर्थिक क्रान्ति मे स्वामित्व और प्रबन्ध मे भी क्रान्तिकारी परिवर्तन आ ही जाता है । स्वामित्व और प्रबन्ध के नाते हर हालत मे राज्य प्रबन्ध ही हो यह आवश्यक नही है, स्वामित्व राज्य का भी हो सकता है । व्यक्ति या व्यक्तियो की कम्पनी या रजिस्टर्ड सोसाइटी इनके मिश्रित रुपो का भी जैसे सहयोग समिति, स्थानीय समिति, ग्राम सभा, ग्राम समूह, समूह सभा, प्रखण्ड सभा, जिला परिषद आदि का भी हो सकता है, और इनके कई मिश्रित रुप भी हो सकते है । यानी स्थानीय स्वामित्व तथा पूर्व वर्णित स्वामित्वो का समिश्रण, उपभोक्ता का स्वामित्व, उत्पादको का स्वामित्व आदि । सामाजिक परिवर्तन ऐसा हो

---

240 - जय प्रकाश नारायण-''जीवन दान'' पृष्ठ 9

241 - जय प्रकाश नारायण-' सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज मे मेरी विचार यात्रा'' (स0), सव्र सेवा सघ प्रकाशन वाराणसी, पृष्ठ 86

कि सामाजिक कुरीतियॉ दूर हो । इसमे से नया समाज निकले जिसमे सभी सुखी हो, धनी-गरीब का भेद न हो, शोषण न हो ।

राजनैतिक क्रान्ति का अभिप्राय है, भारतीय लोकतन्त्र को लोकभिमुखी तथा सुदृढ़तर बनाना, जनता का राज्य कायम करना, सर्वोपरि सत्ता जनता के हाथ मे होना सास्कृतिक परिवर्तन का मतलब है, सामज मे त्याग-बलिदान, प्रेम, अहिंसा भाइचारा आदि सद्गुणों का विकास। जे0 पी0 के अनुसार "सम्पूर्ण क्रान्ति मे व्यवस्था भी बदलेगी और व्यक्ति भी इनमे कोई आगे पीछे नही, साथ-साथ होगा । व्यक्ति समूह के लिए जिये और समूह व्यक्ति के लिए । यह मानवीय क्रान्ति होगी,ऐसी क्रान्ति जिसमे भारत का आध्यात्म व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन मे उतर जायेगा । तब व्यक्ति अपने हितो का दर्शन समूह के हितो मे करने लगेगा ।इस क्रान्ति के बिना न समाजवाद आयेगा न साम्यवाद ।"[242] सम्पूर्ण क्रान्ति के सारे परिवर्तन मौटे तौर पर महात्माँ गाँधी की विचारधारा के अनुरुप होगे, सर्वोदय इस क्रान्ति का दूसरा नाम है ।

जे0 पी0 इस निष्कर्ष पर पहुॅचे कि सामूहिक हितो की रक्षा सामूहिक चेतना ही कर सकती है । इसी सामूहिक चेतना को वह सम्पूर्ण क्रान्ति द्वारा जगाना चाहते थे । जे0 पी0 के शब्दो मे "हमे सामान्य जनता का राज्य चाहिए इसलिए हिंसा का मार्ग तो हमारे लिए सर्वथा त्याज्य है ।जहॉ कानून निष्फल हो जाता है वहॉ अहिंसा से ही आगे बढना होता है ।कोई कहे कि अहिंसक क्रान्ति से रक्तपूर्ण क्रान्ति जल्दी होती है तो भ्रम है, दुनियॉ की क्रान्तियॉ देखने से ऐसा लगता है, पुराने समाज को तोडने मे हिसा क्रान्ति लम्बे अरसे के बाद सफल होती है । और उसके बाद नये सामाजिक निर्माण मे और अधिक समय लगता है ।"[243] लेकिन अहिंसक क्रान्ति मे पुराने समाज को बदलने और नये समाज के गठन का काम साथ-साथ होता है । अहिंसक प्रक्रिया मे यह सबसे बडा गुण है कि परिवर्तन और नवर्मािण दोनो साथ-साथ चलते है ।

जे0 पी0 गॉधी जी के ही मार्ग पर चलकर इस देश मे राजनीतिक, सामाजिक क्रान्ति एवं आर्थिक-सास्कृतिक परिवर्तन लाना चाहते थे । इसी को उन्होने "सम्पूर्ण क्रान्ति" का नाम दिया । सम्पूर्ण क्रान्ति का विचार जे0 पी0 का अपना मौलिक विचार नही है । डा0 लोहिया ने सप्त क्रान्ति

---

242 _ जय प्रकाश नारायण-" सम्पूर्ण क्रान्ति खोज मे मेरी विचार यात्रा' (स) सेवा सघ, प्रकाशक वाराणसी,पृष्ठ 86

243 _ अवध बिहारी लाल-"सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्राधार-जय प्रकाश" पृष्ठ 8

की कल्पना की थी जिसमे वे सभी तत्व मौजूद है जिसकी कल्पना जे0 पी0 करते है। जे0 पी0 ने सम्पूर्ण क्रान्ति के कारणो की ओर सकेत किया क्योकि सम्पूर्ण क्रान्ति होनी चाहिए। आजादी मिलने के बाद से भारतीय समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढाचे मे कोई परिवर्तन नही हुआ। आजादी मिलने से लेकर आजतक राजनीतिक, सार्वजनिक और व्यावसायिक नैतिकता का ह्रास भी होता रहा है।

कुछ अशो मे जय प्रकाश नारायण अपने ध्येय मे सफल भी हुए। सन् 1977 ई0 का सत्ता परिवर्तन उन्हीं के परिणामो का प्रयास रहा है। नेहरु एव जे0 पी0 की क्रान्ति सबधी अवधारणा मे काफी साम्यता है। दोनो ही विचारक अहिसक क्रान्ति के पक्षपाती है। जबकि भिन्नता यह है कि नेहरु का सोचने विचारने का तरीका पाश्चात्य विचारको से ओत-प्रोत था जबकि जे0 पी0 विदेशी विचारो को ग्रहण करने के बाद उसका भारतीयकरण कर देते थे। वे अधिकतर गॉधी जी के सविनय अवज्ञा सिद्धात को मानते थे जो कि अहिंसक क्रान्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। वे मार्क्सवादी विचारो मे आस्था रखते हुए भी मार्क्सवादी साहित्य की सबसे बडी देन हिन्सात्मक क्रान्ति से हमेशा दूर रहे।[244]

---

244 - जय प्रकाश नारायण-"सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज मे मेरी विचार यात्रा," पृष्ठ 112

अध्याय—3

भारत में दलीय समाजवाद

अध्याय-3

भारत में दलीय समाजवाद

भारत के समाजवादी दल

1 कांग्रेस समाजवादी दल

(i) **स्थापना व लक्ष्य**-सन् 1848 के साम्यवादी घोषणा पत्र को सामाजिक और आर्थिक समानता सबधी घोषणा[1] का भारत के समाजवादी नेताओ पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके फलस्वरुप सन् 1922 से 1939 की अवधि मे भारत मे समाजवादी आन्दोलन की गति काफी तीव्र रही[2] और देश मे अनेक समाजवादी तथा साम्यवादी दलो की स्थापना हुई।[3]

मई 1934 मे काग्रेस समावादी दल की स्थापना भारत मे समाजवाद के संगठनात्मक विकास मे एक महत्वपूर्ण घटना थी ।[4]काग्रेस के प्रगतिशील नेताओ मे अधिकारिक नेतृत्व के दक्षिणपथी नीतियो एव कार्यवाहियो के विरुद्ध असतोष की ज्वाला सुलग रही थी। गाँधी की सरकार के समक्ष घुटनाटेक गॉधी-इर्विन समझौते की कार्यवाही से प्रज्वलित हुई। और इन नेताओ ने काग्रेस मे ही एक ऐसे सगठन की आवश्यकता महसूस की जो समाजवादी एव प्रगतिशील रुझानो से प्रतिबद्ध हो। प्रगतिशील नेताओ की इसी इच्छा की परिणति अनत· काग्रेस समाजवादी दल की स्थापना मे हुई।

गॉधी के नेतृत्व के विरुद्ध जो प्रतिक्रियाएँ आरम्भ हुई और जिसके कारण काग्रेस के प्रगतिशील (वामपथी) नेताओ मे असन्तोष फैला उसका विश्लेषण आवश्यक है। सन् 1927 के काग्रेस महासम्मेलन मे यह बात स्पष्ट हो गयी कि काग्रेस पर गॉधी का नेतृत्व निर्विवाद नही है। जवाहर लाल नेहरु तथा सुभाष चन्द्र बोस ने सर्वप्रथम सम्पूर्ण स्वतन्त्रता से सबद्ध जो प्रस्ताव रखा, वहॉ गॉधी के विरोध के बावजूद पारित हो गया और कार्यकारिणी समिति में बोस, नेहरु तथा उस0 कुरैशी ले लिए गये। उसके साथ ही मद्रास काग्रेस के दौरान इस बात की प्रमाणिक

---

1 - मार्क्स एगेल्स-कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, पृष्ठ 65

2 - डा0 राम मनोहर लोहिया- समाजवादी आन्दोलन का इतिहास, पृष्ठ 12

3 - एम0 आर0 मसानी- दि कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया, पृष्ठ 2

4 - जब मई 1934 मे काग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी, समाजवादियो ने उसे 'वामपथी सुधारवाद' बताया तथा उसकी निन्दा की ।

डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति ही अपना उद्देश्य मानता है तथा दूसरा सम्पूर्ण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्ति के उद्देश्य से ओत प्रोत है। गॉधी इससे सन्तुष्ट नही थे क्योंकि वे पहले तत्व के प्रबलतम समर्थक थे और येन केन प्रकारेण वह चाहते थे कि काग्रेस डोमेनियन स्टेट्स का ही समर्थन करे। नवम्बर 1928 मे कलकत्ता काग्रेस के दौरान उन्होने इससे सम्बद्ध प्रस्ताव भी रखा जिसका वामपथी नेताओ (तत्वो) द्वारा डटकर विरोध हुआ। बोस और नेहरु ने प्रस्ताव का डटकर विरोध करते हुए उसमे सशोधन पेश किया, जिसमे यह कहा गया था कि सम्पूर्ण स्वतन्त्रता तथा ब्रिटिश सरकार से सम्पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद की बात स्वीकार की जाए । जब सशेधन पर मतदान हुआ तो अधिकाश सदस्यो ने गॉधी के मौलिक प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इस सशोधन प्रस्ताव को रद्द कर दिया। सशोधन के पक्ष मे 973 मत पडे जबकि विरोध मे 1350 मत गॉधी की हठधर्मिता यहा स्पष्ट थी कि येन-केन प्रकारेण, उन्होने मद्रास प्रस्ताव को बदलवा दिया । इतना ही नही जिन लोगो ने सशोधन के विरोध मे मतदान किया था, उन्होंने भी यह कहा कि वे सशोधन के विरुद्ध इतना नही है, जितना उन्हे इस बात का डर है कि यदि सशोधन पारित हो जाता तो गॉधी काग्रेस से पृथक हो जाते जो काग्रेस के लिए अन्तत घातक सिद्ध होता। इससे स्पष्ट होता है कि गॉधी ने इस प्रकार की धमकी भी दी थी। गॉधी की इस कुटिल योजना से वामपथी तत्वो का खिन्न होना स्वाभाविक था। किन्तु इससे एक बात स्पष्ट हो गयी कि काग्रेस मे इन तत्वों की स्थिति नगण्य नही थी।जिसे सरकार ने भी अपने दस्तावेज मे स्वीकार किया। इसी अवधि के दौरान नेहरु ने विदेश यात्रा की और ब्रुसेल्स मे साम्यवादियो द्वारा प्रेरित "उत्पीड़ित जातीयताओ की कांग्रेस" मे भाग लिया। समाजवादी व मार्क्सवादी शिक्षाओ और सिद्धातो से वे काफी प्रभावित हुए तथा भारत लौटने पर वे इन मूल्यो के समर्थक बन गये थे। इसके बावजूद वे उदारवादी परम्परा से इतना अधिक प्रभावित थे कि उससे नाता तोडना उसके लिए सभव नही था। इसी तथ्य को ध्यान मे रखते हुए नेहरु के विषय मे बोस ने लिखा कि वे मस्तिष्क से तो वामपथियो के साथ हैं परन्तु हृदय से महात्मा गॉधी के अन्यतम समर्थक है। सुभाष चन्द्र बोस का यह कथन बाद मे सन् 1929 ई0 मे लाहौर काग्रेस के दौरान सच्चा साबित हुआ । गॉधी ने नेहरु को काग्रेस की अध्यक्षता प्रदान करने की पेशकश की । वामपथियो ने गॉधी की नीतियो को समझा तथा उन्होने यह आशंका व्यक्त की कि नेहरु गॉधी के हाथो मे खिलौना मात्र बन जायेगे। नेहरु अध्यक्ष बने लेकिन वह नाम मात्र के लिए अध्यक्ष थे। निर्णय गॉधी की इच्छानुसार ही होते थे। लाहौर काग्रेस

के दौरान गॉधी ने एक और कुटनीतिक चाल खेली । सम्पूर्ण स्वतन्त्रता के सिद्धात का समर्थन करते हुए बहुत से वामपथी सदस्यो को गॉधी ने अपने खेमे मे ले लिया अर्थात गॉधी ने वामपथी तत्वो को बडी चतुराई से विखण्डित करने का प्रयास किया जिसमे तत्कालिक तौर पर उन्हे सफलता प्राप्त हुई और वामपथी खेमे मे उदासीनता छा गयी।

लाहौर काग्रेस के दौरान गॉधी का बोल बाला रहा। इस काग्रेस मे उन्होने एक प्रस्ताव रखा जिसमे कहा गया था कि वायसराय को ईश्वरीय इच्छा के फलस्वरुप बम विस्फोट से बच निकलने पर बधाई दी जाये। वामपंथियो ने इसे निरर्थक और अनावश्यक माना, लेकिन गाँधी के प्रयत्नो से यह प्रस्ताव थोडे से बहुमत से पारित हो गया। बोस का वह प्रगतिशील प्रस्ताव भी रद्द कर दिया गया। जिसमे समान्तर सरकार व किसानो, मजदूरो और युवको के स्तर पर सगठन बनाने की बात की गयी थी। इतना ही नही, गॉधी अपनी इस कूटनीति मे भी सफल रहे कि अधिक से अधिक वामपथी तत्वो को सगठनात्मक दायित्वो से निकाल फेका जाए । सुभाष चन्द्र बोस एव श्रीनिवास आयगर को कार्यकारिणी समिति से इस आधार पर निष्काषित कर दिया गया कि परस्पर विरोधी विचार वालो को कमेटी मे नही रखना चाहिए । इस निष्कासन का यद्यपि घोर विरोध हुआ लेकिन काग्रेस को एक जुट बनाये रखने के नाम पर वामपथी तत्वो को इसे भी स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पडा । इस तरह लाहौर कांग्रेस मे सारा मैदान गॉधी के हाथ रहा और वामपथी तत्वो को असफलता एव विवशता का सामना करना पडा । गॉधी व वामपथी तत्वो के मध्य अन्तर्विरोध बढ रहा था यह स्पष्ट है ।[5]

मार्च 1931 मे काग्रेस की बैठक जब कराची मे हुई उस समय राजनीतिक वातावरण मे काफी परिवर्तन हो चुका था । इस बैठक का मुख्य उद्देश्य गॉधी-इर्विन समझौते का स्वागत करना था । नागरिक अवज्ञा आन्दोलन का प्रथम चरण समाप्त हो चुका था । इस आन्दोलन के दौरान जन साधारण मे जो अद्वितीय राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई थी, उससे दक्षिणपंथी नेतृत्व भयग्रस्त हो गया था।जबकि वामपथी तत्वो को अपनी बात व्यापक रुप से कहने का अवसर प्राप्त हुआ । नागरिक अवज्ञा आन्दोलन उठा लिये जाने के कारण जन साधारण मे असन्तोष उत्पन्न हो गया था जो निश्चय ही गॉधी एव दक्षिपथी नेतृत्व के विरोध मे अधिक था । जन साधारण के असन्तोष का दूसरा कारण और भी गम्भीर था। स्वतन्त्रता सग्राम के तीन सेनानियो

---

5 - सत्या राय (सपादिका)- 'भारत मे राष्ट्रवाद' पृष्ठ 262

(क्रान्तिकारियो)भगत सिह, राजगुरु और सुखदेव को फासी की सजा भुगतनी पड़ी। गाँधी को बोस ने समझौता वार्ता आरम्भ होने पूर्व यह सम्मति दी थी कि यदि सरकार इन तीनो क्रान्तिकारियो की रिहाई की माग को स्वीकार नही करती है तो वे (गॉधी) समझौता वार्ता को भंग कर दे।गॉधी ने इस सम्मति को स्वीकार नही किया तथा समझौता वार्ता जारी रही और सरकार ने इन क्रान्तिकारियो को फॉसी की सजा दे दी। गॉधी भले ही, इस सजा के पक्ष में प्रत्यक्षत न रहे हो, लेकिन वे निर्दोष नही कहे जा सकते। इस घटना से जन साधारण व उनके नेतृत्व से अत्यन्त क्षुब्ध था, जिसके फलस्वरुप जब गॉधी व निर्वाचित अध्यक्ष बल्लभ भाई पटेल करॉची अधिवेशन मे भाग लेने पहुँचे तो उन्हे जबरदस्त जन आक्रोश एव प्रदर्शन का सामना करना पडा । खुले अधिवेशन मे भगत सिह व उनके साथियो के बलिदानो का स्वागत करते हुए जब प्रस्ताव रखा गया तो गॉधी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, वहॉ भी उन्हे गभीर जन आक्रोश का सामना करना पडा । हालाकि प्रस्ताव सशोधित रुप मे पारित हुआ तथापि गॉधी की छवि धूमिल हुई। इसमे कोई सन्देह नही वामपथी तत्वो का यह विचार था कि गॉधी-इर्विन समझौते को समर्थन न मिले तथापि पार्टी की एकता को बनाये रखने तथा सरकार की इस नीति को असफल बनाने के लिए काग्रेस मे विभाजन न हो और न विघटन स्पष्ट रुप से सामने आ जाए, उन्होने इसका विरोध खुलकर नही किया और समझौते के स्वागत से सम्बद्ध प्रस्ताव पारित हो जाने दिया । इसके बावजूद वामपथी तत्वो का प्रभाव काग्रेस रणनीति एव नीति-निर्धारण पर व्यापक रुप से पडा तथा दक्षिणपथी गुट को (जिसके नेता गॉधी थे) सुरक्षात्मक नीति अपनानी पडी ।[6]

दक्षिणपथी तत्वो ने गॉधी की इच्छा के प्रतिकूल कराची मे, वामपथी तत्वो की विजय इस बात मे भी रही की वे मौलिक अधिकारो व आर्थिक नीति से सबद्ध प्रस्ताव को पारित करवा लेने मे सफल रहे। जिसमे मोटे तौर पर इस बात पर बल दिया गया था कि जन साधारण के शोषण को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक स्वतन्त्रता अनिवार्य रुप से वास्तविक आर्थिक स्वतन्त्रता से आबद्ध हो । बड़े-बडे उद्योगो और सेवाओ के राष्ट्रीयकरण की माग वास्तव मे प्रगतिशील तो थी ही, जो गॉधी समेत दक्षिण गुट को मान्य नही थी। कराची मे यह सिद्ध हो गया कि कांग्रेस का वामपथी तत्व सर्वथा नगण्य नहीं है, उसका अपना प्रभाव है और कंाग्रेस नेतृत्व उसे दृष्टि से ओझल नही कर सकता । इससे इस तथ्य की भी पुष्टि हुई कि गॉधी व उनका

---

6 - सत्या राय (सपादिका)-"भारत मे राष्ट्रवाद' के ' काग्रेस समाजवादी पार्टी तथा अन्य वामपथी दल" नामक अध्याय वी0 पी0 पाण्डये द्वारा लेखबद्ध किया गया।

नेतृत्व ही काग्रेस नही है, उसमे ऐसे भी तत्व है जिनका स्वतन्त्र राजनीतिक चिन्तन है और ये तत्व काग्रेस मे पर्याप्त तथा व्यापक प्रभाव रखते है जिनसे काग्रेस नेतृत्व विमुख नही हो सकता ।

काग्रेस की गैर प्रगतिशील नीतियो एव कठमुल्लावादी नीति से असन्तुष्ट कुछ काग्रेसियो ने सन् 1931 ई0 मे सर्व प्रथम उत्तरी बिहार मे समाजवादी सघो की स्थापना की । सन् 1932-33 के दौरान नासिक केन्द्रीय कारागार मे रखे गये कुछ काग्रेसियो ने (जिसमे जय प्रकाश नारायण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी) अखिल भारतीय समाजवादी दल का खाका तैयार किया जिसे बाद मे उत्तर प्रदेश और बम्बई के क्षेत्रो मे लोकप्रियता प्राप्त होती गयी । धीरे-धीरे समाजवादी विचारो से प्रभावित काग्रेसी समाजवादी पार्टी की स्थापना की । इस तरह सन् 1934 ई0 मे पटना मे काग्रेस महासमिति की बैठक के समय ही इन सदस्यो की एक अलग बैठक हुई जिसमे अखिल भारतीय काग्रेस समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई तथा बम्बई मे अक्टूबर-नवम्बर के दौरान इसकी नीतियॉ एव कार्य प्रणाली तय की गयी । इस तरह काग्रेस समाजवादी दल की स्थापना मे जिस नेताओ ने सक्रिय योगदान दिया उनमे निम्नलिखित थे- जय प्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेन्द्रदेव, अच्युत पटवर्धन, एम0 आर0 मसानी0, डा0 राम मनोहर लोहिया, एन0 जी0 गोरे, एस0 एम0 जोशी, पुरुषेत्तम विक्रमदास, यूसूफ मेहर अली, गगा शरण सिह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि ।[7]बाद मे जिन अन्य काग्रेसी व अन्य विचारधाराओ से सम्बद्ध नेताओ ने इसकी सदस्यता ग्रहण की उनमे मुख्य थे- ई0 एम0 एस0 नम्बूदरी पाद, रायवादी चार्ल्स मतकारेन हास, रजनी मुखर्जी, धर्मदास गुणवर्धन, मनी बेनकर, आर0 एम0 एन0 ए0 खेडमिकर, एम0 आर0 शेट्टी, बी0 एम0 तारकुण्डे, एच0 आर0 महाजनी, जी0 पी0 खेर, आर0 के0 खडिलकर, अहमदाबाद मे ठाकुर प्रसाद पड्या, डी0 एम0 ठक्कर तथा दक्षिण के ए0 के0 पिल्लई (जो प्रसिद्ध रायवादी थे) आदि । जिन दो राष्ट्रीय नेताओ का इस पार्टी को आशीर्वाद था और जो इसकी नीतियो का खुलेआम समर्थन भी करते थे, लेकिन इससे सक्रिय रुप से सम्बद्ध नही हो पाये थे, वे थे पं0 जवाहर लाल नेहरु तथा सुभाष चन्द्र बोस, गॉधी के अन्यतम विश्वास पात्र होने के कारण सम्भवत नहेरु समाजवादी पार्टी से अपने को सम्बद्ध नही कर पाये । लेकिन सन् 1929 मे उन्होने जो घोषणा की थी वह समाजवादी नीतियो से काफी ओत-प्रोत लगती थी । बाद मे वह भी समाजवाद से अपनी सम्बद्धता का प्रलाप

---

7 - अशोक मेहता- ''डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एण्ड स्टडीज इन एशियन सोशलिज्म'

करते रहे, लेकिन सक्रिय रुप से इसे अपना नही पाये । सुभाष चन्द्र बोस सम्भवत· गॉधी के जबरदस्त विरोधी होने के कारण इस सस्था से अपने को सक्रिय रुप से सम्बद्ध नहीं कर सके, हालाकि उस पार्टी की नीतियो से वे काफी सीमा तक आबद्ध रहे । गॉधी कग्रेस समाजवादी पार्टी के सदैव विरोधी रहे क्योकि उनके लिए वर्ग संघर्ष सदैव असहमति का विषय ही बना रहा तथा वर्ग सहयोग की कामना उनका एक आदर्श लक्ष्य था, जिसकी प्राप्ति तो नही हो सकी और नही यह सभव था ।

एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि काग्रेस समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस बात को ध्यान मे रखा कि वह काग्रेस पार्टी से ही सम्बद्ध रहे और कोई ऐसा कार्य न करे जो काग्रेस की नीतियो का विरोध करता हो ।उनका सीधा लक्ष्य था कि काग्रेस को समाजवादी मूल्यो से आबद्ध किया जाये तथा इसकी बुनियादी नीतियो को बनाये रखा जाये ।इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि काग्रेस समाजवादी दल के लोग समाजवाद की वैज्ञानिक मान्यताओ को स्वीकार करने के स्थान पर काग्रेस की नीतियो मे समाजवादी सुधारो के लिए कृत सकल्प थे । अर्थात वे काग्रेस की नीतियो को समाजवादी मूल्यो से ओत-प्रोत तो करना चाहते थे लेकिन काग्रेस को समाजवादी नीतियो के बनाने के प्रबल समर्थक नही थे।

बहुत थोडे लोग थे जो इस विचार के थे । उनकी सख्या इतनी कम थी कि यदि ऐसा करने का प्रयास किया जाता तो काग्रेस समाजवादी दल बनने से पहले ही टूट जाता । पार्टी के सस्थापको की राजनीतिक विचारधारा समान नही थी अर्थात वे पृथक-पृथक राजनीतिक विचारधाराओ से प्रतिबद्ध थे, जिसका प्रभाव पार्टी के नीतिनिर्धारण आदि क्रियाकलापो पर स्पष्ट रुप से पडा ।चूँकि पार्टी की नीतियॉ सदस्यो के पूर्वाग्रहो से ग्रसित राजनीतिक मान्यताओ से निर्धारित हुई । इसलिए पार्टी अन्त तक सार्वजनिक, शाश्वत एव मौलिक नीतियो तथा कार्यक्रमो के निर्धारण मे असफल रही । यहॉ काग्रेस समाजवादी पार्टी से सम्बद्ध शीर्षस्थ नेताओ की राजनीतिक पृष्ठ भूमि का अवलोकन सदर्भवश, युक्ति सगत तो है ही, काफी दिलचस्प व भ्रामक भी है। काग्रेस समाजवादी पार्टी के घटक तत्वो की प्रकृति का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि पार्टी के सगठक तत्व आरम्भ मे भिन्न-भिन्न राजनीतिक अवधारणाओ से जुड़े हुए तो थे ही बाद मे भी यह स्थिति बनी रही और इन विभिन्न तत्वो ने सदैव इस बात को ध्यान मे रखा कि उनकी मौलिक राजनीतिक अवधारणा न केवल अप्रभावित रहे, बल्कि पार्टी की छत्रछाया मे ही

फूले-फूले । प्रमुख रुप से जिन राजनीतिक विचारधाराओ को पार्टी मे प्रतिनिधित्व प्राप्त था उसमे मार्क्सवादी और समाजवादी विचारधारा (कम गम्भीर और अधिक आकर्षक), फेबियन विचारधारा और उदारवादी समाजवादी विचारधारा । इन तीनो विचारधाराओ के लोग अपनी आस्था के प्रति सजग रहे व इस चेष्टा मे रहे कि पार्टी के माध्यम से क्रमश उनकी अपनी विचारधारा का प्रचार व प्रसार हो जिसके कारण इन सगठक तत्वो के मध्य गंभीर राजनीतिक मतभेद हमेशा ही बना रहा । एम0 एन0 राय को यह आशका थी कि चूँकि यह पार्टी अपने उद्देश्यो के प्रति स्पष्ट नही है । अत यह बुर्जुआ-संसदवाद व सुधारवादी प्रवृत्तियो मे आत्मसात हो सकती है । उनकी राय यह भी थी कि ऐसे सुधारवादी दलो के विघटन के बिना शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण नही हो सकता । अपने इन उद्देश्यो को प्रमुखता प्रदान करते हुए उन्होने अपने अनुयायियो को यह हिदायत दी थी कि वे पार्टी मे सम्मिलित तो हो लेकिन इससे अपने को आबद्ध न करे । इसे आगे बढाने के साधन के रुप मे प्रयुक्त करे । अर्थात राय व उनके अनुयायी पार्टी के माध्यम से अपनी राजनीतिक विचारधारा का प्रचार चाहते थे। राय ने मीनू मसानी व विक्रमदास आदि नेताओ को हमेशा सन्देह की दृष्टि से देखा और कमला देवी तथा मेहर अली को प्रगतिशील माना ताकि पार्टी के नेताओ मे अन्तर्विरोध बना रहे । जैसे ही राय को यह लगने लगा कि उनके उद्देश्यो की पूर्ति मे पार्टी बाधाएँ डाल रही है, उन्होने उसे तोड़ने की हर सभव चेष्टा की । कम्युनिस्ट विचारधारा से जुडे लोगो या कम्युनिस्टो को यद्यपि पार्टी मे प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन मसानी व विक्रमदास आदि उदारवादियो ने उन्हे सदैव सन्देह की दृष्टि से देखा तथा वे हमेशा इस प्रयत्न मे रहे कि कम्युनिस्टो को पार्टी मे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त न हो । आलोचना के बावजूद जब मसानी अपने उद्देश्य मे सफल नही हुए तो उन्होने सन् 1939 मे पार्टी को ही छोड दिया । उनके साथ ही अशोक मेहता, डा0 लोहिया, अच्युत पटवर्धन आदि नेताओ ने भी पार्टी की कार्यकारिणी से सबध-विच्छेद कर लिया । लेकिन इससे पहले कम्युनिस्टो के विषय मे कुछ अपमानजनक निर्णय पार्टी द्वारा लिए जा चुके थे । जैसे- सन् 1937 मे पार्टी ने यह निर्णय लिया कि अब कम्युनिस्टो को पार्टी मे प्रवेश नही मिलेगा, लेकिन जो पहले से पार्टी के सदस्य हैं, वे बने रह सकते है । काग्रेस समाजवादी पार्टी की इस नीति से कम्युनिस्टो का असन्तुष्ट होना स्वाभाविक था जिसका परिणाम यह हुआ कि मई 1940 के आते-आते उन्होने भी पार्टी छोड़ने के विषय मे गभीर रुप से सोचना आरम्भ कर दिया । जवाहरलाल नेहरु व सुभाष चन्द्र बोस को

पार्टी अपनी नीतियो से ओत-प्रोत मानती थी और उसकी गतिविधियो मे इन दोनो की महत्वपूर्ण भूमिकाएँ भी थी, लेकिन औपचारिक रुप से इनमे से किसी ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण नही की। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान पार्टी के विभिन्न घटको मे इतने गम्भीर मतभेद हो गये थे कि अब आगे एक साथ बने रहना उनके लिए असम्भव हो गया। पर्दे के पीछे कार्य करने वाले नेताओ (नेहरु और बोस) के अन्तर्विरोध भी इस बात पर स्पष्ट हो गये कि विश्वयुद्ध मे भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए। इसलिए आदि से अन्त तक काग्रेस समाजवादी पार्टी के सघटक तत्वो मे राजनीतिक मतभेद व गतिरोध बने रहे, जिसके कारण पार्टी का विघटन, अन्तत एक स्वाभाविक अनिवार्यता बन गया और उसका विघटन भी हो गया।

जय प्रकाश नारायण व आचार्य नरेन्द्र देव मार्क्सवादी चिन्तन से प्रभावित थे। जय प्रकाश नारायण ने तो अपनी पुस्तक "समाजवाद ही क्यो"[8] समाजवादी नीतियो का भरपूर गुणगान किया है।

जय प्रकाश नारायण ने हमेशा यह स्वीकार किया कि उन्हे मार्क्सवादी चिन्तन से आबद्ध करने मे एम0 एन0 राय का ही प्रमुख योगदान था। यह एक वास्तविकता है कि राय ने मार्क्सवाद को अपनी स्वतन्त्र दृष्टि से देखा और उसे अपने राजनीतिक हितो के लिए सुविधाजनक रुप मे अपनाया। अन्त मे वे एक काग्रेसी के रुप मे काल-कलवित हुए।

अत इन नेताओ की राजनीतिक समझदारियो के अध्ययन से इस बात का ज्ञान हो जाता है कि काग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के दौरान इन लोगो मे परस्पर राजनीतिक मतभेद थे। इन मतभेदो का प्रभाव पार्टी पर पडा जिसके फलस्वरुप पार्टी न तो किसी

---

8 - सन् 1936 मे सामाजवाद ही क्यो ?' का गुणगान करने वाले जय प्रकाश नारायण इस शताब्दी के पाचवे दशक मे गाँधीवाद से इतना प्रभावित हुए कि गाँधीवाद ही उन्हे सभी सामाजिक-आर्थिक समस्याओ के समाधान मे राम वाण औषधि के रुप मे दिखाई पड़ने लगा।इतना ही नही सन् 1954 मे सक्रिय राजनीति से सन्यास लेने की घोषणा करके वह विनोबा भावे के भूदान महायज्ञ से सम्बद्ध हो गये ताकि भारतीय दरिद्र नारायण की समस्या का समाधान हो सके। भूदान महायज्ञ की विफलता ने उन्हे पुन राजनीति मे सक्रिय किया और सन् 1974-75 के दौरान उनके नेतृत्व मे सम्पूर्ण क्रान्ति का आह्वान हुआ जो सन् 1977 मे जनता पार्टी के गठन मे परिणत हुआ और जो विलोम राजनीतिक विचारधाराओ का गठबन्धन होने के कारण पाँच वर्ष की अवधि भी सत्ताधारी दल के रुप मे पूरा न कर सका। जनता पार्टी के विघटन व श्रीमती इन्दिरा गाँधी के सत्ता मे पुनरागमन से जय प्रकाश नारायण का राजनीतिक भ्रम टूटना ही था, जो मृत्यु के समय स्वय भी देख सके।इसका अर्थ यह है कि जय प्रकाश नारायण की राजनीतिक विचारधारा प्रतिबद्धता और अनन्यता का जो अभाव दिखाई देता है, उसका प्रभाव काग्रेस समाजवादी पार्टी के नीति निर्धारण पर पड़ना स्वाभाविक ही था। मीनू मसानी ने सन् 1939 मे काग्रेस समाजवादी पार्टी से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया व सन् 1959 मे स्वतन्त्र पार्टी की स्थापना मे सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। स्वतन्त्र पार्टी घोर प्रतिक्रियावादी व प्रारम्भिक पूँजीवादी मूल्यो की समर्थक भी, इसमे सदेह नही।समाजवादी से पूँजीवादी विचारधारा के अपनाने वाले नेता की राजनीतिक मन. स्थिति को सहज आका जा सकता है।अशोक मेहता ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से सन् 1962 मे सम्बन्ध विच्छेद किया तथा काग्रेस के सदस्य बन गये। वे श्रीमती गाँधी की सरकार मे सन्1966 मे योजना मत्री के पद पर आसीन हुए। इसी तरह डा0 लोहिया को 1955 मे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया और अन्तत उन्होने सयुक्त समाजवादी दल की स्थापना की जिसका राजनीतिक परिणाम सर्व विदित है।

राजनीतिक विचारधारा से पूर्ण रुप से सम्बद्ध हो पायी और न ही वह ऐसे कार्यक्रम तय कर पायी जिनके माध्यम से उसके उद्देश्यो की पूर्ति हो पाती जिनका उल्लेख पार्टी ने सर्वप्रथम किया था। इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे-

1- ब्रिटिश साम्रज्य से भारत को सम्पूर्ण आजादी मिले।

2- भारतीयो को अपने भविष्य के लिए स्वतन्त्रता पूर्वक सविधान बनानें का अधिकार प्राप्त हो।

3- स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत मे समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हो ताकि भारतीय समाज से शोषण की वीभत्स सस्था का उन्मूलन हो सके।

4- निजी सम्पत्ति का उन्मूलन हो ताकि समाज के दो वर्गों मे व्याप्त खाई को पाटा जा सके।"इस उद्देश्य का समर्थन नेहरु ने सन् 1936 मे लखनऊ काग्रेस की अध्यक्षता करते हुए किया, जिसमे उन्होने घोषणा की कि भारतीय समस्याओ का समाधान समाजवादी रास्ते से ही हो सकता है जिसके लिए भारत की सामाजिक तथा राजनीतिक सरचना मे क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है, जैसे निजी समपत्ति की सस्था की समाप्ति (सीमित रुप मे) तथा वर्तमान लाभ कमाने की व्यवस्था के स्थान पर सहकारिता के सिद्धात की स्थापना आदि"।[9]

5- काग्रेस समाजवादी दल की सदस्यता के लिए काग्रेस पार्टी की सदस्यता का होना अनिवार्य है। इस उद्देश्य मे हालाकि बाद मे सशोधन हुआ जिसके फलस्वरुप अन्य दलो के सदस्यो को भी इस पार्टी की सदस्यता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ।

6- स्थापना के प्रारम्भिक काल मे पार्टी के दो मोटे उद्देश्य थे, जो अत तक बने रहे। पहली,काग्रेस के वरिष्ठ नेताओ को यह बतलाना कि राष्ट्रीय आन्दोलन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि इसमे भाग लेने वाले मजदूरो और किसानो की सहभागिता को अधिक विस्तृत किया जाये। दूसरा, भारतीय जन-साधारण मे इस बात का प्रचार करना कि उनकी वास्तविक समस्याओ के समाधान का प्रश्न उस राजनीतिक सघर्ष के साथ जुडा हुआ है जो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लडा जा रहा है। अत उन्हे इस सघर्ष मे सक्रिय भाग लेना चाहिए।

काग्रेस समाजवादी पार्टी के इन उद्देश्यो का अध्ययन यदि ध्यान पूर्वक किया जाय तो

---

[9] - जे0 पी0 हेथ्काक्स कम्युनिज्म एण्ड नेशनेलिज्म ...

ज्ञात होता है कि इसका वास्तविक लक्ष्य काग्रेस को मजबूत करना तो था ही, भारतीय जन साधारण पर काग्रेसी नेतृत्व की निरन्तरता को बनाये रखना भी था। कांग्रेस दक्षिण पन्थियो के नेतृत्व मे थी। यदि जन साधारण उसके नेतृत्व को स्वीकार करता जो कभी भी उसकी समस्याओ का समाधान करने का पक्षधर नही था। जिसका प्रमाण इतिहास मे भरा पडा है। गॉधी का भी तो यही उद्देश्य था।

अन्तर्विरोधी नीतियो के कारण पार्टी की सफलता निश्चय ही सन्देहास्पद थी। गॉधी तथा उसके अनुयायियो ने पार्टी की हर उस नीति और कार्यक्रम का विरोध किया जो समाजवादी के पक्ष मे था।[10] उदाहरण के लिए काग्रेस समाजवादी पार्टी जहॉ जमीदारी [illegible] सम्पत्ति की सस्था के उन्मूलन का आह्वान कर रही थी, एव इसकी पूर्ति के लिए कार्य क्रम बनाने मे मशगूल थी, वहॉ गॉधी ने इसका खुलकर विरोध किया। इसी तरह जब समाजवादियो ने काग्रेस महासमिति के गठन के बारे मे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की चुनाव-प्रक्रिया की वकालत की तथा सदस्यो की सख्या मे वृद्धि की माग की तब गॉधी ने मनोनयन तथा सदस्य सख्या घटाने पर जोर दिया।[11] उन्होने इस बात का विरोध करते हुए काग्रेस समिति से अपील की कि बैठको मे सूत काटने को काग्रेस की सदस्यता प्राप्ति के लिए आवश्यक बना दि जाये तथा काग्रेस की बैठको मे भाग लेने वाले सदस्यो की सख्या छ हजार से एक हजार कर दी जाये।[12] आखिर गॉधी का यह विचार किस बात का द्योतक कहा जा सकता है ? उत्तर साफ है कि वह काग्रेस सगठनो मे समाजवादियो के बढते प्रभाव से क्षुब्ध थे तथा उन्हे येन-केन प्रकारेण प्रभावहीन बनाना चाहते थे। इन प्रस्तावो के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए काग्रेस समाजवादी पार्टी ने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमे यह स्पष्ट कहा गया कि इन प्रस्तावो का एक मात्र उद्देश्य काग्रेस मे समाजवादियो के बढते हुए प्रभाव को कम करना है।[13]

बम्बई महाधिवेशन मे काग्रेस समाजवादी पार्टी की आधार शिला रखी गयी और पार्टी के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यो की घोषणा हुई। इन उद्देश्यो की पूर्ति हेतु कुछ सगठनात्मक तथा

---

10 - सत्य, एम0 राय (स0),"भारत मे राष्ट्रवाद" पृष्ठ 269

11 - सन् 1934 मे ही उ0 प्र0 के जमीदारो को गॉंधी ने यह कहकर आश्वासन दिया,' मै सम्पत्तिवान वर्ग को सम्पत्तिहीन करने के पक्ष मे नही हूँ। मेरा उद्देश्य तो उनका हृदय परिवर्तन करना है ताकि वे सम्पत्ति को धरोहर न समझकर उसका प्रयोग सम्पत्ति विहिनो के कल्याणार्थ करे। मेरा अन्तिम उद्देश्य पूँजी और श्रम तथा मालिक और किरायेदारो के मध्य सामजस्य तथा सहयोग की स्थापना करना है। काग्रेस की कोई ऐसी नीति नही है जिससे जमीदारो को डरने की जरुरत हो।

12 - 1934 मे काग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक (वर्धा) मे डा0 राजेन्द्र प्रसाद के अध्यक्षीय भाषण से उद्धत, पृष्ठ 15

13 - जे0 एस0 शर्मा-' भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस" पृष्ठ 565

राजनीतिक निर्णय भी लिये गये । सम्पूर्ण स्वतत्रता प्राप्ति तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत मे समाजवादी समाज की स्थापना का जो निर्णय हुआ, उसमे कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक आकाक्षाएँ भी अन्तर्निहित थी । सम्पूर्ण स्वतन्त्रता का तात्पर्य यह बतलाया गया कि पूर्ण स्वतन्त्र भारत की स्थापना होगी और किसी भी स्तर पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद से समझौता नही किया जायेगा ।[14] ब्रिटिश साम्रज्यवाद से किसी भी स्तर पर समझौता न करने के आह्वान मे यह विश्वास अन्तर्निहित था कि तालमेल और समझौते के आधार पर स्वतन्त्रता की प्राप्ति नही हो सकती । तालमेल और समझौते के आधार पर प्राप्त की गयी स्वतन्त्रता वास्तविक स्वतन्त्रता नही हो सकती । काग्रेस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व का हमेशा यह विश्वास बना रहा और उसके इस विश्वास को भी साम्यवादियो तथा अन्य वामपथी घटको का समर्थन भी प्राप्त था ।[15] सगठनात्मक पक्ष के विषय मे जो निर्णय लिये गये वे लोकतान्त्रिक पद्धति से ओत-प्रोत थे । महाधिवेशन मे यह पारित हुआ कि-

1- सर्वोच्च नीति-निर्धारण शक्ति वार्षिक महाधिवेशन मे सन्निहित होगी, जिसमे प्रान्तीय इकाईयो के सदस्य प्रतिनिधि के रुप मे सम्मिलित होगे

2- वार्षिक महाधिवेशन मे एक कार्यकारिणी समिति निर्वाचित की जायगी, जिसमे एक महामत्री चार सयुक्त मन्त्री और ग्यारह साधारण सदस्य होगे ।

3- पार्टी की सदस्यता केवल उन्ही लोगो को प्रदान की जायेगी जो काग्रेस पार्टी से सम्बद्ध तथा प्रान्तीय काग्रेस समाजवादी पार्टी के सदस्य होगे ।

4- साम्प्रदायिक सगठन से सम्बद्ध लोग सदस्य के रुप मे अग्राह्य होगे।

5- किसी अन्य ऐसे राजनीतिक सगठन से सम्बन्धित लोगो को सदस्यता प्रदान नही की जायेगी, जिसकी नीतियॉ, पार्टी की दृष्टि मे, पार्टी से मेल नही खाती अथवा उसकी अपनी नीतियो के विरुद्ध हो ।[16]

सगठन सबधी इन निर्णयो को देखने से यह ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय भारतीय काग्रेस से येन-केन प्रकारेण सम्बद्ध लोगो को ही काग्रेस समाजवादी पार्टी मे प्रवेश का अधिकार प्राप्त

---

14 - काग्रेस समाजवादी पार्टी के पहले सम्मेलन की रिपोर्ट

15 - एल0 पी0 सिन्हा-"लेफ्ट विंग इन इण्डिया" पृष्ठ 325

16 - काग्रेस समाजवादी पार्टी के पहले सम्मेलन की रिपोर्ट

था । जिसकी महत्वूपर्ण कीमत बाद मे पार्टी को चुकानी पडी और अन्तत यह कांग्रेस की पिछलग्गू ही बनी रही ।

(II) **कांग्रेस समाजवादी दल के कार्यक्रम तथा उपलब्धियॉ**

काग्रेस समाजवादी पार्टी का अस्तित्व सन् 1934 से 1947 तक रहा इस अवधि मे जन साधारण की समस्याओ के समाधान, समाजवादी समाज की स्थापना, सम्पूर्ण स्वतन्त्रता के सिद्धात, मार्क्सवादी विचारधारा के विकास तथा सविधान सभा के सगठन आदि से सम्बद्ध राष्ट्रीय समस्याओ के (सदर्भ मे उसकी भूमिका निर्णायक नही रही तथापि) उसकी कुछ सकारात्मक भूमिकाए अवश्य रही । यह स्प्ष्ट है कि काग्रेस समाजवादी दल ने कभी भी समाजवाद के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास नही किया, वह भी व्यवहारिक रुप मे तो बिल्कुल ही नही । सम्भवत इसका प्रमुख कारण इसके प्रवर्तको के अलग-अलग राजनीतिक विचार थे । जिसका प्रतिनिधित्व हमेशा ही होता रहा । काग्रेस समाजवादी पार्टी विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओ से सम्बद्ध राजनीतिज्ञो की जमात ही बनी रही और उसके पृथक-पृथक विचारो की अभिव्यक्ति का एक राजनीतिक रगमच अथवा साधन । मार्क्सवाद, उदारवादी समाजवादी व गॉधीवादी के परस्पर विरोधी आदर्शो से सम्बद्ध इस पार्टी से किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रचार एव प्रसार की आशा न तो न्याय सगत थी और न व्यवहारिक ही थी । काग्रेस समाजवादी पार्टी की सरचना समिति की प्रकृति के आधार पर न तो किसी हो राजनीतिक उद्देश्य की स्थापना ही संभव थी और न एक स्वतत्र राजनीतिक दल के रुप मे कार्य करने की आशा ही थी । ठोस राजनीतिक कार्यक्रम के अभाव मे, काग्रेस से बधे रहना इसके लिए स्वाभाविक था जिसे वह कभी भी नजर अदाज नही कर सकी ।इसका एक मात्र उद्देश्य, काग्रेस को उन सभी लोकप्रिय राजनीतिक सिद्धातो से सम्बद्ध करना था ताकि जन आन्दोलनो और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता सग्राम का नेतृत्व उसके हाथ मे बना रहे, तथा अन्य कोई राजनीतिक दल उस पर अधिकार न जमा ले । जब कभी इस दिशा मे दूसरे राजनीतिक दलो ने प्रयास किया तब काग्रेस समाजवादी पार्टी ने केवल उनका साथ ही नही दिया बल्कि भरसक उनका विरोध भी किया । रायवादियो तथा कम्युनिस्टो के प्रति इस दल के रवैये से यह बात प्रमाणित हो जाती है कि बड़े पैमाने पर इस दल से रायवादियो और कम्युनिस्टो का निष्कासन इसी बात का परिचायक है ।

उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस पार्टी ने जिस भूमिका का निर्वाह किया, उसे नि सन्देह इसकी सफलताओ और उपल्बिधयो का प्रतीक कहा जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस पार्टी के द्वारा समय-समय पर जो कदम उठाये गये। उसका सक्षिप्त विवरण आवश्यक एव प्रासगिक भी है।

काग्रेस के दक्षिणपथी नेताओ एव गॉधी के हठधर्मिता के फलस्वरुप जन-आन्दोलन, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता सघर्ष, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग तथा प्रमुख सस्थाओ पर से काग्रेस का नेतृत्व कम होता जा रहा था जिसकी पुन प्राप्ति के लिए काग्रेस समाजवादी पार्टी द्वारा उठाये गये कदम नि सन्देह काग्रेस पार्टी की दृष्टि से उपलब्धि की श्रेणी मे आते है। यह अलग बात है कि इस पार्टी के सिद्धांत और व्यवहार मे पर्याप्त अन्तर था। इस पार्टी ने लोकप्रिय समाजवादी नारो की इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भरपूर प्रयोग किया। इसने यह प्रचार किया कि स्वतन्त्रता सग्राम मे जनसाधारण को अधिकाधिक मात्रा मे भाग लेना चाहिए तभी उसकी वास्तविक समस्याओ का समाधान हो सकेगा। काग्रेस आधिकारिक नेतृत्व को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने इसका भरपूर लाभ उठाया। गॉधी की 'दरिद्र नारायण' की पूजा को वैज्ञानिक जामा पहनाया गया। 'किसान सभा' मे इस बात का प्रचार किया गया कि उसे काग्रेस के नेतृत्व मे स्वतन्त्रता सग्राम मे हिस्सा लेना चाहिए। इसमे इस दल को सफलता भी प्राप्त हुई जिसके फलस्वरुप काग्रेस के परम्मपरावादी व दक्षिणपथी नेतृत्व ने फैजपुर-कृषि कार्यक्रम को सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। समाजवादियो की इस नीति से किसान वर्ग पर काग्रेस नेतृत्व की आशिक स्थापना हुई, मजदूर वर्ग पर यद्यपि अत्यधिक प्रभाव न पडा क्योकि उस पर कम्युनिस्टो क व्यपाक प्रभाव बना रहा। परन्तु यह वर्ग समाजवादियो की इस नीति से बिल्कुल अप्रभावित भी न रहा। अत यह कहा जा सकता है कि जन साधारण मे कांग्रेस के गिरते प्रभाव को पुन· स्थापित करने मे काग्रेस समाजवादी दल सफल रहा।[17]

युवा आन्दोलन के नेतृत्व पर भी काग्रेस समाजवादी पार्टी ने सकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया। तत्कालिक राजनीतिक वातावरण मे युवा वर्ग पर समाजवाद के सिद्धान्तो का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था, जिसे लेकर काग्रेस बडी चिन्तित थी। युवा वर्ग का नेतृत्व उनके हाथो से निकलता जा रहा था। युवा समाज से सम्बद्ध लोग रायवादियो से प्रभावित हो रहे थे अथवा

---

17 - सत्या एम0 राय (स0) 'भारत मे राष्ट्रवाद'', पृष्ठ 271-272

कम्युनिस्टो का प्रभाव उन पर बढ रहा था । और अधिकाश युवा वर्ग गॉधी तथा काग्रेस की प्रतिक्रियावादी नीतियो से निराश होता जा रहा था । ऐसे समय मे, काग्रेस समाजवादी दल ने उस पर प्रभाव जमाने का प्रयास किया तथा उसके द्वारा दिये जाने वाले अति उत्साही नारे प्रभाव जमाने मे काफी कामयाब रहे । युवा जगत को काग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रगतिशील नारे आकर्षित करने लगे जिसके फलस्वरुप उसके नेतृत्व पर इस दल का प्रभाव पडा जो अन्तत स्वय काग्रेस पार्टी के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हुआ । यदि काग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना न होती और काग्रेसी मच से प्रगतिशील नारे न दिये जाते तो यह लगभग तय था कि काग्रेस एक मात्र ऐसा राजनीतिक दल न बन पाती जिसे चहुमुखी समर्थन प्राप्त हो सके । इसका अर्थ यह है कि काग्रेस की नीतियो से तत्कालीन युवा वर्ग को सम्बद्ध करने का श्रेय समाजवादी दल को ही दिया जा सकता है जिसने काग्रेस की डूबती नैय्या को सुदृढ पतवार प्रदान की ।

अपने उपर्युक्त दो महत्वपूर्ण उद्देश्यो की पूर्ति के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम निर्धारित किया जिसे अत्यन्त महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कहा जा सकता है । इन कार्यक्रमो की घोषणा पार्टी प्लेटफार्म से की गयी तथा इसके विषय मे लिया गया निर्णय लगभग सर्वसम्मत था ।यहा यह भी उल्लेखनीय है कि 15- सूत्रीय कार्यक्रम मे सन्निहित नीतियॉं भारत मे समाजवादी समाज की स्थापना व उद्देश्य से अधिक ओत-प्रोत तथा आकर्षक थी । 15 सूत्रीय कार्यक्रम मे निम्नलिखित बाते सन्निहित थी-

1- उत्पादक जन साधारण मे सभी शक्तियो का हस्तान्तरण हो ।

2- देश की आर्थिक विकास प्रक्रिया राज्य द्वारा नियोजित तथा नियन्त्रित हो ।

3- प्रमुख उद्योगो का सामाजीकरण (जैसे-इस्पात,सूत,जूट,रेल, जहाजरानी, तथा खान आदि उद्योग) तथा उत्पादन के साधनो के वितरण तथा विनिमय का सामाजीकरण ।

4- विदेश व्यापार पर राज्य का एकाधिकार ।

5- उत्पादन,वितरण और सार्वजनिकरण के दोनो क्षेत्रो मे सहकारी सस्थाओ का सयोजन ।

6- राजाओ तथा जमीदार वर्ग तथा अन्य शोषक वर्गो का बिना किसी क्षतिपूर्ति के उन्मूलन ।

7- किसानो मे भूमि का पुनर्वितरण ।

8- सहकारिता तथा सामूहिक खेती को राज्य द्वारा प्रोत्साहन तथा नियन्त्रण

9- किसानो और श्रमिको पर ऋणो की समाप्ति ।

10- काम पाने के अधिकार को मान्यता ।

11- आर्थिक वस्तुओ का प्रत्येक को उसकी आवश्यकतानुसार अतत वितरण ।

12- वयस्क मताधिकार के सिद्धात की स्थापना ।

13- किसी भी धर्म के विषय मे राज्य द्वारा भेदभाव किये जाने की मनाही तथा जाति और साम्प्रदायिक आधारो पर मान्यता प्रदान करने का निषेध ।

14- लिग के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव करने की मनाही ।

15- तथा कथित सार्वजनिक ऋण की समाप्ति ।

काग्रेस समाजवादी दल द्वारा घोषित उपर्युक्त 15-सूत्रीय कार्यक्रम [illegible] का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुँचते [illegible] शासन के दौरान प्रगतिशील व वामपक्षीय सिद्धान्तो को इसमे पर्याप्त मा[illegible] को [illegible] । कार्यक्रम अत्यन्त आकर्षक एव प्रगतिशील थे जिनके प्रति जनसाधारण मे [illegible] का भाव जागृत होना स्वाभाविक था । काग्रेस के इस वामपथी घटक को पर्याप्त जन समर्थ[illegible] इस घटक के शीर्षस्थ नेताओ को व्यापक जन समर्थन मिलने के बावजूद [illegible] और न ही भारतीय सविधान के निर्माण पर इसका कोई मौलिक प्रभाव ही पडा । यदि काग्रेस समाजवादी पार्टी इस कार्यक्रम को हृदय से लागू करने का प्रयास करती तो भारत का जो आज रुप है वह उससे काफी सीमा तक भिन्न होता तथा भारत मे समाजवादी समाज की स्थापना सभव हो सकती थी ।लेकिन स्वय पार्टी मे व्याप्त पर्याप्त अन्तर्विरोधो के कारण इस क्रान्तिकारी कार्यक्रम का लागू होना न तो सभव था और न यह तत्कालीन नेतृत्व को स्व कार्य ही था । इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन मे काग्रेस समाजवादी पार्टी के नेताओ को नतत् उदासीनता, प्रतिक्रियावादी तत्वो से गठजोड बनाये रखने की [illegible] इच्छा तथा आ[illegible] अन्तर्निहित थे, जिससे नेतृत्व उबर न सका और पार्टी अन्तत पतन की ओ[illegible] हुई ।

(III) **कांग्रेस समाजवादी पार्टी की असफलता तथा समीक्षा**

काग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जिस राजनीतिक वातावरण [illegible] पहले दिया गया है । प्रगतिशील, दक्षिणपथी तथा जनसाधारण की समस्याओ के प्रति इमानदारी

बरतने की नीतियो से बराबर प्रतिबद्ध काग्रेस समाजवादी पार्टी को जहॉ काग्रेस पर छा जाना चाहिए था, वहॉ वह असफल हुई और अन्तत पतन की ओर अग्रसर हुई । इ के कारणो की तह मे जाने पर ही सही स्थिति का स्पष्टीकरण हो सकता है ।मोटे तौर पर इन कारणो को तीन भागो मे बॉटा जा सकता है । **पहला** वैचारिक तथा सैद्धान्तिक, **दूसरा** काग्रे र्टी से अन्यतम सम्बन्ध तथा **तीसरा** काग्रेस समाजवादी दल व अन्य वामपथी विचारधार ा वाले राजनीतिक सगठनो की इसके प्रति सदेहास्पद धारणाऍ । इन कारणो की सक्षिप्त व्या इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अन्तत कागेस समाजवादी दल का काल के गर्त मे जाना थवा समाप्त होना स्वाभाविक ही था ।

काग्रेस समावादी पार्टी की स्थापना निश्चय ही वामपथी विचारधार प्रभावित होने के कारण हुई । इसके साथ ही पार्टी ने सदैव ही इस बात को ध्यान मे रखा कि काग्रेस के बाहर उसका कोई अस्तित्व न तो है और न ही इस बात की वह चेष्टा ही कर । दल के शीर्षस्थ नेताओ की उद्घोषणाओ से इस तथ्य की पुष्टि स्वत ही होती है ।काग्रेस ाजवादी पार्टी की सैद्धान्तिक एव वैचारिक अवधारणओ का उल्लेख प्रो0 एल0 पी0 सिन्हा ने ब ी सुन्दर शब्दो मे व्यक्त किया है जो काफी सीमा तक आधिकारिक माना जा सकता है । नुसार "काग्रेस समाजवादी ऐसी मन स्थिति के शिकार थे, जहॉ वे हृदय से गां थे लकिन सिर मार्क्स से प्रभावित था । हालाकि गॉधीवाद का प्रभाव अधिक था [illegible] से वे मुक्त न हो सके ।[18] यह ठीक है कि काग्रेस समाजवादी पार्टी का [illegible] पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्ति तथा समाजवादी समाज की स्थापना था, लेकिन इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिन सिद्धात और वैचारिक मान्यताओ को उन्होने स्वीकार किया, उसमे [illegible] अन्तर्विरोध मौजूद थे, जिसके कारण उद्देश्य प्राप्ति का मामला हमेशा सदिग्ध ही वना र काग्रेस पार्टी के प्रति लगातार उनके पूर्वाग्रहो के बने रहने से इस धारणा को ठोस आधार ि ता है, इसमे कोई सन्देह नही । काग्रेस पार्टी का तत्कालीन नेतृत्व तथा गॉधी ने केवल समाजवादी मूल्यो से सहमत नही थे अपितु उनके घोर आलोचक एव विरोधी भी थे । और गॉधी की यह रणा निरन्तर बनी रही । काग्रेस समाजवादी पार्टी का नेतृत्व इस वस्तुस्थिति से अनभिज्ञ नही ा तथापि वह इस आशावाद से हमेशा ग्रस्त रहा कि वह काग्रेस के दक्षिणपथी नेतृत्व को [illegible] तने

18 - एल0 पी0 सिन्हा-' लेफ्ट विंग इन इण्डिया'', पृष्ठ 507

मे सफल हो जायेगा कि पूर्ण स्वतन्त्रता और समाजवाद के द्वारा ही भारतीय समस्याओ का मौलिक समाधान हो सकेगा। दक्षिणपथी नेतृत्व अनजाने मे समाजवाद का घोर विरोधी होता तो यह सभव हो पाता। लेकिन वस्तुस्थिति इसके विपरीत थी, क्योकि वह बहुत सुनियोजित ढग से समाजवादी मूल्यों एव अवधारणओ के विरुद्ध था, जिसका प्रमाण काग्रेस महासमिति द्वारा पारित उस प्रस्ताव से मिलता है जो काग्रेस समाजवादी दल के गठन के साल मे ही लाया गया, इस प्रस्ताव के द्वारा समाजवादी मूल्यो को स्पष्ट नकारा गया।

जून 1934 मे पारित उस प्रस्ताव मे स्पष्ट किया गया कि निजी सम्पत्ति का उन्मूलन तथा वर्ग सघर्ष का सिद्धात काग्रेस पार्टी की अहिंसात्मक सस्कृति के ठीक विपरीत है[19] इस प्रस्ताव के दौरान दक्षिणपथी नेतृत्व ने यह विचार व्यक्त किया कि काग्रेस समाजवादी दल पहले अन्तर्राष्ट्रीयतावादी है, इसलिए राष्ट्रीय मुक्ति कें सघर्ष मे उनपर पूर्णरुपेण निर्भर नही किया जा सकता।[20] गॉधी तथा दक्षिणपथी नेतृत्व के इस रवैये के विपरीत काग्रेस समाजवादी पार्टी की उक्ति थी कि काग्रेस नेतृत्व द्वारा ही स्वतन्त्रता सग्राम का सफल नेतृत्व सभव है, तथा काग्रेस के बिना इस सघर्ष मे विजय प्राप्त करना असम्भव है। जे0 पी0 के शब्दो मे "काग्रेस समाजवादी दल का गठन काग्रेस पार्टी के समानान्तर तथा उसके विरुद्ध नही हुआ बल्कि इसलिए हुआ कि काग्रेस मे रहते हुए उसे मजबूत किया जाये और उसकी नीतियो मे परिवर्तन एव सशोधन किया जाए।[21] काग्रेस की शक्ति एवं महत्ता का गुणगान करते हुए जे0 पी0 ने लिखा कि "काग्रेस ही केवल ऐसा संगठन है जिसके नेतृत्व मे राष्ट्रीय सघर्ष सभव है, तथा राष्ट्रीय एकता को बनाये रखा जा सकता है। काग्रेस साम्राज्यवाद विरोधी युद्ध का सर्वशक्तिशाली मोर्चा है, और साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष यदि आरम्भ होता है तो वह काग्रेस के तिरगे झण्डे के नेतृत्व मे ही होगा। किसान सभा, मजदूर सगठन तथा छात्रसघ इस सघर्ष के आरम्भ मे निर्णायक भूमिका का निर्वाह नही कर सकते तथा काग्रेस ही इस सघर्ष की निर्विवाद शक्ति है।[22] काग्रेस पार्टी की भूमिका राष्ट्रीय संघर्ष मे अद्वितीय है जिसे मानते हुए जय प्रकाश नारायण ने भावात्मक घोषणा की "काग्रेस ही देश का एक मात्र विस्तार है। याद रखना चाहिए कि काग्रेस का तात्पर्य पूरे से है भाग से नही।

---

19 - "इण्डियन एनुअल रजिस्टर "(कलकत्ता), भाग-1, पृष्ठ 300

20 - आचार्य नरेन्द्र देव- सोशलिज्म एण्ड दि नेशनल रिवोल्यूशन" पृष्ठ 66

21 - वही, पृष्ठ 137

22 - नरेन्द्र देव-' सोशलिज्म एण्ड दि नेशनल रिवोल्यूशन", पृष्ठ 139

पूरे शरीर से कटा हुआ कोई हिस्सा न तो शक्तिशाली होता है और [illegible] अतत यह मृत्यु को प्राप्त होता है ।[23]

उपर्युक्त ब्यौरे से स्पष्ट होता है कि भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का नेतृत्व दक्षिणपथी गुट मे सन्निहित था जिसका सैद्धान्तिक तथा वैचारिक विरोध दल के कार्यकर्ता [illegible] जिसकी परिणति काग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना मे हुई । यह ठीक है कि दल अति प्रगतिशील नीतियो को पार्टी के कार्यक्रम मे स्थान दिया, लेकिन दक्षिणपथी नेतृत्व की उदासीनता तथा इन प्रगतिशील कार्यक्रमो की उपेक्षा व खुलकर विरोध के कारण, ये कार्यक्रम काग्रेस पार्टी को ग्राह्य न हो सके । काग्रेस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की इस सतत् हठधर्मी कि काग्रेस को प्रगतिशील बनाया जा सकता है, पार्टी को असफलता की ओर अग्रसर होने के लिए बाध्य कर दिया । वस्तुस्थिति यह थी कि काग्रेस नेतृत्व इन प्रगतिशील सिद्धान्तो और कार्यक्रमो को मानने के लिए कदापि भी तत्पर नही था, और काग्रेस समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर काग्रस से सम्बन्ध-विच्छेद को तैयार नही थी, भले ही उसे अपनी इन प्रगतिशील नीतियो के कार्यान्वयन मे बेमेल समझौता करने के लिए बाध्य होना पड़ा । परिणाम स्वाभाविक [illegible] काग्रेस का नेतृत्व दक्षिणपथी हाथो मे बराबर रहा और काग्रेस समाजवादी [illegible] अंतत परिवर्तन और सशोधन काग्रेस की नीतियो [illegible] फलस्वरुप पार्टी के कार्यकर्ताओ मे निराशा की भावना उत्पन्न हुई । जिन्होंने दक्षिणपथी नेतृत्व को स्वीकार किया वे काग्रेस मे बने रहे । जिसने उसका विरोध किया वे पार्टी से निकाल दिये गये, और जो ढुलमुल रहे वे या तो पार्टी को छोड गये अथवा चुप बैठने को बाध्य हुए । दक्षिण पथी नेतृत्व ने काग्रेस समाजवादी पार्टी को तब तक सहन किया जब तक उसके लिए आवश्यक था । अत काग्रेस पार्टी व काग्रेस समाजवादी दल के सिद्धातो व नीतियो मे पर्याप्त अन्तर्विरोध था । जिसका बहुत दिनो तक चलना न तो सभव ही था और न स्वाभाविक ही । फलत काग्रेस समाजवादी दल की बदनामी हुई जिसके परिणाम स्वरुप न तो उसे काग्रेस पार्टी से सम्मान मिला और नही वह अन्य उभरने वाले वामपथी दलो की [illegible] प्राप्त कर [illegible] इस तरह सैद्धान्तिक और वैचारिक नीतियो, व्यावसायिक कार्य प्रणालियो [illegible] के कारण दल की असफलता एव पतन स्वाभाविक तथा [illegible]भावी था।

---

23 - वही, पृष्ठ139-40

का0 स0 पार्टी की असफलता और पतन का कारण निश्चय ही काग्रेस पार्टी से इसका घनिष्ठ सबन्ध होना था, जिसे पार्टी किसी भी स्थिति मे छोड़ने को तैयार नही हुई । सन् 1934 से 1947 तक की अवधि (जब तक काग्रेस समाजवादी पार्टी का अस्तित्व रहा) के दौरान काग्रेस समाजवादी पार्टी की यह कार्यनीति निरन्तर बनी रही कि काग्रेस पार्टी से उसके सबध बिगड़े नही, भले ही गौण रुप मे भी कार्य करने को बाध्य क्यो न होना पडे । दक्षिपथी नेतृत्व के कट्टर पथी के बावजूद काग्रेस समाजवादी पार्टी इस हठधर्मी पर डटी रही कि वह काग्रेस का अभिन्न अग है, और काग्रेस का अभिन्न अग रहते हुए वह काग्रेस की नीतियो व कार्यक्रमो मे क्रान्तिकारी परिवर्तन व संशोधन की चेष्टा करती रहेगी । जिसकी सफलता सदैव सदिग्ध रही जो सच है । एक ओर काग्रेस समाजवादी नेता काग्रेस को समाजवादी बनाने के लिए [illegible]-प्रतिज्ञ थे और इसे भारत मे लोकतान्तित्रक व्यवस्था की स्थापना का प्रतीक मानते रहे ।[24] [illegible] दूसरी ओर गॉधी और दक्षिणपथी नेतृत्व इस पार्टी की नीतियो के खुल्लम-खुल्ला विरोधी [illegible] गॉधी और दक्षिण पथी नेतृत्व ने काग्रेस समाजवादी पार्टी की नीतियो की स्पष्ट आलोचना की और इसका प्रचार भी किया । गॉधी की दृष्टि मे, "कांग्रेस के भीतर समाजवादी गुट का निर्माण स्वागत योग्य था लेकिन उसके कार्यक्रम असहाय तथा अस्वीकार्य थे ।" गॉधी का यह विचार था कि 'समाजवादियो द्वारा प्रचारित वर्ग सघर्ष का सिद्धान्त हिंसानिष्ठ था और यह काग्रेस के मौलिक सिद्धान्तो के सर्वथा विपरीत था ।"[25] गॉधी की इस स्पष्ट उक्ति के बावजूद, काग्रेस समाजवादियो का काग्रेस मोह ज्यो का त्यो बना रहा ।

काग्रेस समाजवादियो की दृष्टि मे काग्रेस,यद्यपि राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्यधारा थी फिर भी प्रतिक्रियावादियो के प्रभाव का इस पर इतना जोर था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध होने वाले सघर्ष के नेतृत्व मे यह सक्षम नही थी ।नि सन्देह यह भारती[illegible] साधारण की राष्ट्रीय भावना का प्रतिनिधित्व करती थी, परन्तु इसके सविधान व कार्यक्र[illegible] प्रताड़ित व शोषित जन साधारण के हितो के अनुकूल नही थे । इसलिए तात्कालिक आवश्यक[illegible] की थी कि नेतृत्व एव पार्टी के कार्यक्रमो मे आमूल परिवर्तन किये जाय ताकि यह साम्राज्यवाद विरोधी सघर्ष के मोर्चे के रुप मे कार्य कर सके । अत काग्रेस समाजवादियो ने यह लक्ष्य निर्धारित किया कि

---

24 - आचार्य नरेन्द्र देव, सोशलिज्म एण्ड दि नेशनल रिवोल्यूशन, पृष्ठ 115-16

25 - इण्डियन एनुअल रजिस्टर (कलकत्ता), भाग-2

काग्रेस के दक्षिणपथी नेतृत्व को पार्टी के क्रान्तिकारी तत्वो द्वारा स्थानापन्न किया जाए ।[26] इस उद्देश्य मे उन्हे न सफलता मिलती थी न मिली क्योकि काग्रेस से बॅधे रहना उनका सर्वोच्च लक्ष्य बना रहा । उनकी अपनी स्थिति क्या थी ? उन्होने काग्रेस से अलग सगठन क्यो नही बनाया ? इन प्रश्नो का उत्तर आचार्य नरेन्द्र देव के शब्दो मे-"हमने काग्रेस से सम्बन्ध-विच्छेद नही किया, क्योकि ऐसा करने से हम ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध होने वाले राष्ट्रीय सघर्ष से अलग-थलग पड जाते जिसका प्रतीक काग्रेस थी ।"[27] आचार्य नरेन्द्र देव और जयप्रकाश नारायण की काग्रेस सबधी इन भावनात्मक उद्घोषणाओ का अध्ययन करने पर यह तथ्य स्वमेव सिद्ध हो जाता है कि समाजवादी काग्रेसियो का काग्रेस से बॅधे रहना एक मजबूरी थी, जिससे छुटकारा पाना, उन्होने न कभी सोचा और न ठीक ही समझा । यह भावनात्मक सबध सुनियोजित रणकौशल का प्रतीक था अथवा समाजवादी सिद्धातो के प्रति ढुलमुल नीति का, इस पर विद्वानो मे व्यापक मतभेद है । लेकिन एक बात स्पष्ट है कि काग्रेसी समाजवादी, काग्रेस से इस सीमा तक बॅधे रहने के लिए दृढ प्रतिज्ञ थे कि समाजवाद के शाश्वत मूल्यो की वैज्ञानिकता को भी नकारने के लिए तैयार थे, जिसके कारण उन्हे न तो कभी काग्रेस के दक्षिपथी नेतृत्व का विश्वास प्राप्त हो सका और न ही अन्य वामपथी दल उनकी समाजवादी सिद्धान्तो के प्रति आस्था को स्वीकार कर सके । फलत काग्रेस समाजवादी पार्टी की असफलता व पतन निश्चित हो गया । काग्रेस समाजवादी पार्टी के जो लोग समाजवादी सिद्धान्तो के प्रति सतत् आस्थावान बने रहे, उन्होने या तो नये वामपथी दल की स्थापना कर डाली अथवा किसी वामपथी दल मे मिल गये । काग्रेस और काग्रेस समाजवादी दल की नीतियो मे मौलिक अन्तर्विरोध थे जिनके कारण दोनो दलो की सदस्यता (एक साथ ही) अधिक दिनो तक नही चल सकती थी । काग्रेस पूर्व थी तो समाजवादी काग्रेस पश्चिम (कम से कम सिद्धातो और नीतियो की दृष्टि से) जिनमे अवाछनीय मेल की कल्पना मात्र थी अर्थात यथार्थ से अत्यधिक दूर ।

काग्रेस समाजवादी पार्टी की असफलता और पतन काफी सीमा तक वामपथी दलो से उसके सबधो के कारण भी हुई । दक्षिण पथी तत्व उसे सन्देह की दृष्टि से देखते थे, तथा वामपथी दल उसे वैज्ञानिक समाजवाद से अत्याधिक दूर मानते थे । काग्रेस समाजवादियो की राजनीतिक विचारधाराऍ भी एक नही थी । यह कई विचारधाराओ के राजनीतिक मनीषियो की जमघट थी

---

26 - एस0 राय चौधरी 'लेफ्टिस्ट मूवमेट इन इण्डिया, (1917 47) पृष्ठ 173

27 - नरेन्द्र देव-' सोशलिज्म एण्ड दि नेशनल रिवोल्यूशन,' पृष्ठ 4

जिसके कारण सर्वसम्मत निर्णय न तो सभव ही था और न स्वाभाविक ही। काग्रेस समाजवादी पार्टी मे कम से कम तीन प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओ के मानने वाले लोग तो थे ही। मार्क्सवादी समाजवादी, फेबियनवादी समाजवाद और उदारवादी समाजवाद के समर्थको मे एकबद्धता के अभाव का बने रहना स्वाभाविक तौर पर अनिवार्य था। वामपथी दलो से इसके सबधो की विवेचना यहा आवश्यक है। सुभाष चन्द्र बोस ने काग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना के कारणों का विश्लेषण करते हुए लिखा, "काग्रेस की दक्षिणपथी नीतियो के प्रतिक्रिया स्वरुप काग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना का प्रयास वैध और स्वाभाविक था। यदि यह प्रतिक्रिया न हुई होती तो काग्रेस का पतन निश्चित था। काग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना सर्वथा न्याय सगत थी, लेकिन इसकी नीतियो मे स्पष्टता का अभाव था।[28] कहना न होगा कि काग्रेस समाजवादी पार्टी ने सुभाष चन्द्र बोस को पार्टी की सदस्यता प्रदान करने का भरसक प्रयास किया लेकिन बोस इसकी नीतियो से न तो पूर्णरुप से सन्तुष्ट थे और न उन्हे पार्टी द्वारा किसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाये जाने की ही आशा थी। काग्रेस समाजवादी पार्टी पर असामयिक तथा अप्रसांगिक प्रभावो पर व्यग करते हुए बोस पार्टी की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए लिखा, "ऐसा प्रतीत होता है कि काग्रेस समाजवादी पार्टी फेबियन समाजवाद से प्रभावित है जो 50 वर्ष पूर्व इंग्लैण्ड मे एक फैशन बन गया था। तब से अब तक टेम्स और गगा मे काफी पानी प्रवाहित हो चुका है। विश्व के विभिन्न भागो मे, प्रथम विश्वयुद्ध के बाद महत्वूपर्ण घटनाए घटित हो चुकी है और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रो मे व्यापक नये अनुशधान हो चुके है, कोई भी आधुनिक पार्टी यूरोप के 50 वर्ष पूर्व के अनुभवो के आधार पर सफलता पूर्वक कार्य नही कर सकती।"[29] बोस के इस मत से यह स्पष्ट हो जाता है कि काग्रेस समाजवादी पार्टी को पूर्णत वह आधुनिक समाजवादी संगठन मानने को तैयार नही थे। सम्भवत: इसी कारण इस पार्टी मे सम्मिलित न होते हुए भी उन्होने एक अन्य वामपंथी राजनीतिक पार्टी की स्थापना की जो "फारवर्ड ब्लाक" के नाम से प्रसिद्ध हुई।

काग्रेस समाजवादी पार्टी की प्रकृति के विषय मे एक आम वामपथी धारणा थी कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से सबद्ध लोग इतने दीर्घ काल तक गॉधी के प्रभाव मे रहे कि उनसे यह आशा करना व्यर्थ था कि समाजवाद को यथार्थत अपनी सस्कृति मान लेते। एम0 एन0 राय व

---

28 - सुभाष चन्द्र बोस-" द इण्डियन स्ट्रगल,' पृष्ठ 363-64

29 - वही, पृष्ठ 384

उनके अनुयायी इस धारणा के मजबूत स्तम्भ थे कि इस पार्टी द्वारा समाजवादी लडाई वास्तविक अर्थो मे नही लड़ी जा सकती, इस धारणा से सन्तुष्ट होकर उन्होने यह प्रयत्न करना आरम्भ किया कि यह पार्टी जितनी जल्दी हो सके टूट जाये। कुछ रायवादी पार्टी से निकल गये और कुछ को निकाल दिया गया। जैसे- बी0 एम0 तारकुण्डे का मोहभग बाद मे हुआ, तब उन्होने स्वय ही पार्टी सदस्यता का परित्याग कर दिया। जिसका परिणाम यह हुआ कि पार्टी की वामपथी प्रकृति और अधिक सदग्धि होती गयी।

काग्रेस समाजवादी पार्टी के विरुद्ध वामपथियो का दूसरा गभीर आरोप यह था कि इस पार्टी का निर्माण काग्रेस पार्टी व बुर्जुआजी के मध्य हुए गुप्त समझौते का परिणाम था ताकि जन साधारण को धोखे मे रखा जा सके और उसके द्वारा किये जाने वाले सघर्ष मे व्यवधान उत्पन्न किया जा सके।[30] इस आलोचना पर काग्रेस समाजवादी पार्टी का नतृत्व बहुत ही तिलमिलाया और उसके शीर्ष नेताओ जैसे-आचार्य नरेन्द्र देव ने इस आलोचना एव आरोप को बेबुनियाद बतलाया तथा मूर्खतापूर्ण माना। उन्होने यह घोषणा की कि यह आरोप बेबुनियाद है और इतना मूर्खतापूर्ण है कि इस पर गभीरता पूर्वक सोचने की भी आवश्यकता नही है।[31] काफी सभव है कि यह आरोप बेबुनियाद हो, लेकिन इसमे दम दिखाई देता है। काग्रेस समाजवादी दल का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि अपनी नीतियो को काग्रेस द्वारा पूर्णरुपेण अस्वीकार किये जाने तथा आलोचना के बावजूद उसके अधिकाश नेताओ का मोहभग नही हुआ। वे काग्रेस द्वारा किये गये इस दुर्व्यवहार को शालीनता पूर्वक स्वीकार करते रहे। इसका तात्पर्य हालाकि यह नही निकालना चाहिए कि इस पार्टी के सारे लोग कूटनीति के समर्थक व पक्षधर थे लेकिन इसके विपरीत निष्कर्ष निकाला भी जैसा कि आचार्य नरेन्द्र देव का अभिमत था, जिसे युक्ति सगत एव आधिकारिक नही माना जा सकता। पार्टी मे कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थको के प्रवेश के सन्दर्भ मे आचार्य नरेन्द्र देव ने जो आशका व्यक्त की उसे निष्पक्ष आशका नही कहा जा सकता। उनकी दृष्टि मे, कम्युनिस्ट लोग पार्टी मे समाजवादी एकता के उद्देश्य से प्रवेश लेने के लिए आतुर नही थे। बल्कि वे उन क्षेत्रो मे अपने प्रभाव जमाने के लिए आतुर थे जिनका प्रभाव नगण्य था। उनके प्रवेश का विरोध करते हुए उन्होने आगे कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक ही साथ, दो दलो की नीतियो के प्रति आस्थावान बने रहना असम्भव है। वैचारिक अन्तरो से पार्टी का

---

30 - एस0 राय चौधरी -"लेफ्टिस्ट मूवमेट इन इण्डिया" (1917-47), पृष्ठ 171

31 - नरेन्द्र देव- सोशलिज्म एण्ड दि नेशनल रिवोल्यूशन" पृष्ठ 66

विकास होता है लेकिन इसका तात्पर्य यह नही हो सकता कि हम ऐसे लोगो को पार्टी मे प्रवेश दे, जो प्रत्यक्षत किसी अन्य दल से निर्देशन ग्रहण करते हो ।[32] नरेन्द्र देव के इस मत मे निहित सच्चाई स्वत स्पष्ट है कि काग्रेस व काग्रेस समाजवादी दल की नतियो मे मौलिक अन्तर्विरोध के बावजूद एक सूत्र मे बने रहना सभव था जबकि दूसरे दलो का समर्थन प्राप्त होना फिर सभव नही हो सकता था । येन-केन प्रकारेण काग्रेस पार्टी से अपने को आबद्ध रखना काग्रेस समाजवादी पार्टी की यही नीति थी (जो स्पष्ट भी है) तो उपर्युक्त आरोप को आसानी से काट पाना उसके लिए मुश्किल था,भले ही उसकी चेष्टा भरपूर हुई हो । काग्रेस समाजवादी पार्टी के आदर्श की घोषणा करते हुए नरेन्द्र देव ने कहा था, "काग्रेस समाजवादियो का आदर्श है कि भारत मे एक वर्गहीन समाज की स्थापना हो, जहॉ शोषण, बेराजगारी और भुखमरी की समस्याओ का सर्वथा अभाव हो ।" यदि वास्तव मे, काग्रेस समाजवादी पार्टी का यही आदर्श था तो उनके उपर्युक्त मत को युक्ति सगत नही माना जा सकता, और यदि पार्टी का उद्देश्य इस लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ और था तो आरोप फिर बेबुनियाद नही माना जा सकता । तत्कालीन काग्रेस समाजवादी पार्टी के अधिकाश नेता सन् 1947 के बाद काग्रेस पार्टी से सम्बद्ध रहे और काग्रेस शासन के अधीन उपर्युक्त समस्याओ का समाधान कितना हुआ यह सर्व विदित है । काग्रेस समाजवादी दल के नेता इससे मुक्त नही कहे जा सकते ।

काग्रेस समाजवादी पार्टी की दोहरी, भ्रामक व अन्तर्विरोधी नीतियो का प्रमाण उसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओ से प्राप्त होता है ।जिनमे से दो का उल्लेख इस बात की पुष्टि करता है । सन् 1939 ई0 मे त्रिपुरा अधिवेशन के दौरान सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व मे काग्रेस के समस्त वामपथी तत्वो के मेल के सिद्धान्त को समाजवादी नेतृत्व ने अपना सहयोग प्रदान नही किया जो इसकी नीतियो के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रतीत होता था । सुभाष चन्द्र बोस ने काग्रेस समाजवादी पार्टी की इस डगमगाहट को विश्वासघात घोषित किया और यह मत व्यक्त किया कि वह पार्टी काग्रेस के सम्पूर्ण नेतृत्व और अनुशासन से इतनी अधिक आबद्ध थी कि वह अपनी पूर्व निर्धारित नीतियो का खुलेआम उल्लघन सहने को भी तैयार थी । इसमे कोई सन्देह नही कि यदि पार्टी ने सुभाष चन्द्र बोस को अपना सहयोग प्रदान किया होता तो इनकी नीतियो का काफी हद तक लागू होना सम्भव था । पार्टी के इस रवैये से क्या अभीष्ट था, यह स्पष्ट नही

32 - आचार्य नरेन्द्र देव- 'सोशलिज्म एण्ड दि नेशलन रिवोल्यूशन", पृष्ठ 109

33 - सुभाष चन्द्र बोस-"क्रास रोडस" पृष्ठ 113

होता और उसकी ढुलमुल नीति साफ परिलक्षित होती है । इसी तरह द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान युद्ध मे भारतीय सहभागिता का पार्टी ने डटकर विरोध किया और यह घोषणा की कि भारत को इस युद्ध मे किसी भी रुप मे भाग नही लेना चाहिए । जे0 पी0 ने पार्टी के इस रुख को सन् 1940 मे इन शब्दो मे व्यक्त किया," भारत इस युद्ध मे भाग नही ले सकता क्योकि जर्मन नाजीवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद दोनो ही अपने-अपने स्वार्थो से आबद्ध है ताकि विजय व आधिपत्य के माध्यम से शोषण और उत्पीड़न कर सके । ग्रेट ब्रिटेन नाजीवाद की समाप्ति के लिए नही लड़ रहा, क्योकि इसी की देखरेख मे उसका उत्थान हुआ । बल्कि इस लिए लड रहा है ताकि इन दोनो की होड़ मे वह अपना सर्वोच्च स्थान कायम रख सके और साम्रज्य की शक्ति तथा कीर्ति को सुरक्षित रख सके । भारतीय साम्राज्य को बनाये रखना उसका प्रथम उद्देश्य है ।[34] आचार्य ने भी इस कथन की पुष्टि की ।[35] युद्ध मे भारतीय सहभागिता के इस तीखे विरोध का हस्र यह हुआ कि पहले तो बिना किसी शर्त के वे (काग्रेस समाजवादी) इसके विरोध मे थे लेकिन बाद मे सशर्त सहभागिता को अपनी सहमति प्रदान कर दी ।[36] सम्भवत पार्टी के रुख मे इस बदलाव का कारण यही था कि उसके लिए कांग्रेस का तत्कालीन नेतृत्व व एकता सर्वोच्च थी, जिसके लिए वे अपनी स्वनिर्धारित नीतियो को भी ताक पर रखने के लिए कृत सकल्प थे । भारतीय जन साधारण के समक्ष उसके इस दोहरे चरित्र का पर्दाफाश होना स्वाभाविक था, और जो हुआ भी, अत इसके प्रति जन साधारण मे उदासीनता घर करती गयी और अन्तत पार्टी का पतन सुनिश्चित हो गया ।

2- समाजवादी पार्टी (कांग्रेस के बाहर)

काग्रेस समाजवादी पार्टी के कानपुर अधिवेशन मे यह निश्चय किया गया कि "काग्रेस" को पार्टी के नाम से हटा दिया जाय । इस निश्चय के परिणाम स्वरुप समाजवादी पार्टी एक स्वतन्त्र पार्टी के रुप मे संगठित करने की पृष्ठभूमि तैयार हो गयी । समाजवादी पाटी के नासिक अधिवेशन से पूर्व महात्मा गॉधी के शहीद हो जाने के बाद काग्रेस मे सरदार बल्लभ भाई पटेल का वर्चस्व स्थापित हो गया । कांग्रेस के सविधान सशोधन के बाद समाजवादी पार्टी के सामने कोई विकल्प नही रह गया और पाटी को काग्रेस से बाहर आने पर मजबूर होना पडा ।

---

34 - जय प्रकाश नारायण-"टुअर्ड्स स्ट्रगल" पृष्ठ 203

35 - नरेन्द्र देव- सोशलिज्म एण्ड नेशनल रिवोल्यूशन,' पृष्ठ 144

36 - एस0 राय चौधरी-"लेफ्टिस्ट मूवमेंट इन इण्डिया,' (1917-47), पृष्ठ 175-76

समाजवादी पार्टी का नासिक सम्मेलन आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता मे 1948 मे हुआ उसमे उन्होने समाजवादी पार्टी को काग्रेस से बाहर निकाले जाने पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया । उन्होने अपने भाषण मे कहा कि काग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के नाम से "काग्रेस" शब्द हटा दिया जाये और पार्टी मे गैर काग्रेसी सदस्यो को शामिल करने पर कोई रोक न रखी जाये । उनका कहना था कि ऐसा करने के बाद समाजवादी पार्टी कांग्रेस मे बनी रह सकेगी । हमने उनके सुझाव के अनुरुप समाजवादी पार्टी के नाम से "काग्रेस" शब्द हटा दिया । अब ऐसी स्थिति है कि हमे काग्रेस छोड़नी पड रही है । यह हमारे लिए सुखद नही है । मैं 30 वर्षो से कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूॅ । मैं इस पुराने सम्बन्धो को छोड़ रहा हूँ राजनीति अजीब है, इसमे मित्र शत्रु बन जाते है ।[37]

नासिक सम्मेलन के निर्णय के अनुसार आचार्य नरेन्द्र देव के नेतृत्व मे उत्तर प्रदेश विधान सभा से 12 समाजवादी विधायको ने त्यागपत्र दे दिया । बाद मे उपचुनाव मे केवल एक समाजवादी जीता है । आचार्य नरेन्द्र देव भी पराजित हो गये । उनके विरुद्ध चुनाव प्रचार मे प0 गोविन्द बल्लभ पन्त ने यह आरोप लगाया कि यदि समाजवादी जीत गये तो भारतीय सस्कृति नष्ट हो जायेगी । काग्रेसी प्रत्यासी बाबा राघवदास को रामभक्त बताकर धार्मिक और साम्प्रदायिक भावनाओ को उकसाया गया था । काग्रेस उस समय केन्द्र और राज्यो मे सत्ता मे थी। बम्बई कारपोरेशन के चुनाव मे समाजवादी पार्टी के 26 सदस्य चुने गये । उस समय उसमे कुल 49 स्थान थे । इसके बाद श्री युसूफ अली मेहर भी चुने गये ।

समाजवादी पार्टी के नासिक सम्मेलन मे पार्टी के स्वरुप, संगठन और उसकी रीति-नति के सम्बन्ध मे विचार किया गया था । किसानो, मजदूरो, छात्रो और युवा लोगो को संगठित करने पर विचार किया गया । पार्टी की वैदेशिक नीति को स्थिर करने के लिए डा0 राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व मे एक समिति गठित हो गयी थी ।

समाजवादी पार्टी का 1949 मे पटना मे अधिवेशन हुआ । उसमे पार्टी की नीति निर्धारित करने के लिए जो वक्तव्य तैयार किया गया था उसमे कहा गया था कि परिस्थितियो के अनुसार सत्ता पर अधिकार करने के लिए शान्तिपूर्ण अथवा सशस्त्र क्रान्ति के मार्ग को अपनाया जा सकता है ।उस समय समाजवादियो की धारणा थी कि सत्ता पर अधिकार सशस्त्र सघर्ष और

---

37 - 1948 मे नासिक अधिवेशन मे समाजवादी पार्टी के अध्यक्षीय भाषण के कुछ अश

लोकतान्त्रिक दोनो तरीको से किया जा सकता है। लोकतान्तित्रक तरीको मे ससदीय और गैर ससदीय दोनो कार्य शामिल हैं। इस सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण के रुप मे कहा गया कि लोकतान्त्रिक तरीके उसी स्थिति मे अपनाये जा सकते हैं जब देश मे लोकतान्त्रिक पद्धति का पूर्ण रुप से प्रयोग हो और जब मजदूर, किसान और निम्न मध्यम श्रेणी के लोगो को राजनीतिक दृष्टि से ठीक से सगठित किया गया हो और उनको अपने वर्ग स्वार्थो के आधार पर राजनीतिक दल के रुप मे सगठित किया गया हो।[38]

समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मे जुलाई 1947 मे ट्रेड यूनियनो को कम्युनिस्टो और काग्रेस के प्रभाव से मुक्त रखकर सगठित करने पर जोर दिया गया था।अशोक मेहता को ट्रेड यूनियन क्षेत्र मे पार्टी के काम काज की देखभाल करने का अधिकार दिया गया था। उन्होने मजदूरो को इस प्रकार सगठित करने पर जोर दिया जिसके आधार पर समाजवादी पार्टी को सुदृढ बनाया जा सके। समाजवादी पार्टी को लोकतान्त्रिक प्रणाली के आधार पर देश की सामजिक व्यवस्था की पुनर्रचना का प्रयास करना चाहिए। इसी सिद्धांत के आधार पर हिन्द मजदूर सभा सगठित की गयी। श्री रुइकर ने उसमे सहयोग किया। बाद मे इण्डियन फेडरेशन आफ लेबर के विघटित होने पर सर्व श्री बी0 बी0 कर्णिक और श्रीमति मणिबेन राय ने हिन्द मजदूर सभा के साथ सहयोग किया। 1947 से 1949 तक जे0 पी0 रेलवे मेन्स फेडरेशन, डाकतार कर्मचारी सघ के अध्यक्ष थे। एस0 एम0 जोशी रक्षा कर्मचारी सघ के अध्यक्ष थे। उन दिनो समाजवादियो ने दिल्ली, बम्बई, कानपुर तथा बिहार के अनेक क्षेत्रो मे मजदूर सघर्ष चलाये। 1949 मे डाकतार और रेल कर्मचारियो की हडताल की नोटिश दी गयी।लेकिन बाद मे जय प्रकाश नारायण ने उन्हे वापस ले लिया। कहा जाता है कि कम्युनिस्टो की अतिवादी नीति के कारण उनसे बचने के लिए जे0 पी0 ने ऐसा किया था।

समाजवादी पार्टी के नासिक सम्मेलन में किसानो को सगठित करने के लिए एक उपसमिति बनायी गयी थी। किसान सभा पर कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव था। 1947-1949 तक समाजवादी पार्टी की ओर से किसानो की मागो के लिए अनेक सघर्ष पूर्ण आन्दोलन किये गये। उत्त प्रदेश, विन्धय प्रदेश मे किसानो पर अत्याचारो और उनकी बेदखली के विरुद्ध आन्दोलन में जब जमीदारो की ओर से हिंसापूर्ण दमन का सहारा लिया गया तो पार्टी की ओर से जवाबी हिंसा

[38] - "समाजवादी पार्टी का नीति वक्तव्य-" 1951 बम्बई

और हिंसा के प्रयोग की धमकी दी गयी। 30 नवबर 1949 को लखनऊ विधान सभा के समक्ष एकलाख किसानो का प्रदर्शन किया गया। 3 जून 1951 मे दिल्ली मे समाजवादी पार्टी की ओर से विशाल प्रदर्शन किया गया।

काग्रेस सरकारो द्वारा जमीदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाने का सिलसिला 1948 से शुरु होकर 1951-52 तक चलता रहा। जमीदारी उन्मूलन के बाद समाजवादी पार्टी का किसान क्षेत्र मे प्रभाव घटने लगा। गन्ना किसानो की मागो के लिए गेदा सिह ने उत्तर प्रदेश मे कई आन्दोलन चलाये। लेकिन बाद मे ग्रामीण क्षेत्र मे किसानो अर्थात् बडे और मध्यम किसानो के विरोध के डर से समजावादी पार्टी ने खेतिहर मजदूर और भूमिहीन किसानो को सगठित करने का प्रयास नही किया जो समाजवादी सिद्धात के अनुसार एक अनिवार्य आवश्यकता थी।

समाजवादी पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्रो मे रचनात्मक कार्य करने के उद्देश्य से फरवरी 1951 मे बिहार के 'देकुली' मे ग्रामीण रचनात्मक कार्यकर्ताओ का सम्मेलन किया। उस समय समाजवादी पार्टी ने श्रमदान और "एक घटे देश को दो" का अभियान चलाया।

अगस्त क्रान्ति के प्रभाव के कारण 1944 मे "स्टूडेण्ट्स काग्रेस" नामक सस्था गठित की गयी थी। उसमे समाजवादियो का प्रभाव अधिक था। उस समय "स्टूडेण्ट्स फेडरेशन" कम्युनिस्टो के प्रभाव मे था। स्टूडेण्ट्स काग्रेस का सम्मेलन हैदराबाद मे हुआ, और काग्रेस तथा समाजवादियो के पारस्परिक विरोध के कारण वह छिन्न-भिन्न हो गयी। 1950 मे ब्रिटेन की भॉति भारत मे नेशनल यूनियन आफ स्टूडेण्ट्स सगठित की गयी। इस सगठन को राजनीति से अलग रखने का प्रयास किया गया। बाद मे सत्ता के प्रभाव के कारण इस सगठन पर काग्रेस का ही प्रभाव हो गया।

1950 मे समाजवादी युवजन सभा अथवा सोशलिस्ट यूथ लीग की स्थापना की गयी। इसको देश के अनेक प्रदेशो मे सगठित किया गया। महाराष्ट्र मे राष्ट्र सेवा दल नामक युवाओ का सगठन समाजवादी पार्टी के प्रभाव मे काम कर रहा था।

1949 मे पटना मे समाजवादी पार्टी का सम्मेलन आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता मे हुआ। जय प्रकाश नारायण ने सगठन की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होने अपनी रिपोर्ट मे इस बात पर जोर दिया कि पार्टी को नये आधार पर जन संगठन के रुप सगठित किया जाना चाहिए।

आचार्य नरेन्द्र देव ने यह सुझाव दिया कि पार्टी मे ट्रेड यूनियन, किसान पचायत, समाजवादी यूथ लीग तथा सहकारी सस्थाओं को सम्बद्ध करके उनको पार्टी में प्रतिनिधित्व देना चाहिए।

रामचन्द्रन मिश्र और श्रीमती अरुणा आसफ अली ने समाजवादी पार्टी को सक्रिय क्रान्तिकारियो की पार्टी बनाने पर जोर दिया और यह विवाद काफी लम्बा चला। अन्तत आचार्य नरेन्द्र देव के आग्रह से सम्मेलन मे समाजवादी पार्टी को खुले जन सगठन के रुप मे गठित करने के लिए जय प्रकाश नारायण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इस विवाद मे मार्क्सवाद की सैद्धान्तिक बहस उठी और कहा गया कि संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था पूँजीवादी व्यवस्था के भीतर उसकी समर्थक बनकर रहती है।दूसरी ओर से कहा गया कि लेनिन की बाल्शेविक पार्टी भी संसदीय पद्धति का अनुसरण करती थी। अतः समाजवादी पार्टी को अपने लक्ष्य और सिद्धान्त के अनुरुप समाज की रचना के लिए प्रत्येक क्षेत्र मे काम करके अपना प्रभाव बढाना चाहिए। जय प्रकाश नारायण ने उस समय यह दावा किया था कि उनका प्रस्ताव पूर्ण रुप से मार्क्सवादी सिद्धांतो के अनुरुप है।

"लोकतान्त्रिक समाजवाद" नामक पुस्तक मे जय प्रकाश नारायण ने इस सबध मे कहा था कि भारत में इस समय केवल लोकतान्त्रिक उपाय ही सबसे अधिक उपर्युक्त है। यदि देश मे लोकतान्त्रिक आचार-व्यवहार का विकास होता है तो भारत मे समाजवाद की स्थापना के अन्तिम दौर मे भी लोकतान्त्रिक ढंक को अपनाना उचित होगा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उस समय तक कांग्रेस में सरदार पटेल का प्रभाव अधिक था। केन्द्रीय सरकार में पूँजीवादी तत्व, सामन्तवादी प्रभाव सामाजिक क्षेत्र मे, सरकारी तन्त्र मे अफसर शाही के प्रभाव के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत मे पूँजीवादी सामन्ती व्यवस्था ही चल रही थी।राष्ट्रीय अहमान्यता और साम्प्रदायकिता के प्रभाव के कारण फासिस्टवादी प्रवृत्तियाँ प्रकट हो रही थीं।

1950 मे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव मे सरदार पटेल ने राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन को अपना प्रत्याशी बनाया था। पं० जवाहर लाल नेहरु ने आचार्य जे० बी० कृपलानी को अपना प्रत्याशी बनाया जो चुनाव में पराजित हो गये।कांग्रेस के भीतर "डेमोक्रेटिक फ्रन्ट" नाम से एक सम्मेलन दिल्ली मे किया गया, जिसमे पं० जवाहर लाल नेहरु, मौलाना अबूल कलाम आजाद और पश्चिम बंगाल के प्रफूल्ल चन्द्र घोष आदि ने हिस्सा लिया। बाद मे जून 1951 मे

पटना मे एक सम्मेलन के बाद आचार्य जे0 बी0 कृपलानी ने "किसान मजदूर प्रजा पार्टी" सगठित की । रफी अहमद किदवई भी उस सम्मेलन मे शामिल हुए थे । बाद मे उन्होने उससे अपना सम्बन्ध तोड़ लिया ।

1951 के आरम्भ में सरदार बल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद काग्रेस मे आन्तरिक संकट उत्पन्न हो गया। पं0 जवाहर लाल नेहरु ने राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन द्वारा गठित कार्य समिति मे रहने से इन्कार कर दिया । काग्रेस महासमिति के बगलौर अधिवेशन मे एक जटिल स्थिति उत्पन्न हो गयी । उसके बाद राजर्षि टण्डन ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया और पं0 जवाहर लाल नेहरु को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया ।[39] वे 1955 तक कांग्रेस के अध्यक्ष और देश के प्रधान मत्री थे तथा राष्ट्रीय नेतृत्व उनके हाथ मे आ गया था ।1952 के आम चुनाव के समय पं0 जवाहर लाल नेहरु का एक छत्र प्रभाव था ।

समाजवादी पार्टी का आठवाँ सम्मेलन मद्रास मे हुआ । सन् 1950 मे पार्टी की सदस्य संख्या एक लाख उन्तीस हजार चार सौ सैंतालीस थी । हिन्द मजदूर सभा की सदस्य संख्या सात लाख थी और उससे पार्टी मे 19,146 प्रतिनिधि थे ।किसान पचायत की सदस्य सख्या पॉच लाख थी । और उससे संबंधित 339 पार्टी सदस्य प्रतिनिधि थे । छात्र और युवा सगठन उस समय उत्तर प्रदेश मे सक्रिय थे ।

समाजवादी पार्टी के 1950 के मद्रास सम्मेलन में इस बात की पुन· स्पष्ट रुप से घोषणा की गयी कि समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक आधार और व्यवहार के लिए पूरी तौर से प्रतिबद्ध है और उसकी आस्था है कि भारत में सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन लोकतान्त्रिक तरीको से सम्भव है । इस कार्यपद्धति को पूर्णतः मार्क्सवादी कहा गया था ।मद्रास सम्मेलन मे डा0 राम मनोहर लोहिया ने जय प्रकाश नारायण के कार्य पद्धति की कटु आलोचना की थी ।जिससे खीझकर जय प्रकाश नारायण पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के पद को छोड़ने के लिए तत्पर हो गये थे ।

कलकत्ता में एशियन यूथ्स और कम्युनिष्ट पार्टी ने फरवरी 1948 में अति उग्रवादी नीति अपनायी थी । पूर्ण चन्द्र जोशी के स्थान पर वी0 टी0 रणदिवे कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी चुने गये थे।उस समय अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट नेता जेडे नोव की थीसिस के अनुसार नव

---

39 - चन्द्रोदय दीक्षित-" भारतीय समाजवादी आन्दोलन", पृष्ठ 99

स्वतत्र पूँजीवादी देशो मे मजदूर-किसान आदि के सहयोग से क्रान्ति का प्रयास किया जाना चाहिए । इस नीति के कारण 1948 से 1950 तक तेलगाना मे कम्युनिस्टो ने किसान विद्रोह चलाने का प्रयास किया । इसके प्रतिउत्तर मे आचार्य विनोबा भावे ने अपना सर्वोदय आन्दोलन और भूदान के लिए देश भर की पद यात्रा का अभियान चलाया जिसे सत्ता रुढ काग्रेस का पूरा समर्थन मिला और भूदान का व्यवहारिक रुप देने के लिए भूमि कानूनो मे भी सशोधन किये गये।

समाजवादी पार्टी के नासिक सम्मेलन मे डा0 राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व मे एक वैदेशिक समिति बनायी गयी थी । उन्होने उस समय गुट-निरपेक्ष राजनीति का समर्थन किया था। उन्होने अनेक देशो का दौरा कर सभी एशियाई देशो के समाजवादियो को एशियाई सोशलिस्ट कान्फ्रेन्स के रुप मे संगठित करने का प्रयास किया । 1953 मे रगून मे एशियाई सोशलिस्ट सम्मेलन भी किया गया था । उस समय डा0 लोहिया का कहना था कि एक विश्व सरकार की स्थापना तभी सम्भव होगी जब विभिन्न देशो की जनता को आर्थिक बराबरी का दर्जा मिले । सभी देशो के निवासियों के मौलिक अधिकारो और अवसर की समानता के आधार पर शोषण मुक्त समाज सगठित किया जा सकता है । संसार के उत्पीड़ित और शोषित लोग ऐसे समाज की स्थापना के लिए लालायित हैं ।

समाजवादी पार्टी ने 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस से बाहर आने के बाद पहली बार हिस्सा लिया । ज्ञात है कि भारतीय सविधान 1950 से लागू हो गया था । 3 जून 1947 के पूर्व समाजवादियों ने सविधान सभा मे इसलिए हिस्सा नही लिया क्योकि सविधान सभा को सार्वभौमता प्राप्त नही थी ।और भारत मे अंग्रेजी शासन और फौजें बरकरार थी । 3 जून 1947 के बाद जय प्रकाश नारायण ने पं0 जवाहर लाल नेहरु को सूचित किया कि समाजवादी संविधान सभा में अब भाग ले सकते हैं ।लेकिन उसके बाद भी समाजवादियो ने अपने पारस्परिक मतभेद के कारण सविधान सभा मे नही पहुँच सके ।संविधान सभा मे केवल तीन समाजवादी शामिल हुए थे ।उत्तरप्रेदश काग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते दामोदर स्वरुप सेठ सविधान सभा के सदस्य थे । इसके अतिरिक्त दो अन्य सदस्य थे, उनमे उड़ीसा के शारंग दास और उत्वा के हरेश्वर गोस्वामी शामिल थे ।बाद में समाजवादी सदस्यो को यह आदेश दिया गया कि वे लोग संविधान पर अपने हस्ताक्षर न करे ।

नये संविधान के अनुसार संसद और विधान मण्डलों के लिए चुनाव की तैयारियाँ 1951 से शुरु हो गयी थी । उस समय देश में सत्तारुढ़ कांग्रेस के अतिरिक्त समाजवादी पार्टी, किसान, मजदूर प्रजा पार्टी एवं जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी के अतिरिक्त छोटी बड़ी अनेक पार्टियाँ थी । समाजवादी पार्टी के नेतागण विशेष रुप से जे0 पी0, आचार्य नरेन्द्र देव, डा0 लोहिया, अच्युत पटवर्घन, युसूफ मेहर अली, अशोक मेहता, एस0 एम0 जोशी तथा एन0 जी0 गोरे आदि राष्ट्रीय आन्दोलन के राष्ट्रीय नेताओं में गिने जाते थे ।समाजवादी पार्टी कांग्रेस के विकल्प की दावेदार थी। इस दृष्टि से प्रथम आम चुनाव में उसका भाग लेना अत्यन्त महत्वपूर्ण था । कांग्रेस के भीतर समाजवादी प्रभाव के कारण उसमें वामपंथी झुकाव हो जाता था और जनता में क्रान्तिकारी छवि बनाने में भी सहायक थे । लेकिन कांग्रेस संगठन पर पुराने दक्षिणपंथी नेताओं का प्रभाव था । जो 1947 से 1950 तक सरदार बल्लभ भाई पटेल की छत्रछाया में काम करते थे । बाद में उन्होंने पं0 जवाहर लाल नेहरु के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था । 1947 से 1950 तक कांग्रेस ने संसदीय लोकतंत्र को स्थापित करने के लक्ष्य को अपनाया जिसे पूँजीवादी लोकतन्त्र भी कहा जाता है । बाद में पं0 जवाहर लाल नेहरु ने सहकारी सामाजिक व्यवस्था (कोआपरेटिव कामन वेल्थ) की चर्चा की । 1952 के आम चुनाव में जनता में वामपंथी प्रवृत्ति को देखकर उन्होंने 1955 में समाजवादी सामाजिक ढांचे की चर्चा कराना शुरु कर दिया था । संसद में भी एक प्रस्ताव पासकर समाजवाद के लक्ष्य को स्वीकार किया गया और बहुत बाद में तो संविधान की प्रस्तावना में भी "समाजवाद" को रखा गया ।

पाकिस्तान की स्थापना और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत के बाद देश के राजनीतिक सन्तुलन में मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा जैसी संस्थाओं की स्थिति नगण्य हो गयी थी । कम्युनिस्ट पार्टी ने 1950 के बाद अपनी अतिवादी नीति छोड़ी थी ।उसका प्रभाव मद्रास, हैदराबाद और पश्चिम बंगाल में ही सीमित था । समाजवादी पार्टी का प्रभाव अखिल भारतीय स्तर पर सार्वजनिक प्रदर्शनों और आन्दोलनों में स्पष्ट रुप से दिखाई देता था । परन्तु चुनाव में इनकी सफलता बड़ी ही सीमित रही । इसके 12 प्रत्याशी ही चुनाव जीत सके और मत भी 10.6 प्रतिशत ही ये प्राप्त कर सके ।

3. प्रजा समाजवादी पार्टी का उदय और विकास

1952 मे समाजवादी पार्टी का सम्मेलन पचमढ़ी मे डा0 राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता मे हुआ । उस सम्मेलन मे डा0 राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी पार्टी की नीतियो का निरुपण करने का प्रयास किया । उनका आग्रह था कि समाजवादी पार्टी को काग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी से समान दूरी रखनी चाहिए । और उनसे कोई वास्ता नही रखना चाहिए । अशोक मेहता समाजवादी आन्दोलन के प्रमुख अर्थशास्त्री माने जाते थे । वे समाजवादी पार्टी द्वारा ससदीय लोकतन्त्र मे हिस्सा लेने पर जोर देते थे । उनका कहना था कि देश के आर्थिक पिछडेपन के कारण समाजवादी पार्टी को सत्ता रुढ़ कांग्रेस दल के साथ सहयोग करने के क्षेत्रो को ढूढने का प्रयास करना चाहिए । जे0 पी0 का मार्क्सवाद के प्रति मोहभग हो गया था और वे गॉधीवाद के प्रभाव मे अधिक आ रहे थे । उन्होने आचार्य विनोबा भावे द्वारा सचालित भूदान आन्दोलन मे अधिक रुचि ली और बाद मे भूदान और सर्वोदय आन्दोलन मे पूरी तौर से जुटकर काम करने के लिए उन्होने भूदान आन्दोलन के गया अधिवेशन मे जीवनदान की घोषणा कर दी ।

समाजवादी पार्टी मे उच्च आदर्शों से प्रेरित भारतीय नेताओ की कमी नही थी, लेकिन पार्टी का सगठन और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी । 1952 के आम चुनाव मे पार्टी की विफलता का यही कारण था । लन्दन से प्रकाशित "दि टाइम्स" ने समाजवादी पार्टी की विफलता पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि भारत मे शक्तिशाली दल को अधिक शक्ति मिलती है । पचमढी सम्मेलन मे समाजवादी पार्टी के सिद्धात निरुपित करने का प्रयास किया गया । समाजवादी पार्टी को लोकतान्त्रिक और प्रगतिशील विपक्ष की भूमिका का भी निर्वाह करना था उस सम्मेलन मे काग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी से अलग रहते हुए देश में छोटे उद्योगो की तकनीकि विकसित करने और समजावाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा के उपायो का परित्याग करने पर जोर दिया गया । जे0 पी0 ने महात्मा गांधी के उपदेशो के अनुरुप साध्य-साधन दोनो के पवित्र रखने पर जोर दिया । उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी को केवल वामपथी शक्तियो को एकत्र करने का ही प्रयास नही करना चाहिए वरन् सभी लोकतान्त्रिक वामपथी लोगो को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहिए । उन्होने परिगणित जाति संघ (अम्बेडकरवादी), क्षारखण्ड पार्टी और किसान मजदूर पार्टी का सहयोग लेने का सुझाव दिया ।

1 जून 1952 को संसद मे श्रीमती सुचेता कृपलानी के नेतृत्व मे समाजवादी पार्टी और किसान-मजदूर प्रजा पार्टी का सयुक्त गुट "समाजवादी प्रजा गुट"के नाम से गठित किया गया ।

उस गुट के लिए न्यूनतम कार्यक्रम स्वीकार किया गया जिसमे न्याय सगत सामाजिक व्यवस्था की स्थापना, राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण, बड़े उद्योगो का राष्ट्रीयकरण, स्वतन्त्र मजदूर सघो की स्थापना, नागरिक अधिकारो की रक्षा, त्यागपूर्ण जीवन, स्वदेशी की भावना, बडे शक्तिशाली राष्ट्रो के गुटो से अलग रहना (गुट-निरपेक्षता), सेना मे कमी, राष्ट्रीय सेना (मिलेशिया) के गठन की बाते शामिल थी। बाद मे इस गुट के आधार पर समाजवादी पार्टी और किसान-मजदूर प्रजा पार्टी का विलय करके प्रजा समाजवादी पार्टी की स्थापना की गयी। आचार्य कृपलानी ने सितम्बर 1952 मे समाजवादी दल और किसान-मजदूर प्रजा पार्टी को मिलाकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी ने एक 14 सूत्रीय समाजवादी कार्यक्रम निर्मित किया लेकिन नेहरु जी ने इस कार्यक्रम को स्वीकार नही किया, फलस्वरुप इस दल के साथ काग्रेस की न बन सकी।[40] और प्रजा समाजवादी पार्टी भी नेहरु के समाजवाद को छल प्रपच की सज्ञा देते रहे।[41]

मद्रास मे किसान-मजदूर प्रजा पार्टी वहॉ के गैर कांग्रेसी लोकतान्त्रिक मोर्चे मे शामिल थी। जिसमे कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। टी0 प्रकाशम उस मोर्चे के नेता थे, और उसमे समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त सभी विपक्षी दल शामिल थे। समाजवादी पार्टी उसमे इसलिए शामिल नही हुई क्योकि उसमे कम्युनिस्ट पार्टी शामिल थी। उस समय मद्रास विधान सभा मे समाजवादी गुट के 13 सदस्य थे और उनके नेता डा0 के0 वी0 मेनन थे। मद्रास विधान सभा मे 1952 के आम चुनाव मे 375 सदस्य थे, जिनमे से कम्युनिस्ट पार्टी के 62, किसान मजदूर प्रजा पार्टी के 35, अन्य दलो के 61 तथा निर्दलीय 62 सदस्य थे। मद्रास की किसान-मजदूर प्रजापार्टी का सुझाव था कि समाजवादी पार्टी भी लोकतान्त्रिक मोर्चे मे शामिल हो, लेकिन जय प्रकाश नारायण और अशोक मेहता ने इसका विरोध किया। अन्त मे मद्रास के किसान-मजदूर प्रजा पार्टी के विधायको को लोकतान्त्रिक मोर्चे मे शामिल रहने की छूट दी गयी और समाजवादी विधायको को अपना गुट अलग रखने की आजादी दी गयी।

समाजवादी पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के विलय की आरम्भिक वार्ता उस समय हुई थी जब पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष आचार्य नरेन्द्र देव एक प्रतिनिधि मण्डलन मे चीन गये हुए थे। लौटने पर जब विलय वार्ता सुनी तो वे इस बात से दु खी हुए कि समाजवादी पार्टी के

---

40 - हरि किशोर सिंह-" ए हिस्ट्री आफ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी," पृष्ठ-180-82

41 - डा0 शोभा शकर "आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन", पृष्ठ 55

विलय समर्थक नेताओ ने इतनी जल्दबाजी से काम लिया । बाद मे उन्होने विलय का समर्थन किया । प्रो0 मुकुट बिहारी लाल और श्रीमती शीला परेटा ने विलय की आलोचना करते इसे अवसरवादी और अलोकतान्त्रिक बताया क्योकि इस सबध मे नेताओ ने ऊपरी तौर से निर्णय लिया था और दोनो दलो के साधारण सदस्यो की राय जानने का प्रयास ही नही किया गया था।

24-25 अगस्त 1952 को लखनऊ मे किसान-मजदूर प्रजा पार्टी की ओर से आचार्य जे0 बी0 कृपलानी और समाजवादी पार्टी की ओर से आचार्य नरेन्द्र देव, डा0 राम मनोहर लोहिया और अशोक मेहता ने बातचीत की और दोनो दलो के विलय और प्रजा समाजवादी पार्टी के गठन का समझौता किया । इसके बाद इस विलय की पुष्टि के लिए बम्बई मे सम्मेलन किया गया । यह भी निश्चय किया गया कि समाजवादी पार्टी का विधान नयी पार्टी का विधान मान लिया गया । आचार्य नरेन्द्र देव ने विलय के सम्बन्ध मे अपने वक्तव्य मे कहा कि गैर साम्प्रदायिक और गैर कम्युनिस्ट गुटो की एकता की ओर यह विलय पहला कदम है । अशोक मेहता ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्र मे यह नवजीवन की आधार शिला बन सकती है जिसके आधार पर काग्रेस का विकल्प तैयार हो सकता है।

प्रजा समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय आचार्य जे0 बी0 कृपलानी अध्यक्ष , डा0 राम मनोहर लोहिया जनरल सेक्रेटरी, सर्वश्री अशोक मेहता, मधु लिमये और सादिक अली ज्वाइन्ट सेक्रेटरी बनाये गये । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यो मे सर्वश्री आचार्य नरेन्द्र देव, जय प्रकाश नारायण, हरेश्वर गोस्वामी, के0 के0 मेनन, एम0 जी0 गोरे, पी0 सी0 घोष, बालेश्वर दयाल, चेन्नादुराई, के0 आर0 कारन्थ, श्रीमती लीला राय, पट्टम थानु पिल्लई, प्रेम भसीन, तथा पी0 बी0 राजू आदि । इस पार्टी की सदस्य सख्या 2 लाख 70 हजार थी। लोकसभा मे 27, राज्य सभा मे 8, राज्यो की विधान सभाओ मे 209 प्रजा समाजवादी सदस्य थे ।उस समय तर्क यह प्रस्तुत किया गया था कि 1952 के चुनाव फल के आधार पर 16 31 प्रतिशत मत मिले थे जो काग्रेस के बाद दूसरा स्थान था ।

प्रजा समाजवादी पार्टी की स्थापना के समर्थक लोगो मे इतना अधिक उत्साह था कि वे अपने को कांग्रेस का विकल्प मानने लगे थे ।दूसरी ओर ऐसे लोग थे जो इस बात से दु खी थे कि समाजवादी पार्टी ने मार्क्सवाद और समाजवाद के प्रति अपनी निष्ठा को दूषित कर लिया ।उस

समय जे0 बी0 कृपलीन का कहना था कि राजनीतिक दल के लिए सिद्धात (आइडियोलाजी) कोई अनिवार्य आवश्यकता नही है।

फरवरी 1953 मे काग्रेस अध्यक्ष और प्रधान मत्री प0 जवाहर लाल नेहरु ने जय प्रकाश नारायण को काग्रेस और प्रजा समाजवादी पार्टी मे शासन और बाहर सहयोग के आधार ढूढने के लिए बातचीत हेतु आमन्त्रित किया । उस समय डा0 लोहिया जेल मे थे और आचार्य नरेन्द्र देव का स्वास्थ्य ठीक नहीं था । जिसमें जय प्रकाश जी डा0 लोहिया से परामर्श ही न कर सके और नरेन्द्र देव जी को केवल सूचना भर दे सके । इससे इनमे आपसी कटुता बढी । उधर जे0 पी0 ने काग्रेस से सहयोग के लिए 14 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया परन्तु उस पर नेहरु सहमत न हो पाये, जिससे दोनो के मध्य वार्ता विफल रही ।यही नही इस बातचीत का विरोध दोनो पक्षो मे भी व्यापक रुप से रहा । जहॉ काग्रेस मे इसके नेता केशव देव मालवीय थे वही प्रजा सोशलिस्ट पार्टी मे डा0 लोहिया व उनके समर्थक प्रमुख थे ।[42]

इसके बाद प्रजा समाजवादी पार्टी मे दो धर्म सकट सामने आये । आन्ध प्रदेश के 'स्थापना की घोषणा'[43] के बाद वहॉ सयुक्त सरकार बनाने की दिशा मे प्रजा समाजवादी पार्टी ने आन्ध्र प्रदेश के स्थापना आन्दोलन के जनक टी0 प्रकाशम को नये राज्य मे सयुक्त सरकार की स्थापना की दिशा मे उचित कदम उठाने का अधिकार सितम्बर 1953 मे सौप दिया लेकिन काग्रेस द्वारा टी0 प्रकाशम का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए यह शर्त रखी गयी कि वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से वे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर ले ।25 सितम्बर, 1953 को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को छोडकर वे काग्रेस के सदस्य बन गये ।[44] प्रजा समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी ने टी0 प्रकाशम के इस आचरण को नैतिकताहीन बताकर इसकी कटु आलोचना की ।

प्रजा समाजवादी पार्टी का दूसरा धर्मसकट त्रावनकोर-कोचीन मे उपस्थित हुआ। पहले आमचुनाव मे काग्रेस को विधान सभा मे क्षीण बहुमत प्राप्त हुआ। जिसके फलस्वरुप वहॉं सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जो अस्वीकृत हो गया । जिसके बाद मुख्यमत्री ने विधान सभा को भंग कर नये चुनाव कराने की माग की । फलस्वरुप 1954 मे वहॉ चुनाव हुए

---

42 - बेतुल सम्मेलन मे प्रजा समाजवादी पार्टी की नीति निश्चित करने के लिए नीति आयोग स्थापित किया गया, जिसमे अशोक मेहता और डा0 राम मनोहर लोहिया को सेक्रेटरी बनाया गया ।

43 - 25 मार्च, 1953 को प0 जवाहर लाल नेहरु ने यह घोषण की थी ।

44 - टी0 प्रकाशम ने 25 सितम्बर 1953 को अपने अनुयायियो के साथ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी छोड़कर "प्रजा पार्टी" की स्थापना की ।

जिसमे किसी दल को पूर्ण बहुमत नही मिला । अत प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने गैर कम्युनिस्ट दलों से सहयोग कर सरकार बनाया । पट्टमथानु पिल्लई सरकार के मुखिया बने । परन्तु सरकार बनने के कुछ समय के भीतर अगस्त 1954 मे वहॉ गोलीकाण्ड हो गया । इस पर डा0 लोहिया ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से पिल्लई को तयागपत्र देने का आदेश दिया, जिसे मानने से पिल्लई ने इन्कार कर दिया, इस पर डा0 लोहिया ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया ।और जे0 पी0 तथा अशोक मेहता के विरुद्ध काग्रेस से साठ-गाठ करने का आरोप लगाया । प्रजा समाजवादी पार्टी के इस आन्तरिक संकट पर विचार करने के लिए एक विशेष अधिवेशन नागपुर मे आचार्य जे0 पी0 कृपलीन की अध्यक्षता मे आहुत की गयी । इसमे 303 सदस्यो मे से 217 डा0 लोहिया के पक्ष मे थे । अत· पार्टी विभाजन के कगार पर आकर खडी हुई । आचार्य कृपलानी व जयप्रकाश नारायण दोनो ने ही ऐसी राजनीतिक घटना के लिए जिसके लिए मुख्यमत्री प्रत्यक्ष रुप से उत्तर दायी न हो, उसकी निन्दा करना अनुचित माना और विवाद बढने पर आचार्य कृपलानी ने अधिवेशन के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया । जिससे प्रजा समाजवादी पार्टी कुछ समय तक बिना नेता के नेतृत्व के ही रही ।[45] परन्तु आचार्य नरेन्द्र देव ने कुछ समय बाद नेतृत्व का कार्यभार स्वय संभाल लिया ।

4. प्रजा समाजवादी पार्टी का विभाजन

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1955 मे अबाडी नामक स्थान पर हुआ । इसमे कांग्रेस ने समाजवादी ढांचे की सामाजिक व्यवस्थ की स्थापना करना अपना लक्ष्य घोषित कर दिया । काग्रेस के इस प्रस्ताव के बाद प्रजा समाजवादी पार्टी मे काग्रेस से सहयोग करने के प्रश्न पर विवाद तेजी से उभरा । मधु लिमयेन कांग्रेस के नये प्रस्ताव की कटु आलोचना करते हुए उसे मतदाताओ को धोखा देने का प्रयास बतलाया । दूसरी ओर बम्बई की प्रजा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अशोक मेहता और नौ अन्य सदस्यो ने अध्यक्ष से काग्रेस से सहयोग करने के प्रश्न पर पुनर्विचार शुरु कराने की मांग की। मधु लिमये ने यह आरोप लगाया कि अशोक मेहता और उनके सहयोगी काग्रेस के आबाड़ी प्रस्ताव का स्वागत करना चाहते हैं । और वे काग्रेस से सहयोग करने के लिए आतुर हैं । प्रजा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेन्द्र देव ने मधुलिमये से

---

45 - प्रजा समाजवादी पार्टी के प्रमुख पत्र "जनता" ने उस स्थिति की आलोचना करते हुए लिखा था कि कुछ समय तक प्रजा समाजवादी पार्टी का जहाज बिना कप्तान, बिना नेता के रह गया, और साधारण कार्यकर्ता अपने आपको अनाथ अनुभव करने लगे थे ।

कहा कि वे अपने आरोपो के लिए अशोक मेहता से मॉफी मागे । उन्होने कहा कि पार्टी के प्रत्येक सदस्य को अपनी बात कहने की पूरी स्वतन्त्रता है, लेकिन मेरे मत से किसी भी स्वाभिमानी राजनीतिक दल को बिना मागे काग्रेस से सहयोग करने की बात चलाना, सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार की बातचीत पार्टी के प्रति विश्वासघास है । इससे अनेक प्रकार की शकाए उत्पन्न होती है ।

मधु लिमये ने आचार्य नरेन्द्र देव की बात नही मानी फिर भी उन्होने बम्बई की पार्टी को उनके विरुद्ध कार्यवाही न करने की सलाह दी । परन्तु बम्बई प्रजा समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी ने मधु लिमये के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित कर दिया और बाद मे उन्हे व उनके 21 सहयोगियो को पार्टी से निल्मबित कर दिया ।[46] आचार्य नरेन्द्र देव इस निलम्बन को रद्द कराना चाहते थे, तथा डा0 लोहिया ने तो इस निम्बन के विरोध मे आलोक मेहता एवं बम्बई कार्यकारिणी की निन्दा भी की । उधर उ0 प्र0 मे डा0 लोहिया का समर्थन अधिक था, अत प्रदेश पार्टी अधिवेशन मे उन्होने मधु लिमये को आमान्त्रित किया, जिसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अपना अपमान माना और कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से आचार्य नरेन्द्र देव ने गाजीपुर अधिवेशन पर[47] रोक लगा दिया।लेकिन इसके बावजूद सम्मेलन सम्पन्न हुआ जिसमे डा0 लोहिया के निर्देश से केन्द्रीय नेतृत्व की निन्दा की गयी । इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने 3 जून 1955 को उ0 प्र0 प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष गोपाल नारायण सक्सेना को निलम्बित करके उ0 प्र0 प्रजा समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी के स्थान पर तदर्थ नियुक्ति कर दी । डा0 लोहिया को भी निलम्बित कर दिया गया ।

प्रजा समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति ने 15-22 जुलाई 1955 तक जयपुर मे पार्टी के प्रान्तीय अध्यक्षो, सचिवो, का शिविर आयोजित किया। जिसमे डा0 लोहिया ने हिस्सा नही लिया । राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा डा0 लोहिया के निलम्बन की पुष्टि के बाद उनके समर्थको ने सामूहिक रुप से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से इस्तिफा दे दिया ।

दिसम्बर 1955 में डा0 राममनोहर लोहिया ने समाजवादी पार्टी का गठन किया और वे स्वय उसके अध्यक्ष बने । और इसके बाद प्रजा समाजवादी पार्टी का पूर्ण रुप से विभाजन हो गया। आन्ध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश मे अधिकाश सदस्य प्रजा समाजवादी पार्टी मे मे बने रहे, लेकिन तरुण कार्याकर्ता डा0 लोहिया के प्रभाव मे अधिक थे ।

---

46 - 26 मार्च 1955 को बम्बई प्रजा समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी ने मधु लिमये के निलम्बन की पुष्टि की ।

47 - 23 मार्च 1955 को प्रजा समाजवादी पार्टी का गाजीपुर मे अधिवेशन सम्पन्न होना था।

डा0 लोहिया समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय सत्ता मे आने के लिए सात वर्ष की अवधि निश्चित की थी। लेकिन 1957 के आम चुनाव मे लोक सभा मे समाजवादी पार्टी के 7 सदस्य चुने गये थे, तथा 1962 के आम चुनाव मे उसे 6 स्थानो पर ही सफलता मिली। 1957 मे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के 19 सदस्य लोक सभा मे पहुॅचे थे तथा 1962 मे उनकी सदस्य सख्या 12 तक पहुॅच गयी। इस प्रकार दोनो ही समाजवादी पार्टियॉ आम चुनावो मे बुरी तरह विफल रही तथा मतदाताओ को अपनी ओर आकर्षित करने मे भी सफल नही हुए। विधान सभाओ मे भी उनके सदस्यो का हाल करीब-करीब यही रहा। इस प्रकार 1962 तक डा0 राम मनोहर लोहिया और उनकी समाजवादी पार्टी सत्ता से उतनी ही दूर थी जितनी अपने जन्म काल के समय थी। 1963 मे समाजवादी पार्टी का सम्मेलन कलकत्ता मे हुआ,जिसमे डा0 लोहिया ने व्यवहारिक राजनीति अपनाने का नारा दिया। और जन सघर्षो तथा चुनावो मे विपक्षी दलो को एकजुट करने का प्रस्ताव किया। कम्युनिस्टो के तिरस्कार की नीति छोड़ दी गयी। इसी नीति के कारण डा0 लोहिया ने समाजवादियो की एकता का नारा दिया और विपक्षी दलो की एकता के लिए गैर-काग्रेसवाद का नारा लगाया।

1964 मे डा0 लोहिया ने समाजवादी पार्टी और प्रजा समाजवादी पार्टी के विलय का सुझाव रखा था लेकिन विफल हो गया। बाद मे जब अशोक मेहता अपने सहयोगियो के साथ काग्रेस मे शामिल हो गये तो बनारस मे प्रजा समाजवादी पार्टी और समजावादी पार्टी के विलय के लिए विशेष सम्मेलन किया गया और उसके बाद संयुक्त समाजवादी पार्टी का उदय हुआ और एस0 एम0 जोशी को उसका अध्यक्ष तथा राजानारायण को सचिव बनाया गया। लेकिन कुछ समय बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी फिर से अलग हो गयी।[48] जार्ज फर्नांडिस व मधु लिमये समाजवादी पार्टी को सैद्धान्तिक आधार देना चाहते थे। उन लोगो राजनारायण को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद चरण चौधरी द्वारा सगठित भारतीय क्रान्ति दल मे शामिल होने का निश्चय किया।

प्रजा समाजवादी पार्टी के गया अधिवेशन[49] के दो महीने के भीतर आचार्य नरेन्द्र देव के निधन (1956) से समाजवादी आन्दोलन ने मुख्य विचारक और सिद्धात वेत्ता खो दिया। गया

48 - 12 अक्टूबर 1967 को डा0 लोहिया का निधन हो गया। इसके बाद पार्टी मे पुन फूट पडी।

49 - दिसम्बर 1955 मे प्रजा समावादी पार्टी का अधिवेशन गया मे आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता मे हुआ, जिसमे पार्टी के लिए लोकतान्त्रिक समावाद के सैद्धान्तिक पक्ष पर "गया थीसिस" स्वीकार की गयी।

अधिसवेशन मे जो सिद्धांत पत्र स्वीकार किया गया था ।उसके अनुसार प्रजा समजावादी पार्टी को काग्रेस का शिष्ट और शालीन विरोध करने का मार्गदर्शन दिया था । विरोध के लिए विरोध और विपक्षी दलो के तालमेल की नीति को अस्वीकार कर दिया गया था । पार्टी के लिए राष्ट्रीयता, लोकतन्त्र और सामाजिक परिवर्तन की प्रतिबद्धता को आवश्यक माना गया था ।

आचार्य नरेन्द्र देव के निधन के बाद आचार्य जे0 बी0 कृपलानी प्रजा समजावादी पार्टी के अध्यक्ष बने और अशोक मेहता जनरल सेक्रेटरी बने ये दोनो नेता आचार्य नरेन्द्र देव द्वारा प्रतिपादित सिद्धात के विरुद्ध थे । आचार्य नरेन्द्र देव ने समाजवादी आन्दोलन के लिए वर्ग-सघर्ष और सत्याग्रह को अपरिहार्य मानते थे, लेकिन आचार्य जे0 बी0 कृपलानी वर्ग-सघर्ष के परम विरोधी थे, और उन्होने वर्ग-सघर्ष के विरुद्ध एक पुस्तिका प्रकाशित की, इसके साथ ही "गया थीसिस" को एक किनारे रख दिया गया । मधु दण्डवते ने अपनी पुस्तिका "एवोलूशन आफ दि सोशलिस्ट पालिटिक्स एण्ड पर्सपेक्टिव" मे लिखा है कि प्रजा समाजवादी पार्टी ने "गया थीसिस" का उल्लघन करने मे ही अपना कर्त्तव्य पालन समझा ।1957 के आम चुनाव के पूर्व दिस0 1956 मे प्रजा समाजवादी पार्टी का अधिवेश बगलौर मे हुआ और उसमे प्रजा समजावादी पार्टी ने चुनाव मे ताल-मेल की नीति अपनायी जिसको "गया थीसिस" मे अस्वीकार कर दिया गया था ।

प्रजा समाजवादी पार्टी के बगलौर अधिवेशन मे पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र स्वीकार किया गया । उसमे शासन और सत्तारुढ़ दल के अधिनायकवादी प्रवृत्तियो की आलोचना करते हुए कहा गया था कि सत्तारुढ काग्रेस अपनी पार्टी के हितो को बढावा देने के लिए सरकारी तन्त्र का उपयोग करती है और उसमे सत्ता का केन्द्रीकरण इतना बढ गया कि हर मामले मे ऊपर से आदेश दिये जाते है और स्वशासन का आधार क्षेत्र विस्तृत होने के स्थान पर सकुचित होता जा रहा है । प्रशासन मे आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है, भूमि सीमा निर्धारण और भूमि के पुनर्वितरण पर जोर दिया गया ।किसानो को लाभन्वित करने के लिए सहकारी विपणन, ऋण और विकास समितियो को गठित करने का सुझाव दिया गया था । मजदूरो के अधिकारो की रक्षा करने के लिए ट्रेड यूनियन अधिकारो का समर्थन किया गया ।

प्रजा समाजवादी पार्टी ने बैको, खनिज उद्योग और बागानो के राष्ट्रीयकरण की माग की। विदेशो से थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण का भी सुझाव दिया गया । शासन के आर्थिक और वाणिज्यिक कार्यकलापो के लिए आर्थिक सेवा संगठित करने का भी सुझाव दिया गया था ।कर

व्यवस्था मे सुधार और बड़े उद्योगो तथा उद्योग घरानो पर पूँजीगत लाभ के लिए कर अधिक लगाने का सुझाव भी दिया गया । प्रिवीपर्स[50] को समाप्त करने पर भी जोर दिया गया था ।विदेश नीति के सबध मे पाकिस्तान से सम्बन्धो को सुधारने की सलाह सरकार को दी गयी थी ।

प्रजा समाजवादी पार्टी ने गोवा की समस्या को सुलझाने पर जोर दिया था । हगरी के आन्तरिक विद्रोह का सोवियत सघ द्वारा दमन की नीति की निन्दा करते हुए रुस के सन्दर्भ मे भारत द्वारा अपनायी गयी नीति की भी आलोचना की गयी ।1957 के आम चुनाव के पूर्व जय प्रकाश नारायण ने प्रजा समजावादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की एकता का प्रयास किया जो सफल नही हुआ । इसी बीच 1957 मे संयुक्त महाराष्ट्र समिति का आन्दोलन हुआ उसमे प्रजा समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, पीजेन्ट एण्ड वर्कर्स पार्टी तथा अन्य वामपथी लोग शामिल थे। समाजवादी पार्टी ने मई 1957 मे सविनय अवज्ञा आन्दोलन और हिन्दी आन्दोलन चलाया था।

20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया । 22 अक्टूबर को प्रधानमत्री प0 जवाहर लाल नेहरु ने राष्ट्र के नाम सदेश प्रसारित किया । 26 अक्टूबर को देश मे सकट कालीन स्थिति की घोषणा कर दी गयी और राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना की गयी । 31 अक्टूबर को तत्कालीन रक्षा मत्री बी0 के0 कष्णा मेनन रक्षा विभाग के मत्री पद से हट गये और प0 नेहरु रक्षा विभाग भी अपने पास रख लिये । प्रजा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के नाते अशोक मेहता ने प0 नेहरु की भारत-चीन मैत्री की नीति की भी आलोचना की ।

1963 मे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का अधिवेशन भोपाल मे हुआ । उसमे चुनाव मे दूसरी पार्टियो से तालमेल की नीति को छोड़ा गया और पार्टी को समाजवादी पार्टी के रुप मे गठित करने, कम्युनिस्ट पार्टी, साम्प्रदायिक दलो और दूसरी प्रतिक्रियावादी दलो से किसी प्रकार का सबध न रखने का निश्चय किया गया । एस0 एम0 जोशी को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया थ।[51] दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का 1963 का अधिवशेन कलकत्ता मे हुआ । जिसमे "सात वर्ष मे सत्ता" का नारा उस अधिवेशन मे छोड दिया गया और व्यवहारिक राजनीति के नाम चुनाव और सघर्ष मे विपक्षी दलो से एकता करने की रणनीति अपनायी गयी ।[52]

---

50 - प्रिवी पर्स- "भारतीय नरेशो के भत्ते।

51 - भोपाल अधिवेशन मे काग्रेस का विरोध बढ़ा और प0 जवाहर लाल नेहरु से रक्षा के मामले मे विफलता के लिए त्याग पत्र की माग की गयी ।

52 - इस नीति के अन्तर्गत जहा एक ओर प्रजा समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के विलय के चर्चा की गयी और दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य दलो से मेल जोल बढ़ाने की शुरुआत की गयी ।

भोपाल अधिवेशन के दो महीने के भीतर प्रजा समाजवादी पार्टी मे अशोक मेहता द्वारा पार्टी मे रहते हुए योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनने के कारण विवाद उठ खडा हुआ । प्रजा समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अशोक मेहता के आचरण की कटु आलोचना की और उनके काग्रेस से ताल-मेल के प्रयास को पार्टी विरोधी कार्यवाही माना। अशोक मेहता द्वारा त्याग पत्र न देने पर उन्हे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, इस पर अशोक मेहता प्रजा समाजवादी पार्टी छोडकर काग्रेस में चले गये ।

अशोक मेहता और उनके साथियो के काग्रेस मे शामिल होने के बाद डा0 राम मनोहर लोहिया ने बिना शर्त दोनो समाजवादी पार्टियो के विलय का प्रस्ताव रखा । कुछ कठिनाइयो के बाद दोनो पार्टियो का वाराणसी के विशेष अधिवेशन मे विलय कर सयुक्त समाजवादी पार्टीके गठन का निश्चय किया गया ।[53] इसके अक्ष्यक्ष एस0 एम0 जोशी बनाये गये । सयुक्त समाजवादी पार्टी (ससोपा) ने लोकतान्त्रिक और शान्तिमय उपायो से समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य स्वीकार किया, जिसमे मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण और एक देश द्वारा दूसरे देश के शोषण को समाप्त करने की नीति घोषित की गयी । यह भी कहा गया कि ससोपा शान्तिपूर्ण ढग से क्रान्तिकारी,वर्ग-सघर्ष और जनसघर्षो को आयोजित करके सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाये। ससदीय तरीको को अपनाकर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा । पूँजीवादी,सामन्तवादी शोषण और अन्याय को मिटाने के लिए ससोपा निरतर प्रयास करेगी ।

लेकिन वाराणसी अधिवेशन मे डा0 राम मनोहर लोहिया के अनुयायियो की हठवादिता के कारण प्रजा समाजवादियो का मोह भग हुआ, प्रजा समाजवादी पार्टी के 800 प्रतिनिधियो मे से 650 ने सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया और कुछ समय के भीतर प्रजा समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मे स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रखने का निश्चय 31 जनवरी 1965 को किया गया । इस बात को बडी स्पष्टता के साथ कहा गया कि प्रजा समाजवादी पार्टी और सयुक्त समाजवादी पार्टी दो स्वतन्त्र पार्टियॉ है, जिनमे कार्य पद्धति और आचरण मे गभीर मतभेद है ।ऐसी स्थिति मे दोनों पार्टियो को अलग रहकर अच्छे पडोसी की भॉति सद्भावना और सहयोग विकसित करने का प्रयास करना चाहिए ।

---

[53] - 31 जनवरी ,1965 को सयुक्त समजावादी पार्टी (ससोपा) का गठन हुआ ।

5-समाजवादी आन्दोलन (1964 -1974 ई0) तक

1964 से 1974 तक का दशक भारत मे समाजवादी आन्दोलन घटना प्रधान रहा है। इसके पूर्व लोक सभा के उपचुनाव[54] मे डा0 राम मनोहर लोहिया फर्रुखाबाद से और आचार्य जे0 बी0 कृपलानी अमरोहा से चुने गये। लोक सभा मे पहुँचने के बाद डा0 लोहिया ने प0 जवाहर लाल नेहरु एवं साधारण किसान के दैनिक व्यय के अन्तर को उठाते हुए कहा कि जहॉ प्रधान मत्री पर प्रतिदिन 25 हजार रुपये व्यय होते है, वहॉ गरीब किसान तीन आने व्यय करता है।आय के अन्तर का प्रश्न उठाते हुए उन्होने कहा कि देश से गरीबी मिटाना चाहिए। डा0 लोहिया ने "मूल्य बॉधो" और "गरीबी हटाओ" के नारे दिये। उन्होने दूसरे राजनीतिक दलो को प्रभावित करने की नीति अपनायी। अशोक मेहता, गेदा सिह, चन्द्रशेखर, नारायण दत्त तिवारी आदि प्रजा सोशलिस्ट नेताओ के कांग्रेस मे जाने के बाद डा0 राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के विलय की बात चलायी। जनवरी 1965 मे प्रजा समाजवादी पार्टी के वाराणसी के विशेष अधिवेशन मे डा0 लोहिया विशेष रुप से राजनारायण के साथियो की हठवादिता से सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। फिर भी उस सम्मेलन के कथित निश्चय के आधार पर सयुक्त समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। लेकिन प्रजा समाजवादी पार्टी को उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निश्चय के अनुसार पुनर्जीवित किया गया और नारायण गणेश गोरे (एन0 जी0 गोरे) को अध्यक्ष बनाया गया तथा प्रेम भसीन को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया।

सन् 1967 के आम चुनाव के पूर्व डा0 लोहिया ने नया नारा दिया "काग्रेस को हटाओ और देश को बचाओ"। काग्रेस को 1967 के आम चुनाव मे तो बहुत मिल गया लेकिन आठ राज्यो मे उसका बहुमत समाप्त हो गया। काग्रेस से इस्तीफा देने और विपक्ष मे जाने वाले काग्रेसी नेताओ को ही संयुक्त विधायक दलो का नेता चुना गया और सयुक्त विधायक दलो का विघटन होने मे करीब-करीब एक-डेढ वर्ष का समय लग गया।

1967 के आम चुनाव के सम्बन्ध मे जारी घोषणा-पत्र[55] मे (ससोपा के) कहा गया कि राज्यो मे गैर-कांग्रेसी सरकारो की स्थापना का प्रयास किया जाय। केन्द्र और राज्य सबधो को फिर से परिभाषित करने का भी सुझाव दिया गया। भू-राजस्व (लगान) को समाप्त कर उसके स्थान पर कृषि आयकर लगाने, सात वर्षीय सिंचाई योजना कार्यान्वित करने और राज्य

---

54 - 1963 के लोकसभा के उप चुनाव मे।

55 - 1967 के आम चुनाव के सबंध मे 29 नवम्बर 1966 को जारी ससोपा का घोषणा पत्र।

सरकारो द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का सुझाव दिया गया जिसमे औसत उत्पादन न होता हो ।व्यक्तिगत आय को 1500 रुपये मासिक तक सीमित करने पर जोर दिया गया था । और यह सुझाव दिया गया था कि इससे आय को 25 से 30 वर्ष तक की अवधि के लिए जबरन जमा कराने की व्यवस्था की जाये । वैदेशिक नीति के सम्बन्ध मे अमेरिका और सोवियत सघ किसी भी गुट के साथ विशेष सम्बन्ध न रखने पर विशेष जोर दिया गया था ।इसके साथ ही भारत की प्राकृतिक सीमाओ को पुन स्थापित करने का भी सुझाव घोषणा पत्र मे दिया गया था।भारत-पाकिस्तान महासंघ बनाने, तिब्बत की स्वतन्त्रता, पश्चिम जर्मनी, इजराइल तथा ताइवान को मान्यता देने की चर्चा की गयी थी ।

घोषणा पत्र मे ससदीय लोकतन्त्र के माध्यम से ही लोकतान्त्रिक समाजवाद की स्थापना पर बल दिया गया । साथ ही समाजवाद के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए ससद और विधान मण्डलो के बाहर वर्ग-सघर्ष के आधार पर किसानो, मजदूरो, और दूसरे जन आन्दोलनो का भी सचालन किया जाना चाहिए ।

सयुक्त समाजवादी पार्टी ने भूमि सुधारो, भूमि सेना के गठन, बजर भूमि पर खेती के लिए सरकारी प्रयास, सहकारी खेती और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभाव को धीरे-धीरे बढाये जाने पर जोर दिया गया था ।सामान्य उपभोक्ता वस्तुओ का बडे पैमाने का उत्पादन करके मूल्यो को स्थिर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए ।पार्टी ने आगे यह स्पष्ट कर दिया कि उत्पादन के सभी साधनो के राष्ट्रीयकरण की वह समर्थक नही है । तथा निजी क्षेत्र के उद्योगो और व्यापार के क्षेत्र स्पष्ट रखे जाने चाहिए । इस बात पर भी जोर दिया गया कि समाजवाद का यह अर्थ नही है कि व्यक्ति को पहल करने की और उद्यम आरम्भ करने की भावना को ही कुठित कर दिया जाय।करो के निर्धारण के बाद अथवा अन्तर एक और दस गुने से अधिक नही होना चाहिए ।

1967 के आम चुनाव तक काग्रेस ने समाजवादी सिद्धातो को काफी दूर तक स्वीकार कर लिया था ।यही कारण है कि प्रजा समाजवादी पार्टी के लोगो मे काग्रेस के प्रति शत्रुता की भावना नहीं थी लेकिन डा0 राम मनोहर लोहिया और सयुक्त समाजवादी पार्टी ने तो "काग्रेस हटाओ और देश बचाओ" का नारा लगाकर उसको ही लोकतन्त्र और समाजवाद का शत्रु घोषित कर दिया था ।

ससोपा के पटना अधिवेशन[56] मे पार्टी के अन्दर उमडे मतभेद को बडी मुश्किल से नियत्रित किया गया और पार्टी की एकता बचायी जा सकी ।जार्ज फर्नाडिस एव राजनारायण के गुटो के बीच मतभेद उग्ररुप मे प्रकट हुए । पटना के बाद उ0 प्र0 मे जब राजनाराण ने ससोपा का प्रादेशिक सम्मेलन करने का प्रयास किया तो जार्ज फर्नाडिस ने उस पर रोक लगा दी । साथ ही उन्होने राजनारायण गुट को दण्डित करने का प्रयास किया ।इस पृष्ठ भूमि मे ससोपा और प्रजा समाजवादी पार्टी दोनो के विलय की बातचीत शुरु की गयी । ससोपा के सोनपुर अधिवेशन[57] मे दोनो पार्टियो के विलय के सुझाव का समर्थन किया गया, लेकिन इस बातचीत को आगे नही बढाया जा सका । दोनो पार्टियो मे इस बात पर मतभेद था कि काग्रेस के प्रति क्या रवैया रखा जाय । ससोपा काग्रेस को अपना पहला शत्रु मानती थी । और प्रजा समाजवादी पार्टी के नेता एन0 जी0 गोरे का विचार था कि काग्रेस मे जो समाजवादी लोग है उनसे मेल किया जा सकता है।

सन् 1967 और 1969 के बीच उ0 प्र0, बिहार, मध्यप्रदेश, हरियाणा, मैसूर, पाण्डिचेरा और मणिपुर मे सयुक्त विधायक दलो की सरकारे स्थापित हुई। पश्चिम बगाल मे अजय मुखर्जी के नेतृत्व मे सयुक्त मोर्चे की सरकार स्थापित हुई थी । लेकिन दो वर्ष के भीतर दल बदलुओ और पारस्परिक मतभेदो के कारण सयुक्त विधायक दलो की सरकारे गिर गयी ।

1969 मे उत्तर प्रदेश, बिहार, पजाब, पंश्चिम बगाल और नागालैण्ड विधान सभाओ के मध्यावधि चुनाव कराये गये जिनमें संयुक्त विधायक दल मे शामिल अधिकाश पार्टियो की स्थिति पहले से कमजोर हो गयी । प्रजा समाजवादी पार्टी और ससोपा दोनो को अधिक क्षति हुई। उत्तर प्रदेश विधान, सभा मे 1967 के चुनाव मे 11 विधायक थे, 1969 के मध्यावधि चुनाव मे केवल तीन प्रजा समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गये । 1967 के चुनाव मे मैसूर मे प्रजा समाजवादी पार्टी के 20 विधायक थे । इसी प्रकार 1971 के चुनाव मे उडीसा विधान सभा मे प्रजा समाजवादी पार्टी विधायकों की संख्या 21 से घटकर 4 रह गयी । ससोपा के अनेक विधायक उत्तर प्रदेश और बिहार मे कांग्रेस मे चले गये । इसी प्रकार मैसूर मे प्रजा समाजवादी पार्टी विधायक काग्रेस मे चले गये । इस पृष्ठ भूमि मे प्रजा समाजवादी पार्टी और ससोपा के विलय का प्रयास फिर से शुरु किया गया ।

---

56 - अप्रैल 1967 मे ससोपा का पटना मे अधिवेशन सम्पन्न हुआ ।

57 - ससोपा का सोनपुर अधिवेशन 1968 मे ।

प्रजा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एन0 जी0 गोरे ने देश मे नये ध्रवीकरण की सभावनाओ की ओर सकेत करते हुए कहा कि काग्रेस का विभाजन होने पर नये ध्रवीकरण की प्रक्रिया तेज होगी। वे लोकतान्त्रिक समाजवादी शक्तियो की एकता पर जोर देते थे।1967 के बाद पश्चिम बगाल और केरल के वामपथी मोर्चे मे शामिल सी0 पी0 आई0 और सी0 पी0 आई0 एम0 के नीतियो की आलोचना करते हुए एन0 जी0 गोरे का कहना था कि इन मोर्चो और श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीतियो मे बहुत कम अन्तर है। उनका यह भी कहना था कि श्री मोरार जी देसाई और श्रीमती गॉधी के बीच विचारो की समानता नही के बराबर है। इसी आधार मे श्री एन0 जी0 गोरे ने समाजवादी विशेष रुप से "लोकतन्त्र और समाजवाद" मे विश्वास करने वाले लोगो की एकता पर जोर दिया था।

अगस्त 1969 मे जब बगलौर मे काग्रेस कार्य समिति ने काग्रेस मे एकता रखने और विभाजन को रोकने के प्रयास मे एक प्रस्ताव पास किया, तो श्री एन0 जी0 गोरे को बडी निराशा हुई। उन्होने ने एक वक्तत्य मे कहा कि यह तो घटनाक्रम का नतीजा है।1969 के सितम्बर महीने मे प्रजा समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रेम भसीन ने गैर-काग्रेसी लोकतान्त्रिक दलो की एकता पर जोर दिया। इस प्रकार के प्रयास मे उन्होने प्रजा समाजवादी पार्टी, ससोपा, बिहार के लोकतान्त्रिक दल, बगाल काग्रेस, फारवर्ड ब्लाक, महाराष्ट्र की पीजेन्ट्स वर्कर्स पार्टी को शामिल करने का सुझाव दिया।

प्रजा समाजवादी पार्टी कांग्रेस को पूरी तरह समाजवादी पार्टी नही मानती थी, लेकिन उसका यह विचार था कि भातरीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), नक्सलवादी आदि, अति उग्रवादी तत्वो द्वारा उत्पन्न सकटो का सामना करने के लिए काग्रेस और अन्य लोकतान्त्रिक प्रगतिशील तत्वो का सहयोग आवश्यक है।1967 और 1969 के बीच जो सयुक्त विधायक दल बने थे, उनमे परस्पर विरोधी राजनीतिक विचारो का गठबन्धन हुआ था। उससे भी प्रजा समाजवादी नेतागण दु खी थे। उन गठबन्धो मे प्रजा समाजवादी और समाजवादी तत्वो का प्रभाव भी नगण्य था।

1969 मे कांग्रेस के विभाजन के बाद सत्तारुढ़ कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गॉधी के सामने यह सुझाव रखे कि अगले चुनाव में उन्हे कम्युनिस्ट पार्टी अथवा प्रजा समाजवादी पार्टी से ताल-मेल करना चाहिए। उन दिनो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री पाद अमृत डागे

थे । जो श्रीमती इन्दिरा गॉधी की नीतियो के समर्थक थे ।श्रीमती गॉधी ने 1971 मे लोक सभा मध्यावधि चुनाव कराने का निश्चय किया । उस समय उन्होने जनता से काग्रेस को सत्ता सौपने की अपील की । उस चुनाव मे उन्होने कुछ स्थानो पर कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारो के विरुद्ध अपने उम्मीदवार नही खडे किये ।

1971 के लोक सभा के मध्यावधि चुनाव मे प्रजा समाजवादी पार्टी और ससोपा दोनो की शक्ति पहले से भी क्षीण हो गयी ।1969 मे प्रजा समाजवादी पार्टी को यह आशा थी कि काग्रेस के विभाजन के बाद नये ध्रवीकरण के द्वारा समाजवादी शक्तियो की एकता बढेगी और उसका प्रभाव बढेगा । यह दोनो ही बात भ्रातिया ही सिद्ध हुई ।

अगस्त 1971 मे प्रजा समाजवादी पार्टी और ससोपा का विलय करके फिर से समाजवादी पार्टी का गठन नये सिरे से किया गया इसके पूर्व 1971 मे लोक सभा के चुनाव के समय काग्रेस के विरुद्ध "ग्राण्ड एलायन्स" (महान गठजोड) स्थापित किया गया था ।उसमे जनसघ, सगठन काग्रेस,स्वतन्त्र पार्टी और ससोपा शामिल थी ।चुनाव मे इस बडे गठबन्धन को पराजय का मुॅह ही देखना पडा था ।उस समय तक प्रजा समाजवादी पार्टी की सहानुभूमि सत्तारुढ काग्रेस के साथ ही आधिक थी ।

नयी समाजवादी पार्टी के जन्म के समय से उसके सामने अनेक कठिनाइयॉ आयीं । उडीसा मे प्रजा समाजवादी नेता सुरेद्र द्विवेदी और बाके बिहारी दास काग्रेस को शत्रु नही मानते थे, और उन्होने उस नयी समाजवादी पार्टी मे शामिल हाने से इन्कार कर दिया ।गुजरात मे प्रजा समावादी पार्टी और ससोपा के अधिकाश सदस्य भी नयी पार्टी मे शामिल नही हुए । ये सभी लोग श्री राजनारायण की कार्यपद्धति और उदण्डता से रुष्ट थे तथा गैर-काग्रेसवाद के सिद्धात के भी विरोधी थे । पश्चिम बगाल के संयुक्त समाजवादी श्रीमती गॉधी का अन्धविरोध करने और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियो के विरुद्ध थे । अत पश्चिम बगाल के सयुक्त समाजवादियो ने एक विशेष अधिवेशन[58] करके काग्रेस मे शामिल होने का निश्चय किया ।

1971 के घटनाक्रम मे सबसे महत्वपूर्ण बाते, पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण, पाकिस्तान का विभाजन, और स्वतन्त्र बंगलादेश का जन्म, थी । इसके पूर्व भारत-सोवियत

---

[58] - अक्टूबर 1971 मे पश्चिम बगाल मे सयुक्त समाजवादियो का एक विशेष अधिवेशन ।

सहयोग और मैत्री-सन्धि अगस्त 1971 मे हो चुकी थी।[59] इन सब कारणो से 1971 के मध्यावधि चुनाव मे काग्रेस दो तिहाई (करीब 350 सीटे) जीती तथा बहुमत से भी अधिक मत प्राप्त कर लिया । परन्तु इनके विरोधयो के महान गठबन्धन को विफलता ही हाथ लगी ।समाजवादी पार्टी की भी स्थिति अच्छी नही रही । और उसके केवल तीन सदस्य ही लोक सभा मे पहुँच सके ।

राजनीतिक निराशा के वातावरण मे विभिन्न राजनीतिक दलो और गुटो ने अनेक प्रकार के आन्दोलन शुरु किये । 1973 मे जे0 पी0 अपनी पत्नी श्रीमती प्रभावती के निधन के बाद राजनीति से एक वर्ष के सन्यास पर थे । सर्वोदय आन्दोलन भी शीथिल पड गया था । और उसमे आचार्य विनोबा भावे तथा जे0 पी0 के अनुयायियो मे मतभेद उत्पन्न हो चुके थे ।

1973 मे गुजरात मे छात्रो और युवा वर्ग की नव निर्माण समिति ने मूल्य वृद्धि और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया । सगठन काग्रेस के नेता मोरार जी देसाई ने उस आन्दोलन के समर्थन और गुजरात विधान सभा को भग करके, विधान सभा के नये चुनाव कराने की माग के लिए अनशन शुरु किया । इस पर केन्द्र सरकार गुजरात विधान सभा भग करके नये चुनाव कराने की घोषणा की । गुजरात के छात्रो और युवा वर्ग के आन्दोलन का प्रभाव देश के अन्य भागो पर भी पडा, यद्यपि उनकी सफलता क्षणिक ही रही ।

1973 मे समाजवादी पार्टी का अधिवेशन बुलन्दशहर मे हुआ, जिसमे समाजवादी पार्टी को समाजवादी सिद्धान्तो और निष्ठा के अनुसार कार्य करने पर जोर दिया गया। जार्ज फर्नाडिस अखिल भारतीय रेलवे मेन्स फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गये । उन्होने द्वितीय समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीय संघ से सबध स्थापित किया ।

1973 मे उत्तर प्रेदश मे छात्र आन्दोलन की लहर चल पडी । उस वर्ष प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस के विद्रोह और लखनऊ विश्वविद्यालय मे हुए अग्निकाण्ड के समय तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमला पति त्रिपाठी ने अपने सरकार की अक्षमता के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया । वहॉ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और बाद मे हेमवती नंदन बहुगणा को उत्तर प्रेदश का मुख्यमन्त्री बताया गया ।[60]

---

59 - 9 अगस्त, 1971 को भारत-सोवियत सघ मैत्री एव सहयोग सन्धि को भारतीय गुट-निरपेक्षता पर एक गहरा प्रहार अनेक पाश्चात्य पत्र-पत्रिकाओ ने माना, और यह आरोप लगाया कि इस सन्धि के बाद भारत साम्यवादी गुट की ओर झुक गया है, अत अपनी गुट निरपेक्षता की नीति से दूर हो गया है ।

60 - इस परिवर्तन मे किसी प्रकार की कठिनाई नही पड़ी, क्योकि विधान मण्डल मे सत्तारुढ काग्रेस का बहुमत था ।

इन आन्दोलनो की सफलता को देखकर जय प्रकाश नारायण ने 1974 मे बिहार मे छात्र और युवा वर्ग के सहयोग से भ्रष्टाचार और महगाई के विरोध मे आन्दोलन चलाया। इस आन्दोलन को जन समर्थन मिलता गया और उसका प्रभाव बढता गया । जे0 पी0 ने यह भी नारा दिया कि वे भ्रष्ट विधायको के विरुद्ध सत्याग्रह चलायेगे और विधान सभा को काम नही करने देगे ।एक ओर वे उपचुनाव कराने का विरोध करते थे तथा दूसरी ओर विधान सभा भग कराने पर जो दे रहे थे । जे0 पी0 के नेतृत्व मे चलने वाले आन्दोलन मे आर0 एस0 एस0, जनसघ, भू-दान और सर्वोदय आन्दोलन के लोग तथा समाजवादी लोग भी थे । अपने आन्दोलन के प्रभाव को बढते देखकर जे0 पी0 ने सम्पूर्ण क्रान्ति का आह्वान किया ।यद्यपि उन्होने इस क्रान्ति को परिभाषित नही किया ।

1974 मे उ0 प्र0 के विधान सभा के चुनाव मे जे0 पी0 ने काग्रेस विरोधी शक्तियो का समर्थन किया, लेकिन उस चुनाव मे उ0 प्र0 विधान सभा मे काग्रेस का पूर्ण बहुमत हो गया और पुन हेमवती नदन बहगुणा को प्रदेश का मुख्य मत्री बनाया गया ।

1974 के अगस्त महीने मे श्री चरण सिह के नेतृत्व मे दिल्ली मे भारतीय लोकदल की स्थापना हुई । इसमे चरण सिह के नेतृत्व वाले भारतीय क्रान्ति दल (बी0 के0 डी0) के अतिरिक्त, स्वतन्त्र पार्टी, राजनारायण के नेतृत्व वाली संसोपा बीजू पटनायक का उत्कल काग्रेस, किसान मजदूर पार्टी, राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक दल और पजाब खेतिहर जमीदार सभा शामिल हुई ।

6-समाजवादी आन्दोलन-जन आन्दोलन (1974-1977 ई0)

1974 मे उत्तरप्रदेश, उडीसा, मणिपुर और पाण्डिचेरी विधान सभाओ के चुनाव कराये गये इसके बाद उ0 प्र0 मे हेमवती नदन बहगुणा, उड़ीसा मे श्रीमती नदिनी सतपथी काग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री बनाये गये । पाण्डिचेरी मे डी0 एम0 के0 रामास्वामी नायकर मुख्यमत्री बने । मणिपुर मे अलीमुद्दीन का मन्त्रिमण्डल बना, जिसने जुलाई मे त्याग पत्र दिया ।गुजरात विधन सभा 15 मार्च 1974 को भग कर दी गयी ।

श्री जय प्रकाश नारायण ने 15 मार्च 1974 को "सिटीजन्स फार डेमोक्रेसी"[61] की स्थापना की । बिहार में उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन को बढाते हुए उसने बिहार विधान सभा को भग करने की मांग की ।इस आन्दोलन का समर्थन करने के लिए सभी विपक्षी दलो का

---

61 - जे0 पी0-"लोकतान्त्रिक समाजवाद"

समर्थन या सहयोग मागा। पश्चिम बगाल मे नये चुनाव मे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पराजित हो जाने पर काग्रेस का बहुमत हो गया था ।और वहा सिद्धार्थ शकर राय मुख्यमत्री थे । सी0 पी0 आई0 एम0 के नेता ज्योति बसु ने जे0 पी0 से अपनी पार्टी के कार्यकताओ की रक्षा करने के लिए शरण मागी । उन्होने ने जे0 पी0 के आन्दोलन का समर्थन करना भी स्वीकार कर लिया ।

20 अगस्त 1974 को श्री फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति चुने गये और श्री वासप्पा दास जत्ती (बी0 डी0 जत्ती) उपराष्ट्रपति चुने गये ।

1974 मे ही देवकान्त बरुआ काग्रेस के अध्यक्ष बनाये गये । उसके पहले जगजीवन राम और शकर दयाल शर्मा को भी काग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था ।श्री बरुआ ने नरौरा मे काग्रेस जनो का शिविर चलाकर उनसे श्री जे0 पी0 द्वारा सचालित आन्दोलन का राजनीतिक आधार पर सामना करने का आह्वान किया। जे0 पी0 ने बिहार मे मोर्चे का नेतृत्व सभालकर आम हडताल की घोषणा कर दी । दिसम्बर 1974 मे श्रीमती सुचेता कृपलानी का निधन हो गया ।

1975 के दौरान देश का घटना क्रम तेजी से घूम रहा था । समस्तीपुर मे आयोजित समारोह[62] मे ललित नारायण मिश्र का निधन हो गया ।फरवरी 1975 मे शेख मो0 अब्दुल्ला को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया गया तथा महाराष्ट्र मे श्री वी0 पी0 नायिक की जगह एस0 बी0 चव्हाण को वहॉ का मुख्य मत्री बनाया गया ।

1975 के पूर्वार्द्ध[63] मे ही जे0 पी0 ससद के समक्ष प्रदर्शन किया और लोक सभा के अध्यक्ष को जन आन्दोलन की मागो के सबध मे ज्ञापन दिये । 18 मार्च को जे0 पी0 ने बिहार विधान सभा के सामने जनता का मोर्चा लगाया ।

जून 1975 मे राजनीतिक घटना क्रम ने झंझावत का रुप धारण कर लिया । इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री जगमोहन नाथ सिन्हा ने श्रीमति गॉधी के चुनाव के विरुद्ध श्री राजनारायण की याचिका को स्वीकार करके श्रीमती इन्दिरा गॉधी के 1971 के रायबरेली से लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर उनकी सदस्यता को भी अवैध घोषित कर दिया । श्री जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले को एक महीने तक लागू न करने का भी आदेश दिया जिससे उस फैसले पर उच्चतम न्यायालय मे अपील दायर की जा सके ।

---

62 - 2, जनवरी, 1975 को समस्तीपुर मे आयोजित समारोह मे बम बिस्फोट हुआ, जिसमे ललित नारायण मिश्र का निधन हो गया ।

63 - 12 जून, 1975

जून के आखिरी सप्ताह[64] मे उच्चतम-न्यायालय के अवकाश कालीन न्यायमूर्ति श्री वी0 के0 कृष्ण अय्यर ने श्री जगमोहर लाल सिन्हा के फैसले को उच्चतम-न्यायालय मे अपील की सुनवाई तक के लिए स्थगित रखने का आदेश दिया । उन्होने अपने आदेश मे कहा कि श्री जगमोहन सिन्हा ने जिस कानूनी आधार पर फैसला किया है वह सही है ।लेकिन ससद को इस कानून मे सशोधन करने का अधिकार है । यदि ससद कानून मे आवश्यक सशोधन कर दे तो श्रीमती गॉधी का चुनाव वैद्य माना जा सकता है । लेकिन जब तक अपील का फैसला न हो जाय श्रीमती गाँधी प्रधानमंत्री रह सकती हैं । लेकिन लोक सभा मे मतदान मे भाग नही ले सकती । बाद मे उच्चतम- न्यायालय ने चुनाव कानून मे हुए नये संशोधन के आधार पर श्रीमती गॉधी के चुनाव को अवैध धोषित करने वाले इलाहाबाद उच्चन्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया ।

लेकिन श्रीमती, इन्दिरा गॉधी के विरुद्ध इलाहाबाद उच्चन्यायालय के फैसले के बाद जे0 पी0 और विपक्षी दलो के नेताओ ने श्रीमती गॉधी के प्रधानमत्री पद से त्यागपत्र देने की माग के लिए 29 जून से देशव्यापी सत्याग्रह चलाने की घोषणा की । इससे पूर्व मे दिल्ली के रामलीला मैदान मे 24 जून को जे0 पी0 ने अपने भाषण मे कहा था कि श्रीमती गॉधी का प्रधानमत्री बने रहा अनैतिक है । उन्होने सेना और पुलिस बल तथा राज्य कर्मचारियो से सरकार के गैर कानूनी आदेशो का पालन न करने की अपील की । 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश मे आन्तरिक सकटकाल की घोषणा कर दी । 1971 मे पाकिस्तान के आक्रमण के बाद देश मे वाह्य सकटकाल की घोषणा लागू थी । 27 जून 1975 को श्रीमती गॉधी, जगजीवन राम, यशवन्त राव चव्हाण, एच0 आर0 गोखले, के0 ब्रह्मानन्द और ओम मेहता की सकट कालीन समिति बनायी गयी ।

सकटकालीन स्थिति लागू होते ही श्री जय प्रकाश नारायण और 600 विपक्षी नेताओ को गिरफ्तार कर लिया गया और समाचार पत्रो पर गिरफ्तारी अथवा आन्दोलन सबन्धी समाचारो के प्रकाशन पर रोग लगा दी गयी । विपक्षी दलों मे भारतीय लोक दल, सगठन काग्रेस, सर्वोदय और भूदान आन्दोलन के जय प्रकाश नारायण के प्रभाव वाले कार्यकर्ता, जनसघ, समाजवादी पार्टी और काग्रेस के भीतर श्रीमती गॉधी के आलोचक (श्री शेखर कपूर, चन्द्रशेखर, और मोहन धारिया) और अन्य आन्दोलन कारी नेताओ को गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिया गया था।इस

---

64 - 24 जून, 1975

समय ऐसा प्रतीत होता था कि देश विप्लव के ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है ।सकटकालीन स्थिति की घोषणा के बाद सरकार की ओर से आन्दोलन को समाप्त कर दिया गया था । देशभर मे करीब 30 हजार राजनीतिक कार्यकर्ताओ को गिरफ्तार किया गया ।

जुलाई माह मे प्रधान मत्री श्रीमती इन्दिरा गॉधी ने देश के आर्थिक विकास के लिए बीस-सूत्रीय[65] कार्य-क्रम की घोषणा की । सविधान मे 39वे सशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के विरुद्ध न्यायालयो मे विवाद उठाने पर रोक लागा दी गयी। चुनाव कानून मे भी आवश्यक संशोधन किया गया ।इसके फलस्वरुप उच्चतम न्यायालय मे श्रीमती गॉधी के चुनाव को अवैध घोषित किये जाने के विरुद्ध दायर अपील स्वीकार कर ली गयी।

अक्टूबर माह[66] मे आन्तरिक सुरक्षा कानून (मीसा) ससद ने पास किया । इसके आधार पर नजरबदी के विरुद्ध न्यायालयो मे विवाद उठाने पर रोक लगा दी गयी थी । इसी कानून के द्वारा तस्करो की सम्पत्ति जब्त करने का भी अधिकार सरकार को मिल गया था ।11 नवम्बर 1975 को जय प्रकाश नारायण को "पैरोल" पर रिहा कर दिया गया और 16 नवम्बर को उन्हे पुन नजरबन्द कर दिया गया । 4 दिसम्बर 1975 को उन्हे रिहा कर दिया गया । 8 दिसम्बर को सरकार की ओर से तीन नये अध्यादेश जारी किये गये, जो नागरिक अधिकारो पर कुठाराघात ही था ।

जनवरी, 1976[67] को बलिराम भगत लोकसभा के नये स्पीकर बनाये गये । 8 जनवरी को लोकसभा ने संविधान की धारा 19(8) के अन्तगर्त मिले अधिकारो को स्थगित करने का प्रस्ताव पास कर दिया । लोकसभा के उसी अधिवेशन मे लोकसभा की अवधि एक वर्ष के लिए बढा दी गयी ।

नवम्बर माह[68] मे ससद ने 42वॉ सविधान सशोधन विधेयक पास कर दिया ।उसके आधार पर भारतीय सविधान की प्रस्तावना मे यह उल्लेख किया गया कि "भारत समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र" है ।उस सशोधन मे नागरिको के मौलिक अधिकारो के साथ-साथ उनके कर्तव्यो का भी उल्लेख किया गया ।इधर काग्रेस मे सजय गॉधी और उनके

---

65 - पहली जुलाई, 1975

66 - 17 अक्टूबर, 1975

67 - 5 जनवरी, 1976 को बलिराम भगत को लोक सभा का स्पीकर चुना गया ।

68 - 2 नवम्बर, 1976 को 42वॉं सविधान सशोधन ससद ने पास कर दिया ।

अतरग साथियो का प्रभाव बढ़ने लगा, जिससे सकटकालीन स्थिति के आठ-दस महिनो मे अनुशासन और काम काज मे जो चुस्ती आयी थी, वह समाप्त हो चुकी थी और तानाशाही के दुर्गण प्रत्येक रुप मे दिखाई देने लगे थे, चाहे वह "नसबन्दी" अभियान हो या गन्दी बस्तियो की सफाई के नाम पर बस्तियो के तोड-फोड़ और सडको को चौडा करने की बात हो,सभी क्षेत्रो मे अधिनायकवादी दमन और क्रुरता का बोलबाला हो गया था, समाचार पत्रो पर नियत्रण और अकुश के कारण जन-भावनाओ की अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही थी।

दिसम्बर 1976 मे प्रधानमत्री श्रीमती इन्दिरा गॉधी ने लोकसभा के चुनाव कराने की जिस समय घोषणा की थी, उस समय जय प्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और चरण सिह जेलो से बाहर आ चुके थे, बहुत से राजनीतिक कार्यकर्ता भी नजरबन्दी काटकर अथवा "पैरोल" पर जेलो के बाहर आ चुके थे। कुछ समीक्षको का कहना है कि देश मे आर्थिक क्षेत्र मे प्रगति से प्रधान मत्री श्रीमती गॉधी को विश्वास हो गया था कि चुनाव मे उनकी विजय होगी। कहा जाता है कि उन्होने अपने विश्वासपात्र राजनीतिज्ञो, अफसरो और गुप्तचर सस्थाओ से रिपोर्ट पायी। उसमे भी उनको प्रसन्न करने के उद्देश्य से सही स्थिति का उनको पता नही चलने दिया गया।

लोक सभा के चुनाव की घोषणा के बाद सकट कालीन स्थिति मे भी ढील दी गयी। विपक्षी दलो और उनके नेताओ की रिहाई होने पर उनको एक मच पर लाने की कार्यवाही तेजी से की गयी। सत्तारुढ़ दल को यह उम्मीद थी कि भारतीय लोकदल के नेता श्री चरण सिह सौदेबाजी करके सत्तारुढ काग्रेस का समर्थन करेगे। इसी उद्देश्य से चौ0 चरण सिह और श्रीमती गॉधी मे कुछ मत्रणा भी हुई। लेकिन लोकदल मे पीसू मोदी और श्री राजनारायण भी नेता थे, जिनका श्रीमती गॉधी से शत्रुतापूर्ण विरोध किसी से छिपा नही था।

इसके साथ ही जय प्रकाश नारायण ने एडी-चोटी का पसीना एक करके सकटकालीन दमन के शिकार सभी राजनीतिक दलो को एक मंच पर और चुनाव के लिए जनता पार्टी मे शामिल कराने मे सफलता पायी। सगठन काग्रेस और काग्रेस के असतुष्ट नेतागण (मोरारजी देसाई, अशोक मेहता और चन्द्रशेखर) एक साथ आ गये। जनसघ और समाजवादी पार्टी के लोग भी जनता पार्टी के साथ थे। बाद मे चौ0 चरण सिह अपने भारतीय लोकदल के साथ जनता पार्टी मे शामिल हो गये। अकाली दल और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी विपक्षी ताल मेल मे

सहायक बन गये। चुनाव की घोषणा होने के बाद जगजीवन राम ने मन्त्रिमण्डल और काग्रेस से त्याग पत्र देकर "काग्रेस फार डेमोक्रेसी" की स्थापना की । हेमवती नदन बहगुणा इस सस्था के जनरल सक्रेटरी थे। इन लोगो ने भी जनता पार्टी के साथ चुनाव का ताल मेल किया।

1977 के आम चुनाव मे जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली थी। लोक सभा के 539 निर्वाचित सदस्यो मे से 297 जनता पार्टी के थे। 24 मार्च 1977 को जनता पार्टी के सदस्यो को अचार्य जे0 बी0 कृपलानी और जय प्रकाश नारायण ने गॉधी जी की समाधि के निकट नई पार्टी और गॉधी जी के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। मोरार जी देसाई को चौ0 चरण सिह और राजनारायण ने मिलकर जनता ससदीय पार्टी का नेता चुनवाने मे सफलता प्राप्त की।कुछ लो ग जगजीवन राम को जनता पार्टी का नेता बनवाने के पक्ष मे थे लेकिन चौ0 चरण सिह ने इसका विरोध किया। देसाई जनता पार्टी के प्रधानमत्री बने । उन्होने चौ0 चरण सिह को गृह मत्री बनाया।

जनता पार्टी की सरकार ने 27 मार्च को वाह्य सकट कालीन स्थिति (जिसे 1971 मे पाकिस्तान के आक्रमण के समय लागू किया गया था) को समाप्त कर दिया। प्रधानमत्री मोरारजी देसाई ने "निर्भय बनो" का नारा दिया ।यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने "मानव अधिकारो की रक्षा" का जो अभियान चलाया था उसके अन्तर्गत भारत की सकटकालीन स्थिति की कटु आलोचना की गयी थी ।[69]

जनता पार्टी मे आन्तरिक मतभेद जो इसके जन्मकाल से ही परोक्ष रुप मे था, अब समक्ष आया,[70] जबकि गृहमंत्री चौ0 चरण सिंह ने जनता पार्टी की कार्यकरिणी से इस्तीफा दे दिया । प्रधानमत्री मोरारजी देसाई और पार्टी अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर से उनका मतभेद था । 29 जून को सर्व श्री चरण सिह, राजनारायण, नरसिह यादव जगवीर सिह, रामकिंगर और जनेश्वर मिश्र ने मन्त्रिमण्डल से इस्तीफा दे दिये जिन्हे पहली जुलाई को स्वीकार कर लिया गया। बाद मे जनवरी 1979[71] मे, चौ0 चरण सिह को पुन उप प्रधानमंत्री तथा वित्त मत्री बनाया गया । परन्तु जुलाई 1979 मे चौ0 चरण सिह जनता पार्टी से अलग हो गये । 15 जुलाई को अपना बहुमत खो देने के बाद श्री देसाई ने प्रधानमत्री पद से इस्तीफा दे दिया । 16 जुलाई को चौ0 चरण सिह ने

---

69 - आपात काल को लेकर पश्चिमी यूरोपीय देशो मे भी भारत विरोधी प्रचार तेजी से चलाया गया ।

70 - अप्रैल 1978

71 - 24 जनवरी, 1979 को चौ0 चरण सिह को पुन उप प्रधानमत्री तथा वित्तमत्री बनाया गया ।

अपना सेक्यूलर (धर्म निरपेक्ष) पार्टी गठित की और 17 जुलाई को वे प्रधानमत्री बने ।तथा जगजीवन राम ससदीय दल के नेता के रुप मे विपक्ष के नेता बने ।

लोक सभा का अधिवेशन अगस्त 1979 मे बुलाया गया । लोकसभा की बैठक आरम्भ होने से पूर्व जब चौ0 चरण सिह को यह विश्वास हो गया कि लोकसभा मे उन्हे बहुमत का समर्थन नही मिलेगा तो उन्होने राष्ट्रपति से लोकसभा भग करने और नये चुनाव कराने की सिफारिस की। श्री नीलम,सजीव रेड्डी प्रधानमत्री, श्री चौ0 चरण सिह की सिफारिस स्वीकार कर ली और जनता पार्टी के ससदीय दल के नेता जगजीवन राम को नयी सरकार गठित करने का अवसर नही दिया । राष्ट्रपति ने चौ0 चरण सिह को काम चलाऊ सरकार चलाते रहने के लिए प्रधानमत्री बने रहने का परामर्श दिया । इस प्रकार चौ0 चरण सिह लोकसभा मे बिना विश्वास अर्जित किये ही प्रधान मन्त्री बने रहे ।उन्होने स्वत ही अपने जीवन की महत्वाकाक्षा पूरी कर ली। चौ0 चरण सिह ने इसके बाद अपने मन्त्रिमण्डल से हेमवती नदन बहगुणा और ब्रह्मानद रेड्डी को हटा दिया । बाद मे हितेन्द्र देसाई भी हट गये ।

जनवरी 1980 ई0 मे हुए आम चुनाव मे काग्रेस (आई), काग्रेस (यू) तथा लोकदल जिसे एक नई पार्टी के रुप मे चरण सिह और समाजवादियो ने खडा किया था जनता पार्टी जिसमे मूलरुप से जनसघ और जगजीवन राम एव चन्द्रशेखर जैसे कुछ काग्रेसी बचे हुए थे तथा सी0 पी0 आई0 और सी0 पी0 एम0 जिसका पश्चिम बगाल और केरल को छोडकर कही भी तसवीर मे नही थी, के बीच लडा गया । जनता पार्टी की शासन विहीनता, दूरदर्शिता का अभाव तथा लगातार चलने वाले आपसी झगडो से उबकर लोग एकबार फिर से काग्रेस और इन्दिरा की तरफ देखने लगे । लोगो ने इन्दिरा गॉधी की काग्रेस को ही असली काग्रेस समझा।[72]

जनता पार्टी ने अपना मुख्य मुद्दा इस चेतावनी को बनाया कि यदि इदिरा गॉधी फिर से सत्ता मे आई तो लोकतत्र और नागरिक अधिकारो को खतरा पैदा हो जायेगा ।चरण सिह ने किसान राज की बात की, इंदिरा गॉधी ने जनता पार्टी की शासन विहीनता पर ध्यान केन्द्रित किया और लोगो से कहा कि वे काम करने वाली सरकार को वोट दे । लोगो ने एक बार फिर 1971 और 1977 की तरह ही जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठते हुए इस बार काग्रेस (आई) को भारी जनादेश दिया जिसमे कांग्रेस ने 539 सीटों मे से 353 यानी दो-तिहाई बहुमत प्राप्त किया ।

---

72 - विपिन चन्द्र, मृदला मुखर्जी, आदिय मुखर्जी-"आजादी के बाद का भारत 1947-2000,' प्रथम सस्करण-2002, हिन्दी माध्यम कार्यान्वियन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय,पृष्ठ 353

लोकदल 41, जनता पार्टी 31 और काग्रेस (यू) 13 सीटो के साथ काफी पीछे रह गया। सी0 पी0 एम0 और सी0 पी0 आई0 ही अकेले काग्रेस की इस लहर के खिलाफ टिक पायी, जिन्होने क्रमश 36 और 11 सीटे जीती। चुनावो के बाद जनता पार्टी मे एक बार फिर विभाजन हुआ और जनसघ के पुराने नेता गणो ने इसे छोडकर 1980 के अत मे भारतीय जनता पार्टी बनायी और जगजीवन राम काग्रेस मे शामिल हो गये।[73]

31 अक्टूबर 1984 को इदिरा गॉधी की हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गॉधी को प्रधानमत्री बताया गया। समय से पहले यानी 24 से 27 दिसम्बर 1984 को आम चुनाव कराये गये जिसमे काग्रेस को अब तक सबसे बडा बहुमत मिला। यदि पजाब और आसाम के बाद मे हुए चुनावो मे जीती सीटे भी जोड़ ली जाए तो पार्टी को 543 लोकसभा की सीटो मे से 415 मिली। स्वय राजीव अमेठी से भारी बहुमत से जीत गये। उन्होने मेनाका गॉधी को हराया। काग्रेस का चुनाव अभियान भारत की एकता और अखण्डता पर केन्द्रित था। इदिरा गॉधी की मृत्यु के बाद लोगो ने यह खतरा बढ़ता देखा। भारी बहुमत का मतलब ऊची आशाए, यहा तक की अवास्तविक अपेक्षाएं भी थी, जिन्हे एकबार राजीव ने खुद 'डरा देने वाली' बताया था।[74]

यह राजीव गॉधी ही थे जिन्होने इक्कीसवी सदी का विचार भारतीयो के मस्तिष्क मे डाला। जब उन्होनें दूसरी बार 1989 के आम चुनाव मे भाग लिया तो देश के बारे मे उनकी महत्वाकाक्षी योजनाओ के लिए मात्र एक दशक बचा था। इस बीच 1987 मे काग्रेस से अपने निष्कासन के बाद वी0 पी0 सिह द्वारा लगभग अकेले ही चलाया गया अभियान जनता को छू गया।निम्न स्तरो पर अफसर शाही मे भ्रष्टाचार नागरिको के दिन-ब-दिन के जीवन का प्रश्न था,चाहे वे गरीब थे या अमीर लोग यह महसूस कर रहे थे कि उच्च स्तरो पर भ्रष्टाचार निचले स्तरो पर उसे बढावा देता है। वी0 पी0 सिह ने कोशिश की और व्यापक तबको का समर्थन हासिल किया, जिसमे सर्वोदय कायकर्ता, दत्ता सामत जैसे ट्रेड यूनियन नेता महाराष्ट्र मे शरद जोशी के नेतृत्व मे किसान आन्दोलन और कुछ काग्रेस-विरोधी मूलगामी बुद्धिजीवियो के तबके शामिल थे। इस भावनात्मक प्रश्न को उठाने के अलावा वी0 पी0 सिह ने राजीव तथा काग्रेस को अलग करने की एक विस्तृत रणनीति तैयार की। वे सबसे पहले उन काग्रेसियो के साथ मिले जो किसी न किसी कारण से असतुष्ट थे।वी0 पी0 सिह आरिफ मोहम्मद और अरुण नेहरु तथा

---

73 - वही, पृष्ठ 353

74 - निकाल्स नूगेट, राजीव गॉंधी-सन आफ ए डाइनेस्टी, नई दिल्ली, 1991, पृष्ठ 54

इनके साथ मिलकर रामधन, वी० सी० शुक्ला, शतपाल मालिक और दूसरे काग्रेसी असन्तुष्टो ने 2 अक्टूबर 1987 को जनमोर्चा बनाया । इसके इर्द-गिर्द वी० पी० सिह ने एक राजीव विरोधी राजनीतिक मोर्चा बनाना आरम्भ किया ।[75]

वी० पी० सिह ने वामपथियो को अपना स्वाभाविक सहयोगी बताया और सम्प्रदायवाद के विरुद्ध बयान देते रहे । लेकिन उन्होने इस बात का भी ख्याल रखा कि भाजपा उनके साथ रहे, वे उसके मचो पर से भाषण देते रहे और वाजपेयी तथा आडवाणी के साथ गहरे सबध बनाये रखे । लेकिन वी० पी० सिह की रणनीति से बढकर यह वामपथी तथा भाजपा का स्वाभविक काग्रेस-विरोधवाद था, जिसने उन दोनो को वी० पी० सिह के समर्थन मे ला खडा कर दिया । इलाहाबाद के जून 1988 के उपचुनाव मे काग्रेस के खिलाफ उनकी भारी जीत हुई । इसमे बोफोर्स तोप एक प्रकार से अनौपचारिक चुनाव-चिन्ह बन गया । वी० पी० सिह को विश्वास हो गया कि काग्रेस का वे ही जवाब है ।वामपथी हमेशा भाजपा के साथ मित्रता के आरोप से इनकार करते रहे, खासकर तब जब यह स्पष्ट हो चला कि भाजपा को 1989 के चुनाव समझौतो से सबसे अधिक फायदा हुआ है । लेकिन साथ ही, वे भाजपा के साथ वी० पी० सिह के तालमेल के प्रति पूरी तरह वाकिफ थे । इलाहाबाद की जीत की खुशी मे आयोजित एक जन-सभा मे, जिसमे वी० पी० सिह ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एक ही मच पर भाषण दिया, ज्योतिबसु की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए वी० पी० सिह की जीवन-लेखिका सीमा मुस्तफा के अनुसार "इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि वी० पी० सिह अकेले ही भाजपा के साथ 'समझौते के लिए जिम्मेदार नही थे,और छिपे तौर पर उन्हे वामपथी का समर्थन हासिल था । वास्तव मे, वाम पार्टियो ने वी० पी० को बताया कि वे भाजपा के साथ उनके समझौते का विरोध नही करेगे । तथा वे इसका खुलकर समर्थन भी नही कर पायेगे ।[76]

वामपंथी और वी० पी० सिह समझते थे कि 1977-79 के समान भाजपा को अधिक फायदा नही होगा, क्योकि इसकी कोई स्वतन्त्र शाक्ति नही थी । दूसरी ओर भाजपा साथ बनी रही । इसके लिए उसने ऐसे अपमान के घूॅट भी पी लिए जिसे एक कम अनुशासन वाली पार्टी के कार्यकर्ता पीने मे असमर्थ होते । भाजपा को विश्वास था कि सत्ता पाने के लिए काग्रेस को हटाया जाना जरुरी था । वाम और धर्मनिरपेक्ष ताकतो के साथ सहयोग ने इसे वह सम्मान दिया

---

75 - बिपिन चन्द्र "आजादी के बाद का भारत,1947-2000' पृष्ठ 378-379

76 - सीमा मुस्तफा, द लोनली प्रोफेट - वी० पी० सिह, एक पोलीटिकल बायोग्राफी, नई दिल्ली, 1995, पृष्ठ 120

जो इसके पास नही था, इससे सप्रदायवाद का दाग मिटाने मे मदद मिली । इस दाग ने भाजपा को भारतीय राजनीति के हाशिये तक ही सीमित कर रखा था । यह दाग इसे आजादी के सघर्ष के दिनो से ही इस पर धर्म निरपेक्ष राष्ट्रवादियो ने लगाया था । भाजपा ने अपनी सीटे 1984 मे 2 से 1989 मे 86 तक बढा ली ।इससे वह सत्ता के रास्ते पर आ गयी, जो उसे 1998 मे मिली।"1989 मे विकसित सहयोग बिना शक भाजपा के उदय के लिए जिम्मेदार कारको मे एक था ।"[77]

विरोधी पक्ष की एकता की रणनीति को तीन चरणो मे देखा गया । प्रथम मजिल गैर-काग्रेस धर्मरिपेक्ष राष्ट्रीय पार्टियो की एकता थी, दूसरी मजिल सभी गैर-वामपथी धर्मनिरपेक्ष स्थानीय और राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय मोर्चे का निर्माण थी, और तीसरी मजिली थी वाम पार्टियो एव भाजपा के साथ सीटो का तालमेल । दूसरी मजिल पहले पूरी हुई ।इसमे सात पार्टियो के राष्ट्रीय मोर्च का निर्माण 6 अगस्त 1988 को हुआ । 11 अक्टूबर 1988 अर्थात जय प्रकाश नारायण के जन्म दिन के अवसर पर "जनता दल " का निर्माण हुआ । यह जनमोर्चा, काग्रेस(एस), जनता पार्टी और लोकदल के विलय से बना । तीसरी मंजिल तब आयी जब जनता दल के नेतृत्व वाले राष्ट्री मोर्चा और भाजपा ने उन 85 सीटो पर आपस मे नही लडने का निर्णय किया जहॉ वे अन्यथा लड़ते । कुछ सीटो पर इसी प्रकार का इन्तजाम राष्ट्रीय मोर्चा और कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच हुआ ।

7-राष्ट्रीय मोर्चा सरकार :(1989-90 ई0)

1989 के आमद चुनाव मे काग्रेस को करारी चोट लगी थी, फिर भी वह सबसे बडी पार्टी थी, और उसे 197 सीटे तथा 39 5 फीसदी वोट मिले थे ।राजीव गॉधी ने स्पष्ट कर दिया कि काग्रेस को सरकार बनाने कोई दिलचस्पी नही है । वाम पार्टियो और भाजपा ने तुरन्त घोषणा कर दी कि वे बाहर से राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को समर्थन देगे ।इस प्रकार आजादी के बाद दूसरी गैर-काग्रेस सरकार के निर्माण की तैयारी हो गयी । राष्ट्रीय मोर्चे को 146 सीटे मिली और उसे भाजपा के 86 तथा वामपथी पार्टियो के 52 सदस्यो का समर्थन मिला ।

शुरुआत अच्छी नही रही । चन्द्रशेखर, वी0 पी0 सिह को प्रधानमंत्री बनाने के बिल्कुल खिलाफ थे, और देवी लाल ने जोर दिया कि उन्हे कम से कम उप प्रधानमत्री बनाया जाए। चुनाव

---

77 - वही, पृष्ठ 129

समाप्त होने के बाद हर तरह के मतभेद, विरोधी स्वार्थ, अति-अह, विचारधारात्मक हित, उभर आये और बुरी तरह टकराने लगे । वी0 पी0 सिह ने 2 दिसम्बर 1989 को बडी कठिनाई से प्रधान मत्री की शपथ ली, और देवी लाल उप-प्रधान मत्री बने । आपस मे विश्वास की कमी बाद मे खुलकर सामने आ गई । शपथ-ग्रहण समारोह मे देवीलाल ने एक तरह से अपना मजाक ही बनाया । उन्होने इस बात पर जोर दिया कि शपथ मे 'उप-प्रधानमत्री' अवश्य जोडा जाए, मानो उन्हे विश्वास नही था कि प्रधान मत्री अपने वादे पर टिके रहेगे । राष्ट्रपति ने हल्के से उन्हे समझाया कि उन्हे 'मत्री' ही कहना है ।

वी0 पी0 सिह ने बड़े ही ताम-झाम के साथ अपना काम शुरु किया । वे पजाब गये, स्वर्णमन्दिर के दर्शन किये, और खुले जीप मे घूमे, मानो दिखाना चाहते हो कि वे राजीव के समान भारी सुरक्षा मे नही घूमते । काग्रेस की नीतियो को बदलने के लिए काफी हल्ला-गुल्ला किया । लेकिन यह उनके प्रशासन की विशेषता रही कि भारी-भरकम शब्दो के कोई नतीजे नही निकले । उनके शासन काल के अन्त तक पजाब की स्थिति वैसी ही बनी रही, और कश्मीर तो और भी बुरी हालत मे पहुच गया ।उन्होने जार्ज फर्नाडिस को कश्मीर मामलो की समिति का अध्यक्ष बनाया । लेकिन अरुण नेहरु और मुफ्ती मोहम्मद सईद को हस्तक्षेप करने की इजाजत देते रहे । और फिर बिना किसी से सलाह-मशवीरा के जगमोहन को कश्मीर का गवर्नर बना दिया । स्वाभाविक था कि कश्मीर के मुख्यमंत्री डा0 फारुख अब्दुल्ला ने इस्तीफा दे दिया ।यह जगमोहन ही थे जिन्होने 1983 मे उनके खिलाफ विधायको को तोडकर उन्होने मुख्यमत्री पद छोडने पर मजबूर कर दिया था । अपनी आदत के अनुसार जगमोहन ने विधान सभा भग कर दी। फिर बिना किसी से सलाह किये, वी0 पी0 सिह ने उन्हे वापस बुला लिया, और उन्हे खुश करने के लिए राज्य सभा का सदस्य बना दिया सच तो यह है कि श्रीलका से भारतीय सेनाओ की वापसी पूरी करने तथा नेपाल के साथ व्यापार और आने-जाने सबधी झगडो को निबटाने के अलावा राष्ट्रीय मोर्चा सरकार अधिक कुछ न कर पाई । भाजपा और मुस्लिम नेताओ के साथ अपने सबधो का इस्तेमाल भी वह अयोध्या विवाद के हल के लिए न कर पाई । उल्टे, लाल कृष्ण आडवाणी की रथयात्रा ने, सांप्रदायिक भावनाएँ भड़काने का काम किया, वैसे ही जैस मण्डल कमीशन ने जातीय भावनाएं असाधारण रुप से फैलाई ।

सरकार को चल पाने मे शायद इसलिए अधिक दिक्कत हो रही थी कि आन्तरिक मतभेदो को हल करने मे इसकी शक्ति अधिक खर्च हो रही थी । चन्द्रशेखर ने प्रधान मत्री के प्रति अपना विरोध नही छिपाया । फारुख अब्दुल्ला द्वारा इस्तीफा देते ही उन्होने उसे समर्थन प्रदान किया । चौधरी चरण सिह के पुत्र अजीत सिह को देवी लाल पसन्द नही करते थे । और देवी लाल को चन्द्रशेखर के अलावा लगभग सभी नापसन्द किया करते थे ।देवी लाल ने 1967 मे सबसे पहले उत्तरी भारत मे किसान हितों को विशेष महत्व दिया । लेकिन वे अपने पुत्र ओमप्रकाश चौटाला को इतना पसन्द करते थे कि उन्हे स्वय उप-प्रधान मत्री बनने पर अपनी जगह हरियाणा का मुख्यमत्री बना दिया । "महम" से चौटाला द्वारा चुनाव लडने की कोशिश मे घोटाला हुआ । पूछताछ से पता चला कि चुनावो मे बडे पैमाने परे गडबडी हुई, और वोटरो को डराया-धमकाया गया । चुनाव आयोग ने चुनाव खारिज कर दिया । चौटाला ने मुख्यमत्री पद से इस्तिफा दे दिया, लेकिन उन्हे दो महीने बाद फिर से पदासीन कर दिया गया । कम से कम आरिफ और अरुण नेहरु को यह ज्यादती लगी और उन्होने सरकार से इस्तिफा दे दिया । इसका ध्यान रखकर वी0 पी0 सिह ने भी इस्तीफा दे दिया । लेकिन चौटाला के हटने के आश्वासन के बाद वे बने रहे । लेकिन 'ताऊ' देवी लाल की चाले खत्म नही हुई थी ।उन्होने आरिफ और अरुण नेहरु पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया । उन्होने 1987 मे वी0 पी0 सिह द्वारा राष्ट्रपति को कथित रुप से लिखा पत्र पेश किया जिसमे उन पर बोफोर्स काड मे शामिल होने का उल्लेख था वी0 पी0 सिंह ने घोषण की कि यह पत्र पूरी तहर जालसजी का कार्य था, उन्होने 1 अगस्त 1990 को देवी लाल को बर्खास्त कर दिया ।

देवी लाल चुप रहने वाले नही थे उन्होने 9 अगस्त को नई दिल्ली मे एक बडी किसान रैली का आवाह्न किया तांकि वे वी0 पी0 सिह को अपनी ताकत दिखा दे । हालाकि वी0 पी0 सिह ने इस बात से इन्कार किया कि वे इससे विचलित हो गये, और समझा जाता है कि इस स्थिति मे उन्होने अपने शासन का सबसे विवादास्पद निर्णय लिया । 7 अगस्त को उन्होने मडल कमीशन रिपोर्ट ससद मे पेश की । यह कमीशन जनता सरकार (1977-79) ने नियुक्त किया था और इन्दिरा गाधी ने इसकी चुपचाप उपेक्षा कर दी थी । मण्डल की सिफारिशो मे सरकारी नौकरियो और सार्वजनिक क्षेत्रो मे 27 फिसदी आरक्षण 'पिछड़ी जातियो' के लिए रखा गया । इस प्रकार आरक्षित श्रेणी 22.5 फीसदी से बढ़ाकर 49.5 हो गइ । पहले यह 22 5 फिसदी आरक्षण

जनजातियो या दलितो एव आदिवासियो के लिए था ।सिफारिशो मे दूसरा चरण भी था जिसमे आरक्षण शैक्षणिक संस्थाओ और पदोन्नति के लिए था ।[78]

इस घोषणा से व्यापक प्रतिक्रिया और गुस्सा पैदा हुआ । वे भी जो सिद्धात रुप मे इसके निर्णयो से असहमत नही थे, इस अचानक और मनमाने निर्णय से चकित थे । घोषणा करने से पहले वी0 पी0 सिह ने अपने नजदीकी सहयोगियो तक से सलाह नही की । किसी न किसी कारण से इस निर्णय से बीजू पटनायक, आर0 के0 हेगडे, यशवंत सिन्हा और अरुण नेहरु असतुष्ट थे । वामपथी पार्टियॉं और भाजपा नाराज थी क्योकि इस निर्णय का उन्हे पता तक न था। देवी लाल और चन्द्रशेखर ने तीव्र भर्त्सना की । आलोचनाए कई कारणो से की गयी निर्णय का समय, सहमति बनाने की कोशिश का न होना, इसका विभाजनकारी चरित्र और पिछडी जातिया तय करने का गलत तरीका । सी0 पी0 एम0 चाहती थी कि आरक्षण का आधार आर्थिक हो । इस विचार का समर्थन हेगड़े समेत कई नेताओ ने किया । प्रमुख समाजशास्त्रियो का विचार था कि पिछड़ी जातियो की पहचान का तरीका पुराना था, और आजादी के बाद हुए सामाजिक ढाचागत परिवर्तनो का ध्यान नही रखा गया था । रिपोर्ट मे जिन तबको को 'पिछडी जातिया' कहा गया, वे भूमि सुधारो और हरित क्रान्ति से प्रमुख रुप से फायदे मे रहे थे । इसलिए पिछडेपन के आधार पर उनका दावा शायद ही बनता था । इसमे शक नहीं कि कुछ अन्य तबके आर्थिक और सामाजिक रुप से पिछडी जातियो से अलग नही थे । उन्हे विशेष सुविधाए देने की जरुरत थी । लेकिन उनकी पहचान अलग से और बडी सावधानी से करनी जरुरी थी,क्योकि यदि उन्हे उन लोगो के साथ मिला लिया जाता तो जो केवल नाम के पिछडे थे, तो उन्हे फायदा न होता ।[79]

मण्डल निर्णय का सबसे घातक पहलू इसका सामाजिक रुप से विभाजन कारी होना था। सामाजिक न्याय के नाम पर इसने जाति को जाति के विरुद्ध खडा कर दिया । इस कदम से जिन्हे हानि पहुँचती थी, उन्हें यह समझाने का प्रयास नही किया गया कि उन्हे व्यापक हित मे इसे क्यो स्वीकार करने चाहिए ।इसने उन फायदे पाने वाले लोगो को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे विरोधियॉ को उच्च वर्गीय हितो का प्रतिनिधि बताए इसने समाज के उन क्षेत्रो मे भी जाति को सिद्धात एव पहचान के रुप मे लागू किया जहॉ से वह लुप्त हो चुकी थी । इसके अलावा,यह अपेक्षा की जा रही थी कि सविधान मे जनजातियो के लिए आरक्षण लागू करने के

---

78 - बिपिन चन्द्र -"आजादी के बाद का भारत-1947-2000", पृष्ठ 381-82

79 - विपिन चन्द्र- "आजादी के बाद का भारत" 1947-2000 , पृष्ठ, 383 ,

चालीस साल के बाद इसे आगे जारी रखने के सबध मे कम से कम कुछ विचार-विमर्श और बहस होती । इन आपत्तियो पर विचार करना आवश्यक था कि आरक्षण का जारी रहना जिन्हे जरुरत है उनके लिए नही बल्कि इन जातियो के विशेष ऊपरी तबको के हक मे था, सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए आरक्षण एकमात्र रास्ता नही था, बल्कि दूसरी रणनीतिया भी अपनायी जा सकती थी ।[80] जाति पहचान की राजनीति जाति व्यवस्था से पीडित लोगो के बजाए नेताओ को फायदा पहुचाती हैं-ये सभी विचारणीय विषय थे । इन प्रश्नो पर सामाजिक परिवर्तन सबधी कदम उठाने से पहले व्यापक विचार-विमर्श करने की जरुरत थी ।इसकी पुष्टि उत्तर भारत[81] मे छात्र-समुदाय की तीव्र प्रतिक्रिया से हुई । सरकारी क्षेत्र मे नौकरिया छात्रो की बडी सख्या के लिए भविष्य है । अभी भी इसमे धन और प्रभाव की जरुरत नही होती । भर्ती प्रतियोगी परिक्षाओ के जरिए होती है । ऐसी स्थिति मे आरक्षण के नाम पर करीब आधी सीटो को एका एक बद किया जाना अन्याय पूर्ण था । उनकी नजरो मे ऐसे कई लोग जिन्हे फायदा पहुचता, आर्थिक और सामाजिक रुप से उनके बराबर या उनसे बेहतर थे। यह जनजातियो के आरक्षण से काफी अलग था उनकी सामाजिक एव आर्थिक अक्षमता मे कोई शक नही था, और आजादी के सघर्ष के दिनो से ही इस प्रश्न पर सामाजिक एक मत थे । इसके अलावा, छात्र इस निर्णय के पीछे छिपे राजनीतिक उद्देश्यो को पहचानते थे, क्योकि इन पर स्वय राष्ट्रीय मोर्चे के नेताओ के बीच बहस हो रही थी । मण्डल विरोधी आन्दोलन ने सार्वजनिक सम्पत्ति को बर्बाद करने, बसो के जलाने, रैलियो, सभाओ तथा प्रेस मे बहस इत्यादि का रुप धारण किया । इसमे छात्र आगे थे, और अकसर ही उनका समर्थन समाज के अन्य तबके कर रहे थे, जैसे-अध्यापक, आफिस कर्मचारी और गृहणिया । उत्तर भारत के गॉवो और शहरो मे कई घटनाए घटी । दिल्ली, गोरखपुर वाराणसी, कानपुर तथा अन्य स्थानो मे गोलीकाण्ड हुए । यह पाकर कि ये विरोध-प्रदर्शन प्रभावहीन साबित हो रहे है, सिम्बर के मध्य मे कुछ छात्रो ने आत्मदाह की कोशिश की दोनो ओर गुस्सा तेज होने लगा । जो मण्डल के पक्ष मे थे वे इसे बर्बर,कृत्रिम, यहॉ तक की दिखवटी बताने लगे, जो विरुद्ध थे वे इस प्रश्न पर सवेदना और समझदारी की कमी से चकित हो गये । प्रधानमंत्री की अपीलो का कोई प्रभाव नही पड़ा । कुछ समय तक मण्डल-विरोधी आन्दोलन का बडा हिस्सा जातिवाद के प्रभाव से मुक्त रहा । वास्तव मे यह जाति को प्रमुख कारक मानने के

80 - ज्यो द्रेने और अमर्त्य सेन, इण्डिया इकोनामिक डेवलपमेट एड सोशल अपार्चुनिटी, दिल्ली, 1996, पृष्ठ 96-97

81 - बिपिनचन्द्र- "आजादी के बाद का भारत, 1947-2000", पृष्ठ 383-84

विरुद्ध था । लेकिन बाद मे नकारात्मक रुझान पैदा हो गये । इसका एक कारण उन्हे ऊपरी जातियो से प्रेरित बताया जाता था । ऊपरी जाति के छात्र 'ऊपरी जाति सगठनो' मे सगठित होने लगे । कालेजो एव होस्टलो मे तथा मेसो मे जातिवादी व्यक्तियो का आदान प्रदान होने लगा । जो सस्थाए कभी जातीय पहचान लुप्त होने का केन्द्र थी, उन्ही मे इसका पुनर्जन्म होने लगा । विरोध तब समाप्त हुआ जब उच्चतम न्यायालय ने 1 अक्टूबर 1990 को मडल रिपोर्ट लागू करने पर रोक लगा दी ।[82]

इस बीच भाजपा अपनी योजना पर काम कर रही थी और मण्डल ने उसे बेहत मौका दे दिया । मण्डल का व्यापक विरोध देखकर भाजपा ने अपना समर्थन वापस लेने की बात शुरु कर दी । 25 सिम्बर को लालकृष्ण आडवाडी 6000 मील लबी रथयात्रा पर निकले ।यह गुजरात मे सोमनाथ से शुरु हुई, और राम मदिर की आधारशिला रखने के लिए अयोध्या पहुचनी थी । लेकिन 23 अक्टूबर को बिहार के मुख्य मन्त्री श्री लालू प्रसाद यादव समस्तीपुर मे उन्हे गिरफ्तार करवा लिये । गिरफ्तारी के साथ ही उनकी रथयात्रा समाप्त हो गयी । भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया । वी0 पी0 सिंह यदि भाजपा को सतुष्ट करते तो अपनी ही पार्टी ओर वामपथी सहयोगियो को नाराज कर देते । इसलिए उन्होने भाजपा के साथ सबध तोड लेने का फैसला लिया । उत्तर प्रदेश मे जब श्री मुलायम सिह यादव मुख्यमत्री थे तो 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या मे उस भीड़ पर गोलिया चलायी गयी जो कानून को अपने हाथ मे लेते हुए राममन्दिर के शिलान्यास तक उन्मादी तरीके से पहुचना चाह रहे थे । आडवाणी की रथयात्रा और गिरफ्तारी तथा अयोध्या गोलीकाण्ड ने साम्प्रदायिक भावनाए भडका दी ।उत्तर भारत मे कई जगह साम्प्रदायिक दगो मे कई लोग मारे गये । 5 नवम्बर को जनता दल मे फूट पड गयी । 58 सासदो ने चन्द्रशेखर को अपना नेता चुना । 7 नवम्बर को गैर-कांग्रेस सरकार चलाने की दूसरी कोशिश ग्यारह महीनो बाद समाप्त हो गयी । 10 नवम्बर 1990 को चन्द्रशेखर की अल्पकालिक सरकार काग्रेस के समर्थन से बनी । 5 मार्च 1991 को काग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया तथा इसी के साथ 19 मई 1991 को चुनाव की घोषणा कर दी गयी ।

---

82 - बिपिन चन्द्र- "आजादी के बाद का भारत, 1947-2000", पृष्ठ 384-85

अध्याय—४

समाजवादी आन्दोलन का पुर्नगठन एवं सपा की भूमिका

अध्याय 4

समाजवादी आन्दोलन का पुनर्गठन एवं सपा की भूमिका

1-श्री मुलायम सिंह यादव का मुख्यमंत्री पद और कार्यक्रम

बोफोर्स और एच0 डी0 डब्ल्यू पनडूब्बी विवाद के चलते राजीव गाधी से अलग हुए विश्वनाथ प्रताप सिह और उनके जनमोर्चा के साथियो के विपक्ष मे शामिल होते ही काग्रेस विरोधी खेमे मे नई ऊर्जा दिखाई देने लगी। उत्तर प्रदेश मे मुलायम सिह अपने क्राति रथ के साथ विपक्षी एकता का प्रयोग कर रहे थे।इसी की देखा-देखी राष्ट्रीय स्तर पर जनता दल का प्रयोग हुआ। इससे राजनीति की सभावनाए खुली, पर कुछ चिताजनक पहलू भी सामने आए।

विपक्षी एकता राष्ट्रीय राजनीतिक सकट को हल करने का एक फौरी नुस्खा था। 1987 के मार्च मे इस राजनीतिक सकट की नीव पडी थी। जून तक आते-आते प्रतिरक्षा घोटालो ने राजीव सरकार को सदेह के दायरे मे ला दिया। इस दौर की प्रमुख घटनाओ को इस तरह देखा जा सकता है-

30 जून 1987- हरियाणा चुनाव के बाद, "राजीव हटाओ" अभियान शुरू करते हुए लोकदल-भाजपा गठबधन की दिल्ली रैली, जिसमे जनता पार्टी और तेलुगू देशम के नेता भी शामिल हुए।

16 अगस्त 1987- चार वामपंथी पार्टियो- सी0 पी0आई0, सी0 पी0 एम0, आर0 एस0 पी और फारवर्ड ब्लॉक की सयुक्त बैठक मे राजीव गाधी के इस्तीफे और मध्यावधि चुनाव की माग को लेकर धर्मनिरपेक्ष शक्तियो के साथ सयुक्त अभियान चलाने का फैसला।

11 सितंबर 1987- कलकत्ता मे सी0 पी0 एम, लोकदल (ब) और वी0 पी0 सिह ग्रुप को साझा बैठक मे विकल्प-निर्माण के सवाल पर विचार विमर्श।

23 सितंबर 1987- हरियाणा के सूरजकुड मे लगभग तमाम गैर-वामपथी विपक्षी पार्टियो का सम्मेलन।

2 अक्टूबर 1987- वी0 पी0 सिंह ग्रुप द्वारा 'जन मोर्चा' नामक 'गैर-राजनीतिक' फोरम का गठन।

12 अक्टूबर 1987- वाममोर्चा की शक्तियो द्वारा दिल्ली मे साप्रदायिकता व पृथकतावाद विरोधी कन्वेशन, जिसमे लोकदल (ब), तेलुगू देशम, काग्रेस (स), जनमोर्चा और जनवादी पार्टी के लोग भी शमिल हुए।

12 नवबर 1987- पटना मे लोकदल (ब) की रैली, जिसमे भाजपा, जनमोर्चा, जनता पार्टी, असम गण परिषद और तेलुगू देशम के नेता भी शरीक हुए।

28 नवंबर 1987- जन मोर्चा, जनता पार्टी, लोकदल (अ) और काग्रेस (स) द्वारा मिलजुल कर राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक मोर्चे का गठन।

9 दिसंबर1987- राजीव गाधी के इस्तीफे और मध्यावधि चुनाव की माग के साथ, वाममोर्चा की शक्तियो द्वारा दिल्ली मे रैली।

21 जनवरी 1988- वाममोर्चे और राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक मोर्चे की पार्टियो की साझा बैठक मे 'भारत बचाओ दिवस' और 'भारत बंद' आयोजित करने का निश्चय।

23 जनवरी 1988- उपर्युक्त पार्टियो द्वारा राष्ट्रीय पैमाने पर 'भारत बचाओ दिवस' आयोजित। जिला और ब्लाक स्तर प्रदर्शन और रैली।

9 मार्च 1988- राजीव गाधी के इस्तीफे की मांग के साथ,लोकदल-भाजपा गठबधन की दिल्ली रैली।

15 मार्च,1988- वाम मोर्चे और राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक मोर्चे के आह्वान पर 'भारत बद', जिसे भाजपा को छोड़कर लगभग तमाम विपक्षी पार्टियो का समर्थन मिला।

6 अगस्त, 1988- को सात पार्टियो ने मिलकर राष्ट्रीय मोर्चे का निमार्ण किया।

11 अक्टूबर, 1988- जय प्रकाश नारायण के जन्म दिन के अवसर पर 'जनता दल' का का निर्माण हुआ। यह जनमोर्चा काग्रेस (एस), जनता पार्टी और लोकदल के विलय से बना।

इस घटनाक्रम से जाहिर है कि हिंदी इलाको मे मुलायम सिंह का संगठन लोकदल (ब) ही विपक्षी एकता का केद्र था। जनता पार्टी और लोकदल (ब) नई एकीकृत पार्टी का मजबूत आधार बनी और जन मोर्चा व लोकदंल (अ) भी उसमे शामिल किए गए। हालाकि जनमोर्चा गुट अपनी अवसरवादी नीतियो के कारण काग्रेस (इ) से टूट कर आया हुआ गुट था और उस पर यथास्थितिवाद की काग्रेस विचारधारा ही हावी थी, किंतु परिवर्तन की आवश्यकता और जनभावना का सम्मान करते हुए उसे भी जनता दल मे शामिल करना पडा। इस गुट मे कुटिल

और चालबाज राजनीतिज्ञो की भरमार थी, जिन्होने गठन के आरभ मे तो चुनावी फायदे के लिए बीजू पटनायक, देवीलाल, मुलायम सिह, आदि जनाधार वाले नेताओ को आगे रखा, पर चुनाव के बाद अपनी जोडतोड़ की राजनीति के माध्यम से दल पर अपना शिकजा कसना और मुलायम सिह यादव जैसे-वरिष्ठ समाजवादी व सिद्धातनिष्ठ नेताओ के विरूद दुष्प्रचाार करना शुरू कर दिया। लेकिन समाजवादी नेताओ मे राजनीतिक कौशल व जनाधार की कमी नही थी, इसलिए वे इस गुट की कुटिलतापूर्ण राजनीति को विफल बनाने मे सक्षम थे।[1]

जनमोर्चा गुट की राजनीति का पहला उदाहरण नवबर 1989 मे चुनावी विजय के बाद राष्ट्रीय मोर्चा ससदीय दल के नेता पद का चुनाव ही था। यह चुनाव लोकतात्रिक ढग से नही कराया गया और छल-प्रपच से विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री पद पर आसीन कर दिया गया। नेपथ्य से खेले जा रहे सारे खेल की कमान अरूण नेहरू के हाथ मे थी, जो पार्टी पर अपना शिकजा कसने के लिए लगातार प्रयासरत थे। वे एक समय मे राजीव गाधी के विश्वासपात्र रह चुके थे और उन पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप थे। उन्हे राजनीति मे 'थैलीशाही' की स्थापना के लिए भी जिम्मेदार माना जाता था। ऐसे नेताओ का कोई जनाधार नहीं था पर परिस्थितियो के फेर से वे पार्टी राजनीतिज्ञो की अपनी पक्ति मे आ गए थे और सुयोग्य समाजवादी नेता उपेक्षित पडे थे। उनकी गतिविधियो से दल मे अविश्वास और संदेह की एक विभाजन रेखा खिच गई थी।

केद्रीय मत्रिमडल के गठन से ही यह बात स्पष्ट हो गई कि जन मोर्चा गुट पार्टी को सामूहिक आधार पर चलने के बाजय अपनी जेब मे रखना चाहता है। हालाकि जनता पार्टी व लोकदल की तुलना मे जन मोर्चा की राजनीतिक शक्ति जनता दल के गठन से पहले तक बहुत कम थी, किंतु केद्रीय मंत्रिमडल मे जनमोर्चा गुट के सर्वाधिक 15 मत्री लिए गए। इनमे प्रधानमत्री के साथ-साथ गृह, विदेश, रक्षा, वाणिज्य जैसे महत्वपूर्ण विभागो के मत्री शामिल थे। पार्टी संगठन मे भी जन मोर्चा नेताओ को महत्वपूर्ण पदो पर बिठा दिया गया था।

विधानसभा चुनावो के बाद उत्तर प्रदेश व बिहार मे नेता चुनने के सवाल पर भी जनमोर्चा गुट ने राजनैतिक शतरंज की गोटिया खेलनी चाही। अरूण नेहरू व आरिफ मोहम्मद खां को उत्तर प्रेदश व बिहार मे अपनी सुविधा वाले व्यक्तियो को विधायक दल का नेता चुनवाने के लिए भेजा गया। उन्होने मुलायम सिह यादव व लालू प्रसाद यादव को नेता चुने जाने से रोकने

---

1 - डा0 आर0 पी0 त्रिपाठी- मुलायम सिह यादव रचना और सघर्ष, पृष्ठ 69
डा0 लोहिया ट्रस्ट का प्रकाशित द्वितीय सस्करण 1996, 1- विक्रमादित्य मार्ग, लखनाऊ

की हर सभव कोशिश की। उत्तर प्रदेश मे अजित सिह को मुख्यमत्री पद के प्रत्याशी के रूप मे पेश किया गया। लेकिन वे अपने षडयत्र मे सफल नही हो सके और दोनो राज्यो के विधायको ने क्रमश मुलायम सिह व लालू प्रसाद यादव के पक्ष मे स्पष्ट निर्णय दिया। उत्तर प्रदेश मे जनता दल इकाई का अध्यक्ष चुने जाने के मामले मे भी स्पष्ट, पक्षपात किया गया। हर राज्य मे प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश मे इसके लिए बाकायदा चुनाव कराए गए। यह बात और है कि मुलायम सिह को प्रदेश अध्यक्ष बनने से फिर भी नही रोका जा सका।

पाच दिसबर 1989 को मुलायम सिह यादव ने लखनऊ के दिग्विजय सिह बाबू स्टेडियम मे हजारो आम लोगो की उपस्थिति मे शपथ ली। उनके सामने उत्तर प्रदेश के मुख्यमत्री का गौरवपूर्ण सिंहासन था और आगे का रास्ता बहुत आसान नही था। उन्हे अपनी पूर्वर्ती काग्रेसी सरकारो से एक बदहाल उत्तर प्रदेश विरासत मे मिला था। ऐसा राज्य, जिसमे अपने आकार की ही तरह विशाल समस्यओ की भरमार थी गरीबी, पिछडापन, बेकारी, अराजकता, भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता आदि। सबसे बडी और निरतर भयानक रूप लेती हुई समस्या थी साप्रदायिकता की। पर पद सभालने के पहले ही दिन से श्री यादव की दृष्टि स्पष्ट थी। उन्हे अपने उत्तरदायित्वो का पूरा अहसास था और मुख्यमत्री के रूप मे उनका लगभग डेढ वर्ष का कार्यकाल यह साबित करता है कि उन्होने अपनी जिम्मेदारियो को कितनी सफलता से निभाया।

मुख्यमत्री के रूप मे श्री यादव के सामने जनता की उन सब तकलीफो को दूर करने का स्वर्णिम अवसर था जिन्हे वे बरसो से देखते आए थे। जनता के प्रति अपनी वास्तविक जिम्मेदारियो से बेखबर काग्रेसी सरकारो के शासन काल मे इन तकलीफो को दूर न होना श्री यादव को निरतर विचलित करता रहा । ग्रामीण पृष्ठभूमि का होने और शोषित वर्ग की तकलीफो को करीब से जानने-समझने के कारण उन्हे अपनी प्राथमिकताए तय करने मे विशेष परेशानी नही हुई। शासन मे आने से पहले भी विपक्ष के नेता के रुप मे उन्होने पिछडे और गरीब तबके के लिए निरतर आवाज उठाई थी। इस वर्ग के विरूद्ध होने वाली किसी भी प्रमुख घटना की खबर मिलने पर वे सबधित स्थान का दौरा करते थे और पीड़ित वर्ग का पक्ष मजबूती से सरकार के समक्ष रखते थे। सत्ता मे आने के बाद भी उनके जनसेवा के इस दृष्टिकोण मे कोई अंतर नही आया।

मुख्यमत्री के रूप मे अपने पहले ही भाषण से श्री यादव का नजरिया स्पष्ट हो गया। वे उन राजनीतिज्ञो मे से नही थे जिनके जनता के प्रति सीमित सरोकार है और जो सत्ता मे आते ही

जनता को भूल जाते है। गाव-गाव से आए हजारो उत्साही लोगो को सबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा था," आज लोहिया जी का सपना पूरा हो गया। किसान का बेटा मुख्यमत्री बना है। मै सपूर्ण क्षमता से इन भोले-भाले लोगो का कल्याण करने का प्रयास करूगा।"

जिस समय श्री यादव ने मुख्यमत्री पद सभाला उससे पहले उत्तर प्रदेश के कई शहरो मे दगे हो चुके थे और साप्रदायिक व पुनरूत्थानवादी ताकतो ने पूरे देश को विवेकहीन साप्रदायिक उन्माद की ओर धकेल दिया था।

लबे अरसे से ठडे पड़े अयोध्या विवाद को नए सिरे से उठाया गया था। इतना ही नही, उसे हिंदू समाज की अस्मिता का प्रश्न बनाकर प्रदेश के लोगो की भावनाओ से खेला जा रहा था। ये शक्तिया अपने एक पक्षीय व हठधर्मितापूर्ण रवैए पर अडी हुई थी और अपने आपको कानून की परिधि से भी ऊपर मानने लगी थी। पूर्वर्ती काग्रेसी सरकार ने भी राजनैतिक स्वार्थ वश उन्हे परोक्ष प्रोत्साहन दिया।

मुख्यमंत्री के रूप मे कानून और व्यवस्था सबधी जिन जटिल समस्याओ से श्री यादव को जूझना था उनमे महेद्र सिंह टिकैत का तथाकथित किसान आदोलन भी एक था। कुछ वर्ष पहले किसानो की कुछ समस्याए उठाने के नाम पर शुरू हुआ यह आंदोलन तब तक विकृत और अनियत्रित रूप ले चुका था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाको मे टिकैत के समर्थको ने एक नये किस्म का उग्रवाद शुरू कर दिया था और प्रशासन के अधिकारो को ही नकारने लगे थे। अराजकता का आलम यह था कि उस क्षेत्र मे सरकारी अधिकारियो के घूसने तक पर टिकैत के लोगो ने रोक लगा दी थी।

श्री यादव की सरकार को पिछली सरकारों से और भी अनेक समस्याए उपहार में मिलीं। ये समस्याए समाज के लगभग हर वर्ग से जुड़ी हुई थी। इनमे बेरोजगारी की समस्या सर्वोपरि है। उत्तर प्रेदश जैसे विशाल राज्य मे, जो जनसख्या की दृष्टि से देश मे सबसे बडा राज्य है, बेरोजगारी की सख्या भी किसी अन्य राज्य से कम नही थी। इसकी सबसे बडी वजहे अशिक्षा, सरकारी नौकरियो के प्रति अनावश्यक लालसा, पर्याप्त अवसरो का अभाव और सरकारी प्रोत्साहन का अपर्याप्त होना था। युवको का एक बहुत बड़ा वर्ग सुशिक्षित होने के बावजूद दर-दर भटकने पर मजबूर था। राज्य के इतने विशाल व शक्तिशाली जन ससाधानो का कोई उपयोग नही हो रहा था। इस वर्ग का आक्रोश अपराधो मे वृद्धि के रूप मे सामने आ रहा था।

पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की स्थिति दयनीय थी, दलित वर्ग को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं था और उस पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। आर्थिक दृष्टि से भी वह अत्यंत निर्बल था और राजनीतिक दृष्टि से भी किसानों की हालत भी कोई बहुत संतोषजनक नहीं थी। बिजली की पर्याप्त आपूर्ति न होने और सिर पर कर्ज का भारी बोझ होने से वे परेशान थे। दूसरी ओर उन्हें अपनी उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पा रहा था।

गाँवों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव था और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच विषमताएं मौजूद थीं। विशेषतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में विकास की गति बहुत कमजोर थी। वहां सड़कों, विद्यालयों, अस्पतालों जैसी आवश्यक सुविधाएं भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थीं। कई इलाकों में पेयजल व राशन संबंधी कठिनाइयां थीं। इसी परिप्रेक्ष्य में वहां पृथक राज्य के निमार्ण के लिए उत्तराखंड आंदोलन शुरू हो गया था और राजनैतिक स्वार्थवश कई राजनैतिक शक्तियों ने उसे समर्थन भी दे दिया था। गांवों की हालत बदतर थी तो शहरों के हाल भी बहुत अच्छे नहीं थे।

इस सरकार को भ्रष्टचार की समस्या से भी निपटना था। प्रायः हर विभाग से कर्मचारियों व अधिकारियों के भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने की शिकायतें मिल रही थीं। जनता के प्रति पुलिस का दृष्टिकोंण 'सेवक' का नहीं था, बल्कि वह आतंक का पर्याय बन चुकी थी। श्री यादव ने ऐसे समय पर राज्य की बागडोर संभाली थी जब उनके सामने चुनौतियों व समस्याओं के सिवाय कुछ भी नहीं था। यह परिस्थिति किसी भी नए मुख्यमंत्री का उत्साह भंग कर देने के लिए काफी थी, पर मुलायम सिंह ने चुनौतियों से डर कर पीछे हटना नहीं सीखा। उन्होंने महात्मा गांधी, जय प्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव और चौधरी चरण सिंह के सपनों को साकार करने के लिए तमाम चुनौतियों को जीवटता से स्वीकार किया। इससे पहले 1977 में सहकारिता मंत्री के रूप में भी उन्होंने ऐसी चुनौतियों का प्रभावशाली जवाब दिया था और अपने कामकाज की विलक्षण शैली की छाप छोड़ी थी मुलायम सिंह ने इन भारी चुनौतियों का सामना कैसे किया ? इसका जवाब पाने के लिए उनके एक कट्टर आलोचक समीक्षक की कलम से लिखा गया सरकार के चार महीने के ब्यौरे का कुछ अंश देखिए-

"उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की जनता दल सरकार ने आखिरकार चार महीने पूरे कर लिए। ये चार महीने शांति से नहीं गुजरे। इनमें वह सब कुछ हुआ जो घटकवाद में गले

तक डूबी जनता दल सरकार मे सभव था। फिर भी जनता दल सरकार चल रही है। यह मुलायम सिह यादव का सौभाग्य और उपलब्धि दोनो है। हालाकि उन्होने पत्रकारो से अपनी सरकार का कामकाज दिखाने के लिए कम से कम छह महीने मागे थे, लेकिन शायद ही कोई राजनीतिक प्रेक्षक हो जो यह मानता हो कि पिछले चार महीने मे जद सरकार की जो कार्यशैली थी, वह अगले दो महीने मे बदल जाएगी। वास्तव मे जनता दल के अंदर उन्हे वास्तविक चुनौती लोकदल (अजित) घटक से ही मिलती रही है। अजित सिह को हराकर उन्होने कई विवादो को उठाने और लबे समय तक दल के अदर से चुनौती मिलने से खुद को बचा लिया। इससे उनका दल मे दबदबा बढा और खुद का सघर्षशील आत्मविश्वास मजबूत हुआ।

"मुलायम सिह ने जब कुर्सी सभाली तो उतने तो नही, लेकिन फिर भी बहुत से राजनीतिक प्रेक्षको ने यही सवाल पूछा कि केद्र सरकार की तरह यह सरकार कितने दिल चल पाएगी। यह ठीक है कि टिकाऊपन के बारे मे जितने ज्याद और तीखे सवाल केंद्र के बारे मे है, उतने लखनऊ की सरकार के बारे मे नही। लेकिन सच्चाई यह भी है कि लखनऊ की सरकार का भविष्य अनिवार्य तौर पर दिल्ली के भविष्य से जुडा हुआ है।उत्तर प्रदेश ही वह नया कुरूक्षेत्र है जहा दिल्ली और लखनऊ के भविष्य को तय होना है। इसलिए यह मानना भूल होगी कि दिल्ली की राजनीतिक गतिविधियो, दावपेच, घात-प्रतिघात और उठापटक का सीधा असर लखनऊ पर नही पडेगा।

"आज जनता दल की जो स्थिति है, वह किसी से छिपी नही है। एक दल के रूप मे वह खस्ताहाल है। किसी सागठनिक ढांचे के बगैर वह आज तक घटकवाद के सहारे चल रहा है। जनता दल के राज्य अक्ष्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा जमाए रखने की लडाई मे फिलहाल, उन्होने वी0 पी0 सिह के दाव राजपूजन पटेल को देवीलाल, अजित सिह और चंद्रशेखर के सहयोग से चित कर दिया घटको की आपसी लडाई मे जैसे दिल्ली मे वी0 पी0 सिह 'सर्वमान्यता' का कवच धारण किए हुए है वैसे ही लखनऊ मे मुलयाम सिह, वह खुद को 'कठपुतली' सरकार मे नही बदलना चाहते, वह अपनी स्वतत्र छवि और स्वतत्र आधार के निर्माण के लिए सघर्ष करना चाहते है। इसके लिए उन्हे आपस मे जूझते नरेशो और कमजोर केंद्र के कारण इसका मौका भी मिल रहा है और दिक्कते भी झेलनी पड़ रही हैं।

"बेशक, मुलायम सिह लबे संघर्ष के बाद लखनऊ की कुर्सी तक पहुच पाए है। इटावा के डाकू पीडित इलाके का एक शिक्षक धीरे-धीरे उतार-चढाव के बीच यहा तक पहुचा। वे गर्व से बताते है कि वे लोहिया और चरण सिह के शिष्य है। आज से तीन वर्ष पहले जब मुलायम सिह लोकदल पर कब्जे के सवाल को लेकर हुए सघर्ष मे चौधरी साहब के परिवार के खिलाफ खडे हुए और नतीजे मे विपक्षी दल के नेता का पद खोना पडा, तबसे अब तक उनका सघर्ष ही उन्हे मुख्यमत्री की कुर्सी तक लाया। उन्होने ही चौधरी साहब के आधार पर अपना नेतृत्व स्थापित किया। इसीलिए वे नेता पद के चुनाव मे नौसिखिए अजित सिह को चित्त करने मे सफल हुए।

"उन्होने नेता पद का चुनाव जीतने के बाद जो 13 सदस्यीय मत्रिमडल बनाया, वह हालाकि घटको के प्रतिनिधित्व पर बना है, लेकिन शायद ही उसमे से कोई मत्री उनके कद का है। अधिकाश की निष्ठा मुलायम सिह के साथ है और मत्रिमडल पर उनकी छाप है। उनमे से कोई उन्हे चुनौती देने की स्थिति मे नही है। वे खुद 44 विभागो को देख रहे है और साथ ही अन्य मत्रियो पर भी कड़ी नजर रखते है। महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणाए खुद करते है। जैसे उन्होने 26 मार्च को जब अग्रेजी हटाने' जैसी महत्वपूर्ण नीतिगत घोषाणए की तो उनके बारे मे शिक्षामत्री सच्चिदानंद वाजपेयी को कोई सूचना तक नही थी। बिजली, गृह, उद्योग, वित्त, परिहवन जैसे महत्वपूर्ण विभाग उन्होने अपने कब्जे मे रखे है।[2] वाराणसी के छात्र नेता आनद प्रधान मुलायम सिंह के प्रशसको मे से नही है। 'समकालीन जनमत' (बिहार) मे छपी उनके द्वारा लिखी इस आवरण कथा के अश बताते हैं कि उन दिनो मुलायम सिह से सिद्धात सहमत ने होते हुए भी उनकी आलोचना करना कितना काम था।

दरअसल मुलायम सिह यादव की सरकार व्यवस्था परिवर्तन और विकास का सकल्प लेकर सत्ता मे आई थी। प्रेदश की जनता ने सहकारिता मत्री व विपक्ष के नेता के रुप मे उनके प्रभावशाली कार्यो व जनसेवा के प्रति वास्तविक समर्पण को देखते हुए उन्हे बडी उम्मीदो के साथ सत्ता के सिहासन पर बिठाया था। मुलायम सिह ने कुछ ही महीनो के भीतर राज्य का कायाकल्प प्रारभ कर दिया। उन्होने सांप्रदायिकता की समस्या पर काबू किया, जो प्रदेश के विकास की राह मे बहुत बड़ी बाधा थी। इसके बाद तो प्रदेश मे जन कल्याण और विकास का एक नया दौर शुरू हुआ। अपने सत्तारुढ़ होने के तीन-चार महीनो मे ही मुलायम सिह सरकार ने

---

2 - डा0 आर0 पी0 त्रिपाठी- मुलायम सिंह यादव, रचना और सघर्ष,- पृष्ठ 76

प्रदेश की सामाजिक, प्रशासनिक, औद्योगिक व आर्थिक स्थिति मे अभूतपूर्व परिवर्तन कर दिखाया। उन्होने समाज के निचले से निचले वर्गो और प्रदेश के उपेक्षित क्षेत्रो को भी विकास-प्रक्रिया मे शामिल किया और उनकी समस्याओ का निदान किया। सरकार ने चुनाव से पूर्व जनता से किए गए वायदे पूरे करने की दिशा मे भरपूर प्रयास किया। हालाकि साप्रदायिकता, समाज परिवर्तन की विरोधी और जोडतोड़ की क्षुद्र राजनीति मे सलग्न शक्तियो ने समय-समय पर समस्याए उत्पन्न कर प्रदेश मे विकास के चक्र को अवरूद्ध, करना चाहा। किंतु इससे श्री यादव की कर्त्तव्य भावना और दृढ सकल्प मे कोई कमी नही आई।

साप्रदायिकता निवारण की मुहिम के अतर्गत मुलायम सिह यादव ने दगो को होने से पहले ही रोकने के प्रयास किए। उन्होने घोषणा की कि दगो के लिए उस क्षेत्र के जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियो को जिम्मेदार माना जाएगा। यह उनकी दिखावटी चेतावनी ही नही थी, बल्कि मार्च 1991 मे उन्होने गोंडा के डीएम और बिजनौर के एसएसपी को भी इसी कारण हटाया था, सहारनपुर के जिला मजिस्ट्रेट व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मुअत्तल भी कर दिया था। सरकार ने इन दोनो अधिकारियो की लापरवाही की जाच के लिए अलग-अलग जाच भी बैठा दी।

14 जनवरी को प्रतापगढ मे हुइ एक 'फर्जी मुठभेड' मे पुलिस वालो ने तीन ग्रामीणो को मार डाला था। राज्य सरकार ने इस घटना के दोषी 12 पुलिस कर्मचारियो को, जिनमे एक पुलिस उप अधीक्षक भी था, मुअत्तल कर दिया।

प्रदेश सरकार ने जनवरी 1991 मे भारत मे पहली बार दगे रोकने के लिए विशेष शाति सुरक्षा बल के गठन का फैसला किया। इसमे सात बटालियने तैनात की जानी थी। इस पुलिस बल को 'सामाजिक, जातीय और सांप्रदायिक तनाव की चुनौतियो' का सामना करना था और इस पर 56 करोड रूपये की लागत आनी थी। शाति सुरक्षा बल को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसका पर्यवेक्षण कार्य राज्य के पुलिस महानिदेशक को सौपा गया और इसमे भर्ती होने वाले जवानो की सेवा अवधि 45 वर्ष की उम्र तक की रखी गई। उत्तर प्रदेश के इस फैसले की देश भर मे सराहना की गई और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक दगा विरोधी सुरक्षा बल के गठन का प्रस्ताव आया।

प्रदेश मे भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया गया और भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियो को दडित किया। गया प्रशासन को जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी और कर्त्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए योग्य व ईमानदार अधिकारियो को पदोन्नतियॉ व पुरस्कार दिए गए।

मुलायम सिह के निर्देशन मे उत्तर प्रदेश सरकार ने केद्र से वर्ष 1990-91 के लिए वार्षिक योजना के लिए 33 अरब 70 करोड़ रूपये की राशि मजूर कराने मे सफलता प्राप्त की, जबकि इससे पिछले वर्ष मे यह राशि 29 अरब 70 करोड रूपये ही थी। योजना राशि मे से 52 प्रतिशत परिव्यय ग्रामीण क्षेत्रो के विकास हेतु निर्धारित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रो का पिछडापन मिटाने और वहा मूलभूत सुविधाए उपलब्ध कराने की दिशा मे सरकार ने कई कदम उठाए। डा0 राममनोहर लोहिया का सपना पूरा करने के लिए खेतिहर मजदूरो और भूमिहीनो मे भूमि के विवरण के लिए 16 जिलो मे भूमि सेना का गठन किया गया। इसके तहत बजर, ऊपर व बीहड भूमि का विकास किया जाना था।[3]

मुलायम सिह सरकार महात्मा गाधी, डा0 राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण चौधरी चरण सिह के सपनो को पूरा करने की दिशा मे कार्यरत थी। इसीलिए उसने ग्रामीण क्षेत्रो के विकास और किसान, खेतिहर मजदूर व दस्तकार वर्ग के कल्याण के लिए अनेक महत्वाकाक्षी कार्यक्रम चलाए और कई घोषणाए की। राज्य सरकार ने किसानो, खेतिहार मजदूरो व दस्तकार वर्ग के कल्याण के लिए अनेक महत्वाकाक्षी कार्यक्रम चलाए और कई घोषाए की। राज्य सरकार ने किसानो, खेतिहार मजदूरो व दस्तकारो को दस हजार रूपये तक के ऋण माफ कर दिए जिससे सरकारी खजाने पर लगभग एक हजार करोड रूपये तक का बोझ पडा। इसका लाभ 49.66 लाख व्यक्तियो को मिला। एक अप्रैल 87 से 30 नवबर 89 तक 32 माह की अवधि के निजी नलकूप मालिको के करीब 200 करोड़ रूपये के बिजली बकाए माफ कर दिए गए। बिजली की कमी के बाजूद ग्रामीण क्षेत्रो मे प्रतिदिन 14 घटे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की गई।

किसानो की लबे समय से चली आई मागे पूरी करते हुए प्रदेश सरकार ने गन्ने के खरीद मूल्य मे भारी वृद्धि आठ रूपये प्रति क्विटल और 1991 मे तीन रूपये प्रति कुन्तल रही। इससे 29 लाख गन्ना उत्पादक किसानो को लाभ पहुंचा। गन्ना किसानों को चीनी मिल से गन्ने के मूल्य का

---

3 - डा0 आर0 पी0 त्रिपाठी- मुलायम सिह यादव, रचना और सघर्ष पृष्ठ 80

समय पर भुगतान सुनिश्चित किया गया। 1990 के पेराई सत्र मे 1256 करोड रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया, जबकि इससे पिछले सत्र मे 713 करोड रुपए ही दिए गए थे।

दिसबर 1989 के पश्चात उत्तर प्रेदश मे लगभग 52 हजार भूमिहीनो को 17 8 हजार हेक्टेयर भूमि वितरित की गई। इसी अवधि मे एक लाख से अधिक परिवारो को आवास स्थल भी आवंटित किए गए। 90 करोड़ रूपये की दैवी आपदा निधि की स्थापना की गई एव ओला वृष्टि से फसल के नुकसान पर काश्तकारो को 300 रूपये प्रति एकड़ की दर से राहत राशि का भुगतान किया गया। कृषि क्षेत्र मे शोध कार्य को सुनियोजित ढग से सपादित कराने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसधान परिषद का गठन किया गया।

मुलायम सिह सरकार ने प्रदेश मे क्षेत्रीय विषमताओ को दूर करने के लिए भी प्रयास किए। जिन क्षेत्रो मे विकास की गति कमजोर थी और जो बरसो से उपेक्षित पडे थे, उनके लिए राज्य सरकार ने 1990-91 और 1991-92 के बजट मे विशेष प्रावधान किए। पूर्वाचल विकास निधि मे 1990-91 मे 20 करोड व अगले वर्ष 30 करोड पए की राशि की व्यवस्था की गई। पूर्वाचल के मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर, बस्ती, आजमगंढ, सिद्धार्थनगर, महाराजगज, देवरिया, बहराइच व इलाहाबाद के जमुनापार (नैनी क्षेत्र को छोड़ कर) मे स्थापित की जाने वाली निर्दिष्ट औद्योगिक इकाइयो को बिजली के बिलो मे 20 प्रतिशत की छूट दी गई। बुदेलखड मे स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाइयो को पांच वर्ष के लिए बिजली के बिलो मे 50 प्रतिशत की छूट दी गई।

राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रो के विकास को भी प्राथमिकता के तौर पर लिया। इन क्षेत्रो के निवासियो के लिए सरकारी नौकरियो मे दो प्रतिशत का आरक्षण किया गया। पर्वतीय क्षेत्रो के विकास के लिए वर्ष 90-91मे 330 करोड रूपये और 91-92 मे 375 करोड रूपये की राशि का प्रावधान किया गया। 610 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थापित होने वाली औद्यौगिक इकाईयों को पाच वर्ष के लिए बिजली के बिलो मे एक तिहाई छूट दे दी गई। पर्वतीय क्षेत्र के पारपरिक ऊन उद्योग के विकास के लिए ऊन बैक की स्थापना की गई, जिसमे 12 हजार व्यक्तियो को रोजगार के अवसर सुलभ हुए। पर्वतीय क्षेत्रो मे रेशम उद्योग के विकास के लिए देहरादून जनपद मे विश्व बैंक की सहायता से 4.5 करोड़ रूपये की परियोजना लगाई गई। इन इलाको मे पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए नए पर्यटन नगर विकसित करने की दूरगामी योजना तैयार की गई।

मुलायम सिह सरकार सामाजिक न्याय के वायदे के साथ सत्ता मे आई थी। उसने अपना वायदा निभाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जिनमे पिछडी जातियो के लिए नौकरियो मे 27 प्रतिशत अरक्षण की व्यवस्था करना शामिल है। इतना ही नही, सामान्य जातियो के आर्थिक दृष्टि से पिछडे लोगो को भी राज्य सरकार की नौकरियो मे 8 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई। महिलाए लबे समय से उपेक्षित रही है। मुलायम सिह सरकार ने देश मे पहली बार उनके लिए 3 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की । पर्वतीय क्षेत्र के निवासियो के लिए सरकारी नौकरियो मे दो प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई।

शासकीय सेवाओ मे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण कोटे को भरने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। डा0 अबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के लिए सौ करोड रूपए की राशि मजूर की गई। 9,563 अनुसूचित जाति बहुल गावो के सर्वागीण विकास के लिए 'अबेडकर ग्राम' योजना चलाई गई। ग्रामीण क्षेत्रो मे अनुसूचित जाति के परिवारो हेतु एक लाख से अधिक आवास उपलब्ध कराए गए। अनुसूचित जाति-जनजाति के सौ-सौ छात्र-छात्राओ को हाईस्कूल व इटरमीडिएट मे सर्वोच्च अक प्राप्त करने पर डा0 अबेडकर निधि से 250 रूपये व 350 रूपये की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई। इन जातियो की छात्राओ को 240 रूपये मासिक की दर से भरण-पोषण अनुदान मजूर किया गया। इस तरह प्रदेश मे सामाजिक परिवर्तन की दिशा मे अल्पसमय मे ही आशाजनक कार्य हुआ जिसकी देशभर मे प्रशसा की गई।

मुलायम सिह सरकार ने निर्बल वर्गो को सामाजिक सुरक्षा दिलाने की दिशा मे कई कदम उठाए। विधवाओ,विकलागो व वृद्धो को मिलने वाली पेशन की दर 60 रुपए की जगह सौ रूपए प्रतिमाह कर दी गई। 12,46,772 निराश्रित विधवाओ को पेशन के भुगतान हेतु 29.53 करोड की व्यवस्था की गई। 53 हजार विकलागो के भरण-पोषण हेतु 7.45 करोड रूपये मजूर किए गए। प्रदेश भर मे वृद्धावस्था पेशन का लाभ पाच लाख व्यक्तियो तक पहुचाया गया। इस पर हर वर्ष 60 करोड़ ·पए का खर्च आया। स्वतत्रता सेनानियो की पेशन 401 रूपए प्रतिमाह से बंढाकर 500 रूपए कर दी गई। द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व सैनिको या उनकी विधवाओ के लिए सौ ·पए प्रतिमाह पेशन की व्यवस्था की गई जिससे 35 हजार परिवार लाभावित हुए। रिक्शा-आटो रिक्शा चालको व मछली-पालको के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू की गई। होमगार्डो के लिए भी बीमा योजना शुरू की गई।

लगभग 13 5 लाख जरूरतमद छात्रो के लिए 35 करोड रूपये की छात्रवृत्ति योजना लागू की गई। अनतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि एक हजार रूपए से बढाकर दस हजार पए कर दी गई। 35 वर्ष से कम उम्र की विधवाओ से विवाह पर 11 हजार रूपये के अनुदान की व्यवस्था की गई। प्रदेश सरकार अल्पसख्यक वर्ग को सुरक्षा उपलब्ध कराने और उसकी आर्थिक खुशहाली के लिए गभीरता से प्रयासरत थी। उसने 57 हजार बुनकरो के 22 करोड रूपये के ऋण माफ कर दिए। दगे रोकने के लिए शाति सुरक्षा बल की बटालियने गठित की गई। 1984 मे भडके दगो में मृत सिखो की विधवाओ की पाच सौ रूपये प्रतिमाह पेशन दी गई। अल्पसख्यक वर्ग की शिक्षा सस्थाओ मे व्यावसायिक प्रशिक्षण केद्रो की स्थापना की गई। निजी क्षेत्र के बुनकरो व रगाई, छपाई करने वाले व्यक्तियो को सामूहिक बीमा योजना का लाभ पहुचाया गया। बुनकरो को उचित दर पर कच्चा माल उपलब्ध कराने व निर्मित माल की बिक्री बढाने की व्यवस्था भी की गई।[4] सरकार ने युवको के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए। वर्ष 1991-92 के बजट मे रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने हेतु 50 करोड रूपये की विशेष निधि को स्थापना की गई। रोजगार उत्पन्न करने के लिए हर विकास खंड मे कम से कम 30 औद्योगिक इकाइया लगाने का फैसला किया गया।

राज्य मे महिलाओ के लिए नौकरियो मे तीन प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। ग्राम पचायतो मे 30 प्रतिशत पदो पर महिलाओ को आरक्षण दिया गया। महिला उद्यमियो को स्वरोजगार की ओर उन्मुख करने के लिए मार्जिन मनी ऋण योजना लागू की गई जिसके अतर्गत 30 करोड रूपये की राशि स्वीकृत की गई। श्रमजीवी महिलाओ के लिए छात्रावासो का निर्माण किया गया। इसके लिए प्रारभिक तौर पर लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी एव आगरा जनपद चुने गऐ। महिलाओ के लिए रोजगार कार्यक्रम समर्थन योजना भी चलाई गई।

औद्योगिक विकास व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य मे चुगी समाप्त कर दी गई। लघु एव कुटीर उद्योगो को प्रोत्साहन देने के लिए तीन लाख लघु खादी व ग्रामोद्योग इकाइयो की स्थापना का निर्णय किया गया। इनसे 25 लाख लोगो को रोजगार मिलेगा। सरकार ने मध्यम व बड़े उद्योगो के विकास को भी प्रोत्साहन दिया। औरैया मे गैस क्रेकर परियोजना व पेट्रो-रसायन परिसर की स्थापना, बुंदेलखड मे तेलशोधक कारखाना, बांदा मे फ्लोर ग्लास

---

4 - डा0 आर0 पी0 त्रिपाठी- मुलायम सिह यादव, रचना और सघर्ष- पृष्ठ 84-85

परियोजना की स्थापना, आदि की दिशा मे सरकार प्रयासरत रही। प्रदेश सरकार ने नोएडा की भाति जौनपुर-सतहरिया व गोरखपुर-सहजनवा मे औद्योगिक क्षेत्र के विकास की भी योजना बनाई।

मुलायम सरकार की अन्य प्रमुख उपलब्धियो मे दो नये जनपदो पडरौना व भदोही की स्थापना, कश्मीर से आये आर्थिक विस्थापितो के परिवारो को पुनर्वास हेतु प्रति परिवार 750 रूपये की मासिक आर्थिक सहायता देना व चौकीदारो का वेतन 25 रूपये से बढकर सौ रूपए प्रतिमाह करना शामिल है। मुलायम सिह सरकार ने समस्त प्रशासनिक कामकाज हिंदी मे करने का ऐतिहासिक फैसला किया और प्रादेशिक सेवाओ मे चयन के लिए अग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी। साथ ही प्रदेश मे दूसरे राज्यो की भाषाओ के पठन-पाठन हेतु आठ जनपदो मे विशेष व्यवस्था की गई।[5]

2-बदलाव के लिए सघर्ष

उत्तर प्रदेश मे मुलायम सिह यादव, बिहार मे लालू यादव, महाराष्ट्र मे शरद पवार और तमिलनाडु मे करुणानिधि की सरकार बन जाने का साफ मतलब था कि पहली बार राष्ट्रीय पैमाने पर एक गैर-ब्राह्मण राजनीतिक सस्कृति का उदय हो चुका है। ये सभी मुख्यमत्री विभिन्न दलो के होने के बावजूद पिछडे वर्ग के थे। इस परिस्थिति से बनने वाले राजनीतिक दबाव और घोषणा पत्र मे लिखित मडल आयोग की सिफारिशे लागू करने वाले वायदे का नैतिक दबाव प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिह को मजबूर कर रहे थे कि वे वह ऐतिहासिक कदम उठा ही दे जिसे काग्रेस टालती आ रही थी। लोकदल के नेता के रूप मे मुलायम सिह मडल सिफारिशो को लागू करवाने के लिए जेल यात्रा कर चुके थे।

मडल आयोग की सिफारिशे लागू करने का वायदा जनता दल के चुनाव घोषणा पत्र का प्रमुख तत्व था। सदियो से शोषित और सामाजिक दृष्टि से दयनीय जीवन यापन करने वाले पिछडे वर्ग को मडल आयोग की रपट मे न्याय और सुखद भविश्य की आशाए दिखाइ दे रही थी। आयोग ने अनुसूचित जाति व जनजाति के अतिरिक्त अन्य पिछडे वर्गो को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की थी। जनता दल के चुनावी वायदो से इस तबके की जनता की आशाएं बंधी थी और उन्होने उसे सत्ता मे लाने मे प्रमुख भूमिका निभाई। किंतु उसकी उम्मीदे जल्दी ही टूटने

---

5 - डा0 आर0 पी0 त्रिपाठी- मुलायम सिह यादव, रचना और सघर्ष , पृष्ठ 86

लगी, क्योकि जनता दल नेतृत्व मे बैठे सामंती तत्वो व काग्रेसी विचारधारा से निकल कर आए लोग सामाजिक महापरिवर्तन की आधी का सामना करने को तैयार नही थे। समाज के शोषित वर्ग के प्रति उनकी प्रतिबद्धताए वोट बटोरने तक ही सीमित थी और उनका कोई इरादा नही था। दूसरी ओर, मुलायम सिह समेत समाजवादी पृष्ठभूमि वाले नेता इस दिशा मे तत्काल कदम उठाए जाने के प्रबल समर्थक थे। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियो मे पार्टी के नेतृत्व पर उनकी पकड नही थी, इसलिए अपनी तमाम चिताओ के बावजूद के विवश थे।[6]

मडल आयोग का गठन 1979 मे जनता पार्टी की सरकार ने किया था और आयोग ने दिसबर 1980 मे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इदिरा गांधी को अपनी रपट सौप दी थी। श्रीमती गाधी वैसे तो दलितो व शोषितो की राजनीति करती थी और अपने आपको इस वर्ग की सबसे बडी हितचितक के रूप मे प्रचारित करती थी, किंतु पिछडे वर्ग के वास्तविक कल्याण हेतु प्रस्तुत की गई मडल आयोग की सिफारिशो की उन्होने पूरी तरह उपेक्षा की। उनके बाद सत्ता मे आये उनके पुत्र राजीव गाधी ने भी इन्हे लागू करने की कोई परवाह नही की। इसे देखते हुए जनता पार्टी व लोकदल ने पिछड़ो को उनका हक दिलाने के लिए सघर्ष छेडा और मुलायम सिह ने इसमे विशेष भूमिका निभाई। दूसरी ओर जनमोर्चा की पृष्ठभूमि वाले नेताओ ने, जो उस समय काग्रेस सरकार मे जिम्मेदार पदो पर कार्यरत थे और सरकार की नीतियो पर प्रभाव डालने की स्थिति मे थे, इस मामले मे चुप्पी साधे रखी। पूरे दस वर्ष की अवधि मे उन्होने आयोग की सिफारिशो के समर्थन मे दो शब्द भी नही कहे और चुपचाप सत्ता का सुख भोगते रहे। बाद मे यही नेता मजबूरी मे कांग्रेस (इ) छोड़ कर जनमोर्चा मे और फिर जनता दल मे आये तो उनकी मूलभूत विचारधारा मे कांग्रेसी और सामती तत्व ज्यो के त्यो मौजूद थे। यह अलग बात थी कि तत्कालीन परिस्थितियो मे जनता दल पर उनका नियत्रण मजबूत हो गया था।

जनता दल मे सत्तारूढ होने के बाद भी जब मंडल आयोग की रपट की उपेक्षा जारी रही तो पिछडे व दलित वर्गो मे निराशा व आक्रोश की भावना पैदा हुई। जनता की आकाक्षाओ को धूमिल होते देखकर समाजवादी नेताओ का चितित होना स्वाभाविक था। उन्होने केद्र सरकार पर आयोग की सिफारिशे लागू करने के लिए दबाव डाला। मुलायम सिह व अन्य नेताओ का मानना था कि इन्हे लागू किए बिना पिछड़े वर्ग को वास्तविक सामाजिक न्याय दिलाना सभव नही है और

[6] - डा0 आर0 पी0 त्रिपाठी- मुलायम सिह यादव, रचना और सघर्ष, पृष्ठ 102

जन आक्रोश को खाली आश्वासनो के सहारे दबाया नही जा सकता । वे प्रख्यात समाजवादी नेता डा0 राममनोहर लोहिया के सिद्धातो के अनुगामी थे, जिन्होने पिछडे वर्गा को आरक्षण दिये जाने को परिवर्तन के औजार के रूप मे सदैव समर्थन किया। जनता दल नेतृत्व ने जब बहुसख्यक वर्ग की आकाक्षाओ की उपेक्षा जारी रखी तो मुलायम सिंह को जनता से कहना पडा कि शायद अब भी उसे अपने लिए सघर्ष करने की आवश्यकता है, हालाकि अब केद्र मे काग्रेस (इ) की सरकार नही रह गई है। यह अजीब विडबना है कि मडल आयोग की रपट की घनघोर उपेक्षा करने और उसे अपने राजनीतिक स्वार्थो की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करने वाले नेता आज पिछडो के सबसे बडे हितचितक होने का दावा कर रहे है।

जनता दल सरकार का कामकाज करने का लापरवाही भरा ढर्रा, जनता की आकाक्षाओ के प्रति उपेक्षा भाव और जनाधार व सिद्धात वाले नेताओ का प्रभाव सीमित करने की कोशिशो के कारण जनता दल मे असहमति की आवाजे उठने लगी। तत्कालीन उपप्रधानमत्री देवीलाल ने ग्रामीण भारत व किसानो की उपेक्षा का मुद्दा उठाया और समाजवादियो ने पिछडे वर्ग के लिए न्याय मागा। लेकिन जोड-तोड़ व सिद्धातहीनता की क्षुद्र राजनीति मे विश्वास रखने वाले जनमोर्चा गुट के नेताओ ने, जिनके साथ मे पार्टी नेतृत्व का दारोमदार था, इसे सकारात्मक भावना से नही लिया। उन्हे लगा कि किसानो व पिछड़ो की बात करने वाले पार्टी नेताओ का राजनीतिक कद छोटा करने की जरूरत है, अन्यथा वे आगे चल कर लोकप्रियता के शिखर पर पहुच सकते है और ऐसी हालत मे उनकी कुटिलतापूर्ण राजनीति विफल हो सकती है। पार्टी नेतृत्व की मनमानी का पहला शिकार उपप्रधानमत्री देवीलाल हुए जिन्हे पहली अगस्त 1990 की रात को अपमानजनक ढग से पद से हटा दिया गया।

देवीलाल ने नौ अगस्त को नई दिल्ली के बोट क्लब पर रैली का आयोजन करने की घोषणा की जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार को किसान शक्ति से परिचित कराना और किसानो की उपेक्षा समाप्त करने पर विवश करना था। यह रैली देवीलाल की राजनैतिक हैसियत और जनता मे उनकी लोकप्रियता की परिचायक भी सिद्ध होने वाली थी। रैली को विफल करने, देवीलाल के उठायेसमस्त मुद्दों को अप्रासंगिक करार देने और उन्हे नीचा दिखाने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिह ने मंडल आयोग की रपट लागू करने की घोषणा की जिसे तब तक उन्होने पूरी तरह उपेक्षित कर रखा था। ऐसा करते समय उन्होंने धूर्त राजनीतिक चालबाजी और मनमानी का परिचय दिया

और सरकार के समर्थक दलो-भाजपा व कम्युनिस्ट पार्टियो से भी राय मशविरा करने की आवश्यकता नही समझी। इतना ही नही, उन्होने इतना महत्वपूर्ण निर्णय पूरी तरह व्यक्तिगत रुप से लिया और उसे सरकार के सामूहिक फैसले का रूप नही लेने दिया। इसका कारण स्पष्ट था- श्री सिह आयोग की रपट का सपूर्ण श्रेय स्वयं लेना चाहते थे। लेकिन उनकी इस स्वार्थवृत्ति का देश को बहुत बडा नुकसान उठाना पडा।

सभी प्रमुख पार्टियो ने विश्वनाथ प्रताप सिह के तौर-तरीको का विरोध किया।हालाकि उनमे से कोई भी मडल आयोग की रपट लागू किये जाने की खुलेआम आलोचना करने को तैयार नही, पर वे इस कार्य का सपूर्ण राजनीतिक श्रेय एक व्यक्ति विशेष को देने पर भी सहमत नही थे इसका परिणाम यह हुआ कि इन दलो ने सरकार और उसके फैसले का परोक्ष विरोध शुरू कर दिया। रातोरात आरक्षण विरोधी सगठनो की फसल उग आई और सपूर्ण उत्तर भारत मे हिसक आदोलन शुरू हो गया। सवर्ण वर्ग के निराश युवको ने आत्मदाह करने शुरू कर दिये। इधर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के दो सदस्यो राम विलास पासवान और शरद यादव को पिछडे वर्ग के नेता के रूप मे पेश किया और इस वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश की। लेकिन उनके अदूरदर्शितापूर्ण व उत्तेजक बयानो ने आग मे घी का काम किया। आरक्षण विरोधी आदोलन दिन पर दिन जोर पकडता गया और राजधानी दिल्ली समेत देश के अनेक क्षेत्रो मे कानून-व्यवस्था की स्थिति पंगु होकर रह गई। विश्वनाथ प्रताप सिह ने स्थिति मे सुधार लाने या आदोलनकारियो व अन्य राजनैतिक दलो से बातचीत करने की कोई जरूरत नही समझी, क्योकि उन्हे पिछडे वर्ग की अधिक से अधिक सहानुभूति और समर्थन जुटा लेने का लालच था। उनका विचार था कि आदोलन जितना भड़केगा, अगडी और पिछडी जातियो मे विभेद जितना बढेगा, पिछडी जातियां उसी अनुपात मे उनके समर्थन मे एकजुट होगी।

मडल आयोग का मुद्दा श्री सिह के लिए राजनीतिक लाभ उठाने से अधिक कुछ नही था, यह बात बाद मे उनके द्वारा की गई घोषणाओ से स्पष्ट हो गई। उन्होने आयोग की सिफारिशे लागू करने का मामला राज्य सरकारो की इच्छा पर छोड दिया जिसके बाद उनकी अपनी पार्टी की ओडीशा सरकार ने ऐसी घोषणाए की। श्री सिह ने शिक्षण सस्थाओ व कई विशिष्ट सेवाओ को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने, पदोन्नतियो मे आरक्षण लागू न करने जैसी घोषणाए की जिनसे इस बारे मे उनके इरादो पर शक पैदा होता है। इन घोषाणाओ से मडल आयोग की रपट की

आत्मा ही नष्ट हो गई। और उनके उद्देश्य काफी सीमित हो गये। ये घोषणाए श्री सिह ने सामाजिक न्याय की विरोधी शक्तियो के तुष्टीकरण के लिए की। साथ ही उन्होने उच्चतम न्यायालय से मडल आयोग की रपट लागू करने पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगाने का अनुरोध कर इस मुद्दे को लबी अदालती प्रक्रिया के हवाले छोड दिया। इस तरह उन्होने पिछडे वर्ग के लिए कुछ किए बिना ही उसका समर्थन बटोरने की कुटिलतापूर्ण चाले चली दूसरी ओर मडल आयोग के मामले मे मुलायम सिह का दृष्टिकोण एकदम अलग था। वे उसकी सिफारिशो के प्रबल समर्थक थे और उन्हे बिना किसी छेडछाड के लागू करवाने पर जोर दे रहे थे। दूसरी ओर उनका यह भी मानना था कि इस मामले को इस तरह न उछाला जाए कि अगडे वर्ग के नौजवानो मे हताशा व आक्रोश फैले। शरद यादव व राम विलास पासवान ने जिस टकराव के अदाज मे भाषण दिए और पिछडो से सडको पर उतरने का आह्वान किया उसके वे पूरी तरह खिलाफ थे। मुलायम सिह चाहते थे कि अगडे वर्ग को मडल आयोग की सिफारिशे स्वेच्छा से स्वीकार करने के लिए मनाया जाए। वे अपनी सभाओ मे लोगो को समझाते थे कि पिछडे वर्ग के साथ सदियो से अन्याय होता आया है और अब उसे अपने विकास का एक अवसर दिया ही जाना चाहिए। उच्च वर्ग को चाहिए कि वह उदारता से काम लेते हुए पिछड़े वर्ग को उसका जायज हक हासिल करने दे। मुलायम सिह के विचारो का लोगो पर काफी असर पड़ा और प्रदेश मे उसके विशाल आकार और जनसख्या के अनुपात मे उतनी हिंसा व उतने आत्मदाह नही हुए जितने कि अन्य प्रदेशो और दिल्ली मे।

पिछडे व हरिजन वर्ग को न्याय दिलाने के लिए मुलायम सिह की प्रतिबद्धता कोई अचानक पैदा नही हो गई थी, बल्कि वे अपने राजनीतिक जीवन के आरभ से ही इस लक्ष्य के प्रति समर्पित थे 1977 मे जनता पार्टी की सरकार मे सहकारिता मत्री के रूप मे जब उन्होने ऐतिहासिक उपलब्धिया अर्जित की तबभी उन्होने इस दिशा मे कदम उठाए थे। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (सशोधन) विधेयक के माध्यम से उन्होने सहकारी समितियो के चुनावो मे हरिजन और निर्बल वर्गो के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। इसी प्रकार जनता पार्टी के सत्ता से हटने के बाद उन्होने मंडल आयोग की सिफारिशे लागू करवाने के लिए प्रदेश व्यापी आदोलन चलाया था। जब जनता दल सरकार ने केद्र मे सत्तारूढ़ होने के बाद ससद व विधानसभओ मे अनुसूचित जातियो व जनजातियो के लिए आरक्षण की अवधि दस वर्ष बढाने के लिए कदम

उठाए तो श्री यादव ने उसका पूरा समर्थन किया। इसके खिलाफ उठे आदोलनो का उन्होने कठोर जवाब दिया।

जब केद्र ने के मडल आयोग की सिफारिशे लागू करने का मामला प्रदेश सरकारो पर छोड दिया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना कोई समय नष्ट किए अक्टूबर 1990 के पहले सप्ताह से राज्य सरकार की नौकरियो मे कुल आरक्षण का कोटा 50 प्रतिशत से बढाकर 62 प्रतिशत कर दिया। राज्य मे अनुसूचित जाति व जनजाति के अतिरिक्त अन्य पिछडे वर्गो के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था चल रही थी जिसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि 15 प्रतिशत आरक्षण भी राज्य मे जनता पार्टी की सरकार के समय 20 अगस्त 1977 को लागू किया गया था। यह व्यवस्था सरकारी नौकरियो मे पदोन्नतियो के मामलो मे भी लागू थी, पर 30 सितबर 1981 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमत्री विश्वनाथ प्रताप सिह ने पदोन्नतियो मे आरक्षण समाप्त कर दिया था। आज वही विश्वनाथ प्रताप सिंह पिछडे वर्ग के मसीहा का चोला धारण कर चुके है।

मुलायम सिह का मानना था कि पिछडी जातियो को आरक्षण का लाभ देना अत्यत आवश्यक है, पर ऊची जातियो के गरीबो व पिछडो की केवल इस कारण उपेक्षा नही की जा सकती कि उनका जन्म पिछडे वर्ग मे नही हुआ। इसके अतिरिक्त महिलाओ की स्थिति समाज मे सर्वाधिक पिछड़ती हुई है, पर उनके साथ अब तक न्याय नही हुआ है। विश्वनाथ प्रताप सिह की भाति सकीर्ण दृष्टिकोण से काम लेने के बाजय उन्होने उदार और व्यापक नजरिया अपनाया। 31 मार्च 1991 को श्री यादव ने प्रदेश की सरकारी नौकरियो मे ऊंची जातियो के पिछडो को आठ प्रतिशत, महिलाओ को तीन प्रतिशत और पिछडे पहाडी प्रदेश के लोगो को दो प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की। इस तरह राज्य की प्रथम व द्वितीय श्रेणी की नौकरियो मे कुल आरक्षण कोटा 70 प्रतिशत और तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियो मे 68 प्रतिशत हो गया। मुख्यमंत्री के रुप मे श्री यादव ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कालेजो मे भी पिछडी जातियो के आरक्षण की सुविधा देने की घोषणा की। इस तरह उन्होने समाज के सभी शोषित वर्गो को वास्तविक रूप से न्याय दिलाने व उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए गंभीर व ईमानदार प्रयास किए। उन्होने वोटो की राजनीति की खातिर आरक्षण का इस्तेमाल करने के लिए विभिन्न जातियो का आपस में लडाने के बजाय सामाजिक एकात्मकता बनाए रखते हुए अपने दायित्व पूरे करने को वरीयता

दी। यही वजह है कि आज श्री यादव धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक बदलाव के सघर्ष के प्रतीक बन गए है।[7]

3-समाजवादी पार्टी ही क्यो

समाजवादी पार्टी यो तो काग्रेस समाजवादी पार्टी के नाम से 1934 ई0 मे ही पटना के अजुमन इस्लामिया हाल मे अचार्य नरेन्द्र देव जी के सभापतित्व मे बनाई गई थी, परन्तु इसके पहले ही वाराणसी (उ0 प्र0), बिहार, दिल्ली, पजाब और बम्बई मे समाजवादी सगठन को कुछ लोगो ने बनाया था। इसके पहले काग्रेस पार्टी 1884 ई0 मे, 1925 ई0 मे कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ,एव हिन्दुमहा सभा आदि पार्टिया बन चुकी थीं। 1950 ई0 मे राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ का राजनीतिक मच के रूप मे जनसघ की स्थापना हुई। उस समय इसका नाम कांग्रेस समाजवादी पार्टी था।कँाग्रेस नाम इसलिये जोडा गया था क्योकि देश उस समय गुलाम था और गुलाम देश मे समाजवाद की स्थापना करना हमारे लिये सम्भव नही था। उस समय कॉग्रेस देश की गुलामी को खत्म करने का एक बडा मच था। उस मच से अलग रहकर हमारे लिये सम्भव नही कि हम आजादी हासिल कर सके।इसलिये कॉग्रेस को सबल बनाकर समाजवादी विचार का प्रचार-प्रसार करने का उद्देश्य हमारा था। उस समय श्री जय प्रकाश नारायण ने स्थापना सम्मेलन मे कहा था "हम यह नही कहते है कि काग्रेस को समाजवाद का पूरा कार्यक्रम स्वीकार करना चाहिए। किंतु हम यह जरूर कहते और चाहते है कि काग्रेस को कम से कम एक ऐसा आर्थिक कार्यक्रम तैयार कर स्वीकार कर ही लेना चाहिये जिसे काम मे लाने पर जनता को शोषण से मुक्ति मिल सके और राजनैतिक, आर्थिक सत्ता इनके हाथो मे आ जाये। काग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ऐसा ही कार्यक्रम देश के सामने रख रही है। पार्टी का वह कार्यक्रम क्या हो? मूल उद्योगो के राष्ट्रीयकरण के अतिरिक्त स्वराज्य सरकार को और क्या-क्या कार्यक्रम करने है, जिससे जनता को पूरी आर्थिक आजादी प्राप्त हो सके और यह शोषण अन्याय, दुख, दरिद्रता और अज्ञानता से मुक्ति पा जाये।

इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए उस सम्मेलन मे एक 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। उस सम्मेलन मे ही जय प्रकाश नारायण के अतिरिक्त सर्वश्री आचार्य नरेन्द्र देव, यूसुफ मेहर अली, अच्युत पटवर्द्धन, मीनू

---

7 - डा0 आर0 पी0 त्रिपाठी- मुलायम सिह यादव, रचना और सघर्ष पृष्ठ 110

मसानी, डा0 राम मनोहर लोहिया, सेठ दामोदर स्वरूप मोहन लाल गौतम, फरीदुल हक असारी मुन्शी अहमद दीन, अशोक मेहता शिवनाथ बनर्जी, गगाशरण सिह, रामवृक्ष बेनीपुरी और बिहार के एक दर्जन लोग थे। महिलाओ मे श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय, श्रीमती सत्यवती देवी (दिल्ली), श्रीमती मालती चौधरी (कटक) आदि कई महिलाए थी। पार्टी का एक मूल आधार सिद्धात होता है और उसी के सन्दर्भ मे तय की गयी नीति और बनाये कार्यक्रम के अनुसार पार्टी चलती है उसके बाद पार्टी के कई तरह के स्वरूप उभरे परन्तु स्वतत्रता प्राप्ति के बाद जो 1952 मे नये सविधान के अनुसार वयस्क मताधिकार के आधार पर देशव्यापी पहला चुनाव हुआ, उसमे पार्टी को वोट तो 10 प्रतिशत अवश्य पडा, परन्तु लोकसभा और विधानसभाओ मे पार्टी को बहुत कम सीट मिली। इससे पार्टी के शीर्ष नेताओ पर बुरा प्रभाव पडा। उन्होने कॉग्रेस से टूटकर कृषक मजदूर प्रजा पार्टी का जो गठन किया था, उसमे विलय कर समाजवादी पार्टी का नाम प्रजा समाजवादी पार्टी रख दिया। 1947 के बाद पार्टी ने 'काग्रेस' शब्द को हटाकर मात्र समाजवादी पार्टी के रूप मे काम किया परन्तु काग्रेस से निकले जमात के साथ मिलने पर पार्टी के सिद्धात मे मिलावट आ गयी। फलस्वरूप कई तरह की फूट कई बार पार्टी मे हुई। उसके बाद का इतिहास विचारो के आपसी सघर्ष का भी रहा डा0 राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता और जयप्रकाश नारायण के विचारो मे टकराहट होती रही। आचार्य नरेन्द्र देव ही एक ऐसे सर्वमान्य नेता थे जो इसे ठीक कर सकते थे परन्तु वे अपने गिरते स्वास्थ्य और अनुशासन प्रियता के चलते कई जगह चुप रह गये या ममतावश कठोर निर्णय न ले सके।

बाद मे डा0 राम मनोहर लोहिया ने इसे समझा और उन्होने पचमढी सम्मेलन मे समाजवादी सिद्धात, नीति और कार्यक्रम का एक स्पष्ट रूप देश के सामने रखा। जो पार्टी में विघटन हुए थे उसका फिर मिलन हो गया और सयुक्त समाजवादी पार्टी के नाम से पार्टी का गठन हो गया। इस पार्टी से भी एक अच्छी खासी जमात सत्ता मे साझेदारी के लिये कॉग्रेस पार्टी मे चली गयी। जिसका नेतृत्व श्री अशोक मेहता ने किया और उन्होने एक थीसिस "पिछड़ी अर्थनीति की बाध्यता" शीर्षक से देश के सामने रखी। जो समाजवादी बचे वे डा0 राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व मे सघर्षरत रहे। लेकिन डा0 राम मनोहर लोहिया ने गैर कॉग्रेसवाद का नारा देकर एक बार कॉग्रेस के एकाधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया। इस प्रयास मे अच्छी खासी सफलता मिली। फलस्वरूप पंजाब से बगाल तक देश के नौ राज्यो मे पहले-पहले गैर

कॉग्रेसी सरकारे बन गयीं। सरकारे बन तो गयी, परन्तु सारे राज्यो मे भिन्न-भिन्न पार्टियो की मिली-जुली सरकारे रही और सबके मुख्यमत्री दल-बदलू कॉग्रेसी ही रहे। इससे सरकार द्वारा कोई मूलभूत परिवर्तन का काम नही हो सका। इसका बहुत बुरा असर समाजवादी पार्टी के ऊपर भी पडा। बिहार विधानसभा मे कॉंग्रेस के बाद सबसे बडी पार्टी समाजवादी पार्टी ही थी। उसमे सत्ता विरोध के चलते फूट हो गयी और समाजवादियो ने ही बड़ी सख्या मे टूटकर शोषित दल का गठन कर श्री बिन्देश्वरी प्रसाद मण्डल के नेतृत्व मे कॉग्रेस की मदद से बिहार मे सरकार बनाने का काम किया। जो सविद सरकार समाजवादियो की थी, जिसने बिहार के भीषण अकाल मे बहुत ही सराहनीय काम किया था, उसके जब रचनात्मक काम करने का समय आया तो अपने ही घर के चिराग से अपने ही घर मे आग लग गयी। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी 1976 ई0 तक चलती रही और भिन्न-भिन्न जगहो मे इसके नेतृत्व मे शोषण के खिलाफ जातीय विषमता के खिलाफ गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ ग्रामीण व गरीबो के कष्ट के खिलाफ, कारगर आन्दोलन होते रहे।

1974 मे विद्यार्थियो का आन्दोलन बिहार मे प्रारम्भ हुआ, उसे जय प्रकाश नारायण का नेतृत्व मिल जाने के कारण एक जन-आन्दोलन का स्वरूप हासिल कर लिया। जय प्रकाश नारायण भू-दान आन्दोलन से निराश हो गये थे। इस आन्दोलन से उनको भी प्रेरणा मिली और ढलती उम्र मे भी युवा आन्दोलन का बडे उत्साह के साथ नेतृत्व दिया। फलस्वरूप काग्रेस की सरकारें हिल गयीं और इसी बीच श्रीमती इन्दिरा गॉधी समाजवादी नेता राज नारायण से इलाहाबाद हाई कोर्ट से चुनाव का मुकदमा हार गयी। जहॉ श्रीमती गॉधी को सदन की सदस्यता समाप्त होने से अपने पद से इस्तीफा देना था वहॉ पद की रक्षा के लिये कुर्सी मोह मे पडकर आपातकाल की घोषणा देश मे कर दीं। फलस्वरूप एक ही दिन मे हजारो विरोधी पक्ष के नेता और कुछ काग्रेस के भी नेता जो इन्दिरा गॉधी के इस कार्य के विरोधी थे, उनकी गिरफ्तारी हो गयी। 1977 मे आपातकालीन घोषणा हटा ली गयी और ये सभी नेता जेल से छोड दिये गये। देश की अधिकाश जनता इन्दिरा गॉधी के इस अत्याचार के विरोध मे चली गयी और जय प्रकाश नारायण के आह्वान पर जिन पार्टियो के लोग इस आन्दोलन के शरीक हुए वे सब मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़े। उस चुनाव मे इन्दिरा गॉधी और उसकी पार्टी की पराजय हो गयी और दिल्ली मे सर्वप्रथम एक गैर कॉंग्रेसी सरकार का गठन हो गया। श्री जयप्रकाश नारायण के दबाव

से जनता पार्टी का गठन किया गया समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी का पूर्ण विलय जनता पार्टी मे कर लिया। आज की भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसघ के नाम से थी। जनसघ का तो जनता पार्टी मे अवश्य विलयन हुआ परन्तु उसकी मूल प्रमाण आर0 एस0 एस0 ज्यो का त्यो बनी रही। जनता पार्टी की जो सरकार बनी, उसके भी प्रधानमत्री मोरारजी भाई देसाई बनाये गये। मोरारजी देसाई मे अनेंको गुण थे परन्तु इन चार पार्टीयो के मिले हुए सगगठन को चलाने मे वे सक्षम साबित नही हो सके। अब इसमे किसका कितना दोष रहा यह आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। मेरी राय मे यह पार्टी नकारात्मक कार्यक्रम को लेकर बनी थी। इसके आगे ठोस सिद्धात नही था। केवल एक लक्ष्य था, काग्रेस को सत्ता से हटा देना। कम ही दिनो मे आपसी विरोध के चलते यह सरकार टूट गयी और फिर श्रीमती गॉधी पुन सरकार बनाने मे सफल हो गयीं। समाजवादी विचार के लोग भिन्न-भिन्न जगह मे बिखरे थे और मायूसी की स्थिति मे पडे हुए थे।

समाजवादी पार्टी ने स्वतत्रता सग्राम से लेकर आज तक अपनी पार्टी को जो भी क्षति पहुचाई हो परन्तु देश को हमेशा एक नयी दिशा देने का काम किया है। सबस बडा नुकसान समाजवादी पार्टी को तब हुआ जब 1977 मे पार्टी ने अपने को समाप्त कर जनता पार्टी मे विलय कर दिया।जनता पार्टी मे एक राय नही थी और उसमे मिलने वाली और उसमे मिलकर जिन पार्टियो ने एक पार्टी बनायी थी वे सब के सब अपने को अलग गिरोह बनाकर काम कर रहे थे। इसका जो नतीजा हुआ वह देश के सामने है। समाजवादी विचार के जो लोग थे उनमे से अधिकाश को घुटन हो रहा था और कुछ सत्ता के मोह मे कुछ पाकर प्रसन्न भी थे यह स्थिति 1977 से 1991 तक बनी रही, इस बीच भिन्न-भिन्न नाम से कई दल बने जिसमे समाजवादी लोग भी घूमते रह गये। 1992 के अन्त मे कुछ समाजवादी विचार के लोगो ने इकटठे होकर इस स्थिति पर विचार किया और श्री मुलायम सिह के नेतृत्व मे पुन समाजवादी पार्टी का गठन किया। इस गठन के बाद इसका प्रथम सम्मेलन जो लखनऊ मे हुआ उसमे यह साफ निर्णय लिया गया कि भविष्य मे समाजवादी पार्टी किसी के साथ विलय नही करेगी परन्तु कार्यक्रम के आधार पर समयानुसार राष्ट्रहित मे समझौता करने को तैयार रहेगी। समाजवाद पार्टी के गठन से इस देश और बाहर के जिन लोगों ने समझा था कि समाजवादी पार्टी समाप्त हो गयी और अन्य मायूस होकर अनमनस्यता की स्थिति मे चले गये थे उनमे भी कुछ आशा का संचार हुआ। इस पार्टी के

सगठन का वर्ग चरित्र, थोडा साम्यवादी पार्टी से मिलता है परन्तु रूस के विघटन के बाद और दुनिया के कई कम्युनिस्ट देशो की सरकारो और पार्टियो के पतन के बाद जो एक प्रचार विश्वव्यापी शुरू हुआ है कि समाजवादी सिद्धात के दर्शन उसके आर्थिक और राजनीतिक स्थिति विफल हो चुकी है, और दुनिया के विकास का एकमात्र पुजीवादी अर्थ नीति जिसका मुख्य आधार मुक्त व्यापार और अनियत्रित अर्थव्यवस्था है, यही केवल सार्थक है और रहेगा। परन्तु यह भ्रम है। समाजवादी नेता आचार्य नरेन्द्र देव और डा0 राममनोहर लोहिया ने आज से 50 वर्ष पहले यह भविष्य वाणी की थी कि जिस रास्ते से रूस मे सरकार और पार्टी चलाई जा रही है यह अधिक दिनो तक चलने वाली नही है, क्योकि इसमे जनतात्रिक अधिकारो पर भी पाबन्दी है, और यह एक तरह से पार्टी तानाशाही के आधार पर चलाई जा रही है। रूस के समाजवादी व्यवस्था के पतन के अनेको कारण हैं परन्तु उसमे से मुख्य कारण यह भी एक रहा है। आज जहा समाजवादी व्यवस्था कम्युनिस्ट पार्टीयो द्वारा चलाई गयी है वहां भी अर्न्तविरोध के चलते गडबडिया हुई है। और जो अभी पूजीवादी व्यवस्था के अधीन मुक्त और भू मडलीकरण, उदारीकरण के आधार पर मुक्त पूंजी निवेश का काम दुनिया मे चल रहा है इसके भीतर भी अर्न्तविरोध मौजूद हैं। इस अंर्तविरोध का ज्वलन्त उदाहरण अधिकाश लोगो की बढती बेरोजगारी, गरीबी व अनियत्रित अर्थव्यवस्था विधिव्यवस्था की बिगडती स्थिति समाज मे नैतिक मूल्यो का पतन, और अराजकता की स्थिति का सन्देह सारे विचारशील लोगो को दिग्भ्रमित करता रहा है। इस स्थिति मे लोकतात्रिक समाजवाद ही एक मात्र रास्ता (विकल्प) दिखलाई पड़ता है।

देश मे आज भी कुछ समाजवादी लोग अलग-अलग भिन्न-भिन्न मोर्चा वगैरह बनाकर गोष्ठी आदि का काम कर लेते हैं। जिसमे उड़ीसा के श्री किशन पटनायक और महाराष्ट्र के कुछ पुराने समाजवादी लोग राष्ट्र सेवादल के साथ गोष्ठी आदि करते है। ये सभी लोग एक समाजवादी सगठन बनाने की चाह जरूर रखते है परन्तु वैसा कर नही पाते है। जो सगठन श्री मुलायम सिह यादव की अध्यक्षता मे बना है उसके संविधान मे पार्टी का लक्ष्य और उद्देश्य ये है -

1- समाजवादी पार्टी की भारत के सविधान मे सच्ची निष्ठा और श्रद्धा है। गॉधी जी और डा0 लोहिया के आदर्शो से प्रेरण लेकर समाजवादी पार्टी लोकतत्र धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद मे आस्था रखेगी। समाजवादी पार्टी का विश्वास ऐसी राज व्यवस्था मे है,

जिसमे आर्थिक एव राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीयकरण निश्चित रूप से हो। पार्टी शान्तिमय तथा लोकतान्त्रिक तरीको से विरोध प्रकट करने के अधिकार को मान्यता प्रदान करती है, इसमे सत्याग्रह तथा शान्तिपूर्ण विरोध शामिल है।

2- धर्म पर आधारित राज्य की अवधारणा का समाजवादी पार्टी विरोध करती है और धर्म पर आधारित राज्य मे आस्था रखने वाले किसी भी सगठन का कोई भी सदस्य समाजवादी पार्टी का सदस्य नही हो सकेगा।

इससे यह साफ पता चलता है कि आज भी दुनिया मे समाजवादी पार्टी का जो सिद्धात होना चाहिये वह इन वाक्यो मे निहित है यो किसी भी पार्टी का प्राण उसका सिद्धात होता है सिद्धात को कैसे कार्यरूप मे परिणित किया जाये, इसके लिये पार्टी की नीति होती है और उसी नीति के अनुरूप समय, परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति और निवासियो जो किसी भी तरह के शोषण के शिकार हैं, उनकी स्थिति मे सुधार और बदलाव लाने के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। इसलिये किसी पार्टी को समझने के लिए सिद्धात नीति और उसके द्वारा समय-समय पर निर्धारित कार्यक्रम को जान लेना आवश्यक ही नही अनिवार्य भी है। आज अपने देश मे असली रूप मे समाजवादी पार्टी के केवल इसी पार्टी को माना जा सकता है। इस समाजवादी पार्टी का प्रभाव क्षेत्र सबसे सबल उत्तर प्रदेश मे है। जिसकी जनसख्या करीब 17 करोड की है। चुनाव के दृष्टिकोण से भी देखा जाय तो उत्तर प्रदेश की सबसे बडी पार्टी समाजवादी पार्टी ही है। देश के कुल 28 राज्यो मे से केवल पूर्वांचल के आसाम से निकाल कर कुछ छोटे राज्यो को छोडकर सभी राज्यो मे इसके राज्य सगठन है और सगठन का आधार सदस्यता ही है। उसी आधार पर पार्टी का सगठनात्मक ढॉचा खडा किया जा सकता है।अभी 4 व 5 जनवरी सन् 2002 को पार्टी का पचम राष्ट्रीय सम्मेल कानपुर मे सम्पन्न हुआ है पार्टी का सदस्य तीन वर्षो के लिए 10 रुपया शुल्क देकर बन जाता है और जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी के 50 साधारण सदस्यो की भर्ती करे, कार्यशील सदस्य माना जायेगा और पार्टी का पदाधिकारी वही सदस्य हो सकता है । इस पार्टी ने प्रारम्भ से ही अब तक अनेको सघर्ष किये हैं और लोकसभा से लेकर ग्रम पचायतो तक अनेको चुनाव लडे हैं। चुनाव के नतीजे भी आज की परिस्थिति मे अच्छे ही कहे जा सकते हैं। परन्तु जितना अच्छा होना चाहिये, उतना अच्छा नही माना जा सकता है। इसके लिये संगठन को और अधिक सिद्धांतनिष्ठ सबल और संघर्षशील बनाना होगा। ऐसा तभी होगा जब डा0 राम मनोहर

लोहिया के बताये "फावडा-जेल-वोट" के कार्यक्रम को आधार मानकर चला जाय। फावडा का मतलब शहर या गॉव मे रचनात्मक कार्य और श्रम से है, जेल का मतलव किसी भी तरह के अन्याय के विरूद्ध सघर्ष से है और जब दोनो काम निष्ठापूर्वक किया जायेगा तभी वोट की लडाई मे भी विश्वास पूर्वक कम खर्चे मे जीत हासिल की जा सकती है। इसी को अधिकाश समाजवादी साथी, उल्टे समझ बैठे हैं। वे वोट को ही आगे रखकर सभी कार्यो के सम्वन्ध मे निर्णय लेते है और बातचीत मे भी बताते हैं कि ऐसा करने से वोट के ऊपर ऐसा प्रभाव पडेगा। नतीजा होता है कि रचनात्मक कार्य और किसी भी तरह के अन्याय के प्रतिकार का कार्य पीछे छूट जाता है और वोट के स्वार्थ मे हम असली उद्देश्य प्राप्ति से पिछड़े जाते है। आज जब न केवल अपने देश बल्कि दुनिया को जनतात्रिक समाजवादी समाज की आवश्यकता है, तब पार्टी कार्यकर्ताओं की सोच सब तरह से दुरूस्त होना चाहिये। रूस की समाजवादी सरकार के पतन के बाद जिसे वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी चलाती थी, उसकी कजोरी उजागर हो चुकी है और फलस्वरूप यूरोप के छोटे-छोटे देशो मे जो उनके बताये रास्ते पर चलने वाली सरकारे थीं, वह भी समाप्त हो गयी हैं। अब दुनिया के मात्र तीन देशो मे चीन, वियतनाम और अमेरिका के बगल के छोटे से देश क्यूबा मे कम्युनिस्ट पाटी की सरकार चल रही है, परन्तु उसमे भी दुनिया की नयी अर्थनीति का बडा प्रभाव पड गया है। वहॉ भी मार्क्स, लेनिन, माओत्सेतुग और होचिनमिन के बताये रास्ते से अलग होकर अर्थनीति चलायी जा रही है इसका फल यह है कि दुनिया के पूॅजीवादी और नव-साम्राज्यवादी देशो के समाज मे भी अंतर्विरोधी है और गरीबी-अमीरो की खाई बढती जा रही है। इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सचालित सरकारे जहा है, वहा भी गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ रही है। इस अतर्विरोध के चलते कई तरह की समस्याए आज खडी हो चुकी हैं। दुनिया मे इन समस्याओ के समाधान के लिये नये ढग से कुछ बुद्धिजीवी लोग समाजवाद की व्याख्या कर रहे हैं। मार्क्स ने जिसे प्रारम्भिक अवस्था मे सर्वहारा की तानाशाही का नाम दिया था, अब उसकी जगह पर जनतात्रिक समाजवाद का नाम दिया जाने लगा है। अगर एक वाक्य मे कहे तो केवल हमारी समाजवादी पार्टी का सिद्धात ही शुद्ध रूप मे जनतात्रिक समाजवादी है।

समाजवादी पार्टी के मूर्धन्य नीतिकार आचार्य नरेन्द्र देव ने करीब 60 वर्ष पहले कहा था- जनतत्र के बिना समाजवाद नही चल सकता है और उसी समय राजनीतिशास्त्र के प्रसिद्ध ज्ञाता हेराल्ड लास्की ने कहा था बिना आर्थिक समानता के जनतत्र भी सम्भव नही है। इन दोनो

महापुरूषो के कहे वाक्यो के अनुसार और सत्ता के विकेन्द्रीयकरण तथा चौखम्भ राज्य की कल्पना के प्रणेता डा0 राम मनोहर लोहिया शान्तिप्रिय सघर्ष के रास्ते पर चलकर नई दुनिया के समाज निमार्ण के प्रणेता महात्मा गॉधी ने भी केवल कहा ही नही था बल्कि उसका भिन्न-भिन्न जगहो मे प्रयोग भी शुरू किया था। अब इन नेताओ मे से कोई भी हमारे बीच मे नही है परन्तु उनका सिद्धात, उनकी बतायी नीति और उनका कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी को इन नेताओ के बताये रास्ते पर चलकर अपने सगठन को चुस्त-दुरूस्त बनाना चाहिये। अगर हम सगठन को इन महापुरूषो के बताये रास्ते के अनुसार खडा करते और चलाते है तो न केवल अपने देश भारत को बल्कि दुनिया के शोषित पीडित समाज को दलन-दोहन और दास्त्व से मुक्त कराकर एक समतामूलकर समाज की रचना को फलीभूत कर सकते हैं। आज के इतिहास की यही पुकार है। काश हमारे पुराने और नये साथी अपने हित को पीछे रखकर समाज और देश के हित को आगे रखकर अग्रसर होते तो वह समय दूर नही है कि हम आज की दु खी और पीडित मानवता को सही रास्ते पर ले चलने मे सफल हो जाते।

जिस समाजवाद का नाम लोग भूल रहे थे आज श्री मुलायम सिह के नेतृत्व मे समाजवादी पार्टी सभी के जबान और दिलदिमाग को प्रभावित कर रही है। काग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का वर्ग चरित्र एक जैसा है। थोडा सा फर्क साम्प्रदायिक विचरो का है। समाजवादी पार्टी के बारे मे जो लोग यह कहते है कि यह जातिवादी पार्टी है वे या तो अज्ञान है या जान बूझकर पार्टी को बदनाम करने के लिए इस बात का प्रचार करते हैं। देश की जो जनसख्या है उसमे जो हजारो वर्षो से पिछडे और दलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारो से ही केवल वचित ही नही रखे गये थे बल्कि उन्हे सब तरह से समाज मे हीन समझा जाता था, अपवाद स्वरूप कही -कही इसके विपरीत उदाहरण मिलते हैं, परन्तु आम तौर पर स्थिति अच्छी नही थी। अभी उन लोगो मे भी जागृति आयी है और वे भी अब सत्ता मे साझेदारी की लालसा लेकर खड़े हो रहे हैं। इसे नापसन्द करने वाले लोग इस तरह का भ्रामक प्रचार कर लोगो को बरगलाने का काम कर रहे है। डा0 राममनोहर लोहिया ने 'विशेष अवसर का सिद्धात' चलाकर इस देश की राजनीति को जो एक नई दिशा दिया है समाजवादी पार्टी उसी दिशा को आगे बढाने मे प्रयास रत है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से समाजवादी पार्टी का केवल वर्ग चरत्रि ही अलग नही है बल्कि समाजवादी पार्टी का सामाजिक, आर्थिक एव राजनितिक मतभेद भी है। भारतीय जनता

पार्टी से समाजवादी पार्टी को केवल साम्प्रदायिकता के चलते मतभेद नही है उसके चलते उस पार्टी के पुजीवादी समर्थक नीति, गरीब विरोधी काम, आर्थिक अनुदारता की नीति और अन्तर्राष्ट्रीय जगत मे अमेरिका जैसे पूजीवादी राष्ट्र के पीछे चलने की नीति से समाजवादी पार्टी को बहुत बडा मतभेद है। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति से जोडकर राजनैतिक हिसा का कार्य किया है बल्कि इस देश को खडित करने का उस पार्टी का प्रयास है। जहा तक क्षेत्रिय पार्टीयो का सवाल है उससे समाजवादी पार्टी को क्षेत्रिय विकास के मामले मे कोई मतभेद नही है परन्तु राष्ट्रीय मुद्दो पर उनमे जहा खामिया है उस पर समाजवादी पार्टी को अवश्य मतभेद है। ऐसी स्थिति मे समाजवादी पार्टी को अपना कार्यक्रम तेजी से चलाकर अपने स्वरूप को न केवल निखारने बल्कि देश के गरीबो चाहे व किसी भी जाति के हो उनको एक दिशा देने का काम करना है ।समाजवादी पार्टी के लिए आने वाला समय एक विकट परीक्षा का समय है इस परीक्षा मे उत्तीर्ण होने के लिए उसे अपने सगठन को कैडर वेस (मासपार्टी) का रूप देना चाहिए। ऐसा काम वियतनाम के नेता श्री होचितमीन ने कम्युनिस्ट होते हुए अपने सगठन के लिए किया था। यह एक गम्भीर सगठन के स्वरूप का मुद्दा है। समाजवादी पार्टी को गभीरता से इस मुद्दे पर विचार करना है।[8]

4-समाजवादी पार्टी का गठन

यह एक बडी व्यग्य पूर्ण स्थिति है कि भारत मे प्रत्येक सक्रमण-काल मे समाजवादियो ने समय की चुनौतियो को स्वीकार करने के लिए नया रूप और नया सगठन बनाया। यह भी एक विचित्र सयोग है कि कृष्ण की गीता के समान समाजवाद हमेशा कुरूक्षेत्र के मैदान से ही पुनर्व्याख्यायित होता रहा और उसकी मर्यादाओ और सीमाओ का नये सिरे से निर्धारण किया गया। 1977 के बाद 1989 मे केन्द्र तथा उत्तर प्रदेश मे जो गैर काग्रेसी सरकारे बनी थी, जिसमे समाजवादी नये सपने, नये संकल्प के साथ शामिल थे, अन्तर्विरोध का शिकार होकर बिखर गयी। इस बार मूल प्रश्न साम्प्रदायिकता का था। समाजवादी मूल्यो के पक्षधर मुलायम सिह यादव मुख्यमत्री के नाते जब साम्प्रदायिकता के झंझावात से जूझ रहे थे, उनके बहुतेरे समाजवादी साथियो ने उनका साथ नही दिया। नयी व्यवस्था का सपना बिखर गया, निराशा का माहौल पैदा हो गया। लेकिन यह एक सुखद सयोग था कि इस अधकार से घिरे हुए वातावरण मे

---

8 - कपिल देव सिह- सपा ही क्यो, समाजवादी बुलेटिन, दिस0 2002, पृष्ठ 27

पूरे साहस और वर्चस्व के साथ मुलायम सिह ने यह घोषित किया कि वह लोहिया के सिद्धातो के आधार पर नयी सोशलिस्ट पार्टी का गठन करेगे। यही नही, उन्होने अपना हाथ उठाकर समस्त राजनैतिक पार्टियो से पृथक डॉ0 लोहिया के सिद्धान्तो मे अपना विचार व्यक्त किया। मुलायम सिह की इस घोषण के साथ ही सघर्ष का दोतरफा रूप हो गया। एक ओर साम्प्रदायिकता के विष से लडना चालू रहा और दूसरी ओर सामाजिक न्याय के लिए शोषण, भ्रष्टाचार औरअलगाववाद के खिलाफ मोर्चा बनाया गया। कर्म के साथ-साथ आचरण बनाने का सिद्धान्त केवल डॉ0 लोहिया की समाजवादी दृष्टि मे मिलता है। इसीलिए सम्प्रदायवाद से लडने के लिए जरूरी था कि वह अपनी पार्टी को ऐसी बनाये कि उसमे धार्मिक उन्माद की काट ही नही बल्कि समाजवादी नीतियो पर आधारित ऐसी राजनीतिक परम्परा की शुरूआत भी हो जिससे इन दोनो विरोधी तत्वो का असली चेहरा सामने आ जाय।[9]

मुलायम सिह की घोषणा सुनकर कोई भी कह सकता है कि उनका यह कदम एक सही समय मे एक सही दिशा की ओर उठा है। किन्तु प्रत्येक सही कदम कितनी और समस्याएँ उठा देता है, इसे गहराई से समझने की जरूरत होती है। समाजवादी पार्टी के अनेक रूप है किन्तु जब कोई कहता है कि वह लोहिया के विचारो के आधार पर समाजवादी पार्टी का गठन करेगा तो आने वाली तस्वीर उलट जाती है। लोहियावादी समाजवाद का अर्थ है चौखम्भा राज। चौखम्भा राज का अर्थ है ग्राम पचायत का गठन । ग्राम पचायतो के गठन का मतलब है केन्द्र मे स्थापित केन्द्रीकरण मे विश्वास रखने वाली सत्ता से सीधी टक्कर। इस सीधी टक्कर का अर्थ होता है पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को उलटकर एक नयी शुरूआत करना । यही नही, लोहियावादी समाजवाद का मतलब है समता प्रधान समाज के निर्माण को प्राथमिकता देना। समतावादी समाज के प्रति प्रतिबद्ध होने का अर्थ है सम्प्रदायहीन समाज की प्रक्रिया शुरू करना। सम्प्रदायवाद के विरोध का अर्थ है उन प्रतिक्रियावादी एवं अलगाववादी शक्तियो से टक्कर लेना। इसीलिए जब मुलायम सिह ने लोहियावादी समाजवदी पार्टी के गठन की घोषणा की तो लोहिया के समर्थको मे खुशी की एक लहर जरूर दौडी किन्तु उसी के साथ समस्याओ की जटिलताओ ने उदासी का वातावरण पैदा कर दिया। मन मे शका पैदा हुई। लगा कि शायद मुलायम सिंह चौतरफा हमले का सामना करने मे समर्थ नही हो पा रहे हैं। लोहियावादी समजावादी सेना

---

9 - लक्ष्मी कात वर्मा-समाजवादी आन्दोलन लोहियावाद के बाद , पृष्ठ 143

बिखरी हुई थी, समस्याओ की चुनौतियॉ तात्कालिक थी। खासकर उग्र हिन्दुत्व और बहुसख्यक उन्माद अपनी पराकाष्ठा पर था। इनसे टक्कर लेना सहज काम नही था क्योकि 1989 से लेकर 1993 के बीच काग्रेस का निहित स्वार्थ वाला चरित्र पूरी विषमता को तटस्थ होकर देख रहा था और साम्प्रदायिक ताकतो के भविष्य के बारे मे वह किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नही था। यह बात मुलायम सिह से छिपी नही थी।निश्चय ही उनके मन मे वस्तुस्थिति की वास्तविकता को लेकर उहापोह की स्थिति उत्पन्न हुई होगी किन्तु जो प्रसशनीय बात है वह यह कि इन सब खतरो के बावजूद उन्होने लोहिया के विचारो के आधार पर सगठन तैयार करने का फैसला ले ही लिया।

उनकी इस घोषणा के बाद प्राय सभी राजनीतिक पार्टियॉ सतर्कता के साथ समाजवादी आन्दोलन के भविष्य के बारे मे सोचने लगी। पत्र-पत्रिकाओ मे जब प्रतिक्रियाए आई तो लोग हसे। साम्प्रदायिकता मे विश्वास करने वाले लोग कुछ चौकन्ने जरूर किन्तु समस्त स्थितियो और परिस्थितियो का मूल्याकन करके उन्होने मुलायम सिह के सामर्थ्य को कम, उनकी असमर्थता या सीमाओ का गुणगान अधिक किया। वे यह भूल गये कि आखिर मुलायम सिह ने डॉ0 राम मनोहर लोहिया के विचारो के प्रति आस्था व्यक्त की है। साम्प्रदायिक ताकतो तो तोडने का साहस जुटाना कोई मामूली बात नही है। शायद इसीलिए साम्प्रदायिक शाक्तियो ने अपनी शक्ति के प्रति आस्था जताने के बजाय दूसरे की कमजोरी जता कर उसे हतोत्साहित करने का प्रयास किया। लेकिन जिस प्रकार की निष्ठा और विश्वास की पकड मुलायम सिह मे है वह इन छोटी-मोटी उलझनो मे पकडकर समाप्त कैसे होती ? अपने सकल्प के अनुसार बचे खुचे साथियो को लेकर वह साम्प्रदायिकता के विरूद्ध मोर्चाबदी करने मे जुट गये।

जब मुलायम सिह ने समाजवादी पार्टी सगठित करने की घोषणा की थी तो लोगो को विश्वास नही हो रहा था कि वह इतनी जल्दी इस काम को अजाम देने मे सफल होगे। जब सारे प्रदेश और देश का भ्रमण करके समाजवादी आन्दोलन को पुनर्गठित करने का कार्य अकेले अपने दम पर करने की योजना में वह लगे थे उसी समय उन्होने यह घोषित कर दिया था कि समाजवादी सगठन पिछड़े वर्ग के लोगो, दलितो और निर्वलो तथा असहाय लोगो के पक्ष मे काम करेगा और गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग दमघोटू वातावरण मे जी रहे है उन्हे स्वावलम्बी बनाने की कोशिश की जायेगी

आखिर मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी का पुनर्गठन कर ही डाला। वैसे समाजवादी पार्टी का पुनर्जन्म अवश्यम्भावी था। अच्छा हुआ कि समय की चुनौतियो को स्वीकार करके यह सगठन मुलायम सिह द्वारा हुआ क्योकि वह जोखिम उठाने वाले राजनीतिज्ञ हैं और समाजवाद का दूसरा नाम है जोखिम उठाने वाला वाद। यह जोखिम यो ही नही उठाया जाता। इसके लिए समझ और साहस दोनो की जरूरत है। कभी समझ होती है पर साहस नही होता और कभी साहस तो दु साहस के बराबर होता है पर समझ नही होती। साहसी को समझ धीरे-धीरे आ सकती है मगर निष्कर्म होकर न तो साहस ही आता है और न समझ मुलायम सिह मे साहस तो है ही और इस स्थापना सम्मेलन से यह भी स्पष्ट हो गया कि उनके पास अखिल भारतीय स्तर पर सगठन खडा करने की क्षमता भी है।[10]

5-समाजवादी पार्टी के सिद्धान्त,वक्तव्य एवं कार्यक्रम

आजादी के 45 सालो के बाद जनता की हालत और भी बिगड गयी है। गरीबी बढती जा रही, कीमते बढ रही है और बेरोजगारी ने महामारी का रूप ले लिया है। कृषि भूमि पर बोझ बरदास्त के बाहर हो गया है। गावो का विकास बहुत धीमा है। उद्योग और खेती की उत्पादकता अन्य देशो की तुलना मे घटी है। शिक्षा का स्तर गिर गया है। शहरो का विकास भी सुनियोजित नही है और लोग सड़को के किनारे सोने को विवश हैं। हर जगह भ्रष्टाचार है और ऊपर से नीचे तक कुशासन चल रहा है। समाज के सभी अग हताश, उदास और दुखी है।

हम अपने इतिहास के एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गये है जहा हमारी प्रतिष्ठा हीनतम् हो चुकी है। दूसरे देश हमारे आतरिक मामलो मे बिना डर के दखल दे सकते है। देश के अन्दर साम्प्रदायिक शक्तियां राष्ट्र को तोड़ने मे लगी है। सिद्धान्तहीनता और मूल्यहीनता ने समाज को जकड लिया है। आर्थिक विकास की दौड़ मे दूसरे देश हमसे कही आगे निकल गये है।विश्व मे भारत की आर्थिक दशा सबसे गिरी हुई है। जनता मे आशा और उत्साह के बजाय अनिश्चितता, असुरक्षाऔर उदासीनता की भावना छाती जा रही है।

किसान और मजदूर पूरी तरह टूट गया है निर्धन, दलित और पिछडा उपेक्षित है। अल्पसख्यक आतंकित हैं, भयभीत हैं।

---

10 - लक्ष्मी कान्त वर्मा- समाजवादी आन्दोलन लोहिया के बाद, पृष्ठ 148

भारत की नग्न वास्तविकता के वे पाच लाख गाव है जिनमे भारत की आबादी का 80 प्रतिशत रहता है। जिनमे आर्थिक जीवन क्षमता का नितान्त अभाव है। उन 5 लाख गावो के साथ ही साथ वे शहरी गन्दी बस्तिया भी है जिनकी जनसख्या दिन प्रतिदिन बढती जाती है औरअपने दबाव से नागरिक के सभी अवशेषो को मिटाती जा रही है।

इस बिगडती हुई हालत को रोकने के लिए राष्ट्रहित एव जन कल्याण को सर्वोपरि मानते हुये समाजवादी पार्टी निम्न सिद्धान्तो एव कार्यक्रमो पर चलकर देश को नई दिशा देने का प्रयत्न करेगी।

सिद्धान्त

1 कार्यक्रम मूल सिद्धान्तो का अल्पकालिक रूप होता है, वैसे ही जैस अन्तिम लक्ष्य कई क्रमिक कार्यक्रमो का दीर्घकालीन जोड होता है। देश मे राजनीतिक वहस और प्रचार अब तक अन्तिम लक्ष्यो पर केन्द्रित रहे है और अपेक्षित या तात्कालिक कार्यक्रमो की उपेक्षा हुई है। "आर्थिक और सामाजिक समानता", "वर्गविहीन और वर्णविहीन समाज", "शोषण का अन्त और मकान का न्यूनतम स्तर", "स्वतत्रता, मूल्य और अच्छाई", इस तरह की शब्दावली आसानी से शब्दाडम्बर का रूप ले लेती है, और इन्हे सभी मचो पर सुना जा सकता है। शब्दो का बिना मतलब प्रयोग होने लगता है।

2 मजिल जो धुधली, अस्पष्ट रहती है, यदि उस तक पहुचने का रास्ता साफ-साफ न बताया गया हो, तो उसे 'कर्णमधुर लेकिन निरर्थक बातो से भरा जा सकता है। अत समाजवादी पार्टी अन्तिम सिद्धान्तो के स्पष्ट निरूपण के साथ-साथ निश्चित और ठोस कार्यक्रमो पर भी आग्रह करती है इससे सरकार के लिए कथनी और करनी के बीच गहरी खाई रखना सम्भव नही होगा और लोग अन्य राजनीतिक दलो से अलग समाजवादी पार्टी को सार्थक विस्तार से समझ भी सकेगे।

3 यह जरूरी है कि समाजवादी पार्टी समता, सामाजिक स्वामित्व, लोकतत्र और विकेन्द्रीकरण जैसे शब्दो के अर्थ निश्चित करे। इस प्रकार समता का सम्पत्ति और आमदनी के सन्दर्भ मे एक ठोस मतलब होना चाहिए, राष्ट्र के अन्दर और राष्ट्रों के बीच भी। समता के ऐसे ठोस अर्थ में अधिकतम और न्यूनतम आमदनियो का

अनुपात बाधना होगा, तय करना होगा कि निजी स्वामित्व के किन रूपो की इजाजत दी जा सकती है और पहले कदम के रूप मे व्यवस्था करनी होगी कि हर राष्ट्र के युद्ध बजट का कुछ निश्चित प्रतिशत समतापूर्ण विश्व का निर्माण करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय निधि मे दिया जाये।

4 उत्पादन के सारे ऐसे साधनो का जिनमे वेतनभोगी मजदूरो से काम लिया जाता हो, सामाजीकरण होगा। निजी स्वामित्व ऐसी सम्पत्ति तक सीमित होगा जिनमे सामान्यत वेतनभोगी मजदूर न लगे। सामाजिक स्वामित्व राज्य के विभिन्न गठनो के अनुरूप गाव से लेकर केन्द्र तक विभिन्न स्तरो पर होगा।[11] सामाजिक स्वामित्व की उपलब्धि का एक क्रमिक कार्यक्रम इस आधार पर चलाया जायेगा कि कार्यक्रमो के पहले चरण मे कम से कम बैंको और अन्य वित्त सस्थाओ सहित, सभी बडे उद्योग-धधो का सामाजीकरण हो। इसी प्रकार, पाच व्यक्तियो का एक परिवार बिना मजदूर लगाये या मशीनो का इस्तेमाल किये, जितनी जमीन जोत सकता है, उसकी तीन गुनी तक जमीन किसानो और भूमिहीन मजदूरो मे बाट दी जायेगी। नाजायज ढंग से निजी स्वामित्व मे ली गयी जमीन गाव को वापस मिलेगी।

5 समाजवादी पार्टी सहकारिता के सिद्धान्त मे और हमारे आर्थिक जीवन के अधिकाधिक बढ़ते हुए हिस्सो पर सहकारिता को लागू करने मे विश्वास करती है। परस्पर सहायता और आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त को लागू करने की जरूरत न सिर्फ उपभोक्ता सहकार मे है, बल्कि ऋण, खेतिहर उत्पादन की बिक्री, खेती, कुटीर और छोटे उद्योगो मे भी है। किन्तु समाजवादी पार्टी सहकारिता आन्दोलन पर नौकरशाही प्रभुत्व के और उसे स्थिर स्वार्थो व शासक वर्गो का सेवक बनाने की चेष्टाओ विरूद्ध है। समाजवादी व्यवस्था मे समाजिक स्वामित्व के रुपो मे सहकारिता का महत्वपूर्ण स्थान होगा।

6 आमदनी और खर्च की बराबरी का सीधा अनुपात भी रखना होगा क्योकि उत्पादन के साधनो के सामाजिक स्वामित्व के अंतर्गत भी आराम और ऐश के लिए ऊची तनख्वाहे और भत्ते लेने वाले नौकरशाहो, प्रबन्धको और राजनीतिक नेताओ का

---

11 - रजनीकान्त वर्मा-समाजवादी पार्टी के सिद्धात, वकतव्य एव कार्यक्रम से उद्धृत पृष्ठ 24

वर्ग बढ सकता है और स्वतत्र पेशो के सफल लोग भी विशाल मात्रा मे धन कमा या खर्च कर सकते है। सभी आमदनियो और खर्चो को ऐसे अनुपात मे बाधा जायेगा कि अधिकतम सीमा न्यूनतम के दस गुने से अधिक न हो।

7 लोकतत्र का अर्थ, ठोस सन्दर्भ मे, केवल कुछ ऐसे मूल्यो के बारे मे वाग्जाल ही ना रहे, जिनका निरर्थकता की हद तक साधारणीकरण कर दिया गया हो, बल्कि लोकतात्रिक आदर्श को मूर्त करने वाले कुछ ठोस सिद्धान्तो पर आधारित होकर कार्य मे मार्गदर्शन करें। तर्क और बहस के द्वारा जनमत को बदलने की सम्भावना लोकतत्र का मूल सिद्धात है और भाषण की स्वतत्रता उसका सार है। आज के युग मे लोकतत्र का सबसे बडा गुण है विकेन्द्रीकरण, और उसका अर्थ राजनीतिक व आर्थिक दोनो ही सन्दर्भो मे तय करना होगा राजनैतिक सदर्भ मे प्रत्यक्ष लोकतत्र की छोटी इकाइयो के लिये सुनिश्चित राजनैतिक सत्ता और आर्थिक सन्दर्भ मे ऐसी व्यवस्था और ऐसी मशीने जो उत्पादन की प्रक्रिया के नियत्रण की ज्यादा समझ प्रदान करें।

8 इसके लिए प्रशासन का पुनर्गठन करना होगा ताकि वह नौकरशाही या शक्ति या धन की सेवा के उपयुक्त नही वरन् उत्पादन आवश्यकताओ और कुशल अर्थव्यवस्था के उपयुक्त बने। छोटे पैमाने के उद्योगों की पद्धति के समान ही ऐसे राज्य की आवश्यकता है, जिसमे शक्ति अधिकाधिक प्रत्यक्ष, लोकतत्र की छोटी इकाइयो मे हो। जहां भी सम्भव होगा, नौकरशाही द्वारा शासन के स्थान पर चुने हुए प्रतिनिधियो द्वारा शासन की पद्धति चलायी जायेगी। गाव, शहर या जिला जैसी प्रत्यक्ष लोकतत्र की इकाइया गणराज्य की प्रभुसत्ता मे भागीदार होगी, और शक्तियो के उपयुक्त विभाजन और गठन की किसी भी योजना मे उन्हे उतनी ही ऊची सवैधानिक हैसियत दी जायेगी जितनी केन्द्रीय अगो को।

9 लोकतत्र हर हालत मे समाजवाद के विचारो और कार्यक्रमो का मूलाधार रहेगा। लोकतत्र का मतलब है चुनी हुई सभा के प्रति प्रशासन का अनिवार्य उत्तरदायित्व। इसका यह भी अर्थ है कि व्यक्ति, दल, शासन और राज्य के अलग-अलग सीमित व्यक्तित्व को स्वीकार करके उनका आदर किया जाय। ये चारो श्रेणियां

राजनीतिक कार्यवाही की माध्यम है। उनके अलगाव की सीमाओ को तोडने से और इस अलगाव के निश्चित नियमो के उल्लघन से लोकतंत्र खत्म हो जाता है।

10 हमारे देश मे नौकरशाही तथा पूंजीवाद ने रोग को अधिक बढा दिया है। औद्योगिक या खेतिहर उत्पादन की अपेक्षा सट्टेबाजी और व्यापारी लेन-देन मे मुनाफा अब भी बहुत ज्यादा है। शासनतत्र शैतान की आंत जैसा बढता जाता है और उसका काम उत्पादन की अपेक्षा उपदेश देना, सिखाना, नियमन, हस्तक्षेप करना और आमतौर पर एक खास पक्ष के लोगो को रोजगार दिलाना है। सफेदपोशी और हुक्मरानी पर आधारित सभ्यता को नौकरशाही और सामन्ती पूजीवाद ने सर्वथा बाझ बना दिया है। समाजवादी पार्टी ऐसा क्रान्तिकारी दल है जिसे भारतीय इतिहास के सदियो से जमे हुए कूडे को सामाजिक उत्पीडन औरआर्थिक शोषण की परत को, जिसकी अभिव्यक्ति वर्ग और वर्ण के विभिन्न मिश्रण मे होती है और जिसे परम्परागत धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से पोषण मिलता है, साफ करना है। वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा ने भीख मागने को शारीरिक श्रम से अधिक आदरणीय बनाया है और कर्म सिद्धात नये कर्म से छुटकारा पाना चाहता है यद्यपि उसे ज्ञात है कि पुराने कर्मो का सचित फल तो भोगना ही पडता है। इन दोनो ने मिलकर ऐसी सभ्यता निर्मित की है, जिसमे विचार के कठोर अनुशासन की अपेक्षा कर्म का आलस प्राप्त करना कही ज्यादा आसान है।

11 पूजीवाद ने मानवजाति को दो हिस्सो मे बाट दिया है- (i) तीसवे अक्षाश के उत्तर मे रहने वाले लोग जिन्हे खेती और उद्योग मे विज्ञान के पूजीवादी उपयोग का लाभ मिलता है, और (ii) उसके दक्षिण मे रहने वाले दुनिया के दो तिहाई वचित रगीन लोग जिनके उत्पादन के साधनो को नयी पूजीवादी-साम्राज्यवादी व्यवस्था ने क्षति पहुचायी है। पूंजीवाद ने जहां उत्पादन के साधनो और उत्पादन के सबधो के बीच केन्द्रित पूंजी के मालिको और देशी सर्वहारा के बीच सघर्ष पैदा किया है, वही उसने दुनिया के एक तिहाई हिस्से मे उत्पादन के साधनो की विशालता और दो तिहाई दुनिया मे इन साधनो के ह्रास का इससे भी बडा आन्तर्विरोध पैदा किया है। उसने पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अस्ट्रेलिया मे अपनी

औपनिवेशिक शाखाओ को जहां अभूतपूर्व समृद्धि प्रदान की, वही उसने एशिया, अफ्रीका और अन्य क्षेत्रो मे मौत का सन्नाटा कायम किया, जिसमें इन क्षेत्रो की आबादिया बढ़ी और उत्पादन के साधन बिगडे। दुनिया के दो-तिहाई हिस्से मे पूजी-निर्माण का काम इतना बडा है कि निजी पूजी इस काम को नही कर सकती। पूंजीवाद की दो राक्षसी सन्ताने रही है-युद्ध और गरीबी। दो-तिहाई मानव जाति के लिए गरीबी, और शेष के लिए युद्ध । पूंजीवाद मे अपनी इन सन्तानो को नष्ट करने की क्षमता नही है।

12 दुनिया के दो-तिहाई हिस्से से पूजीवाद और सामन्तशाही को मिटाने के बारे मे कोई सन्देह या हिचक नही होनी चाहिए। दुनिया के इस हिस्से मे पूजीवाद का अर्थ शरीर और मन दोनो की अधिकाधिक गरीबी ही हो सकता है। यह केवल मुनाफे के लिए उत्पादन कर सकता है और नयी अल्पविकसित अर्थ-व्यवस्थाओ मे मुनाफे की गुजाइस नही। निश्चय ही भोजन, मकान और औजार ऐसे उपादान नही है जिनसे मामूली आदमी धन उत्पन्न कर सके, जो कि वनस्पति तेल, दवा, सिनेमा, और सबसे अधिक सट्टेबाजी मे इसकी गुजाइस है।

13 साम्यवादी सिद्धांत जिस रूप मे प्रतिपादित एवं विकसित किया गया था, उसकी सफलता पर प्रश्नचिन्ह डा0 राम मनोहर लोहिया ने पहले ही लगा दिया था। पूर्वी योराप एव सोवियत सघ की घटनाए डा0 लोहिया की भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध कर रही हैं। उन्होने कहा था-"कोई नया समेकित सिद्धात ही मानव जाति को नयी आशा और नयी सभ्यता प्रदान कर सकता है।" ऐसा सिद्धात केवल समाजवाद का सिद्धात ही हो सकता है।

14. समाजवाद के सिद्धांत को आधार प्रदान करने के साथ-साथ ऐसी कार्य पद्धतियो का निरूपण भी उतना ही आवश्यक है जिनसे प्रेरणा सिद्धांत को मूर्तरूप दिया जा सके। सभी कार्यो का लक्ष्य होना चाहिए जनता के संकल्प का सगठन और उसकी अभिव्यक्ति और राष्ट्रीय जीवन का पुनर्निर्माण। समाजवादी पार्टी को निरन्तर कोशिशि करनी चाहिए कि वह जनता का प्रवक्ता,उसके सकल्प का सगठक, अन्याय का प्रतिरोध करने वाला, और पुनर्निर्माण करने वाला बने। उसे हमेशा

तैयार रहना चाहिए कि जनमत को प्रबुद्ध बनाने के लिए रचनात्मक कार्यो मे हिस्सा लें और उससे खुद भी सीखें तथा अन्याय का प्रतिरोध करें। कार्य की तीन पद्धतिया-जिनके प्रतीक है फावडा, वोट और जेल। सत्ता से बाहर रहने पर, वर्तमान मे भी अपनी चाहे कितनी भी थोडी उपलब्धियो से यह दिखाना चाहिए कि सत्तारूढ होने पर वह क्या करेगा?

15. सभी छोटे-छोटे रचनात्मक कार्य सचमुच क्रान्तिकारी कार्यकलापो को जीवन शक्ति प्रदान करते है। क्रान्ति कभी भी ससदीय कार्यवाही तक सीमित नही हो सकती। वोट जनता के सकल्प की सर्वोच्च अभिव्यक्ति होता है लेकिन उसका मौका वरसो मे एकबार आता है। मगर वोट के पूरक के रूप में सिविल नाफरमानी द्वारा या वर्ग सघर्ष के किसी कार्य को तात्कालिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। झूठ और हिंसा का प्रयोग नही करना चाहिए, न कभी भविष्य के काल्पनिक स्वास्थ्य के लिए वर्तमान हत्या को उचित ठहराने की चेष्टा करनी चाहिए।[12]

16 हमारे देश मे एक ओर सरकारी हिंसा-क्रूरता और बिना मुकदमा चलाये बहुसख्यक लोगो की गिरफ्तारी, निहत्थी भीडो पर पुलिस का गोली चलाना आदि होते रहे है तथा दूसरी ओर लोगो का लम्बे अर्से तक चुपचाप सहना और अचानक सामूहिक हिंसा और जंगलीपन का विस्फोट जारी रहा है। व्यक्तिगत और सामूहिक सिविल नाफरमानी का भारत के सार्वजनिक जीवन मे कोई कारगर योग नही रहा है। समाजवादियो को निर्णायक रीति से सिविल नाफरमानी को अमल मे लाना चाहिए और इस पुराने विश्वास को गलत साबित करना चाहिए कि बल प्रयोग के बिना वर्तमान व्यवस्था को उल्टना सम्भव नही।

17. समाजवादी पार्टी मानती है कि नयी मानव सभ्यता के निर्माण की दृष्टि से पूजीवाद और साम्यवाद समान रूप से निरर्थक हैं। हमारा प्रयास होगा कि समतापूर्ण जगत मे केवल मनुष्य की सभ्यता निर्मित हो। ऐसी दुनिया केवल इस सिद्धात के आधार पर बनायी जा सकती है कि मनुष्य न केवल एक राष्ट्र के अन्दर, बल्कि विभिन्न राष्ट्रो के बीच भी समान हैं।

---

12 - रजनीकान्त वर्मा समाजवादी पार्टी के सिद्धात, वकतव्य एव कार्यक्रम से उद्धृत, पृष्ठ 28

18 समाजवादी पार्टी मानती है कि शस्त्रो को होड सारी दुनिया की अर्थ व्यवस्था पर भारी बोझ बन चुकी है। इस पर खर्च होने वाला बेहिसाब धन दुनिया के अल्प विकसित देशो के विकास पर खर्च करके सम्पूर्ण मानवता को गरीबी, भुखमरी और विनाश से बचाया जा सकता है। इस हेतु निरस्त्रीकरण जरूरी है।

19 दुनिया मे वास्तविक और कारगर निरस्त्रीकरण तभी हो सकता है जब विश्व मे समता स्थापित हो। मानव जाति के विकसित एक-तिहाई हिस्से की उत्पादक शक्तियो की वजह से जो घोर विषमता है, वह गम्भीर आर्थिक असन्तुलन उत्पन्न करती है जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के सघर्ष होते है और विशेषाधिकार-प्राप्त हिस्सो के धन को बचाने के लिए शस्त्रीकरण की होड चल पडती है।

20 वर्तमान मे विदेशी सहायता, न केवल पाने वालो के लिए अपमानजनक और खतरनाक है, बल्कि उनकी आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए कभी काफी नही हो सकती। ऐसी सहायता निश्चित ही पिछड़े देशो को भ्रष्ट करती है और निरपवाद ही यथास्थिति की शक्तियों को सत्तारूढ रखती है। विश्व बैंक और विश्व मुद्राकोष जैसी सस्थाओ पर भी पूजीवादी ताकतो का पूरा नियंत्रण हो गया है। इसलिए इन सस्थओ से मिलने वाली सहायता एव ऋण विकासशील देशो की सम्प्रभुता के लिए खतरनाक साबित हो रही है।समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय सम्मान एव सम्प्रभुता की कीमत पर मिलने वाले किसी भी कर्ज एव सहायता का विरोध करती है।

21. समाजवाद के सिद्धांत को अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर और दृढता के साथ अमल मे लाने पर ही नयी विश्व व्यवस्था का प्रादुर्भव हो सकता है। इस युग मे समाजवाद का सर्वव्यापी सिद्धात और उस पर किया गया अमल निम्न सात क्रान्तियो के द्वारा व्यक्त होना चाहिए।

1. नर-नारी की समानता के लिए
2 चमड़ी-रंग पर रची असमानताओ के खिलाफ,
3 जन्मजात और जाति प्रथा की विषमताओ के खिलाफ,
4 परदेशी गुलामी के खिलाफ और विश्व लोक राज के लिए,

5 निजी पूजी की विषमताओ के खिलाफ और योजना द्वारा पैदावार बढाने के लिए

6 निजी जीवन मे अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ।

7 अस्त्र-शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए।

22 राष्ट्र के सामाजिक एव शैक्षिक दृष्टि से पिछडे लोगो को विशेष अवसर प्रदान करने के सिद्धात को समाजवादी पार्टी मान्यता प्रदान करती है।पार्टी की मान्यता है कि जब समाज के दलित अल्पसख्यक एव पिछडे विशेष अवसर प्राप्त करके अन्य वर्गो के बराबर खड़े नही होगे-समाजवादी समाज की स्थापना नही हो सकगी।

23 धर्म निरपेक्षता या सर्व-धर्म संम्भाव के सिद्धान्त को समाजवादी पार्टी स्वीकार करती है तथा धर्म निरपेक्षता का उल्लघन करने वाली साम्प्रदायिक शक्तियो के खिलाफ निरन्तर सघर्ष करने के लिए पार्टी कृत सकल्प है। अनेक धर्मावलम्बियो वाले इस विशाल देश को "सर्व धर्म सम्भाव" की भावना के द्वारा ही एकता के सूत्र मे बांधे रखा जा सकता है।[13]

कार्यक्रम

हमारे राष्ट्रीय मामलो मे आ चुके वर्तमान सकट के कई पहलू बढती आबादी, अन्न की सतत् कमी, निरन्तर बढती कीमते, हमेशा बढती गैरबराबरी, धन का कुवितरण और बढ़ता भ्रष्टाचार और नौकरशाही का बढ़ता शिकजा आदि।

आर्थिक विकास के मामले मे भी हमारा देश दूसरे देशो से बहुत पिछडा हुआ है। वक्ती उपाय और अधिक तालमेल बैठाने से यह सकट दूर नही होगा। इसके लिए बुनियादी तब्दीलियो की जरूरत है।

वर्तमान पूंजीवादी-सामन्ती व्यवस्था और नौकरशाही का नाजायज प्रभुत्व देश को और चौपट कर रहा है। पार्टी को इन मामलो मे वर्ग-सघर्ष तेज करना होगा और सामूहिक तथा व्यक्तिगत सिविल नाफरमानी को व्यापक रूप देना होगा ताकि राज्य का चरित्र, राजनीतिक तथा

---

13 - रजनीकान्त वर्मा समाजवादी पार्टी के सिद्धात, वकतव्य एव कार्यक्रम से उद्धृत, पृष्ठ 30

आर्थिक सस्थाए बुनियादी तौर पर बदली जा सके। यहा प्रस्तुत कार्यक्रम और राजनीतिक दिशा पार्टी को आने वाले संघर्ष मे महत्वपूर्ण भागेदारी करने लायक बनायेगे।

नियोजन

1 वर्तमान आर्थिक नियोजन का पूरा दिवालियापन नीचे लिखी बातो से बिल्कुल साफ है -

(क) खेती और अनाज की पैदावार मे गतिरोध,

(ख) ओद्योगिक प्रगति मे गिरावट,

(ग) बेकारी की लगातार बढ़ोत्तरी,

(घ) रहन-सहन ने स्तर तथा आमदनी मे बढती विषमता जिसके कारण एक फीसदी अल्पसख्यक द्वारा राष्ट्रीय आमदनी के बड़े हिस्से की खपत।

2 इस विषम परिस्थिति से देश को छुटकारा दिलाने के लिए चौतरफा पूजीकरण के प्रयास की आवश्यकता है, जो केवल बराबरी के वातावरण मे ही सम्भव है। अधिकतम बराबरी, पूरी सादगी और अनिवार्य वस्तुओ के मूल्यो मे स्थिरता आदि ऐसे पूजीकरण के प्रयास की कुछ अनिवार्य शर्ते है जिनके बिना आर्थिक तरक्की की गति मे तेजी नही आ सकती। कुछ आर्थिक विकास अवश्य हुआ है किन्तु नये स्वतंत्र हुए देशो की तुलना मे और अपनी जरूरतो के सन्दर्भ मे यह प्रगति महत्वहीन ही है। समाजवादी पार्टी सबसे पहले बराबरी पर आधारित क्रान्ति, और खेत-कारखानो मे काम करने वालो के अन्दर आदर्श की भावना जगाकर पूजीकरण और विकास को तेज करने का प्रयास करेगी।

3. भारत को नियोजन के लिए दो रास्तो मे से एक रास्ता चुनना है-भारतीय जन के एक छोटे तबके को क्रमिक ढंग से विकसित करते हुए आधुनिक पश्चिमी स्तर तक पहुंचाना या सारे जनगण के लिए सम्मानीय जीवन स्तर उपलब्ध कराना, इसमे समय चाहे कितना लगे, विकास चाहे कितनी भी कम आखो के सामने आये, समाजवादी पार्टी दूसरे रास्ते की वकालत करती है। समाजवादी नियोजन में बुनियादी उत्पादन ढांचे के निर्माण और गांवों मे पीने का पानी तथा सौचालय की व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाए प्रदान करने का कार्य सर्वोत्तम प्राथमिकता पर

होगा। इस नियोजन मे सत्तर प्रतिशत धन गावो के विकास पर खर्च करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

आमदनी में क्षेत्रीय विषमता

1 देश की आबादी मे उच्च स्तरीय एक फीसदी और निम्न स्तरी 60 फीसदी, की शहरी क्षेत्रो की, विकसित प्रदेशो एव क्षेत्रो की प्रति इकाई तथा पिछडे हुए उपेक्षित क्षेत्रो की आमदनी के बीच जबरदस्त विषमताएं भी है।

2 यह विषमता मुख्यत· विदेशी शासन के उस दृष्टिकोण का परिणाम है जिसके अनुसार उसने 50 से 150 वर्षो तक केवल उन्ही क्षेत्रो को विकसित करने का प्रयास किया जो या तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के केन्द्र बन सकते थे या राजनीतिक दृष्टि से अंग्रेजी शासन को मजबूत बनाने मे सहायक हो सकते थे।आजाद भारत मे भी इस ढाचे को सचमुच बदलने का कोई वास्तविक प्रयास अभी तक नही किया गया। समाजवादी पार्टी जागरूक प्रयास द्वारा ऐसी नयी दिशा देगी। ताकि यह असन्तुलन जल्दी समाप्त हो।

बराबरी

1 समाजवाद का प्रधान लक्ष्य बराबरी लाना है। इसलिये समाजवादी पार्टी बराबरी को ठोस रूप प्रदान करने की चेष्टा करेगी और अपनी इस चेष्टा मे वह विभिन्न उपायो, कर और आमदनी की नीतियो और राष्ट्रीयकरण आदि का उपयोग करेगी। पार्टी सारी गैर बराबरियो को एक और दस के अनुपात मे लाने का प्रयास करेगी। इसी मे आय और खर्च की सीमा बाधने का मतलब होगा-जमा धन और सम्पत्ति की भी सीमा बाधना। मत्रियो एव विधायको, भूतपूर्व राजाओ और व्यापारियो अर्थात देश की शक्तिशाली लोगो की सम्पत्ति के कम से कम एक भाग का राष्ट्रीयकरण करके इसकी शुरूआत करनी होगी। पार्टी की राय मे 1·10 का अनुपात कायम होने पर उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

2. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मुफ्त होगी, साथ ही साथ सबको समान रूप से शिक्षा मिलेगी। विशेष प्रकार के सभी प्राथमिक स्कूल खत्म किये जायेगे।

पूंजी सचय

1 समाजवादी निर्माण का प्रश्न मूलत पूजी सचय का प्रश्न है, हमारा विश्वास है कि सादगी, त्याग और अधिकतम सम्भव बराबरी के आधार पर ही इस समस्या का सामना किया जा सकता है।

2 पूजी कर, व्यय कर, आमदनी और सम्पत्ति पर सीमा, ऐच्छिक श्रम आदि के द्वारा भारत के खेती और उद्योग-धन्धो के पुन निर्माण के लिये साधन एकत्र किये जायेगे। तेजी से आर्थिक विकास होने पर पूजीकरण के लिये अधिकाधिक साधन उपलब्ध होगे और अन्ततः सामान्य लोगो का जीवन स्तर सुधरेगा।

संविधान मे सशोधन

1 समाजवादी पार्टी नीचे लिखी बातो को मद्देनजर रखकर सविधान मे सशोधन करेगी -

(क) सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु।

(ख) राजनैतिक और शासकीय ढाचे को प्रजातांत्रिक स्वरुप प्रदान करने के लिये।

(ग) सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने के लिए।

(घ) नागरिक आजादी पर लगे प्रतिबन्धो को दूर करने के लिए।

2 सविधान मे सभी स्थानीय और स्वायत्त सस्थानो के हितो को परिभाषित करने के लिए नई व्यवस्थाएं जोड़ेगी तथा पिछड़ो को विशेष अधिकार देगी।[14]

नागरकि आजादी

1. सेना, सशस्त्र कान्स्टेबुलरी, पुलिस नीति निर्धारण करने वाले शासकीय और प्रबन्धक अफसरों को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियो को राजकीय दलो मे शामिल होने का अधिकार होगा।

2 सभी सार्वजनिक क्षेत्र, रेलवे, तथा अर्द्धसरकारी कर्मचारियो के राजनैतिक और प्रजातांत्रिक अधिकारियो पर लगे सारे बन्धनो को उठा लिया जायेगा।

---

14 - रजनीकान्त वर्मा-समाजवादी पार्टी के सिद्धात, वकतव्य एव कार्यक्रम से उद्धृत पृष्ठ 34

3 साधारण पुलिस कर्मचारियो को अपनी शिकायते दूर करने के लिए सगठन बनाने का अधिकार होगा।

4 अपराध सम्बन्धी कानूनो मे इस प्रकार सुधार किया जायेगा जिससे किसी नागरिक को जबर्दस्ती डराया, धमकाया तथा अनुचित ढग से गिरफ्तार नही किया जा सके।

5 जल्दी और सस्ता न्याय दिलाने के लिए अदालती कार्यवाही मे सुधार किया जायेगा।

6 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूरी तरह स्वतत्र कर दिया जायेगा और निकटतम मजिसट्रेट के सामने 24 घण्टे के भीतर पेश किये जाने जैसी व्यवस्थओ को कठोरता से लागू किया जायेगा।

विकेन्द्रीकरण

समाजवादी पार्टी लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण को ठोस रुप देने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन करेगी।

(क) पंचायतीराज व्यवस्था तथा स्थानीय निकायो के चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के जरिये कराये जायेगे। पिछडी जातियो, अल्पसख्यको, औरतो, हरिजनो, आदिवासी और अन्य पिछडे समूहो के हितो की रक्षा के लिए स्थान आरक्षित किये जायेगे।

(ख) योजना तथा विकास पर होने वाला कम से कम पच्चीस प्रतिशत सरकारी खर्च स्वायत्त सस्थाओ द्वारा किया जायेगा।

(ग) अत्यधिक आबादी वाले शहरी केन्द्रो मे, नये उद्योगो की स्थापना पर विशेष अपवादो को छोडकर रोक लगायी जायेगी।

(घ) देश के अन्तरीय क्षेत्रो मे कारखानो को इस तरह से फैलाया जायेगा। ताकि सारे देश मे औद्योगिक विकास समान रुप से फैलाया जा सके और शहरो मे आबादी का अस्वस्थ जमाव न हो सके।

(च) शहरो की सभी खुली जमीन व बड़े खुले मैदान, पर नगरपालिकाओ का कब्जा होगा और उनका सही इस्तेमाल दवाखानो, स्कूल, क्रीड़ा मैदान और सार्वजनिक बगीचो के लिए किया जायेगा।

खेती (कृषि)

1. समाजवादी पार्टी का विश्वास है कि गांवों के विकास के वगैर शहरों का विकास सम्भव नहीं है। इसलिए प्राथमिकताओं में सबसे पहले खेती उसके बाद कुटीर, छोटे उद्योग तथा अन्त में भारी उद्योग होंगे।
2. समाजवादी पार्टी कृषि के चहुँमुखी विकास करने को प्राथमिकता देती है।
3. कृषि उत्पादन में वृद्धि तभी सम्भव है जब उत्पादन के तीन कारकों-भूमि, श्रम एवं पूंजी में से किसी एक की मात्रा में वृद्धि की जाय अथवा खेती में नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाये।
4. भूमि का आकार सैदव स्थित रहा है, न यह बढ़ाया जा सकता है और न घटाया देश में श्रम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और आधुनिक व मशीन रहित तकनीकों के प्रयोग से अधिक श्रम शक्ति को खेती में खपाया जा सकता है। लेकिन इसकी भी एक सीमा है। यदि कृषि उपज से ज्यादा आय प्राप्त हो तो इससे पूरे देश का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा।
5. अकृषि क्षेत्रों में समानता लाने के लिए कृषि से उद्योग की ओर श्रमशक्ति का बहाव तब तक जारी रखना पड़ेगा जब तक कृषि व्यवसाय में लगे श्रमिक की आय अकृषि क्षेत्र में लगे श्रमिकों की आय के बराबर न हो जाय।
6. भू-क्षरण, कृषि उत्पादन घटने का प्रमुख कारण रहा है। यदि इस समस्या का निदान नहीं किया गया तो कृषि भूमि की उत्पादन शक्ति समाप्त हो जायेगी। अतः भूमि के उपयोग से भी ज्यादा जरूरी है-भूमि संरक्षण। समाजवादी पार्टी भूमि सरंक्षण के लिए ठोस एवं विस्तृत कार्यक्रम तैयार करेगी।
7. नयी जमीन पर खेती करने के लिए भूमि सेना का गठन किया जायेगा।
8. खेत मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय होगी और उसे लागू करने की व्यवस्था की जायेगी।
9. खेती की पैदावार के पूरक के रूप में आम, अमरूद जैसे मौसमी फलों के उत्पादन को बढावा दिया जायेगा। पहाड़ी क्षेत्रों विशेषकर हिमालय की पहाड़ियों में सरकारी व्यवस्था होगी। सरकार पशुपालन और डेरी उद्योग को भी प्रोत्साहन देगी।

10 किसानो को सुरक्षा प्रदान करने के लिए फसल बीमा की योजना लागू की जायेगी।

11 खेत मजदूरो, हरिजनो, आदिवासियो और साधनहीन स्त्रियो को कर्ज के बोझ से मुक्त कर दिया जायेगा।

12 अलाभकर जोतो के किसानो और खेत मजदूरो को उनकी पसन्द के अनुसार दुधारू गया या भैस उपलब्ध करायी जायेगी। समाजवादी पार्टी का विश्वास है कि ग्रामीण अचल मे एक दुधारू गाय या भैस से एक परिवार का भरण पोषण सम्भव हो सकता है।[15]

सिचाई एव बिजली

1. खेती से अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए गरीब किसानो को सिचाई की सुविधा मुफ्त होगी तथा दूसरे किसानो के लिए सस्ती सिचाई सुविधा की व्यवस्था करना समाजवादी पार्टी के नियोजन का लक्ष्य होगा ।

2 छोटी और बड़ी मध्यम हर प्रकार की सिचाई की ऐसी योजनाए कार्यान्वित की जायेगी। जिससे 7 वर्ष के अन्दर तथा सम्भव कोई भी खेती असिचित न रहे।

3. समाजवादी पार्टी चाहती है कि बिजली गाव-गाव पहुचे। निजी नमकूपो के लिए बिजली कनेक्शनो को शीर्ष वरीयता दी जायेगी तथा सिंचाई के लिए प्रयोग मे आने वाली बिजली की दरें तुलनात्मक रूप से कम होगी।

जंगल और आदिवासी

1 वर्तमान कठोर जगल कानूनो से आदिवासियो को मुक्त किया जायेगा, जगल अफसरो और पुलिस द्वारा उनको तग किया जाना खत्म होगा और जगल की उचित व्यवस्था करने मे आदिवासियो को हिस्सेदार और जिम्मेदार बनाया जायेगा।

2. जलाने की लकड़ी, पत्ते आदि लेने के लिए आदिवासियो के अधिकारो का आदर किया जायेगा।

3. जिन आदिवासी जमीनो पर पहले खेती होती थी, और उन्हे जगल क्षेत्र मे ले लिया गया, उन्हे वापस कर दिया जायेगा।

---

15 - रजनीकान्त वर्मा -समाजवादी पार्टी के सिद्धात, वकतव्य एव कार्यक्रम से उद्धृत, पृष्ठ 37

4 पुर्नप्राप्ति जमीनो मे बसाने को आदिवासियो और हरिजनो को प्राथमिकता दी जायेगी।

5 आदिवासियो और हरिजनो को मकान बनाने क लिए नयी जमीने दी जायेगी।

बाढ़ और अकाल

1 अकाल ग्रस्त इलाको मे सरकार मुफ्त भोजन की व्यवस्था करेगी, चाहे वह मात्र जीवन-रक्षा योग्य ही हो।

2 पुरानी दुर्भिक्ष सहिताओ के स्थान पर एक व्यापक दुर्भिक्ष कानून होना चाहिए, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार लोगो को भोजन देने की अपनी जिम्मेदारी को सविधान के निर्देशक सिद्धान्तो के सन्दर्भ मे स्वीकार करे। प्राकृतिक मृत्यु और भूख से मृत्यु जैसे शब्द साफ-साफ परिभाषित हो।

3. सरकार बार-बार आने वाली बाढ़ो के कारणो का पूरा पता लगाकर उनको रोकने के पर्याप्त उपाय करेगी। मकान, पशु, खेत और अन्य सम्पत्ति का नुकसान होने पर पूरा मुआवजा देने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

भ्रष्टाचार

1 प्रशासनिक सेवा के अधिकारियो द्वारा अवकाश प्राप्त होने अथवा करने के बाद निजी कम्पनियो मे नौकरी स्वीकार करने पर पाबन्दी होगी।

2 हाइकोर्ट या सुप्रीमकोर्ट का कोई न्यायधीश न्यायिक कार्यो के अलावा किसी और सरकारी नौकरी पर नही लगाया जायेगा।

3. किसी भी मंत्री या प्रशासनिक कर्मचारी के एक पीढी तक के रिश्तेदार का लाइसेस या परमिट आदि के लिए प्रार्थना पत्र नही स्वीकार किया जायेगा।

दाम-नीति

समाजवादी पार्टी एक सुसगठित कल्याणकारी दाम नीति लागू करेगी जिसमे मुख्य पहलू होगे:-

(क) रोजमर्रा की जरुरतो की कारखानो मे बनी चीजो का दाम लागत खर्चे के डेढ गुने से अधिक नही होगां इसमे सभी कर और मुनाफे शामिल होगे।

(ख) दो फसलो के बीच अनाज के दामो मे मौजूदा विस्तृत उतार-चढाव पर नियत्रण किया जायेगा। इस उतार-चढाव को सोलह प्रतिशत से अधिक नही होने दिया जायेगा।

(ग) कारखानो के और खेती के दामो मे सतुलन स्थापित किया जायेगा।

(च) सतुलन के इसी सिद्धान्त का आग्रह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे किया जायेगा ताकि अमीर देशो द्वारा गरीब खेतिहर देशो का शोषण कम हो।

(छ) अनाज के थोक व्यापार का सामाजीकरण किया जायेगा।

(ज) थोक व्यापार का समाजीकरण इस प्रकार होगा कि छोटे फुटकर व्यापारियो की सेवाए राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति मे लगायी जा सके।

(ञ) समाजवादी पार्टी छोटे व्यापारी और फुटकर विक्रेता की मित्र है। जो आज सरकारी नियत्रणो और नियमो से परेशान रहने के अतिरिक्त, बडे पूजीपतियो और वितरको, के हथकण्डो के भी शिकार होते है।

(झ) जब तक देश से भूख को खत्म नही कर दिया जाता, भोजन की वस्तुओ का निर्यात बन्द कर दिया जायेगा।

(त) अनाज और खाने-पीने की वस्तुओ पर से बिक्री कर समाप्त कर दिया जायेगा[16]

मिलावट

भोजन-सामग्री और दवाओ मे मिलावट ऐसा जुर्म हो जिसकी सख्त और लम्बी सजा मिले।

उद्योग

1 समाजवादी पार्टी ऐसे हर प्रकार के उत्पादन के साधनो और व्यापारो के सामाजीकरण के पक्ष मे है जिसमे पगारी मजदूर काम करते हो लेकिन ऐसा सामाजीकरण क्रमिक होगा।

2 सार्वजनिक क्षेत्र के बारे समाजवादी पार्टी समझ्ती है कि सार्वजनिक क्षेत्र अफसरो और मामूली मजूदरो के बीच आमदनियो और सुविधाओ की असहनीय विषमताएं कायम कर रहा है। पार्टी सार्वजनिक क्षेत्रो के इन दोषो को दूर कर लोकतात्रिक सिद्धान्तो के आधार पर उसका पुनर्गठन करेगी।

---

16 - रजनीकान्त वर्मा-समाजवादी पार्टी के सिद्धात, वकतव्य एव कार्यक्रम से उद्धृत, पृष्ठ 40

3 भारत की विदेशी सहायता पर बढ़ती हुई निर्भरता विदेशी पूजी विनियोग मे भारी वृद्धि और भारतीय व्यापार प्रतिष्ठानो से विदेशी फर्मो का गठजोड भारत के लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर रहे है।

4. समाजवादी पार्टी बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के भारत मे बेरोकटोक प्रवेश को भारत की आर्थिक अजादी के लिए सबसे गम्भीर खतरा मानती है। इसलिये पार्टी देश मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के प्रेवश पर पूर्ण प्रतिबन्ध का समर्थन करती है।

औद्योगीकरण और रोजगार

औद्योकिगरण मे मानव श्रम का स्थान मशीन ले लेती है आज देश मे जहा पूजी अल्प मात्रा मे उपलब्ध है वहा मानव श्रम प्रचुर मात्रा मे है। पूजी पर ब्याज की तुलना मे मजदूरी काफी कम है जिसकी वजह से मशीनो की अपेक्षा श्रम सस्ता पडता है। ऐसी स्थिति मे देश की अर्थव्यवस्था का आधार विकेन्द्रित छोटे पैमाने के श्रम, प्रधान उद्योगो और पूजी की बचत करने वाली तकनीको को बनाना चाहिए न कि शहरो मे स्थित बडे पैमाने के उद्योगो को जिनमे बडी पूजी की आवश्यकता पडती है।

समाजवादी पार्टी उद्योगो के निश्चित वर्गीकरण के पक्ष मे है। यह वर्गीकरण इस प्रकार का हो कि जिन वसतुओ का उत्पादन करने मे कुटीर उद्योग असमर्थ हो उनका ही उत्पादन छोटे, पैमाने के उद्योग करे और छोटे पैमाने के उद्योग जिन वस्तुओ का उत्पादन नही कर सकते उसका उत्पादन का अधिकार मध्यम श्रेणी के उद्योग को दिया जाये। और ऐसी वस्तुओ का निर्माण बडे उद्योग करे जिनको बनाने मे मध्यम श्रेणी के उद्योग असमर्थ हो।

इस वर्गीकृत व्यवस्था से रोजगार का स्तर अधिकतम किया जा सकता है। कुटीर उद्योगो तथा छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा बडे पैमाने के उद्योगों की तुलना मे (बारह) 12 गुना ज्यादा लोगो को रोजगार दिया जा सकता है।

मजदूर

1 समाजवादी पार्टी एक प्रबल सगठित मजदूर आन्दोलन का निर्माण चाहती है और इस बात के लिए अथक प्रयास करेगी कि सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग एक प्रजातात्रिक आधार पर गठित मजदूर सगठन के अन्तर्गत कार्य करे।

2 इस प्रकार मजदूर आन्दोलन की एकता मजदूर वर्ग को सम्मानजनक समझौतो के लिए ताकतवार आधार प्रदान करेगी और मजदूर आन्दोलनो के प्रयासो मे एक लडाकू तीखापन पैदा करेगी।

3 इस उद्देश्य के लिए पार्टी का पहला कदम होगा कि पार्टी से सम्बद्ध सगठनो को एक ताकवर मजदूर सघ मे ढाले जो एक रचनात्मक/जुझारू समाजवादी आधार पर चले।

4 समाजवादी पार्टी मजदूर आन्दोलन मे सुधार कर उसे पुन सगठित करेगी, भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करेगी, राजनीति विरोधी अलगाव के दृष्टिकोण से जूझेगी और उचित आन्तरिक चुनावो पर आग्रह करेगी।

5. एक मजदूर नीति की दिशा मे पार्टी मजदूर वर्ग को उसका उचित अधिकार दिलाने के लिए निम्नलिखित प्रगतिशील कदम उठायेगी।

(क) विभिन्न संगठित उद्योगो के सगठित क्षेत्रो मे अलग अलग वेतन मडल नियुक्त किया जायेगा।

(ख) समूचे असंगठित क्षेत्र के लिए नयूनतम मजदूरी निर्धारण समितिया बनायी जायेगी।

(ग) बढती हुई कीमतो के प्रभाव को खत्म करने के लिए महगाई भत्ता को जीवन निर्वाह के खर्चे से सम्बद्ध किया जायेगा।

(घ) सरकारी तथा अर्द्धसरकारी कर्मचारियो की आचरण सहिता के नियमो मे सशोधन किया जायेगा।

(द) एक व्यापक कानून बनाया जायेगा जिसके अन्तर्गत·

1 मजदूर यूनियनो को अनिवार्य मान्यता दी जायेगी,

2 समय समय पर मजदूरो के मतदान द्वारा प्रतिद्वन्दी यूनियनो की प्रतिनिधित्व का विवाद हल किया जायेगा।

3 हडताल तोडक कार्यवाहियो पर रोक लगायी जायेगी, लेकिन व्यर्थ हड़ताल पर पाबन्दी होगी।

4. मनचाही मुअत्तलियो तथा बर्खास्तगियो को रोककर रोजगार की सुरक्षा की जायेगी, लेकिन व्यर्थ नेतागिरी भी नही चलने दी जायेगी।

6 माहवारी आमदनी का एक प्रतिशत मजदूर सगठनो की मेम्बरी का न्यूनतम शुल्क होगा।

(त) कार्य शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी ताकि अधिक से अधिक प्रबन्धक कर्मचारी मजदूर वर्ग से ही पदोन्नत किये जा सके।

6 पार्टी बुढापे की पेशन और बेकारी से राहत की ऐसी योजनाए बनायेगी जो धीरे-धीरे सारी जनसख्या पर लागू होगी।

7 उन्ही मजदूर यूनियनो को मान्यता दी जायेगी जो कामगार और देश के हित की बात करेगी।

शिक्षा

1 निरक्षता निश्चित स्वरुप से 7 वर्ष की अवधि से दूर कर दी जायेगी और साक्षरता सेना गठित की जायेगी।

2 शिक्षा प्रणाली मे आमूल परिवर्तन किया जायेगा। वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया जायेगा। अनुसधान तथा वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति को, न कि भाषा पर सतही अधिकार को लक्ष्य बनाया जायेगा।

3 शिक्षा के अवसर का विस्तार होगा। अगर आवश्यकता हुई तो प्रात कालीन और सायकालीन कक्षाएं चलायी जायेगी। नौकरियो मे तरजीह के सिद्धात का यह अभिप्राय न होगा कि किसी को अवसर न मिले। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ और

4. अनुसधान कार्य का पुन सगठन किया जायेगा और उपलब्ध सुविधाओ द्वारा ऐसे उद्योग धन्धो मे विज्ञान के उपयोग तथा लघु इकाई यत्रो को प्रोत्साहित किया जायेगा जो (क) रोजगार मे वृद्धि, (ख) विकेन्द्रीकरण तथा (ग) ग्रामीण विकास मे सहायक बन सके।

5 किसी भी मजहब के नाम पर चलने वाली सस्थाओ को कोई राजकीय सहायता नही मिलेगी।

6 सरकारी स्कूलो के अध्यापको और निजी स्कूलो के बीच वेतन क्रम और सुविधाओ की असमानताओ को दूर किया जायेगा।

6 समाजवादी पार्टी शिक्षा जगत मे नकल की प्रवृत्ति का विरोध करती है और इसको रोकने के लिए परम्परागत तरीको को प्रभावी ढग से लागू करने की हामी है। भावना पैदा होगी, वह देश के लिए आने वाले दिनो मे एक आत्मघाती कदम होगा। ऐसा पार्टी का विश्वास है। इसलिए पार्टी ऐसे सभी अवाछनीय सरकारी कानूनो, अध्यादेशो को तत्काल समाप्त करने की पक्षधर है।

7 समाजवादी पार्टी सबको शिक्षा देने के लिए सकल्पबद्ध है। इसलिए की आबादी वाले हर गाव मे एक पक्का प्राइमरी स्कूल तथा हर दो प्राइमरी स्कूलो के बीच एक जूनियर हाईस्कूल स्थापित करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर हो ऐसा समाजवादी पार्टी का मानना है।

8 समाजवादी पार्टी हर बलाक मुख्यालय पर कन्याओ के लिये एक इण्टर कालेज खोले जाने की प्रबल पक्षधर है।

9. समाजवाद पार्टी शिक्षा क्षेत्र मे नकल को अभिशाप मानती है।[17]

जाति का खात्मा

1 असमानता के खिलाफ सघर्ष का एक आयाम इस देश मे जाति पाति से भी जुड़ा हुआ है। राजनीतिक व आर्थिक समानता सामाजिक क्षेत्र से जुड कर ही हो सकती है। सामन्तवादी, पूजवादी शोषण के खिलाफ छेडा गया वर्ग सघर्ष तभी सफल हो सकता है जबकि सामाजिक समानता के साथ उसे जोडा जा सके।

2 यह बात सदा ध्यान मे रखनी चाहिए कि समानता व समान अवसर एक ही चीज नही है। एक ऐसे समाज मे जिसके भीतर जन्म के आधार पर विभिन्न स्तर बन जाते हो, समान अवसर का सिद्धात समाज मे समता पैदा नही कर सकता। औरत, शूद्र, हरिजन, आदिवासी और पिछड़ी जातियो जिनमें अल्पसंख्यक भी सम्मिलित हैं, को सभी सामाजिक व्यवसायो राजनीतिक एवं शासकीय नेतृत्व स्थानो मे विशेष अवसर के सिद्धान्त पर 60% से 70%

---

17 - रजनीकान्त वर्मा-समाजवादी पार्टी के सिद्धात, वकतव्य एव कार्यक्रम से उद्धत पृष्ठ 44

आरक्षण तब तक मिले जब तक जातिगत विद्या-बुद्धि-सस्कार की भिन्नता मिट नही जाती।

3 आज पिछड़े वर्गो मे, हरिजन, आदिवासी, हिन्दुओ की पिछडी जातिया, औरत तथा अल्पसख्यक माने जा सकते है। ये आज की पूरी आबादी मे 80 प्रतिशत या और भी अधिक है।

4 आर्थिक शोषण के खिलाफ और आर्थिक असमानता के लिए किया गया सघर्ष, आमदनी की अधिकतम सीमा तथा जमीन के बटवारे की लडाई, अग्रेजी भाषा के माध्यम से ऊची जातियो द्वारा समाज की बहुसख्या के शोषण के विरूद्ध जन भाषा का प्रसार, निश्चित ही बराबरी के समाज के निर्माण मे प्रबल सहायक सिद्ध होगे लेकिन इसे साकार रूप देने के लिए पिछडो को विशेष अवसर देने का सिद्धात अनिवार्य रूप से लागू करना होगा।

5 महिलाओ, दलितो, अल्पसख्यको को एव पिछडे वर्ग के लोगो के लिए सरकारी नौकरियो मे 60 से 70 फीसदी आरक्षण का इसीलिए समाजवादी पार्टी समर्थन करती है।

7 समाजवादी पार्टी अपने ईमानदार इरादो की शुरूआत के लिए इस सिद्धात को अपनी पार्टी की समितियो के निर्माण मे तथा विभिन्न विधान मडलो, नगरपालिकाओ और नियमो के लिए उम्मीदवारो के चयन मे लागू करेगी।

8 विशेष छात्रावास की सुविधाए, छात्रवृत्तिया, मुफ्त पाठ्यपुस्तके आदि की व्यवस्था पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियो के लिए जिनमें छात्राए भी शामिल हैं, की जायेगी।

<u>औरत और युवक</u>

1. समाजवादी नियोजन मे प्रथम स्थान गांवो मे शौचालयो तथा पीने के साफ पानी के नलो की व्यवस्था को दिया जायेगा जिससे ग्रामीण औरतो के अपमानजनक कष्ट का निवारण हो सके।

2 सरकार युवक केन्द्रो की शृखला कायम करेगी, खेल कूद और शारीरिक व्यायाम को प्रोत्साहन देगी ताकि ओलाम्पिक खेलो मे भारत के प्रदर्शन मे सुधार हो सके।

3 काम करने वाली मजदूर औरतो के लिए शहरो मे सस्ते आवासो की व्यवस्था की जायेगी।

4 अनतर्जातीय विवाह सरकारी नौकरियो के लिए एक अतिरिक्त योग्यता मानी जायेगी।

भाषा नीति

1 भाषा का सवाल साधारण जनता की नजर से देखा जायेगा।

2 समाजवादी पार्टी सार्वजनिक जीवन से अग्रेजी का तत्काल वहिष्कार चाहती है।

3 अंग्रेजी का सतत् प्रयोग शिक्षा के शीघ्र प्रसार के लिए बाधक बनता है। पूरा प्रशासकीय तत्र थोडे से लोगो मे सीमित रह जाता है तथा विशाल जनसख्या प्रशासन मे शामिल होने से वचित रह जाती है। यह बराबर एक राष्ट्रीय अपमान की याद हमारे दिलो मे ताजा रखती है। और बहुत बडी जनसख्या मे एक हीन भाव बनाये रखती है तथा थोड़े लोगो मे एक दर्द का भाव पैदा करती है।

4. अग्रेजी को हटाना प्रजातात्रिक माग है। भाषावार प्रान्तो के निर्माण के सिद्धात की एक अनिवार्य शर्त उन प्रान्तो मे वहा के क्षेत्रीय भाषाओ के प्रयोग की हो जाती है। इसके बिना आधार पर प्रान्तो का विभाजन एक बेमानी बात हो जाती है।

5 भाषा के सवाल को निम्नलिखित आधार पर हल किया जाना चाहिए -

(क) प्रान्तीय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाए, अंग्रेजी के स्थान पर प्रशासन व शिक्षा का और उच्च न्यायालय व अन्य अदालतो के कार्य का माध्यम बनेगी।

(ख) अहिन्दी क्षेत्रो मे हिन्दी का प्रयोग वैकल्पिक रहेगा।

(ग) हिन्दी भाषी प्रदेशो मे अंग्रेजी के स्थान पर प्रशासकीय व शिक्षा के माध्यम का स्थान हिन्दी लेगी।

(घ) केन्द्रीय स्तर पर अहिन्दी क्षेत्रो मे अग्रेजी का स्थान सभी विभागो मे हिन्दी लेगी। अहिन्दी प्रदेशो के लिए यदि वे ऐसा चाहे अग्रेजी केन्द्रीय व्यवहार की भाषा हो

सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी चाहती है कि अहिन्दी क्षेत्रो मे केन्द्रीय कार्यालयो मे काम-काज मे क्षेत्रीय भाषाओ का प्रयोग हो और अग्रेजी तत्काल हटे। समाजवादी पार्टी इस बात को साफ कर देना चाहती है कि अहिन्दी क्षेत्रो मे हिन्दी थोपने का कोई सवाल ही नही है।

(च) अहिन्दी प्रदेशो मे कुछ ऐसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने चाहिए जिनमे शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो।

(छ) स्कूलो व कालेजों मे अग्रेजी अनिवार्य विषय न होगी। अग्रेजी के ज्ञान की कमी बडे से बडे ओहदे के लिए कभी बाधा न बनेगी।

(ज) समाजवादी पार्टी इस बात को नही मानती कि अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान की खिड़की अग्रेजी है। यह अन्य विदेशी भाषाओ जैसे रुसी, जापानी, चीनी, जर्मन आदि को प्रोत्साहन देगी तथा सीधे इन्ही भाषाओ से हिन्दुस्तानी भाषाओ मे अनुवाद को प्रोत्साहित करेगी।

(झ) पार्टी ससदीय कार्यवाही मे सभी क्षेत्रीय भाषाओ मे स्वानुवाद की व्यवस्था चाहेगी ताकि सभी अहिन्दी भाषी सदस्य अपनी क्षेत्रीय भाषा का उपयोग कर सके।

6 हर क्षेत्र मे भारतीय भाषाओ के उपयोग से ही ये सम्पन्न बनायी जा सकती हैं। उनकी सम्पन्नता की प्रतीक्षा करने मे वे कभी भी सम्पन्न नही हो सकती। समाजवादी पार्टी की राय में भारतीय भाषाओ मे अपने सस्कृति, प्रकृति तथा फारसी के उत्तराधिकार के साथ महान भाषा के सभी तत्व वर्तमान है। जरूरत है कि आधुनिक कार्यो मे उनका प्रयोग चालू हो।

धर्मनिपेक्षता

भारत एक धर्मनिपेक्ष, समाजवादी, लोकतत्रात्मक गणराज्य है। इसमे उन शक्तियो, और सगठनो का कोई औचित्य नही है जो भारतीय संविधान के इन आधारभूत सिद्धांतो के प्रतिकूल आचरण करते है। कुछ दल एव संगठन देश मे साम्प्रदायिक उन्माद फैलाकर देश को तोडने का प्रयास करने मे जुट है। उनका न सविधान मे विश्वास है न न्याय पालिका में । ऐसी साम्प्रदायिक ताकते धर्म आधारित राजनीति में विश्वास करती हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि सरकार

सविधान एव कानून से चलती है न कि आस्था से।समाजवादी पार्टी ऐसी साम्प्रदायिक शक्तियो के विरूद्ध जनसघर्ष का एलान करती है।

विदेश नीति

समाजवादी पार्टी का मानना है कि विदेशनीति का निर्धारण करते समय राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा जाना चाहिये।

दुर्भाग्य से आजादी के बाद से विदेश नीति को गलत दिशा की तरफ मोड दिया गया। चाहे कश्मीर का मामला अपनी तरफ से सयुक्त राष्ट्र सघ को भेजने का हो, तिब्बत पर चीन का स्वामित्व स्वीकार करने का हो, या श्रीलका मे शन्ति सेना भेजने का सवाल हो ये कदम पूरी तरह गलत सिद्ध हुये है।

हमारे सबध पडोसी देशो से अच्छे नही है। चीन तथा पाकिस्तान के कब्जे मे आज भी हमारी भूमि है। समाजवादी पार्टी देश को आर्थिक एव समाजिक मोर्चे पर पूरी तरह आत्म निर्भर बनाकर अपने खोये हुये सम्मान को वापस पाने का प्रयास करेगी।

सोवियत सघ ने विघटन के बाद अमेरिका के एकाधिकार का मुकाबला सशक्त गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के द्वारा ही सभव है। भारत जो इस आन्दोलन के जनक के रूप मे जाना जाता था अपने नेतृत्व की अदूरदर्शिता से इस आन्दोलन का नेता नही रह गया है।

समाजवादी पार्टी का मानना है कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन मे सक्रिय भूमिका अदा करके भारत इसे नेतृत्व प्रदान कर सकता है और पूंजीवादी देशो द्वारा विकासशील देशो के शोषण को रोक सकता है।

समाजवादी पार्टी सभी पड़ोसी देशो से मथुर सम्बन्धो की पक्षधर है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रो के आपसी सम्बन्धो के नियमन के लिये आज भी 'पचशली' के सिद्धान्तो को सर्वथा उपयुक्त मानती है। आपसी द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सीमा विवाद को हल करके खोयी हुयी जमीन को वापस पाने के लिए भारत की तरफ से शीघ्र एवं सक्रिय प्रयास किये जाने का पार्टी समर्थन करती है।

मंडल आयोग

समाज के पिछडे. वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के लिये समाजवादी पार्टी मडल आयोग की सिफारिशो को तत्काल लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

केन्द्र और राज्य सरकारो द्वारा मडल आयोग की सिफारिशा को न्यायालय मे अनिश्चित काल तक उलझाये रखने की कुटिल नीति का समाजवादी पार्टी घोर विरोध करती है।[18]

18 - रजनीकान्त वर्मा-समाजवादी पार्टी के सिद्धात, वकतव्य एव कार्यक्रम से उद्धत, पृष्ठ 48

लोक सभा चुनाव में 1996-99 तक संक्षिप्त विवरण तालिका
लोक सभा निर्वाचन 1998
दलवार स्थिति

कुल सीट - 543
घोषित - 535

वर्ष 1996

क्र.	दल	सीटें
1	भारतीय जनता पार्टी	162
2	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	138
3	जनता दल	29
4	भारतीय कम्युनिस्ट (एम)	32
5	तमिल मनीला कांग्रेस (मू)	20
6	समाजवादी पार्टी	17
7	तेलगुदेशम पार्टी	17
8	द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	16
9	राष्ट्रीय जनता दल	16
10	शिव सेना	15
11	मा0 कम्युनिष्ट	12
12	बहुजन समाजपार्टी	11
13	शिरोमणि अकाली	8
14	समता पार्टी	5
15	रिवोल्यूशनरी सोशलिस्टपार्टी	5
16	असम गण परिषद	5
17	आल इडिया इंदिरा कांग्रेस (तिवारी)	4
18	आल इडिया फारवर्ड ब्लाक	2
19	हरियाणा विकास पार्टी	3
20	समाजवादी जनता पार्टी	3
21	मुस्लिम लीग	2
22	मजलिस ए इत्तिहादुल मुसलमान	1
23	अटोनोमिस स्टेट डिमाड कमेटी	1
24	झारखण्ड मुक्तिमोर्चा	1
25	महाराष्ट्र गोमान्तक पार्टी	1
26	केरल कांग्रेस (एम)	1
27	सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट	1
28	यूनाइटेड गोवा डेमोक्रेटिक पार्टी	1
29	भा0 कि0 कामगार पार्टी	1
30	निर्दलीय	9
31	मनोनीत	2
32	रिक्त	3
	कुल	**544**

वर्ष 1998

दल	सीटें
भाजपा एव सहयोगी दल	
भारतीय जनता पार्टी	177
अन्ना द्रमुक	18
समता पार्टी	12
बीजू जनता दल	9
शिरोमणि अकाली दल	8
तृणमूल कांग्रेस	7
शिव सेना	6
पट्टलि मक्कल काच्ची (पीएमके)	4
मारू मलारची द्रमुक (एम डी एमके)	3
लोकशक्ति	3
हरियाणा विकास पार्टी	1
जनता पार्टी	1
कुल (भाजपा और सहयोगी दल)	**249**
कांग्रेस और सहयोगी दल	
कांग्रेस	141
राष्ट्रीय जनता दल	17
रिपब्लिकन पार्टी आफ इण्डिया	4
मुस्लिम लीग	2
केरल कांग्रेस (एम)	1
कुल (कांग्रेस और सहयोगी दल)	**165**
सयुक्त मोर्चा	
मार्कसवादी कम्युनिस्ट पार्टी	32
समाजवादी पार्टी	20
तेलगुदेशम	12
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	9
जनता दल	6
द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम	6
रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	5
तमिल मनीला कांग्रेस (एम)	3
फारवर्ड ब्लाक	2
धर्मरिपेक्ष कांग्रेस	1
कुल	**96**

निर्दलीय व अन्य

दल	सीटें		दल	सीटें	
बहुजन समाज पार्टी	5		मजलिसे इ मुसलमीन	1	UDF
अरूणाचल कांग्रेस	2	BJP	रा0 जनता पार्टी	1	CONG
समाजवादी जनता पार्टी	1	UDF	यू0 डे0 पा0	1	
आटोनामस स्टेट डी-का	1	UDF	हरियाणा लोकदल	4	BJP
सिक्किम-डे प्रा	1		तमिल राजीव कांग्रेस	1	BJP
यू0 एम0 एफ0	1	UDF	निर्दलीय	6	
			कुल	**25**	

UTTAR PRADESH

LOK SABHA GENERAL ELECTION – 1998
SUMMARY OF ASSEMBLY SEGMENT WISE DETAILED RESULTS

Total Parliamentary Constituencies : - 85

Total No. of Assembly Segments :- 425

PARTY NAME	No of Assembly won
BHARATIYA JANTA PARTY (BJP)	252
BHARATIYA KISAN KAMGAR PARTY (BKKGP)	2
BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP)	32
INDIAN NATIONAL CONGRESS (INS)	9
INDEPENDENT (IND)	7
SAMATA PARTY (SAP)	6
SAMAJWADI JANTA PARTY (RASHTRIYA) (SJP)	3
SAMAJWADI PARTY (SP)	114
Grand Total :-	**425**

UTTAR PRADESH

Lok Sabha General Elections 1999

Assembly Segment Wise Party Performance

Name of Party	**No of assembly segments leading**
Samajwadi Party	129
Bharatiya Janata Party	125
Bahujan Samaj Party	88
Indian National Congress	43
Rashtriya Lok Dal	14
Akhil Bhartiya Lok Tantrik Congress	10
Independent	6
Samajwadi Janta Party (Rashtriya)	5
Apna Dal	3
Janata Dal (United)	2
Total Assembly Segments :	**425**

(N) Party wise Female Candidates Performance

	PARTY NAME	*Contested*	*Won*
PSJP	Parıvartan Samaj Party	2	
BKD	Bahujan Krantı Dal	1	
BRPP	Bharatıya Republıcan Paksha	2	
AJBP	Ajeya Bharat Party	3	
IND	Independent	17	1
AD	Apna Dal	1	
UKKD	Uttarakhand Krantı Dal	1	
CPI	Communıst Party of Indıa	1	
INC	Indıan Natıonal Congress	14	3
BSP	Bahujan Samaj Party	3	1
SP	Samajwadı Party	9	3
BJP	Bharatıya Janata Party	5	1
CP(ML)(L)	Communıst Party of Indıa	1	
AIMLF	All Indıa Muslım Forum	1	
RPI	Republıcan Party of Indıa	1	
		63	9

(O)Party Wise Winning and runner up statistics

	PARTY NAME	*ContestedAt*	*1st Position*	At IInd Posıtıon
BJP	Bharatıya janata Party	77	29	35
SP	Samajwadı Party	84	26	22
BSP	Bahujan Samaj Party	85	14	15
INC	Indıan Natıonal Congress	76	10	08
IND	Independent	610	1	0
RLD	Rashtrıya Lok Dal	7	2	3
ABTC	Akhıl Bhartıya Lok Tantrık Congress	4	2	1
JD(U)	Janata Dal (Unıted)	2		1
SJP(R)	Samajwadı Janata Party (Rastrıya)	2	1	

General Election -1999

Party wise Performance ***Uttar Pradesh***

PARTYNAME		candidates Contested	Won	Vote Secured	Percent 1999	Secured 1998
BJP	Bharatiya Janata Party	17	29	15019970	27 64%	36 49%
SP	Samajwadi Party	84	26	13078686	24 05%	28 69%
BSP	Bahujan Samaj Party	85	14	12001855	22 08%	20 91%
INC	Indian National Congress	76	10	8001649	14 72%	6 02%
IND	Independent	610	1	1965727	3 62%	2 79%
RLD	Rashtriya Lok Dal	7	2	1352694	2 49%	
AD	Apna Dal	45		841429	1 55%	0 94%
ABLTC	Akhil Bhartiya Lok Tantrik Congress	4	2	818713	1 51%	
JD (U)	Janata Dal (United)	2		321294	0 59%	
SJP (R)	Samajwadi Janta Party (Rashtriya)	2	1	249621	0 46%	0 47%
CPI	Communist Party of India	11		150516	0 28%	0 18%
NLP	National Loktantrik Party	27		127382	0 23%	0 25%
AJBP	Ajeya Bharat Party	44		48316	0 09%	0 03%
JD(S)	Janata Dal (Secular)	18		46943	0 09%	
CPI(ML)(L)	Communist Party of India (Marxist-Lennini)	9		38076	0 07%	0 05%
PMSP	Pragatisheel Manav Samaj Party	6		36920	0 07%	0 01%
SHS	Shivsena	16		29610	0 05%	0 05%
BRPP	Bhartiya Republican Paksha	9		25713	0 05%	
UKKD	Uttarakhand Kranti Dal	4		14302	0 03%	0 05%
JP	Janata Party	2		14214	0 03%	
CPM	Communist Party of India (Marxist)	2		13884	0 03%	0 22%
SSD	Shoshit Samaj Dal	4		12795	0 02%	0 00%
JSAP	Jan Satta Party	4		11024	0 02%	
AIMLF	All India Muslim Forum	3		10007	0 02%	0 00%
LS	Lok Shakti	3		9244	0 02%	0 01%
PSJP	Parivartan Samaj Party	6		7963	0 01%	
MUL	Muslim League Kerala State Committee	5		7851	0 01%	0 00%
BSD	Bhartiya Samaj Dal	1		7607	0 01%	

General Elections-1999

Party Wise performance ***Uttar Pradesh***

PARTYNAME		Candidates Contested	Won	VoteSecured	Percent 1999	Secure 1998
ABJS	Akhil Bharatiya Jan Sangh	1		7403	0 01%	0 00%
ASP	Ambedkar Samaj Party	8		7260	0 01%	
ABBP	Akhil Bhartiya Berozgaar Party	3		7134	0 01%	0 00%
LSWP	Loktantrik Samajwadi Party	2		6854	0 01%	0 01%
ABHM	Akhil Bharat Hindu Mahasabha	3		6219	0 01%	0 00%
GSP	Gareebian Samaj Party	2		4725	0 01%	0 00%
RPI	Republican Party of India	3		4514	0 01%	0 00%
RUD	Rashtriya Unnatisheel Dal	1		4104	0 01%	
BND	Bhartiya Naujawan Dal	1		3895	0 01%	
SVSP	Savan Samaj Party	1		3663	0 01%	
IUML	Indian Union Muslim League	1		3069	0 01%	0 00%
AIRKC	All India Rajiv Krantikari Congress	2		2993	0 01%	
BLKD	Bharatiya Lok Kalyan Dal	1		2896	0 01%	
BBMKD	Bharatiya Berozgar Mazdoor Kisan Dal	1		2706	0 00%	
GGP	Gondvana Gantantra Party	1		2455	0 00%	0 01%
JKNPP	J & K National Panthers Party	1		1998	0 00%	
HDVP	Hind Vikas Party	1		1641	0 00%	
RSD	Rashtriya Sawarn Dal	1		1407	0 00%	
SSJP	Sanatan Samaj Party	1		1333	0 00%	
ABLTP	Akhil Bharatiya Loktantra Party	1		1265	0 00%	0 00%
BKD	Bahujan Kranti Dal	1		1218	0 00%	0 00%
RAM	Rashtriya Aikta Manch	1		1169	0 00%	0 00%
BKD(J)	Bahujan Kranti Dal (Jal)	1		957	0 00%	0 00%
PSP	Prapat School Party	1		858	0 00%	
BNJS	Bharat Nav Jyoti Sangh	1		806	0 00%	
AIMF	All India Minorities Front	1		628	0 00%	
ABP	Ambedkarbadi Party	1		543	0 00%	
KRD	Kranti Kal	1		344	0 00%	0 00%
ABSR	Akhil Bharatiya Shivsena Rashtrawadi	1		244	0 00%	

Lok Sabha General Election – 1999

State At A Glance

a	Total Electorates	:	10,31,33,770	
b	Total Votes Polled	:	5,50,78,345	(53 40%)
c	Total Valid Votes Polled	:	5,43,48,306	(98 67%)
d	Total Invalid Votes Polled	:	7,30,039	(1 33%)

Statistics of Electoral data and Candidate performance

(A)	Maximum Contesting Candidates		33 - GONDA	(32 Candidates)
(B)	Minimum Contesting Candidates	.	75 – HATHRAS	(6 Candidates)
(C)	Maximum Electoral Constituency		79 – HAPUR	(1577173)
(D)	Minimum Electoral Constituency		3 – ALMORA	(971789)
(E)	Highest Polling %age		13 – PILIBHIT	(66 33%)
(F)	Lowest Polling %age		77 – KHURJA (SC)	
			01 – TEHRI GARWAL	(38 9%)
(G)	Candidates getting maximum Votes		MANEKA GANDHI FROM 13 PILIBHIT	(4,33,421)
(H)	Largest Winning Margin	:	SONIA GANDHI (INC) Defeated by DR SANJAY SINGH (BJP) 300012 votes [25-AMETHI]	
(I)	Lowest Winning Margin	.	PYARE LAL SANKHWAR (BSP) Defeated by ARUN KUMAR KORI (SP) 105 votes [63 GHATAMPUR (SC)]	
(J)	Total number of Candidates	.	1208	
(K)	Total Candidates whose deposits Forfeited		963	
(L)	Total number of Female Candidates		63	
(M)	Total Female Elected	.	9	

विधान सभा चुनाव वर्ष ,96 के मुकाबले लोकसभा चुनाव वर्ष 99 मे विधान सभा क्षेत्रवार ब.स. पा./ समाजवादी पार्टी की स्थिति का एक तुलनात्मक अध्ययन

ब. स. पा. में 1996 मे 67 विधान सभा क्षेत्रों मे सफलता प्राप्त की थी जिसमे से वर्ष 99 में सम्पन्न चुनाव परिणामो के अनुसार :-

अ- 32 क्षेत्रो मे अपनी जीत बरकरार रखी, 35 क्षेत्र अन्य दलो के हाथो खोये

19 क्षेत्रो मे द्वितीय स्थान पर रही,

13 क्षेत्रो मे तृतीय स्थान पर रही,

03 क्षेत्रो मे चतुर्थ स्थान पर रही।

ब- समाजवादी पार्टी ने 14 क्षेत्र ब स पा से छीने

भा ज पा ने 10 क्षेत्र बसपा से छीने

काग्रेस ने 5 क्षेत्र ब स पा से छीने

लोकतात्रिक काग्रेस ने क्षेत्र बसपा ने छीना

जनता दल (यू) ने 2 क्षेत्र ब स पा से छीने

स ज.पा ने क्षेत्र ब स सपा से छीना

लोकदल ने क्षेत्र ब स पा से छीना

निर्दल ने क्षेत्र बसपा से छीना

....

कुल छिने क्षेत्रो का योग 35

....

समाजवादी पार्टी ने वर्ष 1996 मे 20 क्षेत्रो मे **अपने प्रत्याशी नहीं खड़े किए थे। इन क्षेत्रो में तालमेल के तहत अन्य दलो के प्रत्याशियो ने बसपा का मुकाबला किया।**

वर्ष 99 में एक विधान सभा क्षेत्र मा0 चन्द्र शेखर जी के क्षेत्र मे था जहां स.पा. ने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था। स.पा. ने केवल 66 स्थानो पर सघर्ष किया।

अ- 14 क्षेत्रो बसपा से छीने

23 क्षेत्रों में द्वितीय स्थान पर रही

23 क्षेत्रो मे तृतीय स्थान पर रही

06 क्षेत्रो मे चतुर्थ स्थान पर रही

स्रोत- समाजवादी पार्टी कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ 19 विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ

अध्याय—५

समाजवादी पार्टी के राजनीतिक,सामाजिक एवं आर्थिक बिन्दु

अध्याय 5

समाजवादी पार्टी के सामाजिक, राजनितिक एवं आर्थिक विचार बिन्दु

1.स्थापना सम्मेलन

समाजवादी पार्टी का दो दिवसीय स्थापना सम्मेलन 4–5 नवम्बर 1992 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सम्पन्न हुआ।

अध्यक्षीय भाषण–

समाजवादी पार्टी के स्थापना सम्मेलन में 4 नवम्बर 1992 को श्री मुलायम सिंह यादव जी ने सम्मेलन को सम्बोधिक करते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि–

समाजवादी साथियो,

लखनऊ की इस सर जमीन पर जो सदियों से भाईचारा, आपसी सहयोग, एक साथ मिलकर रहने की परम्परा तथा आजादी, आत्म सम्मान और इंसाफ के लिए मर–मिटने की तबीयत के लिए इतिहास में मशहूर रही है, भारत के कोने–कोने से आये समाजवादी साथियों का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है।

मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अयोध्या से मिला यह शहर राम राज्य की कल्पना को हमेशा साकार करता रहा है जहॉ आदमी को आदमी की शक्ल में देखा जाता रहा है। अवध के नबाबों ने भी वही संस्कृति अपनाकर यह साबित कर दिया था कि भारत का यह हिस्सा, उन संकुचित विचारधाराओ से बहुत आगे है जो मजहबी उन्माद या अलगाववाद के प्रतीक हैं।

1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में हिन्दू और मुसलमानों द्वारा एक जुट होकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की दास्तान को पढ़कर मन रोमांच हो आता है। तात्या टोपे, बेगम हजरत महल औ झांसी की रानी, भारत के उस दिल की धड़कन की गुनगुनाहट हैं जिन्हें राष्ट्रीयता, आजादी और आत्म सम्मान के लिए शहादत देने के लिए सदैव याद किया जाएगा।

ऐसी धरती पर आज भारत के समाजवादी लगभग 20 वर्ष बाद समाजवाद के नाम पर एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं। यह गुजरे हुए 15–20

साल भारत के इतिहास के बड़े ही खट्टे–मीठे साल थे। 1977 मे लोकनायक जय प्रकाश नारायण के आह्वान पर जनता पार्टी बनी थी। हमने उस लाल झंडे को जिसको लेकर हमारे नेता जय प्रकाश, नरेन्द्र देव, डा0 राम मनोहर लोहिया, यूसूफ मेहर अली जैसे लोगों ने समता वाले समाज की रचना के लिये जन आंदोलन चलाये थे, जनता पार्टी को सौप दिया था। हमारा लक्ष्य है, सत्ता हासिल करके जनहित मे उस व्यवस्था को बदलें जिससे गरीब को रोटी, बेकार को काम और राष्ट्र को सम्मान हासिल हो।

जनता पार्टी जब बनी थी, हमारा मन साफ था। हमने बडी ईमानदारी से इस पार्टी को जन–जन तक पहुँचाने का काम किया। सोशलिस्टों का जनहित में लगातार संघर्ष और डा0 लोहिया के विचारों के आधार पर जन–मानस को बदलने की भूमिका रही है। हमें याद है जब 1962 में डा0 लोहिया, भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से फूलपुर के ससदीय क्षेत्र के चुनाव में जाकर टकराये थे, उस समय देश में एक नई लहर का आगमन हुआ था। लोहिया ने उस चुनाव में कहा था कि मैं एक चट्टान से टकरा रहा हूँ। मैं जानता हूँ चट्टान को तोड़ नहीं पाऊँगा लेकिन उसको चटका जरूर दूँगा। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस को हराकर बनी थी वह लोहिया के उस अभियान का नतीजा था जो 1962 में उन्होंने शुरू किया था। जनता पार्टी जब बनी थी उस समय उन्होंने ऐसे दल भी थे जो सोशलिस्ट पार्टी को छोडकर कांग्रेस मे जा मिले थें। एक ऐसा दल भी जनता पार्टी में आकर मिल गया था जिसके सोच का नतीजा, राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की हत्या थी। हमने उस पर भी यकीन किया था, क्योंकि हमारा मानना रहा है कि भूल आदमी ही करता है और अपने को सुधारने का मौका उसे मिलना चाहिये।

हमारी ईमानदारी ही हमारे लिये घातक बन बैठी। जनता पार्टी की सरकार के टूटने का कारण यही रहा कि गैर समाजवादी जो जनता पार्टी में शामिल हुये थे, उनका लक्ष्य था सत्ता का उपयोग करो और अपने घटक को मजबूत बनाकर जनता पार्टी को तोड दो। इसी क्रम में जनता पार्टी की सरकार टूटी और जनता पार्टी भी बिखरी क्योंकि सत्ता का उपयोग व्यवस्था बदलने के लिए नहीं किया गया था।

1977 से लेकर 1991 तक का दौर समाजवादियो के भटकन का दौर रहा है। हर बार मजहबी तनाव फैलाने वाले दल ने यह प्रयास किया कि देश के अंदर फिरकापरस्ती बढे, हिन्दू–सिख, हिन्दू–मुसलमान, हिन्दू–ईसाई के बीच तनाव बढ़े, दंगा, हिंसा और मारकाट हो तथा धार्मिक उन्माद को बढ़ाकर सत्ता प्राप्त की जाय। 1977 से 1990 के बीच भाजपा ने यही किया। फलस्वरूप अलगाव, टूट और हिसा का शिकार सारा देश होता रहा और आज भी देश उसी दौर से गुजर रहा है।

यह एक विडम्बना ही रही कि इस बीच चार–चार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, दिल्ली की कुर्सी पर बैठे। लेकिन अपने को प्रगतिशील कहलाने वाले प्रधानमंत्रियों ने भी व्यवस्था बदलने के लिये, एक भी कदम नहीं उठाया।

उस उथल–पुथल के दौर मे, सबसे ज्यादा हमला सोशलिस्टों पर किया गया क्योंकि यथास्थितिवादी यह जानते थे कि समाजवादी अगर एकजुट रहे तब तब्दीली की ऑधी को रोका नहीं जा सकता। अतः उनका प्रयास, समाजवादियों को तोड़ने का लगातार चलता रहा जो आज भी जारी है।

भारत की दुर्दशा का एक कारण समाजवादियों का विखराव भी रहा है। समाजवादी जब तक एक–जुट थे, सरकार और समाज, दोनों पर उनका अंकुश रहता था। सरकार की जनविरोधी नीतियों का जहाँ एक तरफ समाजवादी विरोध करते थे वहीं विकल्प भी सामने रखते थे और उसके लिए जनमानस बनाने का अभियान भी चलाते थे।

यहाँ देश के सभी समाजवादियों का ध्यान एक कुटिल साजिश की तरफ आकर्षित करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। वह साजिश है देश के इतिहास से समाजवादियों के गौरवशाली योगदान को मिटाने की। भारत छोडो आन्दोलन की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर संसद के केन्द्रीय हाल में राष्ट्रपति द्वारा पढ़े गये भाषण में डा0 लोहिया का नाम तक नहीं लिया गया। जिस लोहिया के बगैर भारत छोड़ो आन्दोलन निर्जीव हो गया होता उसे याद न करना महज एक भूल नहीं कहा जा सकता है। यह एक सोची समझी साजिश का एक अंग है जिसके तहत लोहिया के अलावा जय प्रकाश, यूसूफ मेहर अली, कर्पूरी ठाकुर, राज नारायण तथा राम सेवक यादव जैसे महान समाजवादियों द्वारा भारत के पुनर्निमाण के लिये किये गये योगदान को

नकारने का प्रयास किया जा रहा है। हम इन नेताओं के शानदार इतिहास को देश की एक बेशकीमती धरोहर मानते हैं और इसके स्वतन्त्र अस्तित्व को बनाये रखने के लिये बचनबद्ध है।

1948 से 1975 तक समाजवादियों का शानदार इतिहास रहा है। समाजवादियों ने ही जन आनदोलन चलाकर, यह मांग की थी कि अलाभकर खेती पर से लगान हटाया जाये, सबसे ज्यादा और सबसे कम आमदनी के बीच का फर्क एक और दस के बीच हो–हमारा नारा था–

"सौ से कम, न हजार से ज्यादा
सोशलिस्टों का यही तकाजा।"

भारतीय भाषाओं को स्थापित करने की मांग, हमीं ने की थी। अंग्रेजी हटाओ, भारतीय भाषाओं को लाओं का नारा समाजवादियों ने ही दिया था।

भारत–पाक की जनता के बीच सद्भावना पैदा करने का, तिब्बत को आजाद कराने का, गोवा से पुर्तगाली साम्राज्यवादियों को हटाकर गोवा स्वतन्त्र कराने का, नेपाल में जनतंत्र की स्थापना की, स्वेज कैनाल पर अंग्रेजी हमले के मिश्र के राष्ट्रपति के साथ खड़े होने का, अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ स्वयं डा0 लोहिया द्वारा सत्याग्रह करने का, एशिया के समाजवादियों को एक मंच पर लाने का, दामों की लूट बंद करके एक दाम नीति बनाने का तथा भारत में 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत विशेष अवसर, दलितों, पिछडों,औरतो तथा अल्पसंख्यकों को देने का तथा खर्च पर बंदिश लगाने का, ऐसे जानदार अभियान थे जिसके सामने मजहबी जुनून फैलाकर, सत्ता पर काबिज होने वालों के मंसूबे बराबर परास्त होते रहे। साथ ही कांग्रेस के बड़े से बडे नेता तथा उस समय के प्रधानमंत्री चाहे जवाहर लाल नेहरू रहे हों या इंदिरा गॉधी पर भी अंकुश लगाने में समाजवादी सफल रहे हैं।

लोहिया ने राजनीति को गाँव के लोगों तक पहुँचाकर उन्हें समाजवादी विचारधारा से जोड़ दिया था। लोकसभा में जब लोहिया ने तीन आना बनाम 15 आना की बहस के माध्यम से यह उजागर कर दिया था कि भारत की गरीब जनता की तीन आना रोज की आमदनी है, तब सारा देश चौंक पड़ा था। बड़े–बड़े अर्थशास्त्री भी सकते में आ गये थे।

समाजवादियों ने जनमानस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, चाहे विधान सभा रही हो या लोकसभा, सोशलिस्टों ने इन पंचायतों को जनता के दु:ख, दर्द, आशा और विश्वास का दर्पण बनाने का प्रयास किया था।

जहाँ देश की ऐसी हालत है, वहीं कुछ राजनैतिक दल इस कोढ में खाज का काम कर रहे हैं। जरूरत तो इस बात की है कि देश की अर्थ व्यवस्था को सुधार कर करोड़ों बेरोजगार लोगों को काम दिया जाये। उत्पादन बढ़ाया जाये, परती और ऊसर जमीन को खेती लायक बनाया जाये, पशुधन को बढ़ाकर गाँव वालों को पशु दिया जाये, गॉव को स्वावलम्बी बनाने के लिये वहॉ सड़क, बिजली, स्कूल तथा अस्पताल का निर्माण किया जाये लेकिन केन्द्र की सरकार हो या प्रदेश की, ऐसा कुछ नहीं कर रही है।

ग्राम उद्योग, लघु उद्योग तथा पशुधन यही केन्द्र बिन्दु भारत के आर्थिक विकास के हो सकते हैं। सरकार यह भूलती जा रही है कि भारत एक कृषि प्रधान देश शताब्दियों से रहा है। यहॉ की 85 प्रतिशत जनता, गॉवों में बसती है। उसका उत्थान गॉव के विकास से तथा खेती के विकास से ही सम्भव है। लेकिन इस तरफ न सरकार का ध्यान है और न अन्य राजनैतिक दलों का ही है। भाजपा रोटी और रोजगार की समस्या को हल करने के बजाय, धर्म और मजहब की भावना को भड़का कर देश के अंदर हिंसा को बढ़ावा देने का काम कर रही है। यह ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय अखंडता के नाम पर, राष्ट्र को ही खंडित करने में जुटी है। ये वही लोग हैं जो उन नेताओं की तस्वीर लेकर चलते हैं जो आजादी के आदोलन के विरोधी थे। जो अंग्रेजी हुकूमत के सलाहकार थे।

भाजपा इस देश और समाज को तोड़ने का षडयन्त्र कर रही है और कांग्रेस हर वक्त कभी प्रत्यक्ष रूप से, कभी परोक्ष रूप से इस साजिश में शामिल रही है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश की खुली लूट करने की छूट देने, तथाकथित उदार अर्थनीति के नाम पर पूंजीपतियों को और ज्यादा शोषण का मौका देने वाली कांग्रेसी नीतियों को भाजपा का समर्थन है। दोनों दल सत्ता बनाये रखने के लिये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में कांग्रेस के सामने तो जरूरत से ज्यादा मजबूरी यह भी है कि वह अपनी पूंजीवादी नई आर्थिक नीतियों के लिये भाजपा के समर्थन की छिपी हुयी

इच्छा रखे हैं। राष्ट्रीय नीतियों को आर्थिक नीति सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इसीलिए कांग्रेस जब भाजपा की समान आर्थिक नीतियो के निकट आने के लिये भाजपा के फांसीवादी जीवन–दर्शन को लोकशाही की नकली चादर ओढ़ाकर तालमेल के अवसरों की तलाश करती रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर भी भाजपा सरकार के खिलाफ कार्यवाही न करना कांग्रेस की इसी नीति का अंग था। ये राजनैतिक दल भारत के गरीब, सर्वहारा, किसान, मजदूर, नवजवान और महिलाओं के किस्मत पर कुंडली मारकर बैठै हैं और भ्रष्टाचार, हीनता, उत्पीड़न और बेकारी को जन्म देते जा रहे हैं।

समय आ गया है जब उनके आतंक से जनता को मुक्त कराया जाये। समाजवादी पार्टी इस अभियान का दूसरा नाम है।

होशियार और चैतन्य हो जायें। दुनिया की आबादी के 3/4 हिस्सा संसार के काले–पीले लोग हैं जो एशिया, अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारतीय उपमहाद्वीप में बसते हैं।

लगभग 6 अरब की संसार की आबादी में हम 5 अरब के लगभग हैं। हमारे पास धरती, खेत, खनिज पदार्थ, जंगल, पहाड़, समुद्र, जल, जीव–जन्तु और जनशक्ति है। हम मेहनत करना जानते हैं करते हैं फिर भी भूखे हैं। हमारी सम्पदा को चन्द मुट्ठी भर साम्राज्यवादी सदियो से लूट कर लेते जा रहे हैं। हमारे यहॉ भूख, बीमारी, बेकारी, और असंतोष है। हम अभाव का जीवन व्यतीत कर रहे हैं–आखिर क्यों? इस सवाल की तरफ ध्यान देना अब जरूरी है क्योंकि साम्राज्यवादी चाल अब हमारी सम्पदा को लूटने का विकराल रूप लेती जा रही है।

दुनियॉ के मंच पर सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, साम्राज्यवादियों तथा पूंजीवादी ताकतों का हौसला बुलंद हो गया है। जिस सोवियत संघ को फासिस्ट हिटलर दूसरे महायुद्ध में परास्त नहीं कर पाया था, उसे अमरीका देखते–देखते तोड़ कर टुकड़ों में बॉटने में सफल हो गया।

मार्क्स के सपनों का रूस बिखर गया है और यूगोस्लाविया आज समता–साम्यवाद का प्रतीक न रहकर मजहबी उन्माद में जल रहा है। वहाँ हिंसा भड़काकर उस विकास की परिधियों को तहस–नहस किया जा रहा है

जो वहाँ की मेहनतकश जनता ने अपनी कुर्बानी से प्राप्त किया था। यही हाल लैटिन अमरीकी देशों, दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया का है। लोगों को आपस में लड़ाकर साम्राज्यवादी ताकतें सारी दुनियॉ की पूँजी पर कब्जा करना चाहती हैं।

समाजवादी पार्टी, इस चुनौती को समझती है और संसार के रंगीन चमड़ी वाले लोगों, एशिया, अफ्रीका और अमरीका के काले लोगों का आवाह्न करती है कि वे साम्राज्यवादियों के बॉटो और लूटो" सिद्वान्त को समझें और एकजुट होकर इस शोषण के खिलाफ संघर्ष करने का मन बनायें।

भारतीय उपमहाद्वीप में असंतोष और हिंसा को समाप्त करने का हम आवाह्न करना चाहते हैं। पाकिस्तान की जनता को हम कहना चाहते हैं कि भारत की जनता के मन में पाकिस्तान के जन्म से लेकर आज तक कभी भी बुरी भावना नहीं रही है। हम चाहते हैं कि हम भाई–भाई की तरह रहे, दोनों देश तरक्की करें और अपने–अपने देश में फैली हुई गैर बराबरी, भुखमरी, बेकारी, हिंसा और आतंक के माहौल को समाप्त करें।

पाकिस्तान की जनता से हम यह अपील करना चाहते हैं कि वह अपनी सरकार पर दबाव डाले और आतंकवाद, जो पाकिस्तान की सीमा से भारत भेजा जा रहा है उस पर रोक लगाये। भारत–पाक का इतिहास एक है, हम एक महाद्वीप के बशिन्दे हैं। भारत की माटी की महक और गमक में नफरत कभी नहीं रही है। समाजवादी पार्टी भारत–पाक की जनता से अपील करती है कि वे भारत–पाक बंगला देश महासंघ बनाने के लिये पहल करे। भारत–पाक रिश्तों में मिठास भरने का यही सही कदम है। पिछले 45 वर्षों में भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण वे गाँव जो उत्पादन और खुशहाली के केन्द्र थे, आज वीरान और उजाड़ होते जा रहे हैं।

गाँव की पैदावार का दाम सरकार तय करती है। लेकिन कच्चा माल जो किसान पैदा करता है, वही जब कल कारखानों से सामान बनकर आता है तब सरकार उनके दाम पर अंकुश नहीं रखती है। नतीजा यह है कि किसान और उपभोक्ता दोनों पिस रहे हैं और पूँजीपति तथा आढ़तिया मनमाने ढंग से दामों की लूट करते जा रहे हैं।

बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल , ग्राम उद्योग, लघु उद्योग, पशुधन सबका अकाल गाँवों में है। इसके विपरीत शहर का तथाकथित विकास होता जा रहा है।

समाजवादी पार्टी इस प्रक्रिया को समाप्त करने का संकल्प करती है और वादा करती है कि आने वाले दिनों में हमारा प्रयास होगा कि गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वह सब किया जाए जिससे गाँव खुशहाल हो।

आज गाँव की संस्कृति को बचाने आत्मनिर्भर बनाने, रोजगार के नये–नये अवसर खोजने, अनाज का उत्पादन बढ़ाने, विदेशी सभ्यता से भारतीय संस्कृति को बचाने और जनतन्त्र को जनमुखी बनाने के लिए जरूरी हो गया है कि गाँव की तरफ चला जाये।

समाजवादी पार्टी गरीबो, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों, ऊँची जाति के गरीब लोगों और नवजवानों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी, एक आन्दोलन, एक लहर तथा, एक संकल्प है।

समाजवादी पार्टी अंगेजों की जगह मातृभाषा की पक्षधर है। भारत के गरीब तथा मेहनतकश तबकों के दिल की घड़कन है। उनके सपनों को साकार करने का माध्यम है।

हम जानते हैं कि हमारे पास साधन की कमी है। हमें दो मोर्चो पर एक साथ लड़कर अपना रास्ता बनाना है। दिल्ली तथा प्रदेश की सरकारें हमें पीड़ित करने पर आमादा हैं। साम्प्रदायिक शक्तियों और पूँजीवादी व्यवस्था, अंग्रेजी और विदेशी सभ्यता के नकलची लोगों का विरोध सहना है। लेकिन समाजवादी पार्टी देश की 2 प्रतिशत लोगों की पार्टी नहीं हैं। बल्कि यह पार्टी है भारत के 98 प्रतिशत उन लोगों की, जिनकी जिन्दगी में उल्लास की जगह उदासी ने ले ली है।

आज देश के लोग विभिन्न राजनैतिक दलों के खोखले नारो, सिद्धान्तहीनता व कार्यक्रम शून्यता से निराश हैं। जनता इस देश में ऐसा राजनैतिक विकल्प चाहती है जो उनकी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर सके, जो बुराई के विरुद्ध छाती तानकर लगातार चलने वाली लड़ाई चला सके और वह राजनैतिक विकल्प है समाजवादी पार्टी।

हम सत्य के लिये आग्रह करते रहेंगे। हमारा लक्ष्य समता वाले समाज की स्थापना है–हमारा संघर्ष सिविल नाफरमानी के नियमों के अनुसार होगा। हम जालिम के जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं, हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं, जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेगे। हमें यकीन है समाजवादी पार्टी आज की उमस को खत्म करने में सफल होगी।[1]

राजनैतिक प्रस्ताव–

समाजवादी पार्टी के स्थापना सम्मेलन में जो राजनैतिक प्रस्ताव पास हुआ वह इस प्रकार है–

राष्ट्रीय सम्मेलन का दृढ़ मत है कि आजादी के 45 वर्ष बाद आज देश टूट के कगार पर है। आज साधारण भारतीय का आत्मबल टूट चुका है। वह निराश, उदास और कहीं क्रोध में है। सत्ता उसके लिए एक भयानक राक्षस की तरह है जो हर पल उसका शोषण करती जा रही है। गाँव वीरान हो रहे है। खेती और किसान उपेक्षित हैं। बेकारी सुरसा की तरह बढ़ती जा रही है।

देश में सादगी की जगह विलासिता, अहिंसा की जगह हिंसा, आत्म सम्मान की जगह चाटुकारिता, स्वदेशी की जगह विदेशी चीजों की भूख, भाईचारा की जगह नफरत और उत्पादन की जगह विदेशी कर्ज ने ले ली है। सारा देश सत्ता के संरक्षण में अराजकता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है।

सरकार, नौकरशाह और पूँजीपति का त्रिकोण एक दूसरे की रक्षा करते हुए लूट और अत्याचार को कायम रखने में एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रतिभूति घोटाले से जुड़े लोगों को बचाने के प्रयास इसी सन्दर्भ में देखने होंगे।

परिणाम स्वरूप असन्तोष की हवा चारों तरफ फैल रही है। भूख और अपमान के कारण विद्रोह एवं बदले की भावना सारे देश में व्यापक पैमाने पर फैलती जा रही है जिससे आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ रहा है।

सम्मेलन का मानना है कि राजनैतिक दल दिशाहीनता के शिकार हैं। कांग्रेस सरकार ने देश को महानगरीय संस्कृति, विदेशी कर्ज और विलासिता में आकण्ठ डुबो दिया है। खाद, डीजल, पेट्रोल की कीमतों में भारी वृद्धि करके देश में खाद्य उत्पादन को गिराने की मूर्खतापूर्ण कार्यवाही के

---

1. समाजवादी पार्टी के 'स्थापना सम्मेलन' लखनऊ मे 4 नवम्बर 1992 को दिया गया अध्यक्षीय भाषण

साथ–साथ विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश में खुली छूट देकर देश को पश्चिमी ताकतों का गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के दबाव में भारत का बजट और योजनाएं बनायी जा रही हैं।

पूँजीवादी ताकतों का न केवल देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप है बल्कि भारतीय विदेश नीति को भी प्रभावित किया जा रहा है।

पश्चिम एशिया में अरब देशों के समर्थन की भारत की स्पष्ट नीति थी। फिलिस्तीनियों को जब तक गृह देश न मिले, इजरायल को भारत द्वारा मान्यता दने का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिये था किन्तु यह दुखद सत्य है कि फिलिस्तीनी दर–दर मारे–मारे फिर रहे हैं, और भारत की सरकार ने अमेरिकी दबाव में इजरायल को मान्यता दे दी है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस सरकार के इस कदम से असहमति व्यक्त करती है। सत्ता में आने के सौ दिन के भीतर मंहगाई कम करने का वादा करने वाली सरकार ने सौ फीसदी में ज्यादा कीमतें बढ़ा दी है। इससे कांग्रेस का नकली चेहरा बेनकाब हो गया है और उसका असली स्वरूप जो जन विरोधी है, जनता के सामने आ गया है।

असंगठित मजदूरों की दयनीय स्थिति को सुधारने तथा कर्मचारियों की छंटनी को रोकने का कार्य समाजवादी पार्टी करेगी। डंकल प्रस्तावों तथा एक्जिट पालिसी की काली छाया से देश के जनमानस को बचाने के लिये समाजवादी पार्टी कृत संकल्प है।

समाजवादी पार्टी का मत है कि देश की वर्तमान राजनैतिक स्थिति का सबसे दुखद पक्ष यह है कि राष्ट्रपिता के हत्यारों को भी सार्वजनिक जीवन में सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगी है। राष्ट्रपिता पर प्रश्नचिन्ह लगाना विकृत मानसिकता का द्योतक है। राष्ट्रीय सम्मेलन का विश्वास है कि भाजपा नकली नारे उछालकर, देश में साम्प्रदायिक उन्माद फैलाकर मनुष्य–मनुष्य के बीच नफरत के बीज बोकर देश मे खून खराबा कराकर दिल्ली की सत्ता हासिल करना चाहती है।

पाठ्यक्रम में परिवर्तन करके, इतिहास को कुरूप करके तथा शहरों के नाम बदलकर साम्प्रदायिक सद्भाव को नष्ट करने का लगातार प्रयास भाजपा द्वारा किया जा रहा है। इस दल के लोग ''जातीय श्रेष्ठता' के फांसीवादी

सिद्धान्त को मानने वाले हैं। इसलिए इनका लोकतंत्रीय मान्यताओं एवं मानवीय संवेदनशीलता से कोई दूर का भी रिश्ता नहीं है।

रामकोला में अपने गन्ने का बकाया धन मांगने पर निहत्थे शान्तिप्रिय किसानों को बिजली गुल करके गोलियों से भून दिया गया। मध्य प्रदेश के जगदलपुर में आदिवासियों के हितों की बात करने पर वहाँ के मुख्यमंत्री के इशारे पर अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष को भाजपाइयों द्वारा नंगा करके जूतों की माला पहनाकर जगदलपुर की सड़कों पर घुमाया गया तथा शंकरगुहा नियोगी ही हत्या जैसे की गई, ये सभी घटनाए भाजपा के फासिस्ट चरित्र एवं संवेदनहीनता के उदाहरण हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूंजीवादी ताकतें विकासशील देशों के शोषण में लगी हुई है। सोवियत संघ एवं पूर्वी–यूरोप की कम्युनिस्ट सरकारों के पतन एवं सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका का दुनिया की अर्थ व्यवस्था पर एकाधिकार हो गया है। यद्यपि समाजवादी पार्टी का मानना है कि सोवियत यूनियन एवं पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन का अर्थ मार्क्सवाद की असफलता नहीं है। यह मार्क्सवाद को गलत ढंग से लागू करने का परिणाम है। भारत को स्वावलम्बी बनने का प्रयास करना होगा ताकि तीसरे विश्व को मजबूत नेतृत्व देकर दुनिया की पूँजीवादी ताकतों द्वारा किये जा रहे विकासशील देशों के शोषण को रोका जा सके।[2]

2. समाजवादी पार्टी का दो दिवशीय राष्ट्रीय सम्मेलन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 11–12 अक्टूबर 1994 को सम्पन्न हुआ। जिसकी अध्यक्षता सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी ने किया।

3. तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन–

सपा का दो दिवशीय तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 27–28 जुलाई 1996 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सम्मपन्न हुआ।

अध्यक्षीय भाषण–समाजवादी पार्टी के तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि–

---

2 - सपा के स्थापना सम्मेलन, लखनऊ मे, 5 नवम्बर 1992 को पारित राजनैतिक प्रस्ताव

साथियों,

लखनऊ की सरजमी पर आयोजित होने वाला यह सम्मेलन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस समय भारतीय राजनीति एक संक्रमण काल से गुजर रही है और एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से पूरे देश की राजनीति में जो कुछ बदलाव हुआ, उसके हम साक्षी भी है और भागीदार भी। बाबरी मस्जिद टूटने, साम्प्रदायिक दंगों और ऊँचे पदों पर भ्रष्टाचार के कारण हम पूरी दुनिया में बदनाम हो गये हैं। देश की राजनीति के शिखर पर बैठे हुये लोगों के ऊपर लगे हुये भ्रष्टाचारों के गम्भीर आरोपों के चलते सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले राजनेताओं की विश्वसनीयता खतरे में पड़ गयी है। इस राजनैतिक अव्यवस्था और अस्थिरता का फायदा उठाकर कट्टरपंथी साम्प्रदायिक ताकतों ने अपनी जड़ों को और मजबूत कर लिया है। हालांकि वे भी भ्रष्टाचार के कटघरे में फंस चुके हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव में उत्तर से दक्षिण तक मतदाताओं ने किसी एक राजनीतिक दल को समर्थन नहीं दिया है। इससे एक नकारात्मक राजनीति की भी शुरुआत हुई है। लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी सामने आया है।

किसी एक दल के पूर्ण बहुमत के अभाव में क्षेत्रीय राजनैतिक दलों का महत्व बढ़ा है। वर्तमान लोकसभा त्रिशंकु अवश्य है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री एच0 डी0 देवगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा सरकार का एक नया और सार्थक प्रयोग सामने आया है। लोकसभा चुनाव का जनादेश जनाकांक्षाओं से सीधे जुड़े हुये क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के गठबंधन के पक्ष में है। ऐसा प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए कुछ लोगों को केन्द्र की संयुक्त मोर्चा सरकार में परस्पर विरोध भले ही नजर आता हो लेकिन धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद को बचाने की देश की जनता द्वारा दी गयी जिम्मेदारी को पूरा करने का हर संभव प्रयास केन्द्र सरकार कर रही है। इसको तोड़ने की तमाम साजिशों के बावजूद सरकार चल रही है और धीरे–धीरे मजबूत भी होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के लिये सरकार में शामिल होना और सत्ता में भागीदारी करना जरूरी नहीं था। लेकिन हम संयुक्त मोर्चा को कमजोर नहीं

कर सकते थे क्योंकि यही जनादेश है और भारतीय राजनीति का यही भविष्य भी है।

लोकसभा के पिछले चुनाव मे सभी दलों की ताकत सामने आयी है। लम्बे–लम्बे दावे करने वाली भारतीय जनता पार्टी की असलियत भी सामने आयी है। कुछ दिनों के लिये जब अल्पमत की सरकार दिल्ली की कुर्सी पर बैठी तो देश का राजनैतिक मानस घबरा गया। समाजवादी पार्टी को इस बात का गर्व है कि पार्टी ने उ0 प्र0 की सरहद में साम्प्रदायिकता के खिलाफ जो उद्घोष किया था वह राष्ट्रीय मुद्दा बना और देशी–विदेशी पूँजीवाद के दबाव के बावजूद भाजपा विरोधी लगभग सभी पार्टियों ने हिस्सेदारी एवं सहयोग के जरिये एक धर्मनिरपेक्ष शक्ति के हाथ में भारत की बागडोर सौंपी।

समाजवादी पार्टी साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष में इस घटना को एक शुभ लक्षण मानती है कि जो लड़ाई समाजवादी पार्टी अकेले लडती थी उस लड़ाई को देश की दो तिहाई जनता ने अपनी लड़ाई मान लिया है।

लोकसभा चुनाव के बाद नयी चर्चायें भी शुरू हुई है। एक बार फिर से कुछ लोग संविधान बदलने या प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव कराने जैसे सुझााव उछाल रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर बुनियादी सवालों को लेकर संविधान संशोधन के हम विरोधी नहीं हैं। संविधान सभा ने पूरी सूझबूझ के साथ संविधान बनाया था। इसकी संरचना में यह ध्यान रखा गया था कि भारत बहुभाषी, बहुधर्मी और बहुलतावादी देश है। इसलिए संविधान की रचना में कोई बुनियादी दोष नहीं है। इसी संविधान के कारण नागरिकों को राजनैतिक न्याय के साथ–साथ आर्थिक और सामाजिक न्याय भी दिलाया जा सकता है। आज की परिस्थितियों में अगर कोई बदलाव जरूरी है तो राजनैतिक दलों और नेताओं के सोच में अपने सिद्धान्तों से समझौता करने के बजाय हमें धीरे–धीरे आगे बढ़ना मंजूर है। राष्ट्रीय राजनीति में हमारी यही पहचान है। चार साल पुरानी पार्टी और इतने राजनीतिक भूचालों के बीच जबकि चारों ओर से हमें निशाना बनाकर अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, हमारी प्रगति धीमी लेकिन संतोषजनक है। हमें अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के आधार पर जनता का विश्वास जीतना है। हम एक लम्बी और निर्णायक लड़ाई के लिये तैयार हो रहे हैं। हमें जनता पार्टी नहीं बनना है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हमार लिये सबसे बडी चुनौती है। 1991 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 215 सीटें मिली थी लेकिन 1993 में समाजवादी पार्टी ने इस संख्या को घटाकर 176 पर ला दिया था और उ0प्र0 में समाजवादी पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। लेकिन कुछ अवसरवादी तत्वों के कारण जो साम्प्रदायिक शक्तियों के हाथ की कठपुतली बन बये थे और आज भी साम्प्रदायिक शक्तियों के हाथों में खेल रहे है, जनता की चुनी हुई सरकार अपदस्थ हो गई थी।

पिछले लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है। उस समय भी यह प्रचार किया गया था कि बसपा से गठबंधन टूटने के कारण समाजवादी पार्टी का आधार कमजोर हो जाएगा और जनाधार कटकर दूसरे दलों के साथ चला जायेगा। बसपा ने समाजवादी पार्टी के जनाधार को तो खराब नहीं किया बल्कि कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करके भाजपा को लाभ पहुँचाने का काम अवश्य किया। हम देश की साम्प्रदायिकता विरोधी शक्तियों को आगाह करना चाहते हैं कि उ0प्र0 में बसपा का लक्ष्य भाजपा को हराना नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी को कमजोर करना है।

समाजवादी पार्टी का आधार हमारी नीतियां कार्यक्रम और उ0प्र0 में हमारी सरकार द्वारा किये गये काम हैं। 1993 में सरकार बनाने के तुरन्त बाद चुनाव घोषणा पत्र में किये गये वायदों को हमने पूरा करना प्रारम्भ कर दिया था। शपथ लेने के आधे घंटे के अन्दर चुनाव घोषणा पत्र में किये गये लगभग एक दर्जन प्रमुख वायदों को पूरा किया था। नकल विरोधी कानून की वापसी , गाँवों को 16 घंटों की बिजली देना, किसानों को उपज का लाभकारी दाम दिलाना, मंडल कमीशन की सिफारिश के अनुसार पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण देना, प्रजापति निषाद और दूसरे पिछड़े वर्गों को राहत देना, उर्दू को प्रदेश की दूसरी राजभाषा बनान, 10 हजार अम्बेडकर ग्रामों की घोषणा और उस पर अमल करना, बड़े पैमाने पर स्कूल भवनों का निर्माण जैसे कामों की एक लम्बी सूची है। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ऐसी पहली सरकार थी जिसने एकमुश्त बुनियादी कामों पर ध्यान दिया और उन्हें सफल बनाया। लेकिन हमारी सरकार जाने के बाद उन सारे विकास कार्यों को रोक दिया गया और अनेक कामों के लिये आवंटित किये गये धन को वापस

कर दिया गया। समाजवादी पार्टी आर्थिक रूप से ग्रामीण और कृषि विकास के लिए 70 प्रतिशत योजना के लिये धन देने की शुरु से वकालत करती रही है। मैं इस राय का हूँ कि इस देश में प्रकृतिक संसाधन, जनशक्ति और जमीन की उर्वरा शक्ति पर्याप्त है, जिससे अपना देश दुनिया का सबसे सम्पन्न देश बन सकता है लेकिन योजनाएं और प्रेरणायें प्रारम्भ से ही दिशाहीन रही और गांव पिछड़ते चले गये। समाजवादी पार्टी ने गांव का पैसा गांव पर खर्च करने की घोषणा और इस हेतु संघर्ष भी किया था। पार्टी देश और प्रदेश के आर्थिक ढांचे को ऐसी बनावट में ढालेगी ताकि न कोई वचित रहे और न कोई ज्यादा संचित कर सके।

मैंने यह बात बार–बार दोहरायी है कि हमें सबको साथ–साथ लेकर चलना है। सबको जोड़कर समाज बदलना है और जन समर्थन के सहारे देश में सामाजिक परिवर्तन लाना समाजवादी पार्टी ने जातिवादी सोच और मानसिकता का सदा विरोध किया है। हमने कमजोरों, पिछड़ों, बुनकरो, व्यापारियों, अल्पसंख्यकों छात्रों और महिलाओं की लड़ाई लडी है। उनके साथ खड़े रहे, उनको आगे बढ़ने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। झूठे आरोप चाहे जितने लगाये जायें लेकिन सच बात यह है कि गरीब सवर्णों की लड़ाई भी समाजवादी पार्टी ही देश में लड़ी है। उनको राजनैतिक संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा देने का काम भी हमने किया है। पिछले चुनाव में इसका लाभ भी हमें मिला है और इस चुनाव में भी हमें इस वर्ग का भरपूर समर्थन मिलेगा। पिछली सरकार के दौरान हमने और हमारी सरकार ने बाबरी मस्जिद की रक्षा करके मुसलमानों के दिल की दहशत को दूर करने का काम तो किया ही था, भारत के संविधान की मर्यादाओं की रक्षा भी की थी। आज की समाजवादी पार्टी और हमने ही नहीं हमारे समाजवादी पुरखों विशेषकर डा0 लोहिया और राजनारायण के नेतृत्व में समाज जिनको अछूता कहता है उनको लेकर काशी विश्वनाथ मन्दिर में प्रवेश के समय भी समाजवादियों के शरीर और लोकप्रियता दोनों पर चोट आयी थी। बाबरी मस्जिद के आन्दोलन के समय भी मस्जिद बचाने में हमें अपनी लोकप्रियता जोखिम में डालनी पड़ी थी। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि समाज में जो लोग कमजोर हैं, चाहे वे अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े या महिलायें हो उनके अधिकारों को सुरक्षित

रखने और दिलाने के लिए जो शुरू से समाजवादी चरित्र रहा है उसकी निरन्तरता में कमी नहीं आने दूँगा। केवल वोट एवं लोकप्रियता के लिए नहीं बल्कि वक्त पड़ने पर अपने प्राणों की आहुति देकर भी समाजवादी पार्टी का एक—एक कार्यकर्ता कमजोर की मदद के लिए अन्त तक खड़ा रहेगा। विशेषकर अल्पसंख्यकों और दलितों की रक्षा के लिये।

बेरोजगार नौजवानो को चाहे वे किसी जाति वर्ग या धर्म के हो, हमें समाजवादी पार्टी के मंच पर खड़ा करना पड़ेगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपने—अपने क्षेत्रों के कालेजों और विद्यालयों के छात्रों की संगठित टोलियां निकालनी पड़ेगी। यह दोनों शक्तियां मिलकर सामंती ताकतों, साम्प्रदायिक शक्तियों और चुनाव में धांधली करने वाले अफसरों का मुकाबला करेगी। बिना हिंसा को बढ़ावा दिये जनता को संगठित करके उनका मुकाबला करना पड़ेगा।

नौजवानों और छात्रों को अगले दो महीने प्रदेश को बचाने में लगाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता को सभी वर्गों के एक—एक मतदाता के पास जाकर समझाना पड़ेगा कि साम्प्रदायिक शक्तियों से देश की एकता और अखण्डता को खतरा है और इसलिए समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता को प्रेदश और देश की रक्षा के लिए प्रत्येक मतदाता से मदद करने का आग्रह करना पड़ेगा।[3]

राजनैतिक प्रस्ताव

समाजवादी पार्टी के तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में जो राजनैतिक प्रस्ताव पारित हुआ वह इस प्रकार है—

उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव सर पर है। राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की राजनैतिक गतिविधियां पैंतरेबाजी की शक्ल मे सक्रिय हैं। यह जानते हुये भी कि उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या, मथुरा एवं काशी है तथा साम्प्रदायिकता के खिलाफ असली रणस्थली उत्तर प्रदेश ही है और समाजवादी पार्टी एवं उसके नेता मुलायम सिंह यादव ही इस साम्प्रदायिकता के खिलाफ सही अर्थों में संघर्ष कर रहे हैं और वे ही शिकस्त दे सकते हैं।

---

3 - सपा के तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन मे 27 जुलाई 1996 को दिया गया अध्यक्षीय भाषण

समाजवादी पार्टी यह घोषणा करती है कि दिल्ली में जो संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी है उस संयुक्त मोर्चे को साथ लेकर समाजवादी पार्टी साम्प्रदायिक शक्तियों को उ0प्र0 में नेस्तनाबूद करेगी। कुछ राजनैतिक शक्तियां साम्प्रदायिक शक्तियों से संघर्ष करने के बजाय समाजवादी पार्टी को येन केन प्रकारेण कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं।

समाजवार्दी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन उन सारी पैतरेंबाज शक्तियों को आगाह करना चाहती है कि अगर समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश हुई तो उसका सीधा फायदा साम्प्रदायिक शक्तियों को मिलेगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश के सबन्ध में समाजवादी पार्टी के इस राष्ट्रीय सममेलन का स्पष्ट मत है कि साम्प्रदायिकता के खिलाफ जो हमारे साथ नहीं है, वह साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ है। कुछ राजनीतिक शक्तियां भाजपा विरोध के नाम पर उन लोगों से हाथ मिलाना चाहती हैं जो अपने वक्ती फायदे के लिये साम्प्रदायिक शक्तियों की कठपुतली बन जाती हैं। गाँधी को गाली देने वालों के साथ तथाकथित गाँधी भक्तों का समझौता कोई आश्चर्य की बात नही है। क्योंकि गाँधीवादी, गाँधी के स्वदेशी एवं स्वावलम्बन की नीतियों को तिलांजलि दे चुके हैं और उनके लिए गाँधी को गाली देने वाली शक्तियां अब परहेज की चीज नहीं है। गांधी को गोली मारने वालों का मुकाबला गाँधी को गाली देने वाले और गाँधी की नीतियों को तिलांजलि दे चुके लोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिये देश एवं प्रदेश के सारे असली गाँधी भक्त एक जुट हों और उत्तर प्रदेश के चुनाव के माध्यम से सारे राष्ट्र को प्रतिबद्ध करे कि यह देश गाँधी जी का रहेगा या गाँधी विरोधियों या गाँधी के हत्यारों का?

इस देश में समाजवादी आन्दोलन का इतिहास बहुत पुराना है। प्रारम्भ के दिनों में देश के और विदेश के समाजवादियों ने समाजवाद के सिद्धांत को निरूपित करने के लिये समतामूलक समाज की कल्पना की थी और आदमी–आदमी की गैर बराबरी को समाप्त करने के लिये केवल पूँजीवदी व्यवस्था के खिलाफ वर्ग संघर्ष का नारा दिया था। दुनियाँ के कुछ हिस्सों में इस नारे को पकड़ा भी गया लेकिन बाद के दिनों में ड0 लोहिया ने भारत के दर्द को समझा कि इस देश में केवल पूंजी नहीं बल्कि जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था और भूगोल के आधार पर क्षेत्रीय विषमता भी गैर बराबरी के

कारण है। इसी आधार पर उन दिनों दलितों, पिछडों, महिलाओं (चाहे वे ब्राह्मण हो, ठाकुर या अन्य किसी भी जाति की हो) और गरीब मुसलमानों के लिये विशेष सुविधा की बहस छिड़ी थी। लाजमी है कि जब ऐसी बातें छिडती हैं तो आन्दोलन जहाँ एक तरफ आर्थिक गैर बराबरी खत्म करने के लिये वर्ग संघर्ष का रूप लेता है, वहाँ सामाजिक गैर बराबरी खत्म करने के लिये वर्ण संघर्ष का रूप ले लेता है और साथ ही क्षेत्रीय गैर बराबरी समाप्त करने के लिये कुछ मुकामी मुद्दे भी उभर कर आते हैं।

समाजवादी पार्टी एक ओर साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ सघर्षरत है तो दूसरी ओर गरीबी के खिलाफ जंग में सदियों से उपेक्षित लोगों के हकों की लड़ाई पूरी निष्ठा के साथ लड़ रही है। जन्म के आधार पर कमजोर लोगों जिनमें दलित, पिछड़े, गरीब मुसलमान और महिलायें हैं, के लिए लड़ाई का बिगुल जितनी ताकत से फूँक चुकी है उससे भी ज्यादा ताकत से आर्थिक क्षेत्र में जिन्स की पैदावार के नाम पर कमजोर शक्तियों को अधिकार दिलाने के लिये मैदान में उतरी हैं। कारखाने की पैदावार के मुकाबले खेती की पैदावार कमजोर है। कारखाना कच्चे माल का इस्तेमाल करने के नाम पर खेती का शोषण करते हैं। उ0प्र0 में गन्ना उत्पादकों की, विशेषकर जो दयनीय दशा है और जिस तरह से गन्ने के बकाया भुगतान के लिये किसानों को कभी–कभी लाठी गोली का मुकाबला करना पड़ता है। किसानों के संघर्ष को हर तरह से मद्द करने के लिये अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुये समाजवादी पार्टी यह स्पष्ट करना चाहती है कि जब तक कारखानों में उत्पादन और खेती में उत्पादन के दामों में लागत और लाभ दोनों पक्षों के बीच संतुलन कायम नहीं किया जायेगा, देश के गाँव और खेत शहरों के उपनिवेश बनकर रह जायेगे। समाजवादी पार्टी चौखम्भा राज में विश्वास करती है। ग्राम पंचायत की व्यवस्था को जो सत्ता की भागीदारी में विशेष रूप से कमजोर हैं, इसे विशेषाधिकार देकर प्रतिस्थापित करने का प्रयास करती रही हैं और करती रहेंगी।

समाजवादी पार्टी जहाँ एक ओर समाज के दलित, गरीब, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को सामाजिक परिवर्तन के नाम पर विशेष अवसर देने के निर्णय को कारगर बनाने के लिये संघर्षरत है वहीं देश के तमाम नौजवान को

चाहे वे किसी भी जाति, धर्म के हो उनके बेसहारापन को दूर करने के अवसर और काम करने के अधिकार को दिलाने का वायदा करती है। देश का कर्ता धर्ता एवं लम्बे अरसे से देश के युवाओं को आर्थिक रूप से बेसहारा और मानसिक रूप से लुंजपुंज बनाने की साजिश कर रहा है। इस साजिश के खिलाफ युवा पीढ़ी समय रहते संघर्ष करे। समाजवादी पार्टी उनके साथ है।

समाजवादी पार्टी आदमी के द्वारा आदमी के शोषण, पैदावार के द्वारा पैदावार के शोषण, एक क्षेत्र के द्वारा दूसरे क्षेत्र के शोषण, एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण का विरोध करती है। पुराने उपनिवेशवाद के चलते बहुत सी विदेशी भाषायें नये स्वतन्त्रता प्राप्त किये देशों में वहॉ की मातृ भाषाओं और राष्ट्र भाषा का शोषण करती रहती है। मातृ भाषा के शोषण की प्रक्रिया के खिलाफ समाजवादी पार्टी संघर्षरत है और रहेगी।

समाजवादी पार्टी मजदूरों, छोटे दुकानदारों, बुनकरों, दस्तकारों और व्यापारियों के ऊपर भी होने वाले अन्याय का निराकरण करेगी। पड़ोसी देशों से सम्बन्ध सुधार कर डा० लोहिया के सपनों के मुताबिक एक सांस्कृतिक भारत की कल्पना को साकार करेगी।

इनके बड़े मुद्दों को हासिल करने में राष्ट्रीय सम्मेलन कुछ राजनीतिक अड़चनों को देखकर चिन्तित है। यह सम्मेलन राष्ट्र की जनता को विशेषकर उत्तर प्रदेश की महान जनता और अपने कार्यकर्ताओं का आवाह्न करता है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल में वादों को सही ढंग से निभाया है और नये राष्ट्र के निर्माण के लिये समाज के वंचित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की है तो पार्टी के कार्यकर्ता महात्मा गांधी के करो या मरो के नारे के साथ उत्तर प्रदेश में अपना झण्डा गाड़ने के लिये कटिबद्ध हो जायें।[4]

प्रमुख सचिव की रिपोर्ट

समाजवादी पार्टी का स्थापना सम्मेलन (प्रथम सम्मेलन) 4, 5 नवम्बर 1992, द्वितीय सममेलन 11, 12 अक्टूबर 1994 और तृतीय सममेलन 27, 28 जुलाई 1996 को लखनऊ में ही हो रहा है। यह सम्मेलन दूसरे राज्य में

---

4 . सपा के 'तृतीय राष्ट्रीय सममेलन' लखनऊ मे 28 जुलाई 1996 को पारित राजनैतिक प्रस्ताव''

करना था परन्तु जहाँ का निमंत्रण था वहाँ वर्षा के चलते दिक्कते थी, इस कारण यहाँ सम्मेलन करना पड़ा। यह सम्मेलन एक विशेष परिस्थिति में हो रहा है। आज देश एक नये राजनीतिक मोड पर खड़ा है। दिल्ली ने सयुंक्त मोर्चा की सरकार एक कामन मीनिमम कार्यक्रम पर चल रही है। जिसमें समाजवादी पार्टी भी शरीक है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 श्री मुलायम सिंह यादव सुरक्षा विभाग के मंत्री पद पर आसीन हैं। पार्टी के उपाध्यक्ष मा0 श्री जनेश्वर मिश्र जी, पार्टी के महामंत्री मा0 श्री बेनी प्रसाद वर्मा, मंत्री मरिषद में और श्री सलीम शेरवानी राज्य मंत्री, केन्द्रीय मंत्री मंडल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के स्वतन्त्र प्रभार में हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के अतिरिक्त दोनों मंत्रियों के पास भी महत्वपूर्ण विभाग है। हमें विश्वास है कि हमारे ये नेता लोग मंत्री परिषद में अपनी योग्यता और कार्य कुशलता का परिचय देकर देश की जनता के सामने पार्टी की छवि को चमकाने का काम करेगे। पार्टी संगठन के करीब एक वर्ष के ही भीतर उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव हुआ और हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में बसपा तथा अन्य दलों की मदद से सरकार बनाने में सफल रही। बसपा तो विधान सभा चुनाव में भी साथ मिलकर लड़ी थी और उसे विगत विधान सभा चुनाव में प्राप्त 14 स्थानो की जगह 69 स्थान मिल गये थे। उस सरकार के नेता मा0 श्री मुलायम सिंह यादव ही थे। उनके कुशल नेतृत्व में सरकार ने अल्प अवधि में ही प्रायः अपने सारे वादे पूरे कर लिये थे। इसी अवधि में सहकारिता, ग्रामीण पंचायतों, नगर पंचायतों और नगर निगमों के चुनाव मे पार्टी को उत्तर प्रदेश में भारी सफलता मिली थी। इन चुनावों में हमारा किसी भी दल से समझौता नहीं था। पार्टी की बढ़ती हुई जनप्रियता से अन्य दलों के लोगों में जलन होना स्वाभाविक था। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी विफलता से बौखला गई थी। उनका दिल्ली राज का सपना साकार रूप पाने में उत्तर प्रदेश सरकार और इसके नेता को अपना सबसे बड़ा संकट मानता था जो आज भी उस पार्टी के कार्यों से साफ झलक रहा है। इस बीच बसपा का जो भी दंभ था वह टूट रहा था। उसके नेता भी सत्ता सुख अकेले किसी तरह पाने को लालायित थे। पार्टी और पार्टी नेता की बढ़ती शक्ति से जो बौखलाये लोग थे। वे मुलायम सिंह को गद्दी से

हटाना चाहते थे। इसमें कमोवेश भारतीय जनता पार्टी के साथ सबों की साजिश थी। इतना ही नहीं इसमें देशी और विदेशी पूजीवादी साजिश भी काम कर रही थी। फलस्वरूप 1 जून 1995 को बसपा ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया और 3 जून की अर्धरात्रि में उस समय के राज्यपाल महोदय ने सरकार भंग कर सुश्री मायावती की सरकार बनवा दिया। इस सरकार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। 2 जून की एक छोटी सी घटना को बड़ा भयावह रूप देकर प्रचारित किया गया। इसके पीछे निहित स्वार्थ पूर्णरूपेण था। यह सरकार मात्र चार महीने चली, परन्तु इसने जितना ओछा और घिनौना कार्य किया, उसे जनतांत्रिक व्यवस्था का कलंक ही कहा जायेगा। इसके बारे में जितना भी कहा जायेगा वह कम ही होगा। इसी बीच पार्टी का दूसरा सम्मेलन हुआ। उसी सममेलन द्वारा गठित वतमान पार्टी संगठन है। उस सम्मेलन के बाद से अब तक की मुख्य-मुख्य पार्टी कार्यों की जानकारी दिया जा रहा है।

पार्टी संगठन प्रायः देश के सभी राज्यों में कुछ न कुछ बन गया है। परन्तु वह सब जगह कारगर नहीं है। अगले कार्यक्रम की सूची में पार्टी को इसे प्रथम स्थान देना चाहिये। आज पार्टी का मुख्य रूप से जनाधार उत्तर प्रदेश में हैं। पार्टी अध्यक्ष मा0 श्री मुलायम सिंह अभी उत्तर प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता हो गये है। इनके और राज्य पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में यहाँ की पार्टी सब तरह से सक्रिय है। कमी नीचे की इकाइयों को सक्रिय बनाये रखने की है। सरकार गिरने के बाद नई सरकार जिस तरह संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध बनाई गई उसके विरोध का निर्णय पार्टी ने लिया। सुश्री मायावती की सरकार ने शान्तिपूर्ण विरोध पर भी पाबन्दी लगाई। फलस्वरूप हमारे हजारों कार्यकर्ता सरकारी जुल्म के शिकार बने। फिर भी कार्यकर्ता साहस पूर्वक लड़ते रहे। नवम्बर 17 को राजभवन के घेराव का शानदार कार्यक्रम था। असमय की भयावह वर्षा के बाद भी हमारे हजारों साथी लखनऊ तरह-तरह की बाधाओं के बाद आ गये। उन्होंने भिन्न-भिन्न स्थानों पर सरकारी कानून को तोड़ा। कई जगह लाठी भी चले। हमारे पार्टी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अनेकों नेता लखनऊ में गिरफ्तार किये गये। सारा उत्तर प्रदेश पुलिस कैम्प बन गया था। सारे राज्य में पचास हजार से अधिक गिरफ्तारियां

हुई थीं। हमारी पार्टी के शायद ही कोई नेता बच सके थे। इसमें युवा संगठनों का काम सराहनीय रहा था। पुनः 2 मार्च 1996 को दिल्ली रैली लाल किला के मैदान में हुई। यह अपने मे अभूतपूर्व थी। इसमें देश भर से लोग आये थे परन्तु इसे सफल बनाने का सारा श्रेय उत्तर प्रदेश को जाता है। इसे सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य नेताओ और कार्यकर्ताओं ने अधिक प्रयास किया था। इस रैली ने देश के सामने पार्टी की शक्ति को उजागर किया। इसके पहले जिलों और मंडलीय अनेकों रैलियाँ हुई थी। युवा संगठनों के द्वारा राज्यपाल के सामने जो प्रदर्शन किया गया था। उसमें हमारे दर्जनों साथी गंभीर रूप से घायल हुये थे फिर भी उनका मनोबल ऊँचा था। इस बीच महिला संगठन, युवा संगठन और पार्टी संगठन द्वारा उपेक्षित अति पिछड़ी जातियों, व्यापारियों आदि के अनेकों प्रदर्शन तथा सम्मेलन किये गये।

लोकसभा का चुनाव आया। मुख्यरूप से हम उत्तर प्रदेश में कम्युनिष्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और जनता दल के साथ मोर्चा बना कर चुनाव लड़े। चुनाव हम देश के कई राज्यों में लड़े। पार्टी उत्तर प्रदेश में कुल 64 लोकसभा क्षेत्र में लड़ी थी। हम यहाँ 16 स्थान पर जीते हैं। इस लोकसभा चुनाव से सबक ले कर आगे बढ़ना है। अभी उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव सामने है। मा0 राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिश्रम सराहनीय और साथियों के लिये अनुकरणीय है। अभी उत्तर प्रदेश पार्टी द्वारा राज्य के करीब 42 जिलों में रैलियां की गई है। चार प्रमंडलों को छोड सभी प्रमंडलों में कार्यकर्ता सममेलन हो चुका है। सहकारिता, पंचायत, जिला पंचायत और नगर पंचायत तथा निगमों में जो अपने पार्टी के पदाधिकारी जीते हैं–उनकी बैठकें हो गई हैं। इन बैठकों की उपस्थिति 90 प्रतिशत से अधिक थी। भूतपूर्व जीते–हारे विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और जीते, हारे सांसदों की बैठक भी हमने की है।[5]

4 विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन–

समाजवादी पार्टी कार्य दो द्विवसीय विशेष राष्ट्रीय धिवेशन 19–20 अप्रैल 1998 को महाराष्ट्र की राजधानी मुम्बई के औरगाबाद मे सम्पन्न हुआ।

5 - सपा के तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, लखनऊ मे, 28 जुलाई 1996 को पेश प्रमुख सचिव की रिपोर्ट

अध्यक्षीय भाषण–

भारत की आर्थिक राजधानी मुम्बई में समाजवादी पार्टी का यह राष्ट्रीय विशेष अधिवेशन सम्पन्न हो रहा है। कई द्वीपों जैसें स्थानो पर बसी मुम्बई देश के विभिन्न धर्मों, सस्कृतियो, आस्थाओं और रीति रिवाजो का केन्द्र है। देश के प्रायः सभी प्रदेशों के लेागों ने इसके भव्य–सुन्दर स्वरूप को गढा है। साम्प्रदायिक फासिस्टवादी ताकतों ने यद्यपि समय–समय पर इसके इस स्वरूप को विगाड़ने की नाकाम कोशिश जरुर की है किन्तु लघु भारत का यह स्वरूप अपने पूर्ण यौवन पर बना हुआ है और भविष्य में भी बना रहेगा।

आर्थिक गतिविधियों के अतिरिक्त आजादी की लड़ाई में भी मुम्बई का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। "भारत छोड़ों"आन्दोलन का जयघोष मुम्बई से ही हुआ था। महाराष्ट्र ने ही 42 के आन्दोलन के दौरान जिलों में स्वतंन्त्र सरकार स्थापित करने का संदेश पूरे देश को दिया था।

मुम्बई और महाराष्ट्र ने देश को महान समाजवादी नेता दिये, जिन्होने स्वतन्त्रता तथा समाजवादी आन्दोलन को अभूतपूर्व गति प्रदान की जिसमें मेहर अली, अच्युत पटवर्धन, एन0जी0 गोरे, एस0एम0 जोशी, मधुलिमेय सरीखे ऐसे नक्षत्र रहे और जो हमेशा अपनी आभा से हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगें।

केन्द्रीय सरकार के गठन, राष्ट्रीय एजेण्डा, भाजपा के भ्रामक प्रचार तथा देश के कुछ राजनैतिक पार्टियों के आचरण ने देश की संस्कृति और लोकतंत्र की आत्मा को समाप्त कर देने की व्यूह रचना कर दी है। राष्ट्रीय एजेण्डा एक फर्जी दस्तावेज है। फर्जी दस्तावेज की आड़ में भाजपा अपनी देश–तोड़क नीतियों के दुष्चक्र को चलायेगी। लेकिन देश नहीं चल सकता। देश चलाने और लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम रखने के लिये नैतिकता–सच्चाई और ईमानदारी के लिये सच्ची निष्ठा आवश्यक है। राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी देश की राजनीति के खतरनाक मोड़ पर इन सब बुनियादी बातों पर देश की जनता को सचेत करने और भ्रम की स्थिति को समाप्त करने का अपना नैतिक दायित्व मानती है।

हाल मे हुए लोकसभा के चुनाव परिणामों, उसके बाद विभिन्न राजनैतिक दलों की बुद्धि विलास बैठकों के सिलसिलो तथा भाजपा के नेतृत्व में बनी सरकार ने ऐसे चिन्ताजनक प्रश्न पैदा कर दिये हैं जिनके उत्तरों का दायित्व गैर साम्प्रदायिक लोकतांत्रिक दलों के ऊपर है। समाजवादी पार्टी को साम्प्रदायिक विरोधी मुहिम को देश व्यापी बनाने में अहम भूमिका का निर्वहन किया है और कठिन परिश्रम के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। कि समाजवादी पार्टी जहां समता से समृद्धि और समृद्धि से समता के सिद्धान्त के प्रति समर्पित और इसके लिये व्यवस्था परिवर्तन आवश्यक मानती है,वहीं देश में लोकतन्त्र विरोधी फासिस्टवादी ताकतों को समाप्त करने के लिये संकल्पबद्ध है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से एक बात तो साफ हुई कि देश की जनता ने साम्प्रदायिक द्वेष पैदा करने वाली लोकतन्त्र विरोधी भाजपा को स्वीकार नहीं किया है। झूठ, फरेब, धांधलेबाजी और अफवाहों ने यद्यपि धर्मनिरपेक्ष ताकतों की सीटें जरुर कम कर दी लेकिन भाजपा, कमोवेश पूर्व की स्थिति पर ही स्थिर हो गयी। भाजपा–शिवसेना मिलाकर पिछली लोकसभा की सदस्य संख्या में केवल 6 सदस्य बढ़ा पाये हैं। देश की मीडिया ने तो पत्रकारिता के सारे उसूलों और शिष्टाचार को तिलाजलि दे दी थी। चुनावपूर्व आकलन तथा चुनाव के दौरान किये गये सर्वेक्षणों ने तो झूठ के सारे रिकार्ड तोड़ दिये। ऐसी परिस्थितियों में आये चुनाव परिणामों से निराश होने की तो आवश्यकता नहीं लेकिन संतोष न करके सभी लोकतान्त्रिक और देश की एकता बनाये रखने के लिये प्रतिबद्ध दलों को गम्भीरता के साथ अपनी कमियों की समीक्षा और उनकों दूर करने के उपाय खोजने चाहिए।

मैनें पूर्व में कहा कि देश की जनता ने भाजपा को स्वीकार नहीं किया है। भाजपा के नेतृत्व में बनी सरकार उन दलों और व्यक्तियों के सहयोग के कारण से बनी हैं, जिन्होनें भाजपा की मूलभूत सम्प्रदायवादी नीतियों से अपने को अलग करके जनता से धर्मनिरपेक्षता के मुखौटे लगाकर वोट मांगे और प्राप्त किये। इन नकली धर्मनिरपेक्ष दलों कों पहचानने मे भारी चूक हुई और यहां हम सभी गैर साम्प्रदायिक दलों और व्यक्तियों को अपनी गलती स्वीकारनी होगी कि हम जनता के सामने इन लोगों के नकाब को उतार कर असली चेहरा पहचनवां देने में नाकामयाब हुए। जनता और धर्मनिरपेक्ष ताकतों

को सबसे बड़ा धोखा "तेलगु देशम पार्टी" से मिला है। इसके नेता तो संयुक्त मोर्चा के संयोजक भी थे और उन्होंने संयुक्त मोर्चा और धर्मनिरपेक्षता को बड़ा आघात दिया, लेकिन आश्चर्य तो इस बात पर है कि भाजपा की सरकार को विश्वास मत प्राप्ति के मतदान में साथ देकर बेशर्मी के साथ धर्मनिरपेक्षता का नारा दे रहे है और भाजपा को साम्प्रदायिक दल भी बता रहे हैं। यह सर्वविदित है कि तेलगु देशम के भाजपा के साथ चले जाने पर दल मे बगावत आ गयी है। मैं तेलगु देशम के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ कि जो धर्मनिरपेक्षता के उसूल के लिये लड़ाई लड़ रहे हैं। अवसरवादिता और भ्रष्ट आचरण बढ रहा है। राजनीतिज्ञों की कथनी और करनी में भेद के चलते ही जनता के मन में लोकतन्त्र के प्रति आस्था मे गिरावट आई है। ऐसी बातों और हरकतों को भविष्य में नहीं रोका गया तो हमारा लोकतन्त्र खतरे में पड सकता है। गैर सम्प्रदायिक सरकार के गठन के मामले में केन्द्र में पहले कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिये था क्यों कि संयुक्त मोर्चा के सभी घटकों से लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक थी लेकिन इसके ढुलमुल रवैये और नेताओ के स्पष्ट और सामूहिक कथनों के आभाव से कांग्रेस के एकमत न होने का सदेश देश को मिला। समाजवादी पार्टी के ठीक समय स्पष्ट वक्तव्यों के अनुसार यदि कांग्रेस ने निर्णय लिये होते तो केन्द्र सरकार की दूसरी ही तस्वीर होती।

लेकिन संयुक्त मोर्चे के कुछ घटकों ने भी यथा समय आवश्यक सक्रियता नहीं दिखाई। कुछ दल के नेताओं के अन्तर्विरोध मुखर होकर सामने आये। धर्मनिरपेक्ष सरकार के गठन को लेकर भी परस्पर विरोधी बयान आये। इस प्रकार केन्द्र सरकार बन जरुर गयी है लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह अल्पजीवी सरकार है बशर्ते धर्मनिरपेक्षता की सभी ताकतें स्पष्ट नीति, त्वरित निर्णय तथा अपने किये फैसलों पर अमल करने लिये कटिबद्ध हो जायें । केन्द्रीय सरकार ने एक राष्ट्रीय ऐजेन्डा जारी किया है इसे ही वे कार्यक्रम बता रहे हैं उक्त एजेण्डे में न तो जनहित के ठोस कार्यक्रम है और ना ही अमल करने की कोई रुपरेखा है। केवल सद इच्छाओं की घोषणायें हैं। उसमें एक आयोग गठन करने की बात कही गयी हैं जो संविधान की समीक्षा करेगा उस समीक्षा का क्या उद्देश्य है यह भी स्पष्ट नही

हैं। एक बार फिर से संविधान बदलने की बात उछाली गयी है समाजवादी पार्टी आवश्यकता पडने पर बुनियादी सवालों को लेकर, संविधान में संसोधन करने की विरोधी नहीं है। संविधान सभा ने पूर्ण सूझ–बूझ के साथ संविधान बनाया था। इसको बनाते समय यह ध्यान रखा था कि भारत एक बहुभाषी, बहुधर्मी तथा बहुलतावादी देश है। संविधान की रचना मे कोई बुनियादी दोष नहीं है। इसी संविधान के अर्न्तगत नागरिकों को राजनैतिक अधिकार के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाया जा सकता है। आज की परिस्थितियों में अगर कोई बदलाव अपेक्षित है तो राजनैतिक दलों और नेताओं के सोच में बदलाव लाना आवश्यक है। राजनैतिक दलो की कथनी करनी के फरक को खत्म करना होगा और स्पष्ट नीति और ठोस कार्यक्रम के जरिये राजनीति करनी होगी। यह कार्य संविधान के बदल देने से नहीं वरन् राजनैतिक दलों के मंथन और चरित्र से होगा। समाजवादी पार्टी ने लगातार इस बात को दोहराया है कि अपने सिद्धान्तों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे भले ही हमारे आगे बढ़ने की रफ्तार कुछ धीमी हो। राष्ट्रीय राजनीति में हमारी यही पहचान है। संविधान समीक्षा के लिये आयोग के गठन के पीछे कई खतरे छिपे हुए हैं। यह संघ परिवार द्वारा हिटलर के उसूलों और कार्य शैली अपनाने का नमूना है। लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सत्ता पर काबिज होकर संविधान में संसोधन कर जिस प्रकार हिटलर ने तानाशाही स्थापित की थी, उसी प्रकार संघ परिवार तानाशाही स्थापित कर देश की एकता, संस्कृति और लोकतन्त्र को समाप्त करने साजिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी को इस बात का गर्व है कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सरहद में साम्प्रदायिकता के खिलाफ जो उद्घोष किया था, वह राष्ट्रीय मुद्दा बना और देशी –विदेशी पूंजीवाद के दबाव के बावजूद साम्प्रदायिक दलों की हिस्सेदारी और सहयोग के जरियें एक धर्मनिरपेक्ष शक्ति का संयोजन हो पाया। समाजवादी पार्टी साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष की इस घटना को एक शुभ लक्षण मानती है कि जो लड़ाई समाजवादी पार्टी ने अकेले शुरू की थी उस लड़ाई को देश की दो तिहाई जनता ने अपनी लड़ाई मान लिया है समाजवादी पार्टी के सामने वृहत्तर उद्देश्य एवं लक्ष्य है। समाजवादी पार्टी ने महात्मा गॉधी, से करुणा, डा0 लोहिया से संघर्ष, और व्यवस्था–परिवर्तन तथा चरण सिंह से

कृषि उन्मुख नीतियों को लेकर नये समाजवादी भारत का निमार्ण करने के लिये संकल्प किया है। समाजवादी पार्टी का नजरिया साफ है कि देश का विकास यहां के किसानों बुनकरों, दस्तकारों कामगारो और देश के लिये समर्पित बुद्धिजीवी के द्वारा ही हो सकता है। बाहर से पूँजी लाकर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विकास को जवाबदेही नहीं दी जा सकती। साम्रज्यवादी देश विकासशील देशों का शोषण करने के नये नये रास्ते अख्तियार कर है। हमारे देश मे किसानों की उपज तथा देश की प्राकृतिक सम्पदा पर कब्जा जमाने की कार्यवाही हो रही है। बासमती चावल का लिये गये पेटेन्ट को रद्द करने तथा देश की जड़ी–बुटियों के पेटेन्ट हासिल करने की साजिशों का समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ विरोध करेगी। देश की प्रगति मे सबकी साझेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करनी है। इसके लिये दलितों, पिछड़ों अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं को विशेष अवसर प्रदत्त करना आवश्यक है। समृद्धि से समानता लाने के संकल्प से सभी को न्याय उपलब्ध कराना होगा। समाजवादी पार्टी ने जातिवादी सोच और मानसिकता का सदा विरोध किया है और कमजोरों, पिछड़ो, बुनकरों, व्यापारियों, अल्पसंख्यकों, छात्रो और महिलाओं की लड़ाई को लड़ी है और वह हकीकत है कि गरीब सवर्णों की लड़ाई भी समाजवादी पार्टी ने ही देश मे लड़ी है। हमारे द्वारा ही गठित "कौशिक समिति" की सिफारिश के आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण गरीब सवर्णों को देने के लिये संविधान मे संसोधन करने की मांग समाजवादी पार्टी न की है।

समाजवादी पार्टी, देश की उन्नति और देश में समानता के लिये देशी भाषाओं में राज–काज चलाने को अनिवार्य मानती है।

इस देश मे समाजवादी आन्दोलन का इतिहास बहुत पुराना है शुरु के दिनों में देश और विदेश के समाजवादियों ने समाजवाद के सिद्धान्त को निरुपित करने के लिये समता मूलक समाज की कल्पना की थी और आदमी–आदमी की गैरबराबरी को समाप्त करने के लिये केवल पूँजीवादी व्यवस्था के खिलाफ वर्ग संघर्ष का नारा दिया था। दुनिया के कुछ हिस्सों में इस नारे को पकड़ा भी गया लेकिन बाद के दिनों मे डा0 राम मनोहर लोहिया

ने भारत के दर्द को समझा कि इस देश मे केवल पूंजी नही बल्कि जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था और भूगोल के आधार पर क्षेत्रीय विषमता भी गैर बराबरी के मारक कारण हैं। और इसी आधार पर समाजवादी आन्दोलन ने दलितो, पिछडों महिलाओं और गरीब मुसलमानों के लिये विशेष अवसर के सिद्धान्त को अंगीकार किया। समाजवादी पार्टी पूंजी के आधार पर विषमता, जन्म के आधार पर विषमता एवं क्षेत्र के आधार पर विषमता को खत्म करने के लिए बिगुल बजाया है। देश की जनता ने महसूस कर लिया है कि इन तीनों विषमताओं के खिलाफ जब जिहाद छिड़ा है तो निहित स्वार्थ वाली शक्तियाँ अपने बचाव के लिये तरह–तरह के षड़यन्त्र रचती हैं। सम्प्रदायवाद उसी से निकला जहरीला कीड़ा है। इन विषमताओं को खत्म करने की लड़ाई के साथ–साथ सम्प्रदायवाद के जहरीजा कीड़े को खत्म करने की लड़ाई को लड़ना होगा।

भाजपा सरकार के छिपे ऐजेण्डे से देश के सामने जहां और कई संकट आयेंगे, वही अल्पसंख्यक, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई के सबंध में उनकी नीतियॉ बड़ी घातक है। राष्ट्रीय एजेण्डा की बातों का कोई महत्व नहीं है क्योंकि भाजपा गठन के लोग ऐलान के साथ आयोध्या, काशी, मथुरा, कॉमन सिविल कोड और 370 धारा हटाने के मुद्दों की वकालत कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के साथ अलगाव– दुराव को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। अल्पसंख्यकों –विशेष कर मुसलमानों को न0–2 का नागरिक मानने की भाजपा की नीति का पूरी ताकत से विरोध करना समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता का प्रथम कर्त्तव्य है। भाजपा के नेतृत्व में केन्द्रीय सरकार के बनते ही विभिन्न स्थानों पर साम्प्रदायिक–तनाव पैदा हुआ है।

समाजवादी पार्टी एक ओर साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ संघर्षरत है तो दूसरी ओर गरीबी के खिलाफ जंग मे सदियों से उपेक्षित लोगों के हकों की लड़ाई पूरी निष्ठा के साथ लड़ रही है। समाजवादी पार्टी जन्म के आधार पर कमजोर लोगों, दलित, पिछड़े गरीब मुसलमान और महिलाओं के लिये लड़ाई का बिगुल जितनी ताकत से फूँक चुकी है उससे भी ज्यादा ताकत से आर्थिक क्षेत्र में उतरी है। कारखाने की पैदावार के मुकाबले खेती की पैदावार

कमजोर है। कारखाने कच्चे माल के इस्तेमाल करने के नाम पर खेती का शोषण करते हैं। जब तक कारखानों के बने माल और खेती के उत्पाद के दामों में लागत और लाभ दोनों पक्षो के बीच सन्तुलन कायम नहीं किया जायेगा देश के गांव और खेत शहरों के उपनिवेश बन कर रह जायेगे।

जिस देश में जन्म के आधार पर इन्सान और पैदावार के आधार पर वस्तुयें कमजोर और बेसहारा होने के नाते मजबूत के हाथों से मार खाते है। उस देश में सर्वाधिक कमजोर और बेसहारा होने के नाते बच्चों और नौजवानों के लिये मार खाना उनकी नियति बन जाती है। दुनियां में सबसे अधिक मार खाने वाले भारतीय बच्चे और बेसहारा भारत के नौजवान हैं। समाजवादी पार्टी जहां एक ओर समाज के दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों और महिलाओं को सामाजिक परिवर्तन के लिए विशेष अवसर देने के निर्णय को कारगर बनाने के लिए संघर्षरत हैं वहीं देश के नौजवानों के बेसहारापन को दूर करके काम के अधिकार को दिलाने की लड़ाई का ऐलान करती है।

समाजवादी पार्टी विदेशी निर्भरता के खिलाफ है, पार्टी सहयोगी विश्व व्यवस्था की बात जरूर करती है। लेकिन विदेशी–ऋण लेने के खिलाफ है। विदेशी ऋण से देश की स्वायत्ता समाप्त होती है। और विकास की दिशा गलत राह ले लेती है। समाजवादी पार्टी आर्थिक विकास की परिभाषा गरीबी और पूरी आबादी को काम पर लगाने से ही होगा जिससे भूख,, भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति हो सकती है।

समाजवादी पार्टी नयी विश्व दृष्टि का निर्माण करना चाहती है, संयुक्त राष्ट्रसंघ से जुड़ी विश्व संस्थाएं अब पचास वर्ष पुरानी हो चुकी हैं। उनकी सार्थकता और प्रसांगिकता तो समाप्त हो ही चुकी है, वैसे भी समानता और विश्व बन्धुत्व के उद्देश्य की पूर्ति यह सस्थाएं नहीं करती थी। भेद–भाव की भावना, और बड़े देशों के हित साधने की वरीयता के कारण गरीब देशों के विकास को गति देने में असफल रही है। समानता के आधार पर विश्व पंचायत का निर्माण करना, समाजवादी आन्दोलन की कामना रही है।

भारत प्रायद्वीप को शक्तिशाली और सामर्थ्यवान बनाने के लिए डॉ0 राममनोहर लोहिया ने भारत–पाक–बांगलादेश महासंघ बनाने का सपना

संजोया था। तीनों देशों के विकास के लिए समाजवादी पार्टी सन्दर्भित महा संघ बनाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगी। हमारी नीति अपने सभी पडोसी देशों से मधुर सम्बन्ध बनाये रखने की है। और सभी समस्याओं का निदान वार्ता के जरिये करने की है। यद्यपि हम हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन वर्तमान में सीमाओं की स्थिति को देखते हुए हमें मुह तोड़ जबाव देने के लिए पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद रहना चाहिए। इसके लिए तैयारी में हमें किसी भी देश के दबाव या नाराजगी की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान को किसी देश के बहकावे में आकर हथियारो के दौड़ में नही शामिल होना चाहिए शान्ति और सामंजस्य कायम रख, अपने देश की गरीबी खत्म करने और आर्थिक विकास को गति प्रदान करनी चाहिए।

प्रतिनिधि साथियों, इस गुरुतर कार्य–सम्पन्नता का भार हम सबके ऊपर है। इस महान दायित्व की पूर्ति के लिए एक सशक्त, सक्षम और अनुशासित सगठन होना परम आवश्यक है। इस सम्मेलन में मुझे विश्वास है, आप ऐसा संगठन बनाने के लिए ठोस निर्णय लेगे।[6]

5. चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन

समाजवादी पार्टी का तीन दिवसीय चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन 29–31 जनवरी 1999को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दशहरा मैदान में सम्पन्न हुआ।

अध्यक्षीय भाषण–

समाजवादी पार्टी के चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन कें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपने अध्यक्षतीय भाषण में कहा कि–

प्रतिनिधि साथियों,मध्यप्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। सच्चे अर्थ में यह भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक समन्वय का प्रतिनिधित्व करता है। सात विशाल राज्यों से घिरा यह प्रदेश उत्तर में चम्बल और दक्षिण में नर्मदा

6 - समाजवादी पार्टी के विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन मुम्बई मे 19 अप्रैल 1998 को दिया गया अध्यक्षीय भाषण

से पोषित है। इसका वर्तमान राजनीतिक स्वरूप नया है लेकिन इस इलाके का वर्णन चीनी यात्री फाह्यान ने भी अपनी किताब में किया है। इसकी राजधानी भोपाल जो नवाबी आन में पली और बढ़ी थी, आज भी अपनी खूबसूरती और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है।

मध्य प्रदेश की महान जनता का स्वागत और अभिनन्दन मैं इस लिए करता हूँ क्योंकि उन्होंने विधान सभा के पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक दिया है और पहली बार समाजवादी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के लिए अपने मन में स्थान बनाया है। हमारे कार्यकर्ताओ और समर्थकों की मेहनत से विधान सभा में हमें चार स्थान मिले हैं। मैं इसे एक बहुत अच्छी शुरूआत मानता हूँ। तीन राज्यों में पराजय के बाद भाजपा में यदि लोकतांत्रिक परम्पराओं के प्रति थोड़ा भी सम्मान होता तो केन्द्र की सरकार को तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिए था। इन राज्यों में जनता का फैसला भाजपा की साम्प्रदायिक नीतियो, भ्रष्ट आचरण और निकम्मे प्रशासन के खिलाफ था। इन चुनावों में जीत के कारण कांग्रेस पार्टी को अपनी ताकत के बारे में भ्रम हो गया है क्योंकि इन तीनों राज्यों में जनता के सामने कांग्रेस के अलावा कोई ठोस विकल्प नहीं था। मैं मध्य प्रदेश और पूरे देश की जनता को यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि राजनैतिक ध्रवीकरण के प्रयास मे गैर भाजपा और गैर कांग्रेस शक्तियों को एक साथ खड़ा करने का भरपूर प्रयास होगा। इस कोशिश में समाजवादी पार्टी का यह सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा और अगले चुनाव में जनता को भाजपा और कांग्रेस से अलग कोई विकल्प चुनने में परेशानी नहीं होगी।

समाजवादी पार्टी का यह राष्ट्रीय सम्मेलन ऐसे नाजुक समय पर हो रहा है जब पूरा देश राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अराजकता के दौर से गुजर रहा है। देश की राजनैतिक हालत का विश्लेषण करते हुए हमें यह भी खास तौर से देखना पड़ेगा कि आज की दशा पैदा करने के जिम्मेदार कौन है? मैं आपको याद दिलाता हूँ कि पिछले वर्ष ठीक इसी समय जब बारहवीं लोक सभा के चुलाव की तैयारी हो रही थी तब से इस एक वर्ष में देश में जो कुछ बिगड़ा और बर्बाद हुआ है उसका गहराई से मनथन करना पड़ेगा। एक ओर केवल 11 महीने में भारतीय जनता पार्टी की

केन्द्र सरकार ने आर्थिक गुलामी, देश व्यापी अराजकता, साम्प्रदायिकता, अपसंस्कृति, असहिष्णुता और चारों ओर सामाजिक असुरक्षा को फैलाया है या दूसरी ओर हमें यह भी जनता के सामने मंजूर करना पडेगा कि गैर भाजपा और गैर कांग्रेस ताकतें एक साथ नहीं रह सकीं। वे लोग जो साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहें थे अचानक सत्तालोलुप क्यों हो गये?

इक्कीसवीं सदी में इस देश के किसानों, नौजवानों, अल्पसंख्यको, महिलाओं, मजदूरों और दलितों के सामने हम किस रूप में खडे होना चाहते हैं। ये सभी लोग हमसे पूछेंगे कि देश के बिगड़ते हालात को रोकने के लिए हमने क्या किया है? उस समय उनके सामने हम जवाबदेह होंगे। हम दूसरे दलों की तरह झूठ–सच बोलकर बच नहीं सकते। हमें इसी सम्मेलन मे विचार करके समूची परिस्थियों से लड़ने के लिए देश व्यापी संघर्ष की एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। समाजवादी राजनीति के प्रेरणा पुरूष डा0 राम मनोहर लोहिया का यह वाक्य हमें बराबर याद रखना चाहिए "जिन्दा कौमें पांच साल तक इन्तजार नहीं करतीं" और आजकल तो यह इंतजार घटकर मुश्किल से दो साल रह गया है।

पिछने 11 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहर ढ़ाया है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस जमात को सरकार मानना ही हास्यास्पद है। आज तक कोई एक भी फैसला सरकार सर्वसम्मति से नहीं ले सकी है। इतना बड़ा माखौल पहले कभी नहीं हुआ। गुजरात हो या कर्नाटक, जम्मू कश्मीर हो या असम, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, अल्पसंख्यकों को घेरकर हमले किये जा रहे हैं। मुम्बई, दिल्ली और दूसरे राज्यों से मुसलमानों को बंगलादेशी बताकर बाहर निकाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में मुस्लिम युवकों की हत्यायें हुयी है। महान मुस्लिम विद्वान अलीमियां के घर पर छापा मारा गया। ईसाई स्कूलों, मिशनरियों और अस्पतालों पर हमले की पूरी रपट अल्पसंख्यक आयोग ने गृह मंत्रालय को सौंप दी है। इसके बावजूद गृहमंत्री, भारत सरकार, का यह कहना कि मुद्दे को बेकार उछाला जा रहा है, देश के अल्पसंख्यकों का खुला अपमान है। प्रधानमंत्री हमला करने वाले संगठनों को दण्डित करने बजाय धर्मान्तरण पर

बहस की बात उठाकर देश को गुमराह कर रहे हैं। गृहमंत्री की धमकियो के बावजूद हत्यायें न कश्मीर में रूकी हैं, न दिल्ली में और न असम में। इस सरकार में शामिल दलों के नेता और केन्द्रीय मंत्री खुलेआम जिस तरह संविधान और देश की चिन्ता किये बिना लूटने और माहौल बिगाडने में लगे हैं उसको देखते हुए क्या इस सरकार को एक मिनट भी सत्ता में बने रहने देना चाहिए? अपनी सरकार का झूठ और निकम्मापन छिपाने के लिए राष्ट्रपति तक को बदनाम किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है कि बिहार की सरकार भंग करने की सिफारिश को राष्ट्रपति ने नामंजूर कर दिया था।

भाजपा गठबन्धन के सत्ता मे आने के बाद से देश के अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुसलमानों तथा ईसाईयों की मानसिकता जिस बेचैनी, आतक और घबराहट के दौर से गुजर रही है, उसे हम शिद्दत के साथ महसूस करते हैं। वर्तमान सरकार के राष्ट्रीय एजेण्डे और स्वदेशी की पोल खुल गयी है। राष्ट्रीय एजेण्डा एक फर्जी दस्तावेज साबित हुआ है। भाजपा के नेताओं, संघ परिवार के पदाधिकारियों तथा भाजपा के प्रदेश के मुख्यमंत्री, काशी, अयोध्या, मथुरा, कामन सिविल कानून तथा धारा 370 को हटाने के अपने मुद्दों पर कायम हैं।

यह बिल्कुल सही बात है कि आजादी के बाद कांग्रेस तथा भाजपा शासन में अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों की घोर उपेक्षा हुई है। उनका व्यापार तथा परम्परागत उद्योग धन्धे चौपट हो गये हैं। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की तादात निरन्तर घटी है। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के बावजूद मुसलमानों की संस्कृति, भाषा–लिपि पर निरनतर प्रहार हो रहे हैं। हमारी मान्यता है कि देश की एकता और अखण्डता को बनाये रखने तथा देश की समृद्धि के लिए यह जरूरी है कि सरकारी नौकरियों, पुलिस बलों एवं सेना की भर्ती में मुसलमानों की उपेक्षा पर विराम लगे और उनके परम्परागत उद्योग घन्धों को प्रोत्साहन दिया जाय। राष्ट्रीय एकता से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर इस सरकार ने घोर साम्प्रदायिक रूख अख्तियार किया है। कश्मीर के संबन्ध में गृहमंत्री के अविवेक पूर्ण बयानों से वहां स्थिति और बिगड़ी है। आतंकवादी गतिविधियां तथा उनके परिक्षेत्र की बढ़ोत्तरी रोकने में सरकार नाकामयाब हुई है। समाजवादी पार्टी का मानना है

कि कश्मीर की स्थिति वहा की जनता का विश्वास जीकर तथा दृढ़ संकल्पबद्धता के साथ ही सुधारी जा सकती है, जिसके लिए एक वृहद राष्ट्रीय दृष्टिकोंण का अनुसरण करना होगा। मौजूदा सरकार कश्मीर के मामले में एक संकीर्ण साम्प्रदायिक दृष्टिकोण का अनुसरण कर रही है।

देश की पूरी सुरक्षा व्यवस्था किस खतरनाक मोड पर पहुंच गई है इसका अंदाजा इस उदाहरण से लगाया जा सकता है कि देश का रक्षा मत्री अपने नौसेना प्रमुख को बर्खास्त करते हुए उसे देश के लिए खतरा बता रहा है और बर्खास्त नौसेना रंक्षामंत्री सहित पूरी सरकार को बेईमान और झूठा घोषित कर रहा है। सरकार की यह असफलता देश के प्रति एक बेहद गभीर अपराध है जो पहले कभी नहीं हुआ। पूरी दुनियां में अपनी बहादुरी के लिए मशहूर हमारी सेनाओं की इस धटना से प्रतिष्ठा घटी है, मनोबल टूटा है। ऐसी स्थिति में सीमाओं की पहरेदारी कर रहे हमारे बहादुर सैनिक या तटों की रक्षा करने वाले नौसैनिक अपने पूरे मनोबल से क्या देश की रक्षा कर सकेंगे?

आर्थिक मोर्चे की हलात भयावह है। केन्द्र और लगभग सभी राज्य सरकारें दिवालियां होने के कगार पर पहुँच गयी हैं। आजादी के बाद से देश में अर्थव्यवस्था की यह सबसे बुरी दशा है। इस सरकार में मदी, मंहगाई और मुद्रास्फीति बढ़ी है। रूपये की कीमत आधी हो गई है। बजट में किये गये आर्थिक सुधार के सभी दावे झूठे साबित हो चुके हैं। कोयला, स्टील, पेट्रोलियम जैसे आधारभूत उद्योगों का उत्पादन लगातार गिरा है। एक साल पहले जो व्यापार घाटा 150 अरब से भी कम था वह अब बढ़कर 300 अरब से अधिक हो गया है। पिछले तीन महीनों में निर्यात 4 प्रतिशत घटा है और विदेशों से आयात करके आने वाले सामानों में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार ने20 प्रतिशत निर्यात का लक्ष्य खुद घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है योजना के मदों में कटौती हो रही है और गैर योजना व्यय लगातार बढ़ रहा है। विदेशी कर्ज 4000 अरब रूपया हो गया है और देशी कर्ज अलग है। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति और व बैकों के कामकाज में गिरावट तथा घोटालो को लेकर बार–बार गंभीर चेतावनी दी है भुगतान का संतुलन पिछले वर्षों में सबसे अधिक गंभीर दशा में है, राज्य सरकारों को रिजर्ब बैंक ने कर्ज देने से

मना कर दिया है। कर्मचारियों को वेतन देने के लिए धन नहीं है और सरकार के साथ ही बैंको, यूनिट ट्रस्ट और सरकारी बांडों पर से भी लोगों का भरोसा उठ चुका है।

आर्थिक उदारवाद के नाम पर विश्वव्यापार समझौता कांग्रेस सरकार ने ही देश पर थोपा था और आज भी संसद में जब समाजवादी पार्टी एवं अन्य दल इसके विरोध में खड़े हैं तो काग्रेस पेटेंट कानून, बीमा नियमन कानून में संशोधन पास करने के लिए भाजपा को समर्थन दे रही है। अभी राज्यों में भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक लाकर किसानों को खेती की जमीन से बेदखल करके बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देने का षडयंन्त्र किया जा रहा है। पिछले वर्षों में इन विदेशी कम्पनियों के लिए लगभग सौ कानून बदले गये हैं जरूरत न होने के बावजूद हमे समझौते के तहत अनाज खरीदना पड़ रहा है। इन कम्पनियों के दबाव में इस सरकार ने तीन सौ चालीस वसतुओ को नियंत्रित सूची से हटाकर खुले आयात की सूची में रख दिया है। पेटेंट कानून पास होने से 25 हजार देशी दवा कम्पनियां जो लगभग 6 हजार करोड़ रूपये सालाना का व्यापार करती हैं समाप्त हो जायेंगी या उन पर विदेशी कम्पनियों का कब्जा हो जायेगा। विश्व व्यापार संगठन को लेकर सरकार की मजबूरी चाहे जो हो लेकिन क्या हम अपने देश के गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों की जिन्दगी की कीमत पर यह कानून पास करेंगे? पिछले ग्यारह महीनों में कुल मिलाकर इस सरकार की आर्थिक उपलब्धि यह है कि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। देशी उद्योगों में भारी मंदी चल रही है। लघु उद्योगों जिससे रोजगार के अवसर बनते हैं और बुनकरों तथा हथकरघा उद्योग में लगे लाखों लोगों का रोजगार खतरे मे पड़ने जा रहा है। दस करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं और मध्यम वर्ग के लगभग 40 प्रतिशत लोग महंगाई के कारण अब दो बार की जगह केवल एक बार खाने के लिए मजबूर हैं।

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें 76 प्रतिशत से अधिक लोग खेती के कार्य में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की स्पष्ट मान्यता है कि भारत की तरक्की किसानों की तरक्की के साथ जुड़ी हुई है। जब तक देश के किसानों की समृद्धि नहीं होगी देश गरीब बना रहेगा। लेकिन खेद की बात है

कि हमारे किसानों की दयनीय स्थिति है। उनकी उपज का लाभपरक मूल्य तो क्या लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता जबकि उसे अपनी जरूरत की मीलों में बनने वाली वस्तुएं मंहगे दामों में लेनी पड़ती हैं। बीज, खाद, पानी आदि खेती की आवश्यकता पूरी नहीं की जाती। लेकिन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन जाने पर भारत की सरकार ने किसानों को निरीह और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मोहताज बना देने का दुष्चक्र चला दिया है। विश्व व्यापार संगठन के निर्देशों के अनुसार भारत सरकार पेटेन्ट कानून को बदल रही है। हमारे देश के बीजों पर विदेशी कम्पनियों ने पेटेन्ट हासिल कर लिया है जिसके कारण बोजों पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का अधिकार हो जायेगा। बीज उनसे ही लेनें पड़ेंगे और उनके द्वारा निर्धारित मनमाने दामों पर । इस दुष्चक्र का दूसरा खतरनाक पहलू यह है कि देश में गेहूँ–चीनी आदि जैसे चीजों का भरपूर उत्पादन होने पर भी भारत सरकार को विदेशी गेहूँ और चीनी जैसी वस्तुओं का आयात अनिवार्यतः करना होगा और नतीजा होगा कि किसान को उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पायेगा।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के चंगुल से बचने के लिए हम विश्वव्यापार संगठन की सदस्यता से अलग होना अनिवार्य मानते हैं। साथ ही किसानों को उत्तम बीज, खाद तथा पानी उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व मानते हैं। किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य मिले, मील में बनने वाली वस्तुओं और किसान की उपज के मूल्यों में उचित अनुपात कायम हो तथा मील में बनने वाली वस्तुओं की कीमतें लागत खर्च से ड्योढ़े से ज्यादा न हों तभी किसान और देश तरक्की कर सकता है।

सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण हमारे देश के उद्योगों में भारी मन्दी का दौर चल रहा हैं। नये उद्योगों के जरिये बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है बुनकरों की स्थिति दयनीय हो गयी हैं। उनको सूत उचित मूल्यों और समय पर उपलब्ध नहीं होता और न ही उनके उत्पादन के लिए बाजार बुनकरों को मीटर के हिसाब से नहीं वरन् प्रति हार्सपॉवर पर निश्चित रेट पर विद्युत अपुर्ति की जानी चाहिऐ। संघ परिवार तथा पुलिस की गठजोड़ से कुरेशी समुदाय का जबर्दस्त उत्पीड़न किया जा रहा है। नियम सम्मत उनके व्यापार में बाधा डाली जा रही है।

समाजवादी पार्टी देश में एक समतामूलक व्यवस्था और एक नई राजनीतिक कार्य संस्कृति लाने के लिए अपने संकल्प को दोहराती है। हम भोगवादी संस्कृति और असमान पोषक व्यवस्था को समाप्त कर समता और समृद्धि स्थापित करना चाहते हैं। देश के विकास और उन्नति में अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछडों, नौजवानों, बुनकरों और किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करना हमारा उद्देश्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसकी संस्थाओं का सम्मान तथा उनकी स्वतंत्रता ही देश का भविष्य सुखद बनायेंगे। सहकारी संस्थाओं, जिला पंचायतों को निरीह बनाये जाने तथा नगरपालिकाओं से लेकर कुलपतियों एवं राज्यपालों के मनोनयन तक ऐसे उपक्रम किये जा रहे हैं और ऐसे लोग मनोनीत किये जा रहे हैं जो पद की गरिमा और अस्मिता को लज्जित कर रहे हैं। भाजपा के द्वारा बिहार के मामलों में जिस निर्लज्जता के साथ वहां की सरकार को बर्खास्त करने के हथकण्डे अपनाये गये और आज भी जिस घिनौने तरीके से दुष्प्रयास किये जा रहे हैं, वे निन्दनीय और भर्त्सना करने योग्य हैं। बिहार के राज्यपाल तथा केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा जिस प्रकार के बयान दिये जा रहे हैं वे जनतांत्रिक व्यवस्था और संसदीय प्रणाली की व्यवसथा के विरुद्ध, संविधान की भावना के प्रतिकूल तथा स्थापित मान्य परम्पराओं की अवहेलना करने वाले हैं। बेशरमाई की हद यह है कि महामहिम राष्ट्र पति के तथा बिहार में अभी हुए उप चुनावों के जनता के फैसलों के बाद भी केन्द्रीय सरकार के मंत्री और बिहार के राज्यपाल बिहार सरकार के खिलाफ बयान देते जा रहे हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में हुए दंगों पर श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट को भाजपा शिवसेना सरकार द्वारा पूरी तरह से अस्वीकार करके, रिपोर्ट के खिलाफ जिस तरह मुसलमानों पर आरोप लगाये हैं और जस्टिस श्रीकृष्ण पर मुसलमान समर्थक होने का आरोप लगाया है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है।

आजादी के आन्दोलन के दौरान बनाई गई हमारी विदेश नीति की स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संदेह की नजर से देखी जा रही है। हमारी शान्तिप्रियता की छवि नष्ट हुई है और तटस्थ तथा विकासशील देश हम पर अविश्वास करने लगे हैं। सरकार ने जिस गलत ढंग से पोखरण में परमाणु विस्फोट किया था उससे देश का आर्थिक संकट और गम्भीर हुआ। पड़ोसी

देशों से हमारे सम्बन्ध अधिक खराब हुये हैं और सामरिक क्षेत्र के मामलों में भारत की सर्वोच्चता घटकर पाकिस्तान के बराबर आ गई है। आणविक क्लब का सदस्य बनना तो दूर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य बनने की संभावना भी खत्म हो गई है। इस एक घटना के कारण पाकिस्तान, चीन और अमेरिका भारत के खिलाफ मजबूती से एकजुट होकर खड़े हो गये हैं। विदेश नीति के मोर्चे पर यह सबसे बड़ी असफलता है। अमेरिका, जापान और उन सभी देशों की, जिन्होंने भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये हैं मैं उनकी निन्दा करता हूँ।

भारतीय जनता पार्टी को बारहवीं लोकसभा के चुनाव मे बहुमत नही मिला था। उस समय मैंने यह कहा था कि अधिक सीटे जीतने के बावजूद इनको सरकार बनाने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। क्योकि यह पार्टी संविधान की धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद में विश्वास नहीं करती। यह किसी से छिपा नहीं है कि भाजपा का दो सीट से लगभग एक सौ अस्सी सीट तक पहुंचाने का आधार राम जन्मभूमि मन्दिर का आन्दोलन रहा है। इसी दौर में सबसे बड़े साम्प्रदायकि दंगे हुये हैं। बाबरी मस्जिद ध्वंस करने के बाद अपनी साम्प्रदायिकता का बड़ा जाल फैलाकर भाजपा ने अपना कथित हिन्दू जनाधार बनाया था। उसके पीछे कोई राजनैतिक या आर्थिक दर्शन नहीं था। उस समय मैंने यह कहा था कि देश के हित में भाजपा को रोकने के लिए हम साझा कार्यक्रमों के आधार पर कांग्रेस का समर्थन करेंगे, क्योंकि हम भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को कम अपराधी मानते हैं। बाद में मार्क्सवादी और दूसरे वामपंथी दलों ने भी इस पर अपनी सहमति दी थी। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रपति श्री के0आर0 नारायणन से मिलकर यह कह दिया कि कांग्रेस सरकार नहीं बनायेगी। इसी मध्य प्रदेश में काग्रेस का पंचमढ़ी में जो सम्मेलन हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी की निन्दा की गयी थी। अब जाकर यह रहस्य खुला है कि उस समय कांग्रेस ने सरकार क्यों नहीं बनायी? और आज जबकि भाजपा सरकार ने देश को राजनैतिक अराजकता, भ्रष्टाचार और आर्थिक गुलामी के कगार पर खड़ा कर दिया है, तब भी कांग्रेस भाजपा सरकार को क्यों नहीं गिराना चाहती? सच्चाई यह है कि कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे के पूरक बन गये हैं। पेटेन्ट, बीमा और

दूसरे विधेयक को जिस तरह संसद में कांग्रेस समर्थन दे रही है उसके बाद दोनों में गुणात्मक फर्क देखने की कोशिश करना भारी गलती होगी। सन 1949 ई0 और सन् 1999 अर्थात 50 वर्ष में मन्दिर–मस्जिद मुद्दे को लेकर भाजपा सत्ता में पहुँची है। उसके लिए कांग्रेस और केवल कांग्रेस जिम्मेदार है। मूर्तियां रखने का काम, ताला खुलवाने का काम कांग्रेस ने किया था। सिलान्यास कांग्रेस ने कराया था। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार आयोध्या से शुरू किया था। बाबरी मस्जिद तोड़ दिये जाने के बाद तथा राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद नया मंन्दिर बनवाने तक क्या कांग्रेस की सरकार चुप नहीं थी ? इन सारी घटनाओं के पीछे पहले प्रधानमंत्री कौन और बाद दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? अब फिर कांग्रेस भी ठीक वहीं कर रही है इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि गुजरात में इसाइयों पर हमले की पुष्टि होने के बाद लोक सभा में विपक्ष के नेता द्वारा गुजरात सरकार को बर्खास्त करने की माग के बाद भी कांग्रेस अध्यक्ष भाजपा सरकार को बर्खास्त नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि अटल बिहारी बाजपेयी को जयललिता या ममता बनर्जी के मुकाबले कांग्रेस पर अधिक भरोसा है।

अल्पसंख्यकों के सवाल पर जो रवैया कांग्रेस ने दिखाया है उससे किसी को यह भ्रम नहीं रहना चाहिए। मुसलमानों, इसाइयों या सिक्खों की हिफाजत का यह कांग्रेस का केवल मुखौटा है, असली चेहरा नहीं। कांग्रेस बिल्कुल बदली नहीं है। इसी मध्य प्रदेश के झबुआ जिले में क्रिश्चियन ननों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई थीं। दो करोड़ से अधिक ईसाई समुदाय और पूरी दुनियां के ईसाइयों ने गहरा रोष व्यक्त किया था। यहां की कांग्रेस सरकार ने क्या किया? कांग्रेस और भाजपा के बीच नूरा कुश्ती चल रही है। जिसका पर्दाफास करना जरूरी है। ऐसे राजनैतिक महौल में इस देश के संविधान, साम्प्रदायिक सदभावना और अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का विशेष उत्तरदायित्व उन लोगों पर है जो देश भर में तीसरी ताकत के रूप में पहचाने जाते हैं। जो अपने अहंकारों में चूर होकर खुद बिखर कर हाशिये पर पहुँच गये हैं। इस नाजुक दौर में यदि हमने अपने निजी और दलीय हितों से ऊपर उठकर देश को बचाने का काम नहीं किया तो अगली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी।

देश के तीन नये राज्यों के गठन के सवाल को भाजपा सरकार की गलत नीति, जिसमें काग्रेस पार्टी की सहमति है ने उलझाकर देश में फिर से क्षैतिजता के आधार राज्यों के पुनर्गठन जैसे मामलों पर विवाद खड़ा करने का माहौल बना दिया है। इससे नये राज्यों के सृजन का सिलसिला बन्द न होकर क्षैतिजता तथा अन्य बातों के आधार पर और राज्य बनाये जाने की मांग उठती रहेगी तथा आन्दोलन होते रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश मे प्रस्तावित उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्र के अतिरिक्त मैदानी क्षेत्र तथा हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर को शामिल करने तथा बिहार की जनता की आंकाक्षाओं के विपरीत वनांचल प्रदेश के सृजन का विरोध करेगी। भाजपा सरकार के आने के बाद एक बार फिर हिन्दी प्रदेशों को काटने और बाटने की शाजिस तेज हुई है।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान अंग्रेजी का महत्व अधिक तीव्रता से बढ़ा। और मातृ भाषाओं तथा क्षेत्रीय बोलियों की उपेक्षा की जा रही है। सन् 1954 में राज्य पुनर्गठन आयोग और भाषाओं के आधार पर प्रान्तों की रचना का प्रयोग कांग्रेस सरकार ने किया था। उसके नतीजे सबके शामने हैं। राजनैतिक पहचान के नाम पर वोटों की राजनीति का खतरनाक खेल शुरू हुआ है। इसको समझाना पड़ेगा। आर्थिक विकास के लिए अगर कोई नया राज्य बनाया जाता है तो यह भी सुनिश्चित करना पडेगा कि उसमें सभी पक्षों की सहमति हो। उसका दुष्परिणाम उन राज्य को न भोगना पडे जिसका विभाजन किया गया है। राजनीति का यह खेल विकास के लिए कम चुनाव के लिए ज्यादा है। यह खेल बेनकाब करना पड़ेगा। क्योंकि इस असन्तोष में अराजकता के बीज छिपे हुये हैं। पूरे देश के राजनैतिक नक्शे को एक आम सहमति के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए।

हमारे देश में काग्रेस द्वारा उलझाया हुआ भाषा का सवाल आज भी वैसा ही बना हुआ है। भाजपा की सरकार देशी भाषाओं की घोर उपेक्षा कर रही है। भाषा नीति का सवला एक गम्भीर सवाल है। जिस पर फौरन ध्यान देना जरूरी है। हमे यह तय करना पड़ेगा कि हम और कितने दिन अंग्रेजी को अपने राष्ट्र भाषा के रूप में बरकरार रखेंगे। आजादी के पचास वर्ष बाद भी हिन्दी, उर्दू और सभी भारतीय भाषाएं अग्रेजी की गुलाम है। इसके कारण हमारी राष्ट्रीय एकता को सबसे अधिक चोट पहुँची है। अग्रेजी की गुलामी के

खिलाफ दो सौ साल तक लगातार लड़ने वाले राज्यों में अंग्रेजी पढाने वाले स्कूल तेजी से बढ़ रहे हैं। यह इस लिए हुआ है कि अंग्रेजी जो पहले उच्च शिक्षा और सत्ता की भाषा थी, उसे अब विदेशी कम्पनियों ने उपभोक्ता बाजार की भाषा बना दिया है। केन्द्र की सरकारों ने जानबूझ कर भारतीय भाषाओं के खिलाफ अग्रेजी को बढ़ावा दिया है। किसी भी स्वाभिमानी और स्वतत्र देश के लिए इससे अधिक अपमान जनक बात नहीं हो सकती कि वह अपनी राज्य भाषा और मातृ भाषा के माध्यम से शिक्षा और सरकार को न चला सके। सन् 1815 में जर्मनी के आजादी के बाद केवल एक वर्ष में "विस्मार्क" जर्मन को राजभाषा बना दिया और 1917 में रूस की क्रान्ति के बाद रुसी भाषा फौरन लागू की गयी थी। यह कितना अपमान जनक है कि फ्रांस की संसद कानून बनाकर अंग्रेजी के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगा दे और भारत की संसद अपने सर्वसमस्त से पारित प्रस्ताव को संघ लोकसेवा आयोग से लागू न करवा सके, जबकि दिल्ली में शाहजहाँ रोड पर आयोग के दफ्तर के सामने पिछले दस साल से चल रहे आन्दोलन और धरना का समर्थन सभी राजनेता कर चुके है। खुद प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी संसद में इसे उठा चुके है। समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को लड़ने का संकल्प करती है। महत्मा गांधी ने जिस तरह साम्प्रदायकि सद्भावना, स्वदेशी और अंग्रेजी के खिलाफ लड़ाई क्षेड़ी थी, वहीं काम फिर से शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की भूमिकाएं इस देश को आर्थिक और राजनैतिक के साथ सांस्कृतिक गुलामी की ओर ले जा रही हैं।

हमारा देश हमेशा से धर्मनिर्पेक्षता तथा उदारता को मानने वाला रहा है। हजारों वर्षों से विभिन्न संस्कृतियां देश में आती रही हैं और मूल संस्कृति में शामिल होती रही हैं। भारत अनेक धर्मों, भाषाओं, रहने–सहने की प्रणालियों और रीति–रिवाजों का देश है। अपनी सद्भावना और सामंजस्य के द्वारा ही राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। धर्म, भाषा, जाति, प्रदेश, रीति–रिवाज, रहने–सहने की प्रणालियों आदि की मान्यताएं राष्ट्रीय निन्दा के ही अन्तर्गत हैं और राष्ट्रीय निष्ठा न तो विभिन्न मान्यताओं को कुचलती हैं और न ही ये मान्यताएं राष्ट्रीय निष्ठा में बाधक होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अन्ध, क्रूर, राष्ट्रीय प्रेम की तथाकथित निष्ठा

भारत के सर्वधर्म सम्भाव तथा उदारता के मूलभूत चरित्र को नष्ट भ्रष्ट करना चाहती है। कभी वन्दे मातरम्, कभी सरस्वती वन्दना जैसे मसलों तथा उपासना पद्धति के मामलों को उठाकर देश की एकता को खण्डित करने की चेष्टा हो रही है। भारत के नेतृत्व वाली सरकार से राष्ट्रीय निष्ठा और लोकतंत्र खतरे में पड़ा है। राष्ट्र की एकता, धर्म निरपेक्षता, सर्वधर्म सम्भाव तथा लोकतंत्र को बचाये रखने के लिए हर प्रकार तैयार रहना चाहिए।

समाजवादी पार्टी अनुसूचित जातियों, आदिवासियो, पिछड़ों, अल्पसंख्याकों, महिलाओं के लिए विशेष अवसर के सिद्धान्त को मान्य करते हुए इनको विकास की दौड़ में शामिल होने लायक बनने तक उन्हें नौकरियो, व्यापार तथा राजनीति में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दोहराती है। राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से यह वर्ग सदियों से उपेक्षाओं के कारण बहुत पिछड़े हैं, फिलहाल समान अवसर के उसूल, के बिना देश की आर्थिक, सामाजिक उन्नति मे इनकी भागीदारी हो ही नहीं सकती। जब तक सभी वर्गों की तरक्की नहीं होती देश तरक्की नही कर सकता।

महिलाएं जो सदियों से उपेक्षित रही हैं, आज भी अपना सही हक नहीं पा रही हैं। उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए पार्टी संसद तथा विधान सभाओं में महिलाओं के आरक्षण को एक सही कदम मानती है। लेकिन हमारा मानना है कि 33 प्रतिशत आरक्षण एक असन्तुलन पैदा करेगा। फिलहाल उनके लिए 10 प्रतिशत आरक्षण उचित होगा और उसके साथ ही महिला आरक्षण में पिछड़े वर्ग, मुस्लिम, अनुसूचित जाति एवं आदिवासी महिलाओ के लिए उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था समाज में समरसता और संतुलित विकास के लिए आवश्यक है।

फिल्मों, रंगमंच, चित्रकला से जुड़े कलाकारों को लक्ष्य बनाया जा रहा है। खास तौर से अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को वहाँ के उद्योग, व्यापार भाग रहे हैं। दूसरे राज्यों से रोजी, रोटी कमाने गये लोग आतंकित किये जा रहे है। श्री कृष्ण आयोग ने अपनी रपट में साफ–साफ शिवसेना को दोषी ठहराया है। लेकिन सरकार बेशर्मी से उसे ठुकरा चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट और हाकी टीमों के दौरों को निशाना बनाकर पूरे देश में एक नया साम्प्रदायिक

तनाव पैदा किया जा रहा है किन्तु सरकार के घड़ियालू ऑसू उसकी साजिश में शामिल होने के सबूत हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर साम्प्रदायिक उपद्रव किये गये तो कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा।

केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा और उसके सहयोगी संगठन देश की खेल, कला, व सांस्कृतिक क्षेत्र पर भी शर्मनाक हमले कर रहे हैं। आर्ट गैलरी मे तोड़-फोड़, किसी फिल्म के प्रदर्शन के विरोध में सिनेमा घरो को जलाना, श्री दिलीप कुमार जैसे प्रतिष्ठित कलाकर के घर पर हमला करने तक ही सीमित नहीं है। बकायदा घोषणा करके वीडियो फोटोग्राफरों की उपस्थित मे दिल्ली स्थित स्टेडियम में क्रिकेट पिच खोद दी गयी और सरकार ने कार्यवाही के नाम पर क्रिकेट मैंच को दिल्ली के स्थान पर चेन्नई कराने का फैसला कर दिया। इसी तरह की आराजकता के चलते क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर पर हमला करके विध्वंस किया गया। राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक ट्राफियों को नष्ट कर दिया गया और सरकार ने अपने सहयोगियों की हरकतों के सामने आत्म समर्पण कर दिया। परिणाम स्वरूप क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को अपना कार्यालय भाजपा शासित प्रान्त से हटाकर कलकत्ता ले जाना पड़ा। इससे साफ पता चलता है कि उन्हें भाजपा का समर्थन व संरक्षण प्राप्त है, जो यह अत्यंत खतरनाक बात है। मामला उस समय और भी गम्भीर तथा साफ हो जाता है जब भाजपा नेता कहते हैं कि कला, खेल व सांस्कृतिक मूल्यों पर चोट करने वाले ऐसे संगठनों से भाजपा अपने सम्बन्ध नहीं तोड़ेगी।

गुजरात की कहानी पूरे देश में उजागर हो चुकी है। वहाँ भाजपा सरकार की साम्प्रदायिकता का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि ठीक 25 दिसम्बर के पवित्र दिन को चर्चों पर हमले किये गये। लूट, हत्यायें, आतंक, अत्याचार और साम्प्रदायिकता का एक साथ नजारा भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में है। "सरस्वती वंदना और वंदे मातरम्" का मुद्दा उठाकर तनाव फैलाने की कोशिशों को समाजवार्दी पार्टी ने विफल कर दिया।

विदेशी ताकते इस देश को बंटा हुआ देखना चाहती है। समाजवादी पार्टी के प्रयास से देश की दो बड़ी ताकतें हिन्दुओ और मुसलमाओं के बीच निकटता बढ़ी है, खास तौर से पिछड़ी और कमजोर ताकतों के साथ, इस ताकत के सहारे विदेशी प्रभावों और खासतौर से अंग्रेजी और अंग्रेजियत के

खिलाफ मुहिम चलायी जाय। यह एकता 1857 की तरह मजबूत होगी। जिस समय दोनों ताकतों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ पहली लडाई लडी।

राष्ट्रीय दलों से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। केवल एक चुनाव जीतने और जैसे–तैसे सरकार बनाने की दौड है। लोकतंत्र मे जनता जिसको अवसर देती है उसे शासन चलाने का अधिकार है। लेकिन अगर हिटलर की तरह सत्ता को हथियाकर उसका इस्तेमाल देश के संविधान, देश की एकता और साम्प्रदायकि सौहार्द को नष्ट करने के लिए किया जाय तो संघर्ष के अलावा क्या रास्ता है? यदि भाजपा और कांग्रेस मिलकर इस देश के किसानों, मजदूरों और उद्योगों को विदेशी कम्पनियों के हाथों बेचना चाहेंगी तो देश के नौजवानों, किसानों और छात्रो को खडा करके मुकाबला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह लड़ाई लम्बी है इसकी रणनीति बनाने और उसको कार्यान्वित करने के लिए जिस संकल्प शंक्ति की जरूरत है उस शक्ति को जगाने के लिए मै आप सब का आह्वान करता हूँ।[7]

राजनैतिक प्रस्ताव –

समाजवादी पार्टी के चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन में जो राजनैतिक प्रस्ताव पास किया गया। वह इस प्रकार है–

समाजवादी पार्टी के हम सभी साथी विगत अप्रैल महीने में मुम्बई मे मिले थें। तब तक केन्द्र में 26 प्रतिशत से भी कम वोट पाने वाली भाजपा नें राजनैतिक तिकड़म, जोड़–तोड़ व धनबल से कतिपय पिछलग्गुओं की मद्द से केन्द्र में अपनी सरकार बना ली थी। सपा ने देश की जनता को तभी भाजपा की संकीर्ण मानसिकता से आगाह किया था। हमें विश्वास था कि भाजपा और उसके पिछलग्गुओं की जमात का तथाकथित राष्ट्रीय एजेण्डा एक धोखा है। भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का नारा एक राष्ट्रीय छल है। विगत 11 महीने के शासन में भारतीय समाज की विघटनकारी शक्तियॉ बलवान हुई हैं। देश साम्प्रदायिकता के घोर दलदल में फंस गया है। केन्द्र सरकार के आर्शीवाद और गृहमंत्रालय की साठ–गांठ से अल्पसंख्यक समुदाय पर बर्बर

7_ सपा के "चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन" भोपाल मे 29 जनवरी 1999 को दिया गया अध्यक्षीय भाषण)

आक्रमण प्रारम्भ हो गये हैं। मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के पूजा स्थलों पर घिनौने आकमण राजस्थान, महाराष्ट, गुजरात और कर्नाटक मे हुए। इन आकमणों में संघ परिवार के सगठनों ने बढ चढ कर हिस्सा लिया। भाजपा अपनी पुरानी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री और गृहमत्री के मुख से साम्प्रदायिक सौहार्द, बहुरंगी संस्कृति, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा का राग अलापती रही और अपने सहयोगी संस्थाओं को आकमण करने के लिये उकसाती रही। भाजपा शासित राज्यों के शिक्षामंत्री व केन्द्रीय शिक्षा मंत्री वन्दे मातरम् को अनिवार्य करने; पाठ्य पुस्तकों को बदलकर उनमें साम्प्रदायिक रंग चढाने, महाराष्ट में जिलों के नाम बदलकर अल्पसंख्यक वर्गों को चिढाने, उत्तेजित करने और उनकी आस्थाओं पर हमले करते रहें और केन्द्रीय सरकार के जिम्मेदार मुखिया व कर्ता धर्ता इन कुकृत्य की सौहार्दपूर्ण आलोचना कर अपने कर्त्वय की इतिश्री करते रहे। भाजपा के इस दोगली, दोमुंही राजनीति का सिलसिला बाबरी मस्जिद शहादत से प्रारम्भ होकर चिकमंगलूर के धर्मस्थल के कब्जे की नापाक कोशिश करते हुए इसाई समुदाय के ऊपर संगठित हमले तक पहुँचा है।

भाजपा के लचर, दब्बू विघटनकारी आंतरिक नीति के कारण सम्पूर्ण देश आराजकता के महासागर में डूब गया है। भारत के सम्पूर्ण पर्वोत्तर राज्य उग्रवाद की ज्वाला से झुलस रहे हैं। अलगाववादी ताकतों का पूर्वोत्तर भारत केन्द्र स्थल बन गया है। जम्मू और काश्मीर में सीमा पार से प्रोत्साहित उग्रवाद, अलगाववाद मानों वहां रच बस गया है। पश्चिमोत्तर, पर्वोत्तर राज्य केन्द्र सरकार की लचर मानसिकता के कारण भारत के मुख्य समाज से अलग थलग होने की स्थिति में हैं। देश के मध्य भाग में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों पर होने वाले संगठित आकमण ने इन क्षेत्रों की जनता में भय और आतंक का वातावरण तैयार किया है । इसलिये सपा की राय में इन क्षेत्रों में पनपने वाले उग्रवाद का निस्तारण भाजपा की संकीर्ण मानसिकता के कारण संभव नहीं है।भाजपा शासित राज्यों में विगडते साम्प्रदायिक सौहार्द ने अलगाववादी शक्तियों को ताकतवर बनाया है।देश के महानगरों में कानून व्यवस्था ने एक गम्भीर मोड़ ले लिया है। भारत की राजधानी दिल्ली व भारत की आर्थिक नगरी मुम्बई सीमा पार अन्तर्राष्टीय माफिया गिरोहों के चंगुल में हो गयो है।

भाजपा की संकीर्ण मानसिकता वाली सरकार अन्तर्राष्ट्रीय माफिया गिरोह के समक्ष नतमस्तक है और उसके नेता तो उक्त गतिविधियो को नेस्तानाबूत करने के बजाय उसका भी राजनैतिक इस्तेमाल अपने राजनैतिक विरोधियो के दमन के लिये कर रहे है। समाजवादी पार्टी का यह सम्मेलन केन्द्र की नपुंसक घरेलू नीति की तीव्र स्वर से भर्त्सना करता है।

भारत के प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री अर्न्तराष्टीय पूँजी निवेशों के सम्मेलन में बीमा क्षेत्र में विदेशी पूँजी विनिवेश के लिए दरवाजा खोल देने की महत्वपूर्ण घोषणा करते हैं जबकि संसद का शीतकालीन अधिवेशन चल रहा था। प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री देश के धन्ना सेठों को अपने घर में बुलाकर देश की आर्थिक नीति के बारे में दिशा निर्देश लेते हैं।भारत के आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून के 1981 के विषेश उपबन्धो को समाप्त कर भारत की सरकार मुनाफाखोरों और जवा खोरो को जनता की खुली लूट के लिए प्रोत्साहित करती है जिसके करण निर्भिक भाव से समाज के लुटेरो ने आम जनता को बर्बरतापूर्वक लूटा। सपा का यह राष्टीय सम्मेलन अर्न्तराष्ट्रीय पूँजीवाद के भण्डारवाद व देशी धन्ना सेठों की वफादार भाजपाई सरकार से जंग करने के लिये देश की जनता से एकजुट होने का आह्वान करता है।

समाजवादी पार्टी की राय है कि देश का लोकतंत्र सर्वाधिक संकट के दौर में प्रवेश कर गया है। बिहार के मामले में केन्द्रीय सरकार जनतात्रिक मूल्यों को तहस–नहस करने के लिए तुली हुई है। बिहार की जनता द्वारा चुनी गयी और विधान सभा का पूर्ण बहुमत प्राप्त सरकार को बर्खास्त करने के लिये जिन हथकण्डों को अपना रही है। उससे लोकतन्त्र की मर्यादा खत्म हो रही है। बेशरमाई की हद तो यह है कि यह महामहिम राष्ट्रपति तथा अभी हाल में हुए बिहार के उप चुनावों से जनता के फैसलों के बाद भी केन्द्रीय सरकार के मंत्रीगण बिहार सरकार को भंग करने के बयान दे रहे हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र, में हुए दंगों पर श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट को भाजपा, शिवसेना सरकार द्वारा पूरी तरह अस्वीकार करके रिपोर्ट के खिलाफ जिस तरह मुसलमानों पर आरोप लगायें है और जस्टिस श्रीकृष्ण पर मुसलमान समर्थक होने का आरोप लगाया है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये घातक

है। श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के रुख ने भविष्य में गठित होने वाले न्यायायिक जांच आयोगो की विश्सनीयता को समाप्त कर दिया है और यह भाजपा की लोकतंत्र विरोधी फासिस्टवादी मानसिकता का ज्वलन्त उदाहरण है।

भारत में पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिनका अपनी सरकार और पिछलग्गू दलों पर कोई नियंत्रण नहीं है। जिसके कारण देश का सम्मान दुनियां में घटा है। विश्व के विकासशील राष्ट्रों ने भी भारत से मुंह मोड लिया है और पडौसी देशों के साथ कटुतापूर्ण संबंध बने हैं। विश्व में आणविक शक्ति बनने और भारत के अन्दर राष्ट्रीयता का उन्माद पैदा कर अपने सियासी विरोधियों को समाप्त करने की दूषित मानसिकता के कारण मई में पोखरण में दो विस्फोट किया गया। विपक्षी दलों को विश्वास में लिये बिना और विश्व स्तर पर अपने परम्परागत मित्र देशों को विश्वास में लिये बिना जिस बचकाने ढंग से भारत सरकार ने इतने बड़े संवेदनशील प्रकरण को हल करने की कोशिश की, उससे भारत विश्व स्तर पर अलग थलग पड़ गया। भारत पर जबर्दस्त आर्थिक दबाव बढे, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की पहल करने का जिन देशों का वचन था वे अपने वचन से पीछे हटे। अपनी नाक बचाने के लिए अमेरिकी विदेश उपमंत्री के पीछे–पीछे भारत के नुमाइन्दा पूरी दुनियां में घूमते रहे और अंततः विश्व पंचायत में भारत के प्रधानमंत्री को देश को विश्वास में लिए बिना सी० टी० बी० टी० जैसी संधि पर हस्ताक्षर करने का वचन देना पड़ा। समाजवादी पार्टी ऐसी किसी भी अर्न्तराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने के विरूद्ध है जिसका सीधा असर भारत की दूरगामी सुरक्षा पर पड़ता है। सपा का यह सम्मेलन भारत सरकार को कड़ी चेतावनी देना चाहता है कि अपनी लचर और दब्बू नीति के कारण भारत को स्थायी रूप से सुरक्षात्मक मामलों में विश्व की ताकतवर जमातों के हवाले न कर दें,

भारत की वर्तमान कमजोर सरकार के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा है। संविधानेत्तर संगठनों ने भारत सरकार पर अपना दबदबा कायम करने का प्रयास बढ़ाये हैं। भाजपा ने येन केन प्रकारेण अपनी गद्दी बचाए रखने के

लिये राजनैतिक भ्रष्ट्राचारियों से सन्धि स्थापित किये है अपने राजनेतिक विरोधियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे उछालकर उन्हें अपमानित और राजनैतिक रूप से कमजोर करने के षड़यन्त्र किये गये और दूसरी तरफ अपने सहयोगियो को भ्रष्टाचार करने के लिये अभयदान दिया गया। लोकपाल विधेयक व सर्तकता आयोग विधेयकों का प्रचार तो बहुत किया गया लेकिन उसे अधिनियम का रूप देने की कोई पहल नहीं की गयी। भ्रष्ट और बदनाम सहयोगी दलों के नेताओं के खिलाफ जांच करने वाले जांच अधिकारियों को राज सत्ता के बल पर अपने पदों से हटाया गया अथवा स्थानान्तरित किया गया, जिसके चलते योग्य, निष्पक्ष, ईमानदार अधिकारियों का मनोबल गिरा और भ्रष्टाचारी उत्साहित हुए। भाजपा की सोची समझी रणनीति के तहत संसद की सर्वोच्चता को चुनौती मिलने लगी। भाजपा की स्पष्ट राय संसदीय प्रणाली को समाप्त कर राष्ट्रपति प्रणाली लाने की है क्योकि संसदीय प्रणाली में विगत 50 वर्षो के कठिन संघर्ष के बाद समाज की दबी पिछडी जातियो ने भी अपने ताकत की बदौलत राज सत्ता में अपना थोडा हिस्सा प्राप्त किया है। राष्ट्रपति प्रणाली समाज के कमजोर वर्गो के राज सत्ता में हिस्सेदारी का निषेध है। भारत की न्यायपालिका अपनी सक्रियता के बहाने जिस भद्दे ढंग से भारत के संसद की सर्वोच्चता को चुनौती देती रहती है, उससे सपा की आशंका सच साबित होती है। भारतीय न्यायपालिका अपनी सीमाओ का नये ढंग से अतिक्रमण कर रही है। जन नेताओं को बदनाम करना संवैधानिक धाराओं को अपनी रुचि के अनुसार भाष्य करना, राजनैतिक मामलो मे पसंदीदा फैसला मानों न्यायपालिका का दैनिक कार्य हो गया है। उत्तर प्रदेश में दल–बदल जैसे घिनौने कृत्य का कोई फैसला न देना, मुलायम सिंह यादव सरकार की मनमानी बर्खास्तगी पर चार वर्षों बाद भी संवैधानिक बैंच न बैठाना, लालू प्रसाद की जमानत की दरख्वास्त पर महीनों कोई निर्णय न देना, इसके ज्वलन्त उदाहरण है। लोकतंत्र मे जनता सभी का मूल्यांकन करती है, न्यायपालिका का भी, जजों का भी।

सपा की स्पष्ट राय है कि भारत की संघर्षशील बहादुर जनता भाजपा की गैर जबाबदेह, अक्षम सरकार से छुटकारा हेतु कृत संकल्प है। अभी हाल में तीन राज्यों के चुनाव परिणाम जनता के अभिमत के स्पष्ट संकेत है। भारत सरकार

इस जनादेश को राज्य सरकारो के खिलाफ अभिमत मानकर जनमानस को झुठलाना चाहती है। किन्तु अन्दर से आशंकित भी है, लेकिन हिन्दुत्व एजेण्डा ही भाजपा का एकसूत्रीय एजेण्डा है। इसलिये सपा देश के वृहत्तर हितो को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र की सुरक्षा और अखण्डता के लिये केन्द्र सरकार की लंगडी सरकार को तुरन्त अपदस्थ करने के लिये संकल्पबद्ध है। तीन राज्यों की जनता ने इस राय को और मजबूती दी है। किन्तु इन राज्यों के नकारात्मक वोट प्राप्त करने के बाद की कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार, भाई, भतीजावाद, दामों की लूट बढ़ाने वाली कांग्रेस पार्टी ने उसे अपने पक्ष मे अभिमत मानकर चुनाव की उन उपलब्धियों पर पानी डाल दिया।सपा के बार बार आश्वासनों के बावजूद कॉग्रेस पार्टी ने केन्द्रीय भाजपा और उसके पिछलग्गुओं की सरकार को हटाने में कोई पहल नहीं की अपितु विगत संसद के सत्र में सरकार चलाने मे भरपूर सकारात्मक भूमिका निभायी। बीमा विधेयक और पेटेन्ट विधेयक, जो भारत की अर्न्तराष्ट्रीय स्थायी आर्थिक गुलामी के प्रतीक हैं, उन्हें पास कराने में अग्रिम भूमिका निभायी। पेटेंट विधेयक पर तो राज्यसभा में उनके पक्ष में मतदान किया और बदले में उनसे जोड़ तोड करके लोकसभा उपाध्यक्ष का पद हथिया लिया । राजस्थान, दिल्ली मध्य प्रदेश, में सरकार बनाने से पगलाई कॉग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ भाजपा से मिलकर विभिन्न राज्यों में अपने दल के राज्यपालो की नौकरी बचा रही है, केवल बोफोर्स केस के बहुप्रचारित रक्षा सौदा घूस काण्ड का पर्दा न उठ सके, इसलिये तमाम घोटालों के जाल में फंसी कॉग्रेस पार्टी भाजपा से निर्णायक और महत्वपूर्ण संघर्ष करने से भाग रही है, समाजवादी पार्टी राष्ट्र के समक्ष आयी चुनैती का मुकाबला करने के लिये कटिबद्ध है।

विदेशी ताकतों की साजिश इस देश को बाँटने की है। संघ, भाजपा एवं विश्व हिन्दू परिषद की कुत्सित मानसिकता के बावजूद सपा के प्रयास से देश की दो बड़ी ताकतों हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच गहरी निकटता बढ़ी है। अल्पसंख्यकों, दलितों एवं पिछड़ों की मद्द से विदेशी प्रभावों और खास तौर से अंग्रेजी और अंग्रेजियत के खिलाफ देश भर मे मुहिम चलाने की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी की राय है कि भाषा, जाति और आर्थिक गुलामी के सवालों पर भाजपा और कांग्रेस का वर्ग चरित्र एक है । यह दोनों

दल विदेशी भाषा की गुलामी, परम्परागत वर्णीय समाज व्यवस्था के पोषक और अन्तर्राष्ट्रीय व देशी पूंजीवाद के गुलाम है। सपा भारतीय भाषाओं के पक्ष में जाति विनाश के लिये आर्थिक दासता के खिलाफ ऐतिहासिक संग्राम के लिये अपनी वचन बद्धता दुहराती है। इसे पूरा करने के लिये राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक मोर्चा का गठन एक लघु प्रयास है। सपा का यह राष्ट्रीय सम्मेलन सहमना वैचारिक शक्तियो से आग्रह करना चाहता है कि सपा के इस निर्णायक समाज और देश बनाओं आन्दोलन में सहयोगी बने और इसके लिये यह सम्मेलन देश के राजनैतिक क्षितिज पर एक तीसरी शक्ति के गठन को कांग्रेस और भाजपा, देशी विदेशी पूंजीवाद, असमानता पोषक व्यवस्था तथा अलगाववाद और लोकतंत्र विरोधी नीतियों के खिलाफ जिहाद बोलकर देश के सामने एक सक्षम विकल्प रख सके । लेकिन सम्मेलन तीसरी शक्ति के पक्षधरों, विशेषकर वामपंथी दलों से कहना चाहता है कि इसके गठन में व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपनी पसन्द नापसन्द को मुद्दा न बनायें।[8]

6.पॉचवां राष्ट्रीय सम्मेलन

अध्यक्षीय भाषण –

सपा के पांचवां राष्ट्रीय सम्मेलन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमुलायम सिंह यादव जी ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि– आप जानते है कि कानपुर एक ऐतिहासिक शहर है। हलांकि कानपुर को एक बड़े शहर के रूप में दो सौ साल पहले अंग्रेजो ने ही बसाया था लेकिन 1857 में आजादी के पहले संग्राम के दौरान अंग्रेजों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। अंग्रेजो ने अपने लोगों की हत्या का जबरदस्त बदला लिया था। बिठूर का, जो हमारे धार्मिक, आध्यात्मिक केन्द्र के साथ–साथ नाना साहब पेशवा की कर्मभूमि थी एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व, मध्य और बुन्देल खंड को जोड़ने वाला यह शहर हमारी आर्थिक और राजनैतिक समृद्धि का केन्द्र रहा है। शिक्षा, साहित्य,उद्योग और पत्रकारिता का बड़ा केन्द्र रहा है और आज भी है। हमारे श्रमिक आन्दोलन के

8 – सपा के 'चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन' भोपाल मे31 जनवरी 1999 को पारित राजनैतिक प्रस्ताव

इतिहास में कानपुर का नाम पूरे देश में चर्चित रहा है। महान बलिदानी गणेश शंकर विद्यार्थी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन,कामरेड राम आसरे,आयोध्या नाथ के साथ सैकड़ों महान लोगों ने हर क्षेत्र में योगदान किया है। जहॉ तक कानपुर समाजवादी आन्दोलन का भी बड़ा केन्द्र रहा है कानपुर में 1946 में कॉग्रेस समाजवादी पार्टी को लेकर आचार्य नरेन्द्र देव कॉग्रेस से अलग हुए थे वही से भारतीय राजनीति में समाजवादी आन्दोलन की धारा अलग से प्रवाहित हुई थी। आचार्य नरेन्द्र देव, डा0 राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण की प्रेरणा और विरासत से ही समाजवादी पार्टी बढ़ी है और आज भी निरन्तर संघर्ष कर रही है। ऐसे ऐतिहासिक नगर में आप सभी साथियों का स्वागत और अभिनन्दन है।

आजादी के बाद का सबसे खतरनाक दौर–

देश आजकल कितने गम्भीर संकटों से गुजर रहा है। यह खतरा राजनितिक, आर्थिक और सामाजिक भी है। देश की सीमायें सुरक्षित नहीं हैं और देश में आन्तरिक विद्रोह जैसी स्थितियां बन गयी हैं। उग्रवादी, आतंकवादी और साम्प्रदायिक ताकतें लगातार मजबूत और हिंसक हो गयी हैं। अपराधी और भ्रष्टाचारी लोग राजनीति तथा खासकर सत्ताधारी दलों मे घुसकर उन पर कब्जा कर रहे हैं और यह सबसे बड़ी चिन्ता तथा खतरे की बात हो गयी है कि भारत में लोकतन्त्र बचेगा या नहीं? एक देश के रूप मे क्या हमारी पहचान खत्म हो जायेगी? सबसे ताजा उदाहरण संसद पर हुआ हमला है। आतंकवादी संसद के अन्दर घुस जाते तो उनका निशाना देश की राजनीतिक नेतृत्व था। सभी नेताओं और संसद के सदस्यों को एक साथ समाप्त करना चाहते थे। हमारे 9 बहादुर सुरक्षा कर्मियों ने तेरह दिसम्बर को अपनी कुर्बानी देकर देश को बचा लिया था। उनकी बहादुरी और देशभक्ति की जितनी तारीफ की जाये वह कम है । लेकिन असली सवाल यह है कि यहां तक नौबत कैसे पहुँची। यह पहली घटना नहीं है। आतंकवाद के हमलों का पूरा इतिहास है। बीस साल में आतंकवादियों के हमलों में एक लाख से ज्यादा लोग मारे गये हैं। केवल पिछले तीन साल मे मारे गये लोगों की संख्या बीस हजार से ज्यादा हैं।इसके लिये जिम्मेदार कौन है? तीन साल से

इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतात्रिक गठबंधन की सरकार चल रही है।इस सरकार ने देश को राजनीतिक ओर आर्थिक गुलामी के कगार पर पहुँचा दिया है।

इस सरकार ने पिछले तीन सालों में चुनावों में जीत के लिये देश की सुरक्षा और आजदी को भी दॉव पर लगा दिया है। यह आरोप नहीं है इसके पुख्ता प्रमाण मौजूद हैं। सारी दुनियॉ को पता था कि भारत के पास परमाणु बम बनाने की क्षमता है। इन्दिरा गॉधी ने इसे 1974 मे दिखा दिया था। उसके बाद परमाणु बम का परीक्षण शक्ति वाला देश बनवा दिया। आज सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर भारत –पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा तो ऐटमी हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है। सबसे पहले मैने कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर मे आंतकवादियों को तैयार करने वाले जो प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। उन पर हमला करके उन्हें नष्ट कर दिया जाये। आज तो वे केन्द्र भी शायद पाक अधिकृत कश्मीर से हटा दिये गये हैं। अब युद्ध के लिये भारत को बहुत सोच– समझकर कदम उठाना पड़ेगा दूसरी घटना कारगिल पर आक्रमण को लेकर हुई। कारगिल का युद्ध इस सरकार की असावधानी और गलत नीतियों के कारण हुआ था। उसको जीतने के लिये हमारी बहादुर सेनाओं ने कितना बड़ा बलिदान दिया था यह इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। सभी राजनीतिक मतभेद भुलाकर पूरा देश सेनाओं के पीछे एक चट्टान की तरह खड़ा हो गया था लेकिन पाकिस्तानी सैनिक घुसकर हमारी चौकियों पर कब्जा करते रहे और हमें पता ही नहीं चला, इसके लिये केन्द्रीय सरकार के अलावा कौंन जिम्मेदार है? कारगिल के मामले पर इसी सरकार ने जो जांच कमेटी गठित की थी उसकी रपट आ गयी है लेकिन सरकार उस पर बहस नहीं कराना चाहती है। कारगिल में पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ का पता इस सरकार को था या नही। इसने सूचनाओं को देश से क्यों छुपाया। आज भी जांच रपट पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों हो रही है, इन सवालों पर जवाब देने के बजाय 1999 के लोकसभा चुनाव में इस प्रकार सरकार ने कारगिल युद्ध को को भी भुनाया था शहीद सैंनिको के खून का तिलक अपने माथे पर लगाकर भाजपा ने बहुमत जुटाने की कोशिश की

थी लेकिन देश की जनता ने उसे नकार दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो उसी चुनाव में भाजपा को ठुकरा दिया था।

1998 में जब अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार लोकसभा में हार गयी थी उस समय अगर कांग्रेस ने देशहित में उदार सहयोग का रूख अपनाया होता तो यह सरकार दुबारा सत्ता में नहीं आ सकती थी लेकिन यह नहीं हो सका। पिछले दो साल में यह सरकार देश के लिये खतरा बन गयी है। पाकिस्तान के फौजी राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ कारगिल युद्ध के लिये जिम्मेदार थे। उनको बातचीत के लिये बुलाने की क्या जरूरत थी। उससे क्या निकला? वे हमारी सीमाओं पर हमले करते रहे और भारत सरकार ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित करके सुरक्षा बलों के हाथ बांध दिये थे। उसी का नतीजा आज देश भोग रहा है। यह देश की जरूरत नहीं थी। यह अमेरिका का दबाव था। आज प्रधानमंत्री ऑसू बहा रहे है कि युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था। याद कीजिए जब नेपाल से हवाई जहाज का अपहरण हुआ था और कंधार में समझौता हुआ था । जैश–ए–मोहम्मद जिस पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग हो रही है। उसका संस्थापक अजहर मसूद जम्मू की जेल में बन्द था। उसे निकाल कर विदेश मंत्री जसवंत सिंह शाही ठाटबाट से अपने हवाई जहाज से कंधार पहुँचाने गये थे। अब गृहमंत्री कह रहे हैं कि यह एक भारी भूल थी। अगर सरकार खुद अपनी गलती मंजूर करती है तो इसकों बने रहने का क्या अधिकार है? इस सरकार के रहते देश और लोकतन्त्र की सुरक्षा नहीं हो सकती है।

जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार है। डॉ0 फारूख अब्दुल्ला उसके मुख्यमंत्री है । उनकी उपेक्षा करके सरकार आंतकवादी संगठनों से बातचीत क्यों चलाती है। उनको रिहा करती है योजना आयोग के उपाध्यक्ष कृष्ण चन्द्र पन्त को बातचीत के के लिये भेजती है और फिर पाकिस्तान से बातचीत करने लगती है क्यो? इसके पीछे अमेरिका दबाव है। यह एक खतरनाक सकेत है कि भारत की राजनीति और अर्थनीति पर अमेरिका का शिकंजा कसता जा रहा है। एक नई गुलामी का आरम्भ हो चुका है हमारी स्वायत्तता और प्रभुसत्ता पर हमला अमेरिका ने किया है। दूसरा हमला पाकिस्तान की सह पर

आतंकवादियों ने किया है। पिछले साल ग्यारह सितम्बर को अमेरिका पर आतंकवादियों का हमला हुआ । हमने हर मदद देने की कोशिश की, लेकिन जब 20 दिन बाद श्रीनगर में जम्मू काश्मीर विधान भवन पर आतकवादियो ने जबरदस्त विस्फोट करके हमला किया, पचास से ज्यादा लोग मारे गये तो अमेरिका ने हमारी क्या मदद की? अभी संसद में हमला हुआ तो अमेरिका की यही कोशिश है कि वह पाकिस्तान और भारत को एक ही तराजू मे तौले। यह स्थित देश को मंजूर नहीं है और हमें पूरे देश को अमेरिका तथा बहराष्ट्रीय कम्पनियों की उन कोशिशों के खिलाफ जागरुक करना पडेगा अन्यथा हमारी आजादी फिर खतरे में पड़ जायेगी।

केन्द्रीय सरकार भ्रष्टाचार, घोटाला और देश की सम्पत्ति को नीलाम करने वाली सरकार साबित हुई। अखबारों और टी0वी चैनलों में आपने लगातार देखा है। यूनिट ट्रस्ट 64 काण्ड, तहलका काण्ड और ताबूत घोटाला काण्ड है। सरकार से हमने रक्षामंत्री जार्ज फर्नाडीज को हटाने की मांग नहीं की थी लेकिन जब यह घोषणा की गयी कि जांच कमेटी से पाक साफ साबित होने के बाद ही वह मंत्री बनेगे तो इतनी जल्दी क्या थी ? कैग की रपट से ताबूत खरीदने का जो हवाला है वह बेहद शर्मनाक हैं। अनेक घोटाले अभी सुर्खियों में नहीं आये है। सरकार ने इस वर्ष 2002 तक देश की सत्ताइस सरकारी कम्पनियों को नीलाम करके 52 हजार करोड़ रूपया उगाहने का फैसला किया है। इसके अलावा इण्डियन एयर लाइन्स और एयर इण्डिया जैसी प्रतिष्ठित और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली कम्पनियों को भी बेचने की तैयारी है। दो करोड़ कर्मचारियो को बेरोजगार करने की साजिश शुरू हो गयी है। इन कम्पनियों को विदेशियों के हाथों बेचा जा रहा और उनमें जबरदस्त घोटाला है। माडर्न फूड्स, हिन्दुस्तान लीवर और एल्यूमिनियम बनाने वाली कम्पनी बाल्को को स्टार लाइट कम्पनी को बेचा गया है। अगर इन दोनों उद्योगों की बिकी की जांच कराई जाय तो देश के सामने सच्चाई आ जायेगी। दूसरा बड़ा गम्भीर मामला एक्सप्रेस हाई–वे बनाने का है। सारे ठेके विदेशी कम्पनियों को दिये जा रहे है। जो सड़क भारत के सबसे मशहूर ठेकेदार पांच करोड़ रूपया प्रति किलोमीटर की दर पर बनाने को तैयार हैं।

उसे मलेशिया की कम्पनी को 30 करोड़ की दर में दिया जा रहा है । ऐसे सैकड़ों मामले है जिनके लिये सरकार अपराधी है।

विश्व क्षितिज पर अब अमेरिका अकेला राजनीतिक खिलाड़ी बचा है, सोवियत संघ के विघटन के बाद सारा मैदान उसके हाथ में है। हमेशा अमेरिकी प्रयास रहा है कि भारत एक स्वावलम्बी और तटस्थ राष्ट्र के रुप में खड़ा न हो सके, उसके विदेश नीति का झुकाव सदैव पाकिस्तान के पक्ष में रहा है। भारतीय सरकार ने अपने खराब दिनों के दोस्तों को नमस्कार कर लिया है। सबसे आत्मघाती कदम तो गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की समाप्ति थी। विश्व के सभी घटनाकम पर भारत स्वतन्त्र, निरपेक्ष और निर्भीक राय रखने वाला देश माना जाता था। अब भारत भी अमेरिका के पिछलग्गू देशों की जमान के रूप में देखा जा रहा है। विश्व के विकासमान देश भारत से नेतृत्व की अपेक्षा रखते थे, वह अब समाप्त है। पाकिस्तान की ख़ुफिया एजेन्सी आई0 एस0 आई0 के इशारे पर हमारा सम्पूर्ण पूर्वोत्तर राज्य जम्मू कश्मीर आंतकवाद की साया में है और उस आई0 एस0 आई0 का ताना बाना तैयार करने मे अमेरिकी खुफिया तंत्र सी0 आई0 ए0 और एफ0 बी0 आई0 का आर्शीवाद है। आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा झारखण्ड, बिहार तथा सम्पूर्ण पर्वोत्तर उग्रवादियों की गिरफ्त में है। भारत सरकार की पूरी आन्तरिक सुरक्षा नीति विफल है। हमारे पड़ोसी वर्मा भूटान, नेपाल में उग्रवादियो को प्रशिक्षित करने के कैम्प हैं जो आई0 एस0 आई0 द्वारा संचालित हैं। इसे ध्वस्त करने की सार्मथ्य हमारी सरकार में नही हैं। अब तो हमारे पड़ोसी देशो पर भी उग्रवादी हिंसा ने कब्जा कर लिया है। भारत के पड़ोसी देशों में लोकतांत्रिक आंदोलन और तंत्र खड़ा करने में भारत की सदैव रुचि रही है और हमने राष्ट्रीय हित में न केवल उन आंदोलनों को प्रोत्साहित किया अपितु लोकतांत्रिक व्यवस्था को काफी सहारा दिया। इन पड़ोसी देशों में लोकतंत्र के विनाश से भारत की आन्तरिक शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है। यह चिन्ता का विषय है कि भारत सरकार पड़ोसी देशों के लोकतांत्रिक शक्तियों से अपना रिश्ता तोड़कर सैनिक हुक्मरानों, संकीर्ण साम्प्रदायिक तत्वों और राजाओं से रिश्ते प्रगाढ़ करने में लगी है। इसका नतीजा न केवल पूर्वोत्तर राज्य अपितु बिहार और उत्तराँचल, उत्तर प्रदेश की लोकशान्ति खतरे में पड़ गयी है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के समृद्ध देशों ने व्यापारिक सुविधा के लिये गैट की स्थापना की था। भारत भी उसका संस्थापक देश थी इसलिये विश्व को एक व्यापारिक छतरी में लाने के लिये गत शताब्दी के अन्तिम दशक मे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हो गयी। दुनियॉ के व्यापार नियन्ता और एकमात्र खिलाडी 'यूरो' अमेरिकी समुदाय के लोग बन गये,उनके इशारे पर अर्न्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैक ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था का भूमण्डलीकरण करा दिया। कॉग्रेसी नेताओं ने नई व्यवस्था का ढोल खूब पीटा, लेकिन उसी व्यवस्था को जिसकी तब भाजपाईयों ने कडी निन्दा की थी, सरकार आने के बाद उसकी धारावाहिकता की गति को और तीव्र कर दिया । 13 दिन के लिये दिल्ली में वाजपेयी जी के नेतृत्व मे 1996 में एक सरकार बनी। अपना बहुमत सिद्ध करने के पूर्व ही अमेरिका की बिजली बनाने वाली एक बड़ी कम्पनी एनरॉन को महाराष्ट्र के दाभोल मे विद्युत उत्पादन केन्द्र स्थापित करने की काउन्टर गारन्टी दे दी, जबकि वहॉ के कॉग्रेस मुख्यमंत्री शरद पवार ने जब इस कम्पनी को न्योता भेजा तो भाजपाईयों ने उसका तीव्र विरोध किया था। एनरॉन को काउन्टर गारन्टी भाजपा ने केवल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को संकेत देने के लिये किया था कि हम सत्ता में आये तो आपकी सेवा में कॉग्रेस से आगे बढ़कर हाजिर रहेंगे। फिर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अपना आर्शीवाद भाजपा को भी दे दिया। आज उस कम्पनी क्या हाल है? न केवल विश्व के लाखों लोगों का पैसा खाकर वह कम्पनी दिवालिया हो गयी, अपितु दाभोल की महंगी बिजली खरीद कर इस देश का सम्पन्न राज्य महाराष्ट्र भी तारे गिन रहा है उसकी आर्थिक हालत भी खस्ता हो गयी। अब एनरॉन पावर कम्पनी इस देश के बैंको और वित्तीय संस्थानो का 4 हजार करोड़ रुपये डूबा रही है।

भाजपा की सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के बहाने देश को समृद्ध देशों के हाथ बंधक बना दिया । बेरोकटोक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश ने देश की खेती, उद्योग, व्यापार सभी का विनाश कर दिया। खेती का उत्पादन लगातार घटाव की ओर है। देशी सभी कारखानों में ताले लग रहे हैं। भारत में तैयार होने वाले कपड़े के खिलाफ यूरोप–अमेरिका में एण्टी डम्पिंग कानून लगा है। इसका परिणाम है कि कपडे के विश्व व्यापार में भारत की 4 प्रतिशत

हिस्सेदारी अब कम होती जा रही है। विदेशी खाद्यान्न अपनी खपत के 15 प्रतिशत आयात करती है, खाद्य तेल, चीनी चावल दाल ही नही दूध और अण्डा भी बाहर से मंगाया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियो ने मास की सबसे बड़ी खपत वाला देश भारत को घोषित कर दिया । धीरे-धीरे भारत की सभी रोजगारपरक धन्धों पर विदेशियों का कब्जा होने की तैयारी है जिससे भारत के हक में केवल कगाली और लाचारी बचने वाली है। इसलिये भारत धीरे-धीरे विश्व के गरीब देशों की कोटि में आ रहा है।

भारत में खाद्यान्न के गोदाम भरे हैं। 10 लाख टन अनाज का भण्डार तो सड़ गया दूसरी तरफ देश के विभिन्न हिस्सों में उपज का लाभकारी मूल्य न मिलने से किसान आत्म हत्या को मजबूर है तो दूसरी तरफ उड़ीसा , मध्यप्रदेश, के विभिन्न हिस्सों में भूख से मौते हो रही है। दूर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि संवेदनशून्य प्रधानमंत्री ने भूख से होने वाली मौतो को अखबारनवीसों की गढ़ी कहानी कहकर झुठला दिया है। गरीबी की भयावह स्थिति का आंकलन इसी आशय से किया जा सकता है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में भूख और कुपोषण से एक वर्ष में 8हजार बच्चे मर गये, राजस्थान के 32 मे से 31 जिले अकाल की चपेट में हैं। नई आर्थिक नीति के सबसे बड़े झण्डावर्दार आन्ध्र के मुख्यमंत्री हैं। उनका दावा है कि सूचना क्रान्ति सबसे पहले उनके आंगन में आई, लेकिन वहाँ सैकड़ो बुनकर रोजी-रोटी के अभाव में आत्म हत्या किये। किसानों द्वारा आत्महत्याओं का सिलसिला सबसे पहले आन्ध्र मे ही शुरू हुआ था। वहां के लाचार युवक और ग्रामीण हाथ में हथियार लेकर बगावत का शंख फूंक दिए हें, तो उनको नक्सली कहकर पकड़-पकड़ कर हत्यायें की जा रही हैं। संवेदनहीनता नई अर्थव्यवस्था का मूल तत्व है। "अमीर को और अधिक अमीर बनाओ-लाचार की कंगाली शीर्ष तक पहुँचाओ।"

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल यानी अपराधियों का जमघट

उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव के बाद दो बहनों- भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई । जब यह सरकार बनी तो बसपा की तुलना में भाजपा के विधायकों की संख्या तिगुनी थी लेकिन भाजपा ने सरकार का नेतृत्व बसपा को दे दिया। इसलिए वह किसी

भी कीमत पर सरकार बनाने के लिए आतुर थी । उसकी बस एक ही चाहत थी कि किसी तरह भी हो सरकार मे आ जाओ। सो बसपा के नेतृत्व को स्वीकार कर सरकार बना ली । यह भाजपा ने इसके बावजूद किया कि बसपा,ने उसे पहले एक जबर्दस्त धोखा दिया था। धोखा देना इस पार्टी के घोषणा– पत्र का हिस्सा है भी परन्तु छह महीने सरकार चलाने और प्रदेश भर में जम कर लूटपाट मचाने और हरिजन एक्ट के नाम पर अत्याचार मचाने के बाद अपनी आदत के मुताबिक बसपा ने भाजपा को फिर डक मार दिया। सर्मथन वापस ले लिया । लेकिन भाजपा को किसी भी कीमत पर सत्ता में रहना था सेा उसने कई विपक्षी दलों में भारी तोड़–फोड मचाई, विपक्षी दल तोड़ दिये गयें। टूटकर आने वाले सारे विधायको केा मंत्री बना दिया। सत्ता के दुरुपयोग का ऐसा नाटक इससे पहले कभी इस प्रदेश में नही हुआ था। नजीता यह हुआ कि मंत्रिमंडल वास्तव में अपराधियों और भ्रष्ट लोगों का झुंड बन गया। जो अपराधी जेल से बाहर थे। उन सबके सरगना मत्री बन गये यानी चोरों को कोतवाल बना दिया गया। जिनकी पुलिस को कल तलाश थी, उन्हें पुलिस को सलूट मारने को बाध्य होना पड़ गया।यह सब उस भाजपा की कृपा थी, जो अपने को देशभक्त, रामभक्त और साफ– सुथरी राजनीति का प्रवक्ता बताती थी। इन मंत्रियों के किस्से इतने है कि एक किताब इन पर लिख दी जाय।

मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिनों पहले एक इन्टरव्यू में कहा है कि उनकी सरकार में अब कोई अपराधी या भ्रष्ट मंत्री नहीं है । मै आपको तीन साल पहले के लिये चलता हूँ। भाजपा के एक बड़े नेता है– कुशाभाऊ ठाकरे इन्होने एक प्रेस कांफ्रेंस से खुलेआम स्वीकार किया कि प्रदेश सरकार में अपराधी छवि के लोग मंत्री हैं। कुछ समय पहले समजवादी पार्टी ने एक सांसद को इसलिये पार्टी से निकाल दिया कि उन पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप था। जब तक ये सांसद हमारे साथ थे तो यह आरोप लगता था कि उनके सम्मान मेें आयोजित एक समारोह में यही कुशाभाऊ ठाकरे बाकायदा उपस्थित हुए। अब वे सांसद अपराधी छवि के नहीं रहे अब वे भाजपा के छतरी के नीचे चले गये हैं।

कितने अपराधी सरकार मे है। मुख्यमंत्री में और उनकी पार्टी मे हिम्मत है और वे वाकई अपराधीकरण के खिलाफ है तो स्पेशल टास्क फोर्स की वह रिपोर्ट सार्वजानिक कर दें, जिसमें मंत्रियों और अपराधियों की साठ–गांठ का कच्चा चिट्ठा मौजूद है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। प्रदेश के लोकायुक्त पिछले साल 4 मई को लखनऊमें एक सवाददाता सम्मेलन किया, जिसमें बाकायदा कहा कि प्रदेश मे कुशासन बढ रहा है लोकायुक्त संगठन को पर्याप्त ताकत नहीं दी जा रही है। जिसकी वजह से हम पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं यह हाल है उस भाजपा का जो सालों से लोकपाल विधेयक और लोकायुक्त की रिपोर्ट विधान सभा में इस बहाने से नहीं रखी गई कि उसका अंग्रेजी से हिन्दी मे अनुवाद करने वाला कोई नहीं है।

घोटाले और घपले–

यहाँ से लेकर दिल्ली तक की केन्द्रीय सरकार घोटालों और घपलों की सरकारें हैं। शेयर घोटाला, यूनिट ट्रस्ट घोटाला एवं कस्टम घोटाला तथा न जाने कितने घोटाले इस सरकार में हो चुके हैं। कुछ समय पहले खबर छपी थी कि वृद्धावस्था पेंशन की रकम बड़े पैमाने पर हड़प ली गयी। कोई एक लाख ऐसे लोगों को पेंशन बाँट दी गयी जो अब इस दुनिया में है ही नहीं । बुढे लोगों को पेशन देने की योजना हमारी सरकार ने प्रारम्भ की थी। लेकिन अब इसके नाम पर घोटाले हो रहें हैं। गरीब बच्चों को वजीफा देने की योजना भी भ्रष्टाचार में डूबी दी गयी।

मै पिछले पांच साल में हुए कुछ घोटालों का जिक्र करना चाहता हूँ।सबसे पहला है अम्बेडकर पार्क घोटाला भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस घोटाले का पूरा पदाफार्श कर दिया गया। बाताया यह गया कि करीब 100 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। उस पर कोई कार्यवाही करना तो दूर रहा भाजपा के एक असरदार मंत्री ने अभी हाल में इस घोटाले से सबको बरी करने का ऐलान कर दिया। इस सरकार के लिये अब सी0 ए0 जी0 की रिपोर्ट के भी कोई मायने नहीं रह गये हैं एक और घोटाला है फ्लोटपम्प घोटाला।जॉच सी0 बी0 आई0 ने किया और पूरा मामला

पकड़ लिया लेकिन मामले को दबा दिया गया क्योकि जिन दो पार्टियो की मिलीभगत से यह घोटाला हुआ था, उन्हे आगे फिर गठबन्धन करना पड़ सकता है और भाजपा अपने इस पूराने और भविष्य के सहयोगी को नाराज नही करना चाहती। एक और है सहकारिता घोटाला। 1200 करोड रुपये का यह घोटाला भी सरकारी फाइलों में दबा पड़ा है। जब उसके उजागर होने का खतरा सामने आया तो भाजपा सरकार ने हमारी पार्टी के उन तमाम नेताओ को सहकारी समितियों से बेदखल कर दिया जो इसकी जड में पहुॅचने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक है पिकप घोटाला और दूसरा है मण्डी घोटाला।सारे घोटाले इसी भाजपा व उसके सहयोगियों की देन है और भ्रष्टाचार की बड़ी–बडी बातें करने वाली भाजपा ने उन्हें दफनाकर रख दिया है।

यह है उस पार्टी की सरकार के मंत्रियों की थोड़ी सी सत्यकथाएं, जो अपने को देशभक्त, रामभक्त, ईमानदार तो कभी साफ–सुथरा बताते हुए नहीं थकते।

मंत्रियों की राजसी ठाटबाट–

भाजपा सरकार के मंत्री पूरी तरह स्वयं सेवक है स्वय सेवक मायने जो सिर्फ अपनी सेवा करना जाने। इनके मंत्रियों ने खुद अपनी सेवा करने में सारे रिकार्ड तोड़ दिये। आज से लगभग 15 साल पहले प्रदेश के मंत्रियों का कुछ खर्च लगभग 70–75 लाख सालाना होता था। 1994–95 में यह खर्च बढ़कर एक करोड़ हुआ। आज के मंत्रियों की फौज पर ढाई करोड़ रुपया हर महीने यह बात केवल उनकी है, जो बाकायदा मंत्री है। इसके अलावा 50 ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इनका खर्च अलग है। आज प्रदेश में जो गठबन्धन सरकार चला रहा है, उसमें कई ऐसे दल शामिल हैं जिनमे कोई विधायक नहीं हैं सारे के सारे मंत्री रोजाना ढाई लाख रुपया जेब खर्च में उड़ा देते हैं यह जेब खर्च वे सरकारी खजाने से ले रहे हैं। उस खजाने से जिसमें प्रदेश की आम जनता का पैसा जमा होता है।

भाजपा सत्ता मे बनी रही, इसकी बहुत भारी कीमत प्रदेश की जनता को चुकानी पड़ी रही है। नतीजा यह हो रहा है कि प्रदेश सरकार पर

कर्ज का भारी बोझ लदता जा रहा है। आज प्रदेश सरकार पर पूरे 88 हजार करोड़ का कर्ज है। 31 मार्च 1999 को यह 56 हजार करोड़ था लेकिन यानी इन तीन सालों में कर्ज में 32 हजार करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई है। प्रदेश सरकार का 95 फीसदी खर्च ऐसी मदों पर हो रहा है जो अनुत्पादक मदें कहलाती हैं। यानी जिनसे प्रदेश के और उसके लोगों के विकास में कोई मदद नही मिलती। केवल 5 प्रतिशत खर्च ही उत्पादक कामों में लगा है।

प्रदेश की हालत बिहार जैसी–

सौ मंत्रियों की फौज वाली यह सरकार खुद तो कमजोर है ही, प्रदेश को भी कमजोर कर रही है। अभी दो महीने पहले तक के आकडे बताते हैं कि पूरे देश में करीब साढ़े चार करोड़ बेराजगार युवा है। इनमे से 70 फीसदी शिक्षित बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं, जिनकी संख्या करीब 80 लाख है। यह केवल वे वेरोजगार हैं जिन्होने नौकरी के लिये अपनी पंजीकरण कराया हुआ है। इसके अलावा न जाने कितने ग्रामीण युवा बेरोजगार घूम रहे हैं।

प्रदेश में गरीबी की सीमा–रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या बराबर बढ़ रही हैं। वास्तव में प्रदेश में दो वर्गों की ही संख्या बढ़ रही है। सरकार में मंत्रियों की और शहरों–गांवो में गरीबों की आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर 100 में 38 लोग ऐसे हैं, जिन्हें गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदेश मे दो करोड़ 5 लाख लोग गरीब कहलाने लायक भी नही हैं। वे उससे भी नीचे की श्रेणी में हैं।

पूँजी निवेश के मामले मे 18 प्रमुख राज्यों मे उत्तर प्रदेश सोलहवें नम्बर पर हैं सामाजिक सेक्टर के विकास यानी शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य जैसे कार्यकमों के मामले में भी अपना प्रदेश 18 में से 14 नम्बर पर है। हाल मे कराये गये एक विस्तृत सर्वेक्षण से यह बाता उभरकर सामने आई है कि जहॉ तक सम्पन्नता का सवाल है अपने प्रदेश 17वें नम्बर पर हैं बिहार से वह जरा सा ही आगे है। सर्वेक्षण राजीव गाँधी इन्स्टीट्यूट फॉर कन्टेम्पेरेरी स्टडीज ने भारतीय उद्योग संघ के लिए किया है।

कानून व्यवस्था :

जिस प्रदेश में अपराधी तत्व सरकार में मंत्री हो। उनका काम अपहरण कराकर फिरौती लेना हो, उसमें कानून व्यवस्था की सहज ही कल्पना की जा सकती है। संघ परिवार के लोग ,खुद अयोध्या के विवादित स्थल पर जबरन घुस जाते हों, उसमें कानून व्यवस्था के हालत खराब नही होगे तो और क्या होगा?

कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल किसी ने न तो कभी देखा था। और न ही सुना था। भाजपा के ही एक नेता की, जिसे मत्री का दर्जा प्राप्त था, कानपुर देहात में एक पुलिस थाने के अन्दर हत्या कर दी गयी। जिस सरकार के राज में पुलिस थाने ही असुरक्षित हो, उसमें कानून व्यवस्था के हालात बताने की क्या कुछ जरूरत है। यहाँ मंत्री तक अपनी जान थाने के अन्दर घुसकर भी नहीं बचा सकते तो आम आदमी की बात क्या की जाय?

उपरोक्त सर्वेक्षण के दौरान यह बात उभरकर सामने आयी कानून व्यवस्था के मामलें में भी देश के 18 राज्यों में से अपना प्रदेश 17वें नम्बर पर है। बस बिहार थोडा सा नीचे इससे है। वरना यह प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में असम राज्य से भी पीछे है।

एक तरफ उत्तर प्रदेश को बी0 जे0 पी0 के कुशासन ने पूरी तरह चौपट कर दिया है दूसरी तरफ निर्धारित अवधि से ज्यादा समय तक सत्ता का सुख भोगने के बाद भी येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहने की साजिश चल रही है। भाजपा नेतृत्व उत्तर प्रदेश का चुनाव टालने के लिये सीमा पर युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है। जबकि सारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात के खिलाफ है। जब सरकार को कार्यवाहीं करनी चाहिए थी तब उन्होंने अवसर गँवा दिये। लेकिन भाजपा को देश के हित से भी ऊपर पार्टी हित नजर आता है और पार्टी हित के लिए भाजपाई कुछ भी कर सकते है। कारगिल यूद्ध के बाद भी उत्तर प्रदेश की बुद्धिमान जनता ने भाजपा को करारी शिकस्त दी थी। भाजपा चाहे जो षडयंत्र करे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने से रोक नहीं सकेगी।

साथियों, पूरा देश और खासकर उत्तर प्रदेश बेहद खतरनाक साजिशो का शिकार बनाया जा रहा है। इसमें भाजपा और उसके सहयोगी दलो का हाथ है। उनके लिये चुनाव जीवन–मरण का प्रश्न है तो हमारे लिये भी साम्प्रदायिकता को रोकना, अल्पसंख्यकों, किसानों, नौजवानों और समाज के वंचित लोगों की रक्षा करना हमारी जिन्दगी और मौत का सवाल बन गया है। इस गम्भीर आर्थिक संकट के समय चुनाव हो रहे हैं और मै अपने नौजवानों,युवाओं महिलाओं तथा कार्यकारिणी के सभी साथियों का आह्वान करता हूँ कि अगले चुनाव में भाजपा और उनके साथियों को हटाना उनके कारनामों को आम लोगों तक पहुँचाना और उनके हमलो का सामना करना एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। साम्प्रदायिकता को रोकना राष्ट्र सेवा है। इसके लिये कुछ भी बलिदान करने के लिये तैयार रहना चाहिए। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो हम दोनों मोर्चों पर काम करेगे । आतंकवाद से लडने के लिये लोगों को तैयार भी करेंगे और सरकार के संरक्षण में खडी साम्प्रदायिक ताकतों को रोकने का काम करेंगें । प्रदेश की जनता तैयार है। देश भर हुए पिछले चुनाव में भाजपा हारी। राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र जैसे गढों में भाजपा हार चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी इस बार समाजवादी पार्टी से उसकी हार तय है। हमें यह संकल्प शक्ति जगानी है इस अधिवेशन से इस अभियान को पूरा करना है।[9]

राजनैतिक प्रस्ताव–

आजादी की लड़ाई के गर्भ से समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ। रूस की क्रान्ति और वामपन्थी विचारों से प्रभावित नौजवानों ने सन् 1934 में पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया जो कांग्रेश संगठन के अन्तर्गत ही काम करता था क्योंकि आजादी की लड़ाई का कांग्रेस ही सबसे बडा मंच था। किसानों, नौजवानों और मजदूरो का संगठन बनाकर देश व्यापी संषर्ष छेडा गया। समाजवादी विचारों, कार्यक्रमों और संषर्षो के कारण कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण और जनाधार बढ़ा। समाजवादियो का महत्व भी बड़ा।

---

9 - समाजवादी पाटी का पाचवा राष्ट्रीय सम्मेलन कानपुर मे, तीन जनवरी 2002 को दिया गया अध्यक्षीय भाषण

1942 के आन्दोलन का नेतृत्व समाजवादियों ने किया और जब एक तरफ डा0 लोहिया आजाद रेडियो के जरिये आन्दोलन चला रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जेल की दीवार फांदकर जयप्रकाश नारायण जी अपने कुछ साथियो के साथ निकले और डा0 लोहिया तथा जयप्रकाश नारायण इस संघर्ष मे एक साथ हो गये। इन लोगों ने आन्दोलन को नयी गति दी। आजादी के बाद देश का बंटवारा हुआ। डा0 लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेन्द्र देव ने कहा है कि गांधी जी की चुप्पी और हम समाजवादियों का निष्क्रिय विरोध देश के विभाजन को रोक नहीं पाया। सन् 1948 में काग्रेस से अलग समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। परिस्थितियों के कारण समाजवादी पार्टी का किसान मजदूर पार्टी से एका हो गया और तभी से सिद्धान्तो का विचलन शुरू हुआ। जनता पार्टी बनने के बाद तो समाजवादी सिद्धान्तों और लक्ष्यो से हम दूर चने गये क्योंकि जनता पार्टी का लक्ष्य कांग्रेस को हटाकर सत्ता हासिल करना था। पहले सरकार बनी और बाद में पार्टी। इसलिए सिद्धान्तों के प्रति कोई आग्रह नहीं था। बिना सिद्धान्त के सत्ता न तो टिकाऊ होती है और न ही परिवर्तनकारी। इसका नतीजा यह जरूर हुआ कि समाजवादी पार्टी का सगठन और आन्दोलन छिन्न–भिन्न हो गया। लोंगो में जबर्दस्त हताशा हुई। सन् 1992 के अन्त मे माननीय मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी गठित कर जोखिम उठाया। आज हम यहां सपा के पांचवे राष्ट्रीय सम्मेलन में मील रहे है।

आज भरत अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर में है। विखटनकारी शक्तियां देश की आन्तरिक एकता को चुनौती दे रही हैं, पडोसी देशों से मधुर सम्बन्ध इतिहास का शिष्य हो गया है। राजनैतिक और प्रशासकीय भ्रष्टाचार सीमा लांघ चुका है। दुश्मन देशों के समक्ष भारत घुटनाटेक हालत में है, किसान, मजदूर, बुनकर, छात्र, नौजवान, छोटे व्यापारी और मध्यम उद्योगपति तबाही की मार झेल रहे हैं। देशी–विदेशी कर्जो के बोझ से देश की कमर टूट रही है, देश की बडी विपक्षी पार्टी कांग्रेस से आर्थिक नीतियों मे सहयोग लेकर भाजपा के नेतृत्व में भाजपा गठबंधन सरकार इस देश की कृषि, उद्योग सभी कुछ नष्ट कर भारत की सम्पूर्ण व्यवस्था को विश्व की महान पूंजीवादी व्यवस्था के सुपुर्द कर रही है।

समाजवादी पार्टी आर्थिक और समाजिक गैर बराबरी के विरूद्ध बराबर संघर्ष करती रही है। हरिजन, आदिवासी, महिला, पिछडे एव मुसलमानो को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने और जीवन के हर क्षेत्र मे आगे बढाने की पक्षधर रही है। मण्डल कमीशन की सिफरिशों को सबसे पहले ईमानदारी से मुलायम सिंह यादव ने ही अपने मुख्यमंत्रित्व काल मे लागू किया और गरीब सवर्णों को भी आरक्षण देने की पेशकश की।

आजादी के बाद भारत आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक खतरे के चौराहे पर खडा है। भूमण्डलीकरण, निजीकरण, बाजारीकरण और उदारीकरण की नीतियों को भाजपा सरकार द्वारा अपनाये जाने के कारण देश मे गरीबी, गैर बराबरी एवं बेरोजगारी बढ़ी है और इसी के साथ–साथ धर्मान्धता, आतंकवाद और अपराध भी बढे हैं। इस समय तो युद्ध के बादल मडरा रहे हैं। सभी गरीब एवं विकासशील देश अमेरिका और महाशक्तियो के उपनिवेश बनते जा रहे हैं और उनकी सत्ता और नीतियॉ उन्हीं द्वारा संचालित होती हैं। इस समय दुनियॉ में आर्थिक साम्राज्यवाद पनप रहा है। इन नीतियो के फलस्वरूप हमारी आजादी और सम्प्रभुता भी खतरे में है। अभी हाल की घटनाओं में अमेरिकी बमबारी, यूरोपीय देशों की एकजुटता अैर अफगानिस्तान के सत्ता परिवर्तन ने अमेरिकी प्रभाव, शक्ति एवं वर्चस्व को प्रमाणित किया है और आज वे विश्व व्यवस्था के नियन्ता बन गये हैं। आतंकवाद के विरूद्ध छेडे गये विश्वव्यापी अभियान मे दुनियां से आतंकवाद समाप्त करने की अपेक्षा यूरोपीय देशों के हित एवं बदले की भावना सर्वोपरि है। व्यापक लक्ष्य और समग्र दृष्टि का आभाव है। जिस प्रकार से हथियारों की होड मची हुयी है, हथियारों और मादक पदार्थों का व्यापार खुले रूप से फल–फूल रहा है तथा दूसरे देशों में आतंकवाद एवं अपराधिक कृत्यों से सरकारों को अस्थिर बनाने का दौर चल रहा है, इसके चलते आतंकवाद को समाप्त करने और युद्ध को रोकने की इमानदारी नहीं दिखायी पडती।

स्वतन्त्र, सृजनात्मक एवं तटस्थ विदेश नीति चलाने में वर्तमान सरकार विफल रही है और अमेरिका की पिछलग्गू बन गयी है। हम अपनी पहल खोते जा रहे हैं और इसलिये दूनियां से भी हमारे कोई मित्र नही रहा। हमारी कूटनीतिक विफलता भी इसका कारण है। पड़ोसी देशों से भी हमारे रिश्ते

अच्छे नही हैं, जबकि हमें उनका नेतृत्व करना चाहिए था। पाकिस्तान से तो रिस्ते बराबर विगड़ते ही जा रहे हैं और अब तो युद्ध की स्थिति बन गयी है। सरकार की पाकिस्तान के सम्बन्ध में कभी कोई ठोस एव दीर्घकालिक नीति नहीं रही है। दृष्टि और लक्ष्य का भी अभाव है।

लालकिला, जम्मू–कश्मीर की विधान सभा तथा संसद भवन पर आतंकवादी–आत्मघाती हमला बर्बर और जघन्य है। सम्मेलन इसकी घोर निन्दा करता है और इसे भारत और लोकतन्त्र पर हमला मानता है। इसलिये इस संकट के दौर में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय एकता और आजादी की रक्षा के लिए उठाए गये कदम के साथ एकजुटता प्रदर्शित करती है। लेकिन इसके लिये यह बहुत जरूरी है कि शासक दल या गठबधन अपनी नीयत और नीतियों को बदले और उनके संगठनों द्वारा चलाये जा रहे आतंकवाद पर सख्ती से अंकुश लगाये। क्योंकि यह संम्मेलन मानता है कि बाहरी आतकवाद आन्तरिक आतंकवाद से खाद पाकर पनपता और उग्र रूप धारण करता है।

आज दुनियां राजनीतिक दृष्टि से तीन हिस्सों मे बंटी है। विकसित, विकासशील एवं अति पिछड़े देश हैं। विकसित देश इन अति पिछडे देशो की सही मायने में कोई मदद नहीं करते और धर्मान्धता बढ रही है तथा राजनीति में भी विकृतियां आ रही हैं। समाजवादी पार्टी इन विकृतियों को समाप्त करना चाहती है।

पिछले दो वर्षो में भारत की वर्तमान सरकार ने देश के संकट को और बढाया है। संविधान के बुनियादी ढांचें के साथ छेड–छाड, इतिहास को बदलने व बिगड़ाने तथा शिक्षा के भगवाकरण की नीति, देश मे संघ परिवार के विचारों को मूर्त रूप देने की साजिस है। यह सरकार भूमण्डलीकरण की नीतियों के दर्शन पर ही शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थनीति चला रही है, जिसमें केवल आबादी के एक तिहाई हिस्से का ही हित ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि वे ही बाजार का हिस्सा बनते है। मुफ्त या सस्ती और समान शिक्षा एवं चिकित्सा शेष दो तिहाई आबादी के निए असम्भव हो गये हैं।

अयोध्या में राम मन्दिर के विवादित गर्भ में जबरन प्रवेश, बार–बार मन्दिर निर्माण की घोषणा, ताज महल परिसर को विकृत करने की कोशिश तथा विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल एवं युवा मोर्चा के क्रिया कलापो से

हिन्दू एजेण्डे को जिन्दा रख रही है। इस सरकार की दृष्टी सोच एवं आचरण साम्प्रदायिक है। गांधी जी की हत्या से लेकर बाबरी मस्जिद के ध्वस और राम मन्दिर निर्माण की बात ये सभी इसी साम्प्रदायिक सोच के नतीजे हैं।

भजपा गठबंधन का वर्तमान शासन भ्रष्टतम शासन साबित हो चुका है। रक्षा सौदा में उच्चतम स्तर के भ्रष्टाचार देश की सुरक्षा के लिए जबर्दस्त खतरा है। तहलका डॉट कॉम ने ऊंचें स्तर के भष्ट्राचार को साफ तौर से उजागर कर दिया है। सेना द्वारा कराई गयी जांच ने 'तहलका' द्वारा नामित सेना के अधिकारियों को दोषी पाया है लेकिन सरकार आयोग गठित कर जांच कराने से मामले को खींचले जाने की कोशिश कर रही है। ऊपरी स्तर के भ्रष्टाचार ने पूरे देश में निचले स्तर तक पहुंचा दिया है। रिश्वतखोरी, भाई–भतीजावाद से देश की जनता त्राहि–त्राहि कर रही है। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट के खुलासे के बाद तो यह सरकार कफन चोरो की सरकार साबित हुई है। कारगिल की लडाई में भारत के सपूतों के शहीद हो जाने पर उनके पार्थिव शरीर को लाने ले जाने के लिए जो कांफीन (अर्थिया) खरीदी गयी उनके तथा अन्य सैन्य समानों मे करोडों रूपये की हेरा–फेरी ने देश को हतप्रद्र कर दिया है। भ्रष्टाचार को एक नया आयाम देते हुए आज भी यह सरकार विरोधी दलों के सांसदों को घूस और लालच देकर दल–बदल कराके सभी नैतिक मानदण्डों को तिलाजंलि देने में जुटी है और इसके निशाने पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी है।

इतिहास बदलने की दृष्टि को रखते हुए पाठ्य–पुस्तकों में परिवर्तन किया जा रहा है। संघ की विचारधारा हिन्दू र्धम को सवोत्कृष्ट धर्म मानती है। साथ ही धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को अल्पसंख्यकों के पक्ष में मानती है। जबकी यह बात जगजाहिर है कि और स्वंय सिद्ध है कि भारतीय संस्कृति और इतिहास उदारता, बहुलता, विविधता तथा सर्वधर्म समभाव का हामी और पोषक रहा है। इसके साथ ही पाठ्य–पुस्तकों में नैतिकता के पाठ के नाम पर पोंगापंथी, कट्टरवादी तथा असहिष्णु विचारों के विष को बालकों के दिमाग में बिठाना चाहती है। नैंतिक शिक्षा को धर्म से जोड़ना संकीर्ण एवं प्रतिक्रया वादी कदम है दुनिया के सभी धर्मों, सम्प्रदायों में नैतिकता और अच्छे आचरण

की सीख मिलती है, पर केवल एक विशेष धर्म से जोडना एक प्रतिगामी एव संकीर्ण सोच का परिणाम है

समाजवादी पार्टी शिक्षा में ऐसे विष तत्वो के लाए जाने वाले कदम की निन्दा करती है और इसका डटकर विरोध करने का निश्चय करती है। भारती जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजपार्टी आदि पार्टियां यथास्थिति वादी एवं सडन की पार्टियां है समाजवादी पार्टी का उनसे मौलिक सैद्धान्तिक मतभेद है समाजवादी पार्टी समाजवाद में विश्वास करती है। केवल समाजवादी विचार ही आज दुनिया के सभी शोषित एवं दलित लोगों के लिए आदर्श विचार है

समाजवादी पार्टी का लक्ष्य केवल सरकार बनाना ही नही बल्कि लाखों बेरोजगार युवकों को रोजगार की गारण्टी देना भी है क्यों कि पार्टी का विश्वास है कि गरीबी से बेरोजगारी पैदा नही होती बल्कि बेरोजगारी से गरीबी पैदा होती है इसलिए अगर गरीबी को हटाना है तो बेरोजगारी हटानी होगी समाजवादी पार्टी का यह राष्ट्रीय सम्मेलन पार्टी के कार्यकर्ताओ का आह्वान करता है कि सरकार के किसान, मजदूर, व्यापारी, अल्पसख्यक, दलित एवं पिछड़ो कि विरोधी मानसिकता का पर्दाफाश करे तथा आने वाले चुनाव मे समाजवादी पार्टी का परचम लहराने का काम करें।[10]

आर्थिक प्रस्ताव –: समाजवादी पार्टी के पांचवे राष्ट्रीय सम्मेलन कानपुर में जो आर्थिक प्रस्ताव पारित हुआ वह इस प्रकार है–

समाजवादी पार्टी का यह राष्ट्रीय सम्मेलन देश की निरन्तर बिगड़ती आर्थिक हालत पर चिन्ता प्रकट करता है। समाजवादी पार्टी याद दिलाना चाहती है कि गुलामी के दिनों में भी भारत की गणना एक समृद्ध देश के रूप में होती थी। इस देश का कपडा, दस्तकारी, चीनी व लघु उद्योग आधारित सामान उपयोग में आने वाली वस्तुओं की विश्व बाजार में पूछ थी। अंग्रेजी साम्राज्य शाही ने प्रथम प्रहार इस देश की दस्तकारी और हाथ से तैयार होने वाने कपड़े पर किया। धीरे–धीरे भारत की विश्व व्यापार मे साझेदारी कम होने लगी। भारत विश्व व्यापार की प्रमुख संस्था गैट के संसथपक देशो में एक था। विगत शताब्दी के अन्तिम दशक में जो साम्राज्यवादी और पूँजीवादी का

---

10 - समाजवादी पार्टी के 'पाचवा राष्ट्रीय सम्मेलन' कानपुर मे 4 जनवरी 2002 को पारित राजनैतिक प्रस्ताव

अन्तिम चरण था उस दौर मे पूँजीवाद—साम्राज्यवाद के विकल्प के रूप मे आई सोवियत पद्धति की मार्क्सवादी व केन्द्रीभूत लोकशाही का भी पतन होने लगा। पूँजीवाद अपने नये कलेवर में उदारवाद, भूमण्डलीकरण आदि नारों के साथ विश्व व्यापार संगठन बनाया गया और उसके छतरी तले विश्व के सभी विकसित, अर्द्धविकसित, विकासमान और गरीब देशो को लाकर "सह नौ भुनक्तु" के नारे के साथ विश्व के सभी ससाधनों पर कब्जा जमा और लूट की व्यवस्था चलाते रहने का अभियान शुरू हुआ। समाजवादी आन्दोलन के कोख में जन्मे नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय पूँजीवाद के इस मरिच रूप को ठीक से पहचाना तथा देश और विश्व की जनता को सजग और सावधान करने के लिये फिर से समाजवादी आंदोलन को पुनर्जीवित किया।

समाजवादी पार्टी इस बात को गम्भीरता पूर्वक नोट करती हे कि भूमण्डलीकरण की व्यवसथ लागू होने के 10 वर्ष के भीतर विश्व की एक तिहाई जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे चली गयी अर्थात 1 डालर प्रतिदिन की आमदनी पर गुजर बसर करने वालों की संख्या दो अरब हो गयी है। नई अर्थव्यवस्था के ध्वज वाहकों ने 10 वर्ष की समीक्षा के बाद पाया कि सर्वाधिक गरीब लोगों की टोली दक्षिण एशिया में बसती है और अकेले भारत में 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे है। वास्तविकता यह है कि यह संख्या इससे बहुत ज्यादा है। 'अल्टरनेटिव इकोनोमिक सर्वे' के अनुसार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन—यापन करने वालों की संख्या भारत में लगभग 75 करोड़ है। 20 करोड़ लोग तो घोर निर्धनता और अभाव की जिन्दगी जीने को विवश हैं। उस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के दरिद्रतम देश नाइजीरिया और बंगलादेश हैं। इस विश्व बाजार व्यवस्था का यूरोपीय देशों ने सीधी रणनीति के तहत इस्तेमान किया चूँकि 19वीं शताब्दी के साम्राज्यवादी युग में दुनियाँ की दौलत को लूटकर अपने को दौलतमंद बनाने का उनका पुराना अभ्यास था। इसलिये उन्होंने तत्काल यूरोपीय व्यापार संघ मजबूत किया। अब तो अपनी सभी मुद्राएं खत्म कर एक मुद्रा यूरो के माध्यम से काम चलाने लगे, आपस में वीजा की व्यवसथ खत्म की, जर्मनी का एकीकरण कराया और रेल, सड़क, वायु मार्ग ऐक कर लिया। 19वीं सताब्दी के विश्व लुटेरे विश्व बाजार की लूट का मजा

उडाये थे। फिर उनकी अर्थव्यवस्था चमक उठी। गरीब मुल्को की कीमत पर फिर से वे अमेरिका, जापान, चीन से टक्कर लेने को तैयार है। 10 वर्ष की नई व्यवस्था के बाद देशो को तरक्की के मामले मे रेटिंग हुई है। इसके अनुसार फिनलैण्ड विश्व का नम्बर एक धनी देश उसने अमेरिका को दो पर कर दिया, नार्वे, स्वीडन, जर्मनी इनकी अर्थव्यस्था उछाल मार रही है और एशिया का आर्थिक रिमौर्य कहा जाने वाला जापान का 21 वे स्थान पर अर्थव्यवस्था लडखड़ाने लगी। विश्व का दो नम्बर का दानी सिंगापुर 4 के स्थान पर, मलेशिया 24वें से 30वें स्थान पर और आबादी के हिसाब से विश्व का दूसरा बड़ा देश भारत 48वें स्थान से गिरकर अब 57वे नम्बर पर है, केवल वैज्ञानिक और इंजीनियर की दृष्टि से भारत का 4वॉ स्थान था। आज यूरोप के देश अपने देश के कृषि उत्पादन पर प्रति हेक्टेयर 40000 रूपये की इतनी सब्सिडी दे रहे हैं जा अफीकी देशों के वार्षिक बजट के बराबर है विश्व व्यापार सगठन यूरोप एवं अमेरिका द्वारा अपने कृषि की सब्सिडी खत्म या कम नहीं कर रहा है लेकिन हमारी सरकार कृषि पर से सब्सिडी खत्म करती जा रही है। फलस्वरूप सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश कहने वाला भारत विश्व खाद्यान्न व्यापार में मात्र 1 प्रतिशत साझेदारी रखता है। समाजवादी पार्टी सम्पूर्ण विश्व व खास तौर से भारतीय जन को नई भूमण्डलीकरण की व्यवस्था से फिर एक बार सावधान करना चाहती है। विदेशी कम्पनियॉ हमारे देश में उद्योंग–व्यापार एवं खेती पर कब्जा करती जा रही है। कारगिल कम्पनी नमक तथा अन्य वस्तुओं पर वर्चस्व बढ़ा रही है। मेकडोवल कम्पनी होटल व्यवसाय को कब्जा रही है तथा मोसांटो कम्पनी कपास की खेती तथा अन्य अनेक विदेशी कम्पनियों ने भारत में देशी उद्योग, व्यवसाय एवं व्यापार पर धावा बोल कर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है।

समाजवादी पार्टी का सम्मेलन घोर निन्दा करती है कि भाजपा ने कॉंग्रेस से सौ कदम आगे बढ़कर नई अर्थनीति को स्वीकार कर लिया है और भारत के धरातल की कठिनाइयों को समझे बिना लूट का अर्थतंत्र देश में लाद दिया है। इस नई अर्थनीति से भारत में बेकारी बढ़ती जा रही है। और अन्न की कम होती खपत ने देश के आर्थिक ढाँचे को तोड़कर रख दिया है। आज भी सरकार और योजनाओं का जोर उदारीकरण की प्रक्रिया को तेज

करने पर आयोग के नये दस्तावेज कहते हैं कि भारत के गोदामो मे अनाज सड़ने का कारण जनता के खानपान में बदलाव है। अब जनता दूध, अण्डे, फल खाने लगी, इसलिये अन्न की खपत कम है और उत्पादन ज्यादा है। अत प्रधानमंत्री भी कहते हैं देश मे भुखमरी की खबरें मीडिया तंत्र द्वारा फैलाया गया झूठ है। देश के किसान अन्न उपजाना बंद कर फल–फूल की खेती करें घुटनाटेक नेतृत्व और पूँजीवाद के जरखरीद गुलाम भारतीय अफसर इस देश को खुली ऑख से देखना नही चाहते। देश में दुर्भिक्ष, अकाल और बढती बेकारों की फौज ने देश की बहुसंख्यक आबादी को कंगाल बना दिया है। लगभग 30 करोड़ लोगों को एक वक्त का भोजन जुटाना कठिन है। अन्न खरीदने की उनकी सामर्थ्य समाप्त है। देश के समाजवादी देश की गरीब, बेरोजगार कंगाल जनता से एकजुट होकर जनता के इन दुश्मनो को तत्काल गद्दी से उतारने का आह्वान करती है।

भारत की निरन्तर प्रति व्यक्ति आमदनी गिर रही है। देश की तरक्की की रफ्तार 5 प्रतिशत कैद है जबकि पड़ौसी देश चीन की हमसे अधिक आबादी के बावजूद पिछले 20 वर्षो से 7 फीसदी के हिसाब से बढ रही है। उसका प्रमुख कारण है कि उसने अपने देश की कृषि सुधार पर बल दिया। कृषि क्षेत्र इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आजादी के समय देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 50 प्रतिशत था। सन् 1970 में घटकर 44 प्रतिशत रह गया था और 2000 मे केवल 24 प्रतिशत। आजादी के समय भी कृषि क्षैत्र पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या देश की जनसंख्या के 76 प्रतिशत थी और आज भी लगभग उतनी ही है। लेकिन देश के कुल उत्पाद मे उसकी भागीदारी घटकर आधी से भी कम रह गयी है। किसानों की तबाही का इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है। नई अर्थव्यवस्था आने के बाद सारा सरकारी जोर औद्योगीकरण पर रहा, परिणामतः न उद्योग बढा न खेती। समाजवादी पार्टी इस बात को समझती है कि खेती ही सबसे अधिक रोजगार पैदा करती है। विगत दो वर्षों में खाद्यान्न की उपज 10 लाख टन के हिसाब से कम हो रही है। खाद की खपत में कमी, खेती लायक जमीन में कमी, किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य न मीलना, विश्व की खाद्यान्न व्यापारिक संस्थाओं का भारत में जबरन प्रवेश आदि ऐसे कारण हैं, जिससे खेती और

उससे जुडी गतिविधियॉ कम होती जा रही है। खेती के बाद का जो उसी से जुड़ा क्षेत्र है, कपडा तथा लघु उद्योगो जिसमें सबसे अधिक लोग काम मे लगे थे, आज 403 कपडा मीलें बंद हो गयीं तथा कई लाख लघु इकाइया बद हो गयीं । चीन की खेती तथा लघु उद्योग की भारी उन्नति के हमले के शिकार दक्षिण एशिया के गरीब देश ही होंगे, भारत उससे सबसे अधिक प्रभावित होगा— जो अभी से देश के बाजार में दृष्टिगोचर हो रहा है।

भारत सरकार ने गत वर्ष लगभग हर क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिये हैं। इससे हमारे देशी उद्योग धन्धो तथा उससे जुड़े करोड़ों लोगों का भविष्य पूरी तरह अन्धकारमय हो गया है। विदेशी कम्पनियों ने हमारे बाजारें को, विदेशी गाय—मॉस, सुअर—मॉस, अण्डा, गेहूँ, बाजरा, चावल, तेल, दूध, मक्खन और तरह—तरह के अन्य खाने के तथा अय्याशी के सामानों से पाट दिया है। पश्चिमी पूॅजीवादी उपभोक्ता सस्कृति हमारी आर्थिक रीढ़ को तोड़कर सांस्कृतिक विरासत को भी नष्ट—भ्रष्ट करने पर आमादा है और यह सब हो रहा है राष्ट्रवाद एवं भारतीय संस्कृति के तथाकथित ठेकेदारों की सरकार के रहते, उसके सक्रिय सहयोग एवं सहमति से।

भारत में विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बेरोक—टोक प्रवेश से देश के 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत लोग तो तड़क —भडक की दुनियॉ का मजा ले सकेंगे, लेकिन आने वाले दिनों मे देश के 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग अभाव एवं गरीबी का जीवन जीने को लाचार एवं विवश होंगे।

वर्तमान सरकार की जन विरोधी गतिविधियॉ यहीं तक सीमित नही हैं। अब वह तेजी से डिसइन्वेस्टमेन्ट मंत्रालय बनाकर सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीय महत्व के उपक्रमों को औने—पौंने दामों पर बेच रही है। देश के उपलब्ध प्रतिष्ठित संस्थानों के शेयर विदेशी कम्पनियों को कम रेट पर बेचकर उनमें हमारी भागीदारी को निर्णायक स्तर तक घटाकर बेचने की तैयारी है। ओ0 एन0 जी0 सी0 जैसे लाभ में चल रहे निगम के शेयर बहुत बडी सख्या में कम दाम पर विदेशी कम्पनियों को बेच दिये हैं। अरबों रूपयों की सम्पत्ति जो विभिन्न संस्थानों एवं कल—कारखानों के रूप में है, देशी विदेशी कम्पनियों को कौड़ी के मोल में बेचा जा रहा है। मार्डन फूड एवं बालको जैसी लाभ पर

चलने वाली कम्पनियों को मिटटी के मोल निजी कम्पनियों को बेच दिया जा रहा है। आई0 टी0 डी0 सी0 के अनेक होटलो को मिटटी के मोल बेच दिया जा रहा है। इन सौदो में सैकडों करोड रूपयें के कमीशन की बात लोगो की जुबान पर है। स्टील ऑफ इण्डिया को भी बेचने की तैयारी है। उदारीकरण, भूमण्डलीकरण, बाजारीकरण एवं निजीकरण के नाम पर भाजपा सरकार द्वारा देश को बेचने एवं देश के आत्म–सम्मान को गिरवी रखने का काम बेशर्मी के साथ किया जा रहा है।

समाजवादी पार्टी को इस बात खेद है कि सबसे अधिक स्वदेशी और स्वावलम्बन का राग अलापने वाली भाजपा के राज में देशी विदेशी कर्ज बढ़ा है। देश पर आन्तरिक कर्ज का बोझ 10 लाख करोड़ के आस–पास और विदेशी कर्ज लगभग 5 लाख करोड है। भाजपा सरकार के आने के बाद सम्पूर्ण कर्ज तीन वर्ष मे दूना हुआ है। हमारे बजट का 45 प्रतिशत कर्ज अदायगी में जा रहा है। केन्द्रीय सरकार प्रांतीय सरकार के सम्मिलित जो और इनकी गारण्टी पर मीले कर्जो को जोड दिया जाय तो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 85 प्रतिशत है। इस तरह सम्पूर्ण देश की अर्थव्यस्था कर्ज के बोझ से दबकर मरने वाली है। सरकार के ठाट–बाट, शान–शौकत, फिजूलखर्ची भी उसी प्रकार से बढ़ रही है। सभी पडोसी देशो के साथ कटुतापूर्ण सबधों के नाते रक्षा का बजट हर साल बढाना पड़ रहा है। देश में निरक्षरता, बीमारी, लाचारी बढ़ रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में व्यय करने के नियें निरन्तर पैसों का आभाव है। देश की तरक्की की बुनियाद रेल, सड़क, वायु, मार्ग, विजली इसके स्थान नये संसाधनों के आभाव में हम निरन्तर अधोगति की ओर जा रहे हैं।

समाजवादी पार्टी इन सभी चीजो का विकल्प स्वदेशी, स्वावलम्बन और समाजवादी अर्थ तंत्र को मानती है। देश की तरक्की में सभी की समान साझेदारी, सभी को उत्पादन करने के अवसर और साधन दिये बिना इस देश अथवा विश्व का कल्याण संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन समाजवादी समाज की रचना के लिये अपने को समर्पित करते हुए देश के शासकों को आगाह करता है कि उन्होंने शीघ्र आँखें नहीं खोली तो पूरा देश अराजकता, लूट, मारकाट में सराबोर हो जाएगा। देश की बेरोजगार और लाचार जनता खुले रूप से सामने आकर पूरी व्यवस्था को भंग करने के लिये

विवश होगी। देश के कुछ हिस्सों में बढ रही हिसक घटनाए इसका संकेत दे रही हैं।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन की यह राय है कि देश को बचाने भाजपा शासन से मुक्ति दिलाना परम आवश्यक है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये यह सम्मेलन कार्यकर्ताओ का आह्वान करता है कि घर–घर जाकर भाजपा के काले–कारनामों का पर्दाफाश करे और "करो का मरो" की भावना से चुनावी महासमर में कूदने का काम करें।[11]

11 _ सपा के 'पाचवे राष्ट्रीय सम्मेलन' कानपुर मे 4 जनवरी 2002 को पारित आर्थिक प्रस्ताव।[11]

निष्कर्ष

भारत मे तो समाजवाद किसी न किसी रुप मे बहुत पहले से ही विद्यमान हैं, वैदिक ग्रन्थो मे जिस प्रकार से सभी प्राणियो की सहज समानता, स्वतन्त्रता तथा बन्धुत्व की भावना को उजागर किया गया है उससे सहज ही उसका अनुमान लगाया जा सकता हैं। बौध ग्रन्थ तथा महाभारत मे इसके सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार कहा जा सकता हैं कि भारती ग्रन्थो मे समाजवादी विचारो के मूलतत्व विद्यमान थे लेकिन अर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के दर्शन के रुप मे समाजवाद भारत मे पाश्चात्य प्रभाव के फलस्वरुप ही विकसित और लोकप्रिय हुआ।

समाजवाद की वर्तमान विचारधारा तो 19वी शताब्दी मे विकसित हुई। सन्1807 राबर्ट ओवेन के अनुयायियो के लिए अंग्रेजी भाषा मे समाजवादी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। 19वी शताब्दी की औद्योगिक क्रान्ति तथा पूजीवाद ने समाज मे इतनी अधिक विषमता पैदा कर दी कि उसी के प्रतिक्रिया स्वरुप समाजवाद की विचारधारा पैदा हुई इस प्रकार समाजवाद की विचारधारा भी अपने आप मे एक प्रतिक्रियात्मक विचारधारा है। बीसवी शताब्दी मे विश्व के राजनीतिक और सामाजिक चिन्तन को सबसे अधिक समाजवादी विचारधारा ने ही प्रभावित किया है। वर्तमान में तो समाजवाद एक प्रभावशाली आन्दोलन तथा एक क्रान्तिकारी सिद्धान्त के रुप मे गतिमान है। समाजवाद को सही रुप मे स्पष्ट करना एक कठिन कार्य है क्योंकि विभिन्न विद्वानो ने अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार समाजवाद की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। अरस्तू से लेकर महात्मा गाधी तक ने समाजवाद के विषय मे भिन्न विचार व्यक्त किये हैं।

19वीं शताब्दी के आरम्भ में समाजवादी विचारो का जो विकास इंग्लैण्ड और फ्रास मे तीव्रगति से हुआ वह कोई स्थाई परिणाम के बिना ही 19वी शताब्दी के मध्य मे ही कुछ समय के लिए स्थिर हो गयी। इसके बाद इस विचारधारा का विकास जर्मनी मे बहुत तीव्रगति से हुआ क्योकि वहाँ के समाज संगठन का ढांचा परम्परावादी सामन्तवादी व कुलीन तंत्री आधार पर संगठित था। इस विचारधारा के विकास मे पूर्व के विचारको ने काफी सहयोग दिया।

कार्ल मार्क्स से पूर्व का समाजवाद काल्पनिक समाजवाद कहा जाता हैं, क्योकि वह इतिहास के किसी दर्शन पर आधारति नही था। समाजवादी विचारधारा को वैज्ञानिक स्वरुप प्रदान करने मे कार्ल मार्क्स और एंगेल्स का काफी योगदान रहा हैं। मानव समाज की नवीन

व्याख्या उसके द्वारा ही की गयी मार्क्स ने किसी नवीन विचार का प्रतिपादन नही किया बल्कि पूर्व सिद्धान्तो का प्रवर्तक था। उसे श्रमिको का मसीहा और उसके ग्रन्थ 'दास कैपिटल' को आधुनिक बाइबिल कहा जाता है। मार्क्स ने ऐंगेल्स के साथ मिलकर समाजवाद के वैज्ञानिक सिद्धान्त का प्रतिपादन करके आधुनिक रुप प्रदान किया। मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक इसलिए कहा गया है कि उसने एक ऐसा आन्दोलन चलाया जिसका एक निश्चित सिद्धान्त था और उस समय चल रहे निराधार समाजवादी आन्दोलन को एक आधार प्रदान किया। उसके पूर्व जो समाजवादी विचारधाराएं थी, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से उन पर धार्मिक अथवा भौतिक प्रभाव अवश्य था। जब समाजवाद वैज्ञानिक रुप मे सामने आया तब जनता धार्मिक-विश्वासो से विमुख होने लगी थी, मार्क्सवादी विचारधारा के विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दिया।

भारत मे समाजवाद का विकास राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि पर हुआ जिन प्रारम्भिक चिन्तकों ने राष्ट्रवादी भूमि तैयार करने मे प्रमुख भूमिका अदा की उसमे राजाराम मोहनराय दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द और रामकृष्ण परमंहस के नाम उल्लेखनीय है।

दयानन्द सरस्वती मूलत· एक समाज सुधारक थे किन्तु उनके विचारों मे समाजवादी धारण और दर्शन के प्रमुख बिन्दु मिलते हैं।

विवेकानन्द भारत मे पहले एसे विचारक थे जिन्होने भारतीय इतिहास की समाजशास्त्रीय दृष्टि से यथार्थवादी व्याख्या की। उन्होने जो भारत की व्याख्या की वह स्वरुप मे अंशतः मार्क्सवादी भी है, किन्तु वह उनके अपने ढग की मार्क्सवादी है। ऐसा कोई प्रमाण नही है कि उन्होने दास कैपिटल अथवा साम्यवादी घोषणा पत्र पढ़ी थी। स्वामी विवेकानन्द उस अर्थ मे समाजवादी नही थे जिस अर्थ मे हम आधुनिक किसी राजनीति दार्शनिक को समाजवादी कहते हैं। उनकी दृष्टि मे समाजवादी कोई एकदम निर्दोष या आदर्श व्यवस्था नही थी।

1920 से 1947 ई0 तक भारतीय राजनीतिक युग गाँधी युग कहलाता है। महात्मा गाँधी ने 1920 ई0 मे भारतीय राजनीति मे प्रवेश किया और उन्होने राष्ट्रीय आन्दोलन एव काग्रेस की नीतियो को एक नई दिशा प्रदान की। गाँधी जी की समाजवादी कल्पना का मूल आधार नैतिक है उनका समाजवाद मानवीय समाजवाद है जो वैज्ञानिक समाजवाद से भिन्न है उनके समाजवाद मे वर्ग सघ की हिंसात्मक क्रान्ति और औद्योगिकरण का गौण स्थान है। वे समाजवाद की स्थापना के लिए सत्य, प्रेम, अहिंसा, सत्याग्रह ग्रामोद्धार, पुनर्मिाण एवं ट्रस्टिशिप आदि बातो को विशेष महत्व देते है।

पं0 जवाहर लाल नेहरु को कांग्रेसी नेताओ मे प्रमुख समाजवादी के रुप मे स्वीकार किया जाता है विद्यार्थी जीवन मे वे इंग्लैण्ड मे फेबियनवादी समाजवाद के सम्पर्क मे आये तथापि मूलत राष्ट्रवादी ही रहे। 1927 ई0 मे नेहरु जी द्वारा रुस की यात्रा की और वहाँ साम्यवादियो की उपलब्धियो को प्रत्यक्षत देखा तभी से उनके अन्दर समाजवाद के प्रति रुचि बढ़ने लगी। नेहरु जी के समाजवादी चिन्तन का क्रमबद्ध विकास सन् 1929 के लाहौर (अधिवेशन से प्रारम्भ होता है,) जिसमे कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किया। अध्यक्षीय भाषण मे उन्होने स्वीकार किया कि मै एक समाजवादी और लोकतन्त्रवादी हूँ। उन्होने समाजवाद और राष्ट्रवाद मे समन्वय स्थापित किया। समाजवाद के मुद्दे पर उनका गाँधी के अतिरिक्त नरेन्द्र देव, जय प्रकाश नारायण, सुभाष चन्द्र बोस, डा0 राजेन्द्र प्रसाद, बल्लभ भाई पटेल, एम0 एन0 राय आदि नेताओ से उनका वैचारिक मतभेद हुआ। स्वाधीनता के बाद भी नेहरु जी की समाजवादी चिन्तन मे प्रजातान्त्रिक समाजवाद की झलक दिखाई पड़ता है।

आचार्य नरेन्द्र देव समाजवाद के प्रारम्भिक चिन्तको मे से थे बीसवी शताब्दी के प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात जब समाजवादी विचारो का हमारे देश में विकास होने लगा नरेन्द्र देव ने इसे न केवल स्वीकार किया वरन् आगे बढ़ाने में भी अग्रणी रहे।

भारतीय समाजवाद के प्रणेताओ मे डा0 राम मनोहल लोहिया को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। वे एक लड़ाकू व्यक्तित्व वाले प्रखर समाजवादी माने जाते हैं। जर्मनी मे उन्हे समाजवाद की प्रेरणता प्राप्त हुई जब वे बर्लिन विश्वविद्यालय मे 'नमक और सत्याग्रह' पर शोध कर रहे थे। बाद मे वहॉ से पी0 एच0 डी0 की उपाधि ग्रहण की। उन्होने स्वयं लिख कि सबसे बडा प्रश्न यह उठता है कि भारत का समाजवादी आन्दोलन अपने पैरो पर भी खड़ा हो सकता है। या उसे सदैव दक्षिण या वामपंथी वैशाखियों की जरुरत पड़ती रहेगी।

डा0 लोहिया ने सर्वप्रथम अपने समाजवादी विचारों का प्रतिपादन एक सम्पादक के रुप मे किया उन्होने लिखा कि "समाजवादियो को साम्यवादियो या उदारवादियो के साथ मित्रता के संबंध रखने चाहिए। केवल इसी तरह विश्वभर मे और भारत मे एक सहज और सृजनात्मक समाजवाद की रचना होगी। द्वितीय विश्व युद्ध मे डा0 लोहिया ने अपना एक चार सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रबल विरोध किया। भारत के अन्य समाजवादियो के समान लोहिया भी मार्क्सवाद से प्रभावित हुए। उन्होने कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक

समाजवाद का महान व्याख्याकार माना है। उन्होने मार्क्स के पूंजी संचय संबधी सिद्धान्त, पूंजीवादी एकाधिकार तथा श्रम के समाजीकरण को स्वीकार किया और उसके वर्ग सघर्ष तथा विश्व क्रान्ति को मान्यता नही दी। लोहिया मार्क्सवाद के बारे मे विचार करके भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढ़ालने के पक्षधर रहे हैं। लोहिया ने भारतीय परिस्थितियो के अनुकूल एक नया समाजवादी चिन्तन विकसित करने का प्रयास किया। उनके समाजवादी चिन्तन के मौलिक आधार मे क्रान्तिकरण, सात क्रान्तियां, चौखम्भा योजना, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, जातिप्रथा उन्मूलन, नारी समस्या, साम्प्रदायिकता आदि सामाजिक प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त किये।

सम्पूर्णानन्द की गणना काग्रेस समाजवादी दल के सस्थापको मे की जाती है वे भारतीय सस्कृति के आदर्श से अनुप्रेरित होने के कारण मार्क्सवाद और लेनिनवाद को स्वीकार नहीं किये। उनके ऊपर गांधीवाद का गहरा प्रभाव था। वे गाँधीवाद और साम्यवाद मे समन्वय स्थापित करने के इच्छुक थे उनके चिन्तन मे समाजवाद के स्थान पर सर्वोदय शब्द अधिक उपयुक्त लगता था। उनके अनुसार समाजवाद केवल मात्र शोषण का अन्त करने का एक राजनीतिक या आर्थिक चिन्तन नही है, वरन वह तो मानव के सम्पूर्ण जीवन की दृष्टि है। लोकतंत्र में उनका दृढ़ विश्वास था।उनके अनुसार लोकतंत्र और समाजवाद के अतिरिक्त कोई विकल्प ही नही है। उन्होने डा0 लोहिया के विचार से सहमति रखते हुए कहा कि "समाजवाद न आने पर फासीवाद आयेगा या साम्यवाद अनेक विद्वानो ने सम्पूर्णानन्द के समाजवादी चिन्तन को वेदान्ती समाजवादी सज्ञा दी है।

अशोक मेहता ने सामाजिक लोकतत्र और लोकतान्त्रिक समाजवाद को भारतीय समाजवाद का आधार बनाया। वे पूंजीवाद को एक बुराई के रुप मे स्वीकार करते थें उनका आर्थिक चिन्तन काफी समृद्ध था। वे आर्थिक क्रान्ति के प्रवर्तक थे और उसे वे जीवन की पुर्नव्यवस्था की सज्ञा देते थे।

जय प्रकाश नारायण की मार्क्सवाद में पूर्ण आस्था थी। जे0 पी0 ने समाजवाद के सम्बन्ध में कहा था कि समाजवाद केवल एक रुप है, एक सिद्धान्त है और वह मार्क्सवाद है। जे0 पी0 के ऊपर गाँधी जी के व्यक्तिवाद का काफी प्रभाव पड़ा। जे0 पी0 ने वर्ग सघर्ष की अनिवार्यता को स्वीकार्य करते हुए युवा वर्ग का आह्वान किया कि वह हरिजनों एवं भूमिहीनों को वर्ग के आधार पर संगठित करने का बीड़ा उठाये। इस विचार से यह ध्वनि निकलती है कि उनकी

विचारधारा एक नये दौर से गुजरी है। जय प्रकाश नारायण ने वर्गो के प्रादुर्भाव मे सामाजिक विषमता को आर्थिक तत्व से संबद्ध किया है आर्थिक तत्व वर्ग अभ्युदय के लिए केवल पूर्ण रुपेण केवल उत्तरदायी नही हो सकता।

वर्ग अभ्युदय के सबध मे डॉ0 लोहिया एव जे0 पी0 मे काफी साम्यता है।जे0 पी0 गॉंधी के मार्ग पर चलकर देश मे राजनीतिक, सामाजिक एव आर्थिक-सास्कृतिक परिवर्तन लाना चाहते थे। इसी कारण उन्होने 'सम्पूर्ण क्रान्ति' का नारा दिया सम्पूर्ण क्रान्ति जे0 पी0 का अपना मौलिक विचार नही है, जे0 पी0 की सम्पूर्ण क्रान्ति मे वे सभी पहलू शामिल है। जिसकी कल्पना डा0 लोहिया ने सप्तक्रान्ति के रुप में की थी।

इस देश मे 1885 से लेकर देश के स्वतन्त्र होने से पूर्व तक काग्रेस पार्टी का एक छात्र आधिपत्य था। उसी के नेतृत्व मे इस मूल्क मे कई आन्दोलनो का संचालन भी किया गया। जब कांग्रेस पार्टी मे गॉंधी, पटेल नेहरु तथा सुभाष चन्द्रबोस का पदार्पण हुआ। तब देश की स्थिति मे भी काफी बदलाव आ गया था।

सन् 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा हिन्दू महासभा का गठन किया गया। लेकिन इसमे सभी लोगो एव सगठनो का अपनी-अपनी सोच एव विचारधाराएं थी लेकिन कही न कहीं 1848 के साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रभाव पड़ा। भारत मे 1922 से 1939 तक समाजवादी अन्दोलन काफी तीव्र रहा है। इसके पीछे भी साम्यवादी धारणा काम कर रही थी।

काग्रेस के अन्दर भी कई प्रकार के सोचवाले लोग मौजूद थे। किन्तु दक्षिणपंथी सोच हावी थी। इसी के परिणाम स्वरुप प्रगतिशील एव समाजवादी नेताओ मे अधिकारिक नेतृत्व दक्षिणपंथ की नीतियो एवं कार्यवाहियों के विरुद्ध असंतोष बढ़ता गया। सर्वप्रथम कांग्रेस की गैर प्रगतिशील एवं कठमुल्लावादी नीति के विरोध में बिहार मे कुछ कांग्रेसियो ने 1931 मे समाजवादी संघ की स्थापना की पुन· अखिल भारतीय स्तर पर समाजवादी दल बनायें समाजवादी विचार को आगे बढ़ाने के बारे मे गतिविधियॉं तेज हो गयी। इसी का परिणम हुआ कि मई 1934 मे पटना मे आचार्य नरेन्द्र देव जी की अध्यक्षता में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गयी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के निर्माण में जिन नेताओ का सक्रिय सहयोग रहा उसमे जय प्रकाश नारायण अशोक मेहता, आचार्य नरेन्द्र देव, डॉ0 राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, एम0 आर0 मसानी, एन0 जी0 गोरे, एस0 एम0 जोशी, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसूफ मेहर अली, गंगाशरण

सिंह तथा कमला चटोपाध्याय आदि थे। बाद मे अन्य कांग्रेसी और अन्य विचारधारा से सम्बद्ध नेताओ ने इसकी सदस्यता ग्रहण की। पं0 जवाहर लाल नेहरु और सुभाष चन्द्र बोस ने भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी की नीतियों का समर्थन करते थे, लेकिन इससे सक्रिय रुप से सम्बद्ध नही हो पाये थे। गाँधी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सदैव विरोधी रहे क्योकि उनके लिए वर्ग संघर्ष सदैव असहमति का विषय ही बना रहा।

यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि काग्रेस समाजवादी पार्टी की इच्छा तो थी कि कांग्रेस की नीतियों में परिवर्तन आये। किन्तु उससे सम्बद्ध रहकर ही कांग्रेस समाजवादी अपनी गति विधियो को संचालित करना चाहते थे वे लोग कांग्रेस की बुनियादी नितियो को बनाये रखना चाहते थे, तथा कांग्रेस को समाजवादी मूल्यों से आबद्ध भी करना चाहते थे। कांग्रेस समाजवादी वैज्ञानिक समाजवाद के स्थान पर कांग्रेस की नीतियो मे समाजवादी सुधार के लिए कृत संकल्प थे। पार्टी की नीतियाँ सदस्यो के पूर्वाग्रह से ग्रसित थी। इसलिए पार्टी अन्त तक सार्वजनिक, शाश्वत, मौलिक व नीतियो तथा कार्यक्रमों के निर्धारण में असफल रही। प्रमुख रुप से जिन राजनीतिक विचारधाराओं का उसमें प्रतिनिधित्व था उसमें मार्क्सवादी और समाजवादी फेबियन विचारधारा, तथा उदारवादी समाजवादी विचारधारा थीं वे पार्टी के अन्दर अपनी-अपनी विचारधाराओं को स्थापित करना चाहते थे। और लगातार राजनीतिक मतभेद बने रहे। इसी मतभेद के चलते अशोक मेहता, डा0 लोहिया तथा अच्युत पटवर्धन जैसे नेताओ ने पार्टी की कार्यकारिणी से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान इन घटकों मे इतने अधिक मतभेद बढ़ गये कि आगे एक साथ बने रहना असम्भव हो गया और अन्ततः सभी घटक बिखर गये।

कांग्रेस समाजवादी पार्टी अस्तित्व 1934 से 1947 तक बना रहा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी कभी भी वैज्ञानिक समाजवाद के दृष्टिकोंण को अपनाने का प्रयास नही किया, व्यवहारिक रुप में तने बिल्कुल ही नही। युवा आन्दोलन के नेतृत्व पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने सकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया।

कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना निश्चय ही वामपंथी विचारधारा से प्रभावित होने कारण हुई और इस बात को हमेशा ध्यान में रखा गया कि कांग्रेस के बाहर उसका न तो कोई अस्तित्व है और न ही वह चेष्टा करेगी। जब तक पार्टी का अस्तित्व रहा वह किसी भी हालत में काग्रेस को छोड़ने को तैयार नही थी। इसका परिणाम था पार्टी हर मोर्चे पर असफल रही। कांग्रेस

समाजवादी पार्टी की असफलता और पतन काफी सीमा तक वापपंथी दलो से उसके सबधों के कारण भी हुई दक्षिणपंथी तत्व उसे सन्देह की दृष्टि से देखते थे तथा वामपथी दल उसे वैज्ञानिक समाजवाद से अत्याधिक दूर मानते थे।

कांग्रेस संविधान संशोधन के बाद स्वतन्त्र कांग्रेस समाजवाद पार्टी का निर्माण हुआ। नासिक सम्मेलन 1949 मे आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता मे हुआ। नासिक सम्मेलन में पार्टी के स्वरुप, संगठन और उसकी रीति-नीति के संबंध में विचार विमर्श किया गया।

1952 में लोक सभा चुनाव मे समाजवादी पार्टी कांग्रेस से अलग स्वतंत्र रुपसे चुनाव लड़ी थी। 1952 के चुनाव मे जनता मे वामपंथी प्रवृत्ति को देखकर उन्होने 1955 के समाजवादी सामाजिक ढांचे की चर्चा करना शुरु कर दिया था। संसद मे भी एक प्रस्ताव पास समाजवाद के लक्ष्य को स्वीकार किया गया। और बाद मे संविधान के प्रस्तावना मे भी 'समाजवाद' शब्द को जोड़ा गया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1955 मे पारित प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी के सहयोग के मुद्दे पर विचार उभर गया। इस हद तक गया कि अन्ततः पार्टी विभाजन के कगार पर पहुँच गयी। क्योकि मधुलिमये डा0 मनोहर लोहिया तथा उनके सहयोगियों को पार्टी से निकाल दिया गया। इसलिए डा0 लोहिया ने दिस0 1955 मे अलग से समाजवादी पार्टी की घोषण कर दी। परिणाम यह हुआ कि 1962 के आम चुनाव प्रजा समाजवादी पार्टी तथा समाजवादी पार्टी दोनो को नुकसान हुआ और आम जन मानस मे एक गलत संदेश गया। इसमे दोनों ही पर्टियों ने अपनी कमजोरियों को चिन्हित किया।

डा0 लोहिया ने 1964 में पुनः अशोक मेहता के कांग्रेस मे चले जाने के बाद समाजवादी एकता का प्रस्ताव रखा।इसके बाद संयुक्त समाजवादी दल का निर्माण हुआ। इसलिए समाजवादी आन्दोलन का दूसरा दौर 1964 से 1974 तक रहा और यह दौर घटना प्रधान भी रहा।

1974 के अगस्त महीने में चौ0 चरण सिंह के नेतृत्व मे भारतीय लोकदल की स्थापना हुई। इसमे भारतीय क्रान्ति दल (बी0 के0 डी0), स्वतंत्र पार्टी राष्ट्रीय लोक तान्त्रिक दल, संसोपा, उत्कल कांग्रेस, किसान मजदूर पार्टी, राष्ट्रीय लोक तान्त्रिकदल और पंजाब खेतिहर जमींदार सभा शामिल हुई।

इसके बाद समाजवादी आन्दोलन का अगला दौर 1974 से 1977 तक रहा। इसके अन्तर्गत इंदिरा गाँधी की कांग्रेस सरकार द्वारा पूरे देश मे आपातकालीन स्थिति लागू कर दी गयी और विरोधी नेताओ को गिरफ्तार कर जेल मे बन्द कर दिया गया पुनः आपात कालीन समाप्ति के बाद 1977 मे आम चुनाव की घोषणा कर दी गयी। कांग्रेस के विकल्प के रुप में जनता पार्टी का गठन हुआ। 1977 के आम चुनाव मे पूर्ण बहुमत भी मिला तथा जनता पार्टी की सरकार बन गयी। सरकार मे कई विचारधारा के लोग शमिल थे। इस कारण ज्यादा दिनो तक यह सरकार नही चल पायी। इसके बाद जनता पार्टी सरकार में अन्तर्विरोध अधिक बढ़ गये तथा सरकार गिर गयी।

1980 के आम चुनाव में कांग्रेस (आई) कांग्रेस (यू) तथा लोकदल जिसे चरण सिंह तथा समाजवादियो ने खड़ा किया था। जनता पार्टी जिसमें मूलरुप से जनसंघ और जगजीवन राम एवं चन्द्रशेखर जैसे कुछ कांग्रेसी बचे हुए थे तथा सी0 पी0 आई0 और सी0 पी0 एम0। जनता पार्टी की शासन विहीनता, दूरदर्शिता का अभाव तथा लगातार चलने वाले आपसी झगड़ो से उबकर लोग एक बार फिर कांग्रेस की ओर इन्दिरा की तरफ देखने लगे।

31 अक्टूबर 1984 को इन्दिरा गाँधी की हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गाँधी को प्रधानमंत्री बनाया गया तथा समय से पहले 24 से 27 दिसम्बर 1984 मे आम चुनाव कराया गया। उसमें कांग्रेस को अब तक का सबसे बड़ा बहुमत मिला।

1989 मे राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी। इस चुनाव मे भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रुप मे उभर कर आयी। भाजपा तथा वापथी पार्टियो ने राष्ट्रीय मोर्चा को बाहर से समर्थन की घोषणा की।इसके साथ ही साथ कई प्रान्तों में भी जनता दल की सरकार बनी। केन्द्र मे ऐसे लोग भी शामिल थे जो आते महत्वाकांक्षी थे। इसमें अन्यदलों से आये लोग ही इस केन्द्र में थे तथा प्रभावी भी थें लेकिन यह सरकार भी अपने अन्तर्कलह से उबर नहीं पायी थी तथा मण्डल कमीशन लागू किये जाने के पर भाजपा अपना समर्थन वापस ले लिया तथा सरकार अल्पमत मे आ गयी।

निष्कर्ष रुप मे यह कहा जा सकता है कि 1934 से लेकर 1991 तक समाजवादी विचारधरा एवं आन्दोलन उतार-चढाव के दौर से गुजरा है। जिन समाजवादी अवधारणाओं को

लेकर इसका गठन हुआ था, यह अपने मुकाम तक नहीं जा सका है। और सीधा-सीधा इसका कारण समाजवादियो का बिखराव रहा है।

1977 से 1990 का दौर दिशाहीन एवं नेतृत्व विहीन रहा है घटक दल के रुप मे जरुर अस्तित्व रहा है लेकिन विचारधारा एवं दिशा के स्तर पर लुप्त प्राय रहा है। जनता पार्टी के गठन के समय उसमे जब समाजवादी पार्टी अपने को विलीन कर दी कही न कही वह एक गलत फैसला था। क्योंकि व्यवहार मे ये बात साबित हो चुकी हैं

वर्तमान स्थिति पर यदि दृष्टि डाली जाय तो अजीब स्थिति पैदा हो गयी है। बहुत से ऐसे दल है जो अपने को लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी होने का दावा तो करते है लेकिन व्यवहार मे कुछ अलग ही तथा केन्द्र और कई प्रदेशो मे भाजपा के साथ मिलकर सरकार भी चला रहे है। जो कि विशुद्ध रुप से एक साम्प्रदायिक दल है। क्यो वह हमेशा विवादास्पद मुद्दो जैस धारा 370 की समाप्ति, कामन सिविल कोड, अयोध्या, मथुरा तथा काशी समेत कई मुद्दों को उठा रही है। 1992 के बाद से देश मे साम्प्रदायकि माहौल बढ़ गया है लेकिन तथा कथित समाजवादी उन्ही ताकतों को मजबूत कर रहे हैं।

दूसरी और एक बार पुनः लगभग 18 साल की शून्यता के बाद श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में नवम्बर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन किया गया। यह पार्टी डा0 राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेन्द्र देव तथा चौधरी चरण सिंह के सपनों को लेकर आगे बढ़ने के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ है। इस देश मे एक बार पुनः समाजवादी मूल्यों को स्थापित करने तथा समाजवादी आन्दोलन का पुनर्गठन करने का प्रयास कर रही है। इस पार्टी की दिशा तो ठीक है किन्तु बहुत सी संभावनाए अभी भविष्य के गर्त में है। यदि इस पार्टी का नेतृत्व पिछले पचास वर्ष के समाजवादी आन्दोलन उसके संगठन कार्यशैली एवं बिखराव के कारणों का अध्यक्ष कर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो पार्टी को मजबूती प्रदान होने की पूरा सम्भावनाएं है यदि ऐसा नही किया गया तो पिछले इतिहास के दौहराने की स्थितियां भी बलवान्‍ बनी रहेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
हिन्दी की पुस्तकें

क्रम	लेखक	पुस्तक का नाम	प्रकाशन
1	डॉ0 राम मनोहर लोहिया	समाजवादी आन्दोलन का इतिहास	समता विद्यालय न्यास प्रकाशन, 1969
2	वही,	समाजवादी एकता	समाजवादी प्रकाशन हैदराबाद
3	वही,	क्रान्तिकरण लोहिया साहित्य, 17	नव हिन्द प्रकाशन हैदराबाद, 1967
4	वही,	धर्म पर एक दृष्टि	वही, 1966
5	वही,	भाषा	वही,1964
6	वही,	कचन मुक्ति	वही, 1956
7.	वही,	निजी और साहित्य क्षेत्र, 14	वही, 1966
8	वही,	जाति प्रथा	वही, 1964
9	वही,	समाजवाद की अर्थनीति	प्रथम संस्करण वही,1968
10	वही,	समाजवादी एकता	लोहिया साहित्य,1
11	वही,	हिन्दू और मुसलमान	समता विद्यालय न्यास प्रकाशन, 1964
12	वही,	सिविल नाफरमानी सिद्धान्त और अमल	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी प्रकाशन, हैदराबाद, 1960
13	वही,	सात क्रान्तियॉ, लोहिया साहित्य, 19	वही, 1966
14.	वही,	भारत-चीन व उत्तरी सीमाएँ	नव हिन्द प्रकाशन हैदराबाद, 1963
15	ओम प्रकाश केलकर (स0)	राम मनोहर लोहिया जीवन और दर्शन	चेतन साहित्य प्रकाशन, फैजाबाद, 1968
16.	डॉ0 एस0 एल0 वर्मा	राजनीतिक चिन्तन	मिनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 1999
17	हरिभाऊ उपाध्याय	गॉधीवादी समाजवाद	हिन्दी प्रकाशन, इलाहाबद, 1953
18.	बी0 बी0 रमन मूर्ति	गाँधी इसोन्शियल राइटिंगस	गॉधी पीठ फाउन्डेशन, नई दिल्ली, 1970

19	सी0 ई0 एम0 जोड़	आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त प्रवेशिका (स0 अम्बादत्त पंत)	आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बम्बई, कलक्ता, मद्रास-1957
20	स्वामी दया नन्द सरस्वती	सत्यार्थ प्रकाश	सावर्देशिक प्रकाशन
21	डा0 शोभाशकर	आधुनिक भारतीय	लिमिटेड, दरियागज, नई दिल्ली-1972
22	पट्टाभि सीता रमैया	काग्रेस का इतिहास, प्रथम तीन खण्ड	सस्ता साहित्य मंडल नई दिल्ली-1946
23	रामधारी सिह 'दिनकर'	सस्कृत के चार अध्याय	लोक भारतीय प्रकाशन एम0 जी0 मार्ग, इलाहाबाद-1999
24	रामवृक्ष वेनीपुरी	जय प्रकाश की विचारधारा	बेनीपुरी प्रकाशन, मुजफ्पुर, 1967
25	आचार्य नरेन्द्र देव	राष्ट्रीयता और समाजवाद	प्रथम संस्करण सन् 1949, तृतीयज्ञान मण्डल, वाराणसी ज्ञ 1973
26	वही	समाजवाद का मूल आधार और कार्य	पद्मा पब्लिकेशन, बम्बई, 1946
27	इन्दुमति केलकर	लोहिया-सिद्धान्त और कर्म	नव हिन्द प्रकाशन हैदराबाद, 1963
28	अध्यक्ष माओत्से तुग की विचारोक्तिया		विचार प्रकाशन, कानपुर, 1967
29.	अध्यक्ष माओत्से तुग	चुनी हुई कृतियॉ	चार खण्ड, विचार प्रकाशन, कानपुर, 1969
30	ओकार शरद	लोहिया	राजरंजना प्रकाशन इलाहाबाद, 1967
31	ओकार शरद (स0)	लोहिया के विचार	लोकभारती, इलाहाबाद 1969
32.	कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक ऐंगेल्स	स्वतत्रता सग्राम	नई दिल्ली, 1963
33	कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक ऐंगेल्स	कम्यूनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र	वही, 1974
34.	कार्ल मार्क्स	पूँजी, तीन खण्ड	प्रगति प्रकाशन, मास्को
35	कोकर	आधुनिक राजनीतिक चिन्तन	आगरा, 1960

36	गॉधी, मोहन दास करमचन्द	गॉधी-आत्मकथा	वही, 1970
37	जवाहरलाल नेहरु	मेरी कहानी	सस्ता साहित्य मण्डल नई दिल्ली, 1965
38	वही,	कुछ पुरानी चिटिठया	वही, 1960
39	वही,	विश्व इतिहास की झलक, दो खण्ड	वही, 1974
40	जय प्रकाश नारायण	जय प्रकाश नारायण के विचार (स0)	लोकभारती, इलाहाबाद, 1977
41	महादेव प्रसाद वर्मा	आधुनिक राजनीति के विभिन्न वाद	चैतन्य पब्लि0 हाउस, इलाहाबाद , 1965
42	रजनी पामदत्त	आज का भारत	मैकमिलन, नई दिल्ली, 1977
43	ब्ला0 ई0 लेनिन	सकलित रचनाएँ, चार खण्ड	प्रगति प्रकाशन, मास्को-1969
44	वही	साम्राज्यवाद पूँजीवाद की चरम अवस्था	विदेशीप्रकाशन गृह, मास्को।
45	वी0 अफनास्येव	मार्क्सवादी दर्शन	वही, 1972
46	डॉ0 वि0 प्रसाद वर्मा	पाश्चात्य राजनीतिक विचारधारा का इतिहास	हिन्दी समिति लखनऊ, 1964
47	शोभा शकर	आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन	साहित्य भवन, इलाहाबाद, 1960
48	सम्पूर्णानन्द	समाजवाद	भारतीय ज्ञानपीठ, कलकत्ता, 1964
49	डॉ0 रघुवंश	"जय प्रकाश नारायण के विचार"	लोकतत्र प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम सस्करण 1977
50.	प्रो0 यशपाल	"मार्क्सवाद"	विप्लव प्रकाशन, लखनऊ, 1976
51.	राय, डॉ0 सत्या एम0	"भारत मे उपनिवेश वाद ' और राष्ट्रवाद"	हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली-2000

52	डॉ0 आर0 पी0 त्रिपाठी	मुलायम सिह यादव रचना और सघर्ष	प्रथम सस्करण 1993 डॉ0 लोहिया ट्रस्ट लखनऊ द्वारा प्रकाशित
53	लक्ष्मी कांत वर्मा	समाजवादी आन्दोलन लोहिया के बाद	प्रकाशक, अतुल बगाई, निदेशक सूचना और जनसंचार विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश प्रथम सस्करण मार्च 1995
54	रजनी कांत वर्मा	समाजवादी पार्टी ही क्यो	समाजवादी पार्टी के सिद्धान्त वक्तव्य एवं कार्यक्रम

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

अंग्रजी की पुस्तके

क्रम	लेखक का नाम	पुस्तक का नाम	प्रकाशन
1.	डॉ0 राम मनोहर लोहिया	आस्पेक्ट्स आफ सोशलिस्ट पार्टी	बम्बई, 6 दुलच रोड
2	जय प्रकाश नारायण	सोशलिज्म, सर्वोदय एण्ड डेमोक्रेसी	एशिया पब्लि0, बम्बई, 1964
3.	वही,	टुवर्डस टोटल रेवोल्यूशन	पॉपुलर प्रकाशन पदमा पब्लिकेशन
4	वही,	डेमोक्रेटिक सोशलिज्म	सोशलिस्ट पार्टी
5	डॉ0 राम मनोहर	लोहिया मार्क्स, गॉधी एण्ड सोशलिज्म हैदराबाद,	नव हिन्द प्रकाशन हैदराबाद, 1933
6	वही,	विल टू पावर एण्ड अदर राइटिंग्स	वही, 1956
7	जय प्रकाश नारायण	टुवर्डस न्यू सोसाइटी	दि आफिस आफ इण्डियन अफेयर्स, दिल्ली, 1958
8	वही,	टुवर्डस स्ट्रगल (स0 यूसूफ मेहर अली)	पदमा पब्लि0 बम्बई, 1946
9.	वही,	ह्वाई सोशलिज्म	अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी, वाराणसी, 1936
10	जी0 डी0 एच0 कोल	ए हिस्ट्री आफ सोशलिस्ट थाट 5 वल्यूम	लन्दन, 1953-57
11	वही,	सोशल थ्योरी	न्यूयार्क, 1920
12	वही,	सोशल थाट-दि फोर रनर्स फोर रनर्स	मैकमिलन, लन्दन, 1953
13	जी0 एस0 भार्गव	लीडर्स आफ दि लेफ्ट	मेहरअली बुक क्लब, बम्बई, 1951
14.	एल0 पी0 सिन्हा	दि लेफ्ट विंग्स इन इण्डिया	न्यू पब्लि0 मुजफ्फरपुर, 1965
15.	पं0 जवाहर लाल नेहरू	गिल्मिस ऑफ दि वर्ड हिस्ट्री	लदन, लिन्डसे ड्रूरुमड ,1938
16	वही,	एन् आटोबायोग्राफी	एलाइडष पब्लिशर्स, बम्बई, 1962
17	वही,	दि यूनिटी आफ इण्डिया	लदन, लिन्डसे ड्रूरुमड सोवियत रसिया, ला

18	वही,	नेहरु आन सोशलिज्म	जनरल प्रेस इलाहाबाद पर्सपेक्टिव पब्लि0 1954
19	जे0 बी0 कृपलानी	क्लास स्ट्रगल	काशी, ए0 बी0 एस0 एस0 एस0 प्रकाशन, 1959
20	डोरोथी नार्मन (स0)	नेहरु दि फस्ट सिक्सटी इयर्स	एशिया पब्लि0 बम्बई, 1965
21	जी0 डी0 तेदलुकर	महात्मा (गॉधी),8 खण्ड	बम्बई , 1961
22	राय अखिलेन्द्र प्रसाद	सोशिलिस्ट थाट इन मार्डन इण्डिया	मिनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 1975
23	अशोक मेहता	डेमोक्रेटिक सोशलिज्म	भारतीय विद्या भवन, बम्बई, 1954
24	वही,	इक्लोनामिक प्लानिग इन इण्डिया	यग इण्डिया, नई दिल्ली, 1970
25	वही,	सोशलिज्म एण्ड गॉधीज्म	बम्बई, 1935
26	दि सेमीनार आन सोशलिज्म (स0)		नेहरु मेमोरियल लाइब्रेरी, नई दिल्ली, 1970
27	दि कम्पलीट वर्क्स आफ स्वामी विवेकान्द, 8 व्ल्यूम		अल्मोड़ा, अद्वैत आश्रम
28	नरेन्द्र देव	सोशलिज्म एण्ड दि नेशनल रेवोल्यूशन	पदमा पब्लि बम्बई, 1947
29	वी0 डी0 कौशिक	दि काग्रेस आइ डियोलोजी एण्ड प्रोग्राम	अलाइड पब्लिशर्स, बम्बई, 1964
30	प्रेम भसीन	सोशलिज्म इन इण्डिया	यग एशिया प0, नई दिल्ली, 1969
31	वी0 आर0 पुरोहित	हिन्दू रिवाइवलिज्म	साथी, सागर
32	बर्नाड शा	एसेज इन फेबियन सोशलिज्म	कान्सटेवन, लन्दन 1949
33	भगवानदास	एन्सीएन्ट वर्सेज माडर्न साइन्टीफिक सोशलिज्म	मद्रास, 1910
34	मधुलिमये	ह्वाई सयुक्त सोशलिस्ट	पॉपुलर प्रकाशन बम्बई
35.	मित्रा, एम0 एन0 (स0)	इण्डियन एनुअल रजिस्टर (1919-1947)	कलकत्ता
36	माइकेल ब्रेचर	नेहरु ए पोलिटिकल बायोग्राफी	आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन, 1959

37	सुभाष चन्द्र बोस	दि इण्डियन स्ट्रगल	एशिया पब्लि0 बम्बई, 1964
38	एम0 एन0 मित्रा (स0)	इण्डियन एनुअल रजिस्टर	कलकत्ता ,द एनुअल रजिस्टर आफिस
39	वी0 पी0 वर्मा	पोलिटिकल फिलासफी आफ गॉधी एण्ड सर्वोदय	आगरा, 1981
40	मीनू मसानी	दि कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया	डेरेक वर्सो, वायल लदन, 1954
41	जी0 एस0 भागर्व	लीडर्स आफ दि लेफ्ट	मैहर अली बुक क्लब बम्बई, 1951
42	बनार्ड शा	एसेज इन फेबियन सोशलिस्ट	पॉपुलर प्रकाशन, नई कलकत्ता
43	लेनिन	ए0 बायो ग्राफी	प्रगति प्रकाशन, मास्को 1969
44	वही,	मटीरियालिज्म एण्ड इम्पीरिओक्रटिसज्म	वही, पृष्ठ 1940
45.	लैडलर, हैरी	हिस्ट्री आफ सोशलिज्म	राउटलेज, 1968
46	वी0 पी0 रमनमूर्ति (स0)	इण्डियन एनुअल रजिस्टर (1919-1947)	कलक्ता
47	शकर घोष	सोशलिज्म एण्ड कम्मुनिज्म इन इण्डिया	कलक्त्ता, 1971 एलाइट पब्लि0
48	वही,	सलेक्टैड वर्क्स आफ माओत्से तुग	नवजातक, कलकत्ता, 1973
49.	एम0 गॉधी	कैपिटल एण्ड लेबर	भारतीय विद्याभवन बम्बई, 1970
50.	वही	रिकन्स्ट्रक्शन	वही, पृष्ठ 1956
51.	मधु दडवते	एवोल्यूशन ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसीज एड पर्स पेक्टिव 1934-1984	बम्बई, 1986
52	हरि किशोर सिह	ए हिस्ट्री ऑफ द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी	लखनऊ, 1959
53	हेरी डब्ल्यू 0 लैडलर	हिस्ट्री आफ सोशलिज्म	स्लेज कीगेनपाल, लन्दन, 1961
54	वही,	सोश एण्ड एक्नामिक मूवमेन्ट्स	
55	लाल, मुकुट बिहारी	ब्लू प्रिन्ट आफ ए डेमोक्रेटिक प्रोग्राम	तारा प्रिंटिंग वर्क्स, वाराणसी, 1965
56	सम्पूर्णानन्द	दि टेन्टेटिव सोशलिस्ट प्रोग्राम फार इण्डिया	वाराणसी

57	एलैक्जेण्डर ग्रे	दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन	लॉगमेन्स एण्ड ग्रीन, लदन, 1948
58	निकाल्स नूगेट	राजीव गॉधी सन आफ ए डाइनेस्टि	नई दिल्ली, 1991
59	सीमा मुस्तफा	द लोनली प्रोफेट-वी0 पी0 सिह, ए पोलीटिकल बायोग्राफी,	नई दिल्ली, 1995
60	ज्यो द्रेजे एण्ड अमर्त्यसेन,	इण्डिया इकोनामिक डेवलपमेट एण्ड सोशल अपार्चुनिटी	दिल्ली, 1996

हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएँ

1 यग इण्डिया- 20-1-1920, 15-11-1927, 20-11-1929, 29-3-1927

2 हरिजन-29-6-1935, 28-8-1940, 13-7-1947, 26-1-1952, 25-1-1952, 20-12-1952

3 जन- दिसम्बर, 1967, प्रकाशक-गौड मुरो हरि, नई दिल्ली

4 जन- मार्च 1968 प्रकाशक-गौडमुरो हरि, नई दिल्ली

5 जन -मई 1968 प्रकाशक-गोड मुरो हरि, नई दिल्ली

6 जनवाणी ,आचार्य नरेन्द्र देव काशी विद्यापीठ, वाराणसी,

7 धर्मचुग 30 सितम्बर 1977 सम्पूर्ण क्रान्ति विशेषांक टाइम्स आफ इण्डिया नई दिल्ली

8. सम्पदा, समाजवाद अक दिस0 1970, आशोक प्रकाशन मन्दिर दिल्ली

9 समाजवादी मेमार, 1956 नव हिन्द प्रकाशन, हैदराबाद

10 स्मारिका, चौथा राज्य सम्मेलन रीवा मध्यप्रदेश, समाजवाद पार्टी दिसम्बर 1970

11 सोवियद दर्पण (सम्पादक) अनोपी, बेनुण, सोवियत सघ प्रकाशन मई 1977

12. सोशलिस्ट पार्टी सिद्धान्त और कर्म, 1956, सोशलिस्ट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, हैदराबाद

13 समाजवादी बुलेटिन, सपादक (आलोक मेहता) लोहिया ट्रस्ट, लखनऊ दिसम्बर 2002

रिपोर्टस एण्ड डाक्युमेन्टस

1. आल इण्डिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, III कान्फ्रेंस, बम्बई, 1973
2. दि पालिसी "स्टेटमेन्ट आफ सोशलिस्ट पार्टी, कानुपर, 1947
3. आल इण्डिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कान्फ्रेंस, कानपुर, 1947
4. वही,I, नासिक, 1948
5. वही, II, पटना, 1949
6. वही, III, मद्रास, 1950
7. वही, विशेष कन्वेन्शन, पंचमढ़ी, 1952
8. वही, प्रजा शोसलिस्ट, पार्टी, I, कान्फ्रेंस, इलाहाबाद, 1953
9. वही, II, कांफ्रेंस, गया 1955
10. वही,III, कांफ्रेंस, बंगलोर, 1956
11. वही, I, पूना, 1958
12. वही, I, बम्बई, 1959
13. वही, I, कांफ्रेंस भोपाल, 1963
14. वही, II कांफ्रेंस, भोपाल, 1963
15. वही, III, कांफ्रेंस, वाराणसी, 1965
16. वही, IX, कांफ्रेंस, कानपुर, 1967-68
17. समाजवादी पार्टी का स्थापना सम्मेलन नव0 1992 लखनऊ
18. वही, द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन -अक्टू0 1994 लखनऊ
19. वही, तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन- जुलाई 1996 लखनऊ
20. वही, चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन- जनवरी, 1999 भोपाल
21. वही, पंचम राष्ट्रीय सम्मेलन- जनवरी, 2002, कानपुर